



# भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

[बी० एड० के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार]

लेखक

पी० डी० पाठक

भू० पू० मेथवरार इन हिस्ट्री आन्ड ऐजुकेशन

आर० ई० आई० टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज,

दमोदरगढ़

विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा





## ● सूचिका

“भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ”—इस विषय पर अनेक पुस्तकें होने हुए भी, मुझे इस नई पुस्तक को आपके हाथों में रखते हुए, कुछ सतोष का अनुभव हो रहा है। यह इसलिए कि इस पुस्तक का लेखन—बी० एड० परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के परिचित स्वरूप को निरन्तर ध्यान में रखकर किया गया है। इसीलिए, भारतीय शिक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों एवं आयोगों, विशेषतः कोठारी समीक्षण, के विचारों को मजबूत करके, यथास्थान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न परीक्षणों एवं सर्वेक्षणों पर आधारित आँकड़ों एवं तथ्यों को भी उपस्थित किया गया है।

अपने इस प्रयास के कारण मुझे पूरा भरोसा है कि छात्र—भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याओं का गहन एवं विस्तृत अध्ययन करने के लिए इस अकेली पुस्तक पर निस्मरकोच रूप से निर्भर हो सकते हैं और प्रश्नपत्रों के उत्तर देने में अपनी विशेष योग्यता का परिचय दे सकते हैं।

रसायन

3 अगस्त, 1974

—पी० डी० पाठक



## विषय-सूची

### भारतीय शिक्षा का इतिहास

#### 1. प्राचीन भारतीय शिक्षा

1-23

Ancient Indian Education

(2500 B. C.—500 B. C.)

विषय-प्रवेश 1, शिक्षा का अर्थ 2, शिक्षा का महत्त्व 2, शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श 3, शिक्षा की व्यवस्था 6, शिक्षा के अर्थ क्षेत्र 8, शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ 10, शिक्षा के प्रमुख दोष 17, आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्त्व 20 ।

#### 2. बौद्ध-शिक्षा

24-41

Buddhist Education

(500 B. C —1200 A. D.)

विषय-प्रवेश 24, शिक्षा की व्यवस्था 24, शिक्षा के अर्थ क्षेत्र 28, शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ 30, शिक्षा के प्रमुख दोष 35, आधुनिक भारतीय शिक्षा की देन 37, बौद्ध व वैदिक शिक्षा : समानता व असमानता 38, आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्त्व 39 ।

#### 3. मुस्लिम शिक्षा

42-65

Muslim Education

(1200-1700)

विषय-प्रवेश 42, शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श 43, शिक्षा की व्यवस्था 46, शिक्षा-मंस्थाओं के प्रकार 49, शिक्षा के अर्थ क्षेत्र 51, शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ 54, शिक्षा के प्रमुख दोष 59, आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्त्व 63 ।

4. यूरोपीय मिशनरियों के प्रारम्भिक शिक्षा-कार्य 66-72

Early Educational Activities of European Missionaries  
(1600-1833)

विषय-प्रवेश 66, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों 67, मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरम्भ 67, मिशनरियों के शिक्षा-कार्य 68, चार्ल्स ग्रांट 69, मिशनरी कार्यों का पुनराारम्भ 70, उपसंहार 71 ।

5. इंगलिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-कार्य 73-77

Early Educational Activities of English East India Company  
(1600-1833)

विषय-प्रवेश 73, स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना 74, 1813 का आज्ञा-पत्र 76, उपसंहार 76 ।

6. प्राच्य-पाश्चात्य विवाद, मैकॉले का विवरण-पत्र 78-86

व नित्यन्दन-सिद्धान्त

Oriental-Occidental Controversy, Macaulays Minute  
& Filtration Theory

विषय-प्रवेश 78, विवाद का मुख्य कारण 78, प्राच्यवादी 79, पाश्चात्यवादी 80, मैकॉले का विवरण-पत्र (1835) 80, वैदिक द्वारा विवरण-पत्र की स्वीकृति (1835) 83, विवाद का अन्त (1839) 83, नित्यन्दन-सिद्धान्त 84 ।

7. वुड का आदेश-पत्र, 1854

87-96

Wood's Despatch, 1854

विषय-प्रवेश 87, वुड के आदेश-पत्र का मूल कारण 87, आदेश-पत्र के मुद्दाय व निष्कारित 88, आदेश-पत्र का मूल्यांकन 91, आलोचकों की सम्मति 93, निष्कर्ष 95 ।

8. भारतीय शिक्षा-आयोग

97-107

(हंटर कमिशन)

Indian Education Commission

(Hunter Commission)

(1882-1883)

विषय-प्रवेश 97, आयोग के जीव के विषय 98, आयोग के मुद्दाय व निष्कारित 99, आयोग का मूल्यांकन 105 ।

9. शिक्षा की प्रगति  
Progress of Education  
(1882-1902)

108-111

विषय-प्रवेश 108, आयोग की सिफारिशों के परिणाम 108, शिक्षा की प्रगति :—(1) प्राथमिक शिक्षा 109, (2) माध्यमिक शिक्षा 110, (3) उच्च शिक्षा 110 ।

10 लॉर्ड कर्जन के शिक्षा-सम्बन्धी सुधार 112-121  
Educational Reforms of Lord Curzon  
(1898-1905)

विषय-प्रवेश 112, कर्जन के शिक्षा-सम्बन्धी सुधार :—(1) शिमला-शिक्षा-सम्मेलन (1901) 113, (2) भारतीय विश्वविद्यालय-आयोग (1902) 115, (3) भारतीय विश्वविद्यालय-अधिनियम (1904) 117, (4) शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (1904) 118, कर्जन के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन 120 ।

11 राष्ट्रीय आन्दोलन का शिक्षा पर प्रभाव 122-126  
Influence of National Movement on Education  
(1905-1921)

विषय-प्रवेश 122, राष्ट्रीय शिक्षा की माँग 122, राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धान्त या विभेदताएँ 123, राष्ट्रीय शिक्षा-मस्याओं की स्थापना 125, उपसंहार 126 ।

12 शिक्षा की प्रगति  
Progress of Education  
(1905-1921)

127-135

विषय-प्रवेश 127, शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (1913) 128, बलकृष्ण-विश्वविद्यालय-आयोग (1917-1919) 130, आयोग के सुझाव व सिफारिशें 131, आयोग का मूल्यांकन 132, शिक्षा की प्रगति :—(1) प्राथमिक शिक्षा 133, (2) माध्यमिक शिक्षा 134, (3) उच्च शिक्षा 134 ।

13 हार्टोग समिति, 1929  
Hartog Committee, 1929

136-143

विषय-प्रवेश 136, समिति के सुझाव व सिफारिशें :—(1) प्राथमिक शिक्षा 137, (2) माध्यमिक शिक्षा 140, विश्वविद्यालय-शिक्षा 141, हार्टोग समिति का मूल्यांकन 142 ।

14. वुड-एबट रिपोर्ट, 1937 144-149  
Wood-Abbott Report, 1937

विषय-प्रवेश 144, जांच के विषय 145, वुड-एबट-रिपोर्ट :—(1) सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें 146, (2) व्यावसायिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें 147, वुड-एबट रिपोर्ट का मूल्यांकन 148 ।

15. शिक्षा की प्रगति 150-158  
Progress of Education  
(1921-1947)

विषय-प्रवेश 150, द्विध ज्ञासन में शिक्षा की प्रगति :—(1) प्राथमिक शिक्षा 151, (2) माध्यमिक शिक्षा 152, (3) उच्च शिक्षा 153, प्रान्तीय स्वशासन में शिक्षा की प्रगति :—(1) केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-सम्बन्धी कार्य 154, (2) प्राथमिक शिक्षा 155, (3) माध्यमिक शिक्षा 157, (4) उच्च शिक्षा 157 ।

16. बुनियादी शिक्षा या नई तालीम 159-179  
(वर्धा-शिक्षा-योजना)  
Basic Education Or Nai Talim  
(Wardha Scheme of Education)

विषय-प्रवेश 159, गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी विचार 160, वर्धा-शिक्षा-सम्मेलन 161, जाकिर हुसेन समिति 162, वर्धा-योजना की रूपरेखा 163, बुनियादी शिक्षा नाम क्यों ? 163, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम 164, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताएँ 165, बुनियादी विद्यालयों की समय-सारणी 165, बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक व उनका प्रशिक्षण 166, बुनियादी शिक्षण-विधि 167, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य 168, बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त 170, बुनियादी शिक्षा के गुण या विशेषताएँ 172, बुनियादी शिक्षा के दोष 174, बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन 176 ।

17. सार्जेंट-रिपोर्ट, 1944 180-188  
शिक्षा-विकास की युद्धोत्तर योजना, 1944  
Sargent-Report, 1944

Post-War Plan of Educational Development, 1944

विषय प्रवेश 180, सार्जेंट-योजना के उद्देश्य 181, मुभाच व सिफारिशें 182, सार्जेंट-रिपोर्ट का मूल्यांकन 187 ।

18. विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग 189-201  
(राधाकृष्णन् कमिशन)  
University Education Commission  
(Radhakrishnan Commission)  
(1948-1949)

विषय-प्रवेश 189, आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य 190, आयोग के  
जाँच के विषय 190, आयोग के सुझाव व सिफारिशें 191, आयोग  
का मूल्यांकन 199 ।

19. माध्यमिक शिक्षा-आयोग 202-216  
✓ (मुदालियर कमिशन)  
Secondary Education Commission  
(Mudaliar Commission) ✓  
(1952-1953)

विषय-प्रवेश 202, आयोग के जाँच के विषय 203, आयोग के  
सुझाव व सिफारिशें 203, आयोग का मूल्यांकन 214 ।

20. शिक्षा-आयोग 217-269  
✓ (कोठारी कमिशन) ✓  
Education Commission  
(Kothari Commission)  
(1964-1966)

विषय-प्रवेश 217, आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन 218,  
आयोग की नियुक्ति 220, आयोग के जाँच के विषय 220, आयोग  
के सुझाव व सिफारिशें :—(1) शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य 222,  
(2) शिक्षा की संरचना व स्तर 225, (3) अध्यापक की स्थिति  
228, (4) अध्यापक-शिक्षा 231, (5) छात्रसंख्या व जनबल  
235, (6) शैक्षिक अवसरों की समानता 237, (7) विद्यालय-  
शिक्षा का विस्तार 239, (8) विद्यालय-पाठ्यक्रम 243, (9)  
शिक्षण-विधियाँ, निर्देशन व मूल्यांकन 246, (10) उच्च शिक्षा  
249, (11) स्त्री-शिक्षा 255, (12) वयस्क-शिक्षा 257, (13)  
विज्ञान की शिक्षा 262, (14) कृषि की शिक्षा 263, (15) व्याव-  
सायिक, प्राविधिक व इंजीनियरिंग की शिक्षा 265, आयोग का  
मूल्यांकन 267 ।



शिक्षा 408, शिक्षक-शिक्षा की नवीन धारणा 408, शिक्षा-आयोग व शिक्षक-शिक्षा 410, शिक्षक-शिक्षा का विस्तार 412, प्रशिक्षण-संस्थाओं के प्रकार 413, शिक्षा के प्रादेशिक कॉलेज 415, पत्राचार-पाठ्यक्रम-केन्द्र 417, सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा 419, समस्याएँ व उनके समाधान 421 :— (1) विभाजित उत्तरदायित्व, (2) प्रवेश के मानदण्डों में विभिन्नता, (3) स्वतंत्रताविहीन वातावरण, (4) मानवीय पक्ष की उपेक्षा, (5) मिद्धान्त पर अनावश्यक बल, (6) मिद्धान्त व व्यवहार में पृथक्ता, (7) शिक्षक-शिक्षा की पृथक्ता, (8) शिक्षक-शिक्षा का निम्न स्तर, (9) प्रशिक्षण-संस्थाओं के कार्यक्रमों में विभिन्नता, (10) प्रशिक्षण-संस्थाओं की निम्न कीर्ति ।

## 27. प्रौढ़ व समाज शिक्षा

438-482

### Adult & Social Education

विषय-प्रवेश 438, भारत में प्रौढ़-शिक्षा का विकास 438, पंच-वर्षीय योजनाओं में समाज-शिक्षा 443, प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ व परिभाषा 448, प्रौढ़ कौन है ? 449, प्रौढ़-शिक्षा की नवीन धारणा 449, प्रौढ़-शिक्षा व समाज-शिक्षा में अन्तर 450, समाज-शिक्षा का अर्थ व परिभाषा 450, समाज-शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम 452, समाज-शिक्षा की समस्याएँ 452, प्रौढ़-शिक्षा का पण्डमुखी कार्यक्रम 453, समाज-शिक्षा के उद्देश्य 453, समाज (प्रौढ़) शिक्षा का स्थान व महत्त्व 456, समाज (प्रौढ़) शिक्षा की आवश्यकता 457, समस्याएँ व उनके समाधान 461 :— (1) निरक्षरता, (2) पाठ्यक्रम, (3) शिक्षण-विधि, (4) धन का अभाव, (5) शिक्षकों का अभाव, (6) उपयुक्त साहित्य का अभाव, (7) शिक्षा के साधनों का अभाव, (8) अनवरत शिक्षा का अभाव, (9) नियोजन का अभाव, (10) विभाजित उत्तरदायित्व ।



## 28. प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा

483-517

### Technical & Vocational Education

विषय-प्रवेश 483, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य 484, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता का महत्त्व 485, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा का इतिहास 487, वैदिक काल में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा 487, बौद्ध-काल में

प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा 488, मुस्लिम काल में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा 488, ब्रिटिश काल में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा 489, स्वतंत्र भारत में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा 493, शिक्षा-आयोगों के प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा-विषयक सुझाव 496, पंचवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा 497, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति 503, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति 503, समस्याएँ व उनके समाधान 505 :—(1) हस्तकामों के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, (2) सामान्य व प्राविधिक शिक्षा में स्पष्ट अन्तर, (3) दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, (4) शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम, (5) व्यावहारिक प्रशिक्षण की उपेक्षा, (6) अपव्यय, (7) शिक्षकों का अभाव, (4) अध्ययन के उपरान्त शिक्षा का अभाव ।

### ✓ 29. स्त्री-शिक्षा Women's Education

518-541

विषय-प्रवेश 518, प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा 519, मुस्लिम भारत में स्त्री-शिक्षा 519, ब्रिटिश भारत में स्त्री-शिक्षा 520, स्वतंत्र भारत में स्त्री-शिक्षा 522, राष्ट्रीय महिला-शिक्षा-समिति (1958) 523, राष्ट्रीय महिला-शिक्षा-परिषद् (1959) 524, हसा मेहता समिति (1962) 524, कोठारी कमीशन व स्त्री-शिक्षा 525, पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री-शिक्षा 526, बालिका-शिक्षा का विस्तार 528, समस्याएँ व उनके समाधान 529 ।

### ✓ 30. अपव्यय व अवरोधन Wastage & Stagnation

542-552

विषय-प्रवेश 542, अपव्यय का अर्थ व परिभाषा 542, अवरोधन का अर्थ व परिभाषा 543, अपव्यय व अवरोधन : स्वरूप व परिणाम 543, अपव्यय व अवरोधन : कारण व उपचार 544, कोठारी कमीशन के अपव्यय व अवरोधन-विषयक विचार 551 ।

### 31. विविध विषय Miscellaneous Topics

553-557

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद् 553, (2) ग्रामीण उच्चतर शिक्षा 554, (3) उत्तर प्रदेश में अध्यापक-शिक्षा 555 ।





## प्राचीन भारतीय शिक्षा

### ANCIENT INDIAN EDUCATION

(2500 B. C.—500 B. C.)

“The pre-eminent position, which India once occupied in the contemporary world, was mainly due to the success of her educational system.”—Dr. A. S. Altekar.

#### विषय-प्रवेश

भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत में आज से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व हुआ था। किन्तु, उसके सुसम्बद्ध स्वरूप के दर्शन वैदिक काल के आरम्भ में होते हैं। इन काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। अतः कुछ लेखकों ने वैदिक कालीन शिक्षा को “ब्राह्मणीय शिक्षा” और कुछ ने “हिन्दू-शिक्षा” की संज्ञा दी है।

प्राचीन भारत के मनीषी इस तथ्य से भलीभाँति अवगत थे कि शिक्षा—व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विकास, समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सम्यक्ता की बहुमुखी प्रगति की आधार-शिला है। अतः उन्होंने शिक्षा की ऐसी प्रशमनीय प्रणाली का प्रतिपादन किया, जिसने न केवल विशाल वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा, वरन् ज्ञान के विविध क्षेत्रों में मौलिक विचारों को भी जन्म दिया, जिनसे भारत का भाल आज भी गर्व और गौरव से उन्नत है। इस दृष्टि में भारत की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुए एक० डब्ल्यू० टामस ने लिखा है — ‘भारत में शिक्षा, विदेशी पोषा नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतना प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो, या जिसने इतना विरस्थावी डाला हो।’

"Education is no exotic in India. There has been no country, where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful an influence."—F. W. Thomas : *The History and Prospects of British Education in India*, p. 1.

## शिक्षा का अर्थ

### Meaning of Education

वैदिक साहित्य में 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है; तथा :—'विद्या', 'ज्ञान', 'बोध' और 'चिन्तन'। आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियों के समान प्राचीन भारतीयों ने भी 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग 'व्यापक' और 'सीमित'—दोनों अर्थों में किया है। डा० ए० एस० अल्तेकर के अनुसार :—व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है—व्यक्ति को नम्य और उत्तम बनाना। इस दृष्टि से शिक्षा, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उम्र औपचारिक शिक्षा से है, जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती थी।

प्राचीन युग में 'शिक्षा' को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया और न जीविकोपार्जन का साधन। इसके विपरीत, शिक्षा को बहु प्रकाश माना गया, जो व्यक्ति को अपना बहुअंगी विकास करने, उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देती थी। हमारे शब्दों में, शिक्षा को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को पथ-प्रदर्शन करने वाला प्रकाश माना गया। इस कथन की पुष्टि में डा० ए० एस० अल्तेकर के अश्रित शब्द उल्लेखनीय हैं :—“वैदिक युग से आज तक शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा, प्रकाश का यह स्रोत है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ-प्रदर्शन करती है।”

## शिक्षा का महत्त्व

### Importance of Education

प्राचीन भारत में शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। इसका एक प्रमाण यह है कि शिक्षा को प्रकाश का स्रोत, अन्तर्दृष्टि, अन्तर्ज्योति, ज्ञान-चक्षु और मनुष्य का सीमन नेत्र माना जाता था। उस युग के भारतीयों का विचार था कि शिक्षा का प्रकाश, व्यक्ति के सब मंज्यों का उन्मूलन और उनकी सब बाधाओं का निवारण करता है। शिक्षा से प्राप्त अन्तर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा—व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से सम्पन्न करती है, उसके गुण, गुणन एवं समृद्धि में योग देती है, उसे जीवन के सकारण महत्त्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है, और उसे भव-सागर को पार करके, मोक्ष-प्राप्ति में सहायता देती है।

शिक्षा के महत्त्व के सम्बन्ध में उपरिअंशित और अनेक अन्य धारणाएँ व्यक्त

करके भारतीयों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा—कामधेनु या कल्पवृक्ष के समान व्यक्ति की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उसका सर्वांगीण विकास करती है। उनके इसी विश्वास के आधार पर ङा० ए० एस० अल्तेकर ने अपना यह मत व्यक्त किया है :—“शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था, जो हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरन्तर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके, हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है।”

“Education was regarded as a source of illumination and power, which transforms and ennobles our nature by the progressive and harmonious development of our physical, mental, intellectual and spiritual powers and faculties.”—Dr. A. S. Altekar : *Education in Ancient India*, p 8.

### शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श Aims & Ideals of Education

प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए ङा० ए० एस० अल्तेकर ने लिखा है —“प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है—ईश्वर-भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य-पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार।”

“Infusion of a spirit of piety and religiousness, formation of character, development of personality, inculcation of civic and social duties, promotion of social efficiency, and preservation and spread of national culture may be described as the chief aims and ideals of ancient Indian education”—Dr A. S. Altekar, pp. 8-9.

हम उपर्युक्त उद्देश्यों और आदर्शों एवं दो अन्य का संक्षिप्त विवरण उपस्थित कर रहे हैं; यथा :—

1. ज्ञान व अनुभव पर बल . Stress on Knowledge & Realization—प्राचीन भारत में शिक्षा का गहला उद्देश्य—ज्ञान और अनुभव पर बल देना था। उस समय छात्रों की मानसिक योग्यता का मापदंड उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अरु, प्रमाण-पत्र या उपाधि-पत्र नहीं थे। इनके स्थान पर, उनकी योग्यता का मापदंड था—उनके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, जिसका प्रमाण वे विद्वत्परिषदों में शास्त्रार्थ करके देते थे।

“छान्दोग्य उपनिषद्” में हमें श्वेतकेतु और कमनायन के उ

हैं, जिनको बारह वर्ष के अध्ययन के उपरान्त भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं समझा गया। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य या आदर्श केवल पढ़ना नहीं था, बरन् मनन, स्मरण और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को आत्मसात् करना भी था। डा० आर० के० मुकर्जी के शब्दों में :—“शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात् करना था।”

2. चित्त-वृत्तियों का निरोध : Chitta Vritti Nirodh—प्राचीनकाल में शिक्षा का दूसरा उद्देश्य—छात्रों की चित्त-वृत्तियों का निरोध करना था। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अनश्वर है। अतः आत्मा के उत्थान के लिए, जप, तप और योग पर विशेष बल दिया जाता था। ये कार्य—चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अर्थात् मन पर नियन्त्रण करके ही सम्भव थे। इसलिए, छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपनी चित्त-वृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि उनका मन झूझ-झूझ कर उनकी मोक्ष-प्राप्ति में, जिसे जीवन का चरम नश्य समझा जाता था, बाधा उपस्थित न करे। इस प्रकार, हम डा० आर० के० मुकर्जी के शब्दों में कह सकते हैं :—“शिक्षा का उद्देश्य—चित्त-वृत्ति निरोध, अर्थात् मन के उन कार्यों का निषेध था, जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है।”

“The aim of education was Chitta Vritti Nirodh, the inhibition of those activities of the mind by which it gets connected with the world of matter or object.”—Dr. R. K. Mookerji : *Ancient Indian Education*, p. 366.

3. ईश्वर-भक्ति व धार्मिकता का समावेश : Infusion of Piety & Religiousness—प्राचीन भारत में शिक्षा का तीसरा उद्देश्य—छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। उस समय उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था, जो इन संसार से व्यक्ति की मुक्ति को सम्भव बनाए—“सा विद्या या विमुक्तये”। व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी, जब वह ईश्वर-भक्ति और धार्मिकता की भावना से सश्रवण हो। छात्रों में इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा विकसित किया जाता था। डा० ए० एस० अल्तेकर ने लिखा है :—“सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य—छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था।”

4. चरित्र का निर्माण : Formation of Character—प्राचीन भारत में शिक्षा का चौथा उद्देश्य—छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। उस समय व्यक्ति के चरित्र को उसके पांडित्य से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता था। “मनुस्मृति” में लिखा है :—“केवल गायत्री मन्त्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान् ब्राह्मण, सम्पूर्ण वेदों के ज्ञाता, पर चरित्रहीन विद्वान् से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।” गुरुकुलों के उत्तम

वातावरण, सदाचार के उपदेशों, महापुरुषों के उदाहरणों, महान् विभूतियों के आदर्शों आदि के द्वारा छात्रों के चरित्र का निर्माण किया जाता था। डा० वेद मित्र का कथन है :—“छात्रों के चरित्र का निर्माण करना, शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था।”

“The building of character of the students was deemed as one of the essential objects of education.”—Dr. Veda Mitra : *Education in Ancient India*, pp 55-56.

**5. व्यक्तित्व का विकास : Development of Personality**—प्राचीन भारत में शिक्षा का पाँचवाँ उद्देश्य—छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनमें आत्म-मयम, आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था। साथ ही, गोष्ठियों और वादविवाद-सभाओं का आयोजन करके उनमें विवेक, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उनको बलवती बनाया जाता था।

**6 नागरिक व सामाजिक कर्तव्य-पालन की भावना का समावेश : Inculcation of Civic & Social Duties**—प्राचीन भारत में शिक्षा का छठा उद्देश्य—छात्रों में नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की भावना का समावेश करना था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिये जाते थे; यथा—अतिथियों का सत्कार करना, दीन-दुःखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य की निशुल्क शिक्षा देना, दूसरों के प्रति निस्स्वार्थता का व्यवहार करना, और पुत्र, पिता एवं पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना।

**7. सामाजिक कुशलता की उन्नति : Promotion of Social Efficiency**—प्राचीन भारत में शिक्षा का सातवाँ उद्देश्य—छात्रों की सामाजिक कुशलता में उन्नति करना था। उस समय शिक्षा केवल व्यक्ति का मानसिक विकास ही नहीं करती थी, बल्कि सामाजिक कुशलता में उसकी उन्नति भी करती थी, ताकि वह मरलता से अपनी जीविका का उपाजन करके, अपने सुख में अभिवृद्धि कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को उनकी रुचि और वर्ण के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। डा० आर० के० मुकुर्जी के शब्दों में :—“शिक्षा पूर्णतया सैद्धान्तिक और साहित्यिक नहीं थी, बल्कि किसी-न-किसी शिल्प से सम्बद्ध थी।”

**8. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार Preservation & Spread of National Culture**—प्राचीन भारत में शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य—राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए



## 6 | भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

बिना अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था, प्रत्येक ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता था और प्रत्येक आर्य, वैदिक साहित्य के हिमालय-निकली भाग का अध्ययन करता था। उन कार्यों ने हिमालय की कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं होता था, पर इसकी कल्पना है न केवल पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के, बल्कि हमारा प्रसार भी करने के।

हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा के जिस उद्देश्यों और आदर्शों की अंतिम किया है, उनमें निर्दिष्ट हो जाता है कि उनका निर्माण—धार्मिक के नैतिक और पारस्परिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था।

### शिक्षा की व्यवस्था

#### Organization of Education

डा० ए० एम० अल्तेकर के अनुसार :—"प्राचीन भारत में सम्मिश्रित 400 ई० पू० ने पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय एक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केन्द्र था। उसके पश्चात् कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया।" इसके फलस्वरूप, जिस शिक्षा-प्रणाली का विकास हुआ, हमारे प्राथमिक और उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में शिक्षा के बड़ी हो गयी है। हम उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं।

#### 1. प्राथमिक शिक्षा : Primary Education

1. सामान्य परिचय—प्राथमिक शिक्षा के विषय में सर्वप्रथम उल्लेखनीय बात यह है कि हम पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने धर्म-ग्रन्थों में उसका विवरण न देकर उसकी उपाधा की है। संतोष कुमार दास ने शोक दिया है :—"ब्राह्मणों के पास इस शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे, जो उनके हाथ में नहीं थी।"

'The Brahmins may have had reasons for wishing to ignore any form of education which was not in their hands.'—Santos Kumar Das : *The Educational System of the Ancient Hindus*, p. 38.

ब्राह्मणों की उपेक्षा के बावजूद 'ऋग्वेद' में यज्ञ-यज्ञ से नैतिक मित्रों जिनमें पाठशाला की भाँति किसी शिक्षा-संस्था की कल्पना की जा सकती है।

2. प्रवेश व अवधि—डा० वेद मित्र के अनुसार—प्राथमिक शिक्षा का उ० 5 वर्ष की आयु में "निवारण सम्पन्न" हो जाता था और सभी जातियों के बालक शिक्षा के लिए अनिवार्य था। हमारा अभिप्राय यह है कि सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। हम शिक्षा की अवधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है, पर डा० ए० एम० अल्तेकर का मत है कि हमकी अवधि की थी।

3. पाठ्यक्रम—प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत बातको को पहले कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना और बोलना सिखाया जाता था। जब वे उन मंत्रों को बटस्थ कर लेते थे, तब उनको पढ़ने और लिखने की शिक्षा दी जाती थी। भाषा का वांछित ज्ञान हो जाने के पश्चात् उनको साहित्य और व्याकरण से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार, शिक्षा का पाठ्यक्रम था :— वैदिक मंत्रों का स्मरण, पढ़ना और लिखना, भाषा, साहित्य एवं व्याकरण।

## 2. उच्च शिक्षा : Higher Education

1. सामान्य परिचय—प्राचीन काल में सर्वप्रथम केवल प्राथमिक शिक्षा की ही व्यवस्था थी। किन्तु, सामाजिक प्रगति के साथ-साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और उनके लिए पृथक् शिक्षा-संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई। लेखकों का अनुमान है कि इनकी स्थापना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक हो गई थी। यही से उच्च शिक्षा के इतिहास का सूत्रपात होता है।

2. प्रवेश व अवधि—उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को था। इन जातियों के बालक सामान्य रूप से क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षा-संस्था में प्रवेश करते थे। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी।

3. पाठ्यक्रम—पाठ्यक्रम में परा (आध्यात्मिक) विद्या और अपरा (लौकिक) विद्या—दोनों को स्थान दिया गया था। परा विद्या के अन्तर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद् आदि आध्यात्मिक विषय थे। अपरा विद्या के अन्तर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषय थे।

4. शिक्षण-विधि—मुद्रित पुस्तकों का अभाव होने के कारण शिक्षण-विधि प्रायः मौखिक थी। छात्र, गुरु के मुख में वेदादि ग्रन्थों को सुनते थे, उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे और पाठ्य-विषय को दोहराते थे। तदुपरान्त, वे एकान्त में पाठ्य-विषय का मनन, चिन्तन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे। शिक्षण-विधि में प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वादविवाद आदि का भी प्रयोग किया जाता था।

5. परीक्षाएँ व उपाधियाँ—शिक्षा समाप्त होने पर छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी। इसके लिए उन्हें विद्वानों की गभा में उपस्थित होना पड़ता था, जहाँ उन्हें विद्वानों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उपाधियाँ नहीं दी जाती थीं।

6. शिक्षा-संस्थाएँ—प्राचीनकाल में अनेक प्रकार की शिक्षा-संस्थाएँ थी; यथा :—

(i) टोल—टोल में संगठन की शिक्षा दी जाती थी । एक टोल में एक शिक्षक होता था ।

(ii) चरण—चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी । एक चरण में एक शिक्षक होता था ।

(iii) छटिका—छटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी । एक छटिका में अनेक शिक्षक होते थे ।

(iv) परियद्—परियद् में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी । एक परियद् में साधारणतः दस शिक्षक होते थे ।

(v) गुरुकुल—गुरुकुल में वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी । एक गुरुकुल में एक शिक्षक होता था ।

(vi) विद्यापीठ—विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी । एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे ।

(vii) विजिष्ट विद्यालय—विजिष्ट विद्यालय में एक विजिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी; जैसे, वैदिक विद्यालय में वेदों की और गृध्र विद्यालय में यज्ञ, हवन आदि की । एक विजिष्ट विद्यालय में एक शिक्षक होता था ।

(viii) मन्दिर-महाविद्यालय—किसी मन्दिर में सम्बद्ध मन्दिर-महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेदों, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी । एक मन्दिर-विद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे ।

(ix) ब्राह्मणीय महाविद्यालय—एक महाविद्यालय को 'चतुष्पथी' कहा जाता था, क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों अर्थात् अथर्वान्न चार विषयों की शिक्षा दी जाती थी—दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण । एक ब्राह्मणीय महाविद्यालय में एक शिक्षक होता था ।

(x) विषयविद्यालय—उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने कालान्तर में विश्व-विद्यालयों का रूप ग्रहण किया । इनमें पारमिक शिक्षा के अनिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, विज्ञान-शास्त्र आदि की भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी । बसारन, नागवद और मक्षजिन्ना के विषयविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध थे ।

## शिक्षा के अन्य क्षेत्र

### Other Spheres of Education

1. स्त्री-शिक्षा : Women's Education—वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रियों की भी शिक्षा प्रदत्त करने का अधिकार प्राप्त था । स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी और वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं । प्राचीन काल में अनेक विदुषी स्त्रियाँ थी; यथा—तीता, गार्गी, मंवेयी, अप्सरा, विश्वयरा, जटुगता और अनुमत्या ।

बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य-रचना, वाद-विवाद आदि की शिक्षा दी जाती थी। उनको शिक्षा अधिकतर अपने परिवारों में अपने माता-पिता, भाई-बहिन या कुल-पुरोहित के द्वारा दी जाती थी। यद्यपि बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी, तथापि सहशिक्षा का कुछ सीमा तक प्रचलन था। उदाहरणार्थ, आत्रेयी ने लव और कुश के साथ बाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी।

बालिकाओं और स्त्रियों को 200 ई० पू० तक शिक्षा की सभी सुविधाएँ प्राप्त थी, पर उसके बाद उनकी शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, जिसमें उनकी शिक्षा अवरोध हो गई। इस सम्बन्ध में डा० ए० एस० अल्तेकर के अप्राकृत शब्द उल्लेखनीय हैं —“धर्मशास्त्र युग (200 ई० पू०—500 ई०) में बालिकाओं के विवाह की आयु को कम करके 12 वर्ष कर दिया गया और स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन का निषेध कर दिया गया। इनसे उनकी शिक्षा को प्रबल आपात पहुँचा।”

**2. व्यावसायिक शिक्षा : Professional Education**—प्राचीन भारत में धर्म का मानव-जीवन में विशेष स्थान था। अतः शिक्षा मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक थी। किन्तु, व्यावसायिक शिक्षा को आवश्यक समझ कर उसकी भी समुचित व्यवस्था की गई थी। इस सदर्भ में डा० आर० के० मुकर्जी ने लिखा है :—“व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने आर्थिक जीवन और धर्म का निर्माण करने में सफल हुआ।”

“It was on the basis of professional education that India was able to build up her economic life and prosperity.”—Dr. R. K. Mookerji, p 368.

हम प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण अंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं, यथा —

**1. सैनिक शिक्षा : Military Education**—प्राचीन भारत में सैनिक शिक्षा व्यावसायिक आचार्यों द्वारा दी जाती थी। इन आचार्यों में द्रोणाचार्य का नाम आज भी प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में क्षत्रियों और राजकुमारों के लिए थी। सैनिक शिक्षा आरम्भ करने से पूर्व शिक्षार्थी के लिए उपनयन मस्कार आवश्यक था। उसके पश्चात्, उसे युद्ध-कला का ज्ञान प्रदान किया जाता था और उस समय के प्रमुख अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता था।

**2. चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा : Medical Education**—प्राचीन काल में चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दी जाती थी, जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे। इन शिक्षकों में अश्विनो कुमारों के नाम अपनी विलक्षण प्रतिभा के

लिए छात्र भी प्रसिद्ध हैं। चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा आरम्भ करने में पूर्व-उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के लिए उसी छात्र को योग्य समझा जाता था, जो पूर्णतया स्वस्थ होता था। चिकित्सा-शास्त्र के अध्ययन की अवधि साधारणतः 8 वर्ष की थी।

3. वाणिज्य-शिक्षा : Commercial Education—यह शिक्षा—वैश्यों के लिए थी। 'मनुस्मृति' और कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में इस शिक्षा का पूर्ण वर्णन मिलता है। हमने अनेक विषय सम्मिलित थे; यथा :—क्रय-विक्रय के नियम, आर्थिक एवं व्यापारिक भूगोल, विभिन्न धर्मों की उपज एवं आवश्यकताएँ, उपज-धर्मों और नदियों की जल के मार्ग, इत्यादि। वैश्य बालक को वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा अपने पिता ने और अपनी घर की दुकान पर अनुभव तथा अभ्यास में प्राप्त होती थी। यह शिक्षा कुछ शिक्षकों द्वारा भी दी जाती थी।

### शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

#### Main Features or Characteristics of Education

प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्शों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तत्कालीन शासक शिक्षकों ने जिस विनिष्ट शिक्षा-प्रणाली का विकास किया, उसका गुणगान करने हुए डा० एफ० ई० कीर्ज़ी ने लिखा है :—“ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा-प्रणाली का विकास किया, यह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों में अप्रभावित रही, बल्कि उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा।”

“Not only did the Brahman educators develop a system of education, which survived the crumbling of empires and the changes of society, but they also, through all these thousand years, kept aglow the torch of higher learning.”—Dr. F. E. Keay : *Indian Education in Ancient and Later Times*, p. 18.

इस इस शिक्षा-प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं; यथा :—

1. विद्यारम्भ संस्कार : Vidyarambha Ceremony—यह संस्कार उस समय होता था, जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करता था। कुछ विद्वानों ने इसके लिए “अक्षरस्वीकरणम्” शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द में स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार के समय बालक को अक्षर-ज्ञान कराया जाता था। बालक पहले गुरुदेवी, विनायक और अपने परिवार के देवताओं की उपासना करता था। उसके बाद गुरु उसने वर्णमाला के अक्षरों को सिखाया था। डा० ए० एस्० अल्तेकर के अनुसार—विद्यारम्भ संस्कार, उपनयन संस्कार के अनेक वर्षों बाद उस समय आरम्भ हुआ, जब वैदिक संस्कृत, अनुशासन की बोधनाय की भाषा नहीं रह गई थी। इस संस्कार के विषय में डा० वेद मिश्र ने लिखा है :—“यह संस्कार पाँच वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः सब जातियों के बालकों के लिए था।”

2. उपनयन संस्कार : Upanayan Ceremony—यह संस्कार उस समय होता था, जब बालक—गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरम्भ करता था। 'उपनयन' का शाब्दिक अर्थ है—“पास ले जाना” (Leading Near)। दूसरे शब्दों में, बालक को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। गुरु—बालक को पहले “मावित्री मंत्र” अर्थात् “गायत्री मंत्र” का उपदेश देता था और उसके बाद उसे शिक्षा देना आरम्भ करता था।

डा० ए० एस० अल्तेकर के अनुसार :—“उपनयन संस्कार” का आरम्भ पूर्व-ऐतिहासिक युग से माना जाता है। यह संस्कार, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्णों के बालकों के लिए अनिवार्य था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना “कलमा” के मुसलमान या बिना “वपतिस्मा” के ईसाई नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में कोई बालक बिना “उपनयन” के वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था।

3. समावर्तन संस्कार . Samavartan Ceremony—यह संस्कार उम समय होता था, जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा (या सैनिक शिक्षा, औपधि शास्त्र की शिक्षा इत्यादि) समाप्त कर लेता था। “समावर्तन” का शाब्दिक अर्थ है—“घर लौटना” (Returning Home)। यह संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था, जब छात्र गुरु-गृह से लौट कर अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था।

जिस दिन यह संस्कार होता था, उस दिन दोपहर के समय छात्र, स्नान करके और नए वस्त्र धारण करके गुरु के समक्ष उपस्थित होता था। गुरु पहले उसे मधुपर्क देता और फिर आधुनिक युग के दीक्षान्त भाषण (Convocation Address) के रूप में उसे “समावर्तन उपदेश” देता था। इस उपदेश का कुछ अंश इस प्रकार है :—“हे शिष्य ! सर्वदा सत्य बोलना। अपने कर्तव्य का पालन करना। स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। जो अच्छे कार्य हमने किए हैं, तुम उनका अनुकरण करना। थका से दान देना। तुम्हें हमारा यही आदेश है। यही उपदेश है।”

4 विद्यालय-भवन : Buildings of Institutions—प्राचीन काल में छात्रों के लिए किस प्रकार के भवन थे, इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः डा० अल्तेकर का यह मत सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है :—“अच्छे मौसम में कक्षाएँ वृक्षों की छाया में होनी होंगी, किन्तु वर्षा-ऋतु में किसी प्रकार के साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। जहाँ तक देवानियों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, उनके लिए भव्य और विशाल भवन थे।”

5 प्रकृति से सम्पर्क : Contact with Nature—प्राचीन काल में शिक्षा के अनेक विख्यात केन्द्र, तपोवनो में थे, जहाँ ऋषियों और मुनियों के चरणों में बैठकर छात्र, ज्ञान का मन्त्र करने थे। मुख्य दृश्यों से आवृत्त इन शिक्षा-केन्द्रों में छात्र

अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत करने थे। अतः उनका प्रकृति में प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता था, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव पड़ता था। इसी छात्रों के माध्यम से संपोषकों में आविर्भूत और परिपक्व होते वाली भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का सम्पूर्ण देश में प्रसार हुआ। उनीनिप, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह विचार व्यक्त कर दिया है:—"भारत के बच्चों ने सभ्यता को जो धारा प्रवाहित हुई, उसने सम्पूर्ण भारत को अल्पावधि कर दिया।"

"The current of civilization that flowed from its forests inundated the whole of India."—Rabindranath Tagore : *Visva Bharati Quarterly*, April, 1924.

6. गुरुकुल-प्रणाली : Gurukula System—प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक मुख्य विनियम—गुरुकुल-प्रणाली थी। गुरुकुल किसी गुरु, प्राकृतिक स्थान में, पर साधारणतः किसी ग्राम या नगर के निकट होते थे, ताकि छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उन्हें शिक्षा देने की सुविधा रहे। छात्र अपने गुरु के पास उसके कुल के सदस्य के रूप में रहकर ज्ञान का अध्वन करने थे और उनसे वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। वे गुरु के उच्च विचारों और आदर्शों का अनुकरण करते, अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते थे। गुरुकुल-प्रणाली की संगठना करने हुए, डा० एम० एन० मुकजी ने लिखा है:—"वैदिक कालीन भारत, शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा-संस्थाओं में यांत्रिक विधियों द्वारा विनाश वेमाने पर छात्रों के उद्धार में।"

7. वैदिक शिक्षा आरम्भ करने की आयु : Age at the Commencement of Vedic Education—डा० एम० एन० अल्लेकर ने लिखा है:—"वैदिक शिक्षा, उपनयन संस्कार के बाद, आरम्भ होती थी और अनेक बातों में आधुनिक मार्श्यात्मक शिक्षा के समान थी। अतः उसे आरम्भ करने की आयु साधारणतः 8 और 12 वर्ष के बीच में मानी जाती थी।" मनु के अनुसार—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए। (युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था।) मनु ने उपनयन की उच्चतम आयु भी निर्धारित कर दी थी, जिसके पश्चात् यह संस्कार नहीं हो सकता था। यह उच्चतम आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 थी।

यदि हम बात का उत्तरण कर देना असंभव न होगा कि जिस प्रकार वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए "उपनयन संस्कार" अनिवार्य था, उसी प्रकार वैदिक शिक्षा, श्रौतसिद्धान्त की शिक्षा आदि के लिए भी था।

8. अध्ययन की अवधि : Period of Study—प्राचीन काल में अध्ययन की अवधि साधारणतः 12 वर्ष की थी। इस अवधि में छात्र केवल एक ही अध्ययन कर सकते थे। यदि वे एक से अधिक वेदों का अध्ययन करना चाहते

तो उनको प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ने थे । 12, 24, 36 और 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले छात्र ऋषय, स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य कहलाते थे । साहित्य और धर्मशास्त्र के छात्रों की अध्ययन की अवधि 10 वर्ष की थी ।

9. शिक्षा-सत्र व छुट्टियाँ Academic Session & Holidays—शिक्षा-सत्र, श्रावण मास की पूर्णिमा को 'उपाक्रम' या 'श्रावणी' समारोह से आरम्भ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को 'उत्सर्जन' समारोह के साथ समाप्त होता था । इस प्रकार, शिक्षा-सत्र की अवधि पाँच माह की थी ।

आधुनिक समय के समान प्राचीन समय में भी शिक्षा-मस्याओं में छुट्टियाँ होती थीं । प्रत्येक मास में एक-एक सप्ताह के अन्तर में चार छुट्टियाँ होती थीं । अधिक आयु के छात्रों की अपेक्षा कम आयु के छात्रों को अधिक छुट्टियाँ मिलती थीं । छुट्टियाँ लम्बी नहीं होती थी, क्योंकि आवागमन की कठिनाइयों के कारण छात्र साधारणतः शिक्षा समाप्त करके ही घर लौटते थे ।

10. शिक्षा का स्वरूप : Form of Education—प्राचीन समय में सम्पूर्ण शिक्षा—धर्म से अनुप्राणित थी । शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, व्यवस्था, विषय-सामग्री, यहाँ तक कि छात्रों का दैनिक जीवन भी धर्म पर अवलम्बित था । ज्ञान का अर्जन धर्म के द्वारा और धार्मिक कर्त्तव्य के रूप में किया जाता था । इस प्रकार, शिक्षा का सम्पूर्ण कलेवर, धर्म के अभेद्य आवरण से आवृत था । इस प्रसंग में गम्वार मिरडल के अप्रकृत वाक्यों का अवलोकन कीजिए —“शिक्षा पीढ़ी-दर-पीढ़ी होने वाले धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों का संकलन थी । मंत्रों, देवगीतों, धर्म-ग्रन्थों का उस समय तक पाठ किया जाता था, जिस समय तक वे कठस्थ नहीं हो जाते थे ।”

11. नि शुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा : Free & Universal Education—प्राचीन भारत में शिक्षा नि शुल्क थी, पर शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् प्रत्येक छात्र अपने गुरु को दक्षिणा अवश्य देता था । वह दक्षिणा के रूप में धन, भूमि, पशु, अन्न—कुछ भी दे सकता था । दक्षिणा इतनी कभी नहीं होती थी जो शिक्षक का पर्याप्त पारिश्रमिक कहा जा सके ।

नि शुल्क होने के कारण शिक्षा सार्वभौमिक और सब के लिए थी । किन्तु, कुछ लेखकों का विचार है कि शिक्षा अनिवार्य थी । डा० वेद मिश्र के अनुसार, उनका यह विचार—मनु के इस कथन पर आधारित है :—“मनु का कथन है कि राज्य और समाज को 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात् बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने धन्वे को इस आयु के पश्चात् घर पर रहे, उसको दण्ड दिया जाना चाहिए ।”

12. शिक्षा की पद्धति . Method of Education—प्राचीन भारत में शिक्षा की पद्धति को वैयक्तिक बताते हुए, गम्वार मिरडल ने लिखा है :—“हिन्दू धर्म की





## 16. छात्र-जीवन सम्बन्धी नियम : Rules Regarding Student-Life—

छात्रों के जीवन के सम्बन्ध में अनेक नियम थे, जिनका उनको अनिवार्य रूप में पालन करना पड़ता था, यथा :—

(i) आदर्श—घनी और निर्धन, उच्च और निम्न—सभी परिवारों के छात्रों को गादा और मरल जीवन ध्यनीत करना पड़ता था। महाभारत और रामायण में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे यह पूर्ण रूप से विदित हो जाता है कि राज-परिवारों के छात्रों को भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ना था, जिनका सामना उनके निर्धन सहपाठी करते थे।

(ii) दिनचर्या—छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि में निवृत्त होकर सध्या, हवन आदि विभिन्न कार्य करने पड़ते थे। उनके पश्चात्, वे अपने पुराने पाठों को दोहराते थे और नये पाठों की तैयारी करते थे। मध्याह्न में भोजन के लिए उनको अवकाश मिलता था। उनके उपरान्त वे फिर विद्याध्ययन में संलग्न हो जाते थे। सूर्य अस्त होने के समय वे भजन-पूजा करने के पश्चात् भोजन ग्रहण करते थे।

(iii) खान-पान—मनु के अनुसार, छात्र दिन में केवल दो बार भोजन कर सकते थे—मध्याह्न और मायकाल के समय। उनको कम खाने का आदेश था, ताकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा न पड़े और वे रोग ग्रस्त न हों। वे किसी भी दशा में मांस, मदिरा, मद्य, मादक वस्तुओं और पान का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

(iv) वेश-भूषा—मनु के अनुसार विभिन्न जातियों के छात्रों की वेश-भूषा विभिन्न थी। प्रत्येक छात्र को मेखला धारण करनी पड़ती थी। ब्राह्मण की मेखला मूँज की, क्षत्रिय की तान की और वैश्य की ऊन की होती थी। वे अपने शरीर के निम्न भाग को क्रमशः मन, रेशम और ऊन के वस्त्र में एवं ऊपरी भाग को क्रमशः काले मृग, चित्तीशर मृग और बकरी की खान से ढकते थे। प्रत्येक छात्र के लिये यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य था। कोई भी छात्र अन्न, मुग्ध, छाने, जूतों और फूलमालाओं का प्रयोग नहीं कर सकता था।

(v) आचार-व्यवहार—प्राचीन काल में इस बात पर विशेष बल दिया जाता था कि छात्रों का आचार और व्यवहार उत्कृष्ट हो। अतः उन्हें मर्यादा, शिष्टाचार और आत्म-संयम के नियमों का अनुसरण करने का आदेश दिया जाता था। वे काम-क्रोध, मद-लोभ और दूषित विचारों से मुक्त रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। वे अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए नियमित रूप से हवन और संध्या करते थे। वे गाली-गलौज और चुगलखोरी की बुरी आदतों से दूर रहते थे। वे जुआ, नृत्य, संगीत और स्त्री के पास नहीं जा सकते थे। वे गुह और वृद्धजनों का सम्मान करते थे।

17 गुरु-शिष्य सम्बन्ध : Teacher-Pupil Relationship—प्राचीन भारतीय शिक्षा की सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ विशेषता—गुरु-शिष्य के सम्बन्ध की थी। उन



प्राचीन की पूर्ण करने में विफल रहे और उनका काम आरम्भ हुआ, उनका कार्य-  
प्रणाली प्राचीन-प्रणाली अपने-प्राचीन के कारण प्राचीन की आरम्भ-  
—Dr. F. E. Keay, *op. cit.*, p. 181.

formal, and unable to meet the needs of a progressive civilization."  
"The Brahmanic educational system became stereotyped and  
रही गई।"

प्राचीन की पूर्ण करने में विफल रहे और उनका काम आरम्भ हुआ, उनका कार्य-  
प्रणाली प्राचीन-प्रणाली अपने-प्राचीन के कारण प्राचीन की आरम्भ-  
—Dr. F. E. Keay, *op. cit.*, p. 181.  
प्राचीन की पूर्ण करने में विफल रहे और उनका काम आरम्भ हुआ, उनका कार्य-  
प्रणाली प्राचीन-प्रणाली अपने-प्राचीन के कारण प्राचीन की आरम्भ-  
—Dr. F. E. Keay, *op. cit.*, p. 181.  
प्राचीन की पूर्ण करने में विफल रहे और उनका काम आरम्भ हुआ, उनका कार्य-  
प्रणाली प्राचीन-प्रणाली अपने-प्राचीन के कारण प्राचीन की आरम्भ-  
—Dr. F. E. Keay, *op. cit.*, p. 181.

प्राचीन की पूर्ण करने में विफल रहे और उनका काम आरम्भ हुआ, उनका कार्य-  
प्रणाली प्राचीन-प्रणाली अपने-प्राचीन के कारण प्राचीन की आरम्भ-  
—Dr. F. E. Keay, *op. cit.*, p. 181.  
प्राचीन की पूर्ण करने में विफल रहे और उनका काम आरम्भ हुआ, उनका कार्य-  
प्रणाली प्राचीन-प्रणाली अपने-प्राचीन के कारण प्राचीन की आरम्भ-  
—Dr. F. E. Keay, *op. cit.*, p. 181.

## Chief Defects of Education

### विश्वविद्यालय की प्रमुख दोष

—Dr. F. N. Prabhu : *op. cit.*, p. 130.

well developed and whose intellectual impulse was kept pure and  
"It created strong personalities, whose mental powers were  
प्रकृतियों की।"

प्रकृतियों की पूर्ण करने में विफल रहे और उनका काम आरम्भ हुआ, उनका कार्य-  
प्रणाली प्राचीन-प्रणाली अपने-प्राचीन के कारण प्राचीन की आरम्भ-  
—Dr. F. N. Prabhu : *op. cit.*, p. 130.  
प्रकृतियों की पूर्ण करने में विफल रहे और उनका काम आरम्भ हुआ, उनका कार्य-  
प्रणाली प्राचीन-प्रणाली अपने-प्राचीन के कारण प्राचीन की आरम्भ-  
—Dr. F. N. Prabhu : *op. cit.*, p. 130.

—Dr. P. N. Prabhu : *Hindu Social Organization*, p. 134.  
rol like that of the State or the Government or any party politics."  
"Education in ancient India was free from any external con-

इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि लौकिक पक्ष की उपेक्षा करके आध्यात्मिक पक्ष को महत्त्व दिया गया। फलस्वरूप, प्राचीन युग के व्यक्ति ससार एवं सासारिक जीवन को अमार मानने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गये। अतः इस युग में व्यक्तियों की लौकिक प्रगति का मार्ग बहुत सीमा तक अवरुद्ध हो गया।

**7. विचार-स्वातन्त्र्य का अभाव : Lack of Freedom of Thought—** प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्त्व दिए जाने के कारण व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई कि धर्मशास्त्रों में लिखी हुई सब बातें पूर्णतया सत्य हैं और उन्होंने जिन बातों को असत्य बताया है, वे कदापि सत्य नहीं हो सकती हैं। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारतीय समाज में अनेक अधविश्वासों और रुढ़िवादियों का प्रवेश हुआ।

**8. हस्तकार्य व शारीरिक धम के प्रति घृणा : Hatred for Handwork & Physical Labour—** प्राचीन भारतीय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा की तुलना में लौकिक शिक्षा का स्थान बहुत निम्न था। फलस्वरूप, अध्ययन-केन्द्रों में लौकिक शिक्षा से सम्बन्धित हस्तकार्यों की शिक्षा को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। अतः उच्च वर्गों के छात्रों का, जो इन अध्ययन-केन्द्रों में शिक्षा ग्रहण करते थे, इन कार्यों से कोई सम्पर्क नहीं हुआ। ये कार्य निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक ही सीमित रहे, जिनको इनकी शिक्षा अपने परिवारों में प्राप्त होती थी। इन वर्गों के व्यक्तियों को हेय समझा जाता था। अतः उनके द्वारा किए जाने वाले हस्तकार्यों और शारीरिक धम को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा।

**9. धर्म को अत्यधिक महत्त्व : Immense Importance to Religion—** प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। शिक्षा की सम्पूर्ण संरचना धार्मिक आदर्शों से निमज्जित थी। इन्हीं आदर्शों के अनुसार, शिक्षा के विषयों, उद्देश्यों और पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया था। छात्रों के समय का अधिकांश भाग धर्म-शास्त्रों के अध्ययन और कर्मकांडों के सम्पादन में व्यतीत होता था। उनको निष्काम कर्म करने और अपनी इच्छाओं का दमन करने का उपदेश दिया जाता था। डा० एफ० ई० केई के अनुसार :—“इस प्रकार की शिक्षा ने छात्रों में उच्च आदर्शों का तो समावेश किया, किन्तु शिक्षा की प्रगति में योग नहीं दिया।”

**10. नवीन धर्मों का आविर्भाव : Birth of New Religions—** डा० एस० एन० मुकर्जी का विचार है :—लगभग पंद्रहवीं शताब्दी के अन्त में शिक्षा अधिकांश रूप में ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गई थी और शिक्षा के व्यवसाय पर उनका एकमात्र अधिकार था। इस अधिकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया और उसमें जटिलता को कूट-कूट कर भर दिया। इस जटिलता के परिणामस्वरूप धार्मिक कृत्यों और ब्राह्मणों द्वारा उनमें प्रयोग की जाने वाली संस्कृत भाषा का जनसाधारण के लिए कोई महत्त्व नहीं रह गया। वैदिक धर्म के प्रति जनसाधारण के

इसी परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण दो नवीन धर्मों का आविर्भाव हुआ—बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक गम्भीर दोष थे, जिनके कारण यह कालान्तर में समयानुकूल न रह गई और उनका ह्रास आरम्भ हो गया । इन दोषों और इनके कारण होने वाले ह्रास को रोहते के विषय में डा० एफ० ई० केई ने अत्रांकित विचार लेखबद्ध किये हैं :—  
“प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष थे । इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपान्तरित करने के लिए किसी प्रकार के नव जीवन की आवश्यकता थी ।”

“The ancient Indian education had many defects, and needed some new breath of life to quicken it and transform it.”—Dr. F. E. Keay : *op. cit.*, p. 189.

## आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्त्व

### Acceptable Features for Modern Education

प्राचीन भारतीय शिक्षा और आधुनिक भारतीय शिक्षा के मध्य अनेक शता-  
वियों का अन्तर है । पर, फिर भी प्राचीन शिक्षा के ऐसे अनेक तत्त्व हैं, जिनकी  
सिद्धान्त और व्यवहार—दोनों दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जा सकता  
है । इन प्रकार के मुख्य तत्त्व अधोलिखित हैं :—

1. आदर्शवादिता : Idealism—आज हम आधुनिक युग में निवास कर  
रहे हैं । किन्तु, हमें अपने पूर्वजों से जो सम्पत्ता और संस्कृति विरासत में मिली है,  
उन पर हमें आज भी गर्व है । हम आज भी धर्म, ईश्वर और निष्काम कर्म को महत्त्व  
देते हैं । हम आज भी धन की अपेक्षा चरित्र को, भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता  
को, और विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को श्रेष्ठतर समझते हैं । आज जब कि सम्पूर्ण  
विश्व—धन, जक्ति, हिंसा और कुटनीति में आस्था रगता है, हम प्रेम, सत्य, अहिंसा,  
त्याग और उपम्या के समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं ।

उपरोक्त मनी बातों का अभिप्राय यह है कि हम आज भी उस आदर्शवादिता  
को नहीं भूलें हैं, जिसका प्राचीन शिक्षा द्वारा छात्रों के मन और मस्तिष्क में समावेश  
किया जाता था । इसमें स्वाभाविक निष्कर्ष यही निकलता है कि प्राचीन आदर्श-  
वादिता को आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए ।  
डा० महाश्वरद सिंघल ने राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित “भारतीय  
शिक्षा की पर्यन्त समस्याएँ” नामक अपनी पुस्तक में लिखा है :—“हम वैदिक  
प्राचीन शिक्षा को आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के एक मूल सिद्धान्त के रूप में  
ग्रहण कर सकते हैं और जीवन-निर्माण, चरित्र-निर्माण तथा सादा भोजन और उच्च  
विचार को शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों में स्थान दे सकते हैं ।”

2. अनुशासन व गुरु-शिष्य सम्बन्ध : Discipline & Teacher-Pupil  
Relationship—प्राचीन छात्र की छात्रों की अनुशासन की भावना और गुरु एवं

शिष्य का मधुर सम्बन्ध विश्व-वस्थित है—आज इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण अत्यन्त विषम हो चुका है और अनुशासनहीनता का ताण्डव नृत्य सर्वत्र हो रहा है। छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास और वैदिक कालीन गुरु-शिष्य सम्बन्ध की पुनर्स्थापना करके ही इन दोनों दूषणों से मुक्ति पाने की आशा की जा सकती है।

मानव-सम्बन्धों को धनिष्ठता प्रदान करने के लिए पारस्परिक स्नेह और सम्मान की भावनाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्र, शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं और शिक्षक, अध्ययन कार्य में तभी रचि ले सकते हैं, जब दोनों सुन्दर सम्बन्ध के मून से आवद्ध हों। यह सत्य है कि आज के छात्र और शिक्षक प्राचीन युग के आदर्श पर नहीं पहुँच सकते हैं, पर फिर भी हृदय निश्चय से उसकी ओर अग्रसर होकर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः छात्रों और शिक्षकों का उस आदर्श की दिशा में अग्रसर होना केवल वांछनीय ही नहीं, बल्कि अत्यन्त आवश्यक भी है। पर यह तभी सम्भव हो सकता है, जब छात्र—गुरु-शिष्य सम्बन्धों वैदिक आदर्शों के प्रति निष्ठावान् बनें और शिक्षक उस आदर्श के अनुसार सरस्वती-साधना में लीन होकर मरल जीवन व्यतीत करें।

3. शान्त वातावरण Peaceful Atmosphere—प्राचीन काल की सभी शिक्षा-शालाएँ नगर के कोलाहल और विपाक्त वातावरण में दूर किसी शान्त और रमणीक स्थान में स्थित थीं। आधुनिक युग में नगरीयकरण के प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों में नगरी में निवास करने की प्रवृत्ति सबल हो गई है। ऐसी दशा में आज की शिक्षा-संस्थाओं की नगरी से पृथक्ता सम्भव नहीं है। पर फिर भी, उनका निर्माण नगरी के कोलाहल और गन्दगी से दूर किसी शान्त, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक वातावरण में किया जा सकता है।

इस प्रकार की शिक्षा-संस्थाएँ न केवल छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास में योग देंगी, बल्कि उनकी नगरी के दिन-प्रति-दिन के भगडों, राजनीतिक कुचक्रों और अन्य अवांछनीय प्रवृत्तियों से रक्षा भी करेंगी।

4. अध्ययन के विषय : Subjects of Study—आधुनिक भारतीय शिक्षा में अनेक विषयों को स्थान दिया गया है, पर संस्कृत की प्रायः पूर्ण उपेक्षा की गई है। वस्तुतः संस्कृत भाषा और साहित्य में शान्ति, मानवता और विश्व-भ्रातृत्व की ऐसी अमूल्य निधियाँ हैं, जिनको न केवल भारत के पाठ्यक्रम में, बल्कि सब देशों के पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए। इनके अतिरिक्त, वैदिक पाठ्यक्रम से ऐसे अनेक सत्य ग्रहण किये जा सकते हैं, जो आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्कर्ष में अद्वितीय योग दे सकते हैं। डा० महेशचन्द्र सिंघल का मत है :—  
“यदि इन बातों की उपेक्षा की जाती है, तो भारतीय शिक्षा पश्चिम का चोरा जनुकरण मात्र रह जायेगी, जिसमें मौलिकता की झलक नहीं मिल सकेगी।”

5. शिक्षण-विधि व शिक्षा-सिद्धान्त Teaching Method & Principles

of Education—प्राचीन भारत की शिक्षण-विधि में श्रवण, मनन, चिन्तन, स्मरण, प्रश्नन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद-विवाद आदि का प्रयोग किया जाता था। अतः यह शिक्षण-विधि आज भी विभिन्न विषयों के पठन-पाठन में प्रयोग किये जाने योग्य है और उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

प्राचीन शिक्षा के अनेक सिद्धान्त आज भी उतने ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, जितने कि वे प्राचीन काल में थे। इस प्रकार के कुछ सिद्धान्त हैं—छोटी कक्षाएँ, व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तिगत ध्यान और अच्छी आदतों का निर्माण।

6. छात्रों का सरल जीवन : Simple Life of Students—वैदिक-कालीन भारत के छात्र गाँदा, सरल और संयमी जीवन व्यतीत करते थे। आधुनिक भारत में उनका जीवन भले ही अक्षरशः अनुकरणीय न हो, पर ग्रहणीय अवश्य है। आज के छात्रों के जीवन में आमुल परिवर्तन हो गया है। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य, शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, अपितु सिनेमा देखना, हड़तालें करना, अश्लील साहित्य पढ़ना, नवीली वस्तु-ओं का प्रयोग करना और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना हो गया है।

ऐसी परिस्थिति में प्राचीन काल के छात्रों के उदाहरण को आज के छात्रों के समक्ष रखकर, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है। डा० महेशचन्द्र सिंघल के शब्दों में :—“सिद्धान्त रूप में हमें इतना तो मानना ही चाहिए कि आज भले ही सिर मूँडने, लमोटी बांधने तथा स्त्री-जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बचकर रहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा और संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या तथा दुर्व्यसनों से बचकर रहना प्रांछनीय है।”

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. Discuss the main defects of education prevalent in India in the Vedic Age. How far have these defects been removed from the modern education of India.

भारत में वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोषों की विवेचना कीजिए। भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहाँ तक हुआ है ?

2. What were the chief characteristics of education in ancient India ? To what extent can they be utilized in evolving an effective national system of education in the country today ?

प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं ? वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली विकसित करने के लिए किन सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है ?



3. What were the chief aims of education in ancient India ? How far can they prove useful for modern education in our country ?

प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे ? वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहीं तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ?

4. Mention at least five important ideals of ancient Indian education and discuss their utility for Indian education today.

प्राचीन भारतीय शिक्षा के कम-से-कम पाँच महत्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए ।

5. Write notes on —(a) Gurukula System, (b) Teacher-Pupil Relationship, (c) Organization of Education in the Vedic Age.

टिप्पणियाँ लिखिए :—(अ) गुरुकुल-प्रणालि, (ब) गुरु-शिष्य सम्बन्ध, (स) वैदिक-कालीन शिक्षा-व्यवस्था ।

## 2

### बौद्ध-शिक्षा

#### BUDDHIST EDUCATION (500 B.C.—1200 A.D.)

"Buddhist education rightly regarded is but a phase of the ancient Hindu or Brahmanical system of education."  
—Dr. R. K. Mookerji.

#### विषय-प्रवेश

जनमम देना पूर्व पाँचवीं शताब्दी से जन-जीवन की परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकने के कारण वैदिक कालीन अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा में विश्रुतत्वता के निरुद्ध दृष्टिगोचर होने लगे थे । भारत के सौभाग्य से उसके एक शताब्दी पूर्व ही महात्मा गौतम बुद्ध ने इस देश की भूमि पर अवतरित होकर शिक्षा की समयानुकूल बनाने के विचार से उसके कलमर में परिवर्तन करके बौद्ध-शिक्षा को जन्म दिया । इस शिक्षा के विषय में डा० एफ० ई० कैटने ने लिखा है :—“बौद्ध-शिक्षा 1,500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा-पद्धति का विकास किया, जो ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति की प्रतिद्वन्द्वी थी, पर अनेक बातों में उसके सहृद थी ।”

"For over fifteen hundred years Buddhist education was in vogue, and developed a system of education which was a rival of the Brahmanic system, though in many ways similar to it."—Dr. F. E. Keay : *Indian Education in Ancient and Later Time*, p. 85.

#### शिक्षा की व्यवस्था

#### Organization of Education

बौद्ध धर्म का विस्तार मठों में हुआ था । ये मठ न केवल धर्म के, बल्कि शिक्षा के भी केन्द्र थे और शिक्षा देने का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा

किया जाता था। इन तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए डा० आर० के० मुकर्जी ने लिखा है :—“बौद्ध-मठ, बौद्ध-शिक्षा और ज्ञान के केन्द्र थे। बौद्ध-संसार अपने मठों से पूषक् या स्वतंत्र रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक, सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी।”

“Buddhist education and learning centred round monasteries. The Buddhist world did not offer any educational opportunities apart from or independently of its monasteries. All education, sacred as well as secular, was in the hands of the monks.”—Dr. R. K. Mookerji : *Ancient Indian Education*, p. 394.

प्राचीन काल के समान बौद्ध काल में भी केवल प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी और शिक्षा के यही दो स्तर थे। हम इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं।

### 1. प्राथमिक शिक्षा : Primary Education

1 सामान्य परिचय—हमें “जातक कथाओं” से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलम्बियों को ही नहीं, बल्कि सब जातियों के बालकों को उपलब्ध थी। यह शिक्षा मठों में दी जाती थी और आरम्भ में पूर्णतया धार्मिक थी। किन्तु, जब कुछ समय के उपरान्त ब्राह्मणों ने प्रतिद्वन्द्वी शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करके, उनमें लौकिक शिक्षा देने आरम्भ कर दी, तब मठों में भी इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। पाँचवीं शताब्दी में भारत जाने वाले चीनी यात्री फाह्यान (Fa-Hien) के लेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है।

2 प्रवेश व अवधि—सातवीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री, चाइमिंग (I-Tsing) के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने की आयु 6 वर्ष की थी। इस शिक्षा की अवधि साधारणतः 6 वर्ष की थी।

3 पाठ्यक्रम—सातवीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग (Huen-Tsang) ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन इस प्रकार किया है :—बालकों को प्रथम 6 माह में ‘सिद्धिरस्तु’ (Siddhirastu) नामक बालपोथी पढ़नी पड़ती थी। इस पोथी में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे, जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। 6 माह के बाद बालकों को अष्टाक्षर पाँच विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी—सन्ध-विद्या, हेतु-विद्या, चिकित्सा-विद्या, आध्यात्म-विद्या और शिल्प-स्थान-विद्या (Grammar, Logic, Medicine, Metaphysics & Arts and Crafts)। इस प्रकार, पाठ्यक्रम में धार्मिक और लौकिक—दोनों विषयों को स्थान दिया गया था।

4. शिक्षण-विधि—एल्बर्ट फिट्चे (Albert Fytche) के अनुसार, सामान्य शिक्षण-विधि इस प्रकार थी—शिक्षक, तबड़ी की तल्लो पर वर्णमाला के अक्षरों

की शिक्षा या और उनका उच्चारण करना था। वास्तव उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे। इस प्रकार, जब कुछ समय के बाद उनकी अक्षरों का ज्ञान हो जाता था, तब वे इनकी लिखते थे। पाठ्य-विषय के शिक्षण में अध्यापक आगे-आगे चलता था और बालक उसके कथन की उस समय तक दोहराते थे, जब तक उनकी पाठ्य-विषय तटस्थ नहीं हो जाता था। इस प्रकार, शिक्षण-विधि पूर्णतया मौखिक थी।

5. शिक्षा का माध्यम—मठ-विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम, जनसाधारण की भाषा—प्राचीन थी, न कि ब्राह्मणीय शिक्षालयों की संस्कृति।

## 2. उच्च शिक्षा : Higher Education

1. सामान्य परिचय—उच्च शिक्षा के द्वार सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए खुले हुए थे। इस शिक्षा के प्रमुख केन्द्र—बौद्ध-मठ थे, पर सब मठों में गणान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस शिक्षा की प्रशंसा में डा० ए० ए० ह्यूज अल्तेकर ने अप्रतिष्ठ शब्द लिखिबद्ध किए हैं:—“मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा ऐसे सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके, भारत की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की।”

“The monasteries raised the international status of India by the efficiency of their higher education, which attracted students from distant countries like Korea, China, Tibet and Java.”—Dr. A. S. Altekar : *Education in Ancient India*, p. 234.

2. प्रवेश व अवधि—उच्च शिक्षा का आरम्भ प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् होता था। अतः वास्तव इसका आरम्भ साधारणतया 12 वर्ष की आयु में करने थे। अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी, ताकि छात्र प्राचीन परम्परा के अनुसार 25 वर्ष की आयु में किसी व्यवसाय को ग्रहण करके, गुरुत्व के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

3. पाठ्यक्रम—पाठ्यक्रम दो भागों में विभक्त था—धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम—ब्रिह्मजो और ब्रिह्मसिधियों के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य—उनकी निर्माण प्राप्त करने और धर्म का प्रचार करने की योग्यता प्रदान करना था। उनकी धार्मिक और जीवनोपयोगी—दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मुख्य धार्मिक विषय थे—बौद्ध धर्म, साहित्य, विविष्टत, विनय, धम्म आदि। जीवनोपयोगी विषयों में मन्त्र और विहारों के निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान, धान की सम्पत्ति का प्रत्यक्ष और हिमायन-तत्वाय आदि सम्मिलित थे।

लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य—उनकी सुतेज नागरिक बनाता एवं आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना था। उनके पाठ्यक्रम में अर्द्धांगीय विषय सम्मिलित थे—धर्म, दर्शन, साहित्य, लक्ष्यशास्त्र, व्यावसाय, निर्माण-शास्त्र आदि।

4. शिक्षा का माध्यम—शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप में पाली भाषा थी, पर वैदिक साहित्य की शिक्षा, स्मृतियों के माध्यम में दी जाती थी। इसके अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था। इसका कारण महात्मा बुद्ध की निजुओं को यह अनुमति थी :—“ओ भिक्षुओ ! मैं तुममें से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूँ।”

5. शिक्षा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय—बौद्ध-काल में शिक्षा के मुख्य केन्द्र—मठ और विहार थे। इनमें छात्रावास सम्बद्ध थे। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा प्राप्त थी। कुछ मठों और विहारों ने विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित होकर पर्याप्त ख्याति अर्जित की; यथा :—

(i) नदिया विश्वविद्यालय—यह विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान में था। 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र हो गया।

(ii) वल्लभी विश्वविद्यालय—यह विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में वल्लभा नामक स्थान में था। यह 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा-केन्द्र था।

(iii) विक्रमशिला विश्वविद्यालय—यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यन्त सुन्दर पहाड़ी पर स्थित था। इसमें 108 भिक्षु-शिक्षक और 3,000 छात्र थे। इसे बल्लिवार खिलजी ने सन् 1203 ई० में नष्ट कर दिया।

(iv) तक्षशिला विश्वविद्यालय—यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा का और उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र था। यह 600 ई० पू० में अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। वैयाकरण पाणिनी, राजनीतिज्ञ चाणक्य, अर्थशास्त्री कौटिल्य, महात्मा बुद्ध के ध्येयगत चिकित्सक जीवक एवं सम्राट चन्द्रगुप्त और पुष्यमित्र इसी विश्वविद्यालय की उपज थे। पाँचवीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हूणों ने इसका सदैव के लिए विनाश कर दिया।

(v) नागार्जुन विश्वविद्यालय—यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में था। यह लगभग एक मील लम्बा और आधा मील चौड़ा था एवं चहारदीवारी से घिरा हुआ था। इसमें 8 बड़े सभा-भवन और 3,000 अध्ययन-कक्ष थे। इसका विशाल पुस्तकालय 9 मंजिल का था। इसमें 10 से अधिक सरोवर थे, जिनमें छात्र, जल-श्रीड़ा करते थे। जब यह अपनी पराकाष्ठा पर था, तब इसमें लगभग 1,500 शिक्षक एवं 10,000 छात्र थे और प्रतिदिन 100 भाषण होते थे। इसमें चीन, जावा, ब्रह्मा आदि मुद्गर देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। इस प्रकार, इसने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था। 1203 में बल्लिवार खिलजी ने प्राचीन भारत की सभ्यता के प्रतीक इस विश्वविद्यालय को धराशायी कर दिया।

## शिक्षा के अन्य क्षेत्र Other Spheres of Education

1. स्त्री-शिक्षा : Women's Education—बौद्धिक कान के अन्तिम चरण में लगभग 200 ई० पू० में स्त्री-शिक्षा की अवधारणा आरम्भ हो गई थी। महात्मा बुद्ध द्वारा इस शिक्षा को नया जीवन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य, आनन्द को प्रार्थना स्वीकार करके, स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। इसके अन्वय, स्त्री-शिक्षा का परोक्ष विकास हुआ। बौद्ध-तान्त्रिकों की सुशिक्षित स्त्रियों में यार्तन के नाम उल्लेखनीय है—बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध प्रचारिकाएँ, सुभा, अनुपमा व सुमेधा; लोचनो के रूप में काम्बिदास के बाई मायी जाने वाली विजयका, और तान में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजी जाने वाली सम्राट अशोक की हिन, नयमित्रा।

उपरिर्लखित उदाहरण इस बात का संकेत देते हैं कि स्त्रियों ने संघ में प्रवेश करते-उत्थन लोटि की शिक्षा प्राप्त की और कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से प्रतिद्वन्द्विता करके अपने समानता रखने का प्रमाण दिया। किन्तु, यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि स्त्री-शिक्षा को सामान्य रूप में प्रगति हुई। इसकी पुष्टि में चार कारण दिए जा सकते हैं : पहला, बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से निम्नतर है। अतः सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, संघों में स्त्रियों का प्रवेश भिक्षुओं की आज्ञा पर निर्भर था। क्योंकि भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया जाता था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दी। तीसरा, संघों में प्रवेश करने का अधिकार विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों एवं बालिकाओं को प्राप्त हुआ। अतः इन्हीं की शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, सामान्य स्त्रियों की शिक्षा को नहीं। चौथा, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली स्त्रियाँ—भिक्षुणियाँ कहलाती थीं और उनके लिए बलम मठों की स्थापना हो गई थी। पर उन्होंने भिक्षुओं के समान अपने मठों में स्त्रियों और बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं किया।

उपर्युक्त कारणों की ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बौद्ध धर्म ने दुर्बल और व्यावसायिक स्त्रियों की शिक्षा को, जिनकी संख्या प्रायः कम थी, प्रोत्साहन दिया, पर सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। डॉ० ए० एस्० अलेक्जर के अग्रलिखित वाक्य में ज़रूर मन्व है :—“स्त्री-शिक्षा को बौद्ध धर्म से किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त न हो सकी।”

“Female education could not get any impetus from Buddhism.”  
—Dr A. S. Altekar : op. cit., p. 223.

2. व्यावसायिक शिक्षा : Professional Education—बौद्ध-शिक्षा, धर्म-प्रधान थी। किन्तु, बौद्ध साहित्य में हमसे इस बात के परोक्ष प्रमाण मिलते हैं कि

भिक्षुओं और जनमाधारण को व्यावसायिक शिक्षा की अत्युत्तम सुविधाएँ प्राप्त थी। हम इस शिक्षा के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं, यथा :—

(i) हस्त-शिल्पों की शिक्षा : Education in Handicrafts—“महावाग” (Mahavagga) में हमें एक स्थान पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि बौद्ध-काल में भिक्षुओं को अपने मठों में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उदाहरणार्थ, उनको मूत कातने, कपड़ा बुनने और वस्त्र सीने की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे वस्त्र-सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति कर सकें।

(ii) लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा : Education in Useful Occupations—बौद्ध धर्म के अनुयायियों और जनमाधारण के लिए अनेक लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा को सुन्दर व्यवस्था थी, ताकि वे अपनी जीविका का सरलता से उपार्जन कर सकें। इस प्रकार के कुछ व्यवसाय थे—कृषि, वाणिज्य, लेखन-कला, पशु-पालन और हिसाब-किताब।

(iii) भवननिर्माण-कला, मूर्तिकला व चित्रकला की शिक्षा : Education in Architecture, Sculpture & Painting—बौद्ध-काल में भवननिर्माण-कला की विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध होने के कारण इस कला का आश्चर्यजनक विकास हुआ। उस काल के बौद्ध विहार और स्तूप एवं नागन्द और विभ्रमशिला की विशाल इमारतें—भवननिर्माण-कला की मजीब प्रमाण हैं। इस कला के साथ-साथ मूर्तिकला और चित्रकला की भी, शिक्षा की सुविधाओं के कारण, असाधारण प्रगति हुई। अजन्ता और अलोरा के भित्ति-चित्र, मूर्तिकला और चित्रकला इस प्रगति के आज भी साक्षी हैं।

(iv) प्राविधिक व वैज्ञानिक शिक्षा : Technical & Scientific Education—हमें ‘मिलिन्द पाण्हा’ (Milinda Panha) में बौद्ध-काल में प्रचलित 19 ‘सिप्पाओ’ अर्थात् ‘शिल्पो’ (Sippas or Shilps) का वर्णन मिलता है। इनका सम्बन्ध प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा में था। इनमें से अग्रलिखित 10 की शिक्षा, लक्षशिला में प्रदान की जाती थी—आखेट, चिकित्सा, घनुविद्या, इन्द्र-जाल (Magic Charm), हस्ति-ज्ञान (Elephant Lore), भविष्य-कथन, गौरीरिक्त लक्षणों का अर्थ, मृत व्यक्तियों को जीवित करने का मंत्र, सब पशुओं की बोनियाँ समझने का ज्ञान, और इन्द्रिय-सम्बन्धी मंत्र जादू पर नियंत्रण करने की कला।

इस प्रकार, जैसा कि डा० आर० के० मुकुर्जी ने लिखा है :—“सिप्पाओं के ज्ञान अर्थात् प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा की माँग, सामान्य शिक्षा या धार्मिक अध्ययन को माँग से कम नहीं थी।”

(v) चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा : Medical Education—बौद्ध-काल में चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस शिक्षा का मुख्य केन्द्र—लक्षशिला विश्वविद्यालय था और इसकी अवधि 7 वर्ष की थी। जीवरु, चरक, पञ्चतन्त्र आदि महान् आगुर्वेदाचार्य, बौद्ध युग की ही देन हैं।

## शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

### Chief Features or Characteristics of Education

बौद्ध धर्म के आदर्श, उद्देश्य और निष्पत्ति—वैदिक धर्म से बहुत-बहुत भिन्न थे। जब बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक विनिष्ट शिक्षा-प्रणाली का सम्बन्ध किया गया। तब इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का विवरण निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत उपस्थित कर रहे हैं; यथा :—

1. पब्वज्जा संस्कार : Pabbajja Ceremony—‘पब्वज्जा’ का शाब्दिक अर्थ है ‘आपस’ जाना’ (Going Out)। इस संस्कार का अभिप्राय यह था कि बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके, संघ में प्रवेश करता था। इसमें स्पष्ट हो जाना है कि इस संस्कार का सम्बन्ध केवल उन व्यक्तियों से था, जिनके जीवन का उद्देश्य—सौख्य-निवृत्ति बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले सम्पन्न नहीं हो सकता था।

‘विनय पिटक’ (Vinaya Pitaka) में ‘पब्वज्जा संस्कार’ का वर्णन इस प्रकार किया गया है :—“बालक अपने गिर के बाल मुँड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों की अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उसके सामने पायली मार कर भूमि पर बैठ जाता था। तदुपरान्त, मठ का मुख्य वर्य भिक्षु उसमें तीन बार यह श्राव्य लेने को कहता था :—“बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि”।

जब बालक यह जपन से होता था, तब भिक्षु उसको अग्रांकित 10 आदेश देता था :—1. योग्य मंत्र करना, 2. जीव नष्टा मत करना, 3. असत्य भाषण मत करना, 4. अशुद्ध आचरण मत करना, 5. वर्जित समय पर आहार मत करना, 6. मादक पदार्थों का प्रयोग मत करना, 7. भुङ्गार की वस्तुओं का प्रयोग मत करना, 8. विना शिल्प, कृषि वस्तु को ग्रहण मत करना, 9. मोना, चाँदी और बहुमुल्य वस्तुओं का संग्रह मत करना, 10. गृह्य, मंगील, समाधि आदि के पास जाने का सम्पर्क मत करना।

इस आदेशों के पर्याय् शब्द “नवजिण्य”, “शमण” या “सामनेर” (Novice or Samanera) कहा जाता था और अपने आरा तुने जाने वाले भिक्षु से 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करता था।

2. उपसम्पदा संस्कार : Upasampada Ceremony—नवजिण्य के रूप में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पर्याय् शब्द के लिए मठ की छोड़ना अनिवार्य था। यह ही “उपसम्पदा संस्कार” सम्भारित करते पूर्व भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था और ही अन्य ही स्थिति सम्पन्न हो सकता था।

“उपसम्पदा संस्कार”—ही संस्कार के रूप में ही 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। इनके परजिण्य का आवाधे को होता था। यह अन्य भिक्षुओं की मय-



शिष्य का परिचय देता था। तत्पश्चात्, भिक्षु—नवशिष्य से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। उसके उत्तरों को सुनने के बाद वे बहुमत से यह निर्णय करते थे कि नव-शिष्य को “उपसम्पदा” ग्रहण करने का अधिकार है या नहीं। इस प्रकार का निर्णय यह सिद्ध करता है कि “उपसम्पदा संस्कार” में जनतन्त्रीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था।

यदि निर्णय—नवशिष्य के पक्ष में होता था, तो उसे भिक्षु के रूप में सघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती थी। उस अवसर पर उसे सघ के अग्रांकित 8 नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता था।—1. वृक्ष के नीचे वाम करना। 2. साधारण वस्त्र धारण करना। 3. सात्विक भोजन का प्रयोग करना। 4. भोजन के लिए भिक्षा मांगना। 5. औषधि के रूप में गौ-मूत्र का सेवन करना। 6. चोरी और जीव-हत्या मत करना। 7. अलौकिक शक्तियों का दावा मत करना। 8. स्त्री से यौन-सम्बन्ध स्थापित मत करना।

शिष्यो —बालकों और पुरुषों के समान बालिकाओं और स्त्रियों को भी “पब्बज्जा” और “उपसम्पदा” का अधिकार प्राप्त था।

3 विद्यार्थित्व : Studentship—बौद्ध-शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले हुए थे। केवल चाइलों को इस शिक्षा से वंचित रखा गया था। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दलियों और मछली पकड़ने वालों के पुत्र थे। इनमें अधिकांश मर्यादा—ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के छात्रों की थी।

4. विद्यार्थियों का चुनाव Selection of Students—सिद्धान्त रूप में, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त था। किन्तु, अग्रांकित 10 वर्गों के किसी व्यक्ति का विद्यार्थित्व के लिए चुनाव नहीं किया जाता था :—  
1 जो नपुंसक हो। 2 जो दाम या ऋणी हो। 3 जो राजा की नौकरी में हो। 4. जो डाकू घोषित किया गया हो। 5. जो कारावास से भाग आया हो। 6 जिसका कोई अंग भंग हो। 7. जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो। 8. जिसको राज्य से कोई दंड मिला हो। 9 जिसने अपने माता-पिता की आज्ञा प्राप्त न की हो। 10 जिसको क्षय, कोढ़, खुजली आदि कोई छून का रोग हो।

5 शिक्षा आरम्भ करने की आयु Age at the Commencement of Education—इ० ए० एस० अल्तेकर के अनुसार—शिक्षा आरम्भ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष की थी। यह आयु उन्हीं बालकों के लिए निर्धारित की गई थी, जो सघ में प्रवेश करने का निश्चय कर लेते थे। सघ में प्रवेश करने वाला बालक उसके किसी भिक्षु को अपने शिक्षक के रूप में चुनता था।

6. अध्ययन की अवधि Period of Study—“पब्बज्जा” की अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की और “उपसम्पदा” की 10 वर्ष की थी। “पब्बज्जा संस्कार” 8 वर्ष की आयु में होता था। इस प्रकार, शिक्षा की पूर्ण अवधि 30 वर्ष की थी।

## शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

### Chief Features or Characteristics of Education

बौद्ध धर्म के आरम्भ, उद्देश्य और निष्ठान्त—बौद्ध धर्म से बहुत-कुछ शिक्षा में है। अतः बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा-प्रणाली का व्यवस्थापन किया गया। हम इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का विवरण निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत उपस्थित कर रहे हैं; यथा :—

1. पबबज्जा संस्कार : Pabbajja Ceremony—‘पबबज्जा’ का शाब्दिक अर्थ है ‘जाकर जाना’ (Going Out)। इन संस्कार का अभिप्राय यह था कि वास्तव अपने परिवार और पूर्व नियति का परित्याग करते, संघ में प्रवेश करता था। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार का सम्बन्ध केवल उन व्यक्तियों से था, जिनके जीवन का उद्देश्य—सौदुर्भिक्ष बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले सम्पन्न नहीं हो सकता था।

‘विनय पिटक’ (Vinaya Pitaka) में ‘पबबज्जा संस्कार’ का वर्णन इस प्रकार किया गया है :—“वास्तव अपने सिर के बाल मुँड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उसके सामने पावनवी मार कर भूमि पर बैठ जाता था। तदुपरान्त, मठ का मुखेय यथा भिक्षु उनमें तीन बार यह शपथ लेने को कहता था :—“बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघशरणं गच्छामि”।

यस वास्तव यह शपथ है किना था, तब भिक्षु उनको अर्थात् 10 आदेश देता था :—1. सोयी मत करना, 2. सीढ़ी चढ़ना मत करना, 3. अनृत्य भाषण मत करना, 4. अशुद्ध आचरण मत करना, 5. वसिष्ठ समय पर आहार मत करना, 6. मारक वस्तुओं का प्रयोग मत करना, 7. शृंगार की वस्तुओं का प्रयोग मत करना, 8. जिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण मत करना, 9. सोना, चाँदी और बहुमूल्य वस्तुओं का धन मत लेना, 10. नृत्य, संगीत, समाधि आदि के पास जाने का प्रयत्न मत करना।

इन आदेशों के पश्चात् वास्तव “नसजिण्य”, “अमण” या “सामनेर” (Nasajjina or Samanera) कहा जाता था और अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु से 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करता था।

2. उपसम्पदा संस्कार : Upasampada Ceremony—नसजिण्य के रूप में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् छात्र के लिए मठ को छोड़ना अनिवार्य था। पर 12 “उपसम्पदा संस्कार” सम्पादित करने पूर्व भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था और विद्वत्त्व का स्वरूप ग्रहण कर सकता था।

“उपसम्पदा संस्कार”—सौदुर्भिक्ष के रूप में हम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में किया था। इनके परमिषा का आचार्य की होता था। यह अन्य भिक्षुओं की मक-

(iv) निशाटन—छात्रों को प्रातःकाल निशाटन के लिए जाना पड़ता था। वे वैदिक युग के ग्रहचारियों के समान बोलकर नहीं, बल्कि मौन रूप में ही निशा की याचना कर सकते थे। वे उसी ही निशा माँग सकते थे, तबतभी उनके लिए आवश्यक थी।

(v) अनुशासन—छात्र-अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता था। छात्रों को फूल-पत्तियाँ तोड़ने, मम्यति रखने, सार्वजनिक स्थानों में तमाचे देखने, हानिग्रह मेलों में भाग लेने, शरीर को अलंकृत करने, गाली-भाली और मगड़ा करने का पूर्ण निषेध था। जो छात्र निषिद्ध कार्यों को करते थे, उनको दण्ड दिया जाता था। डा० आर० के मुकर्जी ने लिखा है कि एक बार एक संघ के सब सदस्यों को अनुशासनहीनता के अपराध के कारण सुष से निकाल दिया गया।

(11) गुरु-शिष्य सम्बन्ध : Teacher-Pupil Relationship—बौद्ध काल में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध वैदिक काल की ही भाँति पवित्र और स्नेहपूर्ण था। इस सम्बन्ध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे।

छात्र अपने शिक्षक से पहले उठकर उसके लिए दाँतों और मुँह धोने के लिए जल लाकर रख देता था। वह अपने शिक्षक के बैठने के स्थान को साफ़ करता था। जब शिक्षक आता था, तब वह उसे कोई पेय पदार्थ देता था। वह शिक्षक के बर्तनों को साफ़ करता था और उनके साथ निशाटन के लिए जाता था। वह शिक्षक से पहले नोटकर, उनके भोजन की व्यवस्था करता था। यदि शिक्षक बीमार हो जाता था, तो वह उनकी सेवा में उपस्थित रहता था।

केवल छात्र के ही शिक्षक के प्रति कर्तव्य नहीं थे, बल्कि शिक्षक के भी छात्र के प्रति थे। शिक्षक का संबंधित कर्तव्य यह था कि वह प्रत्येक सम्भव विधि का प्रयोग करके, छात्र का मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास करे। इसके अतिरिक्त, वह छात्र के भोजन, वस्त्र, निशा-मात्र, रहन-सहन आदि की व्यवस्था करता था। छात्र के अस्वस्थ हो जाने पर, वह उसकी सेवा करता था और उसके लिए औषधि का प्रबन्ध करता था।

इस प्रकार, छात्र और शिक्षक में एक-दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और विश्वास की भावनाएँ निहित थीं। डा० ए० एस० अल्तेकर के शब्दों में :—“छात्र और उसके शिक्षक के सम्बन्ध पुत्र और पिता के समान थे। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम के द्वारा एक-दूसरे से आबद्ध थे।”

“The relations between the novice and his teacher were filial in character; they were united together by mutual reverence, confidence, and affection”—Dr. A S Altekar : *op. cit.*, pp. 61-62.

(12) खेल-कूद व शारीरिक व्यायाम : Games, Sports & Physical Exercise—बौद्ध काल में केवल छात्रों के मानसिक और नैतिक विकास को ही

7. अध्ययन के विषय : Subjects of Study—अध्ययन के विषयों में डॉ० ए० एन० प्रसेनकर ने लिखा है :—यद्यपि मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा केवल प्रायः ब्राह्मणिक और संन्यासिक की गई थी, तथापि अध्ययन के विषयों का स्वरूप न तो पूर्णतया धार्मिक था और न पूर्णतया लौकिक । शिक्षा में लोक-रसों की दृष्टान्ता अवश्य थी, पर हिन्दू और जैन धर्मों के अध्ययन के प्रति भी सर्वांगीय ध्यान दिया गया था । शिक्षा केवल धर्म, दर्शन और नैतिकशास्त्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सम्पूर्ण साहित्य, व्याकरण-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा से जाती थी, चाहे छात्र—नागरिकों के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बनकर उनकी सेवा कर सकें ।

8. शिक्षा की पद्धति : Method of Education—बौद्धों ने ब्राह्मणों की अतिरिक्त शिक्षा-पद्धति का अनुकरण न करके, सामूहिक शिक्षा-पद्धति का प्रयोग किया । शिक्षा-केंद्रों में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा छात्रों को सामूहिक रूप में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी ।

9. शिक्षण की विधि : Method of Teaching—शिक्षण-विधि प्रायः सीधीरूप से । इसके सामान्य अंग थे—भाषण, प्रवचन और प्रश्नोत्तर । शिक्षण-विधि से एक विशेषता यह थी कि उसमें वैज्ञानिक, प्रकृति-निरीक्षण और विशेषज्ञों के व्याख्यानों को महत्त्व दिया जाता था । एक अनोखी विशेषता को मन्थार मिरडल ने इन शब्दों में वर्णित किया है :—“सांस्कृतिक विवादों को प्रोत्साहित किया जाता था । इस प्रकार की विद्वत्-सभाएँ—बौद्ध उच्च शिक्षा की एक अनोखी विशेषता थी ।”

“Scholastic debates were encouraged. Such learned assemblies were a novel feature of Buddhist higher education.”—Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Volume III, p. 1629.

10. छात्र-जीवन सम्बन्धी नियम : Rules Governing Student Life—छात्रों के जीवन के सम्बन्ध में अनेक नियम थे, जिनका उनको अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता था; यथा—

(i) भोजन—छात्रों का भोजन अत्यन्त साधारण था । वे दिन में केवल तीन बार भोजन कर सकते थे । वे और उनके विद्यार्थी अपने रात्रि-भोजन के लिए दान्य वहीन हो निर्बन्धित रहते थे ।

(ii) वस्त्र—छात्रों को हम और सामान्य जनता से भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनने से अज्ञेय था । वे साधारणतः तीन वस्त्र धारण करते थे, जिनको समग्र रूप से “तीनवस्त्र” (Ticavata) कहा जाता था ।

(iii) स्नान—छात्रों को गर्मियों में स्नान करने समय कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे—जल में पैर न डराना, एक-दूसरे पर पानी न फेंकना और अपने शरीर को किसी वस्तु या गर्मोत्तर से स्नान करने वाले किसी छत्र के नीचे न आना ।

(iv) भिक्षाटन—छात्रों को प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। वे वैदिक युग के गृहचारियों के समान बोलकर नहीं, बल्कि मौन रूप में ही भिक्षा को याचना कर सकते थे। वे उतनी ही भिक्षा माँग सकते थे, जितनी उनके लिए आवश्यक थी।

(v) अनुशासन—छात्र-अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता था। छात्रों को फूल-पत्तियाँ तोड़ने, सम्पत्ति रखने, सार्वजनिक स्थानों में तमाचे देखने, हानिप्रद खेलों में भाग लेने, शरीर को अलंकृत करने, गाली-गलौज और भगड़ा करने का पूर्ण निषेध था। जो छात्र निषिद्ध कार्यों को करते थे, उनको दण्ड दिया जाता था। डा० आर० के मुकर्जी ने लिखा है कि एक बार एक सघ के सब सदस्यों को अनुशासनहीनता के अपराध के कारण सघ से निकाल दिया गया।

(11) गुरु-शिष्य सम्बन्ध : Teacher-Pupil Relationship—बौद्ध काल में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध वैदिक काल की ही भाँति पवित्र और स्नेहपूर्ण था। इस सम्बन्ध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे।

छात्र अपने शिक्षक में पहले उठकर उसके लिए दाँतों और मुँह धोने के लिए जल लाकर रख देता था। वह अपने शिक्षक के बैठने के स्थान को माफ करता था। जब शिक्षक आता था, तब वह उसे कोई पेय पदार्थ देता था। वह शिक्षक के बर्तनों को साफ करता था और उसके साथ भिक्षाटन के लिए जाता था। वह शिक्षक से पहले लौटकर, उसके भोजन की व्यवस्था करता था। यदि शिक्षक बीमार हो जाता था, तो वह उसकी सेवा में उपस्थित रहता था।

केवल छात्र के ही शिक्षक के प्रति कर्तव्य नहीं थे, बल्कि शिक्षक के भी छात्र के प्रति थे। शिक्षक का सर्वव्यापक कर्तव्य यह था कि वह प्रत्येक सम्भव विधि का प्रयोग करके, छात्र का मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास करे। इसके अतिरिक्त, वह छात्र के भोजन, वस्त्र, भिक्षा-पात्र, रहन-सहन आदि की व्यवस्था करता था। छात्र के अस्वस्थ हो जाने पर, वह उसकी सेवा करता था और उसके लिए औषधि का प्रवन्ध करता था।

इस प्रकार, छात्र और शिक्षक में एक-दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और विश्वास की भावनाएँ निहित थीं। डा० ए० एस० अल्तेकर के शब्दों में :—“छात्र और उसके शिक्षक के सम्बन्ध पुत्र और पिता के समान थे। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम के द्वारा एक-दूसरे से आबद्ध थे।”

“The relations between the novice and his teacher were filial in character, they were united together by mutual reverence, confidence, and affection”—Dr. A. S. Altekar : *op. cit.*, pp. 61-62.

(12) खेल-कूद व शारीरिक व्यायाम : Games, Sports & Physical Exercise—बौद्ध काल में केवल छात्रों के मानसिक और नैतिक विकास की ही

4. मागीर शिक्षा और उच्चरी नगरपालिका

हो, परन्तु उच्चरी नगरपालिका को भी महत्त्व दिया जाता था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, स्वेच्छ प्रसार के क्षेत्र-सूत्र और मागीरिक व्यापक निर्धारित थे। "चल्लारंग" (Challaranga) में हमें इसी एक विस्तृत सूची मिलती है; यथा :—  
कुम्हरी पढ़ना, मुक्तिपत्रों को पढ़ना, भूमि योजना, और चलाना, कुम्हरी बचाना, रवों का रोग करना, इत्यादि। आई-सिंग (I-Tsing) ने नियमित रूप में दृष्टान्त देने का उल्लेख किया है।

(13) सामान्य विद्यालय : Ordinary Schools—भारत में सामान्य विद्यालयों की प्रणाली स्थापित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को प्राप्त है। इसका कारण यह है कि बौद्ध मठ, धार्मिक शिक्षा के अनिवार्य सामान्य शिक्षा के भी केन्द्र थे। धार्मिक घर-घर अपने माना-विद्या के साथ रह कर इन शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। इन प्रकार, ये मठ बहुत कुछ सामान्य विद्यालयों की भांति थे। इन मठों में प्रसार मिशन ने किया है :—“मठ-विद्यालय अधिकतर सामान्य विद्यालयों की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि धार्मिक अपने परिवारों के साथ रह कर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।”

(14) लोकनाटकों को प्रोत्साहन Impetus to Vernaculars—महात्मा बुद्ध के शिष्यानुसार, भिक्षुओं को उच्चरी स्वयं ही भाषाओं में शिक्षा दी जानी थी। इसका परिणाम यथावे हुए, आ० आर० के० मुक्तियों ने किया है :—“बौद्ध धर्म ने देश की लोकभाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और बौद्ध शिक्षा-संस्थाओं में संस्कृत के प्रसार लोकभाषाओं में शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया।”

(15) सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा : Popular Elementary Education—बौद्ध शिक्षा प्रारम्भ में धार्मिक थी और उच्चरी धार्मिकों तक सीमित थी, जो बौद्ध धर्म की प्रतीक के रूप में, भिक्षु बनते थे। किन्तु, जैसा कि आ० ए० एम० प्रोफेसर का विश्वास है, बौद्ध धर्म की जनप्रिय प्रवृत्ति के लिए बौद्धों ने मठों में सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य लगभग पच्चीस शताब्दी के आरम्भ में शुरू कर दिया। इन विचार के समर्थन में आ० एम० के० केरी ने किया है :—  
“बौद्ध मठों ने परोक्ष सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की।”

“The Buddhist monasteries came to supply a good deal of popular elementary education.”—Dr. F. E. Keay : *op. cit.*, p. 106.

(16) शिक्षा का जनतन्त्र आधार : Democratic Basis of Education—बौद्धों ने शिक्षा को जनतन्त्र आधार प्रदान करके, धार्मिकों के अनिवार्य धार्मिकों के साथ ही लोक धार्मिकों को शिक्षा के समान प्रसार प्रदान किया। किन्तु इन प्रकार कार्य की सफलता के लिए, आ० आर० के० मुक्तियों ने किया है :—  
“बौद्ध शिक्षा-संस्थाओं में विभिन्न वर्गों, विभिन्न धार्मिकों और विभिन्न परिस्थितियों के सब प्रकार शिक्षा शिक्षा के समान के पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं और का उत्पन्न करते हैं।”

(17) शिक्षा-संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन : Democratic Organization of Educational Institutions—बौद्ध शिक्षा-केन्द्रों का संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया गया था। डा० महेश चन्द्र सिंघल ने इसके स्वरूप का वर्णन अग्रलिखित वाक्यों में किया है :—“शिक्षा-केन्द्रों का संचालन जनतन्त्र के सिद्धान्तों पर होता था। एक विद्वान् भिक्षु—शिक्षा-केन्द्र का प्रधान संचालक नियुक्त किया जाता था। प्रधान की अधीनता में विभिन्न विषयों के महोपाध्याय होते थे। इन शिक्षा-केन्द्रों को तत्कालीन राजाओं तथा धनिकों से सहायता मिलती थी, किन्तु उनके प्रबंध में किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं था।”

(18) संगठित शिक्षा-संस्थाओं का उदय : Rise of Organized Educational Institutions—वैदिक काल में संगठित शिक्षा-संस्थाओं का अभाव था, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने का कार्य व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा किया जाता था। इसके विपरीत, बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने का कार्य संगठित शिक्षा-संस्थाओं द्वारा किया जाना आरम्भ हुआ। डा० ए० एस० अल्तेकर का मत है कि ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि बौद्ध मठ जिन्होंने इस कार्य का भार सम्हाला, वे पहले से ही एक धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में संगठित थे। अपने इस मत के आधार पर डा० अल्तेकर ने लिखा है :—“यह कहना उचित है कि संगठित सार्वजनिक शिक्षा-संस्थाओं का उदय, बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण हुआ।”

“The rise of organised public educational institutions may be justly attributed to the influence of Buddhism.”—Dr. A. S. Altekar : *op. cit.*, p 231.

### शिक्षा के प्रमुख दोष Chief Defects of Education

डा० एफ० ई० केई के अनुसार —“बौद्ध शिक्षा के आदर्शों और प्रयोग का ब्राह्मणीय शिक्षा के आदर्शों और प्रयोग से घनिष्ठ सम्बन्ध था।”

“The Buddhist educational ideals and practice were closely connected with those of Brahmanism.”—Dr. F. E. Keay : *op. cit.*, p. 109.

डा० केई के उक्त कथन को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा में कतिपय दोष थे, उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा में भी थे। हम इन दोषों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं; यथा :—

(1) बौद्ध धर्म का पतन : Decline of Buddhism—शिक्षा के केन्द्रों के रूप में मठों और विहारों का जनतंत्रीय आधार पर संगठन किया गया था। पर उनके संगठन में कुछ समय के उपरान्त निधिसत्ता आ गई। फलस्वरूप, पृथक् मठों में रहते हुए भी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का सम्पर्क आरम्भ हो गया। इस सम्पर्क





(6) कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश : *Infusion of Puritanical Ideas*—बौद्ध-शिक्षा पर धर्म की इतनी गहरी छाप थी कि इस शिक्षा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति-धर्म की सीमा में बाहर किसी बात की कल्पना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार, बौद्धों ने अपनी शिक्षा द्वारा जनसाधारण के मस्तिष्क में धार्मिक कट्टरता का समावेश कर दिया। डा० ए० एस० अल्तेकर ने ठीक ही लिखा है :—“जन-साधारण के मस्तिष्क में शर्न-शर्नः कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश करने के लिए बौद्ध लोग उत्तरदायी हैं।”

“Buddhists are to be attributed to the hold of the progressively puritanical notions over the popular mind.”—Dr. A. S. Altekar : *op. cit* , p. 247.

### आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन Contribution to Modern Indian Education

आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध-शिक्षा का योगदान अत्यन्त व्यापक और अभिनन्दनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य आयोजित किए गए हैं, जो बौद्ध-शिक्षा के अभिन्न अंग थे, यथा :—

1. सामान्य विद्यालयों का आयोजन।
2. सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन।
3. स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन।
4. खेल-कूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन।
5. प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन।
6. व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन।
7. लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन।
8. बहु-शिक्षक और सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन।
9. उच्च स्तर पर सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन।
10. लोकभाषाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाने का आयोजन।
11. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन।
12. शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम आयु, नियमों और परीक्षा का आयोजन।
13. माता-पिता और अभिभावकों के साथ रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन।
14. सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का आयोजन।



कुछ असमानताओं का होना स्वाभाविक था। मुख्य असमानताओं का विवरण दृष्टव्य है :—

1. वैदिक काल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत, बौद्ध काल में इस शिक्षा की व्यवस्था थी।
2. वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम, संस्कृत थी। इसके विपरीत, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम लोकभाषाएँ थी।
3. वैदिक काल में सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था। इसके विपरीत, बौद्ध काल में इन विद्यालयों का प्रचलन था।
4. वैदिक काल में शिक्षक केवल ब्राह्मण थे। इसके विपरीत, बौद्ध काल में विभिन्न जातियों के भिक्षु, शिक्षक थे।
5. वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप, व्यक्तिगत और पारिवारिक था। इसके विपरीत, बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप संस्थागत और सामूहिक था।
6. वैदिक काल में शिक्षा-संस्थाएँ, एकतन्त्रवाद के सिद्धान्त पर आधारित थी। इसके विपरीत, बौद्ध काल में शिक्षा-संस्थाएँ जनतन्त्रवाद के सिद्धान्त पर आधारित थी।
7. वैदिक काल में शिक्षा के केन्द्र, आश्रम और गुरुकुल थे। इसके विपरीत, बौद्ध काल में शिक्षा के केन्द्र, मठ, विहार और सुमगठित शिक्षा-संस्थाएँ थी।
8. वैदिक काल में केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसके विपरीत, बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लिए खुले हुए थे।
9. वैदिक काल में छात्रों का जीवन सादा और तपोमय था। इसके विपरीत, बौद्ध काल में छात्रों का जीवन सादा पर सुविधापूर्ण था, क्योंकि उनको जीवन-सम्वन्धी सब सुख और सुविधाएँ उपलब्ध थी।
10. वैदिक काल में गुरु की श्रेष्ठता और प्रधानता थी। इसके विपरीत, बौद्ध काल में गुरु का महत्त्व कम हो गया था, क्योंकि भिक्षु के रूप में मठ में प्रवेश करने के बाद छात्र पूर्ण स्वतन्त्रता और जीवन-सम्वन्धी सब अधिकारों का उपभोग करता था।

### आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्त्व

#### Acceptable Features for Modern Education

यद्यपि बौद्ध कालीन शिक्षा का भारत में नोप हो चुका है, तथापि इसके कुछ तत्त्व आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए ग्रहणीय हैं; यथा :—

(1) छात्रों का जीवन : Student's Life—बौद्ध काल में छात्रों के जीवन के दो मुख्य आदर्श थे—सादगी और श्रेष्ठ विचार। इन आदर्शों के बावजूद उनके लिए तपस्यापूर्ण जीवन के बजाय सुख-सुविधापूर्ण जीवन को अच्छा माना जाता था। इसीलिए, उनको भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा आदि की सुविधाएँ प्रदान की गई थीं।

आधुनिक भारत में इस मध्य मार्ग का अनुसरण सर्वथा उचित प्रतीत होता है। छात्रों को आधुनिक आविष्कारों से प्राप्त होने वाली सुख-सुविधाओं से वंचित न करके, सादगी और श्रेष्ठ विचारों के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनुप्राणित किया जा सकता है।

(2) छात्रों के अधिकार : Student's Rights—बौद्ध काल में जब छात्र को भिक्षु के रूप में मठ में प्रवेश करने की आज्ञा मिल जाती थी, तब उसे पूर्ण स्वतंत्रता और जीवन-सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त हो जाते थे।

आधुनिक भारतीय शिक्षा में इस तत्व का अत्यन्त महत्त्व है। छात्रों को अपनी शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्धित सभी कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता और अधिकार होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में इस तत्व की समाविष्ट करके अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। डा० महेश चन्द्र सिंघल के शब्दों में :—  
“आज भारतीय विश्वविद्यालयों के समस्त उपकुलपतियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों में, जिनमें प्रशासन भी शामिल है, किसी सीमा तक छात्रों को सम्मिलित किया जाय और उन्हें अधिकार प्रदान किए जायें।”

(3) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र : Centre of International Education—बौद्ध काल में भारत अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र था। सुदूर देशों से आने वाले छात्र, अव्ययन समाप्त करके अपने देशों को लौटते थे और वहाँ दया, प्रेम, हिंसा, बौद्ध धर्म, विश्व-बंधुत्व और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संदेश फैलाते थे।

हमारा देश आज भी प्रेम, शान्ति और अहिंसा के सिद्धान्तों का उपासक माना जाता है। अतः भारत को एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र बनाकर, इन सिद्धान्तों का विश्व में व्यापक प्रचार किया जा सकता है। डा० महेश चन्द्र सिंघल के अनुसार :—“शान्ति, अहिंसा, प्रेम और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का सिद्धान्त विश्व में फैलाने का कार्य भारतीय शिक्षा और विश्वविद्यालयों के द्वारा आज भी किया जा सकता है।”

(4) शिक्षा-संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन : Democratic Organization of Educational Institutions—बौद्ध काल में शिक्षा-संस्थाएँ बाह्य नियंत्रण से मुक्त थीं और उनका संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया गया था। आज हमारे देश में ऐसी सहस्रों शिक्षा-संस्थाएँ हैं, जो न तो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हैं और न

जिनका संगठन ही जनतंत्रीय है। इन संस्थाओं का स्वरूप बौद्ध काल की शिक्षा-संस्थाओं के अनुरूप बनाया जाना वांछनीय है।

इस स्वरूप को अंकित करते हुए, डा० आर० के० मुकर्जी ने लिखा है :—  
 "बौद्ध-प्रणाली में शिक्षा, विहार या भठ में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व-भावना और जनतन्त्र के लिए अवसर प्रदान होता था।"

"In the Buddhist system, education was imparted in the Vihara or monastery, giving scope to a collective life, spirit of brotherhood and democracy."—Dr. R. K. Mookerji : *op. cit.*, p. 396.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Describe the main characteristics of Buddhist education and trace out the chief contribution of Buddhist system of education to modern education.

बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा-प्रणाली की मुख्य देनों का उल्लेख कीजिए।

2. "Buddhist education shows several radical departures from Brahmanic." Discuss and point out the similarities between the two systems of education.

"बौद्ध शिक्षा अनेक महत्वपूर्ण बातों में ब्राह्मणीय शिक्षा से भिन्न है।" विवेचन कीजिए और शिक्षा की दोनों प्रणालियों में समानताएँ बताइए।

3. Write short notes on :—(a) Organization of Education, (b) Popular Elementary Education, (c) Features acceptable for modern Indian education.

टिप्पणियाँ लिखिए :—(अ) शिक्षा का संगठन, (ब) सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, (स) आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व।



## मुस्लिम-शिक्षा

### MUSLIM EDUCATION

(1200-1700)

"There cannot be said to have been any systematic and consistent educational policy among the Muslim kings before the Mughals."—T. N. Siqueira.

### विषय-प्रवेश

भारत की अतुलित सम्पत्ति से आकृष्ट होकर, मुसलमानों ने इस देश पर आठवीं शताब्दी में अपने आक्रमण आरम्भ कर दिए थे। किन्तु, उनके आक्रमणों का असली तूफान महमूद गज़नी के समय में आरम्भ हुआ, जिसने सन् 1,000 ई० से 1026 ई० तक भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए। उसके आक्रमणों का मुख्य ध्येय—इस देश की सम्पत्ति को लूट कर गज़नी को वैभवशाली बनाना था, न कि यहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना करना। अतः वह प्रत्येक आक्रमण के बाद लूट का माल लेकर स्वदेश को लौट जाता था।

महमूद गज़नी के बहुत समय पश्चात्, सन् 1192 ई० में मुहम्मद गोरी ने दिल्ली के अन्तिम राजपूत राजा, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके, भारत में मुस्लिम शासन का शिलान्यास किया। उसकी मृत्यु के उपरान्त, भारत पर क्रमशः गुलाम, गिलजी, तुग़लक़, सैयद, लोदी और मुग़ल वंश ने सन् 1757 ई० तक शासन किया। उस वर्ष क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजयी होकर, भारत में अंग्रेज़ी शासन का इतिहास आरम्भ किया।

इस प्रकार, लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। उन्होंने यहाँ एक नवीन शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात किया, जिसे "मध्यकालीन

मुस्लिम-शिक्षा-प्रणाली" कहा जा सकता है। इस प्रणाली के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए, डा० एफ० ई० केई ने लिखा है :—“मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी, जिसका भारत में प्रतिरोध किया गया, और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प सम्बन्ध रखकर, अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई।”

“Mohammedan education was a foreign system which was transplanted to India, and grew up in its new soil with very little connection with the Brahmanic education.”—Dr. F. F. Keay : *Indian Education in Ancient & Later Times*, p. 182.

### शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श Aims & Ideals of Education

मुसलमानों ने भारत पर अनेक शताब्दियों तक शासन किया, पर इस सम्पूर्ण अवधि में उनकी स्थिति अपनी ओर अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सैनिकों की-सी थी। ऐसी स्थिति में उनका ध्यान, शिक्षा पर पूर्ण रूप से केन्द्रित न होना, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर, जिन मुस्लिम शासकों का भारत पर आधिपत्य रहा, उनमें से कुछ उदार एवं सहिष्णु और कुछ अनुदार एवं असहिष्णु थे। उदाहरणार्थ, बल्लिहार, अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक और औरंगजेब इतने कट्टर और अनुदार थे कि उनका एकमात्र ध्येय—हिन्दुओं की शिक्षा और संस्कृति के केन्द्रों का विनाश करके, मुस्लिम शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना था। उनके विपरीत, अलतमश, मुहम्मद तुगलक, अकबर और शाहजहाँ के समान कुछ ऐसे मुस्लिम शासक भी थे, जिन्होंने शिक्षा के प्रति अगाध रुचि प्रकट की और उसे अपना संरक्षण प्रदान करके, उसके विस्तार में प्रशसनीय योग दिया।

शिक्षा के प्रति मुस्लिम शासकों के इन विरोधी दृष्टिकोणों के कारण सम्पूर्ण मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों में समरूपता नहीं मिलती है। परन्तु फिर भी, इस्लाम धर्म के सच्चे बन्दे होने के कारण सभी मुसलमान शासकों ने शिक्षा के कुछ ऐसे उद्देश्य और आदर्श निर्धारित किए, जिनमें निश्चित एकरूपता थी। हम इन उद्देश्यों और आदर्शों का संक्षिप्त विवरण लेखबद्ध कर रहे हैं; यथा :—

1. ज्ञान का प्रसार : Spread of Learning—मुस्लिम-शिक्षा का पहला उद्देश्य—इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना था। मुहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया था और कहा था कि ज्ञान ही निजान जर्घात् मुक्ति का साधन है। ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर ही व्यक्ति—धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य से अन्तर कर सकता है। अतः अपने अनुयायियों को मुहम्मद साहब का उपदेश था :—“दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम को स्याही शहीदों के रक्त से अधिक पवित्र है।”

मुहम्मद साहब के इस उपदेश को कार्य रूप में परिणत करना, मुस्लिम शासकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य माना। अतः उन्होंने मुसलमानों के मस्तिष्क को ज्ञान के आलोक में प्रकाशित करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया।

2. इस्लाम का प्रसार : Spread of Islam—मुस्लिम-शिक्षा का दूसरा उद्देश्य—इस्लाम का प्रसार करना था। मुसलमान अपने धर्म का विस्तार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। उनका विश्वास है कि काफ़िरों से इस्लाम धर्म को शर्माकार करवाने वाला मुसलमान, गाँधी होता है। इस विश्वास से प्रेरित होकर, मुसलमान शासकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग करके, भारत के कोने-कोने में इस्लाम धर्म की फैलाने का प्रयत्न किया।

उन विधियों में से एक विधि थी—शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को इस्लाम के सिद्धान्तों से अवगत कराना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के विभिन्न स्थानों में मकतबों और मदरसों की स्थापना की गई, जिनमें धार्मिक शिक्षा का स्थान सर्वोपरि था। मकतबों में क़ुरान की आयतों को कण्ठस्थ करना अनिवार्य था। मदरसों में धर्म, साहित्य और इतिहास की शिक्षा, धार्मिक सिद्धान्तों के आधार पर दी जाती थी। अतः जैसा कि डा० युसुफ़ हुसैन ने लिखा है :—“मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति—धर्म की पृष्ठभूमि में सोचते और विचार करते थे।”

3. मुस्लिम संस्कृति का प्रसार : Spread of Muslim Culture—मुस्लिम-शिक्षा का तीसरा उद्देश्य—मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना था। मुसलमान, भारत में दूसरे देशों ने आण थे। अतः उनकी ओर हिन्दुओं की संस्कृति में प्रत्येक दृष्टि से विषमता थी। इस विषमता का अन्त करने के लिए मुसलमानों ने शिक्षा को माध्यम बनाया। उनकी धारणा थी कि वे शिक्षा के द्वारा भारतवासियों को अपनी भाषा, प्रथाओं, आचार-विचार और सामाजिक नियमों से प्रभावित करके, अपने धर्म का अवलम्बी बना लेंगे।

4. धार्मिकता का समावेश : Infusion of Religiousness—मुस्लिम-शिक्षा का चौथा उद्देश्य—मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश करना था। सज्जुमदार, रायचौधरी व दत्त के शब्दों में :—“भारत में मुस्लिम राज्य, धर्म-राज्य था, जिसका अस्तित्व सिद्धान्त रूप में धर्म की आवश्यकताओं के कारण उचित था।”

‘The Muslim State in India was a theocracy, the existence of which was theoretically justified by the needs of religion.’—Majumdar, Raychaudhuri & Datta : *An Advanced History of India*, p. 391.

धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को समाविष्ट करना अनिवार्य था। यही कारण था कि मकतबों और मदरसों को साधारणतया मसजिदों से सम्बद्ध किया गया, जहाँ प्रतिदिन सामूहिक नमाज़ एक



सामान्य बात थी। मकतबों और मदरसों में शिक्षा-ग्रहण करने वाले छात्रों में इस धार्मिक वातावरण द्वारा धार्मिकता का समावेश किया जाता था। साथ ही, उनके अपने जीवन में धर्म के महत्त्व और गौरव से परिचित कराया जाता था।

5. विशिष्ट नैतिकता का समावेश : Infusion of Distinct Morality—मुस्लिम-शिक्षा का पाँचवाँ उद्देश्य—व्यक्तियों में इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा से पर्याप्त सहायता मिली। मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा मुसलमानों और हिन्दुओं—दोनों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। अतः शिक्षा के द्वारा उनमें मुस्लिम नैतिकता के उन आदर्शों का समावेश किया जाता था, जो हिन्दुओं के आदर्शों से पूर्णतया भिन्न थे। अनेक हिन्दुओं ने मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओं में ज्ञान का अर्जन करके, मुस्लिम संस्कृति और जीवन-विधि में अपना विश्वास प्रकट किया।

6. चरित्र का निर्माण : Formation of Character—मुस्लिम-शिक्षा का छठवाँ उद्देश्य—व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। मुहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर अतिशय बल दिया था। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति—जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। अतः मकतबों और मदरसों में छात्रों में अच्छी आदतों और उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षकों द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता था।

7. सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति : Achievement of Worldly Prosperity—मुस्लिम-शिक्षा का सातवाँ उद्देश्य—व्यक्तियों को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य बनाना था। इस्लाम धर्म में कर्मों के अनुसार व्यक्ति के पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। अतः यह धर्म पारलौकिक जीवन की चर्चा न करके, केवल दृहलौकिक जीवन का ही उल्लेख करता है। इसलिए मुसलमानों का विश्वास है कि उनका जीवन केवल सांसारिक ही है और इसमें सभी प्रकार के सुखों एवं ऐश्वर्यों का उपभोग करना चाहिए।

मुसलमानों की इस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिये मुस्लिम शासकों ने राज्य के निम्नतम पदों से लेकर उच्चतम पदों पर केवल सुशिक्षित व्यक्तियों को ही नियुक्त किया। इसकी पुष्टि करते हुए जाफ़र ने लिखा है—“ज्ञान का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और विद्वान् मनुष्यों के लिए सम्पूर्ण देश में प्रेम और सम्मान था। राज्य ने भी उनको प्रत्येक सम्भव विधि से प्रोत्साहित किया। न्यायाधीशों, कानून वेत्ताओं और धर्माधिकारियों का इसी वर्ग के मनुष्यों में से चुनाव किया जाता था।” अतः यह स्वाभाविक था कि इन पदों की प्राप्ति करने के लिए न केवल मुसलमान, वरन् हिन्दू भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्कटित हो गए।

8. मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना : Establishment of Muslim Supremacy—मुस्लिम-शिक्षा का आठवाँ और अन्तिम उद्देश्य—हिन्दुओं को मुस्लिम

मन्यता और संस्कृति से प्रभावित करके, भारत में मुस्लिम श्रेष्ठता को मुहृद आधार पर स्थापित करना था। मुस्लिम शासक इस तथ्य से नसीनानि अवगत थे। शिक्षा ही वह साधन था, जिसके द्वारा हिन्दुओं के विचारों और दृष्टिकोनों में आमूल परिवर्तन करके, उनको भारत में मुस्लिम शासन का हृद स्तम्भ बनाया जा सकता था। अतः शिक्षा के द्वारा हिन्दुओं के मस्तिष्क में मुस्लिम आदर्शों और सिद्धान्तों को समाविष्ट करने का पूरा-पूरा उद्योग किया गया। अकबर ने अपनी शिक्षा-नीति का निर्माण मुख्यतः इसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किया था।

मुगल सम्राटों ने पूर्व मुस्लिम शासकों की शिक्षा की कोई निश्चित नीति नहीं थी। वे अपनी व्यक्तिगत रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में समय-समय पर बड़ा-बहुत परिवर्तन करते रहे, पर अधिकांश मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्य उपरिअंकित ही थे।

## शिक्षा की व्यवस्था Organization of Education

सामान्य परिचय—भारत के मुस्लिम शासकों ने केन्द्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की, पर उर्दूनि माधारणतः शिक्षा में रुचि अवश्य थी। फलस्वरूप, लगभग सम्पूर्ण मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। उस काल में शिक्षा के केवल यही दो स्तर थे। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिये मुस्लिम शासकों और विद्या-प्रेमी, धनी व्यक्तियों द्वारा मकतबों और मदरसों की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं में शिक्षा का आयोजन मुख्यतः मुसलमानों के लिए ही था। डा० एफ० ई० कैट्टे के शब्दों में :—  
“कुछ अपवादों के अलावा मुस्लिम-शिक्षा जनता के उन अल्पसंख्यकों के लिये थी, जो मुस्लिम-धर्म को अंगीकार कर लेते थे।”

“Mohammedan education, with a few exceptions, was open to that minority of the population, which embraced the Mohammedan faith.”—Dr. F. E. Keay : *op. cit.*, p. 182.

कैट्टे के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम-शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दुओं का प्रवेश बर्जित नहीं था। परन्तु, इन संस्थाओं का धार्मिक कट्टरता का बनावरण, हिन्दू छात्रों के लिए अपना विषाक्त था कि वे इनमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा से पूर्णरूपेण लाभान्वित नहीं हो पाते थे। इस सामान्य परिचय के पश्चात्, हम उपरिअंकित शिक्षा के दोनों स्तरों का परिचय उपस्थित कर रहे हैं।

### 1. प्राथमिक शिक्षा : Primary Education

1. शिक्षा-संस्थाएँ—प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र—मकतब थे। इनके अनिश्चित, खानकाहों और दरगाहों (Khanqahs & Dargahs) में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा-संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा

प्राप्त कर सकते थे। कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अपने परों पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे।

2. प्रवेश—जिस प्रकार वैदिक युग में “उपनयन संस्कार” के पश्चात् और बौद्ध-युग में “पद्मज्जा संस्कार” के उपरान्त बालक की शिक्षा आरम्भ होती थी, उसी प्रकार मुस्लिम युग में “बिस्मिल्लाह-पानी” (Bismillah-Khani) की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा आरम्भ करता था। यह रस्म उन समय होती थी, जब बालक 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन का होता था। इस रस्म के समय बालक के लगभग सभी सम्बन्धी उपस्थित रहते थे और वह नए वस्त्र धारण करके मौनवी साहब के समक्ष उपस्थित होता था। मौनवी साहब कुरान मरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक से उनको दोहराते थे। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था, तो उसके द्वारा केवल “बिस्मिल्लाह” कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था।

इस प्रकार, बालक की प्राथमिक शिक्षा का श्रीगणेश होना था। बा० एक० ई० केई के अनुसार—“सभी मुसलमान बालकों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आशा की जाती थी, ताकि वे अपने प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों में सम्बन्धित कुरान की आयतों को स्मरण कर लें। किन्तु, इस बात को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सभी बालक इस शिक्षा को प्राप्त करते थे।”

3 पाठ्यक्रम—मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न था। माघारणत बालकों को पढ़ने, निगने और माघारण धर्मगणित की शिक्षा दी जाती थी। उनसे गद्यमें पहले वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उनके पश्चात् कुरान की कुछ आयतें कठस्थ कराई जाती थी। बालक के लिए उनका अर्थ समझना आवश्यक नहीं था, पर उनका शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था। उसके पश्चात् बालक को निगना सिखाया जाता था। जब बालक को पढ़ने और निगने का पर्याप्त ज्ञान हो जाता था, तब उसे व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। व्यावहारिक शिक्षा के अन्तर्गत बातचीत करने के ढंग, गुन्दर लेख, पत्र-लेखन और अर्जीनवीमी का प्रमुख स्थान था।

बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करने के लिये उसे शेरश सादी की प्रसिद्ध पुस्तकें, “बोस्ता” एवं “गुलिस्ती” पढ़ाई जाती थी और पैगम्बरों की कथाएँ एवं मुस्लिम फकीरों की कहानियाँ सुनाई जाती थी। इनके अतिरिक्त, उनको “लैला-मजनू”, “यूसुफ़-जुलेखा”, “मिकन्दरनामा” आदि काव्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता था।

यहाँ यह लिय देना अनुपपुक्त न होगा कि शाहबादों और सम्पन्न परिवारों के बालकों को उनके निवास-स्थानों पर व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी और उनका पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञेय प्रकार का होता था।

4. शिक्षण विधि—मकतबों में शिक्षण-विधि मौखिक और दृश्य थी। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद क्रममा और कुरान की कुछ

आयें कंठस्थ करना पड़ती थीं। कक्षा के सब बालक उच्च स्वर में एक साथ बोल कर पढ़ाई पढ़ते थे। मोनरी माइव नवा पाठ नहीं पढ़ते थे, जब बालकों को पिटला पाठ कंठस्थ हो जाता था। इस प्रकार, कंठस्थ करना, शिक्षण-विधि का मुख्य सूत्र था।

बालक द्वारा लिखने के लिये लकड़ी की तख्ती का प्रयोग किया जाता था। वह उस पर मोटे मरकट के कलम से लिखने का अभ्यास करता था। जब उसे लिखने का कुछ अभ्यास हो जाता था, तब वह पत्रि कलम से कागज पर लिखता था।

## 2. उच्च शिक्षा : Higher Education

1. शिक्षा-संस्थाएँ—उच्च शिक्षा की संस्थाएँ—मदरसे थे। बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदरसे में प्रवेश करता था। उसे प्रवेश के समय कोई संस्कार सम्पन्न नहीं करना पड़ता था। उच्च शिक्षा के केंद्र सम्पूर्ण देश में बिखरे हुए थे। इनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, जयपुर, म्यालकोट और मुंशिदाबाद के मदरसों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान अर्जित की थी। दकोनिए, बृक्षारा, अफ़ग़ानिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों के छात्र उनमें आन का अर्जन करने के लिए आते थे।

2. पाठ्यक्रम—उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की थी। उसका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था और निम्नलिखित दो भागों में विभाजित था :—

(i) धार्मिक शिक्षा—धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्र को कुरान की आयतें कंठस्थ करना पड़ती थीं और उनका सूक्ष्म एवं आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त, उसे सूफ़ी सिद्धान्तों एवं इस्लामी इतिहास, कानूनों, सिद्धान्तों और परम्पराओं का अध्ययन करना पड़ता था।

(ii) लौकिक शिक्षा—लौकिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्र को अप्रतिष्ठ विषयों की शिक्षा दी जाती थी :—अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीति-शास्त्र, दर्शन-शास्त्र, युवानां चिकित्सा आदि।

यही यह उल्लेखनीय है कि उद्युक्त सब विषयों की शिक्षा सब मदरसों में नहीं दी जाती थी। इसके विपरीत, प्रत्येक मदरसे में साधारणतः दो विषयों की शिक्षा दी जाती थी; जैसे—दिल्ली के मदरसे में कविता और संगीत की, म्यालकोट के मदरसे में गणित और ज्योतिष की एवं रामपुर के मदरसे में ज्योतिष और अर्थशास्त्र की।

3. शिक्षण विधि—मदरसों में शिक्षण-विधि मौखिक थी और छात्रों की शिक्षा देने के लिए अध्यापक, भाषण-विधि का प्रयोग करते थे। कक्षा-नायकीय पद्धति (Monitorial System) का पर्याप्त प्रचलन था। घमें, दर्शन, तर्कशास्त्र और

राजनीतिशास्त्र के शिक्षण में तर्क-विधि का मुख्य स्थान था। संगीत, हस्तकला, चित्र-कला और चिकित्साशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा में व्यावहारिक कार्य की समुचित व्यवस्था थी। छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उनकी कठिनाइयों का अध्यापकों के द्वारा निराकरण किया जाता था।

इस प्रकार, यद्यपि मदरसों में शिक्षण-विधि मुख्यतः मौखिक थी, तथापि पढ़ने और लिखने को उससे श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया जाता था। गन्नार मिरदल के शब्दों में :—“उच्च-शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ने और लिखने की मौखिक शिक्षण-विधियों में श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया जाता था।”

“Reading and writing took precedence over oral methods of instruction in institutions of higher education”—Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Vol. III, p. 1631.

4. शिक्षा का माध्यम—मुस्लिम शासन-काल में राज्य की भाषा, फ़ारसी थी। इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्यों को राजपद प्राप्त हो सकते थे। इस कार्य में सहायता देने के लिए फ़ारसी की शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। गन्नार मिरदल के अनुसार :—“उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम फ़ारसी भाषा थी।”

5. परीक्षाएँ—आधुनिक युग के समान मुस्लिम युग में छात्रों की परीक्षा को कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। शिक्षक प्रत्येक छात्र के ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन करके, उसे उच्च कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे देता था।

6. उपाधियाँ—सामान्य रूप से, शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण-पत्र या उपाधियाँ नहीं दी जाती थी। किन्तु, जो छात्र अपने अध्ययन के विषय में समाधारण योग्यता का प्रमाण देने थे, उनको उपाधियों से विभूषित किया जाता था। उदाहरणार्थ—साहित्य के छात्रों को “काबिब” की, धर्मशास्त्र के छात्रों को “आलिम” की और तर्कशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र के छात्रों को “फ़ाज़िब” की उपाधि से अलंकृत किया जाता था। छात्रों को उपाधियाँ प्रदान करने के समय नियमित रूप से समारोह का आयोजन किया जाता था।

## शिक्षा-संस्थाओं के प्रकार

### Types of Educational Institutions

मुस्लिम युग में अनेक प्रकार की शिक्षा-मंस्याएँ थीं, यथा :—

1. मक़तब Maktab—“मक़तब” शब्द की उत्पत्ति, अरबी के “कुतुब” (Kutub) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है—“उसने लिखा” (He wrote)। उर्दू भाषा में “कुतुब” शब्द—“किताब” का बहुवचन है। इस प्रकार, “मक़तब” यह स्थान है, जहाँ बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। मक़तब, प्राथमिक

शिक्षा के केन्द्र थे और साधारणतः किसी मसजिद से सम्बद्ध होते थे। कहीं-कहीं मौलवी लोग व्यक्तिगत रूप में अपने घरों पर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर मकतब चलाते थे। मकतबों में मुसलमान बालकों के साथ हिन्दू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। परन्तु, मकतबों की संख्या इतनी कम थी कि सब बालकों की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती थी।

डा० यूसुफ हुसेन के अनुसार :—“मकतब—एक शिक्षक वाली संस्थाएँ थीं। इनमें शिक्षण-कार्य प्रातःकाल से मध्याह्न तक और फिर अपराह्न में होता था। छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षकों के भरण-पोषण की व्यवस्था, धनी व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। राज्य को मकतबों से विशेष प्रयोजन नहीं था। जिन स्थानों में मदरसे नहीं थे, वहाँ के कुछ मकतबों में उच्च शिक्षा का भी प्रबन्ध था।”

2. खानकाह : *Khanqahs*—“खानकाह”, प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे। इनमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इनका व्यय—दान में प्राप्त होने वाले धन से चलता था।

3. दरगाहें : *Dargahs*—“खानकाहों” की भाँति “दरगाह” भी प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे। इनकी स्थिति बहुत-कुछ खानकाहों के समान थी। इनमें भी केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे।

4. कुरान-स्कूल : *Koran Schools*—इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इनका वर्णन करते हुए डी ला फ़ॉस (De La Fosse) ने “*Quinquennial Review of India, 1907-1912*” में लिखा है :—“कुरान-स्कूल साधारणतः किसी मसजिद से संलग्न होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था और फिर कुरान की आयतें कण्ठस्थ कराई जाती थीं। उनको लिखने की और गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी।”

5. फ़ारसी के स्कूल : *Persian Schools*—मुस्लिम शासन-काल में फ़ारसी, राजभाषा थी। अतः राजपद प्राप्त करने के इच्छुक हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए फ़ारसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था। इस माँग की पूर्ति करने के लिए फ़ारसी के स्कूलों की स्थापना की गई थी। इनमें छात्रों को सादी और हाफिज़ के काव्यों एवं मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफी ऊँचा था।

6. फ़ारसी व कुरान के स्कूल : *Persian-Koran Schools*—जैसा कि नाम से विदित है, ये स्कूल—फ़ारसी और कुरान स्कूलों के मिश्रित रूप थे। दूसरे शब्दों में, इन स्कूलों में फ़ारसी और कुरान—दोनों की शिक्षा दी जाती थी।

7. अरबी के स्कूल : *Arabic Schools*—इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य—अरबी भाषा और साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना था। अतः इनमें शिक्षा का स्तर अत्यन्त उच्च होना स्वाभाविक था।

8. मदरसे : Madrasahs—“मदरसा” शब्द की उत्पत्ति, अरबी भाषा के “दरस” (Dars) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है—“भाषण” (A Lecture)। इस प्रकार, “मदरसा” वह स्थान है, जहाँ शिक्षण के लिए भाषण या व्याख्यान-विधि का प्रयोग किया जाता है। मदरसे, उच्च शिक्षा के केन्द्र थे और सामान्यतया किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनकी स्थापना—राज्य और धनी विद्यार्थियों द्वारा की जाती थी। इनमें विभिन्न शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम, फारसी थी।

मदरसे, गांवाम शिक्षा-केन्द्र थे, पर अपने परिवारों के साथ रहने वाले छात्र भी वहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इतिहासकार इलियट (Elliot) ने एक छात्र के विषय में लिखा है, जो दो मील दूर से प्रतिदिन दिल्ली के मदरसे में अध्ययन करने जाया करता था। मदरसों के साथ छात्रावास संलग्न थे, जिनमें छात्रों के दैनिक भोजन की सुन्दर व्यवस्था थी। प्रत्येक छात्र को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धन मिलता था। योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी। शिक्षकों के लिए मदरसों में निवास और भोजन का प्रवन्ध था। इस प्रकार, छात्र और शिक्षक निरन्तर परिचित सम्पर्क में रहते थे।

## शिक्षा के अन्य क्षेत्र Other Spheres of Education

1. स्त्री-शिक्षा : Women's Education—डॉ० एफ० ई० केई के शब्दों में :—  
“पर्दा-प्रथा ने, जिसने छोटी बालिकाओं के अलावा सब मुसलमान स्त्रियों को एकान्त में धन्य रखा, उनकी शिक्षा को महान् कठिनाई का कारण बना दिया।”

“The purdah system, which shut up all Mohammedan women, except young girls, in seclusion, made their education a matter of great difficulty”—Dr F. E. Keay : *op cit.*, p. 80.

पर्दा-प्रथा के कारण केवल छोटी बालु की बालिकाएँ मकतबों में जाकर बालकों के साथ विद्या का अर्जन करती थी, पर उन्हें कुछ ही समय के बाद यह कार्य स्थगित करना पड़ता था। उनको उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि राज्य या समाज की ओर से उनके लिए पृथक् शिक्षा-संस्थाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। फलस्वरूप निम्न और निर्धन वर्गों की बालिकाएँ या तो ज्ञान-प्राप्ति के लाभ में वंचित रह जाती थी या उनका ज्ञान अत्यन्त अल्प पढ़ने और लिखने तक सीमित रह जाता था।

मध्य वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त थे। वे विद्या-ध्ययन के लिए सामान्य मकतबों में न जाकर, व्यक्तिगत रूप से स्त्रियों द्वारा अपने घरों पर चलाए जाने वाले मकतबों में जाकर विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इस सम्बन्ध में डॉ० युसुफ हुसैन ने लिखा है :—“निजी घरों में बालिकाओं

को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मकतब थे, जहाँ अधिक आयु की महिलाएँ उनको कुरान, गुलिस्ताँ, वोस्ताँ और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थीं।”

मालवा के शासक, गियासुद्दीन तुगलक ने, जिसने 1469 से 1500 तक शासन किया, सारंगपुर में सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए, एक मदरसे की स्थापना की। फ़रिश्ता (Ferishta) के अनुसार :—इस मदरसे में बालिकाओं को नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई, बड़ईगीरी, सुनारगीरी, लुहारगीरी, जूते बनाने, मखमल बनाने, युद्ध-कला, रणक्षेत्र-कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। उनकी शिक्षा का भार उनके अभिभावकों को बहन करना पड़ता था। अतः केवल धन-सम्पन्न व्यक्ति ही अपनी बालिकाओं को इस विद्यालय में अध्ययन के लिए भेज पाते थे।

राजघरानों और कुलीन परिवारों की बालिकाओं और स्त्रियों को उनके निवास-स्थानों पर ही व्यक्तिगत रूप में शिक्षा दी जाती थी। उनकी धर्म एवं साहित्य के अतिरिक्त, नृत्य, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने वाली अनेक मुस्लिम राजकुमारियों के नाम आज भी गर्व से स्मरण किये जाते हैं; जैसे—अल्तमश की पुत्री, रजिया सुल्ताना अपनी विद्वत्ता के लिए विख्यात थी। दक्षिण की बीरंगना, चाँद सुल्ताना को तुर्की, अरबी, फ़ारसी और मराठी भाषाओं पर समान अधिकार था। बाबर की पुत्री, गुलबदन बेगम की कृति, “हुमायूँ-नामा” इतिहास की अमूल्य निधि मानी जाती है। हुमायूँ की भतीजी, सलीमा सुल्ताना; जहाँगीर की पत्नी, नूरजहाँ और औरंगज़ेब की पुत्री, ज़ेबुन्निसा बेगम—सभी विदुषी महिलाएँ थीं।

उक्त महिलाओं के अतिरिक्त और भी अनेक सुशिक्षित स्त्रियाँ थीं। किन्तु, इनकी तुलना में उन सामान्य स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक थी, जो अशिक्षित थीं। वस्तुस्थिति यह थी कि जबकि राजघरानों और कुलीन परिवारों की स्त्रियों में शिक्षा का प्रचलन था, सामान्य स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। अतः वे शिक्षा से रंचमात्र भी लाभान्वित नहीं हुईं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए, डा० एफ० ई० केई ने लिखा है :—“मुस्लिम स्त्रियों के विशाल सामान्य समूह को पारिवारिक कर्तव्यों को करने के लिए घरेलू प्रशिक्षण के अलावा किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई।”

“The great mass of Mohammedan women received no education at all, except a domestic training in the performance of the duties of the household.”—Dr. F. E. Keay : *op., cit.* p. 81.

2. व्यावसायिक शिक्षा : Professional Education—दिल्ली के सुल्तानों और मुगल सम्राटों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति किसी-न-किसी रूप में कम या अधिक रुचि अवश्य थी। ऐसी परिस्थिति में व्यावसायिक शिक्षा का विकास होना स्वाभाविक था। हम इसके महत्वपूर्ण अंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं; यथा :—



(i) सैनिक शिक्षा : Military Education—भारत के मय मुस्लिम शासकों का लक्ष्य अपने राज्य को स्थायी और सुदृढ़ बनाना था । विदेशी और विधर्मी होने के कारण, वे भारतीयों को सदैव शत्रु की दृष्टि से देखते थे । उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और बनाए रखने के लिए मुस्लिम शासकों को समय-समय पर हिन्दू राजाओं से युद्ध करने पड़ते थे ।

ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम शासकों द्वारा सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाना आवश्यक था । यह शिक्षा साधारण सैनिकों और राजकुमारों के लिए भिन्न प्रकार की थी । सैनिकों को तीर, भाला एवं तलवार चलाने, दुर्ग का घेरा डालने और पोंडे एवं हाथी पर बैठकर युद्ध करने की शिक्षा दी जाती थी । मुगल काल में उनको गोली चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता था । राजकुमारों को इन सभी बातों के अतिरिक्त, सेना के संचालन, संगठन और नेतृत्व का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था । यहाँ यह बता देना अमंगल न होगा कि सैनिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण-महाशालें नहीं थी । यह शिक्षा, राज्य के अनुभवी सैनिकों द्वारा दी जाती थी ।

(ii) चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा : Medical Education—चिकित्सा-शास्त्र की उपयुक्त शिक्षा देने के लिए ससृत के ग्रन्थों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया, या इन ग्रन्थों के आधार पर फ़ारसी में पुस्तकों की रचना की गई । इस प्रकार की कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें थी :—“मदानुश-शिकाए-सिकन्दरी”, “दस्तूर-उल-अतिब्या” और “तुहफत-अल-मोमिन” ।

चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा, मदरसों में या विशिष्ट शिक्षा-संस्थाओं में दी जाती थी । आगरा में अकबर द्वारा स्थापित किए गए मदरसे और रामपुर की विशिष्ट शिक्षा-संस्था—चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी ।

(iii) हस्तकलाओं की शिक्षा : Education in Handicrafts—अधिकांश मुस्लिम शासक—ऐश्वर्य और विनाशिता का जीवन व्यतीत करते थे । अतः इस जीवन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित सभी हस्तकलाओं की आवश्यक जनक उत्पत्ति हुई । इस प्रकार की मुख्य कलाएँ थी :—कशीदाकारी; जरी, लकड़ी एवं हाथीदात का काम, दर्री, पर्दे, जूते, रेशम, मलमल एवं आभूषण बनाना, आदि ।

इन हस्तकलाओं की शिक्षा—कारखानों में दी जाती थी । मुहम्मद तुग़लक और फिरोज तुग़लक के शासन-काल में इन कारखानों का उल्लेख मिलता है । अकबर के समय में मय कारखाने—“दिवाने-मुयुतात” नामक सरकारी विभाग की अधीनता में थे । इन कारखानों के विषय में जाफ़र ने लिखा है :—“भारत में हजारों कारखाने थे, जिनमें लड़कों को बहुधा विशिष्ट कलाओं और दस्तकारियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय के शिल्पकार का शिष्य बना दिया जाता था ।”

“There were thousands of *Karkhanas* or workshops, & *varcin* boys were often apprenticed with the artisan to the trade .”

ving instructions in particular arts and crafts."—S. M. Jaffar : *Education in Muslim India*, pp. 12-13.

(iv) ललित कलाओं की शिक्षा : Education in Fine Arts—लगभग सभी मुस्लिम शासक, सौन्दर्य के उपासक थे और अपने महलों एवं दरबारों की शोभा में वृद्धि करने के लिए उत्कण्ठित रहते थे। फलस्वरूप, ललित कलाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ। इन कलाओं में अग्रांकित को उच्चतम स्थान प्राप्त था :—संगीत, चित्रकला और नृत्यकला। इन कलाओं का प्रशिक्षण—कारखानों में, वंशानुगत रूप में और व्यक्तिगत रूप में उस्तादों द्वारा दिया जाता था।

### शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

#### Chief Features or Characteristics of Education

भारत पर मुसलमानों के आक्रमणों और तदुपरान्त इस देश में मुस्लिम-शासन की स्थापना के कारण, यहाँ की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली जर्जर होकर अतीत के गर्त में विलीन होने लगी और उसके स्थान पर एक नवीन शिक्षा-प्रणाली का उद्भव हुआ। मुसलमानों की यह नवीन शिक्षा-प्रणाली इस देश में लगभग 600 वर्ष तक प्रचलित रही और मकतबों के रूप में इसके अवशेष आज भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। इस शिक्षा-प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं, जिन्होंने मयंकर विप्लवों और राजनीतिक संघर्षों के मध्य भी इसको जीवित रखा। हम इन विशेषताओं का निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत वर्णन कर रहे हैं; यथा :—

1. व्यावहारिक शिक्षा : Practical Education—मुस्लिम-शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ही नहीं, अपितु व्यावहारिक जीवन के लिए भी थी। परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास न करने के कारण मुसलमान—शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष-प्राप्ति का साधन नहीं मानते हैं। उनका विश्वास है कि जीवन केवल इसी संसार में है और इसलिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। अपने इस विचार से प्रेरित होकर, उन्होंने शिक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

इस दिशा में औरंगजेब के प्रयास प्रशंसनीय हैं। उसने अपने व्यक्तिगत शिक्षक, मुल्ला शाह सलेह की सार्वजनिक रूप में इसलिए तिन्दा की, क्योंकि उसने उसको व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। औरंगजेब ने राजकुमारों के लिए शाब्दिक और शास्त्रीय शिक्षा की अपेक्षा भूगोल, इतिहास, राजतन्त्र, सैन्य-संचालन और समीपवर्ती राज्यों की नापाओं की शिक्षा को अधिक उपयोगी बताया। अपनी इसी धारणा के कारण, उसने सामान्य बालकों के पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन करने की आज्ञा दी।

2. निःशुल्क शिक्षा : Free Education—मकतबों और मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इन शिक्षा-संस्थाओं के व्यय का सम्पूर्ण भार



"Teachers occupied a high position in society, and though their emoluments were small, they commanded universal respect and confidence."—S. M. Jaffar : *op. cit.*, p. 4.

6. गुरु-शिष्य सम्बन्ध : Teacher-Pupil Relationship—यद्यपि औरंगज़ेब ने भरे दरबार में अपने गुरु, मुल्ला शाह सलेह का अपमान और अनादर किया, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि गुरु-भक्ति के प्राचीन आदर्श का पूर्ण लोप हो गया था। अपने पिता को बन्दी बनाने वाले, अपने भाइयों की हत्या करने वाले, राज-सिंहासन पर अपना अवैध अधिकार स्थापित करने वाले और अपनी शक्ति एवं श्रेष्ठता के मद से उन्मत्त होने वाले औरंगज़ेब का अपने गुरु के प्रति दुर्व्यवहार कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके अभद्र व्यवहार को केवल अपवाद कहा जा सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से समाज में शिक्षक का सम्मान होता था और छात्र उसके प्रति विनम्र एवं भक्तिपूर्ण थे। वे गुरु की सेवा करना और उसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करना अपना परम पुनीत कर्तव्य समझते थे। उनका विश्वास था कि गुरु की कृपा से ही उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

शिक्षक भी छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण और पुत्रवत् व्यवहार करता था। जिन मदरसों से छात्रावास संलग्न थे, उनमें शिक्षक और छात्रों का निकट और निरन्तर सम्पर्क रहता था। शिक्षक पग-पग पर उनका पथ-प्रदर्शन करता था, उनके मस्तिष्क को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता था और प्रशंसा एवं निन्दा का प्रयोग करके उनमें अच्छी आदतों और अच्छे चरित्र का निर्माण करता था।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि गुरु-शिष्य के आदर्श सम्बन्ध की जो श्रेष्ठ परम्परा वैदिक काल में आरम्भ हुई थी, वह मुस्लिम काल में यथावत् बनी रही। डा० एफ़ ई० केई के शब्दों में :—“शिक्षक और छात्र का सम्बन्ध वैसा ही था, जैसा कि ब्राह्मणीय शिक्षा में था।”

“The relation between teacher and pupil was similar to that which existed in the case of Brahmanic education.”—Dr. F. E. Keay : *op. cit.*, p. 110.

7. शिक्षा का संरक्षण : Patronage of Education—यह तथ्य निर्विवाद है कि सम्पूर्ण मुस्लिम-काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। साथ ही, यह कथन भी विवादरहित है कि लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने मकतबों और मदरसों की स्थापना करके, शिक्षा के प्रति अपने प्रेम और उदारता का परिचय दिया।

उपयुक्त दोनों धारणाओं की पुष्टि में डा० एफ़० ई० केई का अयोजित मत उद्धृत करना असंगत न होगा :—“भारत के मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के प्रति सामान्यतः अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की और उनमें से अनेक ने अपने राज्य में विभिन्न स्थानों पर मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों का शिलान्यास किया। शासकों के

उदाहरण का उनके अनेक प्रभावशाली प्रजाजनों द्वारा अनुकरण किया गया। विद्वानों, कवियों और अन्य साहित्यिक मनुष्यों को राज्य या जमीनों के संरक्षण के कारण बहुधा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। छात्रों को बहुधा शिष्यवृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी।"

8. शिक्षा की अनिवार्यता : Indispensability of Education—मुसलमानों द्वारा शिक्षा को व्यक्ति के जीवन के लिए तीन मुख्य कारणों से अनिवार्य माना जाता है। पहला, कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है। दूसरा, मुसलमानों द्वारा मुहम्मद साहब के इस कथन में विश्वास किया जाता है :—"जो छात्र, ज्ञान की खोज करता है, उसे ईश्वर स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करता है।" तीसरा, इस्लाम धर्म में कहा गया है :—"जो मनुष्य, ज्ञान प्राप्त करता है, वह धार्मिक कार्य करता है, जो ज्ञान को बात करता है, वह ईश्वर की प्रशंसा करता है, जो ज्ञान को खोज करता है, वह ईश्वर की उपासना करता है।"

"He, who acquires knowledge, performs an act of piety; who speaks of it, praises the Lord; who seeks it, adores God."—Amir Ali : *Spirit of Islam*, p. 360.

इस प्रकार की धार्मिक पृष्ठभूमि में शिक्षा को व्यक्ति के लिए अनिवार्य समझा गया। यही कारण था कि सभी मुस्लिम शासकों और ज्ञान-प्रेमी व्यक्तियों ने मकतबों और मदरसों की स्थापना करके और उनमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके, जन-साधारण के लिए शिक्षा को अधिक-से-अधिक सुलभ बनाने का प्रयत्न किया।

9. सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि : Promotion of Cultural Unity—मुस्लिम शासन के जारम्भ में मकतबों और मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा केवल मुसलमानों तक ही सीमित थी और उनमें हिन्दुओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध था। सिकन्दर लोदी के समय से यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया था। फलस्वरूप, सभी जातियों के हिन्दू—मकतबों और मदरसों में प्रवेश करके, मुसलमानों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे थे।

इस प्रकार, मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओं ने सभी जातियों के हिन्दुओं और मुसलमानों में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित किया, जिसके दो सुन्दर परिणाम दृष्टि-गोचर हुए—जातीय बन्धनों की समाप्ति और सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि। डा० एफ० ई० केई के अनुसार :—"मुस्लिम-शिक्षा ने जाति के बन्धनों को तोड़ने में सहायता दी और भारत की सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि की।"

"Mohammedan education helped to break down caste barriers and promoted the cultural unity of India"—Dr F. E. Keay : *op. cit.*, p. 140.

10. भाषा व विज्ञानों को प्रोत्साहन Encouragement to Language & Sciences—मुस्लिम युग में फारसी भाषा और विज्ञानों का अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त

हुआ। इसका कारण यह था कि फ़ारसी सभी मुस्लिम शासकों की राजभाषा थी। अतः इस भाषा के विद्वानों की राजपदों के लिए बहुत माँग थी। इसी प्रकार, विज्ञान-वेत्ताओं की भी माँग थी।

उक्त दोनों मार्गों को पूर्ण करने के लिए, मुस्लिम युग में फ़ारसी भाषा और विज्ञानों की शिक्षा का प्रधान लक्ष्य निर्धारित किया गया। ग़ज़नार मिरडल का कथन है :—“क्योंकि पदाधिकारियों, प्रशासकों, शिल्पियों और इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों की बहुत माँग थी, इसलिए भाषा और विज्ञानों की शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया।”

**11. साहित्य व इतिहास का विकास : Development of Literature & History**—मुस्लिम युग में साहित्य और इतिहास का पर्याप्त विकास हुआ। अनेक मुस्लिम शासक, विद्या के प्रेमी और विद्वानों के संरक्षक थे। संरक्षण-प्राप्त विद्वानों का आर्थिक चिन्ता से मुक्त होना और इसके फलस्वरूप उनके द्वारा साहित्य-सृजन के प्रति ध्यान दिया जाना स्वाभाविक था। यही कारण था कि मुस्लिम युग में नीति, दर्शन आदि विषयों पर साहित्य का निर्माण हुआ और रामायण, महाभारत आदि हिन्दू ग्रन्थों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया।

भारत में क्रमवद्ध इतिहास का लेखन सर्वप्रथम मुस्लिम-काल में ही आरम्भ हुआ। इस काल से पूर्व हमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक वर्णन बहुत कम मिलता है। कल्हण की “राज-तरंगिणी” को अवश्य इतिहास की कोटि में स्थान दिया जाता है, पर इस प्रकार की किसी अन्य पुस्तक की रचना, मुसलमान शासकों के समय से पूर्व नहीं हुई। इन शासकों में से कुछ ने अपने संस्मरणों और आत्मकथाओं के रूप में इतिहास लिखे एवं अपने दरबारों में इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया। इन इतिहासकारों में ज़ियाउद्दीन बर्नी का “तारीख़े फ़िरोज़शाही”, अबुल फ़ज़ल का “अकबरनामा” और बदायूनी का “मुत्तख़व-उत-तवारीख़” इतिहास के बेजोड़ ग्रन्थ हैं।

**12. धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय : Synthesis of Religious & Secular Education**—मुस्लिम शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी—धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय। मकतबों में बालकों को क़ुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। साथ ही, उनको अंकगणित, वातचीत करने का ढंग, पत्र-लेखन-कला और अर्जोन्वीसी आदि जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। मदरसों में छात्रों की नियमित रूप से क़ुरान का अध्ययन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त, उनको भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार, शिक्षा के दोनों स्तरों पर धार्मिक और लौकिक विषयों का समावेश था।

## शिक्षा के मुख्य दोष Chief Defects of Education

टी० एन० सिक्वेरा का कथन है :—“भारत पर मुसलमानों की विजय इस्लामो शिक्षा के उस अपकारपूर्ण युग की समकालीन थी, जबकि विद्यालयों ने अपने व्यापक सांस्कृतिक आदर्शों को खो दिया था।”

“The Muslim conquest of India coincided with a dark age in Islamic education when the schools had lost their wider ideals of culture.”—T. N. Siqueira : *op cit.*, p. 9.

सिक्वेरा के इस कथन को ध्यान में रखते हुए, हम कह सकते हैं कि मुस्लिम-शिक्षा दोषमुक्त नहीं थी। हम उसके मुख्य दोषों की चर्चा निम्नांकित पंक्तियों में यथास्थान कर रहे हैं :—

1. शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल : Stress on Secular Aspect of Education—मुस्लिम-शिक्षा में धर्म का मूर्धन्य स्थान था। किन्तु, इस्लाम धर्म पार-लौकिक जीवन की अपेक्षा इहलौकिक जीवन को महत्त्व देता है। अतः मुस्लिम युग में शिक्षा के लौकिक पक्ष को प्रधानता प्रदान की गई और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यह स्वीकार किया गया—छात्रों को ज्ञान से सम्पन्न करके, समाज में सुयश और राज्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करना, ताकि वे सभी सामारिक सुखों और ऐश्वर्यों का उपभोग कर सकें। छात्र भी अपने समक्ष इसी उद्देश्य को रख कर, कठोर परिश्रम द्वारा ज्ञान का अर्जन करते थे और अपनी योग्यता में अधिक-से-अधिक वृद्धि करने के लिए प्रति-क्षण प्रयत्नशील रहते थे।

2. स्त्री-शिक्षा की उपेक्षा : Neglect of Women's Education—मुस्लिम-युग में पदों की प्रथा के कारण, स्त्री-शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। जनसाधारण की बालिकाएँ अपने मुहल्लों की मकतबों में बालकों के साथ थोड़ा-सा पढ़ना और लिखना सीख लेती थीं। इसके अतिरिक्त, उनकी शिक्षा के लिए राज्य या समाज की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं था। राजकुलों और धनी परिवारों की बालिकाओं और स्त्रियों को उनके घरों पर शिक्षा दी जाती थी। पर इनकी संख्या अत्यन्त अल्प थी।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि मुस्लिम काल में सामान्य रूप से स्त्रियों की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई। इसका परिणाम बताते हुए, टी० एन० सिक्वेरा ने लिखा है :—“स्त्रियों की शिक्षा पढ़ने और लिखने के न्यूनतम तत्त्वों की संकुचित स्थिति में पहुँच गई थी।”

“Education of women was reduced to the barest elements of reading and writing.”—T. N. Siqueira *op. cit.*, p 139.

3. प्रान्तीय भाषाओं की उपेक्षा Neglect of Vernaculars—मुस्लिम-शिक्षा-पद्धति में फारसी और उर्दू का शीर्षस्थ स्थान था। मकतबों में बालकों को

फारसी की वर्णमाला सिखायी जाती थी और कुरान की आयतें रवाई जाती थीं। मदरसों में उच्च शिक्षा का माध्यम—फारसी थी। फारसी सम्पूर्ण मुस्लिम काल में राजभाषा थी। राजपदों पर उन्हीं व्यक्तियों को आसीन किया जाता था, जिनको फारसी का पूर्ण ज्ञान और अरबी का पर्याप्त ज्ञान होता था। अतः इन पदों के लिए उच्छुक्र न केवल मुसलमानों को, बल्कि हिन्दुओं को भी फारसी और अरबी का अनिवार्य रूप से अध्ययन करना पड़ता था। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि प्रान्तीय भाषाओं के प्रति रचनात्मक भी ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप, उनका विकास अवकट हो गया।

अकबर ने अपनी हिन्दू-नीति के कारण इस बात की चेष्टा की कि विद्यालयों में फारसी के अनिश्चित हिन्दी को भी शिक्षा दी जाय। उसकी चेष्टा के परिणामस्वरूप हिन्दी को प्रोत्साहित तो अवश्य प्राप्त हुआ, पर उसकी प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। औरंगजेब ने प्रान्तीय भाषाओं, मुख्यतः उर्दू में शिक्षण और रचना को प्रोत्साहित किया, पर उसे अपने कार्य में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। यन्तुतः इन दोनों मुगल सम्राटों के प्रयासों का फारसी और अरबी की स्थिति पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ा। इन दोनों भाषाओं की प्रधानता पूर्ववत् बनी रही और प्रान्तीय भाषाओं की पहले के समान उपेक्षा की गई।

4. हिन्दुओं की शिक्षा की उपेक्षा : Neglect of Education of Hindus—आरम्भ में मुस्लिम-शिक्षा केवल उन असमस्यकों को ही उपलब्ध थी, जो इस्लाम धर्म के अनुगामी थे। मिकन्दर तोदी के शासन-काल में नकनवां और मदरसों के द्वारा हिन्दुओं के लिए भी खोल दिए गए थे, पर वहाँ उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। केवल अकबर के शासन-काल में हिन्दू बान्कों को मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओं में स्वतन्त्रतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जहाँ तक हिन्दू शिक्षा-व्यवस्था का सम्बन्ध था, उसकी अनेक मुसलमान शासकों ने नष्ट करने का भरमक प्रयत्न किया।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि लगभग सम्पूर्ण मुस्लिम-युग में हिन्दुओं की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ और मुस्लिम शासकों द्वारा उनको शिक्षा की उपेक्षा की गई। हिन्दुओं की शिक्षा में सम्मिलित उनकी नीति का वर्णन करते हुए, टी० एन० सिक्वेरा ने लिखा है:—“मुसलमान शासकों को अपनी हिन्दू प्रजा की शिक्षा के विषय में दो बातों में से एक का निश्चय करना पड़ा—हिन्दुओं की शिक्षा की उपेक्षा करना या उनके लिए पृथक् विद्यालयों की स्थापना करना। अधिकांश मुस्लिम शासकों ने उनकी शिक्षा की उपेक्षा की, उनकी शिक्षा-संस्थाओं को आर्थिक सहायता नहीं दी और उनके लिए नवीन विद्यालयों का निर्माण नहीं किया। अकबर के समान बहुत ही कम शासकों ने हिन्दुओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया।”

5. शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा : Neglect of Spiritual Aspect of Education—मुस्लिम-शिक्षा, धर्म-प्रधान थी। छात्रों को अपने सम्पूर्ण अध्ययन-काल



में कुरान शरीफ की नियमित रूप से शिक्षा दी जाती थी। किन्तु, इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य—उनमें धार्मिकता की जायना का समावेश करना था, न कि उनका आध्यात्मिक विकास करना।

इस प्रकार, मुस्लिम युग में शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की प्रायः पूर्ण उपेक्षा की गई। परिणामतः मुस्लिम-शिक्षा आध्यात्मिक उन्नति के उस शिखर से बहुत नीचे रह गई, जिस पर प्राचीन भारतीय शिक्षा पहुँच गई थी और जिसके कारण भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था।

**6. शिक्षा में स्थिरता का अभाव : Lack of Stability in Education—** इस्लाम-धर्म में अटिग आस्था रखने के कारण मुसलमान माता-पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। परन्तु, जैसा कि टी० एन० सिक्वेरा ने लिखा है :—“न तो माता-पिता ने और न शासकों ने अपने कर्तव्य का विधिपूर्वक पालन किया। एक शासक या राजकुमार, विद्यालयों की स्थापना करता था, और दूसरा यदि उनको नष्ट नहीं करता था, तो बन्द अवश्य कर देता था।”

सिक्वेरा के कथन से सिद्ध हो जाता है कि मुस्लिम शासकों की शिक्षा-सम्बन्धी नीति में स्थिरता और क्रमबद्धता का नितान्त अभाव था। यही कारण था कि यदि एक शासक के समय में शिक्षा पुण्डित होती थी, तो दूसरे शासक के समय में कुम्हला जाती थी। शिक्षा के इस अस्थिर स्वरूप का कारण बताते हुए, डा० एफ० ई० केई ने लिखा है :—“शिक्षा का अस्थिर और अनिश्चित स्वरूप मुख्यतः निरकुश शासन का परिणाम था।”

*“The fluctuating and uncertain character of education was very largely the result of despotic rule”—Dr. F. E. Keay : op. cit., p. 140.*

**7. शिक्षा में व्यापकता का अभाव : Lack of Universality in Education—** मुस्लिम-युग में शिक्षा को इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता था और उसे राज्य का सरक्षण भी प्राप्त था। फिर भी, वह व्यापक रूप धारण न कर सकी। इसके आधारभूत कारण पाँच थे; यथा—

पहला, मुस्लिम-शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों और बड़े कस्बों में की गई थी, जहाँ मुसलमानों की अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी। दूसरा, मुस्लिम शासकों की जनसाधारण की शिक्षा में लक्षमात्र भी रुचि नहीं थी। अतः नगरों और कस्बों से दूर के स्थानों में न तो मुस्लिम-शिक्षा का आविर्भाव हुआ और न विकास। तीसरा, दान, धर्म और उदारता में प्रेरित होकर मुस्लिम शासकों और उनके जनोद-उमरावों ने केवल महत्त्वपूर्ण स्थानों पर ही मक़तबों और मदरसों का निर्माण किया। चौथा, मुस्लिम शिक्षा-मस्वाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एक नैतिक कटुता की दृष्टि से गहरी और व्यापक छाप थी कि हिन्दू बालक उनमें नानन्दित न हो सके। पाँचवाँ, मुस्लिम-युग में शिक्षा-मस्वाओं की संख्या बहुत कम थी। अतः केवल जनों

और प्रभावशाली व्यक्तियों के बालकों को ही उनमें प्रवेश मिलता था। फलस्वरूप, सामान्य व्यक्तियों के बालकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में शिक्षा में व्यापकता का अभाव होना स्वाभाविक था।

**8. कठोर शारीरिक दण्ड : Severe Corporal Punishment—**मुस्लिम शिक्षा-व्यवस्था में कठोर शारीरिक दण्ड की प्रथा प्रचलित थी। छात्रों को पाठ याद न होने पर या अन्य अपराध करने पर बेंत, कोड़े, धूँसे, लात, थप्पड़ आदि से शारीरिक दण्ड दिया जाता था। यदि वे कोई भीषण अपराध करते थे, तो उनको विभिन्न प्रकार की शारीरिक यातनाएँ दी जाती थीं।

एडम (Adam) ने अपनी "Reports" में कुछ शारीरिक यातनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है :—छात्र को मुर्गा बनाना, उसकी पीठ या गर्दन या दोनों पर निश्चित समय के लिए ईंट या लकड़ी का भारी टुकड़ा रखना, उसे पैरों के बल वृक्षा की शाखा से लटकाना, उसे बिल्ली या किसी अन्य कष्टदायक पशु के साथ बोरे में बन्द करना, उसे भूमि पर पेट के बल लेट कर अपने शरीर को निश्चित दूरी तक घसीटना।

ये सभी दण्ड निष्ठुर एवं अमानवीय होने के साथ-साथ अमनोवैज्ञानिक और शिक्षा-सिद्धान्तों के प्रतिकूल थे। इस प्रकार के दण्ड दिए जाने का कारण यह था कि राज्य की ओर से कोई दण्ड-विधान निर्धारित नहीं था। अतः शिक्षक अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार छात्रों को कोई भी दण्ड देने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र थे।

**9 छात्रों की विलासप्रियता : Students' Love of Luxury—**प्राचीन काल की भाँति मुस्लिम काल में छात्रों को कठोर और तपस्वी-जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता था। उन्हें छात्रावासों में अनेक प्रकार के सुख-साधन और सौन्दर्य-प्रसाधन की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। फलस्वरूप, वे कुछ ही समय में इतने विलासी बन जाते थे कि वे सुखभोग के वास्तविक जीवन से पृथक् किसी अन्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि उनमें आत्म-त्याग, आत्म-निर्भरता और आत्म-अनुशासन आदि सद्गुणों के एक भी चिह्न की भलक दुर्लभ थी।

**1. अन्य दोष : Other Defects—**उपर्युक्त के अतिरिक्त मुस्लिम शिक्षा-पद्धति में कुछ अन्य दोष और थे; यथा :—

पहला, बालकों को मकतबों में कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थीं, जिनका अर्थ जानना उनके लिए आवश्यक नहीं समझा जाता था। इससे उनकी स्मरण-शक्ति तो निश्चित रूप से तीव्र हो जाती थी, पर उनकी मनन, चिन्तन आदि अन्य मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता था।

दूसरा, बालकों को पहले पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था और उसकी समाप्ति के पश्चात् लिखने का। इससे उनका पर्याप्त समय नष्ट होता था और उनका सन्तुलित विकास भी नहीं होता था।

तीसरा, मौखिक शिक्षण पर इतना अधिक बल दिया जाता था कि बालको को निरीक्षण, परीक्षण आदि व्यावहारिक क्रियाओं के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं होता था ।

चौथा, डा० यूसुफ हुसेन के अनुसार :—“मध्यकालीन शिक्षा-पद्धति में सजीलेपन का अभाव था । परिणामतः वह अत्यधिक अनम्य (Rigid) और अनिर्माणकारी (Non-Creative) बन गई थी ।”

पाँचवाँ, डा० यूसुफ हुसेन के शब्दों में :—“मध्यकालीन शिक्षा-पद्धति में छात्रों को व्यावहारिक निर्णय प्रदान करने की क्षमता नहीं थी । वह अत्यधिक निष्प्राण और सुस्तरोय थी ।”

अन्तिम, डा० यूसुफ हुसेन के विचारानुसार :—“यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य होगा कि मध्यकालीन शिक्षा-पद्धति, नेतृत्व के गुणों का विकास करने में विफल हुई । अतः वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए असाधारण व्यक्तियों की माँग को पूर्ति नहीं कर सकी ।”

“It would be historically true to assert that the medieval system of education failed to impart the qualities of leadership and thus ensure the supply of outstanding personalities in the different walks of life”—Dr Yusuf Husain : *Glimpses of Medieval Indian Culture*, p 97

## आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्त्व Acceptable Features for Modern Education

मुस्लिम-शिक्षा में हमें ऐसे अनेक उपयोगी तत्त्व मिलते हैं, जो आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए ग्रहणीय हैं, यथा .—

1. व्यावहारिक शिक्षा Practical Education—आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष-प्राप्ति का माधन बनाना सर्वथा अनुचित है । अतः यह आवश्यक है कि जिस प्रकार मुस्लिम शिक्षा में व्यावहारिक विषयों को महत्त्व दिया जाता था, उसी प्रकार भारत की आधुनिक शिक्षा में भी दिया जाय । व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र—समाज के उपयोगी सदस्य बन सकते हैं और साथ ही अपनी जीविका का सरलता से उपार्जन भी कर सकते हैं ।

2. नि शुल्क शिक्षा Free Education—मुस्लिम शिक्षा, प्राथमिक और उच्च—दोनों स्तरों पर नि शुल्क थी । आधुनिक भारतीय शिक्षा प्राथमिक स्तर पर तो नि शुल्क है, पर माध्यमिक और उच्च स्तरों पर नहीं है । अतः इन स्तरों पर शिक्षा को नि.शुल्क बनाया जाना चाहिए । इसका मुख्य कारण यह है कि आज की शिक्षा इतनी महँगी हो गई है कि अनेक छात्र माध्यमिक और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए सलायित होने पर भी उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं ।

यह तथ्य निधन परिवारों के बालकों के विषय में विशेष रूप से सत्य है। उच्च शिक्षा को निःशुल्क बनाने से राज्य-सरकारों का व्यय अवश्य बढ़ जायगा, पर इससे हित भी अवश्य अधिक होगा। इसकी पुष्टि में यह कारण प्रस्तुत किया जा सकता है कि देश को प्रतिभाशाली व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं, जो प्रखर बुद्धि वाले होते हुए भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं।

**3. व्यक्तिगत सम्पर्क : Individual Contact**—मुस्लिम युग के अधिकांश मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ-साथ रहते थे। फलस्वरूप, उनमें व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित हो जाता था। इस सम्पर्क के माध्यम से शिक्षक, छात्रों में विशिष्ट गुणों का समावेश करते थे।

आधुनिक भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत सम्पर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही कारण है कि छात्रों में उच्छृङ्खलता और अनुशासनहीनता की निरन्तर वृद्धि होती चली जा रही है। इसको समाप्त करने और छात्रों का चारित्रिक उन्नयन करने के लिए, शिक्षकों से उनका निकट और व्यक्तिगत सम्पर्क होना परम आवश्यक है। अतः मुस्लिम शिक्षा में पाए जाने वाले शिक्षकों और छात्रों के व्यक्तिगत सम्पर्क को आधुनिक भारतीय शिक्षा में समाविष्ट किया जाना अनिवार्य है।

**4. शिक्षक की स्थिति में उन्नति : Elevation of Teacher's Status**—आधुनिक भारत में शिक्षक की स्थिति निम्न से निम्नतर होती चली जा रही है। इसके लिए आंशिक रूप में शिक्षक, पर मुख्य रूप में समाज और राज्य उत्तरदायी हैं। इसका कारण यह है कि न तो शिक्षक को समाज का सम्मान प्राप्त है और न राज्य का संरक्षण। अतः यह आवश्यक है कि समाज और राज्य—दोनों ही उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करें और उसकी स्थिति को समुन्नत बनाने का उद्योग करें। मुस्लिम युग में शिक्षक को छात्रों की भक्ति, समाज का सम्मान और राज्य का संरक्षण प्राप्त था। आधुनिक भारत में मुस्लिम शिक्षा के इस तत्त्व को एकमत से स्वीकार किया जाना चाहिए।

**5. धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय : Synthesis of Religious & Secular Education**—आज के भौतिकवादी युग में लौकिक शिक्षा की असीम आवश्यकता है। किन्तु, इस शाश्वत सत्य को विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि धर्म—व्यक्ति के जीवन और चरित्र का प्रधान आधार-स्तम्भ है। आधुनिक भारतीय शिक्षा की परिधि में से धर्म को बाहर निकाल कर इस आधार-स्तम्भ को हटा दिया गया है।

इसके कुत्सित परिणाम, भारत के प्रत्येक स्थान में देखने को मिल रहे हैं। अकारण भूट योजना, स्वार्थवश धोखा देना, निजहित के लिए लूटमार करना, काम-वासना की तृप्ति के लिए अवज्ञाओं का अपहरण करना—ये सभी बातें धर्मविहीन शिक्षा की शोचक हैं। इनके कारण आज के भारतीय अपने आदि पूर्वजों की चर्चर

अवस्था की ओर अत्यन्त त्वरित गति से बढ़ रहे हैं। इससे उनकी रक्षा सभी की जा सकती है, जब मुस्लिम-शिक्षा का अनुकरण करके, आधुनिक भारतीय शिक्षा में भी धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय किया जाय।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Give a brief account of the organization of education in medieval India.

मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. What were the aims and ideals of Muslim education? How far were they formulated keeping in view the interests of Muslim rulers of India?

मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे? उनका निर्माण भारत के मुस्लिम शासकों के हितों को कहीं तक ध्यान में रखकर किया गया था?

3. Describe briefly the essential features of Muslim education. Which of these would you like to revive in modern India and why?

मुस्लिम शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप आधुनिक भारत में इनमें से किन को पुनर्जीवित करना चाहेंगे और क्यों?

4. Describe briefly the main defects of education prevalent in the medieval period. How far have these defects been removed in the modern education of India?

मध्यकाल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोषों का निवेदन कीजिए। भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहीं दूर हुआ है?

# 4

## यूरोपीय मिशनरियों के प्रारम्भिक शिक्षा-कार्य EARLY EDUCATIONAL ACTIVITIES OF EUROPEAN MISSIONARIES (1600-1833)

"The beginnings of the present system of education in India can be traced to the efforts of the Christian missionaries."—A. N. Basu.

### विषय-प्रवेश

मुद्गर अतीत से ही भारत के पश्चिमी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध थे। हिन्दू राजाओं के समय में उन देशों में भारतीय वस्त्र, रत्न आदि की बहुत माँग थी। इन राजाओं की अपेक्षा अधिक ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करने वाले मुसलमान शासकों ने विलान की सामग्री और कला की कृतियों के उत्पादन को उदारतापूर्वक प्रोत्साहन दिया। ये वस्तुएँ शीघ्र ही पश्चिमी देशों में विख्यात हो गईं और वहाँ पहुँचने लगीं। उस समय वहाँ भारत से व्यापार करने के तीन मुख्य केन्द्र थे—टायर, सिकन्दरिया और कुस्तुनतुनिया। इन केन्द्रों को भारतीय वस्तुएँ उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रदेश से होती हुई, प्राचीन स्थल-मार्गों से जाती थीं। इनके बदले में वहाँ से चाँदी, मूँगा, मदिरा आदि वस्तुएँ आती थीं। आयात और निर्यात के इन पदार्थों का क्रय-विक्रय करके यूरोप के व्यापारी धनवान बन गए थे।

पन्द्रहवीं शताब्दी में तुर्कों की दक्षिणी-पश्चिमी एशिया और दक्षिणी-पूर्वी यूरोप की विजय के कारण भारत और यूरोप के मध्य प्राचीन स्थल मार्ग अवरोध हो गए। इससे यूरोप के व्यापारियों को चिन्तित देखकर, वहाँ के नाविकों ने भारत के लिए जल-मार्ग खोजने का बीड़ा उठाया। इस कार्य का श्रेय—पुर्तगाल के नाविक वास्को-

ड-गामा (Vasco-da-Gama) को प्राप्त हुआ। उसने 27 मई, 1498 को भारत के पूर्वी तट पर पहुँच कर, कालीकट के प्रसिद्ध बन्दरगाह में अपने जहाज को समर डाल कर गड़ा किया।

इस नवीन जल-मार्ग की खोज के फलस्वरूप यूरोप के व्यापारियों का भारत में आगमन हुआ। आरम्भ में उनकी रुचि केवल व्यापार में थी। किन्तु, जैसा कि टी० एन० सिक्वेरा ने लिखा है :—“व्यापार के बाद इस देश में उनका सगुना सहराया और उसके साथ उनकी शिक्षा का आरम्भ हुआ।”

“The flag followed trade. And with the trade came education.”—T. N. Siqueira : *The Education of India*, p. 19.

### भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों European Trading Companies in India

वास्को-ड-गामा द्वारा भारत तक पहुँचने के नवीन जलमार्ग की खोज किए जाने का सर्वप्रथम और सर्वाधिक लाभ उसके देश के पुर्तगालियों ने उठाया। उन्होंने सन् 1500 ई० से इस देश में व्यापार करना आरम्भ कर दिया और 100 वर्ष तक अपने एकाधिकार का निर्विघ्नता और स्वच्छन्दता से प्रयोग किया। उनके व्यापारिक लाभ से प्रलोभित होकर, 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में भारत से व्यापार करने के उद्देश्य में व्यापारिक कम्पनियों का निर्माण हुआ। इन कम्पनियों में उल्लेखनीय थी—इंग्लिश ईस्ट इंडिया कम्पनी (1600), डच ईस्ट इंडिया कम्पनी (1602) और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कम्पनी (1664)। हॉलैंड के डेन लोगों ने भी भारत में व्यापार करना आरम्भ किया।

आरम्भ में इन कम्पनियों ने भारत के विभिन्न भागों को अपने केन्द्र-स्थल बनाकर व्यापार किया। परन्तु, समान कार्य में संलग्न होने के कारण उनमें कुछ ही समय उपरान्त पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता का उदय हुआ। इस प्रतिद्वन्द्विता ने शीघ्र ही शक्ति-परीक्षा के लिए पारस्परिक युद्धों का रूप धारण किया। इन युद्धों के विषय में केवल इतना कह देना पर्याप्त ज्ञान पड़ता है कि अन्त में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने सभी प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त करके, भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में अपना अभियान आरम्भ किया।

### मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरम्भ

#### Introduction of Modern Education by Missionaries

यूरोप के व्यापारियों के भारत-आगमन के कुछ समय उपरान्त, यहाँ के ईसाई मिशनरियों ने इस देश में प्रवेश किया। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य—भारतवासियों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना था, न कि यूरोपीय ढंग की शिक्षा सम्प्रदायों का निरालम्बाग करना। फिर भी, उन्होंने इस कार्य की प्रारम्भिकता प्रदान की। इसका कारण बताते हुए, प्रसिद्ध मिशनरी डा० डी० ओ० एलेन (Dr D O Allen)

ने निम्ना है :—“शिक्षा-संस्थाओं ने मिशनरियों को भारतीयों से सम्पर्क स्थापित करने और उन्हें अपने धार्मिक सिद्धान्तों से अवगत करने का अवसर प्रदान किया।”

इस अवसर से पूर्ण लाभ उठाने के लिए, मिशनरियों ने भारत के विभिन्न स्थानों में शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की और उनमें पाश्चात्य ढंग पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य आरम्भ किया। यही कारण है कि मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। इस संदर्भ में नूरुल्ला व नायक के अग्रार्कित शब्द उल्लेखनीय हैं :—“मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है।”

“To the missionaries belongs the honour of being pioneers in the modern educational system of India.”—Nurullah & Naik : *A History of Education in India*, p. XIV.

## मिशनरियों के शिक्षा-कार्य

### Educational Activities of Missionaries

यूरोप के मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए, उनका संक्षिप्त विवरण दृष्टव्य है :—

1. डच मिशनरी : Dutch Missionaries—डच मिशनरियों ने चिनसुरा, नागापट्टम और विमलीपट्टम में कुछ स्कूलों का निर्माण किया। इन स्कूलों में डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों और अन्य भारतीयों के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। डच मिशनरियों ने धर्म-प्रचार के कार्य को बरीयता नहीं दी। अतः उन्होंने अपने स्कूलों को धर्म-प्रचार का केन्द्र नहीं बनाया।

2. डेन मिशनरी : Dane Missionaries—डेन मिशनरियों ने तंजौर, सीरामपुर, त्रिचनापली और फ़ोर्ट सेंट डेविड में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएँ थीं। डेन मिशनरियों ने अपने धर्म-प्रचार के कार्य में मुसलमानों से सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की। अतः उन्होंने मुसलमान बालकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया। उन्होंने ट्रान्कब्यूवर में एक प्रशिक्षण-विद्यालय का भी नव-निर्माण किया, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता था।

3. फ़्रांसीसी मिशनरी : French Missionaries—फ़्रांसीसी मिशनरियों ने माहो, यनाम, कारीकल, पांडिचेरि और चन्द्रनगर में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों की विशेषता यह थी कि इनमें बालकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी। इनमें अध्ययन करने वाले बालकों को कभी-कभी मुफ्त भोजन, वस्त्र और पुस्तकें दी जाती थीं।

4. पुर्तगाली मिशनरी : Portuguese Missionaries—पुर्तगाली मिशनरियों





जीपेंक था—“ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार”  
 (“Observations on the State of Society Among the Asiatic Subjects  
 of Great Britain”)

ग्रांट ने अपनी पुस्तिका में हिन्दुओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए,  
 लिखा :—“हिन्दू इसलिए ग़लती करते हैं, क्योंकि उनमें अज्ञानता है और उनको  
 उनकी ग़लतियाँ उचित प्रकार से कभी बताई नहीं गई हैं।”

“The Hindoos err, because they are ignorant, and their errors  
 have never been fairly laid before them.”—Charles Grant.

ग्रांट ने अपनी पुस्तिका में हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमानों की अज्ञानता का  
 भी चित्र अंकित किया। उसने इन दोनों जातियों की अज्ञानता का निवारण करने के  
 लिए अग्रलिखित पंचमुखी योजना प्रस्तुत की :—(1) भारत में विद्यालयों की स्थापना,  
 (2) विद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा, (3) विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा  
 और साहित्य की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, (4) पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का  
 प्रचार, और (5) ईसाई-धर्म का व्यापक प्रचार। इस योजना को प्रस्तुत करने के  
 पश्चात्, ग्रांट ने लिखा :—“इस योजना की सफलता के लिए केवल सरकार के  
 हार्दिक संरक्षण की आवश्यकता है। यदि सरकार इसकी सफलता चाहती है, तो  
 यह अवश्य सफल हो सकती है।”

“There is nothing wanting to the success of this plan, but the  
 hearty patronage of Government. If they wish it to succeed, it can  
 and must succeed.”—Charles Grant.

ग्रांट की धारणा थी कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने  
 के पश्चात्, भारतीयों की विचारधारा में परिवर्तन हो जायगा और वे ईसाई-धर्म के  
 अनुयायी बन जायेंगे। यद्यपि उसकी यह धारणा निराधार थी, तथापि भारतीयों की  
 शिक्षा के सम्बन्ध में उसके प्रस्ताव उसकी दूरदर्शिता के प्रमाण हैं। उसने 1792 में  
 ही भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के महत्त्व को भली-भाँति समझ लिया था  
 अपने प्रस्तावों द्वारा उसने भारतीयों की शिक्षा के लिए, जिस अग्रिम रूपरेखा का  
 निर्माण किया, उसे भविष्य में मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए, ग्रांट को आधुनिक  
 भारतीय शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। नूरुल्ला व नायक ने ठीक ही लिखा  
 है :—“ग्रांट को कभी-कभी भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है।”

“Grant is sometimes described as the father of modern edu-  
 cation in India.”—Nurullah & Naik : *op. cit.*, p. 77.

### मिशनरी कार्यों का पुनरारम्भ

#### Revival of Missionary Activities

ग्रांट के विचारों का ब्रिटिश लोकमन के सदस्य, रॉबर्ट विल्वरफोर्स  
 (Robert Wilberforce) पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अतः जब 1793

इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का "आज्ञा-पत्र" (Charter) पुनरावर्तन (Renewal) के लिए लोकसभा के समक्ष आया, तब विल्वरफोर्स ने यह प्रस्ताव रखा कि "आज्ञा-पत्र" में एक ऐसी धारा जोड़ दी जाय, जिससे मिशनरियों को पर्याप्त सत्ता में भारत भेजा जा सके। किन्तु, कम्पनी के संचालक—"सीरामपुर निमूति" के कार्यों के कारण भारतीयों में उत्पन्न होने वाले दोष को भूने नहीं थे। वे भारत में अपने नेव-निर्मित राज्य को मिशनरियों को धर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता देकर, खोना नहीं चाहते थे। अतः कम्पनी के संचालकों ने विल्वरफोर्स के प्रस्ताव का प्रबल विरोध करते हुए कहा :—"हिन्दुओं को धार्मिक तथा नैतिक पद्धति अन्य किसी राष्ट्र से कम महत्त्व-पूर्ण नहीं है। अतएव न उनके धर्म-परिवर्तन की ही कोशिश की जाय और न उन्हें उनकी संस्कृति की शिक्षा के सिवा अन्य प्रकार के ज्ञान-प्रदान की चेष्टा ही की जाय।"

संचालकों के विरोध का समर्थन करते हुए, रैंडल जैकसन नामक लोकसभा के एक सदस्य ने कहा :—"हमने अपनी शिक्षा का प्रसार करके अमरीका में अपने उपनिवेशों को पाल दिया। अतः हमें भारत में अपनी शिक्षा का प्रसार नहीं करना चाहिए।"

"We lost our colonies in America by imparting our education there; we need not do so in India too."—Randle Jackson.

उक्त विरोधों के कारण, विल्वरफोर्स का प्रस्ताव उखाड़ कर फेंक दिया गया। किन्तु, इस अनफलता ने ग्रान्ट को निरुत्साहित नहीं किया और वह अपने आन्दोलन को निरन्तर नव जीवन प्रदान करना रहा। अन्ततोगत्वा, जब 1813 में कम्पनी का "आज्ञा-पत्र" पुनरावर्तन के लिए लोकसभा में फिर आया, तो उसमें एक नवीन धारा जोड़कर अंग्रेज मिशनरियों को भारत में बेरोक-टोक प्रवेश करने का अधिकार दे दिया गया। इसका परिणाम बताते हुए, नूडल्ला व नायक ने लिखा है :—"मिशनरियों ने भविष्यक सत्ता में भारत आना और अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार, उन्होंने आधुनिक शिक्षा-पद्धति का सिद्धान्त प्रस्थापित किया।"

"Missionaries began to land in India in large numbers and establish English schools, thereby laying the foundation of the modern educational system."—Nurullah & Naik *op. cit.*, p 82.

### उपसंहार

भारत आने वाले यूरोपीय मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य—यही के निवासियों को ईसाई-धर्म में दीक्षित करना था। उनके उन उद्देश्यों की बाहे जिनकी भी विद्या की जाय, पर हम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्या का माध्यम बना कर, उन्होंने हम क्षेत्र में जो कार्य किए, वे भारतीय शिक्षा व विज्ञान में सर्वत्र स्वर्ण अधरोः।

रहेंगे। उन्होंने इस देश में न केवल आधुनिक शिक्षा-पद्धति को प्रचलित किया, वरन् स्वयं शिक्षा-संस्थाओं का संचालन करके, भारतीयों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया।

उन्होंने यह कार्य उस समय किया, जब प्राचीन भारतीय शिक्षा, यवनों द्वारा पदाक्रान्त की जा चुकी थी और मुस्लिम शिक्षा अपने संरक्षकों के अभाव में डगमगा रही थी। ऐसे समय में मिशनरियों ने एक नवीन शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात करके, इस देश की जनता का अकथनीय हित किया। ए० एन० बसु का यह कथन अशरयः सत्य है :—“यह मुख्यतः मिशनरियों के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों ने इस देश में शिक्षा की एक नवीन पद्धति का आविर्भाव देखा।”

“It was mainly due to the efforts of the missionaries that the early years of the nineteenth century witnessed the emergence of a new system of education in this country.”—A. N. Basu : *Education in Modern India*, p. 17.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Give a brief account of the early educational activities of European missionaries.  
यूरोपीय मिशनरियों के प्रारम्भिक शिक्षा-कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. “The beginnings of the present system of education in India can be traced to the efforts of the Christian missionaries.” Discuss.  
“भारत में शिक्षा की वर्तमान प्रणाली का आरम्भ ईसाई-मिशनरियों के प्रयासों में खोजा जा सकता है।” इस कथन की समीक्षा कीजिए।
3. “Charles Grant is often described as the father of modern education in India.” Elucidate.  
“चार्ल्स ग्रांट को बहुधा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है।” इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए।

## 5

### इंगलिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-कार्य EARLY EDUCATIONAL ACTIVITIES OF ENGLISH EAST INDIA COMPANY (1600-1833)

"The Company was empowered to perform all the State functions—executive, judicial, legislative, and economic"—Dr Balkrishna.

#### विषय-प्रवेश

इंगलिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को रानी एलिजाबेथ प्रथम (Queen Elizabeth I) ने 31 दिसम्बर, 1600 ई० को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए "बाज़ा-पत्र" (Charter) प्राप्त हुआ था। उस समय से लेकर लगभग 150 वर्ष तक कम्पनी का मुख्य उद्देश्य—व्यापार करना था। किन्तु, यूरोप की अन्य व्यापारिक कम्पनियों के समान उसे थोड़ा-बहुत धर्म-प्रचार का कार्य भी करना पड़ा।

1757 में प्लासी की विजय और 1765 में माहू आक्रम में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की "दीवानी" प्राप्त करने के पश्चात्, इस देश के पर्याप्त भूभाग के शासन की बागडोर कम्पनी के हाथ में आ गई और उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण किया। अपनी इस सत्ता को विरस्थापी बनाने के लिए, कम्पनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यही से इंगलिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भारतीय शिक्षा-नीति का आरम्भ होता है। इस नीति के अन्तर्गत कम्पनी ने 1833 तक उच्च शिक्षा को कुछ संस्थाओं को स्थापना की। हम प्रथमदृष्टा की दृष्टि से इनका वर्णन करने से पूर्व, कम्पनी द्वारा संचालित किए जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों का उल्लेख कर रहे हैं।

## स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना

### Establishment of Schools & Colleges

1. प्राथमिक विद्यालय : Primary Schools—सन् 1765 ई० में पहले कम्पनी का ध्यान मुख्य रूप से व्यापार पर और औद्योगिक रूप में धर्म-प्रचार पर केन्द्रित था। अतः उसने जनसाधारण की शिक्षा से कोई संबंध व्यक्त नहीं की। उसने केवल अपने कर्मचारियों के बच्चा ही निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कुछ धर्मार्थ विद्यालयों (Charity Schools) की स्थापना की। इन विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने, लिखने, साधारण गणित और ईसाई-धर्म की शिक्षा दी जाती थी।

1765 तक कम्पनी की शिक्षा-नीति उक्त बच्चों की प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित रही। किन्तु, उसके उत्तरार्ध कम्पनी की शिक्षा-नीति में परिवर्तन हुआ और उसने उच्च शिक्षा की संस्थाएँ स्थापित की। इस उद्यम में चार महत्त्वपूर्ण संस्थाओं का विवरण निम्नवत् कर रहे हैं।

2. कलकत्ता मदरसा : Calcutta Madarassah—इस संस्था की स्थापना, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल और बेंगला एवं फार्मी के प्रजापुत्र विद्वान्, वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) के व्यक्तिगत प्रयास के फलस्वरूप सन् 1781 में हुई। इसकी स्थापना का तात्कालिक कारण हेस्टिंग्स की कलकत्ता नगर के कुछ संभ्रान्त मुसलमानों से प्राप्त होने वाला आवेदन-पत्र था।

“कलकत्ता मदरसा” में शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की थी, और शिक्षा का साध्यम, अरबी भाषा थी। इस संस्था के वाद्यक्रम में श्रयांकित विषयों का स्थान दिया गया था :—दर्शन, व्याकरण, श्रंखणित, ऐतानगित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र-विद्या; मुस्लिम कानून और धार्मिक सिद्धान्त। कुछ ही समय में इस संस्था की स्थिति दूर-दूर तक फैल गई। अतः सुदूर गुजरात, कर्नाटक और कन्नौज तक के विद्यार्थीगण इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे।

“कलकत्ता मदरसा” स्थापित करने में हेस्टिंग्स का प्रत्यक्ष उद्देश्य—कम्पनी की नीतियों के लिए मुसलमानों को उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान करना था। किन्तु, इस्तीफा-निराकरण हेस्टिंग्स के वास्तविक उद्देश्य के दर्शन, इस्लाम के श्रयांकित धार्य में होने हे—“कलकत्ता के मुसलमानों को मदरसायना प्राप्त करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ‘कलकत्ता मदरसा’ स्थापित किया गया।”

“The Calcutta Madarassah was founded by Warren Hastings in order to conciliate the Mohammedans of Calcutta.”—A. Howell : *Education in India*, p. 1.

3. बनारस संस्कृत कॉलेज : Benares Sanskrit College—इस संस्था की स्थापना, भारत राज्य के गेस्टिंग्स, जॉनथन डंकन (Jonathan Duncan) के व्यक्तिगत प्रयास के परिणामस्वरूप 1791 में हुई। इस संस्था में “मनुस्मृति” के

अनुसार हिन्दू-धर्म-सिद्धान्त, न्याय, कानून, गणित, इतिहास, उर्दूशास्त्र और दर्शनशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी।

जिम दृष्टि में मुसलमान नवयुवकों के लिए "कलकत्ता मदरसा" की स्थापना की गई थी, उसी दृष्टि से हिन्दू नवयुवकों के लिए "बनारस संस्कृत कॉलेज" की गृष्टि की गई थी। दूसरे शब्दों में, मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों और हिन्दू नवयुवकों को हिन्दू कानूनों में विशेष योग्यता प्रदान करके, अंग्रेज न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार किया जाता था।

फिर, वास्तव में जिस प्रकार "कलकत्ता मदरसा" की स्थापना, मुसलमानों को प्रमत्त करने के लिए की गई थी, उसी प्रकार "बनारस संस्कृत कॉलेज" का निरालम्बा, हिन्दुओं को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। नूरुल्लाह व नायक के शब्दों में — "बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, कम्पनी के नवनिर्जित प्रदेशों की हिन्दू जनता की सम्भावना प्राप्त करने के प्रयास के परिणामस्वरूप की गई थी।"

"The Benares Sanskrit College was an attempt to conciliate the Hindu population of the newly acquired territories of the Company"—Nurullah & Naik : *op cit.*, p. 58

4. फोर्ट विलियम कॉलेज : Fort William College—इस संस्था की गृष्टि भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल, लार्ड वेल्लेस्ली (Lord Wellesley) द्वारा 1800 में कलकत्ता नगर में की गई। इस संस्था की गृष्टि का मुख्य उद्देश्य बताते हुए, टी० एन० सिक्वेरा ने लिखा है :— "यह कॉलेज कम्पनी के असेनिक कमचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिन्दी, मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करना था।"

इस कॉलेज में डा० कैरे (Carey), कोल्ब्रुक (Colebrooke) और पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे सुविख्यात मनीषी, शिक्षा देने का कार्य करते थे। डा० गिल्क्राइस्ट (Gilchrist) ने, जिनको आधुनिक उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है, इस कॉलेज के प्रिन्सिपल के रूप में सन् 1804 में 1820 तक कार्य किया।

5. पूना संस्कृत कॉलेज Poona Sanskrit College—सन् 1818 में अंग्रेजों ने अन्तिम पेशवा के राज्य का अन्त करके, बम्बई प्रेसीडेन्सी का निर्माण किया। इस घटना के एक वर्ष बाद पूना का रेजीडेन्ट, एल्फिन्स्टन (Elphinstone) इस नव-निर्मित प्रेसीडेन्सी का गवर्नर नियुक्त हुआ। पूना में कुछ समय तक निवास करने के कारण, वह इस तथ्य से अवगत था कि पेशवागण अपने दक्षिण-कोष में लगभग 5 लाख रुपया प्रति वर्ष ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देते थे।

एल्फिन्स्टन ने दक्षिणा-कोष के कुछ अंश की सहायता से सन् 1821 में "पूना संस्कृत कॉलेज" की स्थापना की। राजनीति-निपुण एल्फिन्स्टन का इस संस्था को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य—दक्षिण के प्रभावशाली ब्राह्मणों को संतुष्ट

करना था। डा० श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय के अनुसार :—“इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य एल्फिन्स्टन का यह था कि पेशवा राज्य का अन्त हो जाने के कारण ब्राह्मणों में असंतोष न फैले।”

## 1813 का आज्ञा-पत्र

### Charter of 1813

इंग्लिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के “आज्ञा-पत्र” का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् ब्रिटिश लोकसभा द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। इस उद्देश्य से सन् 1813 में “आज्ञा-पत्र” को लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस अवसर पर घोर विरोध होते हुए भी ग्रांट और विल्वरफोर्स के दल को विजय प्राप्त हुई। 1813 के “आज्ञा-पत्र” में अशोकित धारा को जोड़कर, भारत में शिक्षा-प्रसार का उत्तरदायित्व कम्पनी के ऊपर रखा गया :—“साहित्य के पुनरुद्धार और समुन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में विज्ञानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपए की धनराशि पृथक् रखी जायगी और व्यय की जायगी।”

“A sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of knowledge of sciences among the inhabitants of the British territories in India.”—Charter of 1813, Section 43.

इस धारा का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कारण ग्रांट और विल्वरफोर्स द्वारा लगनग बीस वर्ष तक चलाए जाने वाले आन्दोलन की इतिथी हुई। इसने भारतीयों की शिक्षा को कम्पनी का उत्तरदायित्व बताया। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात करके, भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा। नूरुल्ला व नायक के अनुसार :—“1813 के आज्ञा-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा।”

“The Charter Act of 1813 forms a turning point in the history of Indian education.”—Nurullah & Naik : *op. cit.*, p. 82.

## उपसंहार

भारत के निवासियों को आशा थी कि 1813 के “आज्ञा-पत्र” में जोड़ी जाने वाली नवीन धारा से उन्हें शिक्षा की अधिक उत्तम सुविधाएँ उपलब्ध हो जायेंगी। परन्तु, उनकी आशा पर तुषारापात हो गया। इसका कारण यह था कि “धारा” में एक लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि का और “साहित्य” शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था।



इन दोनों प्रश्नों को लेकर, कम्पनी के कर्मचारियों में विवाद बारम्बार हो गया। फलस्वरूप, 1813 से 1833 तक कम्पनी ने किसी निश्चित शिक्षा-नीति का अनुसरण नहीं किया। तथापि, इस अवधि के अन्तिम दश वर्षों को एक विशेषता अंकित करने के योग्य है। टी० एन० सिक्वेरा के शब्दों में यह विशेषता व्यक्त है :—“1823 और 1833 के बीच में शिक्षा की एकाकी महत्वपूर्ण विशेषता—अरबी या संस्कृत की अपेक्षा उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है।”

“The only important feature of education between 1823 and 1833 is the increasing popularity of English as a medium of higher education in preference to Arabic or Sanskrit.”—T. N. Siqueira : *op. cit.*, pp 30-31.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Discuss briefly the educational policy of the English East India Company between 1765 and 1833.  
1765 से 1833 तक इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शिक्षा-नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. Write short notes on :—(a) Charity Schools, (b) Calcutta Madarassah, (c) Benares Sanskrit College, and (d) Charter of 1813.  
संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए —(अ) धर्मार्थ विद्यालय, (ब) कलकत्ता मदरसा, (स) बनारस संस्कृत कॉलेज, और (द) 1813 का आज्ञापन।
3. “The Charter Act of 1813 forms a turning point in the history of Indian education.” Discuss  
“1813 के आज्ञापन ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा।” समीक्षा कीजिए।



## प्राच्य-पाश्चात्य-विवाद, मैकॉले का विवरण-पत्र व निस्यन्दन-सिद्धान्त

### ORIENTAL-OCCIDENTAL CONTROVERSY, MACAULAY'S MINUTE & FILTRATION THEORY

"All the funds appropriated for the purposes of Education would be best employed on English education alone."—*Government Proclamation of 1835.*

#### विषय-प्रवेश

1813 के "आज्ञा-पत्र" की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तर-दायित्व कम्पनी पर रखा और उसे उनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपये की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। किन्तु "धारा" में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाय—प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर? फलतः इस प्रश्न को लेकर, कम्पनी के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ। इस विवाद को "प्राच्य-पाश्चात्य-विवाद" की संज्ञा दी गई है। इस विवाद में भाग लेने वाले दो मुख्य दल थे—प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी (Orientalists & Occidentalists)।

#### विवाद का मुख्य कारण

#### Main Cause of Controversy

विवाद का मुख्य कारण—1813 के "आज्ञा-पत्र" की 43वीं धारा में प्रयोग किये गये दो शब्द थे—"साहित्य" और "भारतीय विद्वान्।" प्राच्यवादियों और

पारचात्यवादियों ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या दो विभिन्न प्रकार से की। इस व्याख्या पर प्रकाश डालते हुए, डा० धीधरनाथ मुत्तोवाध्याय ने लिखा है :—  
 “प्राच्यवादियों का कहना था कि इस धारा के ‘साहित्य’ शब्द के अन्तर्गत आते हैं—केवल ‘अरबी और संस्कृत साहित्य’, एवं ‘भारतीय विद्वान्’ का अर्थ है—इन दोनों भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का भारतीय विद्वान्। पारचात्यवादियों का मन था कि इन दोनों शब्दों का अर्थ इतना सूक्ष्म नहीं है। ‘साहित्य’ में अंग्रेजी का भी विशेष स्थान है।”

### प्राच्यवादी : Orientalists

प्राच्यवादी दल में कम्पनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। इनमें सर्व-प्रथम स्थान, चार्ल्स हेस्टिंग्स और जानेयन डकन का था, जिन्होंने “कलकत्ता मद्रास” और “बनारस संस्कृत कॉलेज” की गृष्टि करके, प्राच्यवादी नीति के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था। लाई मिंटो भी इसी नीति का पोषक था। इस नीति को बंगाल की “लोक-शिक्षा-सम्मिति” (General Council of Public Instruction) के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इन सदस्यों में दो मुख्य थे—“सम्मिति” का अध्यक्ष, विलसन (H. H. Wilson) और बंगाल का शिक्षा-सचिव, प्रिन्सेप (H. T. Prinsep)। प्रिन्सेप—प्राच्यवादी दल का नेता भी था।

कम्पनी के उपरिनिखित सभी कर्मचारी और प्राच्यवादी-नीति के अन्य पोषक, उच्च कोटि के तूटनीतिज्ञ थे। उनकी धारणा थी कि भारतवासियों को विभाजित रख कर ही उन पर शासन किया जा सकता था। अतः वे इस देश के निवासियों को अरबी, फारसी और संस्कृत पर आधारित शिक्षा प्रदान करके, विभिन्न धर्मों और जातियों में विभाजित रखना चाहते थे। विन्सन इस बात का घोर विरोधी था कि भारतीय, अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके, उसके देशवासियों ने समानता करने का दावा करें। प्रिन्सेप का दृढ़ विचार था कि भारतीयों में अंग्रेजी पर अधिकार प्राप्त करने की क्षमता नहीं है।

अन्य प्राच्यवादियों ने भारतीयों की अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने के विपक्ष में तीन तर्क प्रस्तुत किये। पहला, भारत में पारचात्य ज्ञान और विज्ञानों का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जायगा। दूसरा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से उस भारतीय साहित्य का विनाश हो जायगा, जिसमें अनेक युगों का ज्ञान संचित है। तीसरा, टी० एन० तिरवैत के अनुसार —“जब भारतीयों की अपनी स्वयं की एक प्राचीन और भव्य संस्कृति है, तब उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करना दोषपूर्ण नीति है।”

प्राच्यवादियों ने उपर्युक्त तर्क उपस्थित करके, इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों की प्राचीन शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को बचाने के लिए

अतः उनकी शिक्षा-प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाय और उनमें पाश्चात्य ज्ञान का कदापि प्रसार न किया जाय ।

### पाश्चात्यवादी : Occidentalists

पाश्चान्यवादी दल में कम्पनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे । वे सम्पूर्ण देश में यत्र-तत्र बिखरे हुए थे । इसलिए, उनके दल का न तो कोई संगठित स्वरूप था और न उनका कोई नेता ही था । फिर भी, उन्होंने प्राच्यवादियों की नीति का जम कर विरोध किया । उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य-शिक्षा-प्रणाली मरणामन्न अवस्था को प्राप्त कर चुकी है और उसे पुनर्जीवन प्रदान करना मानव-प्रयत्न से बाहर की बात है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह घोषित किया कि अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के साहित्यों में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा किसी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं मिलता है । अतः भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए, उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराया जाना परम आवश्यक है ।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना असंगत न होगा कि पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञानों के प्रसार का समर्थन किसी निस्स्वार्थ भावना से नहीं, बरन् निज हित की भावना से प्रेरित होकर किया । उन्हें अपने व्यापारिक और प्रशासकीय कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित “बाबू-वर्ग” की आवश्यकता थी । उन्हें यह बात असह्य थी कि उनके देशवासी, इंग्लैंड से आकर इस निम्न वर्ग में सम्मिलित हों । अतः उन्होंने यही अधिक विवेकपूर्ण समझा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करके “बाबू-वर्ग” का निर्माण किया जाय ।

इस प्रकार, प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का विवाद 1834 तक चलता रहा । अन्त में, जनवरी, 1835 में “लोक-शिक्षा-समिति” के मन्त्री ने दोनों दलों के वक्ताओं को भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल, लार्ड विलियम बेंटिक (Bentinck) के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया ।

### मैकॉले का विवरण-पत्र, 1835

#### Macaulay's Minute, 1835

10 जून, 1834 को लार्ड मैकॉले (Macaulay) ने गवर्नर-जनरल की कोसिल के “कानून-मदस्य” के रूप में भारत में पदार्पण किया । उस समय तक “प्राच्य-पाश्चात्य-विवाद” उग्रतम रूप धारण कर चुका था । बेंटिक का विश्वास था कि मैकॉले जैसा प्रकाण्ड विद्वान् ही इस विवाद को समाप्त कर सकता था । इस विचार से उसने मैकॉले को बंगाल की “लोक-शिक्षा-समिति” का सभापति नियुक्त किया । फिर, उसने मैकॉले से 1813 के “आज्ञा-पत्र” की 43वीं धारा में अंकित एक लाघव वाक्य की धनराशि को व्यय करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया । साथ ही, उसने “समिति” के

मन्त्री को प्राच्यवादी और पश्चात्यवादी दलों के वक्तव्यों को मैकॉलि के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया।

मैकॉलि ने सर्वप्रथम "आज्ञा-पत्र" की उक्त धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया। तदुपरान्त, उसने तर्कपूर्ण और वक्तव्यी भाषा में अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध "विवरण-पत्र" में लेखबद्ध करके, 2 फरवरी, 1835 को बेट्टरि के पास भेज दिया। हम मैकॉलि के "विवरण-पत्र" के दो प्रमुख अंशों का वर्णन कर रहे हैं; यथा :—

### (1) 43वीं धारा की व्याख्या Interpretation of 43rd Section

मैकॉलि ने अपने "विवरण-पत्र" में 1813 के "आज्ञा-पत्र" की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की :—

1. एक भाषा रूप की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार भी व्यय कर सकती है।
2. "साहित्य" शब्द के अन्तर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. "भारतीय विद्वान्"—सुसंस्कृत मान्यताओं एवं मूल्यों के पण्डित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान् भी हो सकता है।

### (2) अंग्रेजी के पक्ष में तर्क Arguments in Favour of English

"आज्ञा-पत्र" की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद, मैकॉलि ने प्राच्य-विद्या एवं साहित्य का प्रबल सफाई और अंग्रेजी के माध्यम से पश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा का प्रोत्तिजाली समर्थन किया। सरप्रथम मैकॉलि ने भारतीय भाषाओं की अध्ययन के लिए, पूर्णतया निरर्थक प्रमाण दिए। — "भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान-कोष का अभाव है, और ये इतनी अविकसित तथा गवारा हैं कि जब तक उनकी बाह्य-भण्डार से सम्पन्न नहीं किया जायगा, तब तक उनमें किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद नहीं हो सकेगा।"

भारतीय भाषाओं की अपेक्षा में पश्चात्य के पक्षार्थ, मैकॉलि ने अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा में अंग्रेजी का उच्च स्थान देते हुए कहा :— "एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक जन्मदारी का भारत और अरब के संस्कृत साहित्य से कम महत्व नहीं है।"

"A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia."—Macaulay's *Minute*.

इस प्रकार, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत की अध्ययन-क्षेत्र से बाहर निकाल कर, मैकल्लि ने अंग्रेज़ी को उनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बनाया और उसके अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित बातें दीं :—

1. अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेज़ी अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है।
2. अंग्रेज़ी हम देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा बन सकती है।
3. जिस प्रकार लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं ने इंग्लैंड में, और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं ने हम में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेज़ी ने भारत में होगा।
4. भारतवासी—अरबी और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेज़ी की शिक्षा के लिए अधिक उत्कृष्ट हैं।
5. भारतवासियों को अंग्रेज़ी का अच्छा विद्वान् बनाना जा सकता है और हमारे प्रवास इसी दिशा में होने चाहिए।
6. अंग्रेज़ी की शिक्षा द्वारा हम देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है, जो एक ओर रस में भरे हो भारतीय हो, पर रचियों विचारों, नीतिकला और विद्वता में अंग्रेज़ होंगे।

"It is possible through English education to bring about a class of persons, Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."—

Macaulay. H. Sharp, ed. 'Macaulay's Minute's, Selection from Educational Records, Part I, p. 117.

उपयुक्त बातों के आधार पर मैकल्लि ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य-शिक्षा की सन्वासी पर धन व्यय करना मूर्खता है और इसको बन्द कर दिया जाय। इसके स्थान पर अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं की सृष्टि की जाय। अंग्रेज़ी भाषा का जगमान और समर्थन करने हुए, मैकल्लि ने कहा :—"अंग्रेज़ी पश्चिम की भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेज़ी भाषा जानता है, वह उस विज्ञान ज्ञान-भण्डार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है, जिसकी विषय की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है।"

"English stands pre-eminent even among the languages of the West. Whoever knows the English language has ready access to all the vast intellectual wealth, which all the wisest nations of the earth have created."—Macaulay's *Minute*.



वनरानि देने की घोषणा की। इन घोषणा ने प्राच्यवादियों को प्रमत्त कर दिया। फनस्वरूप, लम्बे काल से चले आने वाले विवाद का अन्त हो गया। डा० एल० एन० मुक्तजी के जर्चों में :—“लाउं ओकलैंड को इस बात का अभिमान था कि उसने 31,000 रुपए प्रति वर्ष की मामूली रकम अधिक व्यय करके, उत्तेजित विवाद का अन्त कर दिया।”

“Lord Auckland could boast that with an additional expenditure of a meagre sum of Rs. 31,000 per year, he could close a heated controversy.”—Dr. S. N. Mukerji : *History of Education in India*, p. 96.

### निस्यन्दन-सिद्धान्त : Filtration Theory

1. सिद्धान्त का अर्थ—अंग्रेजी के “Filtration” शब्द का अर्थ है—“निस्यन्दन” अर्थात् “छानने की क्रिया”। व्यापारियों की कम्पनी होने के कारण, वह भारतीयों की शिक्षा पर कम-से-कम धन व्यय करना चाहती थी। अतः उसने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए किया जाय, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन-छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुँच जायगी। इस सिद्धान्त के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए, बरयर मेहू ने लिखा है :—“शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके, जनसाधारण तक पहुँचनी थी। सामप्रद ज्ञान, भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूँद-बूँद करके नीचे टपकना था।”

“Education was to permeate the masses from above Drop by drop from the Himalayas of the Indian life useful information was to trickle downwards.”—Arthur Mayhew : *The Education of India*, p. 92.

2. सिद्धान्त के समर्थक—“निस्यन्दन-सिद्धान्त” के समर्थकों में थे—ईसाई मिशनरी, बम्बई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य, फ्रांसिस वार्डेन (Francis Warden), कम्पनी के संचालक और मैकालि।

(i) ईसाई-मिशनरियों का आग्रह था कि यदि भारत के उच्च वर्गों के हिन्दुओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर, ईसाई-धर्म का अवलम्बी बना लिया जायगा, तो निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई-धर्म में दीक्षित हो जायेंगे।

(ii) फ्रांसिस वार्डेन ने 23 दिसम्बर, 1823 के अपने “विवरण-पत्र” में यह विचार व्यक्त किया :—“बहुत-से व्यक्तियों को थोड़ा-सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े-से व्यक्तियों को बहुत-सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है।”

(iii) कम्पनी के संचालकों ने 29 नवम्बर, 1830 के अपने “आदेश-पत्र” में मतदान के गवर्नर को यह परामर्श दिया :—“शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है, जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाय, जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है।”



(iv) मैकलि ने अपने 1835 के "विवरण-पत्र" में "निस्पन्दन-सिद्धान्त" को गमयन करने का प्रयास किया :—“हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए, जो हमारे और उन लोगों के बीच में बुनियादी का काम करे, जिन पर हम शासन करते हैं।”

3. ऑकलैंड द्वारा सिद्धान्त की स्वीकृति—भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, लार्ड ऑकलैंड ने "निस्पन्दन-सिद्धान्त" की शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया और 24 नवम्बर, 1839 के अपने "विवरण-पत्र" द्वारा अशास्त्रिक घोषणा की :—“सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन-छन कर जनसाधारण तक पहुँचेंगी।”

“Attempts of Government should be restricted to the extension of higher education to the upper classes of society who have leisure for study and whose culture would filter down to the masses”—Auckland's Minute, 1839.

4. परिणाम व असफलता—सरकारी नीति के रूप में "निस्पन्दन-सिद्धान्त" के भारतीय शिक्षा के स्वरूप को 1854 तक के लिए निश्चिन्न कर दिया। इस नीति का कम्पनी के कर्मचारियों ने हार्दिक स्वागत किया। फलस्वरूप, देश में अंग्रेजी की उच्च शिक्षा के प्रसार में तीव्रता आ गई।

किन्तु, ऑकलैंड ने जिस उद्देश्य में "निस्पन्दन-सिद्धान्त" को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में घोषित किया था, उसकी प्राप्ति में सफलता नहीं मिली। शिक्षा, उच्च वर्गों से छन-छन कर निम्न वर्गों तक नहीं पहुँच सकी। इसका मुख्य कारण यह था कि जिन व्यक्तियों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरियाँ मिल जाती थी, उनके विचारों, आदर्शों और मान्यताओं में आधुनिक परिवर्तन हो जाता था। साथ ही, उनमें श्रेष्ठता की एक ऐसी भावना का उदय हो जाता था, जिसके कारण वे निम्न वर्गों से सम्पर्क स्थापित करने में अपनी मान-हानि समझते थे।

कुछ समय के पश्चात् अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के एक पृथक् वर्ग का निर्माण हो गया, जिसका अपने निर्धन देशवासियों से पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद था। भारत के दुर्भाग्य से, सरकार के टुकड़ों पर चलने वाले इसी वर्ग के व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अपने देशवासियों पर अक्रान्तीय प्रत्याचार करके अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण दिया। उनके इसी दायें से शुद्ध होंकर जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन भारत में लिखा था :—“अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया था। यह अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त वर्ग था, जो जनसाधारण से पृथक् अपने स्वयं के संसार में रहता था और अपने शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्व प्रयत्नशील रहता था।”

"The British had formed a new class in India, the English educated class, which lived in a world of its own, cut off from the mass of the population, and looked always towards its rulers"—  
Jawaharlal Nehru : *Discovery of India*, pp. 413-414.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. What were the main causes of the Oriental-Occidental Controversy ? How was it brought to a close ?  
प्राच्य-पारश्चात्य-विवाद के मुख्य कारण क्या थे ? इसका अन्त किस प्रकार किया गया ?
2. "Macaulay's *Minute* gave a new direction to the History of Education in India." Comment.  
मैकॉले के विवरण-पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की ।" आलोचना कीजिए ।
3. Write short notes on :—(a) Filtration Theory, (b) Orientalists and Occidentalists, and (c) Government Proclamation of 1835.  
अग्रोक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—(अ) निस्वन्दन-मिद्धान्त, (ब) प्राच्यवादी और पारश्चात्यवादी, और (ग) 1835 की सरकारी घोषणा ।

## ४

### वुड का आदेश-पत्र, 1854 WOOD'S DESPATCH, 1854

"Wood's Despatch is the Magna Charta of Education in India."—H. R. James.

#### विषय-प्रवेश

भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। ब्रिटिश की 1835 की "विज्ञप्ति" ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार की शिक्षा-नीति बनाया। इस नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए "लोक-शिक्षा-समिति" ने अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए, संस्थाओं का नव-निर्माण किया। 1833 के "आज्ञा-पत्र" ने भारत के सिन्धुद्वार सब देशों के मिशनरियों के लिए खोल दिए। जब अंग्रेज मिशनरियों के अलावा अन्य देशों के मिशनरियों ने भी भारत में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए मिशन स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की।

इन सब कार्यों के फलस्वरूप 1853 के जून तक भारत में अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस अवधि की इन दो विशेषताओं के साथ-साथ कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, डा० थोपरलाथ मूलोपाध्याय ने लिखा है :—'शिक्षा-छनाई सिद्धान्त का बोलबाला रहा, जन-शिक्षा असम्भव मानी गई एवं देशी शिक्षा कुचन दी गई, पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ा, प्राच्य विद्या गिरथंक मानी गई, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ, सांस्कृतिक एवं सांक्रभाषाएँ निकम्बी ठहराई गई।'।

#### वुड के आदेश-पत्र का मूल कारण Origin of Wood's Despatch

1853 में इन्डियन ईस्ट इण्डिया कंपनी के 'आज्ञा-पत्र' के पुनरावर्तन का

अवसर आया। उस अवसर पर ब्रिटिश लोकसभा ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था। इस विचार से प्रेरित होकर, लोकसभा ने एक "जांच-समिति" की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। इस "समिति" के सुझावों के आधार पर कम्पनी के संचालकों ने 19 जुलाई, 1854 को एक आदेश-पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा की नीति का प्रकाशन किया। उस समय सर चार्ल्स वुड (Sir Charles Wood) कम्पनी के "बोर्ड ऑफ कंट्रोल" (Board of Control) का सभापति था। अतः आदेश-पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश-पत्र" (Wood's Despatch) कहा गया। यह तो अनुच्छेदों का लम्बा लेख-पत्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग-प्रत्यंग पर विचार किया गया है और उनके सम्बन्ध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशों की गई हैं।

### आदेश-पत्र के सुझाव व सिफारिशें

#### Suggestions & Recommendations of the Despatch

हम "वुड के आदेश-पत्र" में लिखित महत्वपूर्ण सिफारिशों का निम्नांकित स्तम्भों में क्रमबद्ध वर्णन कर रहे हैं :—

1. शिक्षा का उत्तरदायित्व : Responsibility of Education—“आदेश-पत्र” में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी पर है। इस उत्तरदायित्व को पुनर्निर्धारित करने के लिए, “आदेश-पत्र” में कहा गया :—“अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकर्षित नहीं करता है, जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है।”

2. शिक्षा के उद्देश्य : Aims of Education—“आदेश-पत्र” ने भारतीयों की शिक्षा के अग्राधिकार चार उद्देश्य घोषित किए :—(1) भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके, उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना; (2) भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करके, उनकी भौतिक समृद्धि करना; (3) भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना; और (4) भारतीयों को अपने देश को समृद्धिवासी बनाने में सहायता देना।

3. पाठ्यक्रम : Curriculum—“आदेश-पत्र” ने अरबी, फ़ारसी और संस्कृत को उपयोगी बताने हुए, उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया। किन्तु, भारतीयों के लिए यूरोप के समुन्नत कला-तोजल, विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अधिक उपयोगी बताने पर, पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया गया। इन विषयों को यूरोपीय ज्ञान की संज्ञा देते हुए, “आदेश-पत्र” में घोषित किया गया :—“हम यत्नपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं, वह है—यूरोपीय ज्ञान।”

4. शिक्षा का माध्यम : Medium of Instruction—"आदेश-पत्र" ने अंग्रेज़ों का समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए अंग्रेज़ों को और अन्य व्यक्तियों के लिए देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया। इस प्रकार, अंग्रेज़ों और देशी भाषाओं—दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए, "आदेश-पत्र" ने यह आगा प्रकट की।—"हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेज़ी भाषा और भारत की देशी भाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ-साथ देखने की आशा करते हैं।"

"We look to the English language and to the Vernacular languages of India together as the media for the diffusion of European knowledge."—Wood's Despatch.

5. शिक्षा-विभागों की स्थापना : Establishment of Education Departments—"आदेश-पत्र" ने मुद्राव दिया कि प्रान्तीय बोर्डों और शिक्षा-समितियों (Provincial Boards & Councils of Education) को बन करके भारत के पाँचों प्रांतों (पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश) में एक-एक लोक-शिक्षा-विभाग (Department of Public Instruction) की स्थापना की जाय। इस विभाग के संचालन का सम्पूर्ण भार लोक-शिक्षा-संचालक (Director of Public Instruction) पर रखा जाय। उसे अपने कार्य में सहायता देने के लिए उपशिक्षा-संचालकों, विद्यालय-निरीक्षकों और सहायक विद्यालय-निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाय।

6. विश्वविद्यालयों की स्थापना . Establishment of Universities—"आदेश-पत्र" में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। "आदेश-पत्र" में कहा गया कि इन विश्वविद्यालयों का संगठन, सन्दन-विन्यासविधानों को आदर्श मान कर किया जाय, जो उस समय केवल परीक्षण-संस्था थी।

7. क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना Establishment of Graded Institutions—"आदेश-पत्र" में यह मत प्रकट किया गया कि सम्पूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा-संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाय। "आदेश-पत्र" ने इन संस्थाओं के स्वरूप को इस प्रकार निश्चित किया -

विश्वविद्यालय

कलेज |

हाईस्कूल

मिडिल स्कूल

देशी प्राथमिक विद्यालय

8. जन-शिक्षा का विस्तार Expansion of Mass Education—"आदेश-पत्र" में यह निम्नलिखित रूप से स्वीकार किया गया कि कम्पनी के "फैक्टरी मिडलान्त" का अनुसरण करके जन-साधारण की शिक्षा की पूर्ण उद्देश्य

“आदेश-पत्र” ने यह सिफारिश की कि सरकार—प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करे, प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालयों का सुधार करे और मेधावी, पर निर्भर छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करे, ताकि उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले।

9. सहायता-अनुदान-प्रणाली : Grants-in-Aid System—“आदेश-पत्र” ने भारत में जन-शिक्षा-कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा-संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए “सहायता-अनुदान-प्रणाली” को प्रचलित करने का सुझाव दिया। उसने यह भी सुझाव दिया कि भवन-निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोग-शालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए भी अलग-अलग अनुदान दिए जायें। “सहायता-अनुदान-प्रणाली” की रूपरेखा का संकेत देते हुए, “आदेश-पत्र” में यह वाक्य अंकित किया गया :—“हमने भारत में उसी सहायता-अनुदान-प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है, जो इस देश में अत्यधिक सफलता से सम्पादित की गई है।”

“We have resolved to adopt in India the system of grants-in-aid which has been carried out in this country (England) with very great success.”—Wood's Despatch.

10. अध्यापकों का प्रशिक्षण : Training of Teachers—“आदेश-पत्र” ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थाओं का शिवाग्रास किया जाय। “आदेश-पत्र” ने यह इच्छा व्यक्त की कि छात्रों को प्रशिक्षण-काल में छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर, शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाय।

11. व्यावसायिक शिक्षा : Vocational Education—“आदेश-पत्र” में व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा करते हुए कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कलेजों की गृष्टि की जाय, जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके।

12. स्त्री-शिक्षा : Female Education—“आदेश-पत्र” में यह सिफारिश की गई कि स्त्री-शिक्षा को उदारतापूर्वक सहायता-अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाय। “आदेश-पत्र” ने उन व्यक्तियों की सराहना की गई, जिन्होंने स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था।

13. मुसलमानों की शिक्षा : Education of Muslims—“आदेश-पत्र” में यह स्वीकार किया गया कि मुसलमानों की शिक्षा पिछड़ी हुई दशा में थी। अतः उसने उद्घाटनपूर्वक कहा कि कम्पनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के विशेष प्रयत्न करने चाहिए।

14. प्राच्य-साहित्य व देशी भाषाओं को प्रोत्साहन—Encouragement to Oriental Literature & Vernacular Languages—“आदेश-पत्र” में यह

बुड का आदेश-पत्र, 1854 |

अभिलाषा अधरबद्ध की गई कि प्राच्य-साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाय। इसके अतिरिक्त, उनमें यह अभिलाषा भी लिखबद्ध की गई कि देशी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाय, उनके लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाय और पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाय।

15 शिक्षा व रोजगार : Education & Employment—"आदेश-पत्र" ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियाँ दी जायें। इस सम्बन्ध में कम्पनी के सचिवों की इच्छा को "आदेश-पत्र" में अग्रगण्य शब्दों में व्यक्त किया गया — "जो बात हम चाहते हैं, वह यह है कि यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएँ समान हों, तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, उस व्यक्ति को

"What we desire is that, when other qualifications of the candidates for appointments under government are equal, a person who has received a good education should be preferred to one who has not."—Wood's Despatch.

### आदेश-पत्र का मूल्यांकन Estimate of the Despatch

"बुड के आदेश-पत्र" का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए उसके गुणों और दोषों का अवलोकन करना वांछनीय है। जत हम मक्षेप में उनका उल्लेख कर रहे यथा —

- 1 गुण Merits—"आदेश-पत्र" के प्रमुख गुण अधोलिखित हैं —
- 1 'आदेश-पत्र' ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया, शिक्षा की नीति का निर्धारण किया और शिक्षा को निश्चित दिशा प्रदान की।
- 2 "आदेश-पत्र" ने प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के प्रति ध्यान देकर, क्रमबद्ध शिक्षा-नास्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया।
- 3 "आदेश-पत्र" ने "निस्यन्दन-मिडाल" को सर्वथा अनुपयुक्त बताकर, जन-शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले मिडाल को मान्यता प्रदान की।
- 4 "आदेश-पत्र" ने भारतीय भाषाओं के महत्त्व को स्वीकार करके, उनको माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित किया।
- 5 "आदेश-पत्र" ने भारतीय साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार करके, उनको पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्रदान किया।

6. "आदेश-पत्र" ने लोक-शिक्षा-विभागों, प्रशिक्षण-संस्थाओं और विश्व-विद्यालयों के नव-निर्माण का सुझाव देकर, भारतीय शिक्षा को विकसित और संगठित करने का उद्योग किया।
7. "आदेश-पत्र" ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूलों और कलियों की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत करके, देश में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या का समाधान करने की चेष्टा की।
8. "आदेश-पत्र" ने स्त्रियों और मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करना सरकार का कर्तव्य बना कर, उनकी शिक्षा का मार्ग प्रगस्त करने में योग दिया।
9. "आदेश-पत्र" ने सब प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान-प्रणाली का अनुमोदन करके भारतीय शिक्षा के प्रसार में सहायता की।

2. दोष : Defects—उपरिर्णित गुणों ने हमें इस ध्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि "आदेश-पत्र" दोषरहित था। वस्तुतः उसमें अनेक स्पष्ट दोष थे; यथा :—

1. "आदेश-पत्र" ने शिक्षा पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। फलस्वरूप, चिरकाल से चले आने वाले स्वतंत्र शिक्षण-कार्य का अन्त हो गया।
2. "आदेश-पत्र" ने अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का आदेश अंकित किया। फलतः प्राच्य-शिक्षा, साहित्य और विद्यालयों का अस्तित्व संकट में पड़ गया।
3. "आदेश-पत्र" ने अंग्रेजी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य—सरकारी नौकरियों प्राप्ति करना निर्धारित किया। इस उद्देश्य को निर्धारित करके, "आदेश-पत्र" ने शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को नष्ट कर दिया।
4. "आदेश-पत्र" ने भारतीय शिक्षा को पूर्णतया विदेशी रंग में रंग दिया और भारतीयों को उसे ग्रहण करने के लिए राजपदों का प्रलोभन दिया। उनका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों का अपने देश की शिक्षा-प्रणाली में सम्बन्ध-विच्छेद हो गया।
5. "आदेश-पत्र" ने अंग्रेजी को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बना दिया। अतः शिक्षा-संस्थाओं में प्राच्य-भाषाओं का गौण स्थान हो गया।
6. "आदेश-पत्र" ने निम्न शिक्षा-प्रणाली का अनुमोदन किया, उसमें परीक्षाओं का स्थान सर्वोपरि था। अतः छात्रों का एकमात्र उद्देश्य—ज्ञान का अर्जन करना न होकर, परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो गया।



7. "आदेश-पत्र" ने भारतीय विश्वविद्यालयों को लन्दन-विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित किये जाने का निर्देश दिया। इस निर्देश के फल-स्वरूप भारत में प्राचीन विश्वविद्यालयों की परम्पराओं की पूर्ण उपेक्षा हो गई।
8. "आदेश-पत्र" ने अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बना कर भारतीय छात्रों का महान् अहित किया। इसका कारण यह था कि इन छात्रों के लिए अंग्रेजी के माध्यम से सब विषयों को गहराई तक पढ़ाकर, उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असम्भव था।
9. "आदेश-पत्र" ने शिक्षा की परिधि में वे घर्म को निकाल कर उगे पूर्णतया लौकिक बना दिया। परिणामतः भारतीयों के लिए आध्यात्मिक विकास केवल कल्पना की धनु हो गई।
10. "आदेश-पत्र" ने अरबी, फारसी और संस्कृत की उपयोगिता को स्वीकार करके, उनको पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया। परन्तु, पारम्पर्य ज्ञान की प्राप्ति को शिक्षा का लक्ष्य बनाकर, उनकी उपयोगिता को अनुपयोगिता में परिणत कर दिया।

### आलोचकों की सम्मतियाँ

#### Views of Critics

1854 के "आदेश-पत्र" के उल्लिखित गुणों में मुग्ध होकर, कुछ आलोचकों ने उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उनके विपरीत, "आदेश-पत्र" के दोषों से धुम्प होकर, कुछ आलोचकों ने उसकी कड़ी निन्दा की है। हम कनिष्ठ अनुभूत और प्रत्यूत सम्मतियों का दिग्दर्शन करा रहे हैं, यथा —

1 हैम्पटन :—"1854 का आदेश-पत्र एक युग का, शिक्षा के महान् अपभूतो के युग का, अन्त करता है।"

"The Despatch of 1854 marks the end of an era, the age of the great educational pioneers."—H. V. Hampton *Biographical Studies in Modern Indian Education*, p. 115

2 जेम्स —"1854 का आदेश-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में घरम बिन्दु है। जो-कुछ उससे पहले हुआ, वह उसकी ओर सकेत करता है; और जो-कुछ उसके बाद हुआ, वह उससे निकलता है।"

"The Despatch of 1854 is the climax in the history of education; what goes before leads up to it what follows flows from it." —H. R. James *Education & Statesmanship in India*, p. 42.

3. जमु —"इस आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का शिताधार कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली का शिताग्याप्त किया।"

"This Despatch is said to be the corner-stone of Indian education. It is said to have laid the foundation of our present system of education."—A. N. Basu : *Education in Modern India*, pp. 37-38.

4. **उल्लेखनीय :**—"आदेन-पत्र में सम्पूर्ण भारत के लिए शिक्षा की योजना थी। यह योजना उस योजना से अधिक विस्तृत और अधिक व्यापक थी, जिसे स्थानीय या केन्द्रीय सरकार प्रस्तुत करने का साहस भी नहीं कर सकती थी।"

"The Despatch contained a scheme of Education for all India, far wider and more comprehensive than the Local or the Supreme Government could have even ventured to suggest."—Dalhousie's *Minute* of 1854.

5. **डा० मुकरजी :**—"आदेन-पत्र ने देश की प्राचीन परम्पराओं का पता नहीं लगाया और इन बात पर विचार भी नहीं किया कि भारत में शिक्षा—धार्मिक संस्कार था।"

"The Despatch did not enquire into the past traditions of the country and did not at all consider that education was a religious sacrament in India."—Dr. S. N. Mukerji : *History of Education in India*, p. 130.

6. **भगवान दयाल :**—"यूट के आदेन-पत्र का मुख्य दोष—शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य था। यह उद्देश्य—पूर्व और पश्चिम की सर्वोत्तम बातों का समन्वय न होकर, केवल यूरोपीय ज्ञान की प्राप्ति का था।"

"The fundamental defect in Wood's Despatch was the wrong aim of education. It was not to be a synthesis of the best things that both the East and the West had to offer; but only European knowledge."—Bhagwan Dayal : *The Development of Modern Indian Education*, p. 233.

7. **प्रांजपे :**—"1854 में आदेन-पत्र का चाहें जो भी महत्त्व हो, पर इस समय उसकी शिक्षा का अधिकार-पत्र कहना हास्यास्पद होगा।"

"Whatever were its value in 1854, it would be ridiculous to describe the Despatch as an Educational Charter now."—M. R. Paranjpe : *Progress of Education*, Poona, July 1941, p. 52.

8. **प्रांजपे :**—"आदेन-पत्र के रचयिताओं का उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा, नेतृत्व के लिए हो; शिक्षा, भारत के औद्योगिक पुनर्स्थापन के लिए हो; शिक्षा, मानव-वृद्धि के लिए हो; संसार में शिक्षा प्रसार हो, जो स्वतन्त्र राष्ट्र के व्यक्तियों के लिए आवश्यक होती है।"

"The authors of the Despatch did not aim at educational leadership, education for the industrial regeneration of India for the defence of the motherland; in short, education red by the people of a self-governing nation."—Paranjpe : op. p. 52.

### निष्कर्ष

आलोचकों की उपरिब्रूत सम्मतियों के आधार पर हम निम्नकोच कह सकते हैं कि "बुड का आदेश-पत्र" भारतीय शिक्षा के इतिहास में बेनज़ीर उसने भारतीय शिक्षा के सभी पक्षों के सम्बन्ध में इतनी व्यापक और महत्वपूर्ण मिकारिमें की, जिनको आज भी पूरा करना असम्भव है। उसने भारतीय शिक्षा के अनेकरूपता को समाप्त करके एकरूपता प्रदान करने की चेष्टा की। उसी के गुन्नाय के फलस्वरूप मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई मन्गुल देश में क्रमवद्ध शिक्षा-मन्त्रालयों की योजना कार्यान्वित की गई, सहायता-प्रणाली का गूत्रपात किया गया, प्रान्तों में लोक-शिक्षा-विभागों का निर्माण हुआ और छात्र-वृत्तियाँ देने की परम्परा आरम्भ हुई।

किन्तु, "आदेश-पत्र" का दूसरा पहलू भी है। उपरिब्रूत कार्यों के कारण उसका चाहे जितना भी यशमान क्यों न किया जाय, पर उसको शिक्षा का महाधिकार कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इंग्लैंड के 1215 के "महाधिकार पत्र" ने उस देश के जन-जन को स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया। परन्तु, 1854 के "आदेश-पत्र" ने गावर्नमेंट शिक्षा के सम्बन्ध में मौन धारण करके, भारतीय जनता को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार में वंचित रखा। इनके अतिरिक्त, "आदेश-पत्र" ने भारतीय शिक्षा को मरगार ने जधीन करके, उसे जड़ों से जकड़ दिया, उस पर विदेशी ढाँचे से षोष रर प्राचीन शिक्षा-पद्धतियों का नामोनिजान मिटा दिया और धर्म को शिक्षा से मदेव के लिए शिक्षा करके, शिक्षा के प्राचीन आदर्शों को बुनियाद को हिला दिया।

इस प्रकार, बुड के 'आदेश-पत्र' ने भारतीयों और उनकी परम्परागत शिक्षा को अहित किया, उसको ध्यान में रखकर हम निर्भयता से कह सकते हैं कि इस 'आदेश-पत्र' को शिक्षा का महाधिकार पत्र बड़े जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी विचार में उत्प्रेरित होकर नृक्षता से नायक ने लिखा है — "हमें उन सशयोक्तिपूर्ण शब्दों में, जिनमें कुछ इतिहासकारों ने आदेश-पत्र का वर्णन किया है इसे 'भारतीय शिक्षा का महाधिकार-पत्र' बताया है, कोई ओचित्य नहीं है।"

"We cannot find any justification for the superlative terms which some historians have described the Despatch and even

called it, "The Magna Charta of Indian Education." —Nurullah & Naik : *op. cit.*, pp. 215-216.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. What were the main recommendations of Wood's Despatch of 1854? Give a critical estimate of the place of this Despatch in the history of modern Indian education.  
1854 के वुड के आदेश-पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस आदेश-पत्र के स्थान का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।
2. "Wood's Despatch is called the Magna Charta of Indian education." Discuss.  
"वुड का आदेश-पत्र, भारतीय शिक्षा का महाचिकार-पत्र कहा जाता है।" समीक्षा कीजिए।
3. Point out some of the important recommendations of Wood's Despatch which can prove useful for education in modern India.  
वुड के आदेश-पत्र की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें बताइए, जो आधुनिक भारत में शिक्षा के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं।



भारतीय शिक्षा-आयोग  
(हटर कमिशन)  
INDIAN EDUCATION COMMISSION  
(Hunter Commission)  
(1882-1883)

"Institutions under private managers cannot be successful unless they are frankly accepted as an essential part of the general scheme of education"—*Indian Education Commission Report*

विषय-प्रवेश

1854 ई. युद्ध के 'आर्देन-पत्र' र फलस्वरूप भारतीय शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में प्रान्तिकारी परिवर्तन परिनिश्चित हुए। 1855 के अन्त तक प्रत्येक प्रान्त में 'लोक-शिक्षा-विभाग' की स्थापना हो गई, महायन्त्रा-अनुदान-प्रणाली प्रचलित की गई। 1857 में और विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की योजना प्रियान्वित की गई। किन्तु, मद्रास, बम्बई और बनारस में विश्वविद्यालयों का निराल्प्याप्त किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी 1857 की प्रान्तिक विस्फोट ने भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरोध कर दिया। यह प्रान्तिक-कम्पनी के नामन के विरुद्ध भारत-वासियों के प्रबल असन्तोष की प्रतीक थी। अतः 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कम्पनी के शासन को समाप्त करके, ईंग्लैंड की रानी विक्टोरिया (Victoria) को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया।

इस प्रकार, भारत के नामहीन तो परिवर्तन हो गया, किन्तु कम्पनी के कर्मचारियों में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वे भारत की साम्राज्ञी के सेवकों के रूप

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

मान्य कार्य करते रहे। कमन्दी के अधिकारी रहे चुकने के कारण उनके मान-दृष्टिगत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अतः उन्होंने "आदेश-पत्र" के इस अंश के प्रति रचनात्मक भी ध्यान नहीं दिया कि सरकार द्वारा "नित्यन्दन-सिद्धान्त" पर विचार करने, जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए सक्रिय पग उठाए जाने चाहिए। उनकी इस दृष्टि में न केवल भारत में, बल्कि इंग्लैंड में भी व्यापक असंतोष की लहर फैल गई।

भारत में शिक्षा की सामान्य समिति" (General Council of Education in India) का संगठन करने प्रवर्तित किया। उन्होंने अपने आन्दोलन-कार्य में मिशनरियों ने पर्याप्त सहायता मिली।

"समिति" और भारत के सी.आर. से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन् 1880 में लार्ड रिपन (Ripon) को इस देश के नए गवर्नर-जनरल के रूप में मनोनीत किया। उस अवसर पर "समिति" के कुछ सदस्यों ने लार्ड रिपन से भेंट करके, उसे भारत-विषय पर "समिति" के कुछ सदस्यों ने लार्ड रिपन से भेंट करके, उसे भारत-विषय पर "समिति" की अनुदार शिक्षा-नीति में अवगन कराया और यह अनु-सूचित कि भारतीय शिक्षा की गतिविधियों की जाँच करके, उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाय।

लार्ड रिपन ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। अपने इसी वचन का पालन करने के लिए, उसने भारत पहुँचने के कुछ समय पश्चात्, 1882 में "भारतीय-शिक्षा-आयोग" (Indian Education Commission) की नियुक्ति की। इस "आयोग" का अध्यक्ष गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी मन्त्रालय - मन्त्र विनियम टेंटर (Sir William Hunter) था। अतः उसी के नाम से इस "आयोग" को "हंटर-कमीशन" (Hunter Commission) कह कर भी पुकारा जाता है।

### आयोग के जाँच के विषय

Terms of Reference of the Commission

"आयोग" का निम्नलिखित विषयों की जाँच करके, उनके सम्बन्ध में मुझको तीस विचारों की प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया :—

1. क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की है?
2. प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके सु-विकास के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए?
3. माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसका प्र-साधन क-सा किया जाना चाहिए?
4. देश की शिक्षा-प्रणाली में राष्ट्रीय विद्यालयों की क्या स्थिति भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनकी आवश्यकता है या नहीं?



3. सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का स्वयं संचालन न करके, उनका उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ देना चाहिए।
4. सरकार को माध्यमिक स्कूलों और कलेजों का प्रथम क्रम में कुशलता-पूर्वक कार्य करने वाली व्यक्तिगत संस्थाओं को मौज देना चाहिए।
5. सरकार को नविष्य में केवल सहायता-अनुदान के आधार पर स्थापित किए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों और कलेजों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए।

सारांश में, "आयोग" ने शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में सरकार को 1854 के "फ़ार्मेशन-बिल" के अप्रारिक्त मुन्नाय का अनुसरण करने का परामर्श दिया :— "राजकीय शिक्षा-संस्थाओं की उन स्थानों में चलने दिया जाय, जहाँ उनकी आवश्यकता है। किन्तु, सरकार का मुख्य कर्तव्य— ध्यत्तिगत शिक्षा-संस्थाओं की उत्पत्ति और प्रसार करना होना चाहिए।"

## 2. प्राथमिक शिक्षा : Primary Education

"आयोग" ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, प्रकार, प्रशासन, वित्त-व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षा-स्तर के उन्नयन और सरकार की नीति के सम्बन्ध में सारसहित मुन्नाय दिए; यथा :—

1. उद्देश्य व प्रकार—प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य—जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना होना चाहिए। इस शिक्षा का आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियों में प्रसार करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

2. प्रशासन—प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तर-दायित्व, सरकार को जिला-परिषदों, नगरपालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर देना चाहिए।

3. वित्त-व्यवस्था—प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं और पुनर्-कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रानीय सरकारों को इस लेख का  $\frac{1}{2}$  का सम्पूर्ण व्यय का  $\frac{1}{2}$  भाग आवित सहायता के रूप में स्थानीय निकायों को देना चाहिए।

4. पाठ्यक्रम—प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करने के उद्देश्य से उनमें पहले से समाविष्ट विषयों के अनिरिक्त अप्रारिक्त जीवस्रोतोंवा विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए— कृषि, यक्षमाता, रोध-मिति, मरुत विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, महापत्नी गति और जीवमिक कलाएँ। सम्पूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होता चाहिए और उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. शिक्षा-स्तर का उन्नयन—प्राथमिक शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिए प्रतीक विद्यालय-विशेष के अधिकार-क्षेत्र में कम-से-कम एक नामक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए।



6. सरकार की नीति—प्राथमिक शिक्षा की नीति के विषय में सरकार को अप्रतिन संनधा दी :—“देश की यतमान परिस्थितियों में यह है कि जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा और उसकी ध्यवस्था, प्रसार एवं शिक्षा प्रणाली का यह अंग धोवित किया जाय, जिसके प्रति अब राज्य धेष्टाएँ पहले से अधिक मात्रा में केन्द्रित की जानी चाहिए।”

“It is desirable, in the present circumstances of the country to declare the elementary education of the masses, its provision, extension, and improvement, to be that part of the educational system to which the strenuous efforts of the State should now be directed in a still larger measure than heretofore”—*Indian Education Commission Report*

### 3 माध्यमिक शिक्षा : Secondary Education

“आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार, पाठ्यक्रम, शिक्षा-स्तर के उन्नयन शिक्षा के माध्यम और सरकार की नीति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुभाव दिए, यथा :—

1 प्रसार- माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए सहायता-अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रणाली के प्रयोग में सरकार को अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए।

2 पाठ्यक्रम—माध्यमिक शिक्षा के कार्यों का निवारण करने के लिए, “आयोग” ने उच्च कक्षाओं में दो प्रकार के पाठ्यक्रमों का सुभाव दिया :—“अ” कोर्स और “ब” कांस (‘A’ Course & ‘B’ Course)। “आयोग” का मत था कि “अ” कोर्स माहिन्यिक होना चाहिए और उन छात्रों के लिए होना चाहिए, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक हों। “ब” कोर्स में व्यापारिक, व्यावसायिक और अमाहिन्यिक विषयों का समावेश होना चाहिए। यह कोर्स उन छात्रों के लिए होना चाहिए, जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् व्यावसायिक या अमाहिन्यिक कार्यों में सलग्न होने के इच्छुक हों।

3 शिक्षा-स्तर का उन्नयन— माध्यमिक शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिए, लाहौर और मद्रास में पहले से स्थापित प्रविधन-कालेजों के अलावा अन्य स्थानों पर प्रविधन-कालेजों की स्थापना की जानी चाहिए। इन कालेजों में छात्राधारकों की शिक्षा-विद्यालय और कक्षा-प्रविधन में भली-भाँति परिचित कराया जाना चाहिए।

4 शिक्षा का माध्यम —“आयोग” ने शिक्षा के माध्यम के विषय में बोर्ड का सुभाव नहीं दिया। अपने केरन यह कहा कि मिडिल स्कूलों में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अधिक वांछनीय है, पर छात्रों की अपेक्षा का भी कुछ ज्ञान आवश्यक है। यह विचार ध्यक्त करके “आयोग” ने हाई-स्कूलों के अतिरिक्त स्कूलों में भी शिक्षा के माध्यम के रूप में अपेक्षा का पक्ष लिया।

5. सरकार की नीति—माध्यमिक शिक्षा के विषय में “आयोग” ने यह नीति निर्धारित की कि सरकार ही इस शिक्षा का भारकुशल भारतीयों को सौंप कर, उसमें मुक्त हो जाना चाहिए। सरकार को केवल सहायता-अनुदान द्वारा माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। “आयोग” ने यह सुझाव भी दिया कि सरकार को अपने स्कूलों की क्रमशः व्यक्तिगत संस्थाओं को हस्तान्तरित कर देना चाहिए। सरकार की राजकीय विद्यालयों का निर्माण और संभालन केवल उन स्थानों में करना चाहिए, जहाँ ही जनता अनुदान-प्रवाह के आधार पर विद्यालयों को चलाने में असमर्थ हो। परन्तु, इस सम्बन्ध में भी “आयोग” ने सरकार की शिक्षा-नीति को अग्रगण्य स्थानों में स्पष्ट कर दिया :—“सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में केवल एक हाई स्कूल की स्थापना करना है। उसके पश्चात्, उसे उस जिले में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए।”

“The duty of the Government was only to establish one high school in every district and after that the expansion of secondary education in that district should be left to private enterprise.”—  
*Indian Education Commission Report.*

#### 4. कॉलेज-शिक्षा : College Education

यद्यपि कॉलेज-शिक्षा—“आयोग” की भाँच का विषय नहीं था, तथापि उसने नावैज्ञानिक कॉलेजों और उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक लाभप्रद सुझाव दिए; यथा :—

1. कॉलेजों को सहायता-अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि को उनके व्यय, शिक्षकों की संख्या, छात्र-कुल्लता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियंत्रित किया जाना चाहिए।
2. कॉलेजों को समय-समय पर फर्नीचर, पुस्तकालय, भवन-निर्माण और शिक्षक-निरन्तरता अन्य जगहों के लिए आवश्यकानुसार आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।
3. कॉलेजों में शिक्षकों को नियुक्त करने समय यूरोप के विख्यात विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. कॉलेजों के प्राध्यापकों का विस्तार करके, छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
5. कॉलेजों के छात्रों के नैतिक स्वरूप का उन्नयन करने के लिए उनकी प्राकृतिक धर्म (Natural Religion) और मानव-धर्म के सिद्धान्तों से परिचित कराया जाना चाहिए।
6. कॉलेजों के छात्रों को मानव और नागरिक कर्तव्यों के अवगत करने के लिए अवसरमत्त तर्कों का उपयोग किया जाना चाहिए।



3. धार्मिक शिक्षा : Religious Education—धार्मिक शिक्षा के विषय में “आयोग” के मुताबिक ये थे :—“धर्म-निरपेक्ष राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का दिया जाना सम्भव नहीं है। राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का कदापि समावेश नहीं हो सकता है, पर व्यक्तिगत विद्यालयों में प्रबन्धकों की इच्छा से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।”

### 6. मिशनरी प्रयास : Missionary Efforts

“आयोग” को भारत की शिक्षा-व्यवस्था में मिशन स्कूलों के स्थान के सम्बन्ध में अपने विचारों की सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। भारत-सरकार की शिक्षा-नीति के विरुद्ध आन्दोलन करने वालों में मिशनरी भी थे। अतः जब “आयोग” की नियुक्ति हुई, तब मिशनरी इस देश के शिक्षा-क्षेत्र में अपने मोक्षाम्य-मुख्य के उद्देश्य होने का स्वप्न देखने लगे। किन्तु, उनके स्वप्न ने साकार रूप धारण नहीं किया। इसका कारण यह था कि “आयोग” ने शिक्षा के सभी स्तरों के विषय में गूँगे मुन्हाव दिए, जिनके कारण मिशनरियों ने अपने को निराशा की काली घटाओं से आवृत पाया।

“आयोग” ने प्राथमिक शिक्षा की स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने का मुताबक दिया। इन शिक्षा ने मिशनरियों को कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, क्योंकि उनके प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अति अल्प थी। अतः उन्होंने “आयोग” के मुताबक की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

“आयोग” ने उच्च और माध्यमिक शिक्षा के विषय में यह प्रस्ताव रखा कि सरकार को इन दोनों स्तरों की शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर, इनका भार व्यक्तिगत प्रयासों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसका निष्कर्ष नामान्यतः यह निकाला गया कि इन दोनों स्तरों की शिक्षा पर मिशनरियों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो आयगा। पर, वास्तविकता कुछ और ही थी। “आयोग” ने अपने विचार का स्पष्टीकरण करने हुए, कहा :—“भारत के समान विभिन्न आवश्यकताओं वाले देश में शिक्षा के उत्तरदायित्व को किसी एक दल को नहीं सौंपा जा सकता है, चाहे वह हिन्दू हो उदार क्यों न हो। हम अपने इस विचार को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार को न तो ईसाई-मिशनों को माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व देकर इस क्षेत्र में पथ-होना चाहिए, और न उच्च शिक्षा की संस्थाओं को इन मठलियों को हस्तान्तरित करना चाहिए। इनके भारतवासियों में मार्गजनिता कार्यों के लिए संगठित होने से आशय का निर्माण नहीं होता। भारत में शिक्षा का प्रसार तभी हो सकता है, जब भारत के निवासी इस कार्य को सफल बनाने का प्रयास करें।”

“आयोग” के उक्त वक्तव्य में मिशनरियों को घोर निराशा हुई, पर भारतीयों के वेत गुन गए। उनको इस बात का पूर्ण आभास हो गया कि अपने देश की शिक्षा का भार उनकी ही अपने ऊपर रखा है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि



"आयोग ने लगभग उन्हीं सिद्धान्तों की पुनरावृत्ति की, जिनको चर्चा पूर्व वुड के आदेश-पत्र में स्वीकार किया गया था। उसने उन सिद्धान्तों में से कुछ को केवल विस्तृत कर दिया और कुछ पर यत्र-तत्र थोड़ा-सा बल दे दिया।"

"The Commission practically reiterated the principles which had already been accepted years ago in Wood's Despatch. It only elaborated some of the points and added some emphasis here and there."—A. N. Basu : *Education in Modern India*, p. 51.

यमु के कथन में सत्य अवश्य है, क्योंकि "आयोग" ने 1854 के "आदेश-पत्र" की निफारिशों की पुनरावृत्ति की। किन्तु, इस पुनरावृत्ति के द्वारा उसने "आदेश-पत्र" की उन निफारिशों में जान डाल दी, जिनमें दुर्बलता और शिथिलता थी। अपने इस कार्य द्वारा "आयोग" ने एक ऐसी शिक्षा-नीति का प्रतिपादन किया, जिसको सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया। यही कारण था कि भारत में लगभग अगले बीस वर्षों (1882-1902) में "आयोग" के सुझावों ने भारतीय शिक्षा के प्रत्येक अंग को प्रभावित किया। उमीनिए, भारतीय शिक्षा के इतिहास में "भारतीय शिक्षा-आयोग" को विशेष स्थान दिया जाता है। अतः हम निष्कर्ष रूप में टी० एन० सिक्वेरा के शब्दों में कह सकते हैं :—"अपने सब सुझावों के लिए 'आयोग' हादिक सराहना का पात्र है। यदि आज भारतीय शिक्षा-प्रणाली के विषय में इतने अधिक असंतोष का अनुभव किया जा रहा है, तो इसका कारण यह है कि 1882 में निर्धारित की जाने वाली शिक्षा-नीति के मुख्य अभिप्राय का अनुसरण नहीं किया गया है।"

"For all this the Commission deserves hearty approval. If so much dissatisfaction is felt with the educational system today, it is because it has not followed the spirit of the policy laid down in 1882."—T. N. Siqueira : *The Education of India*, p. 73.

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. What were the main recommendations of the Indian Education Commission of 1882 and how did they influence education in India?

1882 के भारतीय शिक्षा-आयोग की मुख्य निफारिशों कोन-सी थीं और उन्होंने भारत में शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया?

2. State and discuss the recommendations of the Indian Education Commission of 1882 regarding either Primary Education or Higher Education.

प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के विषय में 1882 के "भारतीय शिक्षा-आयोग" की सिफारिशों का वर्णन कीजिए और उनकी विवेचना कीजिए।

3. Mention the chief recommendations of the Hunter Commission of 1882 on Secondary Education and trace their influence on the subsequent development of Secondary Education in India.

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में 1882 के हटर कमीशन की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए और भारत में माध्यमिक शिक्षा की भावी उन्नति में उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए।



## शिक्षा की प्रगति PROGRESS OF EDUCATION (1882-1902)

"The local bodies did substantial service to the cause of primary education."—Nurullah & Naik.

### विषय-प्रवेश

हम इस संक्षिप्त अध्याय को केवल एक संयोजक कड़ी के रूप में स्थान दे रहे हैं। इसे स्थान देने का हमारा मुख्य प्रयोजन—“भारतीय-शिक्षा-आयोग” की सिफारिशों के परिणामों और उन सिफारिशों के आधार पर शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है।

### आयोग की सिफारिशों के परिणाम

#### Results of the Commission's Recommendations

भारत-भारत ने धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त, “भारतीय शिक्षा-आयोग” की सभी सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की। डा० एस० एन० मुकजी के अनुसार, इस स्वीकृति के 3 मुख्य परिणाम दृष्टिगोचर हुए :—

1. सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व—नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया।
2. सरकार ने उच्च और माध्यमिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना का कार्य स्वर्गित कर दिया, किन्तु उसने इन संस्थाओं के प्रबंध को किमी. दूर की हस्तांतरित न करके, स्वयं अपने हाथ में रखा।



3. सरकार ने मिशनरियों के शिक्षा-सम्बन्धी प्रयामों को मर्यादित करके, भारतवासियों के प्रयामों को विशेष प्रोत्साहन दिया।

एक अन्य परिणाम की ओर संकेत करते हुए, हॉवेल ने लिखा है :—“भारत में ब्रिटिश शासन-काल में सर्वप्रथम शिक्षा को अवहेलना की गई, फिर उपेक्षा एवं सफलता से उसका विरोध किया गया, तदुपरान्त एक ऐसी प्रणाली का मूलप्रपात रिया गया, जो सार्वजनिक रूप में हानिकारक थी और अन्त में उसे अपनी वर्तमान स्थिति प्रदान की गई।”

“Education in India under the British Government was first ignored, then violently and successfully opposed, then conducted on a system now universally admitted to be erroneous and finally placed on its present footing.”—Howell. Quoted by W. H. Sharp: *Selections from Educational Records*, Vol. I, p. 2.

### शिक्षा की प्रगति Progress of Education

सरकार की नवीन नीति के फलस्वरूप शिक्षा के सभी क्षेत्रों में ग्युनाधिक प्रगति हुई। हम शिक्षा के तीन प्रमुख क्षेत्रों का निम्नांकित पंक्तियों में वर्णन कर रहे हैं :—

1. प्राथमिक शिक्षा—“भारतीय शिक्षा-आयोग” की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगरपालिकाओं, जिला-परिषदों आदि स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दिया। इस नवीन व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा की उप्रति तो हुई, पर उसको सतोषजनक नहीं कहा जा सकता था। इसका मुख्य कारण था—घनाभाव। इसके लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराते हुए, नूटलस व नायक (p. 362) ने लिखा है :—“1881-82 से 1901-02 तक स्थानीय निकायों ने प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले अपने धन को 24.9 लाख रुपए से बढ़ा कर 46.1 लाख रुपए कर दिया, पर इसी अवधि में सरकार ने अपने व्यय को 16.77 लाख रुपए से बढ़ा कर केवल 16.92 लाख रुपए किया।”

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि 1882 से 1902 तक प्राथमिक शिक्षा की जो भी प्रगति हुई, उसका एकमात्र कारण स्थानीय निकायों की उदारता थी। यदि सरकार उसकी उपेक्षा न करती और उसके प्रसार के लिए आर्थिक सहायता देने में उदारता का परिचय देती, तो प्राथमिक शिक्षा में सम्बन्धित अंकड़े निम्नांकित से भिन्न होते (Nurullah & Naik, p. 488) —

	1881-82	1901-02
1. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	82,916	93,604
2. छात्रों की संख्या	20,61,541	30,76,671

2. माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में "भारतीय शिक्षा-आयोग" की सिफारिश यह थी कि सरकार को उसकी व्यवस्था को क्रमशः व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़कर स्वयं अपने पूरा हो जाना चाहिए। किन्तु, सरकार ने इस शिक्षा-विभाग के विभिन्न कार्य किया और पूर्ण की नहीं माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में संलग्न की। उपर्युक्त, इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार अति सीधे गति में हुआ। इस इसकी पुष्टि में निम्नांकित आँकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं (Nurullah & Naik, p. 300) :—

	1881-82	1901-02
1. माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	3,916	5,124
2. छात्रों की संख्या	2,14,077	5,90,129

3. उच्च शिक्षा—"भारतीय शिक्षा-आयोग" ने कनिष्ठों की महायन्त्रा-अनु-धान शिखे जाने का विचार प्रकट करके, अपेक्षित रूप में उच्च शिक्षा के प्रसार में योग दिया था। इस प्रकार का एक कारण यह भी था कि माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी और इसलिए उच्च शिक्षा की संख्याओं की स्थापना आवश्यक हो गई थी। "आयोग" ने यह विचार स्पष्ट रूप में प्रकट किया था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर प्रयासों की अपेक्षा भारतीयों के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाय। "आयोग" के इस विचार से प्रेरणा प्राप्त करके, अब कि निम्न कनिष्ठों की स्थापना हो। मन् 1902 में उनकी संख्या 42 थी, जब कि निम्न कनिष्ठों की संख्या 36 थी।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीयानियों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया था। अतः उन्होंने अनेक राष्ट्रीय कनिष्ठों का प्रिलान्वास किया; उदाहरणार्थ, 1859 में बाबू गंगाधर तिलक ने 'विद्यार्थी' और आगरकर के सहयोग में पूना में "महामुमुक्षु सचिव" का, 1886 में जय गंगाधर ने लाहौर में "दयानन्द मॉडर्न वैदिक कॉलेज" का और 1899 में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने बंगाल में "नैट्रल हिंदू कॉलेज" का निर्माण किया।

1882 में 1902 तक की अवधि में कनिष्ठों और उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में निम्नांकित वर्धन में स्पष्ट किया गया है (Nurullah & Naik, pp. 285-287) :—

	1881-82	1901-02
1. कनिष्ठों की संख्या	68	179
2. छात्रों की संख्या	5,399	23,009

समय का मैं, हम कह सकते हैं कि यद्यपि 1882 से 1902 तक की अवधि प्राथमिक शिक्षा के विकास में निर्दिष्टता रही, तथापि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हम अपने इस भाग की दृष्टि में मुहम्मद ब. सादत के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं :— 'इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि— माध्यमिक और कॉलेज-शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार था।'

"The most significant achievement of the period was an unprecedented expansion of secondary and collegiate education."—  
Kutubuddin & Naik : *A History of Education in India*, p. 272.

### UNIVERSITY QUESTION

- 1 Describe briefly the results of the recommendations of the Indian Education Commission. How did these recommendations influence the progress of education in India ?

'भारतीय शिक्षा-आयोग' की सिफारिशों के परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इन सिफारिशों ने भारत में शिक्षा की प्रगति को किस प्रकार प्रभावित किया ?

# 10

## लॉर्ड कर्जन के शिक्षा-सम्वन्धी सुधार EDUCATIONAL REFORMS OF LORD CURZON (1898-1905)

"Lord Curzon was not only the ablest, but also the most-hated Viceroy that ever came to India."—Nurullah & Naik.

### विषय-प्रवेश

19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में भारत-सरकार अपनी नीति के अनुसार, अंग्रेजी के माध्यम से सामान्य ज्ञान के प्रसार में दक्षिण होकर संलग्न थी। भगवान् इमान का कथन है :—“उन नीति के विरुद्ध आम जनता की गिरावट यह थी कि अंग्रेजी के माध्यम से केवल कुछ ही व्यक्ति, सामान्य ज्ञान का अभ्यास कर सकते थे। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी के माध्यम के कारण भारतीय संस्कृति का लोप होता जा रहा था।”

सरकार की इस विरुद्ध नीति को और राष्ट्रीय आन्दोलन के कथित कर्ने-पारी का प्रभाव आह्वित हुआ। अतः उन्होंने उनके विरुद्ध आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया। 1898 में जब यह आन्दोलन अपने चरम बिन्दु की ओर दृढ़ गति ले रहा था, तब लॉर्ड कर्जन ने भारत के नए गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य-भार संभाला। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति, दुर्लभ राजनीतिज्ञ और कर्तव्यपरायण शासक था। उनके अनुसार, अर्थात् कि ए० एन० एन० ने किया है :—“कर्जन स्वभाव से उदार एवं निरंकुश शासक और प्रतिभान के कारण स्टोर गारम में अविचल विश्वास रखने वाला स्टोर नायान्वयशी था।”

"By temperament Curzon was a benevolent autocrat and by training a diehard imperialist with implicit faith in a strong rule."  
—A. N. Basu : *Education in Modern India*, p. 60.

### कर्जन के शिक्षा-सम्बन्धी सुधार Educational Reforms of Curzon

कठोर और निरतुन पागल होने के कारण, कर्जन का राष्ट्रीय धाम्दोनन का विरोधी होना नितान्त स्वाभाविक था और इसलिए भारतीयों द्वारा उससे घृणा किया जाना भी स्वाभाविक था। परन्तु, हमें उसके चरित्र के इस पक्ष से कोई प्रयोजन न होकर उस पक्ष में है, जिसका भारतीय शिक्षा पर भारक प्रभाव पड़ा। इस पक्ष के अन्तर्गत आती है—कर्जन की धमापारण विद्वता और इस विद्वता के उल्लेख्य शिक्षा में उसकी अभिरुचि। वह अंग्रेजी का उतना ही घुरपर विद्वान् था, जितना कि मैकॉले। इनीलिए, नूटस्ता व नायरु ने यह घोषित किया है :—“कर्जन से धेष्टतर मानसिक योग्यता का कोई वादसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था।”

“No Viceroy of greater intellectual capacity had ever come to India so far.”—Nurullah & Naik *A History of Education in India*, p. 450.

इस प्रकार, कर्जन में प्रज्ञानकीय क्षमता और मानसिक योग्यता का उच्चोच्च सम्मिश्रण था। इस सम्मिश्रण के कारण उसकी यह धाम्ना थी कि शिक्षा में सुधार करके ही, प्रज्ञासन में सुधार किया जा सकता है। अपनी इस धारणा के कारण उसने भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार में पहले “सिमला-शिक्षा-सम्मेलन” का स्वयं सम्भाषनित्व किया। उसके पश्चात् उसने “भारतीय विश्व-विद्यालय आयोग” की नियुक्ति की, “भारतीय विश्वविद्यालय-अधिनियम” पारित करवाया, और “शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव” प्रकाशित किया। हम इसी क्रम में इनका वर्णन कर रहे हैं; यथा :—

#### 1. सिमला-शिक्षा-सम्मेलन, 1901 Simla Educational Conference, 1901

जिस समय लार्ड कर्जन ने भारत के वादसराय के रूप में इस देश की भूमि पर पैर रखा, उस समय यहाँ की शिक्षा अत्यन्त शोचनीय दशा में थी। इस दशा का चित्र “Progress of Education in India, 1902-07” में अशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया गया था :—“1897 से 1902 तक का समय प्रगतिशील शिक्षा के इतिहास में सबसे अधिक अप्रगतिशील था। शिक्षार्थियों की संख्या बहुत कम थी और विद्यालयों की संख्या भी कम हो गई थी।”

विद्या और शिक्षा का प्रेमी होने के कारण, कर्ज़न को भारत आते ही यहाँ की शिक्षा की अप्रगतिशील स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो गया। कर्ज़न ने स्वयं इस सम्बन्ध में अपने विचारों को उद्घोषित करते हुए कहा :—“जब मैं भारत आया, तब शिक्षा-सम्बन्धी मुद्धार उन कार्यों में से मेरे समक्ष उपस्थित हुआ, जिसका प्रशासकीय पुनर्संगठन के किसी भी कार्यक्रम में प्रमुख स्थान होना उचित प्रतीत हुआ।”

“When I came to India, Educational Reform loomed before me as one of those objects, which appeared to deserve a prominent place in any programme of administrative reconstruction.”—Lord Curzon. Quoted in *Lord Curzon in India*, Vol. II, p. 65.

शिक्षा-मुद्धार के कार्य की व्यावहारिक रूप प्रदान करने के विचार से, लाउड कर्ज़न ने सन् 1901 में “शिक्षा-विज्ञान-सम्मेलन” का आयोजन किया। कर्ज़न ने प्राचीनों के शिक्षा-संवादाओं और विद्वानों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। किन्तु, उसने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया। अतः भारतीयों का कर्ज़न के कार्य की शंका की दृष्टि से देवता स्थापित था।

“विज्ञान-शिक्षा-सम्मेलन”—कर्ज़न के सभापतित्व में 15 दिन हुआ और उसमें शिक्षा-सम्बन्धी 150 प्रस्तावों की सर्वसम्मति से निश्चित किया गया। कर्ज़न ने अपनी शिक्षा-नीति को इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित किया। सम्मेलन के विषय में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि उसकी कार्यवाही की आरम्भ से अन्त तक गोपनीय रखा गया था और उसकी समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित नहीं होने दिया गया था। सम्मेलन के प्रति भारतीय पहले से ही संतुष्ट थे। उसकी गुप्त कार्यवाही से उनको इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया था कि उनके विरुद्ध किसी-न-किसी पक्षधर की रचना अवश्य की गई थी। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे :—“सम्मेलन, भारतीयों को घातना देने वाली सभा थी, जिसने उनके विरुद्ध किसी भयंकर पक्षधर की रचना की थी।”

“The Conference was a Star Chamber conclave, that was engaged in some dark and sinister conspiracy.”—Lord Curzon in *India*, Vol. II, p. 67.

“विज्ञान-शिक्षा-सम्मेलन” में भारतीय शिक्षा ने सम्मिलित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-निमित्त किया गया और उसी के आधार पर कर्ज़न ने अपनी मुद्धार योजना का निर्माण किया। पर, क्योंकि भारतीय “सम्मेलन” की गुप्त कार्यवाही से अवगत नुचित थे, इसलिये उन्होंने कर्ज़न के मुद्धारों की उपयोगिता की कसौटी पर परखने का प्रयास नहीं किया।

## 2. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1902

Indian Universities Commission, 1902

1. नियुक्ति के कारण—“आयोग” की नियुक्ति के 4 मुख्य कारण थे; यथा:—

1. पञ्जाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के सभी विश्वविद्यालयों का समूह, तदन-विश्वविद्यालय को आदर्श मान कर रिया गया था। तदन-विश्वविद्यालय का 1898 में पुनर्संरचना हो गया था। अतः भारतीय विश्वविद्यालयों को उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाना आवश्यक था।

2. विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कलियों की संख्या में अति तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्य-भार हो गया था कि वे अपने कर्तव्यों का कुशलता से पालन नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप, कलियों का शिक्षण-स्तर निम्न हो गया था।

3. मीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उसमें विश्व-विद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था।

4. विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करने थे। उनमें शिक्षण की, जो उनका मुख्य कार्य था, कोई व्यवस्था नहीं थी। इस विषय में कर्जन का मत था — “आदर्श विश्वविद्यालय, ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए।”

“The ideal university should be a place for the dissemination of knowledge and the encouragement of learning”—

Lord Curzon Quoted in *Lord Curzon in India*, Vol II, p 62.

उपरोक्त आदर्शों को प्राप्त करने और कलियों एवं विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधार करने के लिए, लॉर्ड कर्जन ने 27 मार्च 1902 का “भारतीय विश्व-विद्यालय-आयोग” की नियुक्ति की।

2. जांच के विषय—“आयोग” को निम्नलिखित 3 विषय दिए गए; यथा:—

1. ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या और उनकी भावी उन्नति की जांच करना।

2. विश्वविद्यालयों की शिक्षण-विधियों का प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

3. विश्वविद्यालयों की शिक्षण-विधियों को उठाने और विद्या की उन्नति करने के लिए उपायों का प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

3. सुझाव व सिफारिशें—“आयोग” ने ब्रिटिश भारत के मंत्रिमंडल की सूझ-झाड़ों के अनुसार 1902 के उपरोक्त सरकार के समक्ष

धरम प्रस्तुत किया। इन प्रतिवेदन में "आयोग" ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुधार करने के निमित्त जिन सुझावों और सिफारिशों को लेखबद्ध किया, उनमें से निम्नांकित महत्वपूर्ण हैं :—

1. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए।
2. वर्तमान विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण-कार्य किया जाना चाहिए।
3. स्नातक-पूर्व शिक्षण का कार्य, सम्बद्ध कॉलेजों में और स्नातकोत्तर-शिक्षण का कार्य, विश्वविद्यालयों में किया जाना चाहिए।
4. प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी जानी चाहिए।
5. सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जानी चाहिए और उनकी सदस्यता की अवधि पांच वर्षों की होनी चाहिए।
6. सिंडीकेट (Syndicate) के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होनी चाहिए, और उनका निर्वाचन सीनेट (Senate) के द्वारा किया जाना चाहिए।
7. प्रत्येक सम्बद्ध कॉलेज का प्रबन्ध, एक संगठित समिति के द्वारा किया जाना चाहिए।
8. कॉलेजों को मान्यता देने के नियमों में कड़ाई की जानी चाहिए और द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।
9. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग्य अध्यापकों को सीनेटों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
10. इण्टरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्षों का कर देना चाहिए।

4. आयोग का मूल्यांकन — "आयोग" के लगभग सभी सुझावों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारतीय विश्वविद्यालयों को लन्दन-विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित किया जाए। अतः उसने भारतीय विश्वविद्यालय-व्यवस्था के आधारभूत पुनर्संगठन के सम्बन्ध में एक भी सुझाव नहीं दिया। उसने केवल भारत में प्रचलित विश्वविद्यालय-व्यवस्था को इस देश के लिए हितकर समझकर, उसको समुचित और शक्तिशाली बनाने के लिए ही सुझाव दिए। इन प्रसंग में डा० एस० एन० मुकजी का यह कथन अत्यन्त महत्त्व है :—“विश्वविद्यालय-शिक्षा के सम्बन्ध में 'आयोग' की सिफारिशों का उद्देश्य — विश्वविद्यालय-प्रणाली में किसी प्रकार का मौलिक पुनर्संगठन करना नहीं था, बल्कि प्रचलित प्रणाली को केवल पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना था।”

“The Commission's recommendations on university education did not aim at any fundamental reconstruction of the system, but





और उसकी सीमेटी के सदस्य, योग्य व्यक्ति होने लगे। विषय-विशय-विद्यालयों ने शिक्षण-कार्य को आरम्भ कर दिया। विश्वविद्यालयों की महाधन-अनुदान मिलने लगी। अब उन्होंने मकानों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की सुन्दर व्यवस्था की। विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सम्बद्ध विषयों का विशेषज्ञ किया जाने लगा। फल-स्वरूप, विज्ञान के शिक्षण-स्तर का उन्नयन हुआ, जिसने विश्वविद्यालयों के मान में पर्याप्त वृद्धि हुई।

इस प्रकार, "विश्वविद्यालय-प्रतिनियम" ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं में नवोद्गीर्णन सुधार किए। किन्तु, उसने शिक्षा की प्रणाली में किसी प्रकार का स्थानान्तरण नहीं किया। इस प्रणाली में पूर्ण के समान पुनर्जीव जान और सांकेतिक विषयों की प्रदानता बनी रही, क्योंकि इसमें जीवनोन्मुखी विषयों का समावेश नहीं किया गया। प्रतिनियम ने भारतीयों को तीन मुख्य प्राप्ति दी—विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान-कार्य का आरम्भ, सीमेटी के सदस्यों प्रभाव की कमी और कविता पूर्व विश्व-विद्यालयों को प्राथमिक समस्याओं का समाधान। पर इस प्राप्ति में ने एक भी पूर्ण नहीं हुई। इसके प्रतिफल, "प्रतिनियम" ने विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रवर्धन पर परभाव का अपना कठोर निर्वहन स्थापित कर दिया कि उनही सब स्वयंसेवा का प्रभाव प्राप्त हो गया।

"विश्वविद्यालय-प्रतिनियम" के उद्देश्यविहित गुणों और नीतियों की ध्यान में रखकर, इस निष्कर्ष रूप में सुरक्षा प्रमाण के अर्थों में कह सकते हैं:—“यह स्पष्ट है कि 1904 के ‘प्रतिनियम’ ने कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। किन्तु, कर्तव्य की विश्वविद्यालय-सुधार में एक नवीन प्राप्तिजन आरम्भ करने का श्रेय प्राप्त रहेगा। यह प्राप्तिजन सीमेटी-पेरे पर निरन्तर अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।”

“It is true that the Act of 1904, by itself did not achieve much. But Curzon will have the credit of having been the pioneer to start a new movement in university reform, which slowly but steadily, has ever been progressing to its destined goal.”—Nurullah & Naik, op. cit. pp. 474-475.

#### 4. शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, 1904

##### Government Resolution on Educational Policy, 1904

सात: ईस ने 11 मार्च, 1904 को अपनी शिक्षा-नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करके, प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में हमने क-कार्तीय शिक्षा के साथ ही भारतीय जनता के सम्मुख रखकर, अपनी शिक्षा-नीति की पुनर्जागर की। यहाँ :—

1. संस्थात्मक दोष—संस्थात्मक दृष्टि से तरकातीन भारतीय निधा-प्रणाली के दोषों के विषय में प्रस्ताव में लिखा गया :—“संस्थात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोष सर्वविदित हैं। पाँच में से चार ग्रामों में कोई विद्यालय नहीं है। चार में से तीन जातकों की शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, और पाँचों में से केवल एक जातिका किसी प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है।”

2. गुणात्मक दोष—गुणात्मक दृष्टि से तरकातीन भारतीय निधा-प्रणाली में “प्रस्ताव” द्वारा निम्नांकित दोषों की ओर मकत किया गया :—

1. पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से माहिरिक है।
2. परोक्षों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है।
3. अग्रेजी की निधा को प्रमुख स्थान देकर, भारतीय भाषाओं की अवहेलना की जाती है।
4. स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की बुद्धि का क्रम और स्मृति का अधिक विकास किया जाता है।
5. उच्च निधा का लक्ष्य केवल राजपद प्राप्त करना है। इस लक्ष्य ने उच्च निधा के क्षेत्र को अत्यधिक सूती बना दिया है। इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों को राजपद प्राप्त नहीं हो पाते हैं, वे अन्य कार्यों के लिए अयोग्य हो जाते हैं।

3. निधा की नीति—निधा के उपरिजित दोषों का निष्पन्न करने के उपरान्त “तरकारी प्रस्ताव” में निधा की नीति निर्धारित की गई। इस नीति की उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित की —

1. प्राथमिक निधा के प्रति बहुत कम ध्यान दिया गया है और उसके प्रसार के लिए अव्यक्त प्रयास किए गए हैं। इसका प्रसार करना—सरकार का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए।
2. प्राथमिक निधा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
3. प्राथमिक निधा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं का प्रमुख स्थान होना चाहिए।
4. प्राथमिक विद्यालयों में निष्पन्न करने के लिए माध्यम और सहायता प्रदान की जाए। निधा में अधिक कड़ाई की जानी चाहिए।
5. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निधा के स्तर को ऊँचा किया जायें।

4. मूल्यांकन—“भारतीय प्रस्ताव” में, लार्ड कर्जन ने भारतीय भारतीय विद्या के योग्यता का सर्वोच्च बिन्दु ज्ञात किया था और विद्या के प्रकार और अनुपस्थिति के विषय अतिरिक्त भारतीय गुणों के विषय में। किन्तु, यह विषय यौन का अनुपस्थान करने के कारण काफी से सम्मानित करना चाहता था, उनके प्रति भारतीय समर्पित थे। एक अन्य दृष्टि से कर्जन ने—“यद्यपि योग का निदान ठीक था, तथापि प्रस्तावित जोषधि न तो उपयुक्त थी और न मार्गदर्शक। लार्ड कर्जन ने जो बातें कही, उनमें से अनेक सत्य थी। किन्तु, विषय विधि में यह गुणों के कारण चाहता था, उससे शिक्षित भारतीयों के सम्मुख में सम्मानित सम्पदा की उद्घाटन हो गई। वे यह समझे कि इस गुणों-कार्य में कोई भारी सामाजिक बाधा द्विती हुई थी।”

### कर्जन के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन

#### Estimate of Curzon's Educational Reforms

भारत के अनेक भारतीय-कार्यो में लार्ड कर्जन का नाम सर्वोच्च कीर्ति में रखा जाता है। किन्तु, भारतीय जन्यता का प्रत्यक्ष उपयोग और भारतीयों के प्रति वास्तविक निरंकुश रीति के कारण, यह हमें यह कि विद्यार्थियों की श्रद्धा का नाश न कर सका। फिर भी, उही एक विद्या का सम्बन्ध है, उनके कार्यों का निरन्तर करना—सुदृढ़-प्रवृत्ति का प्रमाण दिया है।

लार्ड कर्जन ने विद्या के विभिन्न क्षेत्रों में जो गुणों के लिए, उनके लिए भारतीयों के प्रति उनके अनुपस्थित रीति। उनके “भारतीय विद्यार्थियों-प्रवृत्ति-प्रयोग” की निर्णय करने और “भारतीय विद्यार्थियों-प्रवृत्ति-प्रयोग” की पारित किया के उच्च विद्या के स्तर का उद्घाटन दिया। उनके सामाजिक विद्या के कार्यक्रम में भारतीय भाषा की सम्मानित स्थान देकर, उनकी नवशोधन प्रदान किया। उनके पारंपरिक विद्या के विचार की सरकार का स्वरूप उन्मुखित्व बनाकर, उनकी गुणों-कार्य और जन्यता के प्रति के लिए भारतीय प्रयोग किए।

सर्वोच्च में, हम यह नहीं है कि लार्ड कर्जन ने अपने प्रत्यक्ष कार्य-क्षेत्र में भारतीय विद्या के सभी क्षेत्रों में गुणों के लिए, उनके समर्थन बनाया। उनके हमें यह गुणों के लिए, उनके गुणों के लिए, उनके गुणों के लिए है—“जो कार्य, कर्जन ने मान लिये में किए, उनकी क्षमता में किसी अन्य मनुष्य की निम्न स्तर से गुणों या निम्न स्तर की जन्यता नहीं है।”

“What Curzon achieved in seven years would certainly have required twice or three or much more for any other man.”—Nuru-Bah & Nall (p. 101, p. 451).

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Discuss briefly the educational reforms of Lord Curzon.  
(लार्ड कर्जन के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।)

2. Write short notes on :—(a) Indian Universities Commission of 1902 and (b) Government Resolution on Educational Policy of 1904.

अप्रतिष्ठित पर मशहूर टिप्पणियाँ निम्निए :—(अ) 1902 का भारतीय विश्वविद्यालय-आयोग, और (ब) 1904 का शिक्षा-नीति-समस्या सरकारी प्रस्ताव ।

- 3. What was the effect of the Indian Universities Act of 1904 on the universities and affiliated colleges of India ?  
1904 के “भारतीय विश्वविद्यालय-अधिनियम” का भारत के विश्व-विद्यालयों और कॉलेजों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

# II

## राष्ट्रीय आन्दोलन का शिक्षा पर प्रभाव INFLUENCE OF NATIONAL MOVEMENT ON EDUCATION (1905—1921)

"Indian education must be controlled by Indians, shaped by Indians, carried on by Indians."—Mrs. Annie Besant.

### विषय-प्रवेश

1857 के प्रथम स्वतन्त्रता-आन्दोलन ने पूर्व ही भारतवासियों के हृदय में स्वतन्त्रता का प्रबल प्रसङ्ग उत्पन्न हो गया था। 1885 में "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस" की स्थापना ने उसे राष्ट्रीयता के दल में सींच कर परिपक्वचित करना आरम्भ किया। 1905 में "बंगाल के विभाजन" (Partition of Bengal) ने उनके वास्तविक रूप को प्रदर्शित किया। उसी वर्ष उत्पन्न होने वाले "कांग्रेस-अधिपत्य" में भारत की विदेशी सरकार के विरुद्ध स्वतन्त्रता-आन्दोलन प्रारम्भ करने का सर्वनाममणि से निरूपण किया गया। इस आन्दोलन के चार मुख्य प्रंग थे—(1) स्वराज्य की प्राप्ति, (2) स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, (3) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और (4) राष्ट्रीय शिक्षा की मांग।

### राष्ट्रीय शिक्षा की मांग Demand of National Education

बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रीय आन्दोलन और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग को परिप्रशन्न की। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आन्दोलन की गति तीव्र होती गई, जैसे-जैसे शिक्षा के राष्ट्रीय रूप का अवसर स्वर्णोदय की गति बढ़ती गई और भारतीय शिक्षा के

अप्रेक्षीकरण के विरुद्ध देशप्रेमियों की आवाज भारत के कोने-कोने में गूँबने लगी। इस निशा के उद्बर्द्ध निन्दक थे—महात्मा गांधी और भीमती एनी बेसेंट।

महात्मा गांधी ने "यंग इण्डिया" (Young India) में अपने लेख प्रकाशित करके, भारतीय निशा के विदेशी स्वरूप पर प्रचंड प्रहार किए। उन्होंने इस निशा के निम्नलिखित 4 गम्भीर दोष बताकर, भारतीयों के लिए इसका अनौचित्य सिद्ध किया :—

1. यह निशा, अन्यायपूर्ण ज्ञान में सम्बन्धित है।
2. यह निशा, विदेशी संस्कृति पर आधारित है और इसमें भारतीय संस्कृति का कोई स्थान नहीं है।
3. इस निशा का एकमात्र उद्देश्य—मस्तिष्क का विनाश करना है। इसमें हस्तकायों के लिए कोई स्थान नहीं है और यह हृदय को प्रभावित नहीं करती है।
4. इस निशा का माध्यम—अप्रेक्षी है। अप्रेक्षी, विदेशी नापा होने के कारण वास्तविक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती है।

भीमती एनी बेसेंट ने भारतीय निशा के अप्रेक्षीकरण को निन्दा और राष्ट्रीय निशा की माँग करते हुए कहा :—“राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय चरित्र को अधिक शीघ्रता और अधिक निश्चित रूप में निर्बल बनाने के लिए इससे अधिक उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता है कि बालकों की शिक्षा पर विदेशी प्रभावों और विदेशी आदर्शों का प्रभुत्व हो।”

“Nothing can more swiftly emasculate national life, nothing can more surely weaken national character, than allowing the education of the young to be controlled by foreign influences, to be dominated by foreign ideals”—Mrs. Annie Besant. Quoted by Lala Lajpat Rai in *The Problem of National Education in India*, p. 28

### राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धान्त या विशेषताएँ

#### Principles or Characteristics of National Education

भारत के नेताओं और निशाविरोध ने अपने देश के लिए जिस राष्ट्रीय निशा की माँग की, उसके प्रमुख सिद्धान्त अथवा विशेषताएँ दृष्टव्य हैं :—

1. भारतीय नियंत्रण : Indian Control—राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय निशा पर विदेशियों के नियंत्रण को सर्वथा अनुचित बताया और कहा कि इस निशा पर भारतीयों का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। इस सम्बन्ध में भारतीयों के विचारों का प्रकाशन करने हुए, भीमती एनी बेसेंट ने कहा :—“भारतीय शिक्षा—भारतवासियों द्वारा नियंत्रित, भारतवासियों द्वारा निर्मित और भारतवासियों द्वारा संचालित की जानी चाहिए।”

"Indian education must be controlled by Indians, shaped by Indians, carried on by Indians."—Mrs. Annie Besant. Quoted by Lala Lajpat Rai : *op. cit.*, p. 28.

2 शिक्षा के आदर्श : Ideals of Education—राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों को स्पष्ट करने हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा :—"भारतीय शिक्षा को भक्ति, ज्ञान एवं नैतिकता के भारतीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए और उसमें भारतीय धार्मिक भावना का समावेश होना चाहिए।"

3 मातृभूमि के लिए प्रेम : Love for Motherland—भारत की तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली में राजभक्ति की शिक्षा दी जाती थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस शिक्षा को पूर्णतया अनुपयुक्त बताया। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें उनमें अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और आदर की भावनाओं का आविर्भाव हो।

4 राष्ट्रीय चरित्र का विकास : Development of National Character—तत्कालीन शिक्षा, भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करने में असमर्थ थी। अतः श्रीमती एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और उसके उद्देश्य को राष्ट्रीय चरित्र का विकास बताते हुए कहा :—"राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना चाहिए।"

5 ब्रिटिश आदर्शों को समाप्ति : End of British Ideals—अंग्रेजी शिक्षा-भारतवासियों के सम्मुख अंग्रेजी आदर्शों को प्रस्तुत करती थी। ये आदर्श उनके लिए अव्यक्त अहितकर थे। अतः उनका विरोध करते हुए, और भारतीयों के लिए भारतीय आदर्शों को ही उपयुक्त बताते हुए, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा :—"ब्रिटिश आदर्श, ब्रिटेन के लिए अच्छे हैं, किन्तु भारत के लिए भारत के आदर्श ही अच्छे हैं।"

"British ideals are good for Britain, but it is India's ideals that are good for India."—Mrs. Annie Besant. Quoted by Lala Lajpat Rai : *op. cit.*, p. 30.

6 भारतीय भाषाओं पर बल : Stress on Indian Languages—देज के नेताओं ने घोषित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा में भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए और इन्हीं भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि माध्यम में अंग्रेजी के महत्त्व का अन्त कर देना चाहिए।

7 व्यावसायिक शिक्षा पर बल : Stress on Vocational Education—राष्ट्रीय आन्दोलन की एक मुख्य विशेषता थी—स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। यह तभी सम्भव हो सकता था, जब व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करके, भारतीय उद्योगों को उद्यत्तशील बनाया जाता। इसके अनिवार्य, व्यावसायिक शिक्षा



से देश की आर्थिक समस्या का धीरे-धीरे भारतीयों की निर्धनता का समाधान हो सकता था। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय निशा में औद्योगिक और व्यावसायिक निशा की समुचित व्यवस्था पर बल दिया।

8. **पाश्चात्य ज्ञान पर बल : Stress on Western Knowledge**—राष्ट्रीय निशा के समर्थकों का विश्वास था कि आज के वैज्ञानिक युग में भारत का अन्य देशों में सम्पर्क होना अत्यन्त आवश्यक था। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय छात्रों के लिए पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों का अध्ययन करना अनिवार्य था। ताता साजवत राय का विचार था :—“मेरे विचार से भारत में यूरोपीय भाषाओं, साहित्यों और विज्ञानों के अध्ययन को प्रोत्साहित न करने का प्रयास—मूर्खता और पागलपन होगा।”

“In my judgment, it will be a folly and madness to try to discourage the study of European languages, literatures, and sciences in India.”—Lala Lajpat Rai : *op. cit.*, p. 85.

### राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना

#### Establishment of National Educational Institutions

1905 में कर्जुन की नोकुरताही ने बग-बग की घोषणा करके, सम्पूर्ण देश में अमनोप का साम्राज्य स्थापित कर दिया। भारतीयों और विद्यार्थियों ने अपने अमनोप को अभिव्यक्त करने के लिए, मभाएँ की और जनम निकाले। कठोर मासन में विश्वास करने वाले कर्जुन के लिए उनके ये कार्य अमम हो गए। अतः उसने अपना दमन-चक्र आरम्भ किया और छात्रों को राजनीति में पृथक् रहने की आज्ञा दी। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों को निशा-संस्थाओं में निकाल दिया जाएगा। विद्यार्थियों ने इसका उत्तर स्वयं निशा-संस्थाओं का बहिष्कार करके दिया।

इन उत्साही और देश-प्रेमी विद्यार्थियों की निशा का समुचित प्रबन्ध करना—राष्ट्रीय कर्तव्य माना गया। अतः भारत के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय निशा-संस्थाओं की स्थापना की गई। इस कार्य में पहला कदम बंगाल में उठाया गया। यहाँ गुरुदाम बनर्जी की अध्यक्षता में “राष्ट्रीय निशा-प्रचार समिति” (Society for the Promotion of National Education) की सृष्टि की गई। इस “समिति” ने सम्पूर्ण बंगाल में 51 हाई स्कूलों का नव-निर्माण किया। रबीन्द्रनाथ टैगोर, रास-बिहारी घोष और अरविन्द घोष के मयुक्त प्रयानों के परिणामस्वरूप “नेशनल कॉलेज” की स्थापना हुई।

राष्ट्रीय निशा-आन्दोलन का एक अन्य रूप भी परिलक्षित हुआ। 1901 में रबीन्द्रनाथ टैगोर ने दाम्बिनिकेनन नामक स्थान में एक ‘ब्रह्मचर्य आश्रम’ की स्थापना की, जो आज ‘विश्वभारती’ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी समय के आसपास “आर्य-प्रतिनिधि-सभा” ने हरिद्वार और गुरुदास में गुरुकुलों का निशा-वास किया।



# 12

## शिक्षा की प्रगति

### PROGRESS OF EDUCATION (1905-1921)

"It is my wish that there may be spread over the land a network of schools and colleges."—King-Emperor George V

#### विषय-प्रवेश

1904 के "शिक्षा-नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव" में साहें कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना—सरकार का प्रमुख कर्तव्य बताया था। अतः सरकार ने उसके प्रति अधिक ध्यान देना और उस पर अधिक धन व्यय करना आरम्भ कर दिया था। फलस्वरूप, 1905 के बाद प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तीव्रता दृष्टिगोचर हुई। किन्तु, दूसरी समुद्रमाली जनाने का श्रेय प्राप्त हुआ, दिसम्बर, 1911 में भ्रमण के लिए भारत पधारने वाले सम्राट् जार्ज पंचम थे। उनके सम्मानार्थ आयोजित किये जाने वाले दिल्ली दरबार में सम्राट् ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए 50 लाख रुपए की प्रतिष्ठित धनराशि व्यय किए जाने का आदेश देकर, हम देश की जन-साधारण की शिक्षा में अपनी रचि व्यक्त की।

इससे भी अधिक रचि, सम्राट् जार्ज पंचम ने 6 फरवरी, 1912 की कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राण में भारत की जनता को अपना बहुमन देकर व्यक्त की :—  
"मेरी इच्छा है कि सम्पूर्ण देश में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछ जाय, जहाँ से उपयोगी, कृषि और जीवन के समस्त व्यवसायों में कुछ करके दिखाने वाले राजभक्त, निर्भीक और उपयोगी नागरिक, शिक्षा प्राप्त करके निकलें।"

"It is my wish that there may be spread over the land a network of schools and colleges, from which will go forth loyal and

## कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग, 1917-1919 Calcutta University Commission, 1917-1919

सन् 1913 के "शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव" में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की उत्पत्ति एवं विस्तार के लिए अनेक बहुमूल्य विचार व्यक्त किए गए थे। किन्तु इन विचारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए शिक्षाविदों की सम्मति ही आवश्यकता थी। अतएव, एक शिक्षा-आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रमुख विचार दिया। परन्तु, 1914 में आरम्भ होने वाले विश्वयुद्ध ने आयोग की नियुक्ति का असम्भव बना दिया और शिक्षा-सम्बन्धी सब सुधार कामजूर पर लिये रह गए। विश्वयुद्ध की समाप्ति में कुछ पहले भारत-सरकार ने "कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग" की नियुक्ति की।

1. नियुक्ति का कारण—सन् 1916 में कलकत्ता-विश्वविद्यालय के उप-कुलपति सर आमुत्तम मुखर्जी ने विश्वविद्यालय में "स्नातकोत्तर विभाग (Post-Graduate Department)" की स्थापना की। इस विभाग की स्थापना करते, सर आमुत्तम मुखर्जी एक नवीन प्रयोग का उद्घाटन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। उनकी दृष्टि इच्छा थी कि स्नातकोत्तर-शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालय में ही किया जाय। उसी इस इच्छा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ। अतः उसने स्नातकोत्तर-शिक्षण के लिए कलकत्ता-विश्वविद्यालय की क्षमता की जाँच करने के लिए 14 नवम्बर, 1917 को "कलकत्ता विश्वविद्यालय-आयोग" की नियुक्ति की। इस आयोग का अध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय (Leeds University) का उप-कुलपति डा० माइकल सैडलर (Michael Sadler) था। अब उसके नाम पर इस आयोग को "सैडलर आयोग" (Sadler Commission) भी कहा जाता है।

2. जाँच का विषय—"आयोग" की जाँच का विषय था :—"कलकत्ता-विश्वविद्यालय की स्थिति एवं आगामी की जाँच करना, और उससे सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के लिए रचनात्मक नीति पर विचार करना।"

"To enquire into the condition and prospects of University of Calcutta and to consider the question of a constructive policy in relation to the question it presents." *Resolution Appointing the Commission*

"आयोग" की मुख्य परामर्शदायकविद्यालय की स्थिति की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया था। किन्तु, उसे कुलनायक दृष्टि ने अन्य विश्वविद्यालयों की भी जाँच करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। उसने इस अधिकार के सदरभाव किया के अन्तर् उसी की जाँच करने के अधिकार का भी प्रयोग किया। उसने 17 मार्च 1918 तक सर्वेक्षण करते, मार्च 1919 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया।

## आयोग के सुझाव व सिफारिशें

### Suggestions & Recommendations of the Commission

“आयोग” ने शिक्षा के सम्बन्ध सभी जगों के विषय में अपने विचार लगे रखे हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण जगों पर उनके सुझावों और सिफारिशों पर प्रकाश डाल रहे हैं; यथा :—

1. माध्यमिक शिक्षा—“आयोग” ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का मुख्य आधार मानकर, उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए :—

1. विश्वविद्यालय में केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए।
2. स्नातको (Graduates) का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए।
3. इण्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से पृथक् कर दिया जाना चाहिए।
4. इण्टरमीडिएट की शिक्षा के लिए पृथक् इण्टरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए।
5. इण्टरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम—भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए।
6. प्रत्येक प्रान्त में “माध्यमिक और इण्टरमीडिएट शिक्षा-बोर्ड” (Board of Secondary & Intermediate Education) का निर्माण किया जाना चाहिए।
7. माध्यमिक स्कूलों और इण्टरमीडिएट कॉलेजों के नियन्त्रण और निरीक्षण का कार्य उनके बोर्डों को दीया जाना चाहिए।

2. कलकत्ता-विश्वविद्यालय—“आयोग” ने कलकत्ता-विश्वविद्यालय की विभाजन छात्र-संस्था को ध्यान में रखकर, अधोलिखित सिफारिशों की :—

1. इसका में “आवास और शिक्षण” (Residential and Teaching) विश्वविद्यालय की सीद्धान्तिकीय स्थापना की जानी चाहिए।
2. कलकत्ता नगर के सब कॉलेजों की इस प्रकार मजदूरी किया जाना चाहिए कि एक शिक्षण-विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाय।
3. कलकत्ता नगर के आस-पास के कॉलेजों की इस प्रकार मजदूरी किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त स्थानों पर प्रथम नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाय।

3. भारतीय विश्वविद्यालय—“आयोग” ने भारतीय विश्वविद्यालयों के संरचना, शासन आदि के सम्बन्ध में अधोलिखित सुझाव दिए :—

नीच शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्यस्थान

विश्वविद्यालयों की सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर, अधिक स्वतंत्रता  
तथा उत्तमता करना चाहिए।

- 3 विश्वविद्यालयों में "पास कोर्स" (Pass Course) के अलावा "आनर्स  
कोर्स" (Honours Course) का भी प्रचलन किया जाना चाहिए।
- 4 माननीय डा. पाटवर्धन 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए।
- 5 विश्वविद्यालयों में कृषि, कानून, डाक्टरों, अध्यापन, इंजीनियरिंग  
आदि की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 6 विश्वविद्यालयों में अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन की सुविधा  
प्रदान की जानी चाहिए।
- 7 छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में  
"फार्सेटिक प्रसिक्शन-मैनेजर" (Director of Physical Training)  
की नियुक्ति की जानी चाहिए।

4. स्त्री-शिक्षा—“आयोम” में स्त्री-शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से दो  
मुख्य मुद्दाएँ दिए गए हैं :—

1. जो बालिकाएँ 15-16 वर्ष की अवस्था तक बालिकाओं में पढ़ाई  
आधा करना चाहती हैं, उनके लिए “पूरदाह स्कूलों” (Purdah Schools)  
का प्रबंध किया जाना चाहिए।
2. जनकता-विश्वविद्यालय में “स्त्री-शिक्षा की विशिष्ट परिपक्व  
(Special Board of Women's Education) की स्थापना की  
जानी चाहिए। इन “परिपक्व” के द्वारा स्त्रियों की चिह्निता-शिक्षा  
और शिक्षा-प्रतिष्ठान की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

5. मूल्योत्तर—“जनकता-विश्वविद्यालय-आयोम” में उच्च शिक्षा के विस्तार  
और महत्त्व के लिए अभिनवनीय कार्य किया। “आयोम” को केवल जनकता-  
विश्वविद्यालय की स्थिति की ओर करने के लिए नियुक्त किया गया था, किन्तु उसने  
और भी उच्च शिक्षा-विश्वविद्यालयों की ओर करने, भारत के सब विश्वविद्यालयों के  
साथ-साथ में अनुमान मुताब देकर, उनका महत्त्व उत्पन्न किया। उपरान्त इनके  
विषय, विशेष भाग-महत्त्व में “आयोम” के सभी मुद्दों को महत्त्व स्वीकार करके,  
केवल मुद्दा यह था कि भारतीय विश्वविद्यालयों के सभी मुद्दों में सर्व-  
विधायक और अनुमान के भी केवल एक मूल्य।

“आयोम” के मुद्दा-महत्त्वों के कुछ क्षेत्रों की चर्चा करना भी  
साध्यक प्रतीत होता है। भारत में प्रतिष्ठित देश के लिए मानव विश्वविद्यालय  
की स्थापना के मुद्दा में कोई सीमा नहीं थी। “आयोम” का दूसरा मुद्दा  
मुताबक था कि भारतीय शिक्षा के निरीक्षण और नियंत्रण का भार नव-निर्माण

"निधा-बोर्डो" को गीत दिया जाय। "आयोग" के महत्व का विचारहीन अहंकार के विचारानुसार हम गुणाव को विमोचित करने का अहंकार परिणाम नहीं हुआ। इण्डियानोविड कलेजों के परीक्षण में गणना प्राप्त नहीं हुई।

हम प्रकार, यद्यपि "आयोग" के गुणावों में वन-तन कुछ दोष वर्तमान थे, तथापि उमने अपने गुणावों के द्वारा विश्वविद्यालय-शिक्षा में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, वे निरंतरमणोव रहे। उमने गुणाव करने बहुमुख्य थे कि जागामी 30 वर्षों में उमने प्रतिवेदन के पत्रों को उत्पन्न कर निधा-सम्बन्धी गुणावों की समय-समय पर सूचना प्राप्त की गई। "आयोग" के प्रतिवेदन के इसी महत्व पर प्रकाश डालते हुए, अरवर मेहलू ने लिखा है :—“कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग का प्रतिवेदन—गुणाव और सूचना का जनन्त स्रोत रहा है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका महत्व असीम है।”

‘The Report of the Calcutta University Commission has been a constant source of suggestion and information. Its significance in the History of Indian education has been incalculable.’—Arthur Mayhew *The Education of India*, pp 5-6

## शिक्षा की प्रगति Progress of Education

“निधा-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव” और “कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग” के उपर्युक्त विवरण के पश्चात् हम 1905 में 1921 तक की अवधि में भारतीय शिक्षा की प्रगति पर दृष्टिगत कर रहे हैं -

1 प्राथमिक शिक्षा—वर्ष 1904 ई “सरकारी प्रस्ताव” में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना—सरकार का प्रमुख उद्देश्य बताया गया था। उसी समय में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देना आरम्भ किया था। 1905 में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर धन की जाने वाले अनुमानों को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया। 1910 में स्थापित होने वाले “केंद्रीय शिक्षा-विभाग” को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजना बनाने का आदेश दिया गया।

वर्ष 1911 में मोगले ने केंद्रीय सभा में प्राथमिक शिक्षा की प्रगत प्रतिवेदन बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसी वर्ष भारत में महात्मा गांधी का गुनागमन हुआ और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए की अर्जित राशि की स्वीकृति दी। 1913 ई “सरकारी प्रस्ताव” के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई। किन्तु इन सब प्रयासों के बावजूद 1905 में 1921 तक की अवधि में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति अयोग्य नहीं थी। हमका प्रमाण दो हुए, डा० धीरन्दास मुजोराध्याय ने लिखा :—





## UNIVERSITY QUESTIONS

1. "In spite of some defects, it is universally admitted that the 'Calcutta University Commission' wielded the greatest influence on university education in this country."

Comment.

‘कुछ दोषों के बावजूद यह बात सामान्य रूप में स्वीकार की जाती है कि ‘कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग’ ने इस देश की विश्वविद्यालय-शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाला।’ समीक्षा कीजिए।

2. Write a critical note on : "Government Resolution on Educational Policy" of 1913.

1913 के "शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकार की प्रस्ताव" पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

## हार्टोग-समिति, 1929

## HARTOG COMMITTEE, 1929

"Throughout the whole educational system, there is waste and ineffectiveness."—*Hartog Committee Report.*

## विषय-प्रवेश

सन् 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के शासन-स्वरूप को स्वयन्तर्हित करने के विचार में "भारत-सरकार अधिनियम" (Government of India Act) के अनुसार "द्वैध शासन-पद्धति" (Dyarchy) का सूचपात्र किया। भारतवासियों ने शासन की इस नवीन पद्धति में असन्तुष्ट होकर, इसका धीरे-धीरे विरोध किया। इस विरोध के कारणों की जांच करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 8 नवम्बर, 1927 को "सिमन कमीशन" (Simon Commission) की नियुक्ति की।

इस कमीशन की नियुक्ति के समय भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन अत्यन्त तीव्र था और इस देश पर अंग्रेजों द्वारा खोली जाने वाली विदेशी शिक्षा पद्धति की तीव्र आलोचना की जा रही थी। इस आन्दोलन के अंगित्व की जांच करने के लिए "हार्टोग" ने सर फिलिप हार्टोग (Sir Philip Hartog) की अध्यक्षता में एक "सहायक समिति" (Auxiliary Committee) की नियुक्ति की। वही "समिति" भारतीय शिक्षा के इतिहास में "हार्टोग समिति" के नाम से प्रसिद्ध है।

## समिति के सुझाव व सिफारिशें

## Suggestions &amp; Recommendations of the Committee

"हार्टोग-समिति" ने भारतीयों भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में सभी पहलुओं का सम्पूर्ण विचार-विमर्श करके, नवम्बर, 1929 में अपने प्रतिवेदन को "कमीशन"

के समक्ष प्रस्तुत किया। "समिति" ने अपने प्रतिवेदन में 1917 से 1927 तक की अवधि में शिक्षा के अनेक अंगों के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया। उनमें शिक्षा के प्रति भारतीयों की जागरूकता और उसकी समस्याओं को समझने एवं सुलझाने की अभिलाषा पर प्रकाश डाला। उसने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि यद्यपि शिक्षा के सभी अवयवों का विस्तार हुआ है, तथापि उनमें अनेक दोष अवलोकित होते हैं। इन दोषों के निवारण के लिए, "समिति" ने मोटे तौर पर बयान किया :— "हमसे शिक्षा के संगठन के विषय में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इस संगठन के प्रत्येक पक्ष पर पुनर्विचार करने एवं उसकी शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा के संगठन के लिए जो संस्थाएँ उत्तरदायी हैं, उनके सम्बन्धों को पुनर्निर्धारित करना अनिवार्य है।"

"We were asked to report on the organization of education. At almost every point that organization needs reconsideration and strengthening, and the relations of the bodies responsible for the organization of education need re-adjustment."—*Hartog Committee Report*, p. 346

भारतीय शिक्षा के दोषों का निवारण करने के लिए मुख्य उपायों का उल्लेख करने के पश्चात् "समिति" ने शिक्षा के विविध अंगों के दोषों और उन दोषों के निराकरण के उपायों के सम्बन्ध में अपने सुझावों और गिफारिशों को अधारबद्ध किया। हम इनमें से महत्त्वपूर्ण का वर्णन अधोलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर रहे हैं; यथा :—

## 1 प्राथमिक शिक्षा : Primary Education

"समिति" ने यह स्वीकार किया कि यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो रहा था, तथापि यह सन्तोषजनक नहीं था। 'समिति' ने हमारे दो मुख्य कारण बताए— अव्यय्य और अवरोधन। उनमें पहले इन दोनों के अर्थ का स्पष्टीकरण किया, फिर इनके कारण बताए और अन्त में इन कारणों के निवारण के लिए प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपने सुझावों एवं गिफारिशों को लिखित रूप प्रदान किया, यथा :—

1 "अव्यय्य" व "अवरोधन" का अर्थ Meaning of 'Wastage' & 'Stagnation'— "समिति" के विचारानुसार प्राथमिक शिक्षा में "अव्यय्य" और "अवरोधन" की समस्याएँ अत्यन्त विचलित थीं। इन दोनों समस्याओं के अर्थ को "समिति" ने निम्नलिखित प्रकार में स्पष्ट किया —

(1) " 'अव्यय्य' से हमारा अभिप्राय है—प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों की विद्यालय की हितों को बहा से हटा लेना। "

"By 'wastage' we mean the premature withdrawal of children from school at any stage before the completion of the primary course."—*Hartog Committee Report*, p. 47.



3. सुझाव प सिफारिशें : Suggestions & Recommendations—  
 "गमिति" ने "अवब्यय" और "अवरोधन" के कारणों को दूर करने और प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करने के लिए अग्रनिश्चित विचार व्यक्त किए:—

1. प्राथमिक विद्यालयों की गुणात्मक (Qualitative) वृद्धि की ओर गुणात्मक (Qualitative) उन्नति पर बल दिया जाना चाहिए।
2. प्राथमिक शिक्षा की टोंग (Consolidation) बनाने की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए।
3. उन विद्यालयों को जो छोटे हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या कम है और जिनमें शिक्षण की उचित व्यवस्था नहीं है, उनको मग कर दिया जाना चाहिए।
4. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की अवधि कम-से-कम 4 वर्षों की होनी चाहिए और उनके शिक्षण स्तर का उन्नयन किया जाना चाहिए।
5. प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम को उदार एवं व्यापक और वातावरण एवं परिस्थिति के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
6. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण का समय, छुट्टियों और अन्य कार्यक्रमों की स्थानीय श्रुतियों और आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।
7. प्राथमिक विद्यालयों की निम्नतम कक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसमें होने वाले "अवब्यय" एवं "अवरोधन" का निराकरण करने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए।
8. प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य, गठराशना, आत्म-विश्वास आदि गुणों का विकास किया जाना चाहिए।
9. प्राथमिक विद्यालयों को मनोरंजन, ग्राम सुधार, व्यवस्था-शिक्षा और माध्यामिक चरित्रता के केन्द्र बनाया जाना चाहिए।
10. शिक्षा के निष्पन्न-स्तर का उन्नयन करने के लिए, उनके प्रशिक्षण-काल में वृद्धि की जानी चाहिए।
11. शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और उनकी कार्य-स्थल की सुविधाओं में सुधार करके, दोष व्यवस्था की निष्पन्न-स्तरों के प्रति आकर्षित किया जाना चाहिए।
12. प्रशिक्षण-विद्यालयों में सुधार किया जाना चाहिए और उनमें "जीवन-नयन-आदर्शकों" (Reflected Coaches) की योजना आरम्भ की जानी चाहिए।

## 2. माध्यमिक शिक्षा : Secondary Education

“हर्टीग-समिति” ने माध्यमिक शिक्षा के दो प्रमुख दोष बताए :—  
 मेट्रीकुलेशन परीक्षा की प्रधानता, और (2) अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की विशाल संख्या। माध्यमिक शिक्षा को इन दोषों से मुक्त करने के लिये, “समिति” ने अधोलिखित सुझाव दिये :—

1. मिडिल स्कूलों का पाठ्यक्रम इतना संकीर्ण है कि उसका अध्ययन करने के पश्चात् विद्यार्थी किसी भी जीवनोपयोगी कार्य को नहीं कर सकते हैं। अतः पाठ्यक्रम का विस्तार करके, उसमें इस प्रकार के विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए, जो विद्यार्थियों को धन का उपार्जन करने में सहायता दें।
2. मिडिल स्कूल का पाठ्यक्रम समाप्त करने के उपरान्त विद्यार्थियों की परीक्षा ली जानी चाहिए और उसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उन उद्योगों एवं व्यवसायों की शिक्षा दी जानी चाहिये, जिनके लिये उनकी उपयुक्त समझा जाय।
3. हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों का समावेश किया जाना चाहिये और विद्यार्थियों को उनका अध्ययन करने के लिये उत्प्रेरित किया जाना चाहिए।
4. हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के वैकल्पिक विषयों का समावेश किया जाना चाहिए, जिनसे विद्यार्थियों को लाभ हो और जिनका अध्ययन वे अपनी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार कर सकें।
5. शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये। साथ ही, प्रशिक्षण-विद्यालयों को बढ़ावा देकर, उनमें शिक्षण की नवीनतम विधियों का प्रयोग करने का अवसर मिले।

समय का नोटिस देकर अपने पद से हटा दिया जाता है। इन सब दोषों को दूर करके, शिक्षक के पद को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

### 3. विश्वविद्यालय शिक्षा : *University Education*

"हर्टिंग-समिति" ने विश्वविद्यालय-शिक्षा की जांच करने के पश्चात् उनमें व्याप्त दोषों का ज्ञान प्राप्त किया :—शिक्षण का निम्न स्तर, छात्रों की संख्या में वृद्धि, "आनर्स कोर्स" की अनुपयुक्त व्यवस्था, अनुत्तीर्ण छात्रों की अत्यधिक संख्या, स्नातको में बढ़ती हुई बेरोजगारी, उत्तम पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का अभाव, इत्यादि।

"समिति" ने विश्वविद्यालय-शिक्षा को उक्त दोषों से रहित करने के निम्नलिखित सुझाव दिए —

1. उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं एकतात्मक (Teaching & Unity) विश्वविद्यालय सर्वोत्तम होते हैं। परन्तु, भारत की परिस्थितियों को देखते हुए, अभी सम्बद्धक (Affiliating) विश्वविद्यालयों की पर्याप्त संख्या तक आवश्यकता रहेगी। अतः देन में दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
2. विश्वविद्यालयों के शिक्षा-स्तर का उपग्रहण किया जाना चाहिए। इससे विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के अलावा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का भी हित होगा।
3. विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने के नियमों की कड़ा बना दिया जाना चाहिए और उनमें केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, जिनमें उच्च शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता हो।
4. विश्वविद्यालयों को उत्तम पुस्तकालयों, सुसज्जित प्रयोगशालाओं और श्रेष्ठ अनुसंधान-शालों की अनिवार्य रूप से समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।
5. विश्वविद्यालयों में "आनर्स कोर्स" के शिक्षण का उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए और उसे 'पान कोर्स' में वृद्धि रखा जाना चाहिए। "आनर्स कोर्स" की गणना के लिए विश्वविद्यालय और उनमें सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों पर सम्मिलित उत्तरदायित्व रखा जाना चाहिए।
6. स्नातको की बढ़ती हुई बेरोजगारी का अन्त करने के लिए, विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रचलन किया जाना चाहिए। इस शिक्षा को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों दी जानी चाहिए।
7. स्नातको की अपनी योग्यताओं के अनुकूल नौकरियों प्राप्त करने में

महायता देने के लिए, विश्वविद्यालयों में "रोजगार के कार्यालयों" (Employment Bureaus) की सृष्टि की जानी चाहिए।

8. विश्वविद्यालयों का एक महत्वपूर्ण कार्य—जनसाधारण में ज्ञान का विस्तार करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालयों में व्याख्यान-मालाओं की योजना आरम्भ की जानी चाहिए।

### हार्टग-समिति का मूल्यांकन

#### Estimate of Hartog Committee

"हार्टग-समिति" के प्रतिवेदन का भारतीय शिक्षा के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। "समिति" ने शिक्षा के अनेक अवयवों के जिन दोषों की ओर संकेत किया, वे सभी स्पष्ट और सर्वविदित थे। उसने इन दोषों को दूर करने और शिक्षा के पुनर्संयोजन के सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिए, वे उसके विवेक और दूरदर्शिता के प्रमाण थे। ये सभी सुझाव उसके इस निष्कर्ष पर आधारित थे कि शिक्षा की गुणात्मक उन्नति का बलिदान करके, उसका संख्यात्मक विस्तार किया गया था। अतः उसने पूर्ण विश्वास से यह विचार व्यक्त किया कि शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार पर स्थायी अंकुश लगा कर, पहले उसकी गुणात्मक उन्नति की जाय।

"समिति" के इस विचार का भारत में मिश्रित स्वागत हुआ। भारतीय जनता ने शिक्षा के गुणात्मक उन्नति के सुझाव की निन्दा की। उसका कहना था कि यह सुझाव इसलिए दिया गया था, ताकि इस देश में शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध हो जाय। इसके विपरीत, भारत-सरकार ने इस सुझाव की प्रशंसा की। उसका कहना था कि शिक्षा का संख्यात्मक विस्तार करने से पूर्व उसकी गुणात्मक उन्नति की जानी अत्यन्त आवश्यक है। इस सुझाव ने सरकार की प्रतिनिधि शिक्षा-नीति को निश्चित रूप प्रदान किया। उसने इस सुझाव की आड़ में शिक्षा के प्रसार को रोक दिया और वह लगभग 20 वर्ष तक अर्थात् 1947 तक रुका रहा। डा० एस० एन० मुकर्जी के अंशकित वाक्य से हमारे कथन को बल प्राप्त होता है :—"हार्टग-समिति के प्रतिवेदन ने इस देश में अपने जीवन के अन्तिम दो दशकों में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा-नीति का बहुत-कुछ निर्माण किया।"

"The Hartog Committee Report more or less shaped the educational policy of British Government during the last two decades of its existence in this country."—Dr. S. N. Mukerji : *History of Education in India* p. 228.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. What were the views of the Hartog Committee on "Wastage" and "Stagnation" in Primary Education? What measures did it suggest to overcome them?



प्राथमिक शिक्षा में "अप्यय" और "अवरोधन" के विषय में हर्दग-समिति के क्या विचार थे ? उसने उनके समाधान के लिए क्या उपाय बताए ?

2. Summarize and criticise the main recommendations of the Hartog Committee and say how far they have influenced the modern conception of Secondary Education in India.

हर्दग-समिति की मुख्य सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और उनकी आलोचना कीजिए । बताइए कि उन्होंने भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान धारणा को वहाँ तक प्रभावित किया है ?

## वुड-एवट रिपोर्ट, 1937

### WOOD-ABBOTT REPORT, 1937

"Vocational education should not be regarded as being on a lower plane than literary education."

—Wood-Abbott Report.

#### विषय-प्रवेश

हर्टाग-समिति की सिफारिश के फलस्वरूप भारत-सरकार ने सन् 1935 में "केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड" (Central Advisory Board of Education) की पुनः स्थापना की। इस "बोर्ड" ने दिसम्बर, 1935 की अपनी पहली बैठक में शिक्षा-सुधार के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव पारित किए। उनमें से एक प्रस्ताव यह था :—"छात्रों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्राविधिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय।"

"बोर्ड" के उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार करके, भारत-सरकार ने 1936 में इंग्लैंड के दो प्रसिद्ध शिक्षा-विशेषज्ञों को भारत आने के लिए आमन्त्रित किया। ये विशेषज्ञ थे :—

1. एस० एच० वुड, इंग्लैंड के शिक्षा-बोर्ड का डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस (S. H. Wood, Director of Intelligence, Board of Education).
2. ए० एवट, इंग्लैंड के शिक्षा-बोर्ड के प्रौद्योगिक स्कूलों का भूतपूर्व चीफ-इंस्पेक्टर (A. Abbott, Ex-Chief Inspector of Technical Schools, Board of Education).

## जॉच के बिषय

### Terms of Reference

भारत-सरकार ने उपर्युक्त दो विनियमों की समिति में 4 बातों की जाँच करने के लिए कहा; यथा :—

1. क्या वर्तमान औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार दिया जाना चाहिए ?
2. क्या नवीन औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए ?
3. काम के बावनों के लिए दिन प्रारंभ की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ?
4. क्या प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों में किसी प्रकार का व्यावसायिक या व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप और विस्तार क्या होना चाहिए ?

"Whether any vocational or practical training should be imparted in primary, secondary, and higher secondary schools, and if so, what should be its nature and extent ?"—*Resolution Appointing the Committee.*

## वुड-एबट रिपोर्ट

### Wood-Abbott Report

वुड और एबट नवम्बर, 1936 में मार्च, 1937 तक भारत में रहे। उनके काम समय का अन्त था। अब उन्होंने स्वयं शिक्षा, स्वास्थ्य और मनुष्य प्रशिक्षण करने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया और जून, 1937 में अन्तिम रिपोर्ट को भारत-सरकार के पास प्रेषित किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक है :— "Vocational Education in India with a Section on General Education and Administration" यह रिपोर्ट - वुड-एबट रिपोर्ट" के नाम से प्रसिद्ध है। यह दो भागों में विभक्त है; यथा :—

1. वुड द्वारा लिखा - 'सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन' (General Education & Administration)
2. एबट द्वारा लिखा - 'व्यावसायिक शिक्षा' (Vocational Education)

हम इस दोनो भागों से अतिव्यक्तिगत रूप से शिक्षा के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं।

## 1. सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिश

### Recommendations on General Education

1. विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की अवधि इस प्रकार होनी चाहिए :—  
(i) प्राथमिक शिक्षा—4 वर्ष; (ii) निम्न माध्यमिक शिक्षा—4 वर्ष;  
(iii) उच्च माध्यमिक शिक्षा—6 वर्ष, (iv) स्नातक-शिक्षा—3 वर्ष।
2. शिशु-शिक्षा (Infant Education) की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए और शिशु-कक्षाओं के लिए केवल प्रशिक्षित अध्यापिकाएँ नियुक्त की जानी चाहिए।
3. प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा को पुस्तकों पर आधारित न करके, बालकों की स्वाभाविक रुचियों, क्रियाओं और प्रवृत्तियों पर आधारित किया जाना चाहिए।
4. निम्न माध्यमिक (Lower Secondary) कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा पर बल नहीं दिया जाना चाहिए।
5. उच्च माध्यमिक (Higher Secondary) कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
6. हाई स्कूल तक की शिक्षा—भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए।
7. अंग्रेजी की शिक्षा को साहित्यिक रूप न देकर, अधिक व्यावहारिक बनाने का यत्न किया जाना चाहिए।
8. रचनात्मक हस्तकार्य (Constructive Handwork) की शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उसकी शिक्षा सभी विद्यालयों में दी जानी चाहिए।
9. सज्जित कलाओं (Fine Arts) की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनके शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
10. ग्रामों के मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में वहाँ की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यविषयों को स्थान दिया जाना चाहिए।
11. विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए विद्यालय-निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनको कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए।
12. अध्यापकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक कम-से-कम मिडिल पास होने चाहिए। उनके प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए और उनके लिए "अभिनवन पाठ्यक्रमों" (Refresher Courses) का आयोजन किया जाना चाहिए।

## २. व्यावसायिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें

### Recommendations on Vocational Education

1. माध्यमिक शिक्षा का प्रसार देना ही औद्योगिक आवश्यकताओं का, में रण कर दिया जाना चाहिए।
2. व्यावसायिक शिक्षा को यही पद प्रदान दिया जाना चाहिए, जो साहित्यिक शिक्षा को प्राप्त है।
3. व्यावसायिक शिक्षा प्रकृष्ट करने वाले विद्यालयों को जीविकोपार्जन के उद्देश्य से व्यवसाय का चयन करने में सहायता देने के लिए उचित परामर्श दिया जाना चाहिए।
4. देश के विभिन्न प्रांतों में व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप वही के उद्योगों, व्यापारों और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निश्चित किया जाना चाहिए।
5. सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा को एक-दूसरे से भिन्न नहीं समझा जाना चाहिए, अपितु उनको निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया का पूर्ववर्ती एवं परवर्ती चरण समझा जाना चाहिए।
6. सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यमों एवं तरीकों में अन्तर है। अतः दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए अलग-अलग विद्यालयों की सृष्टि की जानी चाहिए।
7. कुटीर उद्योग-धन्धों में सलग्न व्यक्तियों को उपयुक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. उद्योग तथा व्यापार और उद्योग तथा शिक्षा में निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रांत में "व्यावसायिक शिक्षा की सलाहकार समिति" (Advisory Council for Vocational Education) का अनिवार्य रूप से निर्माण किया जाना चाहिए।
9. कम-से-कम 50 हजार जनसंख्या वाले औद्योगिक प्रदेशों में जूनियर और सीनियर टेक्निकल स्कुलों की सृष्टि की जानी चाहिए।
10. व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समाप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र (Certificates) दिए जाने चाहिए।
11. उद्योगधन्धों द्वारा धन, सामग्री और भवन देकर व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
12. विभिन्न व्यवसायों में सराफ़ व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए अल्पकालिक (Part-Time) व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को उनके स्वामियों द्वारा एक महीना में छई दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए।

13. ग्राम के निवासियों का प्रधान व्यवसाय—कृषि है। अतः ग्रामों में स्थापित किए जाने वाले निम्न और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि की शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए एवं इस विषय के शिक्षण का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए।
14. भारत-सरकार को एक व्यावसायिक प्रशिक्षण-महाविद्यालय (Vocational Training College) की स्थापना करनी चाहिए, जिसका अन्य प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण-महाविद्यालयों से सम्बन्ध होना चाहिए।
15. भारत-सरकार को अग्रलिखित प्रकार के पूर्णकालिक (Full-Time) व्यावसायिक स्कूलों का गिलान्यास करना चाहिए :—(i) प्राथमिक शिक्षा-प्राप्त छात्रों के लिए "ट्रेड स्कूल" (Trade Schools), (ii) आठवीं कक्षा पास छात्रों के लिए "जूनियर वोकेशनल स्कूल" (Junior Vocational Schools), (iii) दसवीं कक्षा पास छात्रों के लिए "सीनियर वोकेशनल स्कूल" (Senior Vocational Schools), और (iv) बी० एस०-सी० पास छात्रों के लिए "प्रौद्योगिक संस्थान" (Technological Institutes)।

### वुड-एबट रिपोर्ट का मूल्यांकन

#### Estimate of Wood-Abbott Report

समय का अभाव होने के कारण वुड और एबट ने सम्पूर्ण भारत की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का निरीक्षण किए बिना अपने प्रतिवेदन को अत्यन्त अल्प काल में तैयार किया। पर, क्योंकि इन दोनों शिक्षा-विचारकों की अपने समय के विवेचनों में गणना थी, अतः उन्होंने केवल दिल्ली, पंजाब और संयुक्त प्रान्त की विभिन्न परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन करके, समस्त देश की शिक्षा की वास्तविक स्थिति का बहुत-कुछ मूल्य अनुमान लगा लिया। अपने इसी अनुमान के आधार पर उन्होंने सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के विषय में अत्यन्त विवेकपूर्ण और व्यावहारिक सिद्धांतों को अपने प्रतिवेदन में निगमवद्ध किया और भारत-सरकार ने उसी उपयोगिता को अंगीकार किया। अतः जैसा कि डा० श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है :—“इस प्रतिवेदन की सिद्धांतियों के फलस्वरूप भारत में कुछ औद्योगिक एवं व्यावसायिक विद्यालय खोले गए। उनके साथ-साथ देश में सर्वप्रथम बहु-उद्योगीय विद्यालय अस्तित्व में आया। यह संस्था है—दिल्ली पॉलीटेक्नीक।”

भारत-सरकार—“वुड-एबट प्रतिवेदन” की कुछ ही सिद्धांतियों को कार्यान्वित कर पाई थी कि मई 1939 में द्वितीय विश्व-युद्ध के आकस्मिक विस्तार ने सम्पूर्ण विश्व में संघटनकारी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। उस परिस्थिति में ब्रिटेन—यूरोप में अपने अनुश्रुतों के विरुद्ध और उस देश में “भारत छोड़ो” आन्दोलन के विरुद्ध—दो मोर्चों पर संघर्ष करने में कम-कम से मुँटे हुए थे। अतः उन्होंने “वुड-

एबट प्रतिवेदन" को बन्द करके, एक और राय दिया। इन प्रकार, वाग-वक्त्र ने "प्रतिवेदन" के महत्व को नष्ट कर दिया और भाव भी इगना कोई महत्व नहीं है। नूतनता व नायक ने तथ्य ही लिया है। — "इस समय गुड और एबट के प्रतिवेदन का ऐतिहासिक महत्व के अभाव और कोई महत्व नहीं है।"

"Today, the report of Messrs. Wood and Abbott has hardly any, except a historical, importance"—Nurullah & Naik : *A History of Education in India*, p. 788.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Summarize the views expressed by Messrs. Wood and Abbott on the development of general education in this country

इस देश में सामान्य शिक्षा के विकास के लिए गुड और एबट द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों को संक्षेप में लिखिये।

2. Summarize the views expressed by Messrs. Wood and Abbott on the development of vocational education in India. How far were they put into practice?

भारत में व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए गुड और एबट द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को संक्षेप में लिखिये। उनमें कहीं तक कार्यान्वित किया गया?

# 15

## शिक्षा की प्रगति PROGRESS OF EDUCATION (1921-1947)

"It was under *Diarchy* that Indians first obtained the control of the Education Department."

—Nurullah & Naik.

### विषय-प्रवेश

हम सुविधा की दृष्टि से 1921 में 1947 तक की शिक्षा की प्रगति का वर्णन निम्नांकित दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर रहे हैं :—

1. द्वैध-शासन (Diarchy) में शिक्षा की प्रगति (1921-1937) ।
2. प्रांतीय स्वशासन (Provincial Autonomy) में शिक्षा की प्रगति (1937-1947) ।

### द्वैध-शासन में शिक्षा की प्रगति

#### Progress of Education under Diarchy

1919 के "भारत-सरकार-अधिनियम" (Government of India Act) के अनुसार इस देश में 1921 में "द्वैध-शासन" अर्थात् "दोहरे शासन" की व्यवस्था की गई । "दोहरे शासन" का अभिप्राय यह था कि प्रांतों के प्रशासकीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था—संरक्षित और हस्तान्तरित (Reserved & Transferred) । संरक्षित विषयों पर अंग्रेज मंत्रियों का अधिकार था, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे । हस्तान्तरित विषयों पर लोकप्रिय भारतीय मंत्रियों का अधिकार था, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे । उदाहरणार्थ—वित्त-विभाग, अंग्रेज मंत्रियों को और शिक्षा-विभाग, भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था ।



इस परिस्थिति में, शिक्षा-मंत्रियों की अपनी शिक्षा-संरचनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक मंत्रियों का मुँह देगना पड़ता था, जो उनकी योजनाओं के प्रति सामान्यतः उदासीन रहते थे। फिर भी, उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन और शिक्षा के प्रति अपने देशवासियों की जागरूकता से प्रेरणा प्राप्त करके, शिक्षा के विस्तार के लिए यथानक्ति प्रयास किए। किन्तु, उनको अपने प्रयासों के अनुसार में सफलता प्राप्त नहीं हुई और सरकार पूर्ण की नीति प्राथमिक शिक्षा की उद्देश्य करने, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विस्तार में व्यस्त रहो। हम द्विप-काल (1921-1937) में शिक्षा की प्रगति का वर्णन अपोनिमिड शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं।

### 1 प्राथमिक शिक्षा : Primary Education

इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित दो विधेयकान् उल्लेखनीय हैं— प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए पारित किए जाने वाले “प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम” (Primary Education Acts) और प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में निमित्तता।

1. प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम—इस अवधि में बम्बई, आन्ध्र, मद्रास प्रान्त और बंगाल में “प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम” बनाकर, इस शिक्षा की अनिवार्य कर दिया गया। इनमें पूर्व भी कुछ प्रान्तों में इस प्रकार के अधिनियम लागू किए जा चुके थे। हम इन अधिनियमों का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य में इनका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं (Nurullah & Naik, p. 662), यथा—

1. सन् 1919 में पंजाब में सब बालकों और बालिकाओं के लिए।
2. सन् 1919 में मद्रास प्रान्त में केवल सहरी बालकों और बालिकाओं के लिए।
3. सन् 1919 में बंगाल में केवल सहरी बालकों के लिए।
4. सन् 1919 में बिहार और उड़ीसा में केवल सब बालकों के लिए।
5. सन् 1920 में बम्बई में केवल बम्बई नगर के सब बालकों और बालिकाओं के लिए।
6. सन् 1920 में मध्य प्रान्त में सब बालकों और बालिकाओं के लिए।
7. सन् 1920 में मद्रास में सब बालकों और बालिकाओं के लिए।
8. सन् 1923 में बम्बई में बम्बई नगर के अलावा सब बालकों और बालिकाओं के लिए।
9. सन् 1926 में आन्ध्र में सब बालकों और बालिकाओं के लिए।
10. सन् 1926 में मद्रास प्रान्त में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों और बालिकाओं के लिए।
11. सन् 1930 में बंगाल में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों और बालिकाओं के लिए।

## 2 | भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

2. प्राथमिक शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा के अधि-  
यमों के बावजूद इस शिक्षा की संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। इसके कारणों पर  
विशेष ध्यान देने हुए, डा० श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है :—“सन् 1931-37 के  
बीच सम्पूर्ण जगत् में एक विश्व-व्यापी मन्दी छा गयी। इस कारण किसी भी शिक्षा-  
यात्रना को चलाना सम्भव था। इसके अतिरिक्त, हर्टीग-मिसिती की सिफारिशों के  
अनुसार सरकार ने ठोस नीति अपनाई। इसके अनुसार जहाँ तक बन सका, नए स्कूल  
स्थापित नहीं हुए, एवं कमजोर स्कूलों का पोषण कर दिया।” इस अवधि में प्राथमिक  
शिक्षा की प्रगति का अनुमान निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है (Nurullah  
& Naik p. 680) :—

	1921-1922	1936-1937
1. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1,55,017	1,92,244
2 छात्रों की संख्या	61,09,752	1,02,24,288

## 2. माध्यमिक शिक्षा : Secondary Education

इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की दो विशेषताएँ हमारे ध्यान को आकृष्ट  
करती हैं—माध्यमिक शिक्षा की अनेक दिशाओं में उन्नति और माध्यमिक शिक्षा की  
तीव्र प्रगति।

1. माध्यमिक शिक्षा की उन्नति—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की अग्रो-  
न्त दिशाओं में उन्नति परिलक्षित हुई :—(1) विश्वविद्यालयों और शिक्षा-विभागों  
का संयोग सम्पन्न हो गया। फलतः विश्वविद्यालयों ने शिक्षा-विभागों द्वारा स्वीकृत  
हर्टी स्कूलों की मान्यता प्रदान कर दी। (2) अंग्रेजी पर कम दल दिए जाने के कारण  
मान्यता प्राप्त शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। (3) पाठ्यक्रमों का विस्तार करने  
उपलक्ष्य नवीन विषयों का समावेश किया गया। (4) कृषि, तकनीकी और अन्य व्या-  
वसायिक विद्यालयों की स्थापना हुई। (5) विद्यालयों की सामग्री और उपकरणों  
प्रति विशेष ध्यान दिया जाने लगा।

2. माध्यमिक शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की  
अत्यन्त तीव्र प्रगति ने हुई। इसके तीन प्रधान कारण थे : पहला, जनसाधार-  
जागृति होने के कारण माध्यमिक शिक्षा की माँग में वृद्धि हुई। दूसरा, प्रा-  
प्त माध्यमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के निमित्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में  
माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। तीसरा, स्त्रियों और पिछड़ी जा-  
तों में माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने की नीति अपनाई गई। इन कारणों के फलस्वरूप  
जर्मनी में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति हुई, उसे अग्रोन्त मानिकता में  
गया है (Nurullah & Naik, p. 646) :—

	1921-1922	1936-1937
1. माध्यमिक स्कूलों की संख्या	7,530	13,056
2. छात्रों की संख्या	11,06,803	22,87,872

### 3 उच्च शिक्षा : Higher Education

इस अवधि में उच्च शिक्षा की सर्वाधिक और अनेकगुनी प्रगति हुई; यथा :—

1 नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना—सन् 1913 के “शिक्षा-सम्बन्धी सरकारों प्रस्ताव” की सिफारिश के अनुसार, इस अवधि में 5 नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई, यथा —(1) दिल्ली विश्वविद्यालय, 1922; (2) नागपुर विश्वविद्यालय, 1923, (3) आंध्र विश्वविद्यालय, 1926; (4) आगरा विश्वविद्यालय, 1927; और (5) अमृतसर विश्वविद्यालय, 1929।

2 पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्संरुद्धन—इस अवधि में पुराने विश्वविद्यालयों में सुधार करके, उनका पुनर्संरुद्धन किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय में विज्ञान के “आनर्स कोर्स” का विस्तार करके, उसे अधिक व्यापक बनाया गया। मद्रास विश्वविद्यालय में विज्ञान के अन्तर्गत अनेक नवीन विषयों की स्थापना देकर, उनके शिक्षण एवं अनुसंधान का प्रबंध किया गया। बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और औद्योगिक शिक्षा का आयोजन करके, शिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया गया। इस विश्वविद्यालयों के असावा पटना और बनारस विश्वविद्यालयों का भी पुनर्संरुद्धन करके, उनकी कार्य-क्षमता में अभिवृद्धि हो गई।

3 उच्च शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में विश्वविद्यालय और कॉलेज-शिक्षा की आवश्यकजनक प्रगति हुई। इस समय का स्स्थीकरण निम्नांकित तालिका में कर रहे हैं (Nurullah & Naik, pp 631 & 632) —

	1921-1922	1936-1937
1. विश्वविद्यालयों की संख्या	12	17
2. कॉलेजों की संख्या	207	366
3. विश्वविद्यालयों व कॉलेज-छात्रों की संख्या	66,258	1,26,228

### प्रान्तीय स्वायत्तता में शिक्षा की प्रगति

Progress of Education under Provincial Autonomy

1935 के “शासन-कारण-अधिनियम” (Government of India Act) के अनुसार इस देश में 1937 में “प्रान्तीय स्वायत्तता” की स्थापना हुई। “प्रान्तीय स्वायत्तता” का अन्विष्ट यह था कि प्रान्त के मन्त्रिमंडल प्रशासकीय क्षेत्र पर सरकारों

4 | भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

मन स्वाधित हो गया। फलस्वरूप, "द्वैध शासन" का अन्त हो गया, संरक्षित और स्वातंत्र्य विषयों का भेद समाप्त हो गया और प्रान्त के समस्त विषयों पर सक्रिय भारतीय मन्त्रियों का अधिकार हो गया।

इस परिस्थिति में शिक्षा-मन्त्रियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता के वातावरण में अपना कार्य आरम्भ किया। किन्तु, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए 1939 में आरम्भ होने वाले द्वितीय विश्व-युद्ध में भारत को फँसा दिया। उनकी इस निष्ठुर नीति के विरोध में 1937 में 6 प्रान्तों में पद-ग्रहण करने वाले कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने अपने त्याग-पथ दे दिए। युद्ध के उपरान्त, 1946 में 8 प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल फिर स्थापित हुए।

इस प्रकार, "प्रान्तीय स्वाशासन" की 10 वर्ष की अवधि में लगभग 3 वर्ष ही प्रान्तीय शासन का मूल भारतीय मन्त्रियों के हाथ में रहा। अतः इस अल्प काल में वे शिक्षा का उतना विस्तार न कर सके, जितनी कि उनकी आशा की गई थी। फिर भी, उन्होंने 'प्रान्तीय स्वाशासन' (1937-1947) की अवधि में शिक्षा की प्रगति में योग देने का प्रयास किया। हम इस प्रगति के विविध अंगों पर निम्नांकित पंक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं।

### 1. केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-सम्बन्धी कार्य

Educational Activities of the Central Government

1919 के "अधिनियम" के अनुसार, शिक्षा का अधिकांश भार प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया था। परिणामतः केन्द्रीय सरकार—शिक्षा के क्षेत्र से पृथक् हो गई थी। 1935 के "अधिनियम" के अनुसार, शिक्षा-सम्बन्धी सब कार्यों को दो स्पष्ट भागों में विभक्त कर दिया गया—केन्द्रीय और प्रान्तीय। फल-स्वरूप, 1937 से शिक्षा-विषयक कार्यों का उत्तरदायित्व पुनः केन्द्रीय सरकार पर आ गया। इन कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पादित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कतिपय समितियों और मंस्याओं का निर्माण किया, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

1. केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड : Central Advisory Board of Education—इस बोर्ड का निर्माण सन् 1920 में केन्द्रीय और प्रान्तीय शिक्षा-समितियों में नामजस्त्य स्थापित करने और प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देने के उद्देश्य से किया गया था। यद्यपि इस बोर्ड ने अत्यन्त लामप्रकार्य किया था तथापि व्यय में कमी करने के विचार से केन्द्रीय सरकार ने 1922 में इसको भंग कर दिया था।

"होर्टन-समिति" की मिकारिज के फलस्वरूप इस बोर्ड को 1935 में पुनर्गठित किया गया। उसी समय से यह बोर्ड भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुधारपूर्वक सम्पन्न करता आ रहा है। इस बोर्ड के चार मुख्य कार्य हैं—

(1) अपने वार्षिक अधिवेशन में सन्तुलित भारत की शिक्षा की स्थिति और प्रगति

करना, (2) प्रांतीय सरकारों को निधा-प्रकार के विषय में समय-समय पर देना, (3) निधा-विषयक समस्याओं का समाधान करने के लिए विनिर्दिष्ट धन की निगुक्ति करना, और (4) निधा के विभिन्न प्रकार के संचयन में धन को प्रयोजित करना।

2. केन्द्रीय निधा-सचिवालय : Central Secretariat of Education—सचिवालय की स्थापना मई 1945 में "केन्द्रीय निधा-महाद्वार बोर्ड" को अधिन के फलस्वरूप हुई थी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् मई 1947 में इसको शिक्षा-मन्त्रालय में आग बसा दिया गया। इसका सर्वप्रमुख कार्य—मग्नपूर्ण भारत की "सचिवालय" का सर्वोच्च अधिकारी—निधा-महाद्वार (Educational Adviser) है। यह निधा-मन्त्रालय के सचिव का भी कार्य करता है। यह निधा-मन्त्री को मग्नपूर्ण देश की निधा-नीति एवं प्रशासन के विषय में परामर्श देता है।

3. केन्द्रीय निधा-सूचना-कार्यालय : Central Bureau of Education—इस कार्यालय के मुख्य कार्य अज्ञात हैं—(1) देश-विदेश में निधा-सम्बन्धी जाँचों और समाधानों का संचालन करना, (2) प्रांतीय सरकारों और निधा-सम्बन्धी की निधा-विषयक समस्याओं का समाधान करना, (3) सरकार की निधा-सम्बन्धी रिपोर्टों को प्रकाशित करना और (4) निधा-सम्बन्धी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

4. विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग : University Grants Commission—"केन्द्रीय निधा-महाद्वार बोर्ड" की अधिन के परिणामस्वरूप मई 1945 में "विश्वविद्यालय अनुदान-मार्मिति" (University Grants Committee) की गृष्टि की गई। तीन वर्ष पश्चात् गणराज्यन आयोग के गृष्टि का स्वीकार करके, इस 'मार्मिति' को मई 1953 में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग का एक प्रधान किया गया।

इस "आयोग" के मुख्य कार्य हैं—(1) निधा-सूधार और निधा-प्रकार उन्नयन के विषय में विश्वविद्यालयों का परामर्श देना (2) विश्वविद्यालयों की कोष में से धन देना एवं उसका सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करना, और (3) विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति की जाँच करना एवं केन्द्रीय सरकार से उहायता-अनुदान देन की निधारित करना।

## 2. प्राथमिक शिक्षा : Primary Education

इस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की दो विधियाँ उत्पन्न हुई हैं—प्राथमिक शिक्षा का प्रचलन और प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में प्रवेश।

1. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा—राष्ट्रीय सर्व-व्यवस्था की, 1930 के अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रा. 14 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख है।

राष्ट्रीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ  
में इस शिक्षा की स्थिति निम्नांकित तालिका में स्पष्ट की गई है (Nuru-  
Naik, p. 777) :—

### अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

प्रान्त	केवल बालकों के लिए		बालकों व बालिकाओं के लिए	
	नगरों की संख्या	ग्रामों की संख्या	नगरों की संख्या	ग्रामों की संख्या
विहार	17	....	....	....
बम्बई	9	134	110	5,100
मध्य प्रदेश	34	1,031	....	....
पूर्वी पंजाब	37	1,420	....	1,607
मद्रास	16	31	12	....
उड़ीसा	1	1	3	3
उत्तर प्रदेश	36	1,371	....	....
पश्चिमी बंगाल	1	....	....	....
दिल्ली	1	7	....	....
योग	152	4,995	125	6,710

2 प्राथमिक शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए अप्रोक्षित उपाय अपनाये :—(1) विद्यालय-रहित ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, (2) स्थानीय निकायों को अतिरिक्त सहायता-अनुदान, (3) बालिका-विद्यालयों की आवश्यकतानुसार स्थापना, और (4) प्राथमिक विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की नियुक्ति।

उक्त उपायों के बावजूद भी इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में अपरोध उत्पन्न हो गया। नूरुल्लाह नायक ने इसके दो मुख्य कारण बताए हैं : पहला, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना को विनाश पैमाने पर क्रियान्वित नहीं किया गया। दूसरा, द्वितीय विश्वयुद्ध ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के प्रतिकूल परिस्थितियों को जन्म दिया। हम इन अवधि में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को निम्नांकित तालिका में स्पष्ट कर रहे हैं (Nurullah & Naik, p. 778) :—

	1936-1937	1946-1947
1. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1,92,244	1,34,866
2. छात्रों की संख्या	1,02,24,288	1,05,25,941

### 3. माध्यमिक शिक्षा : Secondary Education

इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा में सम्बन्धित दो तथ्य हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। माध्यमिक शिक्षा की नवीन विनियोजित और माध्यमिक शिक्षा की प्रगति में प्रवृत्ति।

1. माध्यमिक शिक्षा की विशेषताएँ—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा में निम्न नवीन विशेषताएँ दृष्टिगोचर हुईं—(1) अमेरिकी के मूल में नूतन, (2) शिक्षा में माध्यमिक के रूप पर भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठापन, (3) शिक्षकों का शिक्षण व्यवसाय में उन्नयन, (4) प्रशिक्षण-संस्थानों की संख्या में वृद्धि, (5) हाई-स्कूल में वाणिज्य की शिक्षा का गुरुत्व, (6) अनेक राज्यों में दृष्टि और श्रवण की दृष्टिकोणों की स्थापना और (7) सहायक एवं पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन।

2. माध्यमिक शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार निम्न हुआ, परन्तु राज्यों की तुलना में उसमें निम्नलिखित प्रवृत्ति थी। इसके चार प्रसार कारण थे—(1) माध्यमिक शिक्षा की प्रगति में निम्नलिखित होने के कारण माध्यमिक शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि, (2) शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि, (3) पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा की सामग्री के सुलभ होने के कारण शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि और (4) युद्ध के दौरान शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि। (Nurullah & Nank p. 76)

	1936-1937	1946-1947
1. माध्यमिक शिक्षा की संख्या	13,056	11,907
2. छात्रों की संख्या	22,87,872	26,81,981

### 4. उच्च शिक्षा : Higher Education

इस अवधि में उच्च शिक्षा में प्रसार के दो तथ्य उल्लेख करने के योग्य हैं—

1. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना—इस अवधि में अत्यन्त 4 नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई—(1) गुरुदास विश्वविद्यालय, 1937, (2) उज्जैन विश्वविद्यालय, 1941, (3) माधव विश्वविद्यालय, 1946, और (4) राजस्थान विश्वविद्यालय, 1947।

2. उच्च शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में उच्च शिक्षा का प्रसार निम्न हुआ—(1) शिक्षकों और शिक्षण-संस्थानों की संख्या में वृद्धि, (2) युद्ध के दौरान उच्च शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि के कारण उच्च शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि, (3) पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा की सामग्री के सुलभ होने के कारण उच्च शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि और (4) युद्ध के दौरान उच्च शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि के कारण उच्च शिक्षा के छात्र संख्या में वृद्धि।

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ  
7-48 में इस शिक्षा की स्थिति निम्नांकित तालिका में स्पष्ट की गई है (Nuru-  
& Naik, p. 777) :—

### अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

प्रान्त	केवल बालकों के लिए		बालकों व बालिकाओं के लिए	
	नगरों की संख्या	ग्रामों की संख्या	नगरों की संख्या	ग्रामों की संख्या
बिहार	17	....	....	....
बम्बई	9	134	110	5,100
मध्य प्रदेश	34	1,031	....	....
पूर्वी पंजाब	37	1,420	12	1,607
गुजरात	16	31	....	....
उड़ीसा	1	1	3	3
उत्तर प्रदेश	36	1,371	....	....
पश्चिमी बंगाल	1	....	....	....
दिल्ली	1	7	....	....
योग	152	4,995	125	6,710

2 प्राथमिक शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए वसूली उपाय अपनाये :—(1) विद्यालय-रहित ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, (2) स्थानीय निकायों को अतिरिक्त सहायता-अनुदान, (3) बालिका-विद्यालयों की स्थापना, और (4) प्राथमिक विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की नियुक्ति।

उक्त उपायों के बावजूद भी इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में जबरन उन्नति हो गया। नूरुल्ला व नायक ने इसके दो मुख्य कारण बताए हैं पहला, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना को विशाल पैमाने पर क्रियान्वित किया गया। दूसरा, द्वितीय विश्वयुद्ध ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के प्रतिकूल परिस्थितियों को जन्म दिया। हम इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को निम्न तालिका में स्पष्ट कर रहे हैं (Nurullah & Naik, p. 778) :—

	1936-1937	1946-1947
1. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1,92,244	1,34,000
2. छात्रों की संख्या	1,02,24,288	1,05,25,000



### 3. माध्यमिक शिक्षा : Secondary Education

इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित दो तथ्य हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं—माध्यमिक शिक्षा की नवीन विशेषताएँ और माध्यमिक शिक्षा की प्रगति में अपेक्षाहीन मन्दता।

1. माध्यमिक शिक्षा की विशेषताएँ—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा में अग्रगण्य नवीन विशेषताएँ दृष्टिगोचर हुईं :—(1) अंग्रेजी के महत्त्व में न्यूनता, (2) शिक्षा के माध्यम के पद पर भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठापन, (3) स्त्रियों का शिक्षण-अभ्यवसाय में पदार्पण, (4) प्रशिक्षण-कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, (5) हाई-स्कूलों में वाणिज्य की शिक्षा का सूत्रपात, (6) अनेक प्रान्तों में कृषि और तकनीकी हाई-स्कूलों की स्थापना, और (7) शब्दावली एवं पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन।

2. माध्यमिक शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार दो दृष्टि, पर पूर्व कालों की तुलना में उसमें निश्चित मन्दता थी। इसके चार प्रधान कारण थे :—(1) प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में शिथिलता होने के कारण माध्यमिक विद्यार्थियों की संख्या में ह्रास, (2) शिक्षकों को मँहगाई-भत्ता देने के कारण शिक्षा-मुक्त में वृद्धि, (3) पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा की सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, और (4) युद्ध-जनित मँहगाई के कारण सामान्य स्थिति के अभिजातकों के पान घन का अभाव। हम इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को निम्नांकित तानिका में दर्शाते हैं (Nurullah & Naik, p. 767) :—

	1936-1937	1946-1947
1. माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	13,056	11,907
2. छात्रों की संख्या	22,87,872	26,81,981

### 4 उच्च शिक्षा : Higher Education

इस अवधि में उच्च शिक्षा के विषय में केवल दो तथ्य उल्लेख करने के योग्य हैं :—

1. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना—इस अवधि में अप्रतिष्ठित 4 नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई :—(1) बाराकौर विश्वविद्यालय, 1937, (2) उच्च विश्वविद्यालय, 1943, (3) नागर विश्वविद्यालय, 1946, और (4) राज-पुत्र विश्वविद्यालय, 1947।

2. उच्च शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में उच्च शिक्षा का विस्तार बहुत-कुछ पूर्व कालों की अपेक्षा अधिक था। इसके अप्रतिष्ठित 4 मुख्य कारण थे :—(1) स्त्रियों और पिछड़ी जातियों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की लालसा, (2) युद्ध से सम्बन्धित व्यवसायों के लिए शिक्षित व्यक्तियों की माँग, (3) उच्च

5 | भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

947-48 में इस शिक्षा की स्थिति निम्नांकित तालिका में स्पष्ट की गई है (Nurullah & Naik, p. 777) :—

### अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

प्रान्त	केवल बालकों के लिए		बालकों व बालिकाओं के लिए	
	नगरों की संख्या	ग्रामों की संख्या	नगरों की संख्या	ग्रामों की संख्या
बिहार	17	....	....	....
बम्बई	9	134	110	5,100
मध्य प्रदेश	34	1,031	....	....
पूर्वी पंजाब	37	1,420	....	1,607
मद्रास	16	31	12	....
उड़ीसा	1	1	....	3
उत्तर प्रदेश	1	1,371	3	....
पश्चिमी बंगाल	36	....	....	....
दिल्ली	1	7	....	....
योग	152	4,995	125	6,710

2 प्राथमिक शिक्षा की प्रगति—इस अवधि में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए असांकित उपाय अपनाये :—(1) विद्यालय-रहित ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, (2) स्थानीय निकायों की अतिरिक्त सहायता-अनुदान, (3) बालिका-विद्यालयों की आवश्यकतानुसार स्थापना, और (4) प्राथमिक विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की नियुक्ति।

उक्त उपायों के बावजूद भी इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति अवनीत उत्पन्न हो गया। नूतनता व नायक ने इसके दो मुख्य कारण बताए पहला, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना के विनाश के समाने पर क्रियान्वित किया गया। दूसरा, द्वितीय विश्वयुद्ध ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के प्रतिकूल स्थितियों को जन्म दिया। हम इन अवधि में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को निम्न तालिका में स्पष्ट कर रहे हैं (Nurullah & Naik, p. 778) :—

	1936-1937	1946-1
1. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1,92,244	1,3
2. छात्रों की संख्या	1,02,24,288	1,05,



58 | भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक सहा-  
यता-अनुदान, और (4) युद्ध-काल में अधिक धन का अर्जन करने के कारण व्यवसायी-  
युग द्वारा उच्च शिक्षा की संस्थाओं को आर्थिक सहायता। इस अवधि में उच्च शिक्षा  
की प्रगति का अनुमान अधोलिखित तालिका में प्रदर्शित किए गए आंकड़ों से लगाया  
जा सकता है (डा० मुन्शोपाध्याय, पृष्ठ 203) :—

	1931-1932	1946-1947
1. कॉलेजों की संख्या	417	933
2. छात्रों की संख्या	99,893	1,99,253

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Describe the progress of Primary, Secondary and Univer-  
sity Education from 1921 to 1937.  
1921 से 1937 तक प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-शिक्षा  
की प्रगति का वर्णन कीजिए।
2. Write a short account of the educational activities of the  
Central Government from 1937 to 1947.  
1937 से 1947 तक केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों का  
संक्षेप में लिखिए।
3. Write short essays on the development of the following  
from 1937 to 1947 :—(a) Primary Education, and  
(b) Secondary Education  
1937 से 1947 तक अवलिखित के विकास पर संक्षिप्त नि-  
र्लेखिए :—(अ) प्राथमिक शिक्षा, और (ब) माध्यमिक शिक्षा।

# 16

## बुनियादी शिक्षा या नई तालीम (वर्धा-शिक्षा-योजना)

BASIC EDUCATION OR NAI TALIM  
(Wardha Scheme of Education)

"The Wardha Scheme was first sketched in 1937  
by M. K. Gandhi in the *Harijan* published at Wardha."

— T. N. Siqueira.

### विषय-प्रवेश

अविनाशनिष्ठम् ते नन्दो म 'बुनियादी शिक्षा—हमारे राष्ट्रविकास का  
अन्तिम और सम्भवतः महान्तम उपहार है।"

"Basic education is the last, and perhaps the greatest gift of  
the Father of our Nation. T. N. Vinashlingam *Understanding  
Basic Education*, p. 1

हमारे राष्ट्र विना महा-मा शोधों के इसी उपहार को 'नई तालीम' और  
'बुनियादी-शिक्षा-योजना' के नामों से भी पुराण जाता है। उन्होंने यह उद्घार सन् 1937  
को किन परिस्थितियों में और किस व्यक्ति से माध्यम से करने देशवासियों को भेंट  
किया, इसका उपाध निम्न प्रस्तुत करेंगे। ए० एन० सेन ने लिखा है — "काँग्रेसी  
मन्त्रिमण्डलों के कार्यक्रम में जो मुख्य बातें थीं जन-शिक्षा और नाना विधेय। किन्तु,  
ये एक बुद्धिमान थे। नाना विधेय का पर्यायवाची करने का परिणाम होता — प्रायः में  
भारो कमो, जबकि जन-शिक्षा के कार्यक्रम को वास्तव में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए  
आर्थिक प्रतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता थी। इन दोनों बिरोधी बातों में समन्वय  
विल प्रकार स्थापित किया जा सकता था? उस प्रकार वह शोधियों ने अपनी स्वा-  
सम्पत्ति बुनियादी शिक्षा को योजना प्रस्तुत की।"



क्रिया। यही "रिपोर्ट"—"वर्धा-शिक्षा-योजना" (Wardha Scheme of Education) के नाम से प्रसिद्ध है और बुनियादी शिक्षा का आधार है।

### वर्धा-योजना की रूपरेखा

#### Outline of Wardha Scheme

"वर्धा-योजना" अथवा "बेसिक शिक्षा-योजना" की रूपरेखा इस प्रकार है:—

1. बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है।
2. यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है।
3. शिक्षा का माध्यम—मातृभाषा है।
4. पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है।
5. सम्पूर्ण शिक्षा का सम्बन्ध किसी आधारभूत कौशल (Basic Craft) से होता है।
6. कौशल को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर चुना जाता है।
7. चुने हुए कौशल की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि यह बालकों को अच्छा कौशल बना कर, उनको रोजगार देती है।
8. उक्त कौशल की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्त्व में अपनी प्रति प्रतिष्ठित हो सके।
9. नैतिक धर्म पर बल दिया जाता है, ताकि बालक गीते हुए कौशल के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके।
10. शिक्षा का बालक के जीवन, यह सब घाम में और उसके घाम के उपयोग, हस्त-कौशल और व्यवसायों में प्रतिष्ठित सम्बन्ध होता है।
11. बालकों द्वारा बनाई जाने वाली सम्पूर्ण ऐसी होती है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है या जिसका उपयोग विद्यालय का कुछ धन खर्च हो सकता है।

इस प्रकार, बेसिक शिक्षा की योजना में मातृभाषा के शिक्षा-दर्शन के मुख्य तत्वों का समावेश है।

### बुनियादी शिक्षा नाम क्यों ?

#### Why Termed Basic Education ?

अंग्रेजी के "Basic" शब्द का हिन्दी अर्थ है—"आधारभूत" और उर्दू अर्थ है—"बुनियादी"। क्योंकि यह शिक्षा अक्षरिगता बालकों के आधारभूत "आधारभूत" या "बुनियादी" मानो गई है, इसलिए इसका नाम "बेसिक शिक्षा" रखा है —

1. यह शिक्षा — भारत की राष्ट्रीय मान्यता, महत्त्व और शिक्षा का आधार मानो गई है।

2. यह शिक्षा—प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई है।
3. यह शिक्षा—प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य सम्पत्ति है।
4. यह शिक्षा—बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरूचियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करती है।
5. यह शिक्षा—सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से सम्बन्धित है।
6. यह शिक्षा—सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है, जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देता है।
7. यह शिक्षा—किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने माघी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता है।

इस प्रकार, जैसा कि स्वयं गांधीजी ने लिखा है :—“बुनियादी शिक्षा—बच्चों को, छोटे घे नगरों के हों या ग्रामों के, भारत को समस्त सर्वोत्तम और स्वाधीनता से सम्बन्धित करती है।”

“Basic Education links the children, whether of the cities or of the villages, to all that is best and lasting in India.”—M. K. Gandhi : *Constructive Programme*, p. 16.

### बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम Curriculum of Basic Education

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए हैं :—

1. आधारभूत शिल्प—अप्रांक्ति शिल्पों में से कोई एक—(i) कृषि, (ii) कलार-बुनाई, (iii) लकड़ी का काम, (iv) चमड़े का काम, (v) मिट्टी का काम (चिलोने और बर्तन बनाना), (vi) पुस्तक कला (कामग और काटे-बोर्ड का काम), (vii) गड्ढी पालना, (viii) फल और सब्जी का बागबानी, (ix) गृह-विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए), (x) स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद हस्तशिल्प।
2. गणितशास्त्र।
3. गणित।
4. सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र)।



बुनियादी शिक्षा या नई तालीम (बर्धा-शिक्षा-योजना) ।

5. सामान्य विज्ञान—(i) प्रकृति अध्ययन, (ii) वनस्पति-विज्ञान, (iii) जीव-विज्ञान, (iv) रसायन-शास्त्र, (v) स्वास्थ्य-विज्ञान, (vi) नक्षत्र का ज्ञान, (vii) महान् अन्वेषण और वैज्ञानिकों की कहानियाँ ।
- 6 कला—गीत और निवृत्ता ।
- 7 हिन्दी—बढ़ी यह मातृभाषा नहीं है ।
- 8 नारीशिक शिक्षा - ध्यायम और गेन-रूट ।

### बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

Characteristics of Basic Education Curriculum

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

1. पाँचवीं कक्षा 11 मूल-शिक्षा है और बाकियों एवं वांछितों के लिए समान पाठ्यक्रम है ।
2. पाँचवीं कक्षा के पश्चात् बाकियों और वांछितों के लिए गृह विद्यालयों की व्यवस्था है ।
3. छात्रों और मातृवी कक्षाओं में वांछितों आधारभूत जितने के स्थान पर गृह विज्ञान में मकनी है ।
4. मातृवी और पाठवी कक्षाओं में छात्र, पाषण्य आधुनिक भारतीय भाषाओं धादि की शिक्षा की व्यवस्था है ।
5. शिक्षा का माध्यम—मातृभाषा है, पर मातृभाषा हिन्दी का अध्ययन सब बाकियों और वांछितों के लिए अनिवार्य है ।
6. पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान प्रौढ़िक व समरक्ष है ।
7. पाठ्यक्रम में अकेले और पम का वाद स्थान नहीं है ।

अपनी योजना में पम का स्थान न देने का कारण बताया है, महामा बीपी लिखा है "हमारी कक्षा-शिक्षा योजना में म पामक शिक्षा का बहिष्कार कर दिया गया है क्योंकि हम भव है । यह बात कि पमों की शिक्षा दी जाती है अथवा न दिया जाता है वे मेन के स्थान पर नमरे उत्पन्न कराए हैं । साथ ही, मेरा मत है कि बच्चों का ऐसी शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, जिसमें सभी मुख्य बातें गौर निहित हों । पम का यह गौर बहुत बड़ा और गुराही में नहीं पड़ा जाता है । हम न बाक्य स्वन शिक्षा का वैदिक और पमों में ही गौर है ।"

### बुनियादी विद्यालयों की समय-सारणी

Time Table of Basic Schools

बुनियादी विद्यालयों की प्रतिदिन 5½ घंटे कार्य होता है और निम्नलिखित की का अनुसंधान किया जाता है



प्रतिक्षण-विद्यालयों में उन्हीं धर्मियों को प्रवेश दिया जाता है, जो या तो हार्द-स्नान परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, या वर्नास्नान परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् एक से-न-म दो वर्ष तक किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर चुके हों।

### बुनियादी शिक्षण विधि Basic Method of Teaching

रायबर्न के अनुसार :—“बैसिक शिक्षा—शिक्षण की विधि नहीं है। यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है, जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग किया जा सकता है।”

“Basic education is not a method of teaching. It is a method of determining the curriculum. The teacher uses the methods which have proved to be the most interesting and effective. All progressive methods can have their place and be used in Basic Education”—W. M. Ryburn, *The Progressive School*, p. 263.

बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाय, पर शिक्षण का वास्तविक कार्य—विद्यार्थी और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षण-विधि इनकी व्यावहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है। साथ ही, उसे यह ज्ञान भोके समय में प्राप्त हो जाता है। विस्तार रूप में, प्रत्येक वक्ता के बालकों का निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा दी जाती है—

वक्ता के बालकों को सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा का मौखिक ज्ञान कराया जाता है। इसके लिए बाल्यीन और स्थानीय को माध्यम रखा जाता है। मातृभाषा का ज्ञान हो जाने के उपरान्त बालक पहले पढ़ना और फिर लिखना सीखते हैं। जिस समय वे लिखना सीखते हैं उस समय वे किसी आधारभूत ज्ञान का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, बालक जो जो जगह से वक्ता का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे विभिन्न विषयों का ज्ञान अधिष्ठित करते हैं।

कला के माध्यम से अनेक विषयों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। बालक को अपनी रसि के अनुसार हस्त-शिल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

इन प्रकार, जब बालक—बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम समाप्त करते हैं, तब उनमें सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। साथ ही, उन्हें आधारभूत शिल्प की इनकी अच्छी जानकारी हो जाती है कि वे उसकी सहायता से धन का उपार्जन कर सकते हैं।

## बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य

### Aims of Basic Education

बुनियादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य दृष्टव्य हैं :

1. आर्थिक उद्देश्य : *Economic Aim*—इस उद्देश्य के दो अभिप्राय हैं :—(i) बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना, और (ii) बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना। इस सम्बन्ध में स्वयं गांधीजी ने लिखा है :—“प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात् किसी व्यवसाय में लगकर स्वावलम्बी बनना चाहिए।”

2. नैतिक लक्ष्य : *Moral Aim*—आधुनिक भारतीय समाज का अविराम रसि ने नैतिक पतन हो रहा है। अतः बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है—बालक का नैतिक विकास करना। नैतिक शिक्षा में अपना विश्वास प्रकट करते हुए, गांधीजी ने लिखा है :—“भले हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी आयु और पालन-पोषण में कितना अन्तर है।”

“I had given the top place to the culture of the heart or the building of character, and I felt confident that moral training could be given to all alike no matter how different their ages or upbringing.”—M. K. Gandhi : *Autobiography*, p. 408.

3. सांस्कृतिक उद्देश्य : *Cultural Aim*—हमारी शिक्षा-प्रणाली का एक प्रमुख दोष यह है कि उनमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराया जाकर, बालकों को पारदात्मक जातों और विचारों का नश्वर बनाया जाता है। फलस्वरूप, वे अपनी परम्परागत संस्कृति से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते हैं। इसके दुष्परिणाम तो बताते हुए, गांधीजी ने लिखा है :—“यदि किसी स्थिति में पर्युच्चकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रथाओं से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है, या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है, तो यह बुरा हो जाता है।”



One of the aims of Basic Education is to reconstruct society in accordance with Gandhiji's conception of the Sarvodaya Samaj."

- Dr. M. S. Patel : *The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi*, p. 193.

## बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त Principles of Basic Education

बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त अवलोकित हैं :—

1. जनसाधारण की शिक्षा : Education of the Masses—भारत की अधिकांश साधारण जनता—अमानवता के अंधकार से आवृत है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम सिद्धान्त—जनसाधारण की शिक्षित बनाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, गांधीजी के अग्रोक्ति कथन के अनुसार कार्य किया जा रहा है :—“जनसाधारण की शिक्षा—पाप और कलंक है। अतः उसका अन्त किया जाना अनिवार्य है।”

“Mass illiteracy is India's sin and shame, and must be liquidated.”—M. K. Gandhi : *India of My Dreams*, p. 181.

2. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा : Free & Compulsory Education—गांधीजी तो भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में अडिग विश्वास थे। परन्तु भारत अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की शिक्षा का आयोजन करने में विफल रहा। अतः स्वतन्त्र “भारत के संविधान” में यह प्रोचिप्त किया गया :—“जब तक सब बच्चे 14 वर्ष की अवस्था पूर्ण नहीं कर लेंगे, तब तक राज्य उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।”

“The State shall endeavour to provide for the free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.”—Article 45 of the Constitution of India.

3. स्वायत्तम्बी शिक्षा : Self-Supporting Education—गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त की ओर संकेत करते हुए कहा :—“सच्ची शिक्षा स्वायत्तम्बी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा से पूँजी के अतिरिक्त यह सब धन मिल जाना चाहिए, जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया जाय।”

बुनियादी शिक्षा के इस स्वायत्तम्बी पहलु के प्रति विशेष ध्यान देकर उसे स्वायत्तम्बी बनाया गया है। डा० एस० एन० एन० पटेल के अनुसार, बुनियादी शिक्षा दो प्रकार से स्वायत्तम्बी है—(i) बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी व्यवसाय से सीखकर उसे अपने भावी जीवन के निर्वाह का साधन बनाए, और (ii) विद्यार्थी के मन में इससे स्फूर्ति मिले जाती वस्तुओं की बनकर, व्यवसायों की



## बुनियादी शिक्षा के गुण या विशेषताएँ Merits or Characteristics of Basic Education

जीवनाभिवृद्धिम् न बुनियादी शिक्षा ही मनुष्यता गीतो का "मनुजन्तुम् उपहार" माना है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें प्रत्येक अद्वितीय गुण या विशेषताएँ हैं।

1. **क्रिया-प्रधान शिक्षा : Activity Centred Education**—बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान है, क्योंकि इसमें मनुष्यों ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है। रायचर्मे ने अनुमान :— "बालक हस्त-चित्र के क्षेत्र में सक्रिय रहकर, मानसिक अनुभवों के साथ साथ अन्य प्रकार के अनुभव भी प्राप्त करता है।"

2. **बालक-प्रधान शिक्षा : Child Centred Education**—बुनियादी शिक्षा—बालक-प्रधान है। इसमें बालक ही शिक्षा का "ग्रहण" समझा जाता है। जब इसकी आवश्यकताओं का अध्ययन लिया जाता है और उनको पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है। यों एम० एम० मुकर्जी ने शब्दों में :— "जहाँ तक बाल-केंद्रित शिक्षा है और बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है।"

"No Talim is child-centred education, and the child learns through activity"—Dr S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 58.

3. **बालक का आध्यात्मिक विकास : Spiritual Development of Child**—बुनियादी शिक्षा बालक के आध्यात्मिक विकास की और पूर्ण ध्यान देती है और इसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार, यह शिक्षा—बालक को अपने और सामाजिक जीवन की पूर्णता के आनन्द का अनुभव कराती है।

4. **गृह, स्कूल व समाज में सामंजस्य : Harmony between Home School & Society**—बुनियादी शिक्षा—गृह, स्कूल और समाज के जीवन में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करती है। इसका तात्पर्य यहाँ यह है, रायचर्मे ने शिक्षा है :— "बालक, हस्त-चित्र की शिक्षा प्राप्त करके, अपने को गृह, स्कूल और समाज में प्रसमान या उत्तम रूप में बनाता है।"

5. **अर्थिक आधार : Economic Basis**—बुनियादी शिक्षा का अर्थ आर्थिक है। इसके अर्थों में यह अर्थपूर्ण शिक्षा या मरने है; यथा :— बुनियादी शिक्षाओं में बालक द्वारा जहाँ जहाँ बालक को अपनी ही शिक्षा का अनुभव मिलता है, और (ii) बालक किसी हस्त-चित्र की सीखने का अनुभव करता है, और (iii) बालक किसी हस्त-चित्र की सीखने का अनुभव करता है, और (iv) बालक किसी हस्त-चित्र की सीखने का अनुभव करता है।

"Basic Education proposes to solve the problem of employment"—Dr. S. N. Mukerji : *op. cit.*, pp. 58-59.



6. सामाजिक आधार : Social Basis—बुनियादी शिक्षा का आधार—सामाजिक है, क्योंकि हमें बालक के अनेक सामाजिक गुणों को विकसित करने की चेष्टा की जाती है। बालक में हस्तनित्य के माध्यम में सेवा और सहृदयता, सहयोग और सहिष्णुता, ज्ञान-नयन और आत्म-विश्वास के गुणों को सुविकसित करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है। अतः “बैंगिक शिक्षा-योजना” के निर्माताओं ने यह आभा प्रकट की — “ध्यावहारिक उत्पादक कार्य—भारीक और मानसिक कार्यकर्ताओं के मध्य उपस्थित द्वेष की बीमार को नष्ट कर देना।”

“Practical productive work will tend to break down the existing barriers of prejudice between manual and intellectual workers.”  
*Educational Reconstruction*, p 121.

7 मनोवैज्ञानिक आधार Psychological Basis—बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि हमें बालक को प्रभावित हो जाते हैं, न कि उसके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्य विषयों को। बालक वास्तविक विश्व की किसी वस्तु से सम्बन्ध होकर ही हा सज्ज है। हम मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर, बुनियादी शिक्षा में हस्त-नित्य द्वारा उत्पादक कार्य को प्रदान स्थान दिया गया है।

8 भारीक धर्म का सम्मान Dignity of Labour—बुनियादी शिक्षा—बालक में भारीक धर्म का प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करती है। बालक स्वयं हस्तनित्य के माध्यम में किसी उत्पादक कार्य को करता है। अतः वह भारीक धर्म को महत्व देने लगता है और हम प्रसार का धर्म करने वाले व्यक्तियों को प्रसार की दृष्टि में देखने लगता है।

9 सम्बन्धी शिक्षण विधि Correlated Method of Teaching—बुनियादी शिक्षा में सम्बन्धी शिक्षण-विधि का प्रयोग किया जाता है। बालक को समस्त विषयों की शिक्षा किसी वस्तु या हस्त-नित्य के माध्यम में दी जाती है। दूसरे शब्दों में, उसे विद्या के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह दृष्टि, कठार-सुन्दर, शास्त्र-ज्ञान आदि में किसी हस्त नित्य का प्रयत्न करता है। उनके द्वारा वह उन कार्य को करके उसका और उसका सम्बन्धित बाकी का ज्ञान प्राप्त करता है।

हम अती कथन का स्वीकार करने के उद्देश्य में विचारण्य हूँ के कक्षागत ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं — बुनियादी शिक्षा में दत्तकारी द्वारा शिक्षा को प्रदानता हो गई है और विविध विषयों के ज्ञान को रखना भी इसी मूल-उद्देश्य के दृष्टि-निर्देश की गई है। दत्तकारी को ज्ञान का बाह्य अवस्था साधन बताया गया है। तदर्थ यह है कि विविध विषयों का ज्ञान बालक को विज्ञानों में ही सम्बन्धित किया जाता है। इसी सम्बन्ध के जोड़ने की सम्भाव्य करती हैं।

10. ज्ञान की अत्यवस्था Unification of Knowledge—बुनियादी शिक्षा में ज्ञान को एक अन्तिम और अग्रणी इकाई माना जाता है। अतः

## बुनियादी शिक्षा के गुण या विशेषताएँ

### Merits or Characteristics of Basic Education

अधिनारसिंहम् ने बुनियादी शिक्षा को महात्मा गांधी का “महानतम् उपहार” बताया है। इसका कारण यह है कि इसमें अनेक अद्वितीय गुण या विशेषताएँ हैं; यथा

1. क्रिया-प्रधान शिक्षा : Activity Centred Education—बुनियादी शिक्षा क्रिया-प्रधान है, क्योंकि इसमें सम्पूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है। रायबर्मन के अनुसार :—“बालक हस्त-शिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर, मानसिक अनुभवों के साथ-साथ अन्य प्रकार के अनुभव भी प्राप्त करता है।”

2. बालक-प्रधान शिक्षा : Child Centred Education—बुनियादी शिक्षा बालक-प्रधान है। इसमें बालक को शिक्षा का “ग्राहक” समझा जाता है। अतः उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन लिया जाता है और उनको पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है। डा० एन० एन० मुकर्जी के शब्दों में :—“नई तालीम बालक-केन्द्रित शिक्षा है और बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है।”

“Nai Talim is child-centred education, and the child learns through activity.”—Dr. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 58.

3. बालक का आध्यात्मिक विकास : Spiritual Development of Child—बुनियादी शिक्षा बालक के आध्यात्मिक विकास की ओर पूर्ण ध्यान देती है और उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार, यह शिक्षा—बालक को अपने और सामाजिक जीवन की पूर्णता के आनन्द का अनुभव कराती है।

4. गृह, स्कूल व समाज में सामंजस्य : Harmony between Home, School & Society—बुनियादी शिक्षा—गृह, स्कूल और समाज के जीवन में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करती है। इसका कारण यही है, रायबर्मन ने लिखा है :—“बालक, हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके, अपने को गृह, स्कूल और समाज में प्रायः समाज जातधरम में पाता है।”

5. आर्थिक आधार : Economic Basis—बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। इसके समर्थन में दो बड़े उपलब्ध सिद्धांत या मन्त्र हैं; यथा :—(i) बुनियादी विद्यालयों में आन्तरिक द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचने से विद्यालय का कुछ भाग निकल सकता है, और (ii) बालक किसी हस्त-शिल्प को सीखकर अपने भावी जीवन में पैसा का अर्जन कर सकता है। एक अन्य बड़ा डा० एन० एन० मुकर्जी ने बुनियाद :—“बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है।”

“Basic Education proposes to solve the problem of unemployment.”—Dr. S. N. Mukerji : *op. cit.*, pp. 58-59.

6 सामाजिक आधार : Social Basis—बुनियादी शिक्षा का आधार—सामाजिक है, क्योंकि हमें बालक के अनेक सामाजिक गुणों को विकसित करने की चेष्टा की जाती है। बालक में हस्त-कला के माध्यम से मेरा और स्नेह, सहयोग और सहिष्णुता, ज्ञान-मन्य और आत्म-निश्चय के गुणों का सुविकसित करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है। अब "बैंगन शिक्षा-योजना" के निर्माताओं ने यह आशा प्रकट की - - "व्यावहारिक उपकरण कार्य—शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमताओं के मध्य उपस्थित द्वेष को दूर करने को नष्ट कर देगा।"

"Practical productive work will tend to break down the existing barriers of prejudice between manual and intellectual workers." *Educational Reconstruction* p 121

7 मनोवैज्ञानिक आधार Psychological Basis—बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि हमें बालक की प्रकृति को जानना है, न कि उसने द्वारा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्य विषयों को। बालक के सामाजिक विकास किसी कार्य में मगन होकर ही हो सकता है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर, बुनियादी शिक्षा में हस्त-कला द्वारा उत्पादक कार्य को प्रदान प्रदान किया गया है।

8 शारीरिक धर्म का सम्मान Dignity of Labour—बुनियादी शिक्षा—बालक में शारीरिक धर्म का प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करती है। बालक स्वयं हस्त-कला के माध्यम से किसी उत्पादक कार्य को करता है। अब यह शारीरिक धर्म को महत्व देने लगता है और इस प्रकार का धर्म करने वाले व्यक्तियों को आदर की दृष्टि में देखने लगता है।

9 सम्बन्धी शिक्षण विधि Correlated Method of Teaching—बुनियादी शिक्षा में सम्बन्धी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। बालक को सम्बन्धी विषयों की शिक्षा किसी कार्य या हस्त-कला के माध्यम से दी जाती है। दूसरे शब्दों में, उसे किया क द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह दृष्टि, कटार-पुनर्निर्माण, वाष्पन-कला आदि में किसी हस्त-कला का प्रयोग करना है। उससे पता चलता है कि उस कार्य को करके उसका और उसमें सम्बन्धित कार्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

इस भाग प्रयत्न का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से विचार-विमर्श करने के अभाव में हमें उक्त १ २ २ २ है - बुनियादी शिक्षा में रसिकारी द्वारा शिक्षा को प्रदानता को गई है और विविध विषयों के ज्ञान को रखना भी इसी मूल प्रयोग के इर्द-गिर्द की गई है। रसिकारी को ज्ञान का बाह्य प्रकाश साधन बताया गया है। तात्पर्य यह है कि विविध विषयों का ज्ञान बालक को विज्ञानों में ही सम्बन्धित किया जाता है। इसी सम्बन्ध के जोड़ने को सम्बन्ध कहते हैं।

10. ज्ञान की व्यवस्था Classification of Knowledge—बुनियादी शिक्षा में ज्ञान को एक प्रविष्ट और व्यवस्था इकाई माना जाता है। यह

विषयों को अलग-अलग विभाजित नहीं किया जाता है और न उसका ज्ञान ही अलग-अलग दिया जाता है। इसके विपरीत, नव विषयों का ज्ञान किसी उपयोगी शिल्प के द्वारा परस्पर सम्बन्धित करके दिया जाता है। हुंटराज भाटिया के शब्दों में :— "बुनियादी शिक्षा में ज्ञान— एक अभिन्न-अखण्ड समष्टि (One unified whole) है, और उनका अनेक अतन्त्र और अनेक बार, परस्पर अभिवर्जित विषयों (Exclusive Subjects) में विभाजन निषिद्ध है।"

11. शिल्प द्वारा शिक्षा : Education through Craft—बुनियादी शिक्षा का माध्यम—आधारभूत शिल्प (Basic Craft) है। नव विषयों की शिक्षा इसी शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। आधुनिक युग के सभी शिक्षाशास्त्रियों द्वारा इन बातों को स्वीकार किया जाता है कि बालक की शिक्षा का माध्यम कोई उत्पादक कार्य होना चाहिए। उनका मत है कि केवल इसी प्रकार की शिक्षा—बालक का वास्तविक जीवन में सम्बन्ध स्थापित कर सकती है।

12. बालक व शिक्षक की स्वतन्त्रता : Independence of Child & Teacher—बुनियादी शिक्षा में बालक और शिक्षक पर्याप्त स्वतन्त्रता का उपयोग करते हैं। बालक को कार्य करने, कार्य में रुचि लेने और कार्य को करके उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण अवसर मिलता है। शिक्षक को न तो किसी निर्धारित पाठ्य-पुस्तक का अनुसरण करना पड़ता है और न कोई निश्चित पाठ ही पढ़ाना पड़ता है। उसे न तो पाठ्य-पुस्तकों को समाप्त करने की आवश्यकता रहती है और न जाने वाली परीक्षा के कारण व्याकुलता। वह अपनी रुचि के अनुसार प्रयोग एवं परीक्षण कर सकता है, और जानती ही योग्यता के विकास एवं विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी उपयुक्त विधान-विधि और लाभप्रद उद्योग का प्रयोग कर सकता है।

भारत में, द्रम दी० एन० सिन्घेरा के शब्दों में कह सकते हैं :—"वर्धा-योजना की भारत की निरक्षरता की महान् समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और सम्पूर्ण माना जा सकता है।"

"The Wardha Scheme may be considered the boldest and completest attempt so far made to solve the great problem of India's illiteracy." - T. N. Siqueira : *The Education of India*, pp. 221-222.

### बुनियादी शिक्षा के दोष Defects of Basic Education

बुनियादी शिक्षा के कुछ स्पष्ट दोषों की जहाँ भीधे की पंक्तियों में की जा रही है :—

1. यह शिक्षा बच्चों के अज्ञान दोषों के लिए अधिक उपयुक्त है।

2. यह शिक्षा—“उत्पादन के सिद्धान्त” (Principle of Productivity) पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। अतः युनियादी विद्यालय, शिक्षण के केन्द्र न रह कर, उद्योग के केन्द्र बन जाते हैं।
3. यह शिक्षा—कताई, बुनाई और धुनाई के समान प्राचीन उद्योगों को महत्त्व देती है। इस प्रकार, यह शिक्षा—भारत की औद्योगिक उन्नति में बाधक है। यह युग मशीनों का है, न कि हस्त-शिल्पों का।
4. यह शिक्षा किसी हस्त-शिल्प के माध्यम में बालक को सब विषयों का ज्ञान प्रदान करने की धृष्टि करती है, जो पूर्णतया असम्भव है। डा० धीपरनाथ मुखोपाध्याय के शब्दों में :—“केन्द्रीय वस्तुकारों के द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है।”
5. यह शिक्षा—आधारभूत शिल्प के द्वारा न तो बालक का सर्वांगीण करने में और न उसे सामान्य शिक्षा प्रदान करने में सफल होती है।
6. यह शिक्षा—नकती द्वारा कताई पर अत्यधिक बल देती है। तरुती से बहुत समय में थोड़ा-सा सूत काता जाता है। इस प्रकार, यह शिक्षा न केवल बालक का समय नष्ट करती है, बल्कि उसके लिए मँहगी भी पड़ती है।
7. डा० मुखोपाध्याय के अनुसार<sup>1</sup> :—यह शिक्षा स्वावलम्बी नहीं बन सकती है, क्योंकि बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं में शिक्षकों के वेतन का भ्रय नहीं निराल सकता है।
8. डा० मुखर्जी के अनुसार<sup>2</sup> :—“यह शिक्षा, बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों का विकास होने से पूर्व और उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त किए बिना, बालक को अल्प आयु में ही किसी हस्त-शिल्प से बांध देती है।”
9. श्रीहरन व शर्मा के शब्दों में<sup>3</sup> :—“यह शिक्षा, काल्पनिक है, एक अनावश्यक विद्यार्थ है, एक मन मृष्टि है और वास्तविक व्यवहार से परे है।”
10. इस शिक्षा में बालक के मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण में किसी प्रकार का समुन्नत नहीं है।
11. इस शिक्षा में “उत्पादन के सिद्धान्त” पर बल दिए जाने के कारण शिक्षकों का नैतिक पतन हो जाता है, क्योंकि वे विद्यार्थियों को कौशलों

1. डा० धीपरनाथ मुखोपाध्याय ‘भारतीय शिक्षा का इतिहास’, पृ० 198।

2. S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 58

3. Jhingran & Sharma : *Reports on Indian Education*, p. 37.

में और बालकों को धन का उपार्जन करने वाली मशीनों में परिणत कर देता है।

12. "Education in India" (1947-57) के अनुसार :—इस शिक्षा में उनका और अध्यापकों को कोई आकर्षण नहीं मिला है। अतः दोनों ने उनका पौन विरोध किया है।
13. "Modern Review" (April, 1955) के अनुसार :—इस शिक्षा का प्रतिभावलों ने स्वागत नहीं किया है। उनका कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, न कि कताई-बुनाई और गुड़ाई-निहाई करने के लिए।
14. डॉपरन व शर्मा के शब्दों में :—“इस शिक्षा में सुस्विर शिक्षा-दर्शन की अपेक्षा भावुकता अधिक है। इसे गांधीजी की महानता से प्रभावित व्यक्तियों ने भावुकतावश ही स्वीकार किया है।”
15. “मूल्यांकन-समिति” के विचार से :—“सामान्य धारणा यह है कि बुनियादी विद्यालय—साधारण विद्यालय से अधिक महंगा है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का सौघता से प्रसार नहीं किया जा सकता है।”  
“There is a general view that a Basic School is more costly than an ordinary school. This is followed by the corollary that that is why Basic Education cannot be spread quickly.”—*Report of the Assessment Committee on Basic Education*, p. 33.

### बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन Estimate of Basic Education

बुनियादी शिक्षा के उपरिचालित मूल्या के आधार पर हम निम्नलिखित भाव से स्वीकार कर सकते हैं कि दार्शनता के समय के संकुल में कैसे हुए, हमारे देश के लिये यह शिक्षा एक अनुपम प्रदान है। यह न तो प्राचिन शिक्षा के समान पुस्तकीय एवं व्यावहारिक है और न परीक्षा एवं पाठ्यक्रम की बाँधी हुई है। जबकि प्राचिन शिक्षा केवल बालकों के मानसिक विकास की ओर ध्यान देती है, बुनियादी शिक्षा उनके आधारीक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए समस्त उद्योग करती है। बुनियादी शिक्षा की सर्वप्रधान विशेषता—उनका उत्पादन का मिश्रण है। इस मिश्रण की व्यावहारिक रूप प्रदान करते, बालकों को अपने भावी जीवन में वैविध्य रूप में काम-निर्भर और स्वावलम्बी बनाया जा सकता है।

बुनियादी शिक्षा के उपरिचाल और अन्य मूल्या के कारण हमारे देश के अनेक दार्शनिक तथा अन्य शिक्षा-मर्मज्ञों ने इसका और स्वागत किया है और कामस्वात

होकर इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। किन्तु, यदि इस शिक्षा का मूहमता से विश्लेषण किया जाय, तो वास्तविकता कुछ और ही दिखायी देती है। इसका व्यापारभूत कारण यह है कि बेमिक शिक्षा की योजना यथायं जगत् से सम्बन्धित न होकर, कल्पना-प्रदेन की वस्तु है। आचार्य कृपलानी ने तो यहाँ तक कह दिया है.—  
“बेसिक शिक्षा की योजना—शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी की अन्तिम मनःसृष्टि है।”

“The scheme of Basic Education is Gandhiji's latest fad in the domain of education.”—Acharya Kripalani.

केवल “मनःसृष्टि” का आरोप ही बुनियादी शिक्षा के समस्त गौरव, समस्त महत्त्व और समस्त उपयोगिता को गढ़-गढ़ करके, नष्ट कर देता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी के कुछ अन्य शैक्षिक विचारों की भाँति उनका बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी विचार भी समयानुरूप न होने के कारण शैक्षिक-समाज में सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाया है। यह सत्य है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसमें कृपाकर करके, इसे इस देश के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। पर इस कार्य को करे कौन? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, डा० एस० एन० मुखर्जी ने लिखा है<sup>1</sup> :—“यह कार्य, महात्मा गांधी के विषयों द्वारा किया जाना चाहिए। किन्तु उनके लिए गांधीजी का प्रत्येक कार्य और प्रत्येक शब्द इतना देवी और पवित्र है कि वे उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का साहस नहीं कर सकते हैं। यदि गांधीजी आज जीवित होते, तो वे अनिवार्यतः अपनी बेमिक शिक्षा की योजना को नये माँच में डाल कर देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप बना देते।”

स्वोक्ति “योजना” में किसी प्रकार का भी हेर-छेर किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए वह गांधीजी के नाम में भारत के विभिन्न राज्यों में जग चल रही है। कुछ राज्यों में वह शिग प्रकार चल रही है, उनका मजबूत बर्णन “मूल्यांकन समिति” के इन शब्दों में पाएँ<sup>2</sup> :—“कुछ राज्यों में हमने बेमिक स्कूलों को किन्तु अस्त-व्यस्त दशा में देखा। एक राज्य में किसी प्रकार का अन्तर किए बिना सब स्कूलों को बेमिक स्कूल कहा जाता था। एक-दूसरे राज्य में हमने पुराने उम्र के प्राथमिक विद्यालयों को बेमिक स्कूलों के नाम से चलते हुए देखा।” इसका कारण बेसिक शिक्षा के प्रति अधिकारियों की उदासीनता थी। “समिति” के अनुसार उनका कहना था :—  
“बेसिक शिक्षा को जभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इससे हमने यह अर्थ निकाला कि बेसिक शिक्षा को अपने प्रसार के लिए अनन्त समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।”

1. S N Mukerji op cit, p 61.

2. Report of the Assessments Committee on Basic Education, p. 20.

"Basic Education had better wait. We thought this would mean that Basic Education would have to wait indefinitely."—*Report of the Assessment Committee on Basic Education*, p. 20.

यह है बुनियादी शिक्षा के बारे में सरकारी अधिकारियों और सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली "मूल्यांकन समिति" की राय। एक दूसरी राय डा० मुजीब के इन शब्दों में पढ़िए:—"वास्तविक बेसिक स्कूल कुछ ही शिक्षाविदों के आदर्श रह गये हैं। दूसरे शिक्षाविद, जिनके पास धन है, वे बेसिक शिक्षा का प्रचार तो करते हैं, पर अपने बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों में भेजते हैं। हाई-स्कूलों में उत्तर-बेसिक स्कूलों के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको शैक्षिक योग्यता कम होती है। इससे प्रामोण जनता में यह विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बेसिक स्कूल गाँवों के लिए तो काफी अच्छे हैं, पर उच्च शिक्षा के अभिलाषी बालकों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं।"

"The genuine basic school remained the ideal of a few educationists, those who had the means sent their children to English-medium schools, while propagating basic education. The high schools refused to admit children from post basic schools, because their academic attainments were low. This made the rural population aware that the Basic School was regarded as something good enough for the village but not good enough for further education."—Dr. M. Mujeeb. His Article in *The Illustrated Weekly of India*, August 18, 1963, p. 12.

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. Discuss the fundamental principles of Basic Education. How far are they workable?

बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। उनसे कितने हद तक कार्य किया जा सकता है?

2. What are the main aims of Basic Education? How far have they been formulated keeping in view the needs of the child and the country?

बुनियादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उनसे बालक और देश की आवश्यकताओं की दृष्टि से कितने हद तक ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है?

3. Write a reasoned criticism of the Wardha Scheme of Education.

"वार्धा-शिक्षा-योजना" की वसति-योजना कीजिए।



4. "Basic Education was Gandhiji's latest fad in the domain of education." Discuss.

"बुनियादी शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी की अन्तिम मनःमृष्टि थी।" विवेचना कीजिए।

5. "Basic Education was the greatest gift of Mahatma Gandhi." Comment.

"बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी की महानतम भेंट थी।" समीक्षा कीजिए।

6. Write short notes on :—(a) Wardha Educational Conference, (b) Zakir Husain Committee, (c) Wardha Scheme of Education, and (d) Basic method of teaching.

अग्रलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—(अ) वर्षा-शिक्षा-सम्मेलन, (ब) ज़ाकिर हुसैन समिति, (ग) वर्षा-शिक्षा-योजना, और (द) बुनियादी शिक्षण-विधि।

# 17

सार्जेंट-रिपोर्ट, 1944

शिक्षा-विकास की युद्धोत्तर योजना, 1944

SARGENT-REPORT, 1944

POST-WAR PLAN OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT, 1944

"The function of the *High School* is to cater for those children who are well above the average in ability."

—Sargent Report.

## विषय-प्रवेश

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति में कुछ समय पूर्व अन्य देशों के समान भारत में भी युद्धोत्तर विकास की योजनाओं के निर्माण-कार्य की दिशा में रचनात्मक कार्य उठाए गए। इन योजनाओं में शिक्षा का भी स्थान था। अतः "गवर्नर-जनरल की प्रत्यक्ष-कारिणी समिति की पुनर्निर्माण समिति" (Reconstruction Committee of Governor-General's Executive Council) ने "केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय बोर्ड" (Central Advisory Board of Education) को भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

"केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय बोर्ड" ने इस निर्देश का पालन करने के लिए भारत-भरदार के अत्यासीन शिक्षा-मन्त्रालय, सर जॉन सार्जेंट (Sir John Sargent) ने एक योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। अतः सार्जेंट ने अपनी योजना को एक "स्मृति-पत्र" (Memorandum) में संक्षेपित करते मई 1944 में "बोर्ड" के समक्ष प्रस्तुत किया। इस "स्मृति-पत्र" को 4 विभिन्न भागों में पुनरायतन किया है; यथा—

1. सार्जेंट-रिपोर्ट : Sargent-Report.
2. सार्जेंट-योजना : Sargent Plan, or Scheme.
3. भारत में युद्धोत्तर शिक्षा-विकास-योजना : Scheme of Post-War Educational Development in India.
4. केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय बोर्ड की रिपोर्ट : Report by the Central Advisory Board of Education.

### सार्जेंट-योजना के उद्देश्य Aims of the Sargent Plan

"सार्जेंट-रिपोर्ट" 12 भागों में विभाजित है। इसमें पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय-शिक्षा तक और शिक्षा के अनेक अन्य वर्गों पर भी सविस्तार विचार किया गया है और उनके विचार के लिए अत्युत्तम सुझावों एवं सिफारिशों को अधरवद्ध किया गया है। इस "रिपोर्ट" में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई है। इस "योजना" के उद्देश्यों के सम्बन्ध में दो लेखकों के विचार दृष्टव्य हैं :—

1. नूरुल्लाह नायक : — "योजना का उद्देश्य — कम-से-कम 40 वर्षों की अवधि में भारत में शैक्षिक योग्यताओं के उसी स्तर का निर्माण करना है, जिस पर इंग्लैंड पहुँच चुका था।"

"The object of the Plan is to create in India, in a period of not less than forty years, the same standard of educational attainments as had already been attained in England"—Nurullah & Naik : *A History of Education in India*, p 834

2. भगवान् दयाल — "योजना का उद्देश्य—313 करोड़ रुपये व्यय करके, शिक्षा की सम्पूर्ण पद्धति का पुनर्संगठन करना था। योजना आठ पंचवर्षीय कार्यक्रमों में पूर्ण की जानी थी। प्रथम पंचवर्षीय कार्यक्रम में केवल शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाना था। शेष सात पंचवर्षीय कार्यक्रमों में योजना का धीरे-धीरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उस समय तक प्रसार किया जाना था, जब तक कि वह सम्पूर्ण देश में न फैल जाय।"

"The Plan aimed at reorganising the entire system of education at a total cost of 313 crores. The Plan was to be carried out by means of eight five-year programmes. The first five year programme was to be entirely devoted to the training of teachers, while the remaining seven five-year programmes were meant for the gradual extension of the scheme from area to area, till it spread over the whole country"—Bhagwan Dayal. *The Development of Modern Indian Education*, p 160

"मार्जेंट-रिपोर्ट" के उपनिर्वाचित उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि यह भारतीय शिक्षा-प्रणाली का प्रादि में अन्त तक पुनर्संगठन करके, उसे एक उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करना चाहती थी।

### सुझाव व सिफारिशें

#### Suggestions & Recommendations

"मार्जेंट-रिपोर्ट" में शिक्षा के विभिन्न अंगों के विषय में निम्नांकित सुझावों और सिफारिशों को स्थान दिया गया है :—

1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा : Pre-Primary Education — "मार्जेंट-रिपोर्ट" में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विषय में अधोनिर्वाचित सिफारिशों की गई है :—

1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा—राष्ट्रीय शिक्षा-योजना की अनिवार्य अंग है।
2. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष-वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं के लिए होनी चाहिए, और कम-से-कम 10 लाख बच्चों के लिए निम्न-शालाओं (Nursery Schools) की स्थापना की जानी चाहिए।
3. निम्न-शालाओं में शिक्षा दूर हावस में नियुक्त होनी चाहिए।
4. निम्न-शालाओं में केवल अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति हो जानी चाहिए और वे विशेष प्रशिक्षण-प्राप्त होनी चाहिए।
5. निम्न-शालाओं की स्थापना सब बड़े नगरों में की जानी चाहिए। ग्रामों में इन शालाओं की प्रतिबन्धन बेमिद स्कूलों के एक भाग में समाया जाना चाहिए।
6. निम्न-शालाओं में निम्न-शालाओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, पर उनके अभिभावकों में उन्हें नियमित रूप से भेजने का आग्रह किया जाना चाहिए।
7. निम्न-शालाओं का मुख्य उद्देश्य—निम्न-शालाओं की सामाजिक अनुभव और विद्यार्जन की शिक्षा देना होना चाहिए, न कि सामान्य शिक्षा प्रदान करना।

2. प्राथमिक या बेसिक शिक्षा : Primary or Basic Education — प्राथमिक शिक्षा के लिए, "मार्जेंट रिपोर्ट" में कुछ परिवर्तनों के पश्चात् "बेसिक शिक्षा-योजना" को स्वीकार किया है। उनके बेसिक शिक्षा में प्राथमिक और मध्यम (Primary & Middle) स्तरों की शिक्षा को सम्मिलित किया है और उनके सम्बन्ध में अवरोधित सुझाव दिए हैं :—

1. 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सब बालकों की नियुक्त और अनिवार्य शिक्षा से लीनी चाहिए।

2. शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए "उपस्थिति-निरीक्षक-पदाधिरारियों" (Attendance Officers) की नियुक्ति की जानी चाहिए।
3. बेसिक शिक्षा किसी आधारभूत जिले के माध्यम से दी जानी चाहिए।
4. बेसिक शिक्षा को आत्म-निर्भर नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं की बचत कठिन है।
5. बेसिक शिक्षा को दो भागों में विभक्त किया जाना चाहिए :—(1) जूनियर बेसिक शिक्षा, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और (2) सीनियर बेसिक शिक्षा, 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए।
6. जूनियर बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इन स्कूलों में सह-शिक्षा प्रचलित की जा सकती है।
7. सीनियर बेसिक स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा साधारणतया नहीं दी जानी चाहिए। किन्तु, यदि किसी प्रान्त में अंग्रेजी की मांग है, तो "प्रान्तीय शिक्षा-विभाग" उसकी पढ़ाई को आज्ञा दे सकता है।
8. दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम —मातृभाषा होनी चाहिए।
9. दोनों प्रकार के स्कूलों में बाह्य परीक्षा के बजाय आन्तरिक परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
10. परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट दिए जाने चाहिए।

3. हाई-स्कूल-शिक्षा High School Education—“साबैन्ट-रिपोर्ट” में स्कूल की शिक्षा के विषय में अधोलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं :—

1. हाई स्कूल की शिक्षा 6 वर्ष की, अर्थात् 11 से 17 वर्ष तक की आयु के बालकों और बालिकाओं के लिए होनी चाहिए।
2. हाई स्कूलों में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, जिनकी क्षमताएं औद्योगिक छात्रों में स्पष्टतः ऊँची हो।
3. जूनियर बेसिक स्कूलों की शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों में से लगभग 20 प्रतिशत को हाई स्कूलों में प्रवेश दिया जाना चाहिए।
4. हाई स्कूलों में 11 वर्ष से कम आयु के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
5. हाई स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 14 वर्ष की आयु की मर्यादा तक अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।
6. हाई स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों में से केवल 50 प्रतिशत छात्रों से नुस्खे लिया जाना चाहिए और शेष 50 प्रतिशत को नि-नुस्ख शिक्षा दी जानी चाहिए।

7. हाई स्कूलों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी छात्रों की छात्रवृत्तियों दी जानी चाहिए ।
8. हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम—मातृभाषा होनी चाहिए और अंग्रेजी की शिक्षा, द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में दी जानी चाहिए ।
9. हाई स्कूलों का पाठ्यक्रम—विश्वविद्यालय-शिक्षा का आधार-मात्र बनकर, अपने आप-में सम्पूर्ण होना चाहिए, ताकि इस पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त छात्रों को किसी व्यवसाय को करने की योग्यता प्राप्त हो जाय ।
10. हाई स्कूल दो प्रकार के होने चाहिए :—(1) साहित्यिक हाई स्कूल (Academic High Schools), और (2) तकनीकी हाई स्कूल (Technical High Schools) ।
11. दोनों प्रकार के हाई स्कूलों में अग्रलिखित विषयों की शिक्षा सामान्य रूप से दी जानी चाहिए :—(1) मातृभाषा, (2) अंग्रेजी, (3) आधुनिक भाषाएँ, (4) भारत तथा विश्व का इतिहास, (5) भारत तथा विश्व का भूगोल, (6) गणित, (7) विज्ञान, (8) अर्थशास्त्र, (9) कृषि, (10) कला, (11) संगीत, और (12) प्रारंभिक शिक्षा ।
12. उक्त सामान्य विषयों के अलावा साहित्यिक हाई स्कूलों में प्राच्य-भाषाओं (Classical Languages) और नागरिक-शास्त्र की भी शिक्षा दी जानी चाहिए । चालिकाओं को गृह-विज्ञान की शिक्षा देने की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ।
13. तकनीकी हाई स्कूलों में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त अग्रलिखित विषयों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए :—(1) काष्ठ-कला, (2) धातु-कला, (3) साधारण इंजीनियरिंग, (4) ड्राइंग, (5) वाणिज्य-सम्बन्धी विषय, (6) बुक बंधिपिंग, (7) फाईटिंग, (8) टाइप-राइटिंग, (9) एकाउन्टेन्टी, और (10) व्यापार-गणित ।
14. हाई स्कूलों में अध्यापक एवं छात्रों का अनुपात 1 : 20 होना चाहिए ।

4. विश्वविद्यालय-शिक्षा : University Education—“सार्जेंट-रिपोर्ट” की विश्वविद्यालय-शिक्षा के सम्बन्ध में अग्रलिखित सिफारिशें हैं :—

1. बी० ए०, बी० एस्-सी० आदि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए ।
2. इंटरमीडिएट कक्षाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए । उनकी 11वीं कक्षा को हाई स्कूल से और 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए ।
3. विश्वविद्यालयों के प्रवेश-नियमों को इतना कठोर बना दिया जाना

चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने वाले 15 छात्रों में से केवल 1 छात्र ही विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सके।

4. विश्वविद्यालयों के शिक्षा-स्तर का उन्नयन करने के लिए अपेक्षित 3 उपाय अपनाए जाने चाहिए :—(1) योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, (2) शिक्षकों के वेतन-क्रम में वृद्धि, और (3) शिक्षकों की सेवा-शर्तों (Conditions of Service) में सुधार।
5. भारत के सब विश्वविद्यालयों में एकरूपता स्थापित करने के लिए "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" (University Grants Commission) का संगठन किया जाना चाहिए।
6. विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के पारस्परिक सम्बन्धों में घनिष्ठता उत्पन्न करने के लिए "उपस्था-प्रणाली" (Tutorial System) का प्रचलन प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

5. तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा : Technical & Vocational Education—“सार्जेंट-रिपोर्ट” ने इस बात पर बल दिया है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए “पूर्ण-कालीन” (Full Time) और “अल्प-कालीन” (Part Time) शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। इन संस्थाओं में भारतीय उद्योगों के लिए निम्नांकित 4 प्रकार के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाना चाहिए :—

1. मुख्य अधिकारी व अनुसन्धानकर्ता Chief Executives & Research Workers—इनकी शिक्षा—प्रौद्योगिक (Technological) या इसी प्रकार की किसी अन्य उच्च शिक्षा-संस्था में होनी चाहिए।

2. साधारण अधिकारी, फोरमैन आदि Minor Executives, Foremen etc.—इनकी शिक्षा तकनीकी हाई स्कूलों में होनी चाहिए।

3. कुशल शिल्पकार : Skilled Craftsmen—इनकी शिक्षा व्यापार या उद्योग के स्कूलों (Trade or Industrial Schools) में होनी चाहिए।

3. अर्ध-कुशल व अकुशल धमिक Semi-Skilled & Unskilled Labour—इनकी शिक्षा सीनियर बेसिक ज्यूनियर मिडिल स्कूलों (Senior Basic, or Middle Schools) में होनी चाहिए।

4. वयस्क-शिक्षा . Adult Education—“सार्जेंट-रिपोर्ट” में प्रजातन्त्र के आदर्शों को सफल बनाने के लिए वयस्क-शिक्षा को परम आवश्यक बताया गया है और इसके सम्बन्ध में अधोनिहित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं :—

1. 10 से 40 वर्ष तक की अवस्था के वयस्कों के लिए वयस्क-शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए।
2. वयस्क-शिक्षा की अवधि कम-से-कम एक वर्ष की होनी चाहिए।
3. वयस्क-शिक्षा के पाठ्यक्रम में पढ़ने, लिखने और जवर्जित '10'

के अलावा संगीत, इतिहास, अर्थशास्त्र, तार्किक-शास्त्र आदि विषयों को भी स्थान दिया जाना चाहिए।

4. वयस्क-शिक्षा को रोचक और हितप्रद बनाने के लिए सिनेमा, रेडियो, मृत्पत्र, चलचित्र, ग्रामोफोन, मैजिक लैन्टर्न, अभिनय आदि के कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए।
5. पुस्तकों, स्थियों, बालकों और युवतियों के लिए पृथक् विद्यालयों की सृष्टि की जानी चाहिए।
6. वयस्कों के लिए सम्पूर्ण देश में जगह-जगह पर 20 वर्ष की अवधि में पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

#### 7. अध्यापकों का प्रशिक्षण : 'Training of Teachers—“मार्जेन्ट-रिपोर्ट”

में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा की योजना को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की विशाल संख्या की आवश्यकता है। “रिपोर्ट” ने इस संख्या का अनुमान विभिन्न प्रकार के स्कूलों में शिक्षक और छात्रों का निम्नांकित अनुपात निर्धारित करके लगाया है :—

	शिक्षक	छात्र
1. पूर्व-प्राथमिक व जूनियर बेसिक स्कूल	1	30
2. सीनियर बेसिक स्कूल	1	25
3. हाई स्कूल	1	20

इस अनुपात के अनुसार “रिपोर्ट” ने शिक्षकों की संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया है :—

1. प्रशिक्षित उप-स्नातक Trained Under-Graduates	लगभग 20 लाख
2. प्रशिक्षित स्नातक Trained Graduates	“ 2 लाख

इतनी विशाल संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए “रिपोर्ट” ने यह मिश्रण की है कि अप्रॉकिम तीन प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थाएँ समुचित संख्या में स्थापित की जानी चाहिए :—

1. पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए।
2. जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए।
3. हाई स्कूलों के शिक्षकों के लिए।

अन्त में, “रिपोर्ट” ने शिक्षक-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 4 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं; यथा :—

1. प्रशिक्षण-संस्थाएँ यथाम्भव आवास (Residential) होनी चाहिए।



2. प्रशिक्षण-संस्थाओं के छात्राध्यापकों से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए ।
3. सब प्रकार के शिक्षकों के लिए "अभिनवन पाठ्यक्रम" (Refresher Course) की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
4. योग्य व्यक्तियों को शिक्षण-व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने के लिए अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए ।

8 अन्य सिफारिशें : Other Recommendations — "सार्जेंट रिपोर्ट" में उल्लिखित जतिरिक्त और भी अनेक विषयों के सम्बन्ध में सिफारिश की गई है । इन विषयों में अश्लेषित महत्वपूर्ण हैं :—(1) छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल की उचित व्यवस्था, (2) विकलांगों (Handicapped) के लिए विनिष्ट विद्यालयों का आयोजन, (3) छात्रों के लिए मनोरंजनात्मक और सामाजिक कार्यों का आयोजन, (4) छात्रों को व्यवसाय का ध्येय करने में परामर्श देने के लिए स्थान-स्थान पर "सेवा-योजनालयों" (Employment Bureaus) की स्थापना, और (5) राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की स्थापना के लिए केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों में निकट सहयोग ।

### सार्जेंट-रिपोर्ट का मूल्यांकन Estimate of Sargent-Report

भारतीय शिक्षा के इतिहास में "सार्जेंट-रिपोर्ट" का अपना विशेष स्थान है । इससे पूर्व भारत में आयोगों की नियुक्तियाँ हुई थी, ममितियों का समूह बना था, सरकारी-प्रस्तावों की उद्घोषणा हुई थी । किन्तु, इनमें से एक को भी "सार्जेंट-रिपोर्ट" के समकक्ष होने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इन "रिपोर्ट" में व्यापकता थी, भारतीय शिक्षा का सम्पूर्ण विषय था और उसके दोषों का निर्भीक वर्णन था ।

इन सब गुणों की उपस्थिति में भी कुछ नुस्खाखोरी करने वालों ने इसमें कुछ चूटियाँ खोज ली हैं । उनका आरोह है कि इस "रिपोर्ट" में प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षा-योजना में मौनिकता का पूर्ण अभाव है । यह योजना—शिक्षा का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है, जो अप्राप्य है । योजना अपूर्ण है, क्योंकि यह ग्रामीण शिक्षा के बारे में विन्युक्त मौन है । यह इनकी छर्बीली काल्पनिक और विलम्बकारी है कि यह भारत जैसे दरिद्र देश के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है ।

"सार्जेंट-रिपोर्ट" के उपरिचलित दोषों और गुणों का मूखम विशेषण करके और उसे उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की कमोटियों पर कम के, भारत के माने हुए शिक्षाशास्त्रियों ने इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । इन शिक्षाशास्त्रियों में सर्वमान्य के० जी० संपर्जन ने अपने अप्रशिक्षित विचार लेखबद्ध किए हैं :—"सार्जेंट-रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा की प्रथम व्यापक योजना है । यह इस धारणा को स्वीकार नहीं करती है कि भारत—शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों से सर्वे निम्नतर स्तर पर रहेगा । यह इस विश्वास पर आधारित है कि अन्य देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो तरकता प्राप्त की है, उसे प्राप्त करने की इस देश में भी पर्याप्त क्षमता है ।"

"The Sargent Report is the first comprehensive scheme of national education. It does not start with the assumption that India was destined to occupy a position of educational inferiority in the comity of nations. It is based on the conviction that what other countries have achieved in the field of education is well within the competence of this country."—K. G. Saiyidain : *Education, Culture & Social Order*, p. 507.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Explain the importance of "Sargent-Report" and summarise its main recommendations.  
 "सार्जेंट-रिपोर्ट" का महत्त्व बताइए और उसकी मुख्य सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. Write a reasoned criticism of the "Sargent-Plan" as a scheme of National Education.  
 राष्ट्रीय शिक्षा की योजना के रूप में "सार्जेंट-योजना" की यथोचित समीक्षा कीजिए।

# 18

## विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग

(राधाकृष्णन् कमिशन)

UNIVERSITY EDUCATION COMMISSION

(Radhakrishnan Commission)

(1948-1949)

"The student is not created for the university, but the university exists for the student."—*Radhakrishnan Commission Report*

### विषय-प्रवेश

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत-सरकार ने इस देश की शिक्षा को सुनियोजित और सुसंगठित करने का दृढ़ निश्चय लिया। उसने यह कार्य विश्व-विद्यालय-शिक्षा से आरम्भ किया। इसका मुख्य कारण यह था कि स्वाधीनता के युग में प्रवेश करने के समय में भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, किन्तु उनमें शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण इस देश के निवासियों में व्यापक असन्तोष था। इसके अतिरिक्त, ये विश्व-विद्यालय—भारत की नवीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ थे।

उच्च शिक्षा के उत्तुंग और अन्य दोषों का निवारण करने के विचार से भारत सरकार ने इस शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुभव किया। उसी समय के आन पास, उच्च शिक्षा की नृत्कालीन कमियों में अवगत होने के कारण "अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा-परिषद्" (Inter-University Board of Education) और "केंद्रीय शिक्षा-मन्त्रालय बोर्ड" (Central Advisory Board of Education)

ने भारत-सरकार के समक्ष एक अखिल-भारतीय विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके, 4 नवम्बर, 1948 को "विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग" की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् थे। अतः उनके नाम से इस "आयोग" को "राधाकृष्णन् कमिशन" भी कहा जाता है।

### आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य

#### Aims of the Appointment of the Commission

"आयोग" की नियुक्ति के उद्देश्य, स्वयं "आयोग" के शब्दों में अप्रकित थे :— "भारतीय विश्वविद्यालय-शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना और उन सुधारों एवं विस्तारों के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना, जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए वांछनीय हों।"

"To report on Indian University Education and suggest improvements and extensions that may be desirable to suit present and future requirements of the country."—*Report of the University Education Commission*, p. 1.

### आयोग के जाँच के विषय

#### Terms of Reference of the Commission

"आयोग" से लगभग 20 विषयों की जाँच करने के लिए कहा गया था, जिनमें से मुख्य थे :—

1. भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा एवं अनुसन्धान-कार्य के उद्देश्य।
2. भारतीय विश्वविद्यालयों के संगठन, नियन्त्रण, कार्य-क्षेत्र एवं विधान के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन।
3. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कॉलेजों में शिक्षा एवं परीक्षा के स्तरों में उत्थान।
4. विश्वविद्यालय-शिक्षा की अवधि, माध्यम एवं पाठ्यक्रम।
5. विश्वविद्यालयों में वार्षिक शिक्षा।
6. प्रादेशिक या अन्य आधार पर अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना।
7. अध्यापकों की योग्यताएँ, सेवान्तराएँ, वेतन, कार्य एवं अधिकार।
8. छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों, उपकक्षा-कार्य (Tutorial Work) आदि का संयोजन।

सारांश में, "आयोग" ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के सब अंगों का अध्ययन करने और उनमें सुधार करने के लिए सुझाव देने की कहा गया। "आयोग" ने इन कार्यों को एक वर्ष से कम समय में ही समाप्त करके, 25 अगस्त, 1949 को अपना प्रतिवेदन—भारत-सरकार को प्रेषित कर दिया।

## आयोग के सुझाव व सिफारिशें

### Suggestions & Recommendations of the Commission

"आयोग" ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के सभी अंगों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए हैं और उनमें सुधार करने के लिए ठोस सुझाव भी दिये हैं। हम महत्वपूर्ण अंगों से सम्बन्धित उसके विचारों, सुझावों और सिफारिशों को पृथक्-पृथक् शीर्षकों के अन्तर्गत लेखबद्ध कर रहे हैं; यथा :—

#### 1. विश्वविद्यालय-शिक्षा के उद्देश्य : Aims of University Education—

"आयोग" ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य बनाए हैं :—

1. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में महान् परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है। अतः अब उन्हें राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व प्रद्वेषण कर मकाने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय—समाज-सुधार के कार्य में महान् योग दे सकते हैं। अतः उन्हें दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक माहस्र वाले व्यक्तियों (Intellectual Adventurers) को जन्म देना चाहिए।
3. विश्वविद्यालयों को प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए, शिक्षा का प्रसार और ज्ञान की प्रोज कर मकाने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए।
4. विश्वविद्यालयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को विस्मृत नहीं करना चाहिए। अतः उन्हें राष्ट्रीय विरासत को अपनाने वाले और उसमें योगदान देने वाले नवयुवकों को तैयार करना चाहिए।
5. विश्वविद्यालय—देश की सम्यता एवं संस्कृति के रक्षक और पोषक हैं। अतः उन्हें सम्यता एवं संस्कृति के अपभ्रूतों का निर्माण करना चाहिए।
6. शिक्षा को व्यक्ति के जन्मजात गुणों की प्रोज करके, उनका विकास करना चाहिए। विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों के प्रति इन दोनों कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
7. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों का न केवल मानसिक विकास, बल्कि शारीरिक विकास भी करना चाहिए।
8. "आयोग" के जन्म में — "हम न्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवं अन्धता की प्राप्ति द्वारा प्रजातन्त्र की प्रोज में सलग्न हैं। अतः हमारे विश्वविद्यालयों को अनिवार्यतः इन आदर्शों का प्रतीक एवं संरक्षक होना चाहिए।"

2. शिक्षक-वर्ग : Teaching Staff—"आयोग" ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की दशा में सुधार करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए हैं :—

1. शिक्षकों को "प्रॉविडेण्ट-फ़ंड" की अधिक उत्तम सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस फ़ंड में शिक्षक एवं विश्वविद्यालय—दोनों को 8-8 प्रतिशत देना चाहिए।
2. शिक्षकों के लिए किराए के निवास-स्थानों की विश्वविद्यालय के समीप ही व्यवस्था होनी चाहिए।
3. शिक्षकों (Teachers) को 60 वर्ष की अवस्था में अपने पदों से अवकाश दिया जाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य वाले प्रोफ़ेसरों (Professors) को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
4. शिक्षकों को अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का और सम्पूर्ण सेवा-काल में 3 वर्ष का आधे वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए।
5. शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घंटे (Periods) से अधिक का शिक्षण-कार्य नहीं दिया जाना चाहिए।

3. शिक्षण के स्तर : Standards of Teaching—"आयोग" ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण-स्तर का उन्नयन करने के लिए अवोलिखित सिफ़ारिशें की हैं :—

1. छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए, शिक्षण-विश्वविद्यालयों में 3,000 और उनसे सम्बद्ध कॉलेजों में 1,500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए।
2. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा-दिवसों को छोड़कर, एक वर्ष में कम-से-कम 180 दिन शिक्षण-कार्य किया जाना चाहिए।
3. शिक्षकों के व्याख्यान परिश्रम और सावधानी से तैयार किए जाने चाहिए। उनके व्याख्यानों की पूर्ति करने के लिए लिखित कार्य, ट्यूटोरियल कक्षाओं और पुस्तकालयों में अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
5. स्नातकोत्तर (Post-Graduate) कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याख्यानों में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।
6. स्नातकोत्तर कक्षाओं में विचार-गोष्ठियों (Seminars) की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए।

7. विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के लिए सायंकासीन कक्षाएँ (Evening Classes) प्रारम्भ की जानी चाहिए।
8. परीक्षाओं के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40 प्रतिशत होने चाहिए।

4 पाठ्यक्रम : Courses of Study—“आयोग” के पाठ्यक्रम-सम्बन्धी

विचार व्यंजित हैं :—

1. स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए।
2. स्नातकोत्तर उपाधि—स्नातक बनने के 2 वर्ष पश्चात् और “आनर्स कोर्स” के 1 वर्ष पश्चात् दी जानी चाहिए।
3. विशेषीकृत शिक्षा (Specialization) के दोषों का निवारण करने के लिए विश्वविद्यालयों और माध्यमिक स्कूलों में “सामान्य शिक्षा के सिद्धान्त एवं प्रयोग” (Theory & Practice of General Education) का शिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिए।
4. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य और विशेषीकृत शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
5. कलाओं और विश्वविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, जो 12 वर्ष की विद्यालय-शिक्षा समाप्त कर चुके हों।

5. स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण व अनुसंधान-कार्य . Post-Graduate Training

& Research Work—“आयोग” ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण और अनुसंधान-कार्य के स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए अवतिष्ठित मुद्दाव दिए हैं :—

1. स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में एक विशेष विषय के उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान की विधियों के प्रशिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिए।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश अखिल-भारतीय स्तर पर दिया जाना चाहिए और छात्रों एवं शिक्षकों में घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिए।
3. पी-एच० डी० के छात्रों का चयन, अखिल-भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए और उनके अनुसंधान-कार्य की अवधि दो वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए।
4. एम० एम-सी० एवं पी-एच० डी० के छात्रों को “शिक्षा-मन्त्रालय” द्वारा बड़ी मर्यादा में छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।
5. डी० लिट० और डी० एल-सी० उपाधियों केवल उच्च कोटि के मौखिक एवं प्रकाशित कार्यों पर दी जानी चाहिए।

6. शिक्षा का माध्यम : Medium of Instruction—“आयोग” ने सब राज्यों और जातियों की भाषाओं पर विचार करने के बाद शिक्षा के माध्यम के विषय में निम्नांकित विचार व्यक्त किए हैं :—

1. उच्च शिक्षा का माध्यम—अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएँ होनी चाहिए, पर संघीय भाषा (हिन्दी) को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
2. संघीय भाषा के लिए केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए और इस लिपि के दोषों को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए।
3. उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय-स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए :—(i) मातृभाषा अर्थात् प्रादेशिक भाषा, (ii) हिन्दी अर्थात् संघीय भाषा, और (iii) अंग्रेजी।
4. संघीय और प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
5. विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सम्पर्क में रखने के लिए हाई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा को बनाए रखना चाहिए।

7. परीक्षाएँ : Examinations—“आयोग” ने विश्वविद्यालयों की परीक्षा-प्रणाली को सबसे अधिक दोषपूर्ण पाया है। अतः “आयोग” ने यह विचार प्रकट किया है :—“हमें इस बात का विश्वास है कि यदि हमसे विश्वविद्यालय-शिक्षा में केवल एक बात के बारे में सुझाव देने के लिए कहा जाय, तो वह सुझाव—परीक्षाओं के सम्बन्ध में होगा।” इन परीक्षाओं को दोष-मुक्त करने के लिए, “आयोग” ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1. छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यथाशीघ्र “वस्तुनिष्ठ-प्रगति-परीक्षाओं” का कुलक (Set of Objective Progressive Tests) तैयार किया जाना चाहिए।
2. त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात् न ली जाकर, प्रत्येक वर्ष के अन्त में ली जानी चाहिए। यह परीक्षा—“स्वतः पूर्ण इकाइयों” (Self-Contained Units) में ली जानी चाहिए और छात्रों के लिए प्रत्येक इकाई अर्थात् प्रति वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए।
3. परीक्षाओं के स्तर का उन्नयन करने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 एवं 40 प्रतिशत होने चाहिए।
4. सब विश्वविद्यालयों की सब परीक्षाओं में कृपांक (Grace Marks) देने की पद्धति समाप्त कर दी जानी चाहिए।



5. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम-से-कम 5 वर्ष के शिक्षण का अनुभव रखने वाले 3 सदस्यों का एक पूर्णकालीन बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। इन बोर्ड के निम्नांकित 3 मुख्य कार्य होने चाहिए :—

- (i) विश्वविद्यालयों एवं उनके सम्बद्ध कलेजों के शिक्षकों को वस्तु-निष्ठ परीक्षाओं की नवीन योजनाएँ बनाने में सहायता देना।
- (ii) उक्त शिक्षकों की राष्ट्रव्याप में संगोपन करने के लिए सामग्री देने की व्यवस्था करना।
- (iii) सम्बद्ध कलेजों के छात्रों की प्रगति का समय-समय पर 'प्रगति-परीक्षाओं' द्वारा मूल्यांकन करना।

8. धार्मिक शिक्षा : Religious Education—“आयोग” ने अपने प्रतिवेदन में यह मत व्यक्त किया है कि यद्यपि भारत—धर्म-निरपेक्ष राज्य है, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका अभिप्राय—धार्मिक कट्टरता और सहिष्णुता का निषेध करना है, न कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतन्त्रता का। अपने इन विचारों के आधार पर, “आयोग” ने धार्मिक शिक्षा के विषय में अनेक व्यावहारिक सुझाव दिए हैं, यथा :—

1. सब शिक्षा-संस्थाओं को अपना दैनिक कार्य कुछ मिनट के भीत चिन्तन के पश्चात् प्रारम्भ करना चाहिए।
2. द्वितीय कोर्स के प्रथम वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं की जीवनीय पढ़ाई जानी चाहिए, यथा—बुद्ध, ईसा, गांधी, गुरु, कबीर, नानक, माधव, गुरुगान, रामानुज, मुहम्मद एवं कनफ्यू-सियस।
3. द्वितीय कोर्स के द्वितीय वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थों में से सार्व-त्राणिक महत्त्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाए जाने चाहिए।
4. द्वितीय कोर्स के तृतीय वर्ष में धर्म-दर्शन (Philosophy of Religion) की मुख्य समस्याएँ पढ़ाई जानी चाहिए।

9. व्यावसायिक शिक्षा : Professional Education —“आयोग” ने व्याव-सायिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया है और उसके विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में अपनी विचारों को विगिन रूप प्रदान किया है, यथा —

(i) कृषि : Agriculture

1. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया जाना चाहिए।
2. छात्रों की कृषि का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रायोगिक क्षेत्रों में कृषि शिक्षा की समस्याओं की स्थापना की जानी चाहिए।

3. कृषि के वर्तमान कॉलेजों को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देकर, अधिक साधन-सम्पन्न बनाया जाना चाहिए ।
4. कृषि के नवीन कॉलेजों को यथासम्भव नवीन ग्रामीण विश्वविद्यालयों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।
5. कृषि-अनुसंधान-कार्य के लिए, केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों द्वारा "प्रयोगात्मक फार्म" (Experimental Farms) खोले जाने चाहिए ।

## (ii) वाणिज्य : Commerce

1. बी० कॉम० की शिक्षा प्राप्त करते समय, छात्रों को 3 या 4 प्रकार की विभिन्न व्यावसायिक फ़र्मों में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।
2. बी० कॉम० परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनने का परामर्श दिया जाना चाहिए ।
3. एम० कॉम० में केवल विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को अध्ययन करने की अनुमति दी जानी चाहिए । इस परीक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ।

## (iii) शिक्षण : Teaching

1. प्रशिक्षण-कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संशोधन एवं सुधार किया जाना चाहिए और पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अध्यापन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ।
2. छायाध्यापकों के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन करने के समय, उनकी शिक्षण-योग्यता को विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिए ।
3. प्रशिक्षण-कॉलेजों में अधिकांश अध्यापक वही होने चाहिए, जो स्कूलों में पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हों ।
4. शिक्षा-सिद्धान्त के पाठ्यक्रम को लचीला एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए ।
5. एम० एड० की डिग्री के लिए, केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कुछ वर्षों का शिक्षण-अनुभव प्राप्त कर चुके हों ।

## (iv) इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी : Engineering & Technology

1. वर्तमान इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की संस्थाओं को देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाना चाहिए और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जानी चाहिए ।
2. फ़ोरमैन, ट्राइडमैन एवं ओवरसियरों की शिक्षा देने वाले इंजीनियरिंग

सूत्रों की सहायता में गृहीत करने के लिए उद्यम उठाए जाने चाहिए।

3. देश की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न प्रकार की सहायता का शिलान्यास किया जाना चाहिए।
4. इंजीनियरिंग के सूत्रों एवं कलियों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को कारखानों में कार्य करके, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए।
5. उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नॉलॉजिकल संस्थाओं (Technological Institutes) की शीघ्र-से-शीघ्र गृहीत की जानी चाहिए।

#### (v) कानून : Law

1. कानून का अध्ययन करने की आज्ञा केवल उन्हीं छात्रों को दी जानी चाहिए जो 3 वर्ष के "पूर्व-कानूनी एवं सामान्य डिग्री कोर्स" (Pre-Legal & General Degree Course) को पास कर चुके हों।
2. कानून के विशेष विषयों के पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए।
3. कानून के विद्यार्थियों को अपने अध्ययन-काल में अन्य डिग्री कोर्स लेने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जानी चाहिए।
4. कानून के अध्यापकों में "पूर्णकालीन" और "अल्पकालीन" दोनों प्रकार के अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए।
5. प्रत्येक स्थान को कानून की कक्षाओं में कानून-सम्बन्धी अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए।

#### (vi) चिकित्सा : Medicine

1. किसी भी मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में योग्य अध्यापक और प्रभुर शिक्षण-सामग्री होनी चाहिए।
3. मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र के लिये 10 रोजी होने चाहिए।
4. स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्राथमिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
5. देशी चिकित्सा-पद्धतियों में अनुसंधान-कार्य के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

10. छात्र-क्रियाएँ व कल्याण : Student's Activities & Welfare—  
 “आयोग” का कथन है :—“छात्र का निर्माण—विश्वविद्यालय के लिए नहीं, वरन् विश्वविद्यालय का निर्माण—छात्र के लिए होता है। अतः विश्वविद्यालय को प्रत्येक सम्भव प्रयास एवं उपाय से छात्रों की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्णतम् और अधिकतम् विकास करना चाहिए।” अपनी इस धारणा के अनुसार, “आयोग” ने छात्रों की क्रियाओं और कल्याण के लिए अधोलिखित सुभाव उपस्थित किए हैं :—

1. प्रवेश के समय और उसके पश्चात् एक वर्ष में कम-से-कम एक बार प्रत्येक छात्र एवं छात्रा की निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।
2. प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की चिकित्सा के लिए एक चिकित्सालय होना चाहिए।
3. छात्रों को मध्याह्न के समय उचित मूल्य पर पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए।
4. प्रत्येक विश्वविद्यालय में और प्रत्येक सम्बद्ध कॉलेज में छात्रों के स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए एक “स्वास्थ्य-शिक्षा-निर्देशक” (Director of Physical Education) की नियुक्ति की जानी चाहिए।
5. छात्रों को स्वस्थ रखने के लिए जेमनेशियमों, व्यायामशालाओं, खेल के मैदानों आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. सब छात्रों एवं छात्राओं के लिए दो वर्ष की शारीरिक शिक्षा अनिवार्य बना दी जानी चाहिए।
7. सब कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में एन० सी० सी० की स्थापना की जानी चाहिए और छात्रों को उसका सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
8. सब कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उत्तम प्रकार के छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें शाकाहारी एवं अशाकाहारी—दोनों प्रकार के भोजन का प्रवन्व होना चाहिए।
9. छात्र-संघों (Students' Unions) को छात्रों की सामूहिक क्रियाओं का प्रमुख केन्द्र होना चाहिए। इन संघों का संचालन, छात्रों के द्वारा एवं छात्रों के लिए किया जाना चाहिए। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
10. छात्रों की प्रशासन में रुचि उत्पन्न करने के लिए “प्रॉक्टोरियल-प्रणाली” (Proctorial System) का प्रचलन किया जाना चाहिए।
11. प्रत्येक विश्वविद्यालय में ‘छात्र-कल्याण-सलाहकार बोर्ड’ (Advisory Board of Student Welfare) का निर्माण किया जाना चाहिए।

11. ग्रामीण विश्वविद्यालय : Rural Universities—"आयोग" का कथन है कि बड़े नगरों में स्थापित होने के कारण भारत के विश्वविद्यालयों को यहाँ के ग्रामीणों से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि भारत ग्रामीणों का देश है, इसलिए यह परम आवश्यक है कि ग्रामीण भारत को सामान्य उपरति और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण कनिष्ठों और विश्वविद्यालयों की पद्धति को अविनाश्य आरम्भ दिया जाय। अपने दम विचार में अनुप्राणित होकर, "आयोग" ने ग्राम-नियामितियों की निम्नलिखित विषय में अग्रगण्य सुझाव दिये हैं :—

1. ग्रामों में छोटे और मायागिक (Residential) स्नातक-पूर्व कनिष्ठों की स्थापना की जानी चाहिए। इन कनिष्ठों के केन्द्र में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. एक कनिष्ठ के छात्रों की संख्या लगभग 300 और विश्वविद्यालय एवं उमते सम्बन्धित गुरु कनिष्ठों के छात्रों की संख्या 2,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. गुरु कनिष्ठों के लिए पूर्ण अस्थापक होने चाहिए, किन्तु एक विश्व-विद्यालय में सम्बन्धित अधिक से अधिक कालों के लिए पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, खेल के मैदानों आदि की व्यवस्था एक ही स्थान पर होनी चाहिए।
4. ग्रामीण कनिष्ठों का प्रमुख उद्देश्य -विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा देना और उनकी व्यक्तिगत रचनाएँ एवं मनोवृत्तियों का अधिकतम विकास करना होना चाहिए।
5. ग्रामीण कनिष्ठों में स्नातक-पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में या व्यावसायिक स्कूल में किसी विशेष विषय का अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
6. स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दम प्रसार विभाजन दिया जाना चाहिए कि जो छात्र, स्नातक-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे कुछ विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा भी ग्रहण कर सकें।

### आयोग का मूल्यांकन

#### Estimate of the Commission

"राधाकृष्णन् समीक्षण" ने विश्वविद्यालय-निर्माण के सभी पक्षों का विस्तृत विधिक अध्ययन करने के पश्चात् उनसे मजबूत बनाने के लिए व्यावहारिक रचनात्मक सुझाव दिए। भारत के लगभग सभी ध्येष्ट शिक्षा-समर्थकों ने इन सुझावों में विश्वविद्यालय-निर्माण के नवीन स्वरूप का मदेन पक्ष है। ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की ओर जनता एवं सरकार का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित करने का ध्येय इसी "समीक्षण" को प्राप्त है। इसी की मार्गचित्र निर्धारित की

स्वीकार करके, भारत-सरकार ने 1954 में "ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति" (Rural Higher Education Committee) का निर्माण करके ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व उसको सौंप दिया।

सम्भवतः यह कहना सत्य से दूर न होगा कि आज तक भारत में विश्व-विद्यालय-शिक्षा का निरीक्षण करने और उसके सुधार के लिए सुझाव देने के विचार से जिन आयोगों और समितियों का आविर्भाव हुआ है, उनमें "विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग" का नाम ही सबसे पहले लिया जाता है। यदि हमारी सरकार ने उसके सब सुझावों और प्रस्तावों को क्रियान्वित कर दिया होता, तो आज हमारी विश्वविद्यालय-शिक्षा का नक्शा ही कुछ और होता। इस तथ्य से पूर्णतया अवगत होने के कारण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने जनता को अपना यह संदेश प्रसारित किया :—

"विश्वविद्यालय-आयोग के प्रतिवेदन का महत्त्व अधिकांश रूप में इस बात में है कि वह इस देश की प्रचलित शिक्षा-प्रणालि में आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करता है, और इस आधार पर उसकी शिक्षा-विषयक समस्याओं की विवेचना करता है। यही कारण है कि प्रतिवेदन को अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों के सुझाव देने पड़े हैं। साथ ही, प्रतिवेदन का एक गुण यह भी है कि वह अतीत से पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करना चाहता है, वरन् उसमें उपलब्ध सर्वोत्तम बातों को सुरक्षित रखना चाहता है।"

"The value of the University Commission Report lies very largely, in the fact that it recognises the necessity for a fundamental change in the set-up of things in this country and proceeds to deal with its educational problems on that basis. It has, therefore, had to recommend many revolutionary changes. It has, further, the merit of not contemplating a complete break with the past but of conserving the best that is available."—*Speeches of President Rajendra Prasad*. Publication Division, 1955, p. 5.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Describe briefly the reforms suggested in the University Education of India by the Radhakrishnan Commission  
राधाकृष्णन् आयोग द्वारा भारत की विश्वविद्यालय-शिक्षा के सम्बन्ध में प्रस्तावित सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. What, according to the Radhakrishnan Commission should be the aims of University Education in India? How far do you agree with them?

राष्ट्राध्यक्ष आयोग के अनुसार भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए ? आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं ?

3. Express the views of the University Education Commission on the following:—(a) Rural Universities, (b) Reform in Examinations, and (c) Medium of Instruction.

अवलिखित पर विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग के विचारों को व्यक्त कीजिए :—(अ) ग्रामीण विश्वविद्यालय, (ब) परीक्षाओं में सुधार, और (स) शिक्षा का माध्यम ।

6. **माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण है।** अतः यह छात्रों को अपनी रुचियाँ एवं मनोवृत्तियों के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर नहीं देती है।
7. **शिक्षण-विधियाँ परम्परागत होने के कारण छात्रों को प्रभावित नहीं करती हैं और परीक्षा-प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं लेती है।**
8. **अंग्रेजी—शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन का अनिवार्य विषय है।** अतः जिन छात्रों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, वे इसके अध्ययन में अपनी शक्ति एवं समय को नष्ट करते हैं।

**2. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य : Aims of Secondary Education—**  
 “आयोग” ने भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, माध्यमिक शिक्षा के अग्रलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं :—

**1. जनतन्त्रीय नागरिकता का विकास : Development of Democratic Citizenship—**माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य—छात्रों में जनतन्त्रीय नागरिकता का विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए, जिससे छात्रों में अनुशासन, देश-प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, स्पष्ट विचार आदि गुणों का विकास हो। इन गुणों से सम्पन्न होकर, छात्र इस देश के योग्य नागरिक बनेंगे और भारत में धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र की स्थापना में योग देंगे। इसी गणतन्त्र की स्थापना करना भारत का उद्देश्य है।

**2. व्यावसायिक कुशलता में उन्नति : Improvement of Vocational Efficiency—**माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य—छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा से छात्रों और देश—दोनों का हित होगा। छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् किसी व्यवसाय को स्वतन्त्र रूप से ग्रहण कर सकेंगे। अतः उनको नौकरी खोजने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। देश का हित यह होगा कि उसे अपने विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति सरलता से मिल जायेंगे।

**3. व्यक्तित्व का विकास : Development of Personality—**माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य—छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास हो। इस विकास के फल-स्वरूप छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के महत्त्व को समझ सकेंगे और उसकी वृद्धि में योग दे सकेंगे।

**4. नेतृत्व का विकास : Development of Leadership—**माध्यमिक शिक्षा का चौथा और अन्तिम उद्देश्य—छात्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास



करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का आजीवन इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे छात्र—भौतिक, मानसिक, औद्योगिक, व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण कर सकें। प्रजातन्त्र तभी सफल हो सकता है, जब इन क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण करने वाले व्यक्ति उपलब्ध हों।

3. माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठित स्वरूप : *New Organizational Pattern of Secondary Education*—“आयोग” ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन को देश की नवीन परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त बताकर, उसके पुनर्संगठन पर बल दिया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अधाकित सुझाव दिए हैं:—

1. माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्षों की होनी चाहिए।
2. माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था के बालकों एवं बालिकाओं के लिए होनी चाहिए।
3. माध्यमिक शिक्षा की अवधि अधाकित दो स्तरों में विभक्त की जानी चाहिए —
  - (i) 3 वर्षों का मध्यम या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर (*Middle or Junior Secondary or Senior Basic Stage*)।
  - (ii) 4 वर्षों का उच्चतर माध्यमिक स्तर (*Higher Secondary Stage*)।
4. वर्तमान 11 टर्मिनेट कक्षाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए। उनकी 11वीं कक्षा को हाई स्कूलों से और 12वीं कक्षा को कॉलेजों में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए।
5. डिग्री कोर्सों की अवधि 3 वर्षों की कर दी जानी चाहिए।
6. बहुउद्देशीय स्कूलों (*Multi-purpose Schools*) की स्थापना की जानी चाहिए। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नोकरण (*Diversification of Courses*) किया जाना चाहिए, ताकि छात्र अपने विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकें।
7. ग्रामीण स्कूलों में कृषि-शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार दिया जाना चाहिए। अतः इन स्कूलों में उद्यान-विज्ञान (*Horticulture*), पशु-पालन (*Animal Husbandry*) एवं कुटीर उद्योग-पथों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए।
9. बड़े नगरों में प्रौद्योगिकी संस्थानों (*Technological Institutes*) का निर्माण किया जाना चाहिए।

10. गृह-वाणिज्य-विशालयों में वाणिज्य-विज्ञान (Domestic Science) के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

4. भाषाओं का अध्ययन : Study of Languages—“आयोग” ने मुख्यतः तीन भाषाओं के स्थान एवं अध्ययन के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए हैं; यथा :—

(अ) हिन्दी का स्थान—“आयोग” ने इस बात पर बल दिया है कि हिन्दी को विद्यालय-स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। इस पक्ष में “आयोग” के तर्क निम्नलिखित हैं :—

1. भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया है।
2. कुछ समय के पश्चात् हिन्दी—केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान की भाषा बन जायगी।
3. कुछ समय के उपरान्त हिन्दी—भारत के अधिकांश व्यक्तियों के विचारों के विनिमय की भाषा बन जायगी।
4. राजभाषा के रूप में हिन्दी हम देश की राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढ़ता के विकास में योग देगी।
5. जो व्यक्ति—हिन्दी का अध्ययन नहीं करेंगे, उनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी और न वे हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों के विचारों को समझ पायेंगे।

(ब) अंग्रेजी का स्थान—“आयोग” का कथन है कि अंग्रेजी लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय है। “आयोग” का मत है कि भविष्य में भी अंग्रेजी को इसी स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में “आयोग” ने अगोलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं :—

1. अंग्रेजी—भारत के शिक्षित वर्गों की अत्यन्त लोकप्रिय भाषा है।
2. अंग्रेजी के अध्ययन ने भारत में राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में एकता स्थापित करने में पर्याप्त योग दिया है।
3. भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो स्थिति है, वह अंग्रेजी के अध्ययन का ही परिणाम है।
4. यदि हम राष्ट्रीय भावना से निर्देशित होकर, अंग्रेजी को माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से हटा देंगे, तो इसके परिणाम भारत के हित के प्रतिकूल सिद्ध होंगे।

(स) संस्कृत का स्थान—“आयोग” ने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को स्थान दिए जाने के पक्ष में अनेक अकादमिक तर्क दिए हैं, यथा :—

1. संस्कृत—भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। अतः इसका ज्ञान अनिवार्य है।

2. मरुत ने धामिक एव माधुतिक दृष्टियों में प्यक्तियों को तईव जनी और आदृष्ट किया है । अतः हमरी उंक्षा करना विवेक का प्रमाण नहीं है ।

3. मरुत का अध्ययन करके ही भारत के प्राचीन प्रथों में विद्यमान ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । अतः हमके अध्ययन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ।

5. पाठ्यक्रम : Curriculum—"आयोग" ने पाठ्यक्रम के दोषों का निराकरण करने के विचार में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एव लचीलापन होना चाहिए, ताकि यह छात्रों की विभिन्न रुचियों एव आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके ।

2. पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं एव परिस्थितियों को ध्यान में रग कर किया जाना चाहिए ।

3. पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन में पनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए और छात्रों को हम जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं के सम्पर्क में लाया जाना चाहिए ।

4. पाठ्यक्रम के विषयों का एक-दूसरे में एव जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना चाहिए ।

6 पाठ्यक्रम के विषय Subjects of the Curriculum—"आयोग" ने माध्यमिक शिक्षा की अधि की जिन दो स्तरों में विभाजित किया है, उनके पाठ्यक्रमों में निम्नीकृत विषयों को स्थान दिया है —

(अ) मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्कूल—इन तीनों प्रकार के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में अधलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए —

(i) भाषाएँ (Languages), (ii) सामाजिक अध्ययन (Social Studies), (iii) सामान्य विज्ञान (General Science) (iv) गणित (Mathematics), (v) कला तथा सुगीत (Art & Music), (vi) मिला (Crafts), और (vii) नारीक शिक्षा ।

(ब) हाई व हायर सेकण्डरी स्कूल—“आयोग” ने इन बात की निराकरण की है कि माध्यमिक शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पाठ्यक्रम के विषयों का विविधीकरण (Diversification) किया जाना चाहिए, ताकि वे छात्रों की अतिरुचियों एव आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें । इन उद्देश्य में “आयोग” ने पाठ्यक्रम के विषयों का दो भागों में विभाजन दिया है (i) आन्तरिक विषय (Core Subjects), और

(ii) वैकल्पिक विषय (Optional Subjects) । “आन्तरिक विषयों” का अध्ययन सब छात्रों के लिए अनिवार्य होगा । वैकल्पिक विषयों के 7 समूह होंगे, जिनमें से छात्रों को किसी एक समूह के विषय का अध्ययन करना होगा । इन्हीं विषयों में

का विभिन्नीकरण" किया गया है। "आयोग" के अनुसार, "आन्तरक" एवं "वैकल्पिक" विषय इस प्रकार हैं :—

### 1. आन्तरक विषय : Core Subjects

आन्तरक विषय सभी बालकों एवं बालिकाओं के लिए अनिवार्य हैं और इस प्रकार हैं :—

अ—(1) मातृभाषा, या प्रादेशिक भाषा, या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा (Mother Tongue, or Regional Language, or Mother Tongue & Classical Language)।

(2) निम्नलिखित में से चुनी जाने वाली कोई एक और भाषा :—

(i) हिन्दी (उन छात्रों के लिए, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है)।

(ii) प्रारम्भिक अंग्रेजी (उन छात्रों के लिए, जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है)।

(iii) उच्च अंग्रेजी (उन छात्रों के लिए, जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन किया है)।

(iv) हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा।

(v) अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा।

(vi) एक शास्त्रीय भाषा।

टिप्पणी :—(1) में मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम होगा। (vi) में शास्त्रीय भाषा का पृथक् पाठ्यक्रम होगा।

ब—(1) सामाजिक अध्ययन—अध्ययन के इन विषयों की शिक्षा केवल प्रथम दो वर्षों में दी जायगी।

(2) गणित और सामान्य विज्ञान—इन विषयों की शिक्षा केवल प्रथम दो वर्षों में दी जायगी।

स—अग्रलिखित में से चुना जाने वाला कोई एक शिल्प (Craft) :—

(1) कताई और बुनाई, (2) घातु का काम, (3) दर्जी का काम, (4) लकड़ी का काम, (5) मुद्रण का काम (Typography), (6) वर्कशॉप में काम (Workshop Practice), (7) मॉडल बनाना, (8) उद्यान-विज्ञान, और (9) कसौदा एवं क्रीशिया का काम।

### 2. वैकल्पिक विषय : Optional Subjects

पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण वैकल्पिक विषयों में होगा। वैकल्पिक विषयों के निम्नलिखित 7 समूह होंगे। छात्रों को किसी एक समूह के 3 विषयों का अध्ययन करना होगा।

समूह 1—मानव-विज्ञान : Humanities—(1) एक शास्त्रीय भाषा या 'अ 2' में से न तो गई एक भाषा, (2) इतिहास, (3) भूगोल, (4) अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, (5) मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र, (6) गणित, (7) संगीत, (8) गृह-विज्ञान ।

समूह 2—विज्ञान : Sciences—(1) भौतिक शास्त्र, (2) रसायन-शास्त्र, (3) जीव-शास्त्र, (4) भूगोल, (5) गणित, (6) नरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य-विज्ञान ।

समूह 3—प्राविधिक : Technical—(1) व्यावहारिक गणित (Applied Mathematics) और रैखिक ड्राइंग (Geometrical Drawing), (2) व्यावहारिक विज्ञान, (3) मेकेनिकल इंजीनियरिंग, (4) विद्युत-इंजीनियरिंग ।

समूह 4—वाणिज्य : Commercial—(1) वाणिज्यिक प्रयोग (Commercial Practice), (2) बही-खाता, (3) वाणिज्य-भूगोल या अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, (4) मार्टेडेंड और टाइपराइटिंग ।

समूह 5—कृषि : Agriculture—(1) सामान्य कृषि, (2) पशु-पालन, (3) औषधानि (Horticulture) और बागवानी, (4) कृषि-रसायन (Agricultural Chemistry) और वनस्पति-विज्ञान ।

समूह 6—सहित कलायें Fine Arts—(1) कला का इतिहास, (2) ड्राइंग और डिजाइन बनाना, (3) चित्रकला, (4) मॉडल बनाना, (5) संगीत, (6) नृत्य ।

समूह 7—गृह-विज्ञान Domestic Sciences—(1) गृह-अर्थशास्त्र, (2) पोषण और पाक-कला (Nutrition & Cookery), (3) मातृकला और शिशु-पालन, (4) गृह-प्रबंध और गृह-उपचारण (Home Nursing) ।

8. पाठ्य-पुस्तकें Text-Books—“आयोग” ने पाठ्य-पुस्तकों में सुधार करने के लिए अपोलितित मुभाव अकित किए हैं —

1. पाठ्य-पुस्तकों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक “उच्चस्तरीय पाठ्य-पुस्तक समिति” (High Power Text-Book Committee) का संगठन किया जाना चाहिए ।
2. पुस्तकों में चित्र बनाने की कला में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक मस्या का निर्माण किया जाना चाहिए ।
3. एक विषय में एक पाठ्य-पुस्तक निर्धारित करने के बजाय पाठ्य-पुस्तकों की पर्याप्त सूच्या निश्चित की जानी चाहिए । विद्यालयों को इन पाठ्य-पुस्तकों में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए ।
4. पाठ्य-पुस्तकों एवं अध्ययन की अन्य पुस्तकों में जोध परिवर्तन करने की प्रवर्तित प्रया का अन्त रिया जाना चाहिए ।

8. शिक्षण की प्रावैगिक विधियाँ : Dynamic Methods of Teaching—“आयोग” के विचारानुसार, माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण-विधियाँ—नोरस एवं निर्जोब हैं। अतः उनके स्थान पर प्रावैगिक अथवा सक्रिय एवं स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण-विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। “आयोग” ने इन विधियों का निम्नलिखित प्रकार से स्पष्टीकरण किया है :—

1. शिक्षण-विधियों का उद्देश्य—छात्रों को केवल कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें उचित मूल्यों, उचित दृष्टि-कोणों एवं कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण करना भी होना चाहिए।
2. शिक्षण में मौखिक बातों और कंठस्थ करने के कार्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अतः इन पर बल न देकर, शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक और साम्प्रदायिक हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण-विधियों में “क्रिया-विधि” (Activity Method) एवं “योजना-विधि” (Project Method) को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।
3. छात्रों में सामाजिक जीवन एवं सहयोगी कार्य के गुणों का विकास करने के उद्देश्य से, उनको समूहों में कार्य करने के लिए अधिक-से-अधिक अवसर दिये जाने चाहिए।
4. प्रावैगिक शिक्षण-विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए “प्रयोगात्मक” एवं “प्रदर्शनात्मक” (Experimental & Demonstration) विद्यालयों की विभिन्न स्थानों पर स्थापना की जानी चाहिए।

9. धार्मिक शिक्षा : Religious Instruction—“आयोग” का विचार है कि चरित्र के निर्माण में धार्मिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः उसने धार्मिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. धार्मिक शिक्षा—विद्यालयों में दी जा सकती है।
2. धार्मिक शिक्षा—विद्यालय के शिक्षण के समय से पहले या बाद में दी जानी चाहिए।
3. धार्मिक शिक्षा—छात्रों के अभिभावकों की अनुमति प्राप्त करने के बाद दी जानी चाहिए।
4. धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी छात्र को विवश नहीं किया जाना चाहिए।

10. चरित्र-निर्माण की शिक्षा : Education of Character—“आयोग” ने चरित्र-निर्माण की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है और इसके विषय में निम्न-लिखित सुझाव दिए हैं :—

1. छात्रों के परिवार का निर्माण करना—मध्य शिक्षकों का अनिवार्य उत्तर-दायित्व होना चाहिए ।
2. प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य—परिवार-निर्माण की शिक्षा देना होना चाहिए ।
3. विद्यालय—विस्तृत समाज के अन्दर एक समाज है । अतः ब्रिज मूल्यों और दृष्टिकोणों का राष्ट्रीय जीवन के लिए महत्त्व है, उनको विद्यालय-जीवन में प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए ।
4. छात्रों में उच्च अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए, उनमें और शिक्षकों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिए ।
5. विद्यालयों में स्वशासन-प्रणाली (System of Self-Government) को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए ।
6. विद्यालयों में "अतिरिक्त पाठ्यक्रम-क्रियाओं" (Extra-Curricular Activities) एवं "पाठ्यक्रम-सहायकी क्रियाओं" (Co-Curricular Activities) को स्थान दिया जाना चाहिए ।
7. 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों को राजनीतिक कार्यों से दूर रखने के लिए, सरकार द्वारा कानून बना दिया जाना चाहिए ।
8. मध्य विद्यालयों में एन० सी० सी०, एम्टे-एड, स्नाउटिंग, मेन्ट जॉन एम्बुलेंस एवं अनियंत्रित ड्राइविंग की आवश्यकता की जानी चाहिए ।

11 निर्देशन व परामर्श Guidance & Counselling—"प्रायोग" ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 'पाठ्यक्रम का विविधीकरण' किया है, ताकि छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो । किन्तु, अनुभवहीन बालक—विषयों का चयन करने में कमी कर सकते हैं । अतः उनको निर्देशन और परामर्श दिए जाने की आवश्यकता है । अपनी हम धारणा के आधार पर, "प्रायोग" ने निर्देशन और परामर्श के सम्बन्ध में अधारित सुझाव दिए हैं :-

1. शिक्षा के अधिकारियों को छात्रों के वैयक्तिक निर्देशन के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए ।
2. छात्रों को विभिन्न उद्योगों के कारखानों में ले जाया जाना चाहिए और उनको इन उद्योगों के क्रिये दिखाए जाने चाहिए, ताकि उनको विभिन्न उद्योगों में सम्बन्धित विभिन्न व्यवसायों की जानकारी प्राप्त हो जाय ।
3. छात्रों को व्यवसायों के विषय में सूचना देने के लिए, विद्यालयों में सम्बन्ध-मय पर "जीविकायात्रा सम्मेलनों" (Career Conferences) का आयोजन किया जाना चाहिए ।
4. विद्यालयों में "निर्देशन-अधिकारियों" (Guidance :

“जीविकोपार्जन-शिक्षकों” (Career Masters) की नियुक्ति की जानी चाहिए।

**12. छात्रों का शारीरिक कल्याण : Physical Welfare of Students—**  
“आयोग” का मत है कि छात्रों के शारीरिक कल्याण के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भावी नागरिक हैं। स्वस्थ नागरिक ही अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर, “आयोग” ने छात्रों के शारीरिक कल्याण के सम्बन्ध में अधोलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. सब राज्यों में “स्कूल-स्वास्थ्य-सेवा” (School Medical Service) की सुसंगठित योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए।
2. सब विद्यालयों के सब छात्रों की एक वर्ष में कम-से-कम एक बार स्वास्थ्य-परीक्षा अवश्य की जानी चाहिए।
3. कठिन रोगों में ग्रस्त छात्रों की स्वास्थ्य-परीक्षा बार-बार की जानी चाहिए।
4. रोगी छात्रों एवं छात्राओं का “विद्यालय-स्वास्थ्य-अधिकारी” (School Health Officer) द्वारा मुफ्त उपचार किया जाना चाहिए।
5. छात्रावासों एवं सावास विद्यालयों (Residential Schools) में विद्यार्थियों के लिये पोष्टिक तथा संतुलित भोजन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

**13. परीक्षा व मूल्यांकन : Examination & Evaluation—**“आयोग” की धारणा है कि प्रचलित परीक्षा-प्रणाली—छात्रों के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन करने में असमर्थ है। अतः “आयोग” ने अधोलिखित सुझावों द्वारा एक नवीन परीक्षा-प्रणाली की रूपरेखा प्रदर्शित की है :—

1. बाह्य परीक्षाओं (External Examinations) की संख्या में कमी की जानी चाहिए।
2. माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात् केवल एक “सार्वजनिक परीक्षा” (Public Examination) होनी चाहिए।
3. परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न—निबन्धात्मक ढंग (Essay Type) के न होकर वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के होने चाहिए, ताकि परीक्षाओं के “आत्मगत-तत्त्वों” (Subjective Elements) का अन्त किया जा सके।
4. छात्रों के कार्य का अन्तिम मूल्यांकन करते समय, अग्रलिखित को उचित महत्त्व दिया जाना चाहिए :—आन्तरिक परीक्षाएँ (Internal Examinations), नियतकालिक परीक्षाएँ (Periodical Tests), एवं विद्यालय-अभिलेख (School Records)।



5. बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में न दिया जाकर प्रतीकों (Symbols) में किया जाना चाहिए।

14. अध्यापकों की स्थिति में सुधार : *Improvement of Teacher's Status*—“आयोग” का कथन है :—“अध्यापकों की स्थिति, वेतन एवं कार्य करने की दशाएँ बहुत ही असंतोषजनक हैं।” इस बात को ध्यान में रखकर, “आयोग” ने उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये अनेक सुझावों को प्रस्तुत किया है; यथा :—

1. देश के सब माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पुनरावृत्ति एवं नियुक्ति की विधि समान होनी चाहिए।
2. अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलता है। अतः विनिश्चित गणितियों की नियुक्ति करके, उनसे यह सुझाव माँगा जाना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में उनका वेतन कितना होना चाहिए।
3. सब अध्यापकों के लिये “त्रिमुखी लाभ-योजना” (Triple Benefit Scheme) आरम्भ की जानी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत उनको पन्शन, जीवन-बीमा एवं श्रविकेष्ट फण्ड की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।
4. अध्यापकों की विशेष कठिनाइयों का समाधान करने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिये, “निर्णायक-मण्डल” (Arbitration Board) की नियुक्ति की जानी चाहिए।
5. अध्यापकों का अप्रशिक्षित सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए — उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, उनके लिये विद्यालयों के समीप निवास-स्थान, उनको स्वास्थ्यपूर्ण स्थानों एवं शिक्षा के सम्पत्तियों में जाने के लिए अवकाश एवं यात्रा के खर्चों में सहायता, और चिरिमतलों के मुक्त चिरिमतता।

15. अध्यापक-प्रशिक्षण *Teacher Training*—“आयोग” का विवरण है कि माध्यमिक शिक्षा की जिस नवीन संरचना को वह भारत में देखने का अभिलाषी है, उसका लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता है। भारत की तत्कालीन प्रशिक्षण-अस्थाएँ अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण इस प्रकार के शिक्षकों का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकती हैं। अतः “आयोग” ने अध्यापक-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निम्नांकित विचार व्यक्त किये हैं —

1. प्रशिक्षण-अस्थाएँ दो प्रकार की होनी चाहिए —
  - (i) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों के लिए। इनके प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की होनी चाहिए।
  - (ii) स्नातकों के लिये। इनके प्रशिक्षण की अवधि अभी एक वर्ष की होनी चाहिए, पर कुछ समय के पश्चात् दो वर्ष की कर दी जानी चाहिए।

2. प्रथम प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थाएँ एक बोर्ड के अधीन होनी चाहिए, जिसका निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाना चाहिये। स्नातकों की प्रशिक्षण-संस्थाएँ—विश्वविद्यालयों के अधीन और उन्हीं से सम्बद्ध होनी चाहिए।
3. छात्राध्यापकों को एक या एक से अधिक "अतिरिक्त पाठ्यक्रम-क्रियाओं" (Extra-Curricular Activities) में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4. प्रशिक्षण-संस्थाओं में छात्राध्यापकों से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको राज्य द्वारा शिष्यवृत्तियों (Stipends) के रूप में पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जो अप्रशिक्षित शिक्षक—विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए।
5. प्रशिक्षण-काल में छात्राध्यापकों का प्रशिक्षण-संस्थाओं से सम्बद्ध छात्रावासों में रहना अनिवार्य होना चाहिए, और उनके लिए सामाजिक जीवन से सम्बन्धित क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
6. ट्रेनिंग कॉलेजों अर्थात् स्नातकों की प्रशिक्षण-संस्थाओं में अप्रलिखित की व्यवस्था की जानी चाहिए :—“अभिनवन पाठ्यक्रम” (Refresher Courses), “लघु-गहन-पाठ्यक्रम” (Short Intensive Courses) एवं “कार्यशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण” (Practical Training in Workshops)।
7. ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षण-शास्त्र के महत्त्वपूर्ण अंगों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाना चाहिए। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज के अधीन एक “प्रदर्शनात्मक विद्यालय” (Demonstration School) होना चाहिए।
8. ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों, माध्यमिक स्कूलों के कुछ विशेष प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय-निरीक्षकों में समय-समय पर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विचार-विनिमय होना चाहिए।
9. एम० एड० कक्षाओं में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, जो प्रशिक्षित स्नातक हों और किसी विद्यालय में कम-से-कम तीन वर्ष तक शिक्षण का कार्य कर चुके हों।
10. अध्यापिकाओं के अभाव को दूर करने के लिए विशिष्ट अल्पकालीन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम (Special Part-Time Training Courses) की योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए।

### आयोग का मूल्यांकन

#### Estimate of the Commission

यह कहना असंगत प्रतीत नहीं होता है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में

“मुदानियर कमीशन” का स्थान बेजोह है। उसने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में अनेक सुन्दर एवं सुदूरगामी सुझाव दिए हैं; यथा :—स्वतन्त्र भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शिक्षा के नवीन उद्देश्यों का निर्धारण, छात्रों की व्यक्तिगत अभिवृद्धि एवं अभिवृद्धि के मातृष्ट करने के लिए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, छात्रों को अपनी वैयक्तिक क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुरूप विभिन्न विषयों का अध्ययन सुव्यवस्थित बनाने के लिए बहु-उद्देशीय विद्यालयों की योजना, छात्रों को अपने भावी व्यवसायों का चयन करने में सहायता देने के लिये निर्देशन एवं परामर्श की उपलब्धि, कृषि-प्रधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये कृषि-शिक्षा की अनिवार्यता का समर्थन, देश के उद्योगों एवं व्यवसायों के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की तैयार करने के लिये तकनीकी मूल्यों एवं प्राविधिक कल्याणों की स्थापना, और परीक्षा-प्रणाली, अध्यापक-प्रशिक्षण एवं शिक्षकों की स्थिति में सुधार किये जाने पर बल।

“माध्यमिक शिक्षा-आयोग” ने माध्यमिक शिक्षा को छात्रों एवं देश के लिये उपयोगी बनाने के विचार में उत्तुल्ल के अनिश्चित और भी अनेक व्यावहारिक एवं रचनात्मक सुझाव दिये हैं। उनके कुछ सुझाव वस्तुतः अपूरे, अमान्य एवं अविलम्बित हैं; जैसे, छात्रों द्वारा तीन भाषाओं का अध्ययन और स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिए विचारों में वृद्धि। पर, यदि हम उनके सुझावों पर समग्र रूप में विचार करें, तो हम सन्तुष्ट होकर कह सकते हैं कि उनके सुझावों की क्रियान्वित करने में माध्यमिक शिक्षा का कनेवर बदल जाता, उसका स्वरूप नवीन एवं आकर्षक हो जाता। हम नवीन माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करके, भारत के भावी नागरिक बनने वाले छात्र अपनी मातृभूमि की आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में उत्प्रेरित करके, उनकी बहुमुखी प्रगति में योग देते।

किन्तु, हमारी सरकार ने न जाने क्या सोच-समझ कर, “आयोग” के कुछ चुने हुये सुझावों को ही क्रियान्वित किया। यदि उसने “कमीशन” के अधिकांश सुझावों को भी क्रियान्वित कर दिया होता, तो माध्यमिक शिक्षा में महत्पूर्ण देश का हित हुआ होता। हम ज्ञान इस कथन के सम्बन्ध में “आयोग” के सुझावों की क्रियान्वित किये जाने में पूर्ण भगवान् शक्ति द्वारा धन्य किया जाने वाला विचार अस्ति कर रहे हैं :—“यदि आयोग के अधिकांश सुझावों को क्रियान्वित कर दिया जायगा, तो माध्यमिक शिक्षा इस देश में निश्चित रूप से एक स्वस्थ आधार पर प्रतिष्ठित हो जायगी, जिसके कतलक्ष्य सन्तुलित देश के हित में सुनिश्चित प्रगति सम्भव हो जायगी।”

“If most of the suggestions of the Commission are carried out, Secondary Education in the country will no doubt be placed on a healthy footing, where planned development will be possible in the interest of the country as a whole” —Bhagwan Dayal : *The Development of Modern Indian Education*, pp 329-330.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Describe briefly the recommendations of the Secondary Education Commission regarding the new organizational pattern of Secondary Education.

माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन के विषय में माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफ़ारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. Elucidate the main recommendations of the Mudaliar Commission regarding the National Pattern of Secondary Education as suggested by it

मुदालियर आयोग द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप के विषय में उसकी मुख्य सिफ़ारिशों पर प्रकाश डालिए।

3. Critically examine the recommendations of the Mudaliar Commission for the reorganization of Secondary Education in India.

भारत में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में मुदालियर आयोग की सिफ़ारिशों का आलोचनात्मक निरीक्षण कीजिए।

## 20

शिक्षा-आयोग  
(कोठारी कमिशन)  
EDUCATION COMMISSION  
(Kothari Commission)  
(1964-1966)

"Secondary Education should be increasingly and largely vocationalized, and in higher education a greater emphasis should be placed on agricultural and technical education"—*Education Commission Report*

### विषय-प्रवेश

1882 से 1952 तक भारत में पाँच आयोगों की नियुक्ति हो चुकी थी। इनमें अन्तिम दो, अर्थात् "राधाकृष्णन् कमिशन" (1948-49) एवं "मुदातियर कमिशन" (1952-53) की नियुक्ति स्वतन्त्र भारत में हुई थी। इन दोनों कमिशनों ने शिक्षा के लगभग सभी अंशों की दोषमुक्ति करने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये थे। भारत-सरकार ने बहुत समय तक गोच-विचार करने के बाद, उनमें से कुछ सुझावों को क्रियान्वित किए जाने का आदेश दिया।

सुझावों को क्रियान्वित किए कुछ ही वर्ष बीत थे कि सरकार ने 1964 में "शिक्षा-आयोग" नामक एक नवीन आयोग की नियुक्ति कर दी और उस पर 15 लाख रुपये से अधिक की धनराशि व्यय कर दी।<sup>1</sup> सरकार ने "राधाकृष्णन् एवं

---

1 "आयोग" पर कुल 1,509,175 रुपये व्यय हुए। देखिए, "आयोग" की रिपोर्ट, पृष्ठ 612।

मुदालियर आयोगों" के सुझावों के क्रियान्वित किए जाने के परिणामों को देखने की प्रतीक्षा किए बिना किन कारणों से विवश होकर यह कदम उठाया ? हम पहले इस प्रश्न का उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा को शान्त कर रहे हैं ।

### आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन

#### Reasons & Purposes for Setting-up the Commission

भारत-सरकार ने अपने 14 जुलाई, 1964 के "प्रस्ताव" (Resolution) में आयोग की नियुक्ति के कारणों एवं प्रयोजनों को निम्नांकित शब्दों में प्रकाशित किया<sup>1</sup> :—

1. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही भारत-सरकार ने अपने देश की लोक-प्रिय परम्पराओं एवं आधारभूत मान्यताओं और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के विकास के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है । इस दिशा में कुछ कार्य भी किया गया है, पर सामान्यतः समय की मांगों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास नहीं हुआ है । शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब भी "विचार एवं कार्य" (Thought & Action) में महान् अन्तर विद्यमान है ।
2. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया है । शिक्षा ही सच्चे लोकतन्त्रीय समाज का निर्माण कर सकती है । शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को सम्भव बना सकती है । शिक्षा ही व्यक्ति को श्रेष्ठता एवं पूर्णता की अनन्त खोज के लिए प्रेरणा दे सकती है । इन सब बातों को ध्यान में रख कर अब यह अनिवार्य समझा जाने लगा है कि शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाय, जिसके फलस्वरूप कम-से-कम सम्भव समय में एक ऐसी सुसंतुलित एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास किया जा सके, जो राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान दे ।
3. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही भारत ने राष्ट्रीय विकास के नव-युग में प्रवेश किया है । इस युग में भारत के लक्ष्य हैं :—न केवल शासन, वरन् जीवन के ढंग में भी धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र (Secular Democracy) की स्थापना; जनता की निर्धनता की समाप्ति; कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का शीघ्र विकास करके, सब व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर का उत्थान; आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Techno-

1. Resolution of the Government of India, Setting-up the Education Commission, dated the 14th of July, 1964.



मुदालियर आयोगों" के सुझावों के क्रियान्वित किए जाने के परिणामों को देखने की प्रतीक्षा किए बिना किन कारणों से विवश होकर यह कदम उठाया ? हम पहले इस प्रश्न का उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा को शान्त कर रहे हैं।

### आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन

#### Reasons & Purposes for Setting-up the Commission

भारत-सरकार ने अपने 14 जुलाई, 1964 के "प्रस्ताव" (Resolution) में आयोग की नियुक्ति के कारणों एवं प्रयोजनों को निम्नांकित शब्दों में प्रकाशित किया<sup>1</sup> :—

1. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही भारत-सरकार ने अपने देश की लोक-प्रिय परम्पराओं एवं आधारभूत मान्यताओं और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के विकास के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। इस दिशा में कुछ कार्य भी किया गया है, पर सामान्यतः समय की मांगों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास नहीं हुआ है। शिक्षा के अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अब भी "विचार एवं कार्य" (Thought & Action) में महान् अन्तर विद्यमान है।
2. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया है। शिक्षा ही सच्चे लोकतन्त्रीय समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को सम्भव बना सकती है। शिक्षा ही व्यक्ति को श्रेष्ठता एवं पूर्णता की अनन्त खोज के लिए प्रेरणा दे सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर अब यह अनिवार्य समझा जाने लगा है कि शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाय, जिसके फलस्वरूप कम-से-कम सम्भव समय में एक ऐसी सुसंतुलित एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास किया जा सके, जो राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण योगदान दे।
3. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही भारत ने राष्ट्रीय विकास के नव-युग में प्रवेश किया है। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं :—न केवल शासन, वर्तन् जीवन के ढंग में भी धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र (Secular Democracy) की स्थापना; जनता की निर्धनता की समाप्ति; कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का शीघ्र विकास करके, सब व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर का उन्नयन; आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Techno-

1. *Resolution of the Government of India, Setting-up the Education Commission, dated the 14th of July, 1964.*



logy) का प्रयोग, और परम्परागत आध्यात्मिक मूल्यों से उनका समन्वय; समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करके, धन का उचित वितरण; और सब व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार एवं सांस्कृतिक प्रगति के लिए अवसरों की समानता ।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए निधा को सबसे अधिक शक्तिशाली साधन माना जाने लगा है । किन्तु, निधा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में तभी सहायता दे सकती है, जब उसके परम्परागत स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर दिया जाय, और उसमें आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाय ।

4. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही सब स्तरों पर निधा का असाधारण विस्तार हुआ है । किन्तु, इस विस्तार के बावजूद निधा के अनेक अंगों के सम्बन्ध में व्यापक अमन्तोष है । उदाहरणार्थ—14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है । जनसाधारण की निरक्षरता का समाधान नहीं किया गया है । माध्यमिक स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तरों का पर्याप्त उपभोग नहीं किया गया है । माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों के विभिन्निकरण (Diversification of Courses) की योजना को पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप एक ओर शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी पहले से अधिक हो गई है, और दूसरी ओर अनेक उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का अत्यधिक अभाव है । निधा के कें वेतनों एवं कार्य की दशाओं (Service Conditions) में बाछनीय परिवर्तन नहीं किए गए हैं । निधा की अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर अब भी तीव्र विवाद चल रहा है ।

संक्षेप में, जिस गति में निधा की सख्यात्मक (Quantitative) उप्रति हुई है, उस गति से गुणात्मक (Qualitative) उप्रति नहीं हुई है । इसके अलावा, निधा की गुणात्मक उप्रति के लिए निर्धारित की जाने वाली नीतियों और निश्चित किए जाने वाले कार्यक्रमों को मन्तोपजनक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

5. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही भारत-सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि निधा—राष्ट्रीय प्रगति एवं कल्याण का आधार है । सरकार का यह भी दृढ़ विश्वास है कि देश एवं जनता का जितना हित निधा से हो सकता है, उतना किसी अन्य वस्तु में नहीं हो सकता है । सरकार ने निधा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सब साधनों का प्रयोग करने का और इन पर अधिक-से-अधिक धन व्यय करने का निश्चय कर लिया है । पर यह तभी किया जा सकता है, जब निधा का आधार उत्तम

एवं प्रगतिशील हों। सरकार ने शिक्षा को इस आधार पर प्रतिष्ठित करने का दृढ़ संकल्प किया है।

6. भारत में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास करने के लिए, शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जानी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा-प्रणाली के सब अंग एक-दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। उत्तम माध्यमिक विद्यालयों के बिना शक्तिशाली एवं प्रगतिशील विश्वविद्यालय नहीं हो सकते हैं, और माध्यमिक विद्यालय तभी उत्तम हो सकते हैं, जब प्राथमिक विद्यालय कुशलतापूर्वक कार्य करें।

अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग-अलग जाँच न करके, शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाय। उक्त “प्रस्ताव” के अन्त में लिखा गया है :—“पिछले समय में अनेक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के सीमित क्षेत्रों एवं विशिष्ट अंगों का सर्वेक्षण किया है। इसके विपरीत, अब सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जायगा।”

### आयोग की नियुक्ति

#### Appointment of the Commission

भारत-सरकार ने 14 जुलाई, 1964 के अपने “प्रस्ताव” में नवीन शिक्षा-आयोग की नियुक्ति के कारणों एवं प्रयोजनों का स्पष्टीकरण करके, उसी “प्रस्ताव” के द्वारा “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” (University Grants Commission) के अध्यक्ष—प्रोफ़ेसर डी० एस० कोठारी (D. S. Kothari) की अध्यक्षता में “शिक्षा-आयोग” की नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफ़ेसर कोठारी के नाम से इस “आयोग” को “कोठारी कमिशन” भी कहा जाता है। “आयोग” में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा-विशेषज्ञ थे।

### आयोग के जाँच के विषय

#### Terms of Reference of the Commission

14 जुलाई, 1964 के “प्रस्ताव” में “शिक्षा-आयोग” के जाँच के विषयों को अग्रांकित शब्दों में लेखबद्ध किया गया :—“आयोग—भारत-सरकार की शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सब स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिये सामान्य सिद्धान्तों एवं नीतियों के विषय में परामर्श देगा। आयोग को चिकित्सा या कानून की शिक्षा की समस्याओं की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह इन समस्याओं के उन पक्षों की जाँच कर सकता है, जो व्यापक जाँच की दृष्टि से आवश्यक हों।”

“The Commission will advise the Government of India on the national pattern of education and on general principles and

policies for the development of education at all stages and in all its aspects. It need not, however, examine the problems of medical or legal education, but such aspects of these problems as are necessary for its comprehensive enquiry may be looked into."—*Resolution of the Government of India Setting-up the Education Commission*, dated the 14th of July, 1964.

"शिक्षा-आयोग" को अपना प्रतिवेदन 31 मार्च, 1966 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। किन्तु, कुछ कठिनाइयों के कारण, उसने अपने प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि से लगभग 3 माह पश्चात् अर्थात् 29 जून, 1966 को भारत-सरकार के तत्कालीन शिक्षा-मंत्री एम० सी० चागला (M. C. Chagla) के समक्ष प्रस्तुत किया। लगभग 700 पृष्ठों का यह प्रतिवेदन तीन भागों में विभाजित है और इसका नाम है :—"शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति" (Education & National Development)।

### आयोग के सुझाव व सिफारिशें

#### Suggestions & Recommendations of the Commission

"आयोग" ने शिक्षा के सभी अंगों के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इनमें से महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित हैं :—

1. शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य : Education & National Objectives.
2. शिक्षा की संरचना एवं स्तर : Educational Structure & Standards.
3. अध्यापक की स्थिति : Teacher Status
4. अध्यापक-शिक्षा : Teacher Education.
5. छात्र-संख्या एवं जनवर्त : Enrolment & Manpower
6. शैक्षिक अवसरों की समानता : Equalization of Educational Opportunities
7. विद्यालय-शिक्षा का विस्तार : Expansion of School Education.
8. विद्यालय-पाठ्यक्रम : School Curriculum
9. शिक्षण-विधियाँ, निर्देशन एवं मूल्यांकन : Teaching Methods, Guidance & Evaluation.
10. उच्च शिक्षा : Higher Education.
11. स्त्री-शिक्षा : Women's Education
12. वयस्क-शिक्षा : Adult Education.
13. विज्ञान की शिक्षा : Science Education.

10. अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय-स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
11. इसी भाषा एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की अन्य भाषाओं के अध्ययन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
12. विश्व की कुछ महत्त्वपूर्ण भाषाओं की शिक्षा देने के लिए कुछ स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
13. बी० ए० एवं एम० ए० के स्तरों पर छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
14. सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास को विद्यालय-शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए।
15. सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता, संविधान के सिद्धान्तों एवं लोकतंत्रीय समाजवादी समाज के स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए।

**3. शिक्षा व प्रजातंत्र को सुदृढ़ता : Education & Consolidation of Democracy**—“आयोग” ने शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
2. वयस्क-शिक्षा के कार्यक्रमों को दो उद्देश्यों को सामने रखकर आयोजित किया जाना चाहिए :—(i) निरक्षरता का उन्मूलन, एवं (ii) व्यक्ति की नागरिक एवं राष्ट्रीय कुशलता और सामान्य सांस्कृतिक स्तर का उन्नयन।
3. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए और छात्रों को इन दोनों स्तरों पर कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4. धर्म, वर्ग, लिंग, जाति एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना सब बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर दिए जाने चाहिए।
5. सब व्यक्तियों में वैज्ञानिक विचार एवं दृष्टिकोण का और सहिष्णुता, पहलकदमी, जन-हित, समाज-सेवा, आत्म-निर्भरता, एवं आत्म-अनुशासन के गुणों का विकास किया जाना चाहिए।

**4. शिक्षा व आधुनीकरण : Education & Modernization**—“आयोग” ने शिक्षा द्वारा भारत का आधुनीकरण करने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. आधुनीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी (Technology) का प्रयोग किया जाना चाहिए।
2. आधुनीकरण करने के लिए शिक्षा को महत्त्वपूर्ण साधन बनाया जाना

चाहिए और आयुनीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ।

3. शिक्षा द्वारा छात्रों में उचित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का विकास किया जाना चाहिए ।
4. शिक्षा द्वारा छात्रों में स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय एवं स्वतंत्र अभ्ययन की आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए ।
5. सामान्य व्यक्ति के शैक्षिक स्तर का उन्नयन किया जाना चाहिए ।

5. सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास : Development of Social, Moral & Spiritual Values—“आयोग” ने यह विचार प्रकट किया है कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके, उनके चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए । इन कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, “आयोग” ने अधोलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. सब प्रकार की शिक्षा-मस्थाओं में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । यह शिक्षा—“विश्व-विद्यालय-शिक्षा-आयोग” द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए ।
2. प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जानी चाहिए ।
3. माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के सम्बन्ध में अध्यासकों एवं विद्यार्थियों में विचार-विनिमय होना चाहिए ।
4. उपर्युक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के वातावरण को सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से निमग्नित किया चाहिए । इस कार्य का दायित्व सब शिक्षकों एवं अधिकाशियों पर रखा जाना चाहिए ।
5. प्रत्येक विश्वविद्यालय में “तुलनात्मक धर्म” (Comparative Religion) नामक विभाग की सृष्टि की जानी चाहिए । इस विभाग द्वारा यह तोज की जानी चाहिए कि इन मूल्यों की प्रभावशाली दम से किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है ।

## 2 शिक्षा की संरचना व स्तर

### Educational Structure & Standards

“आयोग” ने शिक्षा की नवीन संरचना अर्थात् डॉबे और शिक्षा-मन्त्रों के उन्नयन के सम्बन्ध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं, हम उनका सर्वत्र निम्नांकित जोड़ों के अन्तर्गत कर रहे हैं :—

1. विद्यालय-शिक्षा की नवीन संरचना : New Structure of School Education—"आयोग" ने विद्यालय-शिक्षा के प्रचलित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इस शिक्षा की नवीन संरचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया है :—

10 वर्ष की सामान्य शिक्षा	2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
	2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा
	3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा
	4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा
	1 से 3 वर्ष की पूर्व-विद्यालय शिक्षा

2. संरचना-सम्बन्धी सुझाव : Suggestions Regarding Structure—"आयोग" ने विद्यालय-शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में अवोर्णित सुझाव दिए हैं :—

1. सामान्य शिक्षा (General Education) की अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए और इसमें प्राथमिक एवं निम्न माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।
2. सामान्य शिक्षा आरम्भ करने से पूर्व छात्रों को 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व-विद्यालय (Pre-School) या पूर्व-प्राथमिक (Pre-Primary) शिक्षा दी जानी चाहिए ।
3. प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष की होनी चाहिए और इसको अग्रलिखित दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए :—(i) 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा (Lower Primary Education), और (ii) 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा (Higher Primary Education) ।
4. निम्न माध्यमिक (Lower Secondary) शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए ।
5. निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अग्रलिखित दो प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए :—(i) 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा, और (ii) 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) ।
6. उच्चतर माध्यमिक (Higher Secondary) शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए ।

7. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अप्राकृत दो प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए :—(i) 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा, और (ii) 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा ।
8. प्रथम सार्वजनिक बाह्य परीक्षा (First Public External Examination) 10 वर्ष की विद्यालय-शिक्षा के पश्चात् होनी चाहिए ।
9. कक्षा 1 में प्रवेश करने की आयु साधारणतः 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
10. 9वीं कक्षा से पृथक् विद्यालय स्थापित किये जाने की प्रचलित विधि का अन्त कर देना चाहिए ।
11. 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय में विनिष्टीकरण (Specialization) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।
12. माध्यमिक विद्यालय केवल अप्राकृत दो प्रकार के होने चाहिए :—  
(i) हाई स्कूल और (ii) हायर सेकण्डरी स्कूल । हाई स्कूलों में शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की और हायर सेकण्डरी स्कूलों में यह अवधि 12 वर्ष की होनी चाहिये ।

3. उच्च शिक्षा का नवीन संरचना . New Structure of Higher Education—“आयोग” ने उच्च शिक्षा की नवीन संरचना इस प्रकार प्रस्तुत की है :—

— —	2 या 3 वर्ष का स्नातकोत्तर-कोर्स
— —	2 या 3 वर्ष का द्वितीय डिग्री-कोर्स
— —	3 वर्ष का प्रथम डिग्री-कोर्स

4. संरचना-सम्बन्धी सुझाव . Suggestions Regarding Structure—  
“आयोग” ने उच्च शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में निम्नांकित सुझाव दिए हैं :—

1. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् प्रथम डिग्री-कोर्स की अवधि कम-से-कम 3 वर्ष की होनी चाहिए ।
2. द्वितीय डिग्री-कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिये ।
3. कुछ विश्वविद्यालयों में “ग्रेजुएट स्कूलों” (Graduate Schools) की गृष्टि की जानी चाहिये, जिनमें कुछ विशेष विषयों में 3 वर्ष के स्नातकोत्तर (Post-Graduate) कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
4. उत्तर-प्रदेश में त्रि-वर्षीय डिग्री कोर्स (Three Year Degree Course) को कुछ विनिष्ट विषयों और विनिष्ट विश्वविद्यालयों में आरम्भ दिया जाना चाहिए । अन्य विश्वविद्यालयों में यह कोर्स 15 से 20 वर्ष की अवधि में आरम्भ कर दिया जाना चाहिए ।

5. स्तरों का उन्नयन : Raising of Standards—"आयोग" ने शिक्षा के सब स्तरों का उन्नयन करने के लिए अधोलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. 10 वर्ष की विद्यालय-शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जानी चाहिए, ताकि इस स्तर पर होने वाले अपव्यय (Wastage) में कमी की जा सके।
2. 10 वर्ष की अवधि में कक्षा 10 के स्तर का इतना उन्नयन कर दिया जाना चाहिए कि वह वर्तमान हायर सेकण्डरी के स्तर पर पहुँच जाय।
3. विश्वविद्यालयों की उपाधियों के स्तरों का उन्नयन करने के लिये, इन उपाधियों के पाठ्यक्रमों में अधिक उन्नत विषय-वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए।
4. शिक्षा-स्तरों का उन्नयन करने के लिए, शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
5. "विद्यालय-संकुलों" (School Complexes) का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके निकटवर्ती सब प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

### 3. अध्यापक की स्थिति

#### Status of Teacher

अध्यापक की वर्तमान करुणाजनक स्थिति का "आयोग" के लगभग सभी सदस्यों को व्यक्तिगत अनुभव था। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि जब तक शिक्षक की स्थिति में समुन्नति नहीं की जायगी, तब तक सुयोग्य व्यक्ति—शिक्षण-व्यवसाय का आर्लिगन नहीं करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर "आयोग" ने यह विचार लिपिवद्ध किया है :— 'शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति को समुन्नत बनाने और प्रतिभाशाली तरुण व्यक्तियों को शिक्षण-व्यवसाय के प्रति पुनः आकर्षित करने के लिए सघन एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता है।'

"Intensive and continuous efforts are necessary to raise the economic, social, and professional status of teachers and to feed back talented young persons into the profession."—*Education Commission Report*, p. 617.

"आयोग" ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने के लिए जो विचार व्यक्त किए हैं, हम उनका क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं; यथा :—

1. वेतन : Remuneration—"आयोग" ने शिक्षकों के वेतन के विषय में अधोलिखित विचार प्रकट किए हैं :—



1. भारत-सरकार द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतन-क्रम (Minimum Scales of Pay) निश्चित किए जाने चाहिए।
2. सरकारी और गैर-सरकारी—दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन-क्रमों में समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए।
3. विश्वविद्यालयों एवं उनके सम्बद्ध कनिष्ठों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।

2. शिक्षकों के वेतन-क्रम : Scales of Pay of Teachers—“आयोग” ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों और विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं वाले शिक्षकों के लिए निम्नांकित वेतन-क्रमों की सिफारिश की है :—

शिक्षक	वेतन व वेतन-क्रम
1. माध्यमिक कोर्स पास प्राथमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षक	न्यूनतम वेतन 100 रु०
2. उक्त शिक्षकों का 5 वर्षों की सेवा के बाद	न्यूनतम वेतन 125 रु०
3. माध्यमिक कोर्स व 2 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक	न्यूनतम वेतन 125 रु०
4. उक्त शिक्षकों का 5 वर्षों की सेवा के बाद	न्यूनतम वेतन 150 रु०
5. सेकण्डरी कोर्स व 2 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक	न्यूनतम वेतन 150 रु०
6. उक्त शिक्षकों का 20 वर्षों बाद	अधिकतम वेतन 250 रु०
7. श्रेणी (6) में से 15% चुने जाने वाले शिक्षक	250-300 रु०
8. 1 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त प्रेजुएंट	न्यूनतम वेतन 220 रु०
9. उक्त शिक्षकों का 20 वर्षों बाद	400 रु०
10. श्रेणी (9) में से 15% चुने जाने वाले शिक्षक	400-500 रु०
11. अप्रशिक्षित प्रेजुएंट	न्यूनतम वेतन 220 रु०
12. अप्रशिक्षित स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त	300-600 रु०
13. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद श्रेणी 11 व 12 के शिक्षक	जितना वेतन वे पा रहे हैं, उसमें एक वर्षों की वेतन-वृद्धि।

14. माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य	इनका वेतन इनकी योग्यताओं एवं विद्यालय के आकार पर निर्भर होगा। इनको सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के लिए निर्धारित कोई भी वेतन-क्रम दिया जा सकता है।
15. सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षक	(i) लेक्चरर, जूनियर स्केल 300-25-600 रु० (ii) लेक्चरर, सीनियर स्केल 400-30-640-40-800 रु० (iii) सीनियर लेक्चरर या रीडर 700-40-1100 रु० (iv) प्रिंसिपल I 700-40-1100 रु० II 800-50-1500 रु० III 1000-50-1500 रु०
16. विश्वविद्यालय के शिक्षक	(i) लेक्चरर 500-40-800-50-950 रु० (ii) रीडर 700-50-1250 रु० (iii) प्रोफेसर 1100-50-1300-60-1600 रु०

### 3. वेतन-क्रम-सम्बन्धी सुझाव : Suggestions Regarding Pay-Scales—

“आयोग” ने शिक्षकों के वेतन-क्रम के विषय में अधोलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मेंहगाई-भत्ता दिया जाना चाहिए।
2. शिक्षकों के वेतन-क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् दोहराए जाने चाहिए।
3. शिक्षकों के वेतन-क्रमों के विषय में जो सुझाव दिये गये हैं, उन्हें तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
4. वेतन-क्रमों को क्रियान्वित करने के साथ-साथ शिक्षकों की योग्यताओं एवं नियुक्ति की विधियों में सुधार किया जाना चाहिए।

### 4. कार्य व सेवा की दशाएँ : Conditions of Work & Service—

“आयोग” ने शिक्षकों के कार्य एवं सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए अधोलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षकों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
2. शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक उन्नति करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
3. शिक्षकों के अध्यापन-कार्य के घण्टों को निश्चित करते समय, उनके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
4. शिक्षकों को 5 वर्ष में कम-से-कम एक बार, देश के किसी स्थान में भ्रमण करने के लिए, उनके वेतन के अनुसार रियायती दर पर रेल के टिकट दिए जाने चाहिए।

5. सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा-दशाओं में समानता स्थापित की जानी चाहिए ।
6. ग्रामों में कार्य करने वाले शिक्षकों को निवास-स्थान प्रदान किये जाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए ।
7. शिक्षकों को बड़े नगरों में भ्रमण के करारों के लिए भत्ता देने की प्रथा आरम्भ की जानी चाहिए ।
8. शिक्षकों के लिए सरकारी गृह-निर्माण-योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।
9. शिक्षकों को सभी नागरिक अधिकारों का उपभोग करने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ।
10. शिक्षकों में प्रचलित व्यक्तिगत द्यूगनों की प्रथा को नियंत्रित किया जाना चाहिए ।
11. शिक्षकों पर किसी प्रकार के निर्वाचनों में भाग लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए ।
12. शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।
13. अध्यापिकाओं के लिए "वय-व्यवहार द्वारा शिक्षा" (Correspondence Courses) को सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए ।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ते दिये जाने चाहिए ।

#### 4 अध्यापक-शिक्षा

##### Teacher Education

“आयोग” ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व को दर्शाते हुए लिखा है :—“शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है ।”

“A sound programme of professional education of teachers is essential for the qualitative improvement of education.”—*Education Commission Report*, p. 67

अध्यापक-शिक्षा के उपर्युक्त महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, ‘आयोग’ ने हुते अध्यापक-शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया है और उसके बाद इस शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में अपने विचारों को लेखबद्ध किया है, यथा :—

1. अध्यापक-शिक्षा के दोष Defects of Teacher Education—  
‘आयोग’ के मतानुसार, अध्यापक-शिक्षा के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं :—
1. प्रशिक्षण-मंस्थाओं का कार्य—निम्न या साधारण कोटि का है ।
2. प्रशिक्षण-मंस्थाओं में योग्य अध्यापकों का अभाव है ।

3. प्रशिक्षण-संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता का अभाव है।
4. प्रशिक्षण-संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण अधिकांश रूप में परम्परागत है।
5. प्रशिक्षण-संस्थाओं में सिखाई जाने वाली शिक्षण-विधियाँ घिसी-पिटी हैं और शिक्षा के वर्तमान उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं देती हैं।
6. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का इन विद्यालयों को दैनिक समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं है।
7. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का इन विद्यालयों को दैनिक समस्याओं और विश्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यापक-शिक्षा के उपरिवर्णित दोषों का निराकरण करने के लिए, “आयोग” ने जो सुझाव दिये हैं, उनमें से निम्नांकित महत्त्वपूर्ण हैं :—

2. अध्यापक-शिक्षा की पृथक्ता का अन्त : Removal of Isolation of Teacher Education—“आयोग” का कथन है :—“अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, उसे एक ओर विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से और दूसरी ओर विद्यालय-जीवन एवं शिक्षा-सम्बन्धी नवीनतम विचारों के सम्पर्क में लाया जाना परम आवश्यक है।” इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, “आयोग” ने अधोलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं :—

1. “शिक्षा” विषय को विश्वविद्यालयों के बी० ए० एवं एम० ए० के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
2. कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक-शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये “शिक्षा-विभागों” (Schools of Education) की गृष्टि की जानी चाहिए।
3. सब प्रशिक्षण-संस्थाओं में “प्रसार-सेवा-विभाग” (Extension Service Department) का निर्माण किया जाना चाहिये।
4. प्रशिक्षण-काल में छात्राध्यापकों के शिक्षण-अभ्यास के लिये केवल मान्यता-प्राप्त स्कूलों का ही चयन किया जाना चाहिये।
5. प्रशिक्षण-संस्थाओं एवं उनसे सम्बद्ध शिक्षण-अभ्यास (Teaching Practice) के स्कूलों के अध्यापकों को समय-समय पर एक-दूसरे के स्थान पर कार्य करना चाहिये।
6. विभिन्न प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं की पृथक्ता का अन्त करने के लिए, सबको “ट्रेनिंग कॉलेजों” की संज्ञा दी जानी चाहिये और उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

7. सब राज्यों में "कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलेजों" (Comprehensive Colleges) की स्थापना की जानी चाहिये और उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
8. प्रत्येक राज्य में 'अध्यापक-शिक्षा की राज्य-परिषद्' (State Board of Teacher Education) का निर्माण किया जाना चाहिये, जिन पर सब दोनों एव सब स्तरों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व होना चाहिये।

3. **व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति : Improvement in Professional Education**—"आयोग" ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने के लिये निम्नांकित सिफारिशें की हैं :—

1. शिक्षण के अध्यास में गुणात्मक उन्नति करने के प्रयास किये जाने चाहिये।
2. छात्राध्यापकों के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिये।
3. अध्यापक-शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को उन आधारभूत उद्देश्यों की ध्यान में रखकर दोहराया जाना चाहिये, जिनके लिये छात्राध्यापकों को तैयार किया जा रहा है।
4. सब प्रशिक्षण-संस्थाओं के पाठ्यक्रमों की शिक्षा एवं विषय-मामूरी में इस प्रकार रूपान्तर किया जाना चाहिये जिसमें छात्राध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के उद्देश्यों, प्रयोजनों एवं जटिलताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो जाय।
5. विश्वविद्यालयों में सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत (Integrated) पाठ्यक्रम प्रचलित किये जाने चाहिये।

4. **प्रशिक्षण की अवधि Period of Training**—"आयोग" ने विभिन्न प्रशिक्षण-स्तरों की अवधि के विषय में अधोलिखित विचार व्यक्त किये हैं :—

1. प्राथमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिये, जिन्होंने सैकण्डरी स्कूल कोर्स पास किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिये।
2. माध्यमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए, जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष की होनी चाहिये, पर कुछ समय के पश्चात् 2 वर्ष की कर दी जानी चाहिये।
3. शिक्षा में स्नातकोत्तर (M. Ed.) पाठ्यक्रम की अवधि  $1\frac{1}{2}$  वर्ष की होनी चाहिये।

5. **प्रशिक्षण-संस्थाओं की उन्नति Improvement in Training Institutions**—"आयोग" ने प्रशिक्षण-संस्थाओं की गुणात्मक सिफारिशों की हैं :—

1. ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि (Degree in Education) के अतिरिक्त दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ (Post-Graduate Degrees) होनी चाहिए।
2. ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों में "डॉक्टर" (Doctorate) की उपाधियों वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में होनी चाहिये।
3. गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र ऐसे विषयों की शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, चाहे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।
4. प्रत्येक प्रशिक्षण-संस्था से एक प्रयोगात्मक (Experimental) विद्यालय संलग्न होना चाहिए।
5. प्रशिक्षण-संस्थाओं में छात्राध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको ऋण एवं छात्रवृत्तियों के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. वर्तमान प्रशिक्षण-संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि में सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दशा अत्यधिक असंतोषजनक है।
7. विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय स्थानों पर "ग्रीष्मकालीन संस्थाओं" (Summer Institutes) की योजना आरम्भ की जानी चाहिए।
8. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो "शिक्षा" में एम० ए० (M. A. in Education) की उपाधि होनी चाहिये, या बी० एड० (B. Ed.) की उपाधि के साथ-साथ कोई स्नातकोत्तर (M. A., M. Sc.) उपाधि होनी चाहिये।

6. प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार : Expansion of Training Facilities—“आयोग” ने प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से अग्रिम विचार व्यक्त किये हैं :—

1. प्रशिक्षण-संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिये।
2. पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिये।
3. शिक्षकों की माँग को पूरित करने और शिक्षण-कार्य में संलग्न अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रत्येक राज्य को प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार करने के लिये योजना तैयार करनी चाहिये।
4. विद्यालय-शिक्षकों को अध्यापन-कार्य करते हुये शिक्षा तथा प्रशिक्षण

प्राप्त करने की सुविधायें प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण-संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिये।

## 5. छात्र-संस्था व जनबल

### *Enrolment & Manpower*

“आयोग” ने “छात्र-संस्था एवं जनबल” के अन्तर्गत 2 मुख्य विषयों पर विचार किया है—छात्र-संस्था की राष्ट्रीय नीति और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की छात्र-संस्था-सम्बन्धी नीतियाँ। हम निम्नांकित पक्षों में इनका वर्णन कर रहे हैं; यथा :—

1. छात्र-संस्था की राष्ट्रीय नीति : National Enrolment Policy—  
“आयोग” का कथन है :—“आगामी बीस वर्षों में छात्र-संस्था से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति के सामान्य रूप से निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए :—

1. प्रत्येक बालक एवं बालिका को कम-से-कम 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना।
2. निम्न माध्यमिक शिक्षा का अधिक-से-अधिक सम्भव विस्तार करना।
3. इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों के लिए उच्चतर माध्यमिक एवं विश्व-विद्यालय-शिक्षा का प्रबंध करना।
4. उपर्युक्त दोनों प्रकार की शिक्षा को प्रशिक्षित व्यक्तियों की माँग के अनुरूप बनाना।
5. उपर्युक्त दोनों प्रकार की शिक्षा के आवश्यक स्तरों को यथावत् बनाए रखना।
6. उपर्युक्त दोनों प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धन छात्रों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देना।
7. व्यावसायिक, प्राविधिक एवं जीविका-सम्बन्धी शिक्षा (Professional, Technical & Vocational Education) के विस्तार पर बल देना।
8. कृषि एवं उद्योगों की उन्नति के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना।
9. प्रतिभाशाली छात्रों का चयन करके, उनको अपनी सब शक्तियों का पूर्ण विकास करने में सहायता देना।
10. जनसाधारण की निरक्षरता का उन्मूलन करना।
11. बयस्क-शिक्षा एवं अनवरत शिक्षा (Continuation Education) के उपर्युक्त कार्यक्रमों को त्रिविध बनाना।
12. शैक्षिक अवसरों में समानता स्थापित करने के लिए निरक्षर प्रयत्न करना।

2. माध्यमिक व उच्च शिक्षा में छात्र-संख्या-सम्बन्धी नीतियाँ : *Enrolment Policies in Secondary & Higher Education*—इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि “आयोग” के निम्नांकित विचारों से विदित हो जायगा, छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकना है :—

1. उत्तर-प्राथमिक शिक्षा (Post-Primary Education) में छात्र-संख्या-सम्बन्धी नीति को अग्रांकित 4 तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए :—(i) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए जनता की माँग; (ii) छात्रों की सब जन्मजात योग्यताओं का पूर्ण विकास; (iii) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उत्तम शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की समाज की क्षमता; और (iv) जनबल की आवश्यकताएँ।
2. प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए जनता की माँग में अत्यधिक वृद्धि हुई है और भविष्य में होती रहेगी। शिक्षा की इस बढ़ती हुई माँग को पूर्ण करने के लिए शिक्षकों, धन या शिक्षण-सामग्री को जुटाना देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असम्भव है। अतः हायर सेकण्डरी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्व-विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्रों के सम्बन्ध में ‘चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली’ (Policy of Selective Admissions) की नीति का अनुसरण किया जाना आवश्यक है।
3. समस्त योग्य छात्रों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में धनी समाज भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। कम-से-कम निकट भविष्य में भारत द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव है। हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। पर जब तक हम ऐसा न कर सकें, तब तक हमारी छात्र-संख्या-सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए :—माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने वाले प्रतिभागालो छात्रों में से 5 से 15 प्रतिशत को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा दी जानी चाहिए और इन छात्रों की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए, इनको उदारतापूर्वक छात्र-वृत्तियाँ दी जानी चाहिए।
4. पिछले समय में धन, योग्य शिक्षकों, शिक्षण-सामग्री आदि के अभाव के प्रति ध्यान न देकर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विस्तार तीव्र गति से किया गया है। परिणामस्वरूप, शिक्षा का स्तर गिर गया है। अतः देश के हित को ध्यान में रखकर भविष्य में इस नीति का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए।
5. भविष्य में शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार—शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने के अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।



## 6. शैक्षिक अवसरों की समानता Equalization of Educational Opportunities

"आयोग" के शब्दों में :—"शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना है, ताकि पिछड़े वर्ग कम अधिकारों वाले वर्गों एवं व्यक्ति अपनी दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा साधन के रूप में प्रयोग कर सकें।"

"One of the important social objectives of education is to equalize opportunity, enabling the backward or underprivileged classes and individuals to use education as a lever for the improvement of their condition."—*Education Commission Report*, p. 108.

"आयोग" ने शिक्षा के क्षेत्र में दो मुख्य प्रकार की व्यापक असमानताएँ बताई हैं :—(1) शिक्षा के सत्र पक्षों एवं स्तरों पर दानकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता, और (2) उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूत जातियों, पहाड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता। इन दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए, "आयोग" ने 4 सुझाव दिए हैं :—(1) नि.शुल्क शिक्षा की व्यवस्था, (2) शिक्षा के खर्चों में कमी, (3) छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, और (4) छात्रवृत्तियों की योजना। हम इन चारों सुझावों में सम्बन्धित "आयोग" के विचारों को लिपिबद्ध कर रहे हैं, यथा —

1. नि शुल्क शिक्षा . Free Education—"आयोग" ने नि शुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में अप्रतिनिधित विचार व्यक्त किए हैं —

- 1 चौबीसवर्षीय योजना के अन्त में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को नि शुल्क कर दिया जाना चाहिए।
- 2 पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या उससे पूर्व निम्न माध्यमिक शिक्षा को नि शुल्क कर दिया जाना चाहिए।
- 3 पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 10 वर्ष की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय-शिक्षा को योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए नि शुल्क कर दिया जाना चाहिए।

2. शिक्षा के खर्चों में कमी : Reduction in Costs of Education—"आयोग" ने शिक्षा के खर्चों में कमी करने के लिए निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं :—

1. प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें एवं लेखन-सामग्री मुफ्त दी जानी चाहिए।
2. माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में "पुस्तक-बैंकों" (Book-Banks) की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ से छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें दी जानी चाहिए।

3. माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य-पुस्तकें पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए, ताकि छात्र उनको प्रयोग कर सकें।

4. योग्य छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

3. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था : Provision for Scholarships—“आयोग” ने छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अग्रांकित विचार लिपिवद्ध किए हैं :—

1. निम्न प्राथमिक स्तर के उपरान्त शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित किया जाना चाहिए।
2. जब छात्र—शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुँचें, तब इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई निर्धन पर योग्य विद्यार्थी—छात्रवृत्ति न मिल सकने के कारण अपनी भावी शिक्षा से वंचित न रह जाय।
3. उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 1975-76 तक 2.5 प्रतिशत प्रतिभाशाली छात्रों को और 1985-86 तक 5 प्रतिशत योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।
4. माध्यमिक स्तर पर 15 प्रतिशत प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।
5. पूर्व-स्नातक-स्तर पर 1975-76 तक 15 प्रतिशत योग्य छात्रों को और 1985-86 तक 25 प्रतिशत योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।
6. स्नातकोत्तर-स्तर पर 1975-76 तक 25 प्रतिशत योग्य छात्रों को और 1985-86 तक 50 प्रतिशत योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।
7. विश्वविद्यालय-स्तर पर दो प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए :—(i) छात्रावासों में रहकर कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए। इन छात्रों को छात्रवृत्तियों के रूप में इतना धन दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाय। (ii) अपने घरों पर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए। इन छात्रों को केवल इतनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे अधिकांश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाय।

4. छात्रवृत्तियों की योजनाएँ : Schemes of Scholarships—“आयोग” ने छात्रवृत्तियों की अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में अपने विचार अंकित किए हैं; यथा :—

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों (National Scholarships) की योजना का विस्तार एवं विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए।
2. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना की पूर्ति करने के लिए "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" द्वारा "विश्वविद्यालय-छात्रवृत्तियों" (University Scholarships) की योजना आरम्भ की जानी चाहिए।
3. व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों में से विद्यालय-स्तर पर 30 प्रतिशत को एवं कॉलेज-स्तर पर 50 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
4. ऋण-छात्रवृत्तियों (Loan Scholarships) की योजना को कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों के लिए प्रत्यागित किया जाना चाहिए।
5. उक्त योजना को विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले गव छात्रों के लिए अनिवार्य रूप में लागू किया जाना चाहिए।
6. अमाधारण प्रतिभा के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
7. छात्रवृत्तियों पर किए जाने वाले व्यय को कम करने के लिए विद्यार्थियों को आवागमन एवं अध्ययन-काल में फीस-वॉश की सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

## 7 विद्यालय-शिक्षा का विस्तार

### Expansion of School Education

"आयोग" की धारणा है कि यद्यपि पिछले समय में विद्यालय-शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हुआ है, तथापि देश की आवश्यकताओं को पूर्ण न कर सकने के कारण, उमको मतोपजनक नहीं कहा जा सकता है। अपनी इस धारणा के फलस्वरूप "आयोग" ने विद्यालय-शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं और सुझाव भी दिए हैं। हम इनका वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत उपस्थित कर रहे हैं, यथा —

1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विस्तार : Expansion of Pre-Primary Education—“आयोग” ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए प्रस्तावित सुझाव दिए हैं :—

1. प्रत्येक राज्य के “राज्य-शिक्षा-संस्थान” (State Institute of Education) में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य-स्तर पर एक केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।
2. प्रत्येक जिले में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए एक केन्द्र की गृष्टि की जानी चाहिए। इस केन्द्र के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

होने चाहिए :—(i) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, (ii) इन विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन का निरीक्षण करना और इन शिक्षकों के लिए “अभिनव-पाठ्यक्रमों” (Refresher Courses) का संचालन करना ।

3. व्यक्तिगत प्रबंधकों को उदार आर्थिक सहायता देकर, पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए ।
4. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में परीक्षण-कार्य (Experimentation) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि इस शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके ।
5. पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों में ज्ञानेन्द्रिय-शिक्षा (Sensorial Education) के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए ।
6. शिशुओं के “मेल-केंद्रों” (Play Centres) को प्राथमिक विद्यालयों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

## 2. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार : Expansion of Primary Education—

“आयोग” ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये अप्राप्त मुद्दाय दिये हैं :—

1. 1975-76 तक देश के सब बच्चों के लिये 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये ।
2. 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिये 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिये और भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए ।
3. अपव्यय एवं अवरोधन (Wastage & Stagnation) को अधिक-से-अधिक कम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए ।
4. जो बालक कक्षा 7 पान करने के समय 14 वर्ष के न हों और अपनी सामान्य शिक्षा के क्रम की जारी न रखना चाहते हों, उनको इस आयु तक उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ।
5. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिये कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 मील से अधिक दूर न हों ।
6. जो बालक निम्न प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन न करना चाहते हों, उनके लिये अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

**3. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार : Expansion of Secondary Education—**"आयोग" का मत है कि घनाभाव के कारण कुछ वर्षों तक माध्यमिक शिक्षा को माबैभौमिक बनाया जाना सम्भव नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार निम्नांकित उपायों एवं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए :—

1. माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को निश्चित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।
2. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण (Vocationalization) इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20 प्रतिशत छात्रों को एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके।
3. माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता स्थापित की जानी चाहिए।
4. बालिकाओं, जनजातियों एवं अछूत जातियों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए और उनको 10 वर्ष की अवधि में पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दिया जाना चाहिए।
6. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए केवल योग्य छात्रों का ही चयन किया जाना चाहिए।
7. निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों को पूर्णकालीन एवं अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
8. बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार करने के लिए लगभग 20 वर्षों में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

**4. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण : Vocationalization of Secondary Education—**"आयोग" ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर विशेष बल दिया है और इसका कारण बताते हुए लिखा है —"माध्यमिक स्तर के स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।"

"The link between education and productivity can be forged through vocationalization of education at the secondary school level."—*Education Commission Report*, p. 6.

"आयोग" ने अपने विचार को ध्यान में रखते हुए, पहले व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सामान्य सुझाव दिए हैं, और उसके बाद निम्न एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; यथा :—

(i) सामान्य सुझाव : General Suggestions—“आयोग” ने व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित सामान्य सुझाव दिए हैं :—

1. माध्यमिक शिक्षा का विशेष रूप से अधिक-से-अधिक व्यावसायीकरण किया जाना चाहिए ।
2. उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग की पूर्ति करने के लिए माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए ।
3. निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पूर्णकालीन एवं अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
4. माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक बनाने के लिए केन्द्रीय-सरकार द्वारा राज्य-सरकारों को विशेष अनुदान दिए जाने चाहिए ।
5. बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ।

(ii) निम्न माध्यमिक स्तर : Lower Secondary Stage—“आयोग” ने निम्न माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में अग्रांकित सिफारिशें की हैं :—

1. निम्न माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन् 1986 तक इस स्तर की सम्पूर्ण छात्र-संख्या की लगभग 20 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए ।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं (Industrial Training Institutes) में प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले छात्र प्रवेश कर सकते हैं । इस समय इन संस्थाओं में प्रवेश करने की आयु 15 वर्ष है । इस प्रवेश-आयु को कम करके 14 वर्ष कर दिया जाना चाहिए, ताकि प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को इन संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए 1 वर्ष तक प्रतीक्षा न करनी पड़े ।
3. टेक्निकल स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले “अन्तिम पाठ्यक्रमों” (Terminal Courses) में विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके ।
4. कुछ छात्र 7वीं या 8वीं कक्षा के बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए या कोई छोटा-मोटा निजी कारोबार करने के लिए विद्यालयों को छोड़ देते हैं । ऐसे छात्रों के लिए विविध प्रकार की अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
5. ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक बालक अपने परिवारों के कृषि-सम्बन्धी कार्यों में सहयोग देने के लिए प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं । ऐसे बालकों के लिए कृषि-सम्बन्धी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ।

6. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व या कुछ समय पश्चात् अनेक बालिकाओं के विवाह हो जाते हैं। ऐसी बालिकाओं के लिए दृढ़-विमान एवं सामान्य शिक्षा का प्रवर्धन किया जाना चाहिए।

(iii) उच्चतर माध्यमिक स्तर : Higher Secondary Stage—"आयोग" ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के विषय में नीचे लिखी सिफारिशें की हैं :—

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन् 1986 तक हम स्तर की सम्पूर्ण छात्र-संख्या की लगभग 50 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।
2. पॉलिटेक्नीकों (Polytechnics) में विभिन्न विषयों के पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए।
3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित पूर्णकालीन और अल्पकालीन शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए।
4. विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए और उनके लिए "पत्राचार पाठ्यक्रमों" (Correspondence Courses) का कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए।
5. कृषि एवं इंजीनियरिंग के कार्यों में सलग्न उन व्यक्तियों के लिए जो अपने ज्ञान का नवीनीकरण करना चाहते हैं, कृषि और इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्नीकों में "संक्षिप्त-सघन पाठ्यक्रमों" (Short Condensed Courses) की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण-अस्थाएँ ऐसी हैं, जिनमें 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही बालकों का प्रवेश होता है। इन अस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अति तीव्र गति से विस्तार किया जाना चाहिए।
7. स्वास्थ्य, वाणिज्य, प्रशासन, सप्ताह-उद्योग आदि से सम्बन्धित 6 माह से 3 वर्ष तक के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

### 8 विद्यालय-पाठ्यक्रम School Curriculum

"आयोग" का मत है कि विद्यालय-पाठ्यक्रम में अनेक दोषों का उपाय ले लिया गया है। इन दोषों को दूर करने और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए, "आयोग" ने विभिन्न कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं, उनका वर्णन दृष्टव्य है :—

#### 1. निम्न प्राथमिक स्तर : Lower Primary Stage : Classes I to IV

1. एक भाषा—मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा (Mother Tongue or

Regional Language), 2. गणित (Mathematics), 3. वातावरण का अध्ययन (Study of Environment)—कक्षा 3 और 4 में विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, 4. सृजन-आत्मक क्रियाएँ (Creative Activities), 5. कार्य-अनुभव एवं समाज-सेवा (Work-Experience & Social Service), 6. स्वास्थ्य-शिक्षा (Health Education)।

## 2. उच्चतर प्राथमिक स्तर : Higher Primary Stage : Classes V to VII

1. दो भाषाएँ—(अ) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, (ब) हिन्दी या अंग्रेजी, 2. गणित, 3. विज्ञान, 4. सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल एवं नागरिक-शास्त्र), 5. कला (Art), 6. कार्य-अनुभव एवं समाज-सेवा, 7. शारीरिक शिक्षा (Physical Education), 8. नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा (Education in Moral & Spiritual Values)।

## 3. निम्न माध्यमिक स्तर : Lower Secondary Stage : Classes : VIII to X

1. तीन भाषाएँ—अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से अश्रांकित भाषाएँ होनी चाहिए : (अ) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, (ब) उच्च या निम्न स्तर की हिन्दी, (स) उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से अश्रांकित भाषाएँ होनी चाहिए : (अ) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, (ब) अंग्रेजी (या हिन्दी, यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ली गई है), (स) हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, 2. गणित, 3. विज्ञान, 4. इतिहास, भूगोल तथा नागरिक-शास्त्र, 5. कला, 6. कार्य-अनुभव एवं समाज-सेवा, 7. शारीरिक शिक्षा, 8. नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा।

## 4. उच्चतर माध्यमिक स्तर : Higher Secondary Stage : Classes XI & XII

1. कोई दो भाषाएँ—जिनमें कोई आधुनिक भारतीय भाषा, कोई आधुनिक विदेशी भाषा एवं कोई शास्त्रीय भाषा सम्मिलित हो, 2. अप्रलिखित में से कोई तीन विषय : (i) एक अतिरिक्त भाषा, (ii) इतिहास, (iii) भूगोल, (iv) अर्थशास्त्र, (v) तर्कशास्त्र (Logic), (vi) मनोविज्ञान, (vii) समाजशास्त्र, (viii) कला, (ix) भौतिकशास्त्र, (x) रसायनशास्त्र, (xi) गणित, (xii) जीव-विज्ञान, (xiii) भूगर्भ-शास्त्र (Geology), (xiv) गृह-विज्ञान (Home Science), 3. कार्य-अनुभव एवं समाज-सेवा, 4. शारीरिक शिक्षा, 5. कला या शिल्प (Art or Craft), 6. नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा।

5. त्रिभाषा-सूत्र में संशोधन : Amendment in the Three-Language Formula—त्रिभाषा-सूत्र के सम्बन्ध में “आयोग” ने लिखा है :—यह फ़ार्मूला सन् 1956 में “केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-बोर्ड” (Central Advisory Board of Education) के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और सन् 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। किन्तु, व्यावहारिक रूप में इस फ़ार्मूले को



सफलता प्राप्त नहीं हुई है और इसका यह कहकर घोर विरोध किया जा रहा है कि हमने पाठ्यक्रम को भाषाओं की दृष्टि से बहुत बोझिल बना दिया है। अतः इस मूत्र में सुधार किया जाना अनिवार्य है। यह सुधार अधोलिखित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए :—

1. सघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी—मातृभाषा के बाद महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे।
2. छात्रों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी है।
3. तीन भाषाओं की निष्ठा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उद्युक्त स्तर—निम्नतर माध्यमिक है।
4. हिन्दी या अंग्रेजी की निष्ठा उस समय आरम्भ की जाय, जब इनके लिए प्रेरणा या आवश्यकता का अनुभव किया जाय।
5. किसी भी स्तर पर चार भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य न बनाया जाय।

“आयोग” ने उपरिज्जित सिद्धान्तों के आधार पर त्रिभाषा-मूत्र का सुसंशोधित रूप इस प्रकार प्रस्तावित किया है :—

- (i) मातृभाषा या क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषा।
- (ii) सघ की राजभाषा या सह-राजभाषा (जिन समय तक यह है)।
- (iii) एक आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा, जो छात्र ने पाठ्यक्रम में चुनी न हो और जो निष्ठा का माध्यम न हो।

6. भाषाओं का अध्ययन Study of Languages—“आयोग” ने निष्ठा के विभिन्न स्तरों पर भाषाओं के अध्ययन के विषय में अप्राकृतिक विचार लिपिबद्ध किए हैं :—

1. निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सप्ताहगत एक भाषा का अध्ययन करना चाहिए। यह भाषा—मातृभाषा या क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए।
2. उच्चतर प्राथमिक स्तर पर छात्रों को दो भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये भाषाएँ—मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा और उनके राज्य की राजभाषा या सह-राजभाषा होनी चाहिए।
3. निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये भाषाएँ—मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, राजभाषा या सह-राजभाषा और एक आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए।
4. प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए विद्यालयों में अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं की निष्ठा दी जानी चाहिए और छात्रों को उन्हें अंग्रेजी या हिन्दी के बजाय अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. अहिन्दी क्षेत्रों के कुछ चुने हुए विद्यालयों में आधुनिक भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए और छात्रों को उन्हें अंग्रेजी या हिन्दी के बजाय अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
6. उच्च शिक्षा की संस्थाओं में छात्रों के लिए किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
7. हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए सम्पूर्ण देश के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, पर किसी को हिन्दी का अध्ययन करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।
8. अंग्रेजी की शिक्षा 5वीं कक्षा से पहले आरम्भ नहीं होनी चाहिए।
9. संस्कृत या अरबी के समान शास्त्रीय भाषाओं की शिक्षा 8वीं कक्षा से आरम्भ होनी चाहिए, पर इन भाषाओं को वैकल्पिक विषयों में स्थान दिया जाना चाहिए।
10. शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये।

### 9. शिक्षण-विधियाँ, निर्देशन व मूल्याङ्कन

#### Teaching Methods, Guidance & Evaluation

“आयोग” ने विद्यालयों में शिक्षण-विधियों, पाठ्य-पुस्तकों, निर्देशन एवं मूल्यांकन के विषय में अत्यन्त सारगर्भित विचार वाक्यबद्ध किए हैं। हम आपके समक्ष इनका वर्णन उपस्थित कर रहे हैं; यथा :—

#### 1. शिक्षण-विधियों में सुधार : Improvement in Teaching Methods—

“आयोग” के मतानुसार, हमारे विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण-विधियाँ अब भी प्राचीन एवं परम्परागत हैं। अतः वे छात्रों की दृष्टि से तनिक भी लाभप्रद नहीं हैं। उनमें सुधार करने के लिए, “आयोग” ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं; यथा :—

1. शिक्षण-विधियों में लचीलेपन एवं गतिशीलता के गुणों का समावेश किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिये स्वयं शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप में कदम उठाने चाहिए।
2. शिक्षा-संस्थाओं के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण-विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए।
3. शिक्षण-विधियों में गतिशीलता का समावेश करने के लिए अध्यापकों में परीक्षण, पहलकदमी एवं नृजनात्मकता के गुणों का विकास किया जाना चाहिए।
4. नवीन शिक्षण-विधियों का प्रसार करने के लिए प्रदर्शनों, वर्कशॉप्स,

परीक्षणों, मंजिनारों एवं अभिनवन-पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए।

5. शिक्षण-विधियों में अनुसंधान-कार्य की उपयुक्त मुविपाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

2. पाठ्यपुस्तकों में सुधार : Improvement in Text-Books—“आयोग” का कथन है :—“उत्तम पाठ्य-पुस्तकें—शिक्षण-स्तर के उन्नयन में अतिशय योग देती हैं।”

“आयोग” ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि हमारे देश के विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य-पुस्तकें अत्यन्त निम्न कोटि की हैं। अतः “आयोग” ने उनमें सुधार करने के लिए अप्राप्त विचारों की अभिव्यक्ति की है :—

1. पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. पाठ्य-पुस्तकों को “राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद्” (NCERT) के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।
3. पाठ्य-पुस्तकों को लिखने के लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पर्याप्त वारिधमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करवाने एवं उनका मूल्यांकन करने का उत्तर-दायित्व राज्य के शिक्षा-विभाग पर होना चाहिए।
5. पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण-कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा एक “स्वायत्त-संगठन” (Autonomous Organization) की स्थापना की जानी चाहिए।
6. प्रत्येक राज्य में पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का संगठन किया जाना चाहिए।
7. शिक्षा-विभाग को स्वयं पाठ्यपुस्तकों की बिधी न करके, इस कार्य को विद्यालयों के गृहकारी भद्रों को सौंप देना चाहिए।
8. शिक्षा-विभाग की आकाशवाणी से सम्पर्क स्थापित करके रेडियो द्वारा विभिन्न पाठों के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

3. प्राथमिक स्तर पर निर्देशन : Guidance at Primary Stage—“आयोग” का मत है कि निर्देशन का कार्य प्राथमिक स्तर से ही आरम्भ हो जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में “आयोग” के नीचे लिखे गुणाव प्रस्तुत किए हैं :—

1. प्राथमिक विद्यालयों की निम्नतम कक्षा में निर्देशन दिए जाने का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।
2. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रशिक्षण-काल सब जाती का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए।

3. अध्यापकों को निर्देशन-कार्य में सहायता देने के लिए व्यावसायिक साहित्य का निर्माण किया जाना चाहिए।
4. आगे की शिक्षा के विषयों का चयन करने के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सहायता दी जानी चाहिए।

4. माध्यमिक स्तर पर निर्देशन : Guidance at the Secondary Stage—“आयोग” ने माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए अग्रोक्त सुझाव दिए हैं :—

1. माध्यमिक विद्यालयों के सब शिक्षकों को सेवा-काल या प्रशिक्षण-काल में निर्देशन-सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
2. सब माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम निर्देशन का कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये।
3. 10 माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता (Counsellor) की नियुक्ति की जानी चाहिए।
4. प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन का सघन कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए।

5. मूल्यांकन : Evaluation—“आयोग” के अनुसार, मूल्यांकन—शिक्षा का अभिन्न अंग है और इसका शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः मूल्यांकन की विधियाँ वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं व्यावहारिक होनी चाहिए। किन्तु, भारत में प्रचलित परीक्षा-प्रणाली में इन गुणों का सर्वथा अभाव है। इस प्रणाली में सुधार करने और इसे उपयोगी बनाने के लिए, “आयोग” ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

1. मूल्यांकन की नवीन धारणा के अनुसार लिखित परीक्षाओं में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, ताकि वे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का विश्वसनीय ढंग से माप कर सकें।
2. छात्रों की जिन उपलब्धियों का माप लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाना असम्भव है, उनका माप करने के लिए अन्य विधियों का विकास किया जाना चाहिए।
3. निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य—छात्रों की मूलभूत कुशलताओं में सुधार करना और उनमें अच्छी आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास करना होना चाहिए।
4. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए लिखित परीक्षाओं के अलावा मौखिक एवं निदानात्मक (Diagnostic) परीक्षाओं का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के संचित अभिलेख-पत्रों (Cumulative Record Cards) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. प्राथमिक स्तर की शिक्षा समाप्त करने पर बिले के शिक्षा-अधिकारी द्वारा छात्रों की बाह्य परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट दिए जाने चाहिए।
6. बाह्य परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न देने की प्रथा प्रचलित की जानी चाहिए।
7. आन्तरिक जाँचों (Internal Assessments) को इतना व्यापक बना दिया जाना चाहिए कि उनकी गह्रायता में छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा सके। बाह्य परीक्षाओं के माप-माप इन जाँचों की भी प्रमाणपत्र प्रदान करने का आधार बनाया जाना चाहिए।
8. मूल्यांकन की नवीन विधियों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ प्रयोगात्मक विद्यालयों (Experimental Schools) की स्थापना की जानी चाहिए। इन विद्यालयों को कक्षा 10 के अपने छात्रों की स्वयं परीक्षा लेने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

## 10. उच्च शिक्षा Higher Education

“आयोग” ने उच्च शिक्षा के लगभग सभी जगहों के विषय में महत्वपूर्ण विचार अंकित किए हैं। हम इनका यहाँ अपोलितित नीचे की के अन्तर्गत उपस्थित कर रहे हैं; यथा :—

1. विश्वविद्यालयों के लक्ष्य Objectives of Universities—“आयोग” के मतानुसार, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों के मुख्य लक्ष्य अपोलितित होने चाहिए :—

1. नवीन ज्ञान की खोज एवं उसका विकास करना।
2. सत्य की खोज के लिए साहस एवं निर्भयता में कार्य करना।
3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कम करना।
4. गमानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना।
5. राष्ट्रीय अंतर्गत को विकसित करने के लिए कार्य करना।
6. नवीन खोजों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राचीन ज्ञान का विश्लेषण करना।
7. जीवन के सब क्षेत्रों में उचित प्रकार का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना।
8. प्रतिभाशाली नवयुवकों की खोज करना और उनको अपनी क्षमता एवं प्रतिभाओं का विकास करने में सहायता देना।
9. देश के कला, कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी एवं अन्य धर्मनामों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना।

10. छात्रों एवं शिक्षकों में और उनके द्वारा समाज के व्यक्तियों में उचित मान्यताओं और दृष्टिकोणों का विकास करना ।

2. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना : Establishment of New Universities—"आयोग" का मत है कि नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के समय निम्नांकित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

1. कोई नवीन विश्वविद्यालय—"विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" की सहमति के बिना स्थापित नहीं किया जाना चाहिए ।
2. नवीन विश्वविद्यालय सामान्य रूप से उस स्थान पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए, जहाँ कुछ समय से कोई विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है ।
3. नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना तभी की जानी चाहिये जब इस बात का पूरा भरोसा हो कि उससे शिक्षा के स्तर में उन्नति होगी, उसके लिये योग्य शिक्षक उपलब्ध होंगे और उसमें उच्च स्तर का शिक्षण एवं अनुसंधान-कार्य किया जायगा ।
4. जिन स्थानों पर अनेक स्नातकोत्तर कॉलेज कार्य कर रहे हैं, उनको संगठित करके विश्वविद्यालयों का रूप प्रदान किया जाना चाहिए ।

3. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास : Development of Major Universities—वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के विषय में "आयोग" ने अपने विचार इस प्रकार उपस्थित किए हैं :—"उच्च शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार—कुछ वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास करना है, जिनमें सर्वोत्तम प्रकार का स्नातकोत्तर-कार्य एवं अनुसंधान सम्भव होगा और जिनके स्तर की संसार के किसी भाग में इस प्रकार की सर्वोत्तम संस्थाओं के स्तर से तुलना की जा सकेगी । "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" को जल्दी-से-जल्दी वर्तमान विश्वविद्यालयों में से लगभग 6 विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए चुन लेना चाहिए । इनमें से 1 प्रयोगिकी का और 1 कृषि का होना चाहिए । यह कार्यक्रम 1966-67 में आरम्भ हो जाना चाहिए । वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में असाधारण क्षमता एवं अध्ययन-माय के छात्र एवं अध्यापक होने चाहिए ।"

"आयोग" के अनुसार, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास करने में निम्न-लिखित बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :—

1. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के व्यय का भार "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" को वहन करना चाहिए ।
2. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में "उच्च अध्ययन-केन्द्रों के समूहों (Clusters of Advanced Centres) की स्थापना की जानी चाहिए ।
3. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में पूर्व-स्नातक स्तर के लिए कुछ छात्रवृत्तियाँ

होनी चाहिए, ताकि उनको स्नातकोत्तर-अध्यापकों के लिए प्रतिभानाली छात्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकें।

4. बरिष्ठ विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति—राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आधारों पर की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो चुने जाने वाले अध्यापकों को अग्रिम वेतन-वृद्धि या विशेष वेतन-व्यय दिये जाने चाहिए। इन अध्यापकों को अनुसंधान करने के लिये सभी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

4. कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सुधार : Improvement in Colleges & Universities—“आयोग” ने वर्तमान कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए निम्नांकित सुझाव दिये हैं :—

1. विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों का उनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए।
2. यदि किसी विश्वविद्यालय में सम्बद्ध कोई असाधारण कॉलेज है, तो उसे “स्वायत्त कॉलेज” (Autonomous College) बना दिया जाना चाहिए।
3. बरिष्ठ विश्वविद्यालयों को दूसरे विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कॉलेजों को सुयोग्य अध्यापक प्रदान करने चाहिए।
4. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कॉलेजों को पहली बार नियुक्त किए जाने वाले अपने अध्यापकों को कुछ समय के लिए बरिष्ठ विश्वविद्यालयों में भेजना चाहिए, ताकि वे वहाँ अपने विषयों से सम्बन्धित नवीनतम तथ्यों एवं विचारों का ज्ञान प्राप्त कर लें।
5. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कॉलेजों को समय-समय पर विभिन्न विषयों के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं वैज्ञानिकों को आमन्त्रित करके, सेमिनारों एवं अनुसंधान-कार्यों का आयोजन करना चाहिए।
6. “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” को विश्वविद्यालयों में “उच्च अध्ययन-केंद्रों” की स्थापना करने के लिए उदारतापूर्वक वार्षिक सहायता देनी चाहिए।

5. शिक्षण में सुधार Improvement in Teaching—“आयोग” ने विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कॉलेजों में शिक्षण में सुधार करने के विचार में अधोलिखित सुझाव दिये हैं —

1. कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. छात्रों में प्रवर्तित निष्क्रिय रहने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए और उनमें मातृक विस्तार की प्रेरणाहित किया जाना चाहिए।

3. ध्यान्धान के बाद उसकी सामग्री को याद करने के लिए छात्रों को 45 मिनट का समय दिया जाना चाहिए।
4. औपचारिक कक्षा-कार्य और प्रयोगशाला-कार्य के घण्टों में कमी की जानी चाहिए। छात्रों द्वारा इस प्रकार बचने वाले समय का प्रयोग एक निर्देशक (Instructor) के मार्गदर्शन में स्वाध्याय, लेखन-कार्य, समस्या-समाधान, अनुसन्धान-कार्य आदि के लिये करना चाहिए।
5. नए अध्यापकों की नियुक्तियाँ गर्मी की छुट्टियों में कर दी जानी चाहिए, ताकि नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक अध्यापक सत्र के आरम्भ से ही शिक्षण-कार्य करने लगे।
6. सत्र (Term) के मध्य में किसी अध्यापक को एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में जाने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।
7. किसी भी शिक्षक को एक सत्र में 7 दिन से अधिक का अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए।
8. शिक्षण-विधियों में सुधार करने के लिए, "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" द्वारा एक विशेष समिति की नियुक्ति की जानी चाहिये।

6. मूल्यांकन में सुधार : Improvement in Evaluation—"आयोग" ने मूल्यांकन में सुधार करने के लिए अधोलिखित विचार व्यक्त किए हैं :—

1. "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" को विश्वविद्यालयों की सहायता से "केंद्रीय परीक्षा-सुधार-यूनिट" (Central Examination Reform Unit) का निर्माण करना चाहिए।
2. शिक्षण-विश्वविद्यालयों में बाह्य परीक्षाओं की प्रणाली को समाप्त करके, स्वयं अध्यापकों द्वारा "आन्तरिक तथा क्रमिक मूल्यांकन" (Internal & Continuous Evaluation) की प्रणाली का प्रचलन किया जाना चाहिए।
3. सम्बन्धीकरण विश्वविद्यालयों में बाह्य परीक्षाओं के साथ-साथ आन्तरिक जाँचों (Internal Assessments) का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को सेमिनारों, वर्कशॉप्स एवं विचार-सम्मेलनों का आयोजन करके, मूल्यांकन की नवीन एवं उन्नत विधियों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
5. परीक्षकों को उत्तर-पुस्तिकाओं की जाँच करने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिये।
6. एक परीक्षक को 1 वर्ष में 500 से अधिक उत्तर-पुस्तिकाएँ जाँचने के लिए नहीं दी जानी चाहिए।



7. निशा का माध्यम : Medium of Instruction—“आयोग” ने कतिनों एव विश्वविद्यालयों में निशा के माध्यम के बारे में जराकित सुझाव अकित किये हैं :—

1. पूर्व-स्नातक-स्तर पर निशा का माध्यम यथानुभव क्षेत्रीय भाषाएँ और स्नातकोत्तर-स्तर पर निशा का माध्यम—अंग्रेजी होनी चाहिए।
2. क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषाओं (Regional Languages) को 10 वर्ष की अवधि में विश्वविद्यालयों में निशा का माध्यम बना दिया जाना चाहिए।
3. उच्च निशा की सुस्थाओं में कार्य करने वाले गुरु निशकों को यथा-सम्भव दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए।
4. आधुनिक भारतीय भाषाओं (जिनमें उर्दू भी है) के विज्ञान के लिए उच्च अध्ययन-केन्द्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. शास्त्रीय एव आधुनिक भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालयों में अनिवार्य विषयों में स्थान न देकर, वैकल्पिक विषयों में स्थान दिया जाना चाहिए।
6. विश्वविद्यालयों एव सम्बद्ध कॉलेजों में छात्रों को अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
7. उक्त निशा-मस्याओं में छात्रों को अपनी भाषा का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

8. चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली : System of Selective Admission—“आयोग” का मत है कि भविष्य में त्रिम अनुपात में उच्च निशा की माँग में वृद्धि होगी, उस अनुपात में उच्च निशा की सुविधाओं में विस्तार करना सम्भव नहीं होगा। अतः जनबल (Manpower) की आवश्यकता को ध्यान में रगकर “चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली” का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इस प्रणाली की उपयोगिता पर प्रमाण डालते हुए, “आयोग” ने लिखा है —“सामान्य रूप में यह होता है कि थोड़े क्षमताओं वाले घोड़े-जो छात्रों को उच्च निशा की सुस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाता है, और उनमें छात्रों की उस विज्ञान सुस्था का प्रवेश हो जाता है, जो उच्च निशा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं।” इस दोष का निवारण करने के लिए, आयोग ने चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया है और उसके सम्बन्ध में अघाकित सुझाव दिये हैं —

1. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश-योग्यताओं के नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. विश्वविद्यालयों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों में से योग्यतम छात्रों का ही चुनाव किया जाना चाहिए।

3. उच्च शिक्षा की संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या का निश्चय इन संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षक-संख्या और शिक्षण-सुविधाओं के आधार पर किया जाना चाहिये।
4. जब तक प्रवेश-सम्बन्धी नवीन विधियों की खोज न हो जाय, तब तक परीक्षाओं में प्राप्त होने वाले अंकों को प्रवेश का आधार बनाया जाना चाहिये।

9. विश्वविद्यालय-स्वाधीनता : University Autonomy—विश्वविद्यालय-स्वाधीनता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, "आयोग" ने लिखा है :—"यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि स्वाधीनता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, अनुसंधान एवं समाज-सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं।"

"It is important to recognise that without autonomy universities cannot discharge effectively their principal functions of teaching research, and service to the community."—*Education Commission Report*, p. 326.

"आयोग" ने अप्रांकित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्वाधीनता का समर्थन किया है :—छात्रों का चुनाव, शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति, और पाठ्य-विषयों, शिक्षण-विधियों एवं अनुसंधान-कार्य के क्षेत्रों एवं समस्याओं का निर्धारण। इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्वाधीनता को ध्यान में रखते हुए, "आयोग" ने निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं :—

1. विश्वविद्यालयों को अपने विभागों को कार्य करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता देनी चाहिये।
2. प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष की अधीनता में एक प्रबन्ध-समिति का निर्माण किया जाना चाहिये। इस समिति को व्यापक आर्थिक एवं प्रशासनिक शक्तियों से सम्पन्न किया जाना चाहिये।
3. विश्वविद्यालयों को अपने प्रशासन में इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिये कि श्रेष्ठ विचारों का जन्म साधारणतः निम्न स्तरों में होता है।
4. विश्वविद्यालयों को कल्लिजों की स्वतन्त्रता का उतना ही आदर करना चाहिये, जितना वे अपनी स्वतन्त्रता का करते हैं।
5. विश्वविद्यालयों की "नाहित्यिक परिषदों" (Academic Councils) एवं सभाओं (Courts) में छात्र-प्रतिनिधियों की उपयुक्त संख्या को स्थान दिया जाना चाहिये।
6. विश्वविद्यालयों को अपनी स्वाधीनता को बनाये रखने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिये। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये,

उनको अपने बौद्धिक एवं सार्वजनिक कार्यों को सदैव नज़र रखते में करना चाहिये।

7. प्रत्येक कॉलेज के प्रत्येक विभाग में छात्रों एवं अध्यापकों की संयुक्त समितियाँ (Joint Committees) का निर्माण किया जाना चाहिये।
8. प्रत्येक कॉलेज में प्रधानाचार्य को अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया जाना चाहिये, जिसके द्वारा कॉलेज की सामान्य समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन किया जाना चाहिये।
9. "विश्वविद्यालय-अनुदान - आयोग", "अन्तर-विश्वविद्यालय-परिषद्" (Inter-University Board) एवं निश्चित व्यक्तियों द्वारा विश्व-विद्यालय-स्वाधीनता के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाना चाहिये।
10. सरकार, विश्वविद्यालयों, "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" एवं "अन्तर-विश्वविद्यालय-परिषद्" को मनुक्त रूप में अशक्त कार्य करने चाहिये :—विभिन्न प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना, प्रवेष्ट दिये जाने वाले छात्रों की सूची निश्चित करना एवं प्रयोगात्मक अनुसंधान की समस्याओं का समाधान करने के लिये उपाय योजना।

## 11. स्त्री-शिक्षा

### Women's Education

स्त्री-शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए, "आयोग" ने लिखा है :—  
 "हमारे मानव-साधनों के पूर्ण विकास, परिवारों की उन्नति एवं शांतिस्थिति के लिये अधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए, स्त्रियों की शिक्षा का महत्त्व पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक है।"

"For full development of our human resources, the improvement of homes, and for moulding the character of children during the most impressionable years of infancy, the education of women is of even greater importance than that of men"—*Education Commission Report*, p 135

"आयोग" ने स्त्री-शिक्षा के लगभग सभी अंगों के विषय में अपने विचारों को लेखबद्ध किया है। हम प्रमुख अंगों से सम्बन्धित उनके विचारों का वर्णन कर रहे हैं; यथा :—

1. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा Primary & Secondary Education—  
 "आयोग" ने बालिकाओं की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नांकित सुझाव दिये हैं :—

## 56 | भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

1. भारतीय संविधान में अंकित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाना चाहिए।
2. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार की गति इतनी तीव्र कर दी जानी चाहिये, जिससे 20 वर्ष के अन्त में निम्न माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं और बालकों की संख्या का अनुपात 1 : 2 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1 : 3 हो जाय।
3. बालिकाओं के लिये पृथक् विद्यालयों एवं छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिये।
2. उच्च शिक्षा : Higher Education—"आयोग" ने बालिकाओं एवं स्त्रियों की उच्च शिक्षा के विषय में अग्रान्वित सिफारिशों की हैं :—
  1. स्त्रियों के लिये पर्याप्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  2. स्त्रियों के लिये उचित प्रकार के और मितव्ययी छात्रावासों की स्थापना की जानी चाहिये।
  3. शिक्षा, गृह-विज्ञान एवं सामाजिक कार्य (Social Work) के पाठ्य-विषयों का विस्तार करके, उनको समुन्नत बनाया जाना चाहिये।
  4. एक या दो विश्वविद्यालयों में स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित "अनुसंधान यूनिटों" (Research Units) की सृष्टि की जानी चाहिये।
  5. स्त्रियों की कला, विज्ञान, प्रयोगिकी, मानव-शास्त्र आदि विषयों में से अपने अध्ययन के विषयों का चुनाव करने की आज्ञा दी जानी चाहिये।
  6. जिन स्थानों में माँग है, वहाँ स्त्रियों के लिये पृथक् पूर्व-स्नातक कॉलेजों का निर्माण किया जाना चाहिये।
  7. स्त्रियों के लिये पृथक् स्नातकोत्तर-कॉलेजों की स्थापना नहीं की जानी चाहिये।
3. पाठ्यक्रम : Curriculum—"स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति" (National Council of Women's Education) द्वारा श्रीमती हंसा मेहता (Hansa Mehta) के अध्यक्षता में नियुक्त की जाने वाली समिति के विचारानुसार बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं होना चाहिये। "शिक्षा-आयोग"—"हंसा मेहता समिति" (Hansa Mehta Committee) के विचारों से सहमत है। फिर भी "आयोग" बालिकाओं के लिये विभिन्न पाठ्यक्रम के विषय में अग्रान्वित विचार व्यक्त है :—
  1. कक्षा 10 के अन्त तक सब बालकों एवं बालिकाओं के लिये पाठ्यक्रम होना चाहिये और उनको केवल कार्य-अनुभव (Experience) या भाषा में पृथक् चुनाव करने का अवसर दिया चाहिये।

2. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को गृह-विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिये, पर उनके लिये यह विषय अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।
3. बालिकाओं को मशीन एवं कलाओं की शिक्षा देने के लिये अधिक उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को विज्ञान या गणित का अध्ययन करने के लिये विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

4. स्त्री-शिक्षा का विस्तार : Expansion of Women's Education—  
 “आयोग” ने स्त्री-शिक्षा के विस्तार के लिये अप्राप्तित मुद्दाव दिए हैं :—

1. स्त्री-शिक्षा के विस्तार के लिये उधारनापूर्वक आर्थिक महायता दी जानी चाहिए।
2. स्त्री-शिक्षा का प्रचार करने के लिये कुछ वर्षों तक दमे शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रम का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग बनाया जाना चाहिए।
3. स्त्री-शिक्षा के मार्ग में समस्त बाधाओं को हटाने के लिये ठोस एवं निश्चित कदम उठाये जाने चाहिए।
4. स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा के मध्य जो विज्ञान अन्तर उत्पन्न हो गया है, उसे समाप्त करने के लिये विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
5. स्त्री-शिक्षा का मतकतापूर्वक निरीक्षण करने के लिये केन्द्र और राज्य—दोनों स्तरों पर शक्तिशाली प्रशासकीय मण्डलों का निर्माण किया जाना चाहिए।
6. विवाहित स्त्रियों के लिये अल्पकालीन और अविवाहित स्त्रियों के लिये पूर्णकालीन रोजगारों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
7. बालिकाओं एवं स्त्रियों के लिये अल्पकालीन एवं पूर्णकालीन व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

## 12 वयस्क-शिक्षा

### Adult Education

“आयोग” ने वयस्क-शिक्षा के विषय में जो विचार व्यक्त किए हैं, हम उनका वर्णन क्रमबद्ध शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं, यथा :—

1. वयस्क-शिक्षा की आवश्यकता : Need of Adult Education—“आयोग” ने वयस्क-शिक्षा का पूर्वाप्त विस्तार में वर्णन किया है। हम इस वर्णन को “आयोग” के अप्राप्तित मन्तों से आरम्भ कर रहे हैं।—“विद्यालय-शिक्षा के बाद शिक्षा का अन्त नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आज के वयस्क को

नौव्र गति से परिवर्तित होने वाले ससार की ओर समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं की जानकारी होना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों ने सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, उनके लिए भी जीवन में शिक्षा की आवश्यकता है।" अतः वयस्क-शिक्षा का संगठन अनिवार्य है।

"आयोग" ने अपने वर्णन में आगे लिखा है :—“जो देश आर्थिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है, उसे अपने वयस्क नागरिकों को विकास कार्यक्रमों में कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से भाग लेने की शिक्षा देनी चाहिए। यह बात भारत के लिए विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि यहाँ के विशाल जनसमूहों को विद्यालयों में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है और जिनको शिक्षा प्राप्त भी हुई है, वह विकास-कार्यक्रमों के लिए व्यर्थ है। जो कृषक, भूमि को जोतता है, उसे भूमि कीटनायक का ज्ञान होना चाहिए। जो श्रमिक, मशीन को चलाता है, उसे मशीन के अंगों का ज्ञान होना चाहिए। कृषकों, श्रमिकों आदि को अपने कार्यों का ज्ञान नहीं है।” अतः उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए वयस्क-शिक्षा की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

“आयोग” ने अपने वर्णन को जारी करते हुए लिखा है :—“कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के भार को केवल पुलिस एवं सेना को नहीं सौंप सकता है। वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ी सीमा तक नागरिकों की शिक्षा, विभिन्न कार्यक्रमों के उनके ज्ञान, उनके चरित्र, उनकी अनुशासन की भावना एवं सुरक्षा-सम्बन्धी कार्यों में उनके कुशलतापूर्वक भाग लेने की क्षमता पर आधारित रहती है।” अतः नागरिकों में इन गुणों का विकास करने के लिए वयस्क-शिक्षा का कार्यक्रम आवश्यक है।

आयोग ने भारत में वयस्क-शिक्षा की आवश्यकता के दो मूलभूत कारण बताए हैं : पहला, भारत के 70 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं, जिनको साधारण बनाया जाना आवश्यक है; दूसरा, भारत—जनतन्त्रीय गणतन्त्र है। अतः उसका कर्तव्य प्रत्येक वयस्क-नागरिक को ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है, जो वह प्राप्त करना चाहता है और जो उसे अपनी व्यक्तिगत उन्नति, व्यावसायिक प्रगति और सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्राप्त करनी चाहिए।

**2. वयस्क-शिक्षा का कार्यक्रम : Programme of Adult Education—**  
“आयोग” ने वयस्क-शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को स्थान दिया है :—

- (i) निरक्षरता का उन्मूलन : Liquidation of Illiteracy.
- (ii) अनवरत शिक्षा : Continuation Education.
- (iii) पत्राचार-पाठ्यक्रम : Correspondence Courses.
- (iv) पुस्तकालय : Libraries.
- (v) विश्वविद्यालयों के कार्य : Role of Universities.
- (vi) संगठन व प्रशासन : Organization & Administration.



2. उक्त शिक्षा-संस्थाओं को उक्त समय में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिनसे बचस्कॉ को अपनी समस्याओं का समाधान करने और अधिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिले।
3. माध्यम बचस्कॉ को स्कूलों एवं कलियों के छात्रों के समान डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने का अवसर देने के लिए, अल्पकालीन शिक्षा की प्रणाली प्रचलित की जानी चाहिए।
4. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान एवं कुशलता में उन्नति करने, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण का विस्तार करने और उनमें अपने बचस्कॉ के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए विशेष प्रकार की अनवरत शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

(iii) पत्राचार-पाठ्यक्रम : Correspondence Courses—“आयोग” ने बचस्कॉ-शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य में पत्राचार-पाठ्यक्रमों का मुन्ताज दिया है और इनके सम्बन्ध में अधोलिखित विचार प्रकट किए हैं :—

1. पत्राचार-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए की जानी चाहिए, जो अल्पकालीन शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
2. पत्राचार-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए भी की जानी चाहिए, जो सांस्कृतिक एवं सौन्दर्यात्मक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके, अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं।
3. पत्राचार-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए भी की जानी चाहिए, जो देश के “माध्यमिक शिक्षा-बोर्डों” एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षाएँ पास करना चाहते हैं।
4. पत्राचार-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था—कृषि, विभिन्न उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भी की जानी चाहिए।
5. पत्राचार-पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को कभी-कभी अपने शिक्षकों से भेंट करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
6. पत्राचार-पाठ्यक्रमों का रेडियो एवं टेलीविजन के कार्यक्रमों से निकट सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए।

(iv) पुस्तकालय : Libraries—“आयोग” ने बचस्कॉ-शिक्षा में सम्बन्धित पुस्तकालयों के विषय में नीचे लिखे विचार प्रस्तुत किए हैं :

1. बचस्कॉ के पुस्तकालय प्रगतिशील होने चाहिए।
2. उक्त पुस्तकालयों को बचस्कॉ को शिक्षित एवं आकर्षित करना चाहिए।
3. विज्ञानियों के पुस्तकालयों को सार्वजनिक पुस्तकालयों का रूप दिया



जाना चाहिए और उनमें बच्चों एवं नव-साक्षरों (Neo-Literates) की रचियों को ध्यान में रखकर पुस्तकों का संग्रह किया जाना चाहिए।

4. "पुस्तकालय-सलाहकार-मिति" (Advisory Committee on Libraries) द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण देश में पुस्तकालयों की स्थापना की योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

(v) वयस्क-शिक्षा में विश्वविद्यालयों के कार्य : Role of Universities in Adult Education—"आयोग" के मतानुसार विश्वविद्यालयों को वयस्क-शिक्षा के प्रसार के लिए अग्रणी कार्य करने चाहिए :—

- 1 विश्वविद्यालयों को वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए।
- 2 विश्वविद्यालयों को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके, वयस्कों के आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में योग देना चाहिए।
- 3 विश्वविद्यालयों को दिल्ली-विश्वविद्यालय के समान पत्राचार-वाटपक्रमों की योजना आरम्भ करनी चाहिए।
- 4 विश्वविद्यालयों को राजस्थान-विश्वविद्यालय के समान वयस्क-शिक्षा के विभाग की स्थापना करनी चाहिए।
- 5 विश्वविद्यालयों को अपने वयस्क-शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाते रहने के लिए सरकार से उदार आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

(vi) वयस्क-शिक्षा का संगठन व प्रशासन Organization & Administration of Adult Education—"आयोग" ने वयस्क-शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन में निम्नान्वित सुझाव दिए हैं :—

- 1 वयस्क-शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली व्यक्तिगत संस्थाओं को सरकार द्वारा आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता दी जानी चाहिए।
- 2 शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा "राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा-परिषद्" (National Board of Adult Education) की स्थापना की जानी चाहिए।
- 3 उक्त "परिषद्" पर निम्नलिखित कार्यों को सौंपा दित करने का उत्तरदायित्व रखा जाना चाहिए :—

- (i) केन्द्र एवं राज्य की सरकारों की अनौपचारिक वयस्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बारे में परामर्श देना और इनमें सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना।
- (ii) वयस्कों की शिक्षा के लिए उपयुक्त साहित्य, पठन-ग्रामपौ एवं प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का उत्पादन को प्रोत्साहन देना।
- (iii) विभिन्न मन्त्रालयों और सरकारों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ सामंजस्य स्थापित करना।

- (iv) समय-समय पर वयस्क-शिक्षा के प्रसार की जाँच करना और उसमें सुधार एवं परिवर्तन करने के लिए सुझाव देना ।
  - (v) वयस्क-शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना ।
4. उक्त "परिषद्" के समान राज्य-स्तर पर परिषदों का और जिला-स्तर पर समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए । ग्राम-स्तर पर "परिषद्" के कार्यों को विद्यालयों को सौंपा जाना चाहिए ।

### 13. विज्ञान की शिक्षा

#### Science Education

"आयोग" का मत है कि विज्ञान की शिक्षा—भारत की प्रगति, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए परम आवश्यक है । अतः उसने विज्ञान की शिक्षा (जिसमें उसने गणित एवं प्रयोगिकी को भी सम्मिलित किया है) के प्रसार के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं; यथा :—

1. आधुनिक युग में विज्ञान एवं प्रयोगिकी के महत्त्व को स्वीकार करके, इनकी शिक्षा-प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए ।
2. विज्ञान एवं प्रयोगिकी की शिक्षा को देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से सम्बन्धित किया जाना चाहिए ।
3. विज्ञान एवं गणित के पूर्व-स्नातक एवं स्नातकोत्तर-स्तरीय के पाठ्यक्रमों में आमूल संशोधन करके, उनको उच्च बनाया जाना चाहिए ।
4. विज्ञान एवं गणित की शिक्षा के लिए उच्च अध्ययन-केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए और उनमें योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ।
5. विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिए, विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए "ग्रोष्मकालीन संस्थानों" (Summer Institutes) की योजना संचालित की जानी चाहिए ।
6. विज्ञान से सम्बन्धित विषयों के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्षों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ।
7. देश की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विज्ञान के छात्रों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ।
8. प्रत्येक कक्षिक एवं विश्वविद्यालय में विज्ञान की पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशालाएँ एवं वर्कशॉप होने चाहिए, जिनमें छात्रों की विभिन्न कक्षाओं का प्रयोग भलीभाँति मिलाया जाना चाहिए ।
9. विदेशी वैज्ञानिकों एवं विदेशों में कार्य करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय वैज्ञानिकों को भारत में शिक्षण-कार्य करने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए ।

10. "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" को एक अखिल भारतीय समिति निर्माण करना चाहिए। इस समिति को 2 या 3 वर्ष के इकरारना पर विज्ञान के "विजिटिंग प्रोफेसर्स" (Visiting Professors) नियुक्ति करनी चाहिए।
11. प्रायोगिक भौतिकशास्त्र एवं रसायनशास्त्र का विकास करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
12. एम० एस्-सी० स्तर के बाद वैकल्पिक आधार पर एक नवीन उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
13. वर्तमान वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 2 वर्ष के एम० एस्-सी० के कोर्स के अतिरिक्त 1 वर्ष या कम अवधि का कोई विशेष कोर्स आरम्भ किया जाना चाहिए।
14. अन्तिम परीक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि बशा के रेकार्ड के आधार पर प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
15. औद्योगिक कार्यकर्त्ताओं को पत्र-व्यवहार एवं सायकलीन कक्षाओं के द्वारा प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

#### 14 कृषि की शिक्षा

##### Agricultural Education

कृषि-प्रधान देश, भारत में कृषि की हीन दशा और देश के लिए उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, 'आयोग' ने कृषि की शिक्षा में सुधार एवं विस्तार करने के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उनका विवरण दृष्टव्य है—

1 कृषि-विश्वविद्यालय Agricultural Universities—"आयोग" ने विश्वविद्यालयों की स्थापना, कार्यो जादि के विषय में निम्नलिखित सुझाव हैं—

- 1 प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।
- 2 कृषि-विश्वविद्यालयों में कृषि की शिक्षा, अनुमान एवं प्रसार सम्बन्धों को उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए।
- 3 कृषि-विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर-शिक्षा का उपयोजन करने के लिए योग्य एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- 4 कृषि-विश्वविद्यालयों में कक्षा-शिक्षण की अपेक्षा प्रायोगिक एवं प्रयोगशाला-कार्यो पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
- कृषि-विश्वविद्यालयों के 25 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

6. कृषि-विश्वविद्यालयों में कृषि-शिक्षा के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण-केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
7. प्रत्येक कृषि-विश्वविद्यालय में न्यूनतम कम-से-कम 1,000 एकड़ भूमि का फार्म होना चाहिए, जिसमें से 500 एकड़ भूमि कृषि के योग्य होनी चाहिए।
8. प्रथम डिग्री-कोर्स की अवधि 10 वर्ष की विद्यालय-शिक्षा के पश्चात् 5 वर्ष की होनी चाहिए।
9. उपाधि प्रदान करने से पूर्व प्रत्येक छात्र के लिए फार्म पर 1 वर्ष का कृषि-कार्य अनिवार्य होना चाहिए।
10. केन्द्रीय अनुसंधान-केंद्रों एवं कृषि-विश्वविद्यालयों को पारस्परिक सहयोग से स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए उत्तम केंद्रों का निर्माण करना चाहिए।
11. सभी कृषि-विश्वविद्यालय यथासम्भव शिक्षण-विश्वविद्यालय होने चाहिए।
12. राज्य परीक्षाओं को समाप्त करने का यथाशक्ति प्रयास किया जाना चाहिए।

## 2. कृषि-कॉलेज : Agricultural Colleges — “आयोग” ने कृषि-कॉलेजों के विषय में अधोनिम्नित सुझाव दिए हैं :—

1. नवीन कृषि-कॉलेजों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि पुराने कॉलेजों में सुधार करके, उनको नुसार रूप से संचालित किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक कृषि-कॉलेज के पास कम-से-कम 200 एकड़ भूमि का सुव्यवस्थित फार्म होना चाहिए।
3. कुछ कृषि-कॉलेजों में डिग्री-कोर्सों के बजाय उच्च टेक्नीशियन (Technician) स्तर के कोर्सों का आयोजन किया जाना चाहिए।
4. कृषि-कॉलेजों का प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” एवं “भारतीय कृषि-अनुसंधान-परिषद्” (Indian Agricultural Research Institute) द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए।

## 3. कृषि-पॉलिटेक्निक : Agricultural Polytechnics — “आयोग”

निर्धारित की है कि कृषि-शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए “कृषि-पॉलिटेक्निक” का गठन किया जाना चाहिए और उनके सन्वय में अविचार इन प्रकार निम्नलिखित किए हैं :—

1. मेट्रोपॉलिटन-स्तर के बाद प्रत्येक राज्य में कृषि-पॉलिटेक्निकों की स्थापना की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2. पॉलिटेक्नीको को कृषि-विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।
3. पॉलिटेक्नीको में अधिकतम छात्र-संख्या 1,000 होनी चाहिए।
4. पॉलिटेक्नीको में कृषि की ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसे समाप्त करने के पश्चात् छात्रों को कृषि की उच्च शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश मिल सके।
5. पॉलिटेक्नीको में कृषि एवं कृषि में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सघन एवं संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
6. कृषि-शिक्षा की तात्कालिक मांग को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के निकट स्थित पॉलिटेक्नीको में कुछ समय तक कृषि की शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

#### 4. विद्यालयों में कृषि शिक्षा : Agricultural Education in Schools—

“आयोग” की धारणा है कि कृषि-शिक्षा को विद्यालयों की सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। अपनी इस धारणा के अनुसार, “आयोग” ने विद्यालयों में कृषि-शिक्षा के बारे में अधोलिखित सुझाव अंकित किए हैं —

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सब प्राथमिक विद्यालयों में कृषि-सम्बन्धी जानकारी को सामान्य शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए।
2. विद्यालय-स्तर पर कृषि को कार्य-अनुभव (Work Experience) का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाना चाहिए।
3. अध्यापक-शिक्षा के कार्यक्रमों में कृषि एवं ग्रामीण समस्याओं को उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए।

#### 15. व्यावसायिक, प्राविधिक व इंजीनियरिंग की शिक्षा

##### Vocational, Technical & Engineering Education

“आयोग” का कथन है कि देश के औद्योगीकरण को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः औद्योगीकरण की योजनाएँ बनाने वालों का यह कर्तव्य है कि वे विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाएँ और उनके प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का निर्माण करें। इस कार्य में हाथ बँटाने के लिए, “आयोग” ने व्यावसायिक, प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा के विषय में कुछ विचार व्यक्त किए हैं, जिनकी चर्चा दयास्थान की जा रही है।

**1 व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा : Vocational & Technical Education—**“आयोग” ने व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा के विषय में जो विचार अंकित किए हैं, वे अप्रतिष्ठित हैं :—

1. व्यावसायिक शिक्षा का प्रकार सुगठित योजना के अनुसार दृढ़ प्रकार दिया जाना चाहिए, जिसे 1985-86 में निम्न माध्य-

- 20 प्रतिशत छात्र एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत छात्र पूर्णकालीन एवं अंशकालीन व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों।
2. विद्यालय-स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम अपने-आप में सम्पूर्ण होने चाहिए, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा की संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं (Industrial Training Institutes) में सर्वोत्तम के आधार पर प्रशिक्षण की सुविधाओं का अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाना चाहिए।
4. विद्यालय-शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को व्यावसायिक एवं प्राविधिक-प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पत्राचार-पाठ्यक्रमों, अल्पकालीन पाठ्यक्रमों एवं संक्षिप्त-सघन पाठ्यक्रमों (Short-Intensive Courses) की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल हाई स्कूलों की संज्ञा दी जानी चाहिए।
6. टेक्निकल स्कूलों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं में व्यावहारिक कार्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए एवं उनको उत्पादन-उन्मुखी (Production Oriented) बनाया जाना चाहिए।
7. नवीन पॉलिटेक्नीकों की स्थापना औद्योगिक क्षेत्रों में की जानी चाहिए।
8. जो पॉलिटेक्नीक—ग्रामीण क्षेत्रों के चल रहे हों, उनमें कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योगों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
9. पॉलिटेक्नीकों में बालिकाओं की विशेष रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
10. पॉलिटेक्नीकों के शिक्षकों की साहित्यिक योग्यताओं (Academic Qualifications) में कमी की जानी चाहिए और माध्यात्मतः उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो विभिन्न उद्योगों में कार्य करते, औद्योगिक अनुभव प्राप्त कर चुके हों।
11. पॉलिटेक्नीकों के होने वाले अवकाश को समाप्त करने एवं उनको अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
12. कुछ पॉलिटेक्नीकों में डिप्लोमा प्राप्त कर चुकने वाले छात्रों के लिए पोस्ट-डिप्लोमा (Post-Diploma) कोर्सों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. इंजीनियरिंग की शिक्षा : Engineering Education—"आयोग" ने इंजीनियरिंग की शिक्षा के सम्बन्ध में अग्रगण्य सुझाव दिए हैं :—

1. इंजीनियरिंग के जो कॉलेज उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनमें या तो सुधार किया जाना चाहिए या उनको बन्द कर दिया जाना चाहिए ।
2. इंजीनियरिंग की अप्रशिक्षित शरणाओं का अध्ययन करने के लिए केवल योग्य एवं प्रतिभाशाली बी० एम-बी० पाठ विद्यार्थियों का ही चुनाव किया जाना चाहिए :—उपकरण एवं विद्युत-जन्तु (Instrumentation & Electronics) ।
3. इंजीनियरिंग की शिक्षा के पाठ्यक्रमों को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार का बनाया जाना चाहिए ।
4. इंजीनियरिंग की शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए ।
5. इंजीनियरिंग की शिक्षा में अप्रशिक्षित पाठ्य-विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए :—विमान-विद्या, नक्षत्र-विज्ञान, रासायनिक प्रौद्योगिकी (Aeronautics, Astronautics, Chemical Technology), आदि ।
6. छात्रों को डिप्ली-कोर्स के तृतीय वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और कार्यशाला-कार्य (Workshop Practice) में उत्पादन-कार्य पर विशेष रूप में बल दिया जाना चाहिये ।
7. इंजीनियरिंग की शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों की नवीनतम ज्ञान से सम्पन्न करने के लिए “समर-कालीन संस्थाओं” (Summer Institutes) की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
8. प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शिक्षण-व्यवस्था के प्रति आकृष्ट करने के लिए शिक्षकों के वेतन-क्रमों में वृद्धि की जानी चाहिए और उनको ताम्र किया जाना चाहिए ।
9. टेक्नालॉजी की संस्थाओं में उच्च अध्ययन-केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए ।
10. टेक्नालॉजी की संस्थाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निम्ने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

### आयोग का मूल्यांकन Estimate of the Commission

“शिक्षा-आयोग” के सदस्यों में देश और विदेश के माने हुए विद्वान् और गुणवत्ते हुए शिक्षा-मर्मज्ञ थे । सभी को अपने-अपने क्षेत्रों का लम्बा अनुभव था, गहरी जानकारी थी । इसीलिए, उन्होंने भारतीय शिक्षा का लक्ष्य में निम्न तक कायाकल्प करने के लिए बलपूर्वक और अनुपम मुझाव दिया ।

इन मुझावों में से विशेष रूप से उल्लेखनीय है — शिक्षा का नवीन मण्डन.

विज्ञान की शिक्षा पर बल, प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, शैक्षिक अवसरों की समानता, विभाषी-मृत्यु में संशोधन, प्राथमिक स्तर से निर्देशन की आवश्यकता, प्रतिभाशाली छात्रों की चोज और शिक्षकों की स्थिति में उन्नति ।

“शिक्षा-आयोग” के उपरिअंकित सभी सुझाव सारगर्भित हैं, सराहना के योग्य हैं । पर यदि हम थोड़ा-सा समय निकाल कर और एकाग्रचित्त होकर, उन पर विचार करें, तो हमको यह जानने में देर नहीं लगेगी कि उनमें सरलता के बजाय जटिलता है, व्यावहारिकता के बजाय आदर्शवादिता है । अतः उनकी अभि-पूर्ति असम्भव है । उनकी अभिपूर्ति के लिए इतने अपार धन की आवश्यकता है कि भारत के नमान दरिद्र देश के लिए उसे जुटाना असम्भव है ।

यदि हम “आयोग” के कुछ सुझावों पर अलग-अलग विचार करें, तो हमसे उन की निरर्थकता और निस्सारता छिपी नहीं रह सकती है । उदाहरणार्थ—उसने शिक्षकों के पदों की सुरक्षा के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है । उसने संस्कृत के अध्ययन की अनुपयोगी बताकर, उसके उन्मूलन का अच्छा प्रयत्न कर दिया है । उसने धैर्य शिक्षा को शिक्षा के सब स्तरों से बाहर निकाल कर, उसकी मृत्यु के अनुमति-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं । उसने भारत में अंग्रेजी की अनिश्चित काल तक बनाए रखने की सिफारिश करके, एक अन्तर्राष्ट्रीय पट्टयन्त्र से नाता जोड़ लिया है ।

माराज यह है कि “आयोग” के अधिकांश सुझाव चोकाते वाले हैं, परिशानी में प्रचलने वाले हैं । सत्य बात तो यह है कि भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ जिन विदेशियों से भारतीय शिक्षा के विकास के लिए परामर्श लिया गया, उनसे इसी प्रकार के काल्पनिक और कंटकपूर्ण सुझावों की आशा की जा सकती थी । अतः हम केवल यह विचार अपने मूल्यांकन को समाप्त करते हैं कि “आयोग” के केवल दो-चार सुझाव ही क्रियान्वित करने के योग्य हैं । शेष केवल इसी योग्य हैं कि उनकी लागत पर विराट् हुआ रहने दिया जाय ।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Summarize briefly the recommendations of the Education Commission on teacher education. How far are they likely to improve educational standards ?  
शिक्षक-शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा-आयोग की सिफारिशों का मशियन माराज विमर्श । वे शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कहीं तक सहायक सिद्ध हो सकती हैं ?
2. Comment on the view that the Report of the Indian Education Commission of 1966 is the first serious attempt at evolving a comprehensive scheme of a national system of education in India.



इस मत की समालोचना कीजिए कि सन् 1966 के भारतीय शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की एक व्यापक योजना का प्रथम वास्तविक प्रयास है।

3. What reforms have been suggested by the Education Commission to break down the isolation of Primary and Secondary teachers' training institutions from the academic life of the universities and the everyday problems of schools?

प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापकों की प्रशिक्षण-संस्थाओं का विश्व-विद्यालयों के विद्वत्परिपक्व के जीवन तथा विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से पार्थक्य को हटाने के लिए शिक्षा-आयोग ने क्या सुधार प्रस्तुत किए हैं?

4. Give a critical estimate of the need of vocationalization of Secondary Education in India. What difficulties can arise in doing so and how can they be removed?

भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता की समीक्षात्मक आलोचना लिखिए। ऐसा करने से क्या कठिनाइयाँ उठ सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है?

5. Write briefly the recommendations of the Kothari Commission on the following —(a) Three Language Formula, (b) University Autonomy, (c) Pattern of Secondary Education, (d) Reform in Women's Education, and (e) Improvement in University Education

अग्रलिखित पर कोठारी कमिशन की सिफारिशों को मधेन में लिखिए :-

(अ) त्रिभाषा-मूत्र, (ब) विश्वविद्यालय-स्वाधीनता, (स) माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप, (द) स्त्री-शिक्षा में सुधार, और (ए) विश्वविद्यालय-शिक्षा में उन्नति।

# 21

## स्वतन्त्र भारत में शिक्षा EDUCATION IN FREE INDIA (1947-1974)

"Education in India has expanded very rapidly since the attainment of independence". —Saiyidain & Gupta.

### विषय-प्रवेश

15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्रता की मुरझ में भारतीय शिक्षा ने करघट बदली। पराधीनता के कारण भारत में जो विष फैल गया था, उसे दूर करने और जन-चेतना को जाग्रत करके जनतन्त्र के अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग करने के लिए शिक्षा को एक नवीन दिशा देने का निश्चय किया गया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर, जनवरी, 1948 में भारत के शिक्षा-मंत्री ने एक अखिल-भारतीय शिक्षा-सम्मेलन का आयोजन किया।

उस अवसर पर भारत के महात्माजी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्घाटन-भाषण में कहा :—"पराधीन भारत में जब कभी शिक्षा को योजना बनाने के लिए सम्मेलन होते थे, तब उनमें सामान्य रूप से कुछ संशोधनों के बाद प्रचलित शिक्षा-प्रणाली को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। किन्तु, अब हमें इस प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए और शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके उसे देश की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए।"

पंडित नेहरू के इस भाषण से अनुप्राणित होकर देश में शिक्षा की नई दिशा देने और इसकी वृद्धिशील प्रगति के लिए जो "चेष्टाएँ" अब नई की गई हैं, उनका सही-सही विवरण आगे के प्रसंगों द्वारा प्रस्तुत है।

## शिक्षा का उत्तरदायित्व Responsibility of Education

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा-प्रणामन की नीति में कोई हेर-फेर नहीं हुआ है जिस प्रकार 1935 के "भारत-सरकार अधिनियम" (Government of India Act) के अन्तर्गत शिक्षा का उत्तरदायित्व—प्रान्तीय सरकारों पर था, उसी प्रकार स्वतन्त्र भारत के संविधान के अनुसार यह उत्तरदायित्व—राज्य-सरकारों पर है।

इस प्रकार, यद्यपि भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य-सरकारों पर है, तथापि केन्द्रीय सरकार—शिक्षा के सम्बन्ध में अत्यधिक जागरूक है। वह राज्य-सरकारों को शिक्षा के विषय में आवश्यक परामर्श देती है और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वह शिक्षा-आयोगों की नियुक्ति करके और शिक्षा की समस्याओं में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके राज्यों का शिक्षा के सम्बन्ध में मार्ग-प्रदर्शन करती है। वह सब राज्यों में "शिक्षा-मुविषाजो में समन्वय, उच्च शिक्षा के स्तर के निर्धारण, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा-अनुसंधान, हिन्दी और सभी भारतीय भाषाओं के विकास का कार्य करती है। अलीगढ़, दिल्ली, बनारस, विश्व-भारती तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों और समद द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय महत्त्व की अन्य समस्याओं के मचातन का दायित्व भी केन्द्रीय सरकार पर है।"<sup>1</sup> केन्द्रीय सरकार अपने इन सब दायित्वों का निर्वाह "भारतीय शिक्षा-मन्त्रालय" के माध्यम से करती है।

## भारतीय शिक्षा-मन्त्रालय Indian Ministry of Education

भारतीय अर्थात् केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का प्रधान—केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री होता है। उसका मुख्य कर्मचारी—केन्द्रीय शिक्षा-परामर्शदाता (Educational Adviser) होता है। वही शिक्षा-मन्त्रालय के सचिव का भी कार्य करता है। उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि वह सम्पूर्ण देश की शिक्षा-नीति तथा प्रशासन के सम्बन्ध में शिक्षा-मंत्री को परामर्श देता है। इसीलिए, इस पद पर देश का माना हुआ शिक्षा-शास्त्री आमीन किया जाता है। इस पद पर कार्य करने वालों में सर जॉन मार्टिन्ट एव श्री हुमायूँ कबीर जैसे महान् व्यक्ति—शिक्षा के इतिहास में विख्यात हैं।

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय अप्रतिष्ठित 8 विभागों में विभक्त है<sup>2</sup> :—

1. प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा-विभाग।
2. माध्यमिक शिक्षा-विभाग।
3. उच्च शिक्षा तथा यूनेस्को-विभाग।

1. भारत, 1973, p. 74.

2. डा० धीरनाथ मुखोपाध्याय भारतीय शिक्षा का इतिहास, p. 214.

4. हिन्दो-विभाग ।
5. सामाजिक शिक्षा तथा समाज-कल्याण विभाग ।
6. व्यायाम तथा मनोरंजन विभाग,
7. छात्रवृत्ति विभाग, तथा
8. प्रशासन-विभाग ।

केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय का मुख्य कार्य—नीति-निर्धारण, निर्देशात्मक एवं सहयोगात्मक है । अतः मंत्रालय में शिक्षा-सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए अनेक परिषदें हैं, जिनमें से अग्रणीक उल्लेखनीय हैं :— (1) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग, (2) केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-परिषद्, (3) अखिल-भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद्, (4) अखिल-भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद्, और (5) अखिल-भारतीय प्राविधिक शिक्षा-परिषद् ।

1. विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग : *University Grants Commission* (1953)—इसकी स्थापना 1953 में की गई थी । 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था (Autonomous Body) मान लिया गया है । (देखिए अध्याय 15) ।

इस "आयोग" के मुख्य कार्य हैं :—(1) विश्वविद्यालयों को समुचित अनुदान देना, (2) विश्वविद्यालयों की विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करना, (3) विश्वविद्यालयों के स्तर के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, (4) विश्वविद्यालयों में परीक्षा, शिक्षण एवं अनुसंधान के मानदण्ड स्थापित करना एवं उनका पालन करवाना, (5) विश्वविद्यालय-शिक्षा की उन्नति एवं समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाना, (6) विश्वविद्यालय-सम्बन्धी किसी प्रश्न या समस्या के सम्बन्ध में केन्द्र या राज्य-सरकारों को परामर्श देना, (7) शिक्षा के उच्च केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनको विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित करना, (8) छात्रों को भ्रमण के लिए अनुदान (Travel Grants) देना, (9) छात्रवृत्तियों एवं अनिसदस्यताओं (Fellowships) के आवेदनों को मंजूर करना, (10) छात्रावासों का निर्माण करवाना, (11) शिक्षकों के वेतन में सुधार करना, और (12) अवकाश-प्राप्त शिक्षकों की सेवाओं से लाभ उठाना ।<sup>1</sup>

2. केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-परिषद् : *Central Advisory Board of Education* (1935)—इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, परन्तु कुछ कारणवश इसे 1923 में भंग कर दिया गया था । 1935 में इसका पुनः गठन किया गया । (देखिए अध्याय 15) ।

इन "परिषद्" के मुख्य कार्य हैं :—(1) अपनी वार्षिक बैठक में सम्पूर्ण देश के शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करना, (2) समय-समय पर शिक्षा के विशिष्ट



इस "परिषद्" के मुख्य कार्य हैं :—(1) सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का सर्वेक्षण करना, (2) केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के विषय में परामर्श देना, (3) केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों के माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं उन्नति से सम्बन्धित प्रस्तावों की परीक्षा करना, और (4) माध्यमिक शिक्षा में सम्बन्धित शोधों एवं अनुसंधानों पर गवेषण एवं विचार-विमर्श के लिए सुझाव देना ।

5. अखिल-भारतीय प्राविधिक शिक्षा-परिषद् : All-India Council for Technical Education (1945)—इसकी स्थापना 1945 में हुई थी । यह केन्द्रीय और राज्य-सरकारों को हाई-स्कूल के स्तर से ऊपर की प्राविधिक शिक्षा के संगठन और विकास के लिए परामर्श देती है ।

इस "परिषद्" की सिफारिश की स्वीकार करके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वीय और पश्चिमी क्षेत्रों में प्रादेशिक समितियों (Regional Committees) का निर्माण किया गया है । इनके प्रधान कार्यालय क्रमशः कानपुर, मद्रास, कलकत्ता और मद्रास में हैं । ये समितियाँ अपने क्षेत्रों में स्थित प्राविधिक शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण करती हैं और प्राविधिक शिक्षा की सुविधाओं में समन्वय स्थापित करती हैं ।<sup>1</sup>

### राष्ट्रीय शिक्षा-नीति

#### National Education Policy

भारत-सरकार ने शिक्षा के विकास और सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के विषय में परामर्श देने के लिए सन् 1964 में "शिक्षा-आयोग" की नियुक्ति की । "आयोग" ने भारतीय शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का गहन एवं विस्तृत अध्ययन किया । इस अध्ययन के परिणामस्वरूप यह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भारतीयों की कुशलताओं एवं आकांक्षाओं, धारणाओं एवं मान्यताओं में अन्विष्टारी परिवर्तन करके इस देश के कृषिवासी, मध्यमवर्गीय एवं अप्रगतिशील समाज को रूपान्तरित करके आर्थिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उन्नति की दिशा में उन्मुख किया जाना सम्भव है । इस अन्विष्टारी परिवर्तन के लिए शिक्षा से अधिक उत्तम साधन और कोई नहीं है । इस मन्दर्श ने "आयोग" ने किया है :—"अन्य साधन सहायता दे सकते हैं और वास्तव में कभी-कभी उनका अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है । किन्तु, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली ही वह साधन है, जो सब व्यक्तियों तक पहुँच सकती है ।"

"Other agencies may help, and can indeed sometimes have a more apparent impact. But the national system of education is the only instrument that can reach all the people."—*Education Commission Report*, p. 4.

1. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 284.

“आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के विषय में जो विचार व्यक्त किए, उनको संसद के सदस्यों, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों, राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों और भारतीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने कुछ समीक्षण के पश्चात् स्वीकार किए। इसी के आधार पर भारत-सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में 24 जुलाई, 1968 को जारी किया।<sup>1</sup>

स्वतन्त्र भारत की इस प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में 17 कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। इनके अंतर्गत शिक्षा के सब महत्त्वपूर्ण पक्षों, विद्वान्तों, स्तरों एवं संरचना को स्थान दिया गया है और शिक्षा के आधारभूत तथ्यों एवं उद्देश्यों को भी निर्धारित किया गया है। इसमें निहित 17 कार्यक्रम अधोलिखित हैं :—

1. परीक्षाओं में सुधार,
2. धन-शुल्क की व्यवस्था,
3. कार्य-अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा,
4. शैक्षिक अवसरों में समानता की स्थापना,
5. माधरता एवं वयस्क-शिक्षा का प्रसार,
6. अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था,
7. कृषि एवं उद्योगों के लिए शिक्षा का विकास,
8. विज्ञान एवं अनुसंधान की शिक्षा का गमान स्तर,
9. अध्यापकों के वेतन, शिक्षा एवं पदस्थिति में सुधार,
10. मस्ती पाठ्यपुस्तकों के स्तर एवं उत्पादन में सुधार,
11. विभाषा-ग्रन्थ एवं प्रादेशिक भाषाओं का विकास,
12. प्रतिभाशाली छात्रों की खोज एवं उनको प्रतिभा का अधिकतम विकास,
13. अल्पवयस्क शिक्षा एवं पत्राचार-पाठ्यक्रमों की विशाल पैमाने पर व्यवस्था,
14. 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था,
15. माध्यमिक स्तर पर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार,
16. उच्च शिक्षा के केंद्रों की सुविधाओं में विस्तार और स्नातकोत्तर-स्तर पर अनुसंधान एवं पाठ्यक्रमों में सुधार, तथा

1. भारत, 1973, p. 74

2. *Hindustan Year-Book*, 1969, p. 179.

17. शिक्षा की संरचना—10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स।

टिप्पणी—उपरोक्त कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत धन व्यय करने का निश्चय किया गया है।<sup>1</sup>

### शिक्षा का विस्तार

#### Expansion of Education

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। स्कूल और विश्वविद्यालय-स्तर पर दर्ज नामों की संख्या कई गुना हो गई है। इंजीनियरिंग और नर्सरी स्तरों में प्रवेश-क्षमता सात गुना हो गई है। समग्र रूप में शिक्षा का विस्तार निम्नांकित तालिका में स्पष्ट किया गया है :—

शिक्षालय, छात्र, शिक्षक व व्यय<sup>2</sup>

वर्ष	शिक्षालय-संख्या	छात्र-संख्या (लाखों में)	शिक्षक-संख्या (लाखों में)	व्यय (करोड़ रुपयों में)
1950-51	2,86,860	2,55.43	8.04	114.38
1955-56	3,66,641	3,39.24	11.07	189.66
1960-61	4,72,655	4,79.64	15.08	344.38
1964-65	7,53,416	6,74.17	20.13	534.51
1965-66	7,27,263	7,05.55	21.33	622.02
1966-67	7,56,094	7,26.69	22.22	678.42
1967-68	7,93,799	7,65.82	22.50	800.84

### निःशुल्क विद्यालय-शिक्षा

#### Free School Education

भारत में निःशुल्क विद्यालय-शिक्षा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है<sup>3</sup> :—

1. जम्मू-कश्मीर और नागालैंड केवल दो राज्यों में शिक्षा सब स्तरों पर निःशुल्क है।
2. तामिलनाडु में प्री-यूनीवर्सिटी कक्षाओं सहित सम्पूर्ण विद्यालय-शिक्षा निःशुल्क है।
3. आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर में माध्यमिक स्तर के अन्त तक सब शिक्षा निःशुल्क है।
4. महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। बिन धर्षों के अभिभावकों

1. भारत, 1973, p. 74.

2. *Ibid.*

3. *Hindustan Year-Book*, 1974, p. 176.



की वार्षिक आय 1,200 रुपये से कम है, उनकी शिक्षा सब स्तरों पर निःशुल्क है।

5. गुजरात में लगभग वही स्थिति है, जो महाराष्ट्र में है।
6. राजस्थान में बालिकाओं के लिए सब शिक्षा निःशुल्क है। बालकों के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है।
7. पंजाब, हरियाणा और मध्य-प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा सब बच्चों के लिए निःशुल्क है।
8. उत्तर-प्रदेश में बालिकाओं के लिए कक्षा 10 के अन्त तक शिक्षा निःशुल्क है, किन्तु बालकों के लिए केवल कक्षा 6 तक निःशुल्क है।
9. बिहार में कक्षा 1 से कक्षा 7 तक प्रा.मिक शिक्षा सब बच्चों के लिए निःशुल्क है।
10. पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बालिकाओं के लिए शिक्षा निःशुल्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। कनकपुरा और कुछ अन्य शहरी क्षेत्रों में शिक्षा अभी निःशुल्क नहीं है।
11. उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है।
12. आसाम में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बालिकाओं के लिए और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क है।
13. दिल्ली के संघीय क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा सब बच्चों के लिए निःशुल्क है।
14. अन्य संघीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है।
15. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क है।

नागालैंड और हिमाचल-प्रदेश के अतिरिक्त सभी राज्यों द्वारा "अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम" (Compulsory Primary Education Act) पारित कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप 11-14 वय-वर्ग के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा का जागरूक प्रसार हुआ है। हम इसकी पुष्टि निम्नांकित तालिका द्वारा कर रहे हैं।

### प्राथमिक शिक्षा का विस्तार<sup>1</sup>

वय-वर्ग	1951	1971
6-11	लगभग 182 लाख या इस वय-वर्ग के 43% बच्चे	लगभग 605 लाख या इस वय-वर्ग के 80% बच्चे
11-14	लगभग 31 लाख या इस वय-वर्ग के 13% बच्चे	लगभग 143 लाख या इस वय-वर्ग के 35% बच्चे

भारतीय शिक्षा और उमरी समस्याएँ

"एन सी सी" (National Council for Women's Education) प्राधिकारों ने शिक्षा का प्रसार करने की विधियों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दी है। साथ ही, यह वालिका-शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं को भी प्रभावित करती है।

"एन सी सी" (All-India Council for Elementary Education) प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक रूप प्रदान करने के विषय में केन्द्रीय एवं राज्य-स्तरों को परामर्श देती है और कार्यक्रम भी तैयार करती है। प्राथमिक शिक्षा के सामान्यतः दो स्तर हैं—प्राथमिक और मिडिल। किन्तु, प्राथमिक स्तर की शिक्षा को राज्यों और संघीय क्षेत्रों में अनेक विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि निम्नांकित तालिका में स्पष्ट हो जायगा :—

प्राथमिक	मिडिल
कक्षा 1 से 4 या 5	कक्षा 5 से 7 या 6 से 8
प्राथमिक (पंजाब)	मिडिल (पंजाब)
निम्न प्राथमिक (गुजरात)	जूनियर हाई स्कूल (उ० प्र०)
जूनियर बेसिक	मौलिक बेसिक
निम्न प्रारम्भिक (मद्रास)	उच्चतर प्रारम्भिक (मद्रास)

### माध्यमिक शिक्षा Secondary Education

प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा का भी प्रसार हुआ है। 1950-51 में माध्यमिक स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों की संख्या क्रमशः 20,884; 52,32,009; और 21,200 थी, जबकि 1966-67 में ये संख्याएँ क्रमशः 1,08,746, 3,07,15,045 और 10,62,034 थीं। 1950-51 में माध्यमिक शिक्षा पर 30.74 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि 1966-67 में 252.15 करोड़ रुपये खर्च हुए।<sup>1</sup>

प्राप्त प्रेक्ष, जम्मू-कश्मीर, केरल, मेगलैय, तामिलनाडु और त्रिपुरा में माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह शिक्षा केवल छात्राओं के लिए निःशुल्क है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए केवल में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क है।<sup>2</sup>

1. S. N. Mukerji : Education in India, Today & Tomorrow, P.
2. Ibid., 1971-72, p. 66.
3. भारत, 1973, p. 77.



भारत-सरकार ने सन् 1961 में "केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय-प्रशासन" (Central Tibetan Schools Administration) नामक एक स्वतन्त्र संस्था की सृष्टि की। यह संस्था—तिब्बत में आने वाले शरणार्थियों के बच्चों के लिये विद्यालयों एवं अन्य प्रकार की शिक्षा-शालाओं की स्थापना एवं प्रवर्धन करती है। इस समय, यह 5 तावान विद्यालय, एक जैदिक एवं व्यावसायिक संस्था और 7 दिवस-विद्यालयों (Day Schools) का संचालन कर रही है।<sup>1</sup>

### उच्च व विश्वविद्यालय-शिक्षा Higher & University Education

भारत में माध्यमिकोत्तर (Post-Secondary) शिक्षा—कला, विज्ञान एवं व्यावसायिक कलियों, अनुसंधान-संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाती है। ऐसे राज्यों में जहाँ उच्चतर माध्यमिक एवं इण्टरमीडिएट-शिक्षा के बोर्ड हैं, वहाँ उत्तर-इण्टरमीडिएट (Post-Intermediate) शिक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा और शिष्टियाँ प्रधान करता आदि तार्यों का निर्देशन एवं नियन्त्रण विश्वविद्यालयों के हाथों में है। इस समय देश में 86 विश्वविद्यालय और 3,604 से अधिक कलियाँ हैं।<sup>2</sup>

उपयुक्त कलियों एवं विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के लिये और भी अनेक संस्थाएँ हैं; यथा :—(1) बिस्वा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, बिनासी; (2) इण्डियन एग्रो कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली; (3) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ भाइंग, बंगलौर; (4) जानिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; (5) इण्डियन स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली; (6) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार; (7) काशी विश्वपीठ, वाराणसी; (8) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद; (9) वाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, चम्बई; (10) इण्डियन स्कूल ऑफ भाइंग, धनबाद। ये संस्थाएँ 1956 के "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग अधिनियम" (University Grants Commission Act) के सन्दर्भ में विश्व-विद्यालयों के समान हैं।

"इंटर-विश्वविद्यालय-मंडल" (Inter-University Board) ने "वैज्ञानिक अनुसंधान" अध्याय में उल्लिखित अधिकांश अनुसंधान-संस्थाओं और प्रयोगशालाओं की उच्चतर अनुसंधान-केन्द्र के रूप में मान्यता दी है। 1925 में स्थापित किये जाते होते इस "मंडल" में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शिष्टियों एवं डिप्लोमाओं की मान्यता एवं अन्य समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। इस "मंडल" का मुख्य कार्य—उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देना है।

1. *Hindustan Year-Book*, 1974, p. 178.

2. भारत 1973, p. 77 & *Hindustan Year-Book*, 1974, p. 179.



### उपसंहार

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के नये ढंगों एवं क्षेत्रों का असाधारण विस्तार एक निश्चयकारी घटना है, प्रचरण की बात है। पर साथ ही यह घटना—उत्तमता में आने वाली और परमान करने वाली भी है। इस घटना के इन दोनों पक्षों का निरूपण करने हुए, संवेदन व गुप्ता ने लिखा है:—“स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से भारत में शिक्षा का अत्यन्त स्थिति गति से विस्तार हुआ है। सामान्य रूप से, इस सशक्तिकृत वृद्धि की शिक्षण के नये स्तरों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है, और इसने अध्यापकों, मातृ-सम्पदा, भवनों एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की श्रेष्ठता को निम्नतर बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा के लिए उपलब्ध धनराशि के अधिकांश भाग का प्रयोग शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार के लिए और उसकी तुलना में गुणात्मक उन्नति के उपायों की उपेक्षा करने के लिए किया गया है।”

“Education in India has expanded very rapidly since the attainment of independence. The pressure of numbers at all stages of education has, generally speaking, reacted adversely on standards of instruction and tended to lower the quality of staff, equipment, buildings and other necessary amenities. It has led to the diversion of a large proportion of the limited funds available to quantitative expansion and to the comparative neglect of measures for the improvement of quality.”—K. G. Saiyidain & H. C. Gupta : *Access to Higher Education in India*, p. 75.

टिप्पणी :—अधिक अध्ययन के लिए “विविध विषय” देखिए।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Describe briefly the opportunity of free school education in India.

भारत में निम्नलिखित शिक्षा-सम्बन्धी अवसर का संक्षेप में वर्णन लिखिए।

2. Give a short account of the activities of the Government of India in the field of secondary education.

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत-सरकार की गतिविधियों का संक्षेप वर्णन लिखिए।

3. Write short notes on :—(a) University Grants Commission, (b) Central Advisory Board of Education, and (c) National Education Policy.

अर्थपूर्ण पर संक्षेप टिप्पणियाँ लिखिए :—(अ) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग, (ब) केंद्रीय शिक्षा-सलाहकार-परिषद्, और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा-नीति।

# 22

## पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा EDUCATION UNDER FIVE-YEAR PLANS (1951-1979)

"Under the National Programme of Minimum Needs, provisions will be made for achieving the goal of universalization of elementary education." —Draft Fifth Five-Year Plan, Vol I

### विषय-प्रवेश

शतাব्दियों में स्वाधीनता की शृंखलाओं में बन्दी भारत ने 15 अगस्त, 1947 को मुक्त होकर स्वाधीनता की रावन बाण में मौम की। उस समय विगत विश्वयुद्ध, देश के विभाजन और अंग्रेजों की शासन-नीति व फलस्वरूप भारत की आर्थिक दशा इतनी असंतुलित एवं इतनी निम्न स्थिति में थी कि भारतीयों के मुक्त एवं सम्पन्नता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्वाधीनता के नरम तथ्य की सफलता—जन-जन की समृद्धि में निहित थी। श्रमिक धार्मिक अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास सभी कर सकता था, जबकि उसकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एवं राजनीतिक शक्तियाँ सुदृढ़ हो। साथ ही, उसके जीवन का स्तर भी ऊँचा हो, जिसमें यह दरिद्रता एवं बेकारी के भयकर अभिशापों से मुक्त हो सके।

यूरोपरास्त-काल में हमारे क अनेक मध्य एवं समृद्ध देशों में वैभव, सम्पन्नता, समानता एवं सब को समान सुविधाएँ प्रदान करने के निम्न विभिन्न प्रकार की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही थीं। उनके उदाहरण से उत्साहित होकर भारत ने भी अपनी समस्त बिलसी हुई शक्तियों को एहम करने और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की दिशा में अग्रसर होने का निश्चय किया। १९५१-१९५५ के





की व्यवस्था का अनुपात बराबर ही है, परन्तु विश्वविद्यालयों की शिक्षा इतनी विस्तृत है कि बुनियादी शिक्षा उस भार को उपयोगिता की दृष्टि में ठीक से सम्भाल नहीं पा रही है। उच्च शिक्षा को अनावश्यक अधिक महत्व मिलने से अनेक विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान का विकास और उपयोगिता कुठित हो गई है, और टेकनिकल तथा व्यावसायिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ न होने के कारण अनेक विद्यार्थियों को लाचार होकर माधारण शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, जिसकी न तो देश को ही इतनी जरूरत है और न ही विद्यार्थियों की उस ओर रुचि ही है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में शिक्षा-विषयक सुविधाएँ एक-भी प्राप्त नहीं हैं। इसी प्रकार, शहरों और गाँवों में भी शिक्षा की सुविधाएँ ठीक से नहीं बाँटी गई हैं, जिससे गाँव घाटे में रह गए हैं। दूसरा भारी दोष यह है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई है। शिक्षा-क्षेत्र में योग्य और अनुभवी शिक्षकों का भी बड़ा अभाव है और उनमें से अधिकांश अध्यापक ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हैं।"

### पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, 1951-56

#### Education Under First Five-Year Plan, 1951-56

"पहली पंचवर्षीय योजना" अप्रैल, 1951 में आरम्भ की गई। इस "योजना" में भारतीय शिक्षा-प्रणाली को दोष-मुक्त करने और उसे जनतन्त्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए सक्रिय पग उठाए गए। हम इस "योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना के प्रमुख अंगों का वर्णन नीचे कर रहे हैं, यथा —

#### 1 शिक्षा पर व्यय

#### Expenditure on Education

"पहली पंचवर्षीय योजना" में शिक्षा के विकास के लिए 1 अरब 69 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई थी। इनमें से शिक्षा के विविध क्षेत्रों पर व्यय का, जो विभाजन किया गया था, वह निम्न प्रकार है<sup>1</sup> —

शिक्षा के स्तर	व्यय (करोड़ रुपये में)
1. प्राथमिक शिक्षा	93
2. माध्यमिक शिक्षा	22
3. विश्वविद्यालय-शिक्षा	15
4. प्रौद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा	23
5. समाज-शिक्षा	5
6. प्रशिक्षण व विविध	11
<b>योग</b>	<b>169</b>

## 2. शिक्षा-योजना के उद्देश्य

### Aims of Scheme of Education

"पहली पंचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना के अधोलिखित उद्देश्य थे :—

1. शिक्षा-प्रणाली के विभिन्न अंगों का पुनर्गठन करना ।
2. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित करना ।
3. वैज्ञानिक एवं प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना ।
4. माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय-शिक्षा का पुनर्गठन करना ।
5. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना ।
6. स्त्री-शिक्षा का प्रसार करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन देना ।
7. समाज-शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयास करना ।
8. अध्यापक-प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करना ।
9. वैज्ञानिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना ।
10. शिक्षकों के वेतन और कार्य एवं सेवा की दशाओं में सुधार करना ।
11. शिक्षा में पिछड़े हुए राज्यों को उदार आर्थिक सहायता देकर उनकी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रोत्साहित करना ।

## 3. शिक्षा-योजना का कार्यक्रम

### Programme of Scheme of Education

"पहली पंचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना के कार्यक्रम में जिन बातों को स्थान दिया गया, उनका वर्णन नीचे किया जा रहा है; यथा :—

1. 6-11 वय-वर्ग के 60% बालकों को शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करना ।
2. 6-11 वय-वर्ग की 40% बालिकाओं को शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करना ।
3. 11-14 वय-वर्ग के कुछ बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करना ।
4. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों एवं बालिकाओं को संख्या की दृष्टि से 15 और 10 प्रतिशत पर पहुँचाना ।
5. समाज-शिक्षा के क्षेत्र में 14 से 40 वर्ष की आयु तक के पुरुषों एवं स्त्रियों की व्यावसायिक तथ्यों की शिक्षा देना ।
6. उक्त पुरुषों एवं स्त्रियों के अनुपात की दृष्टि से 20 और 10 प्रतिशत करना ।

7. बच्चों, शिक्षकों एवं ब्यस्कों के लिए उपयुक्त साहित्य का उत्पादन करना ।
8. निम्न और उच्च स्तरों पर छात्रों के लिए प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना ।
9. विश्वविद्यालय-शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना ।
10. स्नातकोत्तर-शिक्षा एवं अनुसंधान-कार्य में सभी सम्भव विधियों से उत्प्रेरित करना ।

#### 4. शिक्षा-योजना की उपलब्धियाँ

##### Achievements of Scheme of Education

“पहली पञ्चवर्षीय योजना” के अन्तर्गत शिक्षा-योजना की मुख्य उपलब्धियाँ इस प्रकार थी :—

1. बेसिक एवं प्राथमिक शिक्षा—बेसिक शिक्षा-प्रणाली का विकास; ग्रामों एवं नगरों में बेसिक स्कूलों की स्थापना; प्रचलित प्राथमिक विद्यालयों में सुधार; प्राथमिक स्कूलों का बेसिक स्कूलों में परिवर्तन, और बेसिक एवं प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

2. माध्यमिक शिक्षा—“माध्यमिक शिक्षा-आयोग” की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने का प्रयास; बहु-उद्देशीय (Multipurpose) स्कूलों की स्थापना; पुराने माध्यमिक स्कूलों का सुधार; और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों, कृषि-शिक्षा आदि का समावेश ।

3. विश्वविद्यालय-शिक्षा—विश्वविद्यालय-शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास; विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को आधिक गृहायता, और अनुसंधान-कार्य के लिए विद्यालयों को छात्रवृत्तियाँ ।

4. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा—इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना; प्राविधिक एवं व्यावसायिक स्कूलों की सृष्टि, जिनमें बहुउद्देशीय स्कूलों का निर्माण; औद्योगिक स्कूलों का गिलाखाम, और विशेष व्यावसायिक विषयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

5. सामाजिक-शिक्षा—बयस्क-साक्षरता का विस्तार, जनता कॉलेजों की स्थापना; बयस्कों के लिए नागरिकता, स्वास्थ्य-रक्षा एवं समय के सदुपयोग की शिक्षा की व्यवस्था; बयस्कों के लिए साहित्य का निर्माण, और बयस्कों के लिए पुस्तकालयों की स्थापना ।

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा-योजना की उपलब्धियों को नीचे तालिका में प्रदर्शित कर रहे हैं :—

विवरण	योजना से पूर्व 1950-51	पहली योजना 1955-56
(क) विभिन्न वय वर्गों के बच्चे		
1. 6-11 वय-वर्गों का प्रतिशत	42.6	52.8
2. 11-14 " " "	12.7	16.5
3. 14-17 " " "	5.3	7.4
4. 17-23 " " "	0.8	1.4
(ग) संस्थाओं की संख्या		
1. प्राथमिक स्कूल	2,09,671	2,78,135
2. मिडिल स्कूल	13,569	21,730
3. हाई/हायर मेट्रिकरी स्कूल	7,288	10,838
4. बहुवर्षीय विद्यालय	—	255
5. प्रविधान-विद्यालय	782	939
6. प्रविधान-कनिष्ठ	53	107
7. कनिष्ठ	542	772
8. विद्याविद्यालय	27	32
(घ) प्रतिशत अध्यापक प्रतिशत		
1. प्राथमिक स्कूल	58.8	61.2
2. मिडिल स्कूल	53.3	58.5
3. हाई/हायर मेट्रिकरी स्कूल	53.8	59.7

### दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, 1956-61

Education Under Second Five-Year Plan, 1956-61

पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ और अन्त की तिथियाँ राष्ट्र के प्रतिज्ञान में महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। इसी पंचवर्षीय योजना का अन्त मानें, 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना का आरम्भ करेंगे, 1956 में दूसरी शिक्षा के महत्त्व का उल्लेख करते हुए, "दूसरी पंचवर्षीय योजना" में कहा गया—“आधिक प्रगति जिस तेज़ी से की जा सकती है और उसमें जो खर्च उठाया जा सके है, उसको निश्चित करने में शिक्षा-व्यय का विशेष महत्त्व होता है। आधिक विकास सम्भावित मानव-साधन को अधिक-हीन-अधिक मात्रा में देना है और जनसंख्या में यह ऐसे मूल्यों की अभिवृद्धि को मांग करता है, जिसका निर्माण करने में शिक्षा का गुण आवश्यक तत्त्व है।”

"The system of education has a determining influence on the rate at which economic progress is achieved and the benefits which can be derived from it. Economic development naturally makes growing demands on human resources and in a democratic set-up, it calls for values and attitudes in the building of which the quality of education is an important element."—*Second Five-Year Plan*.

हम "दूसरी पचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना के मुख्य अंगों का विवरण उपस्थित कर रहे हैं; यथा :—

### 1. शिक्षा पर व्यय

#### Expenditure on Education

"दूसरी योजना" में शिक्षा के विकास के लिए 3 अरब 7 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी, जबकि "पहली योजना" में यह धनराशि 1 अरब 69 करोड़ रुपये की थी। पहली और दूसरी योजना में शिक्षा के विविध क्षेत्रों पर व्यय का जो विभाजन किया गया था, वह निम्न प्रकार है<sup>1</sup> :—

शिक्षा के स्तर	व्यय (करोड़ रुपये में)	
	पहली योजना 1951-56	दूसरी योजना 1956-61
1. प्राथमिक शिक्षा	93	89
2. माध्यमिक शिक्षा	22	51
3. विश्वविद्यालय-शिक्षा	15	57
4. प्रौद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा	23	48
5. समाज-शिक्षा	5	5
6. प्रकाशन व विविध	11	57
योग	169	307

### 2 शिक्षा-योजना के उद्देश्य

#### Aims of Scheme of Education

"पहली पचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना का मुख्य उद्देश्य— शिक्षा-प्रणाली को दोषमुक्त करके उसे जनतन्त्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना

1. दूसरी पचवर्षीय योजना, p. 468.

या । किन्तु, इन कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त न हो सकी । इसके कारण थे—इस योजना की भुट्टियाँ । इनकी ओर नज़र करते हुए और इनकी स्वीकार करते हुए श्री देशमुख ने आलोकित भाषा में कहा था :—“तत्स्योर में कुछ घबरे हैं और घबरे का होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि तत्स्योर बहुत बड़ी बन रही है ।”

“तत्स्योर” थी—शिक्षा की योजना और “घबरे” थे—उसके दोष । योजना वास्तव में बहुत बड़ी थी और इसलिए उसमें दोषों का समावेश हो जाना स्वाभाविक बात थी । ये दोनो चीज़ें न केवल योजना-निर्माताओं के अदम्य उत्साह की, अपितु उनकी अनुभवहीनता की भी परिचायक हैं । यदि जिसने उत्साह से योजना का निर्माण किया गया था, उसने ही उत्साह से उसका कार्यान्वयन किया गया होता, तो सम्भवतः अनुभवहीनता के कारण उसमें प्रविष्ट होने वाले दोषों का निवारण हो जाता । पर समय की गतिविधियों और परिस्थितियों की परीक्षाओं ने उन दोषों का उन्मूलन नहीं होने दिया, जिनके फलस्वरूप योजना के आधारभूत उद्देश्य की प्राप्ति असम्भव हो गई । किन्तु, इससे हतोत्साहित न होकर, और अपने पिछले अनुभव से पथ-प्रदर्शित होकर योजना-निर्माताओं ने शिक्षा की दूसरी योजना तैयार की और उसके निर्मातृ उद्देश्य निर्धारित किए :—

1. वैयक्त एवं प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं प्रसार करना ।
2. प्राथमिक शिक्षा के सम्पूर्ण होने का बुनियादी ढाँचा पर आधुनिकीकरण करना ।
3. माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को लागू करके उसके साम्य में परिधर्मेन करना ।
4. राज्यों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा-स्तरो में सुधार एवं उन्नति करना ।
5. विश्वविद्यालय-शिक्षा को बहुमुखी बनाना ।
6. प्राथमिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में नवीन पाठ्यक्रमों को लागू करना और उसी सुविधाओं में विस्तार करना ।
7. उच्च-शिक्षा का विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप प्रदान करना ।
8. शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना ।

### 3. शिक्षा-योजना का कार्यक्रम

#### Programme of Scheme of Education

“दूसरी भारतीय योजना” के अन्तर्गत शिक्षा-योजना का अगोपित्व कार्यक्रम निम्नलिखित किया गया :—

1. वैयक्त शिक्षा का विस्तार करना ।
2. प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना ।

3. प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना ।
4. प्राथमिक विद्यालयों का बेसिक विद्यालयों में परिवर्तन करना ।
5. प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान करना ।
6. "माध्यमिक शिक्षा-आयोग" की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना ।
7. समाज-शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर विस्तार करना ।
8. टेक्निकल कर्मचारियों की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करना ।
9. विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की शिक्षा के स्तरों को ऊँचा उठाना ।
10. "विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग" की सिफारिश के अनुसार उच्चतर ग्राम-शिक्षा की व्यवस्था करना ।

#### 4. शिक्षा-योजना की उपलब्धियाँ

##### Achievements of the Scheme of Education

“दूसरी पंचवर्षीय योजना” के अन्तर्गत शिक्षा-योजना की मुख्य उपलब्धियाँ इस प्रकार थीं :—

1. बेसिक शिक्षा—बेसिक शिक्षा के उत्पादन पक्ष पर चल; कक्षा 8 तक के सम्पूर्ण बेसिक विद्यालयों की स्थापना, अध्यापकों के लिए पूर्णकालीन प्रशिक्षण एवं अभिनवन पाठ्यक्रमों (Refresher Courses) की व्यवस्था; बेसिक विद्यालयों के लिए साहित्य का निर्माण, और “राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा-परिषद्” (National Council of Basic Education) का गठन ।

2. प्राथमिक शिक्षा—शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार, पारी पद्धति (Shift System) का प्रचलन, स्थानीय निकायों को “शिक्षा-कर” (Education Cess) लगाने का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा-पद्धति का बेसिक शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन; अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति एवं शिक्षण-विधियों में सुधार; और बालिका-शिक्षा का विस्तार एवं अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति ।

3. माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन करने के प्रयास; बहुउद्देशीय एवं जूनियर टेक्निकल स्कूलों की स्थापना, हाई स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तन; माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं की मर्यादा में वृद्धि; शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था; और ग्रामीण माध्यमिक स्कूलों में कृषि-शिक्षा की व्यवस्था ।

4. विश्वविद्यालय-शिक्षा—विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की शिक्षा के स्तरों को ऊँचा उठाने का प्रयास; अपव्यय एवं अवरोधन को कम करने का प्रयत्न, त्रि-वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम का मूलपाठ, और भवनो, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं में सुधार ।

2 | भाग्योदय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

5. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा—पहली योजना की अवधि में स्थापित की जाने वाली शिक्षा-संस्थाओं का विवरण; प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं में विस्तार; उच्चतर तकनीक एवं डिप्लोमा-स्तर की संस्थाओं की स्थापना; स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, और इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलॉजी में अनुसंधान की व्यवस्था।

6. समाज-शिक्षा—साक्षरता के प्रविजन में वृद्धि; साक्षरता एवं समाज-केंद्रों की स्थापना, समाज-शिक्षा-कर्मियों एवं संगठनकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, और पुनर्वासियों एवं महिला-प्रवासियों की व्यवस्था।

7. उच्चतर ग्राम-शिक्षा—उच्चतर ग्राम-संस्थाओं की स्थापना; और इन संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था।

“दूसरी पंचवर्षीय योजना” के अन्तर्गत शिक्षा-योजना की उपलब्धियों की नीचे दी जाति है में स्पष्ट किया गया है :—

विवरण	योजना में पूर्व 1950-51	पहली योजना 1955-56	दूसरी योजना 1960-61
(क) विभिन्न चयन-क्रम के चयन			
1. 6—11 आयु-वर्ग का प्रविजन	42.6	52.8	62.4
2. 11—14 " " "	12.7	16.5	22.5
3. 14—17 " " "	5.3	7.4	10.6
4. 17—23 " " "	0.8	1.4	1.8
(ख) संस्थाओं की संख्या			
1. प्राथमिक स्कूल	2,09,671	2,78,135	2,30,399
2. माध्यमिक स्कूल	13,596	21,730	49,663
3. उच्च-माध्यमिक स्कूल	7,288	10,838	17,257
4. बहु-स्तरीय विद्यालय	—	255	2,115
5. प्राथमिक-विद्यालय	782	939	1,138
6. प्राथमिक-विद्यालय	53	107	478
7. प्रविजन-विद्यालय	542	772	1,122
8. विद्यालय	27	32	4
(ग) प्रशिक्षित अध्यापक			
1. प्राथमिक स्कूल	53.8	61.2	64
2. माध्यमिक स्कूल	53.3	58.5	60
3. उच्च-माध्यमिक स्कूल	53.8	59.7	60



## तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, 1961-66

### Education Under Third Five-Year Plan, 1961-66

"पहली पंचवर्षीय योजना" आरम्भ होने के बाद से शिक्षा की गुविषाओं में सभी स्तरों पर प्रगतिशील विस्तार हुआ। किन्तु, जब दृष्टि इस समस्या की विशालता, देश की जन-शक्ति का विकास करने और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की आवश्यकता पर गई, जिनमें सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें, तब शिक्षा के विकास की प्रगति को और भी तीव्र करने का निश्चय किया गया। इस निश्चय को क्रियान्वित करने के लिए "तीसरी पंचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा के विषे एक योजना तैयार की गई। हम इस योजना के प्रमुख पक्षों का दिग्दर्शन करा रहे हैं; यथा :—

### 1. शिक्षा पर ध्यय

#### Expenditure on Education

पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में शिक्षा के विविध अंगों पर व्यय का विभाजन नीचे की तालिका में स्पष्ट किया गया है<sup>1</sup> :—

शिक्षा के स्तर	ध्यय (कराड रुपया में)		
	पहली योजना 1951-56	दूसरी योजना 1956-61	तीसरी योजना 1961-66
1. प्रारम्भिक शिक्षा	85	87	209
2. माध्यमिक शिक्षा	20	48	88
3. विश्वविद्यालय शिक्षा	14	45	82
4. अन्य कार्यक्रम—			
समाज शिक्षा	—	4	6
शारीरिक शिक्षा व	14		
युवक कल्याण	—	10	12
अन्य	—	10	11
5. योग	133	204	408
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम	0	4	10
7. कुल योग	133	208	418

● पहली योजना में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर होने वाला ध्यय अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया था।

### 2. शिक्षा-योजना के उद्देश्य

#### Aims of Scheme of Education

"तीसरी पंचवर्षीय योजना" में शिक्षा-योजना के एक मुख्य उद्देश्य को इन

नदरों में अंकित किया गया — "तीसरी योजना का एक मुख्य उद्देश्य—शिक्षा-सम्बन्धी प्रयास को विस्तृत एवं तीव्र बनाना और प्रत्येक परिवार को इसकी सीमा के अन्तर्गत लाना है, ताकि इस समय के बाद राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों में शिक्षा—नियोजित विज्ञान का केन्द्र-बिन्दु बन जाय।"

"One of the major aims of the Third Plan is to expand and intensify the educational effort and to bring every home within its fold so that, from now on, in branches of national life, education becomes the focal point of planned development."—*Third Five-Year Plan.*

उपर्युक्त के अनुरिक्त, शिक्षा-योजना के अन्य उद्देश्य इस प्रकार थे :—

1. 6 से 11 बय-वय के सब बालकों एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना।
2. प्राथमिक एवं निम्नविद्यालय-स्तरों पर विज्ञान की शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना।
3. प्राथमिक, प्रोद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का देश की आवश्यकताओं के अनुसार प्रसार करना।
4. नयी बर्गों के शिक्षकों की अधिक वेतन देने की समुचित व्यवस्था करना।

### 3. शिक्षा-योजना का कार्यक्रम

#### Programme of Scheme of Education

"तीसरी पंच-वर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना का कार्यक्रम इस प्रकार था :—

1. प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों की वैकल्पिक विद्यालयों में परिवर्तित करना।
3. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना।
4. प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना।
5. प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना।
6. नवीन उपचार प्राथमिक स्तरों और प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना करना।
7. निम्नविद्यालय स्तर पर विज्ञान-शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि करना।
8. निम्नविद्यालय शिक्षा के स्तर की जाँच उठाना।
9. प्राथमिक, प्राथमिक-व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का अन्वेषण करना।

10. यसक-साधरता एव ममात्र-शिक्षा के प्रसार के लिए व्यापक कार्यक्रमों को प्रियान्वित करना ।

#### 4. शिक्षा-योजना की उपलब्धियाँ

##### Achievements of the Scheme of Education

"तीसरी पंचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित थी :—

1. वैज्ञानिक शिक्षा—वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली का विस्तार; अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था; नवीन प्रशिक्षण-मन्त्रालयों में वैज्ञानिक विधि का कार्यान्वयन; और वर्तमान प्रशिक्षण-विद्यालयों की क्षमता में वृद्धि ।

2. प्राथमिक शिक्षा—शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार; अध्यापकों में कमी; बालिकाओं को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहन; अध्यापिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था; संक्षिप्त पाठ्यक्रमों (Condensed Courses) का आयोजन; और प्राथमिक विद्यालयों का वैज्ञानिक विद्यालयों में परिवर्तन ।

3. माध्यमिक शिक्षा—छात्रों एवं छात्राओं की संख्या में वृद्धि; विज्ञान-शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि, विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, बहुदृष्टीय विद्यालयों में सुधार; माध्यमिक स्तरों का उच्चतर माध्यमिक स्तरों में परिवर्तन; और शिक्षा-सम्बन्धी अनुसंधान पर बल ।

4. विश्वविद्यालय शिक्षा—नवीन कनिष्ठों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना; विज्ञान की शिक्षा का विस्तार, प्रयोगशालाओं की सुविधाओं में वृद्धि, शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि; पुस्तकालयों का सुधार, और स्नातकोत्तर-शिक्षा एवं अनुसंधान-कार्य के लिए अधिक धन की व्यवस्था ।

5. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा—प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार, नवीन शिक्षा-मन्त्रालयों की स्थापना, अन्तरराष्ट्रीय एवं पत्राचार-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, और विभिन्न व्यवसायों के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण ।

6. समाज-शिक्षा—साक्षरता के प्रतिष्ठित में वृद्धि, सामुदायिक केंद्रों का विकास; ग्रामों में वाचनालयों का निर्माण, और ग्राम-न्यायतों एवं सहकारी आन्दोलन की सुदृढ़ता ।

"तीसरी पंचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना की उपलब्धियों को प्रकाशित तालिका में प्रदर्शित किया गया है। —



इस दौरान में चौथी योजना के मसविदे को ध्यान में रखते हुए तीन वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं। इनमें तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखा गया। इस अवधि में अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी से विकास परिव्यय कम रहा। तीनों वार्षिक योजनाओं में शिक्षा पर 322.4 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

### चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, 1969-74

#### Education Under Fourth Five-Year Plan, 1969-74

“चौथी पंचवर्षीय योजना” का कार्यकाल अप्रैल, 1969 से मार्च, 1974 तक था। इस “योजना” में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-सेवाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिये जाने का कारण “योजना” में इस प्रकार अंकित किया गया<sup>1</sup> :—“यह सच है कि पिछली तीन योजनाओं के दौरान में भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन बहुत अधिक बढ़ा है। फिर भी, सख्या के बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा-स्तर गिर गया है। भारतीय शिक्षा-वृद्धि विकास के अनुकूल नहीं हो सकी है, विशेषकर प्राथमिक व उच्चतर शिक्षा का स्तर पर्याप्त उन्नत नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा व कृषि-शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। सड़कियों की शिक्षा आज भी लड़कों के मरुवाले बहुत पिछड़ी हुई है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन में स्थिरता आ गई है और कुछ छोड़कर चले जाते हैं। विश्वविद्यालय-स्तर पर काफी बच्चे असफल हो जाते हैं और तीसरी श्रेणी में पास होते हैं।”

“चौथी पंचवर्षीय योजना” में शिक्षा के उपर्युक्त दोषों को दूर करने और उसे देश के आर्थिक विकास के अनुकूल बनाने के लिए, शिक्षा की योजना तैयार की गई। हम इस योजना के प्रमुख अंगों का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं, यथा :—

### 1. शिक्षा पर व्यय

#### Expenditure on Education

“चौथी पंचवर्षीय योजना” में शिक्षा-सम्बन्धी गुविषाओं का विस्तार करने के लिए 1210 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। पहली तीन योजनाओं में शिक्षा पर कुल जितना धन व्यय किया गया, “चौथी योजना” में उससे 20 प्रतिशत अधिक धन की व्यवस्था की गई। प्रस्तावित व्यवस्था का वितरण नीचे दिया जा रहा है<sup>2</sup> :—

1. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), p. 221.

2. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), p. 231.

विवरण	व्यय (करोड़ रुपये में)
1. प्राथमिक शिक्षा	322
2. माध्यमिक शिक्षा	243
3. विश्वविद्यालय-शिक्षा	175
4. प्रव्याप्त-शिक्षा	92
5. प्राविधिक शिक्षा	253
6. नवोदय-शिक्षा	64
7. मानकृत कार्यक्रम	15
8. विविध (सामान्य शिक्षा)	46
योग	1, 210

## 2. शिक्षा-योजना के उद्देश्य

### Aims of Scheme of Education

"चौथी पंचवर्षीय योजना" के अंतर्गत शिक्षा-योजना के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए :—

1. शिक्षा के स्तर, अवधि, गुणवत्ता एवं विविधता पर विशेष ध्यान देना ।
2. 1975-76 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सब बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा से सुविधाएँ प्रदान करना ।
3. देश के सब बालकों एवं बालिकाओं के लिए 8 वर्ष की अनिवार्य एवं माध्यमिक शिक्षा को प्रत्यक्ष करना ।
4. अनिवार्य एवं माध्यमिक शिक्षा को जन-शिक्षा का आधार बनाना ।
5. प्रत्येक नागरिक को 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक होना और उसे यह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना ।
6. 14 वर्ष की आयु के उपरान्त नागरिकों को जीवन के विभिन्न तहों के लिए प्रशिक्षण देना ।
7. शिक्षा के प्रत्येक स्तर के पर्याप्त व्यक्तियों के लिए कुछ संस्थानों के द्वारे योजना ।

## 3. शिक्षा-योजना का कार्यक्रम

### Programme of Scheme of Education

"चौथी पंचवर्षीय योजना" के अंतर्गत शिक्षा-योजना के कार्यक्रम में प्रमुख निर्दिष्ट बातें को स्पष्ट किया गया :—

1. शिक्षा-सूचकांकों को पर्याप्त ध्यान से देना ।

2. शिक्षा-वृद्धि का आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार करना ।
3. शिक्षा-वृद्धि का आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बढ़ती हुई माँगों से प्रभावशाली सम्बन्ध स्थापित करना ।
4. पहली तीन योजनाओं में तीव्र प्रसार के फलस्वरूप शिक्षा-वृद्धि पर पड़ने वाले आन्तरिक दबावों को हटाना ।
5. शिक्षा के सब स्तरों में सुधार करना और उनमें होने वाले अपभ्यय को रोकना ।
6. प्राथमिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की उच्च प्राथमिकता देना ।
7. प्राथमिक स्तर पर अप्रतिष्ठित बातों पर विशेष बल देना :—सर्वत्र निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था; सर्वत्र शिक्षा के स्वरूप में समानता; अपभ्यय की समाप्ति; और पाठ्यक्रम में सुधार ।
8. माध्यमिक स्तर पर अप्रतिष्ठित बातों की ओर विशेष ध्यान देना :— शिक्षा के स्तर में सुधार; व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, विज्ञान की शिक्षा का विस्तार; विविध पाठ्यक्रमों का आयोजन; उच्च माध्यमिक स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तन; और बहुद्देशीय विद्यालयों की गृह्यता ।
9. विश्वविद्यालय-स्तर पर आगे लियी बातों पर जोर देना :—शिक्षा का पुनर्गठन; शिक्षा के स्तर का उन्नयन; कला एवं वाणिज्य के छात्रों में कमी; कृषि, विज्ञान, प्राथमिक एवं चिकित्सा-शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार, विज्ञान-शिक्षा, स्नातकोत्तर-शिक्षा एवं अनुसंधान-कार्य के लिए विशेष सुविधाएँ, पत्राचार-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था; और निम्न श्रेणी के कॉलेजों और नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना पर प्रतिबन्ध ।
10. शिक्षण-स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की अधिक उत्तम व्यवस्था करना और उनकी योग्यताओं एवं वेतनों में वृद्धि करना ।
11. शिक्षण-विधियों एवं पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अनुसंधान-कार्यों को और अधिक संपन्न बनाना ।
12. व्यवस्क-शिक्षा के विस्तार एवं आर्थिक विकास के माध्यम के रूप में साक्षरता पर बल देना ।
13. विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन को और अधिक प्रोत्साहन देना ।
14. अनुसूचित एवं आदिम जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना ।

15. शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाने की दृष्टि से ग्रहण-छात्र-वृत्तियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना।
16. हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों की प्राविधिक, व्यावसायिक एवं नौकरी-पेशा-सम्बन्धी विषयों की ओर मोड़ना।
17. कम व्यय करके शिक्षण-विधियों में सुधार करने के लिए अप्रॉफिट बातों पर बल देना :—बड़ी शिक्षा-संस्थाओं को प्रोत्साहन; अल्पकालीन पाठ्यक्रमों एवं पत्राचार-पाठ्यक्रमों की सुविधाओं में विस्तार करना; और भवनों, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं का अधिक समय तक प्रयोग।
18. अप्रॉफिट कार्यों के लिए स्थानीय साधन जुटाना :—विद्यालय एवं मनुष्य में निकट सम्बन्ध की स्थापना; विद्यालयों के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का प्रयत्न, विद्यालयों के लिए इमारतों का निर्माण; और विद्यालयों में सुधार करने के लिए कार्यक्रमों का विकास।

#### 4. शिक्षा-योजना की उपलब्धियाँ

##### Achievements of the Scheme of Education

"औद्योगिक पंचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ इस प्रकार थीं<sup>1</sup> :—

1. प्राथमिक शिक्षा—शिक्षा की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार; निर्धारित संख्या में छात्रों की शिक्षा की सुविधाएँ देने के लक्ष्य की अप्राप्ति; शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक सुधार-योजनाओं का कार्यान्वयन, और राज्य-सरकारों द्वारा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अपेक्षित एवं अवरोधन को रोकने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन।

2. माध्यमिक शिक्षा—शिक्षा की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार; निर्धारित संख्या में छात्रों की शिक्षा की सुविधाएँ देने के लक्ष्य की अप्राप्ति, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा-प्रणाली में सुधार, और राजस्व-स्रोतों की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन।

3. विश्वविद्यालय-शिक्षा—शिक्षा की सुविधाओं में आज से अधिक विस्तार, निर्धारित संख्या में अधिक छात्रों द्वारा शिक्षा की प्राप्ति, औद्योगिक भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सच्यों की जायित महामता; उच्च अध्ययन-केन्द्रों की स्थापना; स्नातकोत्तर-शिक्षा एवं अनुसन्धान-कार्य की उन्नति एवं विस्तार; और कविजों को अपनी शिक्षा में सुधार करने के लिए जायित महामता।

4. विज्ञान की शिक्षा—विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा की उन्नति, विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने की सुविधाओं में वृद्धि, विज्ञान के शिक्षकों के प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था, और नव प्राविद्य-संस्थाओं एवं कुछ चुने हुए स्कूलों की उपकरण प्रदान करके, विज्ञान की शिक्षा में उन्नति करने का प्रयास।



5. अन्य उपलब्धियाँ—कृषकों को शिक्षा की सुविधाएँ, 100 जिलों में साक्षरता का प्रसार; बालकों की मृत्यु के अनुपात में बालिकाओं की मृत्यु में कम वृद्धि, राष्ट्रीयकरण की जाने वाली पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए तीन मुद्रणालयों की स्थापना, अहिन्दी क्षेत्रों में उच्चतर प्राथमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आर्थिक सहायता, और शिक्षा का समुदाय से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एवं युवकों की राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देने के लिए 100 "नेहरू युवक-केन्द्रों" की स्थापना।

"चौथी पंचवर्षीय योजना" के अन्तर्गत शिक्षा-योजना की वास्तविक उपलब्धियों का अभी तक प्रकाशन नहीं किया गया है। "भारत", 1973 (p. 76) में उनका जो विवरण दिया गया है, उनको पृष्ठ 302 पर तालिका में स्थान दिया गया है।

### पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-1979

#### Fifth Five-Year Plan, 1974-1979

"पाँचवीं पंचवर्षीय योजना"। अग्रेज, 1974 में प्रियान्वित की गई है। इसमें शिक्षा के सभी खण्डों के सम्बन्ध में नीतियाँ निर्धारित की गई हैं, जिनमें से उत्तेजनयोग्य हैं :—भाषा का विकास, पुस्तकों का उत्पादन, कला एवं संस्कृति, शिक्षा एवं रोजगार, और युवकों में सम्बन्धित कार्यक्रम एवं समस्याएँ। "योजना" के अन्तर्गत जिस शिक्षा-योजना में इन नीतियों को लेखबद्ध किया गया है, हम उसके मुख्य खण्डों का वर्णन आपसे अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं; यथा :—

#### 1 शिक्षा पर व्यय

#### Expenditure on Education

'पाँचवीं पंचवर्षीय योजना' में शिक्षा पर 1976 तक क्या व्यय करने की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित व्यय-व्यवस्था इस प्रकार है<sup>1</sup> :—

विवरण	व्यय (करोड़ रुपये में)
1. प्राथमिक शिक्षा	743
2. माध्यमिक शिक्षा	241
3. विश्वविद्यालय-शिक्षा	337
4. समाज-शिक्षा	35
5. सांस्कृतिक कार्यक्रम	35
6. अन्य मौखिक कार्यक्रम	171
सामान्य शिक्षा पर कुल व्यय	1 562
7. प्राथमिक शिक्षा	164
शिक्षा पर कुल व्यय	1,726

बोपी गोजन  
1973-74 (अद्य)

विवरण	सौराष्ट्र क्षेत्र 1950-51	पच्छी संरक्षण 1955-56	दक्षिणी संरक्षण 1960-61	तीसरी संरक्षण 1965-66	1970-71 (अवधारणा)	चौथी संरक्षण 1973-74 (अवधारणा)
(क) विभिन्न प्रयत्नों के फल						
1. 6-11 वर्षीयों का प्रतिशत	42.6	52.8	62.4	76.7	80.3	85.3
2. 11-14 " " " "	12.7	16.5	22.5	30.8	34.1	41.3
3. 14-17 " " " "	5.3	7.4	10.6	16.2	24.4	24.0
4. 17-25 " " " "	0.8	1.4	1.8	2.7	3.7	3.8
(ख) संरक्षण की रकम						
1. प्राथमिकी रकम	2,09,671	2,78,135	2,30,399	3,91,064	4,04,418	4,04,418
2. निहित रकम	13,596	21,730	49,663	75,798	88,587	88,587
3. एड/एडमर तकस्ट्री रकम	7,288	10,838	17,257	27,477	35,773	35,773
4. एड/एडमर विद्यालय	—	255	2,115	2,386	2,625	2,625
5. निवास-विकास	782	939	1,138	1,272	843	843
6. प्रशिक्षण-विकास	53	32	478	1,785	2,792	2,792
7. पत्रिका	542	107	1,122	64	86	86
8. विमर्श-विद्यालय	27	32	45	64	64	64
(ग) प्रतिशत अत्याधिक प्रतिशत	58.8	61.2	64.1	70.5	82.8	82.8
(घ) प्रतिशत रकम	53.3	58.5	66.5	76.9	83.0	83.0
1. प्राथमिकी रकम	53.8	59.7	64.1	68.5	79.6	79.6
2. निहित रकम	—	—	—	—	—	—
3. एड/एडमर तकस्ट्री रकम	—	—	—	—	—	—

## 2. शिक्षा-योजना के उद्देश्य Aims of Scheme of Education

पिछले दो दशकों में नियोजित विकास के फलस्वरूप शिक्षा का अत्यधिक विकास हुआ है। कुछ बातों में हमका विकास उचित दिशा में हुआ है। फिर भी, प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में अनेक कमियाँ हैं, जिनमें से कुछ हमारी अतीत में विकास के रूप में मिली हैं। 'पाँचवीं पंचवर्षीय योजना' में शिक्षा की संरचना (Structure) में परिवर्तन करके, इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जायगा। "पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अनुसार :—“पाँचवीं योजना में मानव एवं आर्थिक साधनों के बचनों की सीमाओं में शिक्षा की संरचना में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास किया जायगा।”

“The Fifth Plan seeks to introduce certain essential changes in the educational structure within the constraints of human and financial resources.”—*Draft Fifth Five-Year Plan, Vol. II, p. 192.*

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रख कर “पाँचवीं पंचवर्षीय योजना” के अन्तर्गत शिक्षा-योजना के निम्नांकित 4 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :—

1. सामाजिक न्याय का विकास करने के लिए शिक्षा के अवसरों में समानता स्थापित करना।
2. शिक्षा का विकास की आवश्यकताओं एवं गैरकारियों में सम्बन्ध स्थापित करना।
3. शिक्षा-संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करना।
4. शिक्षा का सामाजिक वातावरण अर्थात् अधिक एवं सामाजिक विकास के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करना।

## 3. शिक्षा-योजना का कार्यक्रम Programme of Scheme of Education

उपरिर्लखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ‘पाँचवीं पंचवर्षीय योजना’ के अन्तर्गत शिक्षा-योजना के कार्यक्रम में निम्नांकित बातों का ध्यान दिया गया है<sup>1</sup> :—

1. अवसर की समानता : Equality of Opportunity — सामाजिक न्याय या विकास करने के लिए शिक्षा के अवसरों में समानता की स्थापना की जायगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंशित कार्य किए जायेंगे — (1) प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा पर अधिक धन, (2) पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, (3) जनजातियों के बच्चों के लिए सामान्य आश्रम-

विद्यालयों (Residential Ashram Schools) की स्थापना; (4) ग्रामीण क्षेत्रों में नवम् में की गयी योजनाओं के विद्यालयों में सुधार; और (5) जीवन में समय से अपने प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को उन्नति करने में सहायता देने के लिए अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education) की व्यवस्था।

2. रोजगार एवं विकास से सम्बन्ध : Linkage with Employment & Development—शिक्षा का रोजगारों एवं विकास की आवश्यकताओं से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अर्धनियमित उपायों का प्रयोग किया जायता :—(1) पाठ्यक्रम में सुधार; (2) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण; (3) उपयुक्त निदेशन-विधियों का प्रयोग करते, छात्रों में उचित दृष्टिकोणों का विकास; (4) विषय-विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों का समावेश; और (5) व्यावसायिक शिक्षा एवं जनबल (Manpower) में उचित सम्बन्ध की स्थापना।

3. शिक्षा की गुणात्मक उन्नति : Quality Improvement of Education—शिक्षा-संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने के लिए आगे किंग कदम उठाए जायेंगे :—(1) पाठ्यक्रम एवं परीक्षा-प्रणाली में सुधार; (2) शिक्षण की प्रणालियों एवं सीखने की विधियों में सुधार; (3) शिक्षण-प्रशिक्षण में सुधार; (4) पाठ्य-पुस्तकों का समुदाय; (5) अनुसंधान-कार्य की समुन्नति; (6) उच्च प्रशिक्षण-केन्द्रों को अधिक गतिशील बनाने का प्रयास; और (7) प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों का आयोजन।

4. सामाजिक वातावरण में सम्बन्ध : Linkage with Social Environment—शिक्षा का सामाजिक वातावरण में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अग्रगामी विधियाँ अपनाई जायेंगी :—(1) नव स्तरों के पाठ्यक्रमों में सामाजिक-सेवा का अनिवार्य समावेश; (2) नव स्तरों के पाठ्यक्रमों का व्यावहारिक प्रयोग एवं सामाजिक उपयोग को निरूपित करने का प्रयास; (3) छात्रों के चरित्र का निर्माण; (4) छात्रों के दृष्टिकोण का निर्माण; और (5) छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास।

5. प्राथमिक शिक्षा : Primary Education—पंचायती राज योजना में प्राथमिक शिक्षा की और उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस शिक्षा के अन्तर्गत प्रयोग की तुलना में इस पर करने अधिक धन खर्च 743 करोड़ रुपए व्यय करने का निर्णय किया गया है। इस यह है कि इस योजना के अन्तर्गत 6-11 वर्ष-वर्ग के 97 प्रतिशत बालों को इस उद्देश्य के अन्तर्गत प्रदान करने के लिए विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जायगी कि किसी बालक को प्रारम्भिक स्तर में प्राथमिक स्कूल 1-5 कि.मी.मीटर से और निम्न स्तर 5-15 कि.मी.मीटर से अधिक दूर न हो। जनजातियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चिता प्रदान करने के लिए सामान्य जायज-स्कूलों की स्थापना का प्रयास है।

6. माध्यमिक शिक्षा : Secondary Education—माध्यमिक शिक्षा के विषय में दो मुख्य प्रस्ताव हैं। पहला, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जायगा, ताकि छात्रों में इस शिक्षा की प्राप्त करने के पश्चात् किसी व्यवसाय में प्रवेश करने की योग्यता उत्पन्न हो जाय। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा का देश की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से अनिवार्य सम्बन्ध स्थापित किया जायगा।

7. विश्वविद्यालय-शिक्षा : University Education—विश्वविद्यालय-शिक्षा से सम्बन्धित उल्लेखनीय कार्य हैं :—विश्वविद्यालय-शिक्षा के अर्वाञ्छनीय विस्तार पर प्रतिबंध; चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली का प्रयोग करके केवलयोग्य छात्रों का उच्च शिक्षा के लिए चयन; प्रतिभाशाली एवं पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था; परीक्षाओं में सुधार; सामाजिक विज्ञानों (Social Sciences) में अनुसंधान-कार्य की प्रोत्साहन; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान-कार्यों की सुविधाओं में विस्तार; और पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों को स्थान देकर, छात्रों में किसी व्यवसाय में प्रवेश करने की योग्यता की उत्पत्ति।

8. शिक्षा का समान स्वरूप : Uniform Pattern of Education—राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के अनुसार सम्पूर्ण देश में शिक्षा को समान स्वरूप देने का निश्चय किया गया है। इस शिक्षा की अवधि 15 वर्षों की होगी—10 वर्षों की प्राथमिक एवं निम्न माध्यमिक शिक्षा, 2 वर्षों की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, और 3 वर्षों का प्रथम डिग्री कोर्स, अर्थात् 10+3+2।

9. समाज-शिक्षा : Social Education—समाज-शिक्षा के कार्यक्रम में तीन मुख्य बातें हैं; यथा :—शिक्षा-गस्थाओं को वयस्क-शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाना; समाज-शिक्षा का वयस्कों के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करना, और समाज-शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा, कृषि-विस्तार, महत्कारिता और स्वास्थ्य एवं परिवार-नियोजन से सम्बन्ध स्थापित करना।

## उपसंहार

भारतवासियों की सहयोग-भावना, व्यवस्थित नागरिक जीवन एवं सामान्य जनता के सामाजिक कार्यों में बुद्धिमत्ता के माध्यम से योग्यता पर ही सोकृत-राज्य की मकसदता निर्भर है। इसलिए, यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को अधिकारी से अधिक महत्व देने लगे और आलोचनात्मक प्रवृत्ति करने एवं टीका-तर्क में मोचने-बिचारने की उसरी आदत पड़ जाय। इसके अतिरिक्त, यह भी उतना ही आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति—समाज का उत्पादक सदस्य बने और देश की बहुमुखी प्रगति में योग दे। इन्हीं लक्ष्यों को नामने रणरत्न ज्ञान ने चार पंचवर्षीय योजनाओं का कार्य-नियम किया जा चुका है और पंचवर्षीय कार्यक्रम कर दिया गया है।

यह मान है कि उपरिक्तविन पक्षों की अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। किन्तु, हम यह स्वीकार करने में मंजूर नहीं करना चाहिए कि शिक्षा अपने लक्ष्यों की ओर प्रविष्ट गति में प्रचलन हो रही है। वैश्विक शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश, विज्ञान पर आधारित शिक्षा, शिक्षा की सुविधाओं में वित्तीय, सामाजिक क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, शिक्षकों एवं विद्यार्थी जातियों की शिक्षा का विस्तार, वैश्विक अवसरों की समानता और प्राविधिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा-सम्बन्धी हो स्थापना ने शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक परिवर्तन कर दिया है। परिणामतः हमने कुछ सीमा तक व्यक्ति की समाज का उत्पादक मन्दस्व बना दिया है और हमने अपने देश की प्रगति में योग देने की कुछ क्षमता भी उत्पन्न कर दी है।

इन प्रकार, विद्यार्थी योजनाओं के अभाव में शिक्षा के पुनर्गठन के लिए जो उपायार्थी उद्योग किए गए हैं, उनके फलस्वरूप उनका उचित शिक्षा में विकास हो रहा है और उनको नवीकर्य करने में बहुत बचकन पड़े है। पर इन तस्वीर में अभी कुछ बच्चे अज्ञान-वर्ती शिक्षाई दे रहे हैं। उदाहरणार्थ—शिक्षा की मुवात्मक उन्नति नहीं हुई है और उनका स्तर फिर गया है। सामान्य रूप में, बालकों की शिक्षा की भाँति व्यवस्थित की शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ है। देश के कुछ भागों में बालकों की प्राथमिकी—शैली की शिक्षा अब भी बहुत विद्युत हुई दशा में है। प्राथमिक एवं औद्योगिक शिक्षा-मार्गों में भयान, शिक्षकों और उपकरणों का अभाव है। सर्वोपरि, भारी भय संशयान के मुक्त जीवन-निर्देशक निदान के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निम्नलिखित एवं परिवर्धन प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है।

विष्णु ने इसीप्रकार पूर्व जन्म कृतियों की उपस्थिति के लिए मोक्षदा-  
निर्णायकता पर दोषासोधन करना सर्वथा अस्वाभाव्य है । उनका कारण यह है कि  
मोक्षदाता के दोषानुषंग समस्त-समस्त पर ऐसी अधिपत्य एवं वास्तविक साम्राज्य उपलब्ध  
होई, जिस पर विचार प्राप्त करना मानव-शक्ति में परे ही जान थी । इसादृश के  
लिए, मृत्यु व प्राणुप्राण, मनुष्यों के मनुष्य में प्रसिद्ध एवं असाधारण बुद्धि, दो वर्षों  
के असाधारण भक्ति, साक्षात्-सौमन्य और अनेक उपवास आरत-प्रादोष-प्राण-मुक्त ने इस  
विषय की लक्षित विवेची और विवेचनरत हो अपना कार्यरत बना दिया कि विष्णु  
की मृत्यु के लक्षित विवेची के अनुसार ही अस्तु । अन्त में के लिए भक्त उपलब्ध न हो सका ।

[illegible]

वास्तविक किया है :—“न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अपने घरों से निकटतम सम्भव स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।”

“Under the National Programme of Minimum Needs, facilities for elementary education for children up to the age of 14 will be provided at the nearest possible places from their homes.”

—*Draft Fifth Five-Year Plan (Adapted)*, Vol. I, p. 87.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Describe briefly the achievements in the field of education under the First Five-Year Plan.

पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. Write a critical note on “Education in India under the Second Five-Year Plan.”

अवलोकित पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए :—“दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में शिक्षा।”

3. What efforts were made for the development of Primary, Secondary, and University Education under the Third Five-Year Plan?

तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्राथमिक, माध्यमिक, और विश्वविद्यालय-शिक्षा के विकास के लिए क्या कार्य किए गए?

4. Give an account of the failures and achievements in the field of education under the Fourth Five-Year Plan.

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में असफलताओं एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।

5. “The Fifth Five-Year Plan seeks to introduce certain essential changes in the educational structure.” What are these changes and how will they be introduced?

“पाँचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा की संरचना में कुछ आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।” ये परिवर्तन क्या हैं और इनको किस प्रकार किया जायगा?





**भारतीय शिक्षा की समस्याएँ**  
**PROBLEMS OF INDIAN EDUCATION**



## 23

### प्राथमिक शिक्षा

#### PRIMARY EDUCATION

"Why does not the nation move ? First educate the nation. Even for social reforms, the first duty is to educate the people."—Swami Vivekananda

#### विषय-प्रवेश

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा—प्रथम प्राथमिकता को यस्तु है। यह पहली सीढ़ी है, बिना सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन के माथ जितना पविष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है, उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र का निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान इसका है, उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है। इसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर, देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इसका हर ऊँच पर हर व्यक्ति के जीवन से सम्पर्क होता है।

इस प्रकार, हम नहं मरते हैं कि सब व्यक्तियों की शिक्षा जववा जनसाधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूलाधार है। इस शिक्षा की अवहेलना करने के कारण भारत का पतन हुआ। अतः इसका उत्थान करके ही हमारे देश का उत्थान हो सकता है। इस प्रसंग में स्वामी विवेकानन्द के अशक्ति काव्य मंत्र में भरपूर है :—'मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान् राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल रहेगी, जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर दिया जायगा।'

"I consider that the great national sin is the neglect of the masses, and that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated."—Swami Vivekananda : *Works*, Vol. V, p. 152.

प्राथमिक शिक्षा के इस नैतिक परिचय के परचातु हूँ उसके इतिहास पर विह्वल दृष्टिकान कर रहे हैं ।

### प्राथमिक शिक्षा—अनिवार्यता से पूर्व Primary Education Before Compulsion

अनिवार्यता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इतिहास दो स्पष्ट कालों में विभाजित किया जा सकता है :—इंग्लिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन-काल और ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन-काल । हूँ इन दोनों कालों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और प्रगति का वर्णन करने से पूर्व उस समय भारत में प्रचलित देशी शिक्षा (Indigenous Education) की व्यवस्था का नैतिक परिचय दे रहे हैं; यथा :—

1. देशी शिक्षा-व्यवस्था—1757 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के परचातु इंग्लिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारियों के भाग्य ने फलदा गायी और वे इन देश के विज्ञान-भूभाग पर शासन के रूप में प्रतिष्ठित हो गए । इस घटना के लगभग एक शताब्दी उपरान्त, अर्थात् 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अंग्रेजों द्वारा ही ज्ञान-वासी मान्य के मान होता है कि भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा प्रसार करने के लिए पाठशालाओं और मकतबों का जाल बिछा हुआ था ।

उदाहरणार्थ—इंग्लिश-मिल मिड (Mill) के अनुसार, 1822 में मद्रास के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक स्कूल था ।<sup>1</sup> बम्बई के मखेर की तालिका के तदनुसार, प्रेंडरगस्ट (Prendergast) के मतानुसार, 1832 में बम्बई में ऐसा छोटे भी ग्राम नहीं था, जिनके समाने-सम एक प्राथमिक विद्यालय न हो ।<sup>2</sup> एडम (Adam) की "प्रथम रिपोर्ट" (First Report) के आधार पर जेम्स ने किया है कि 1835 के लगभग केवल उदात्त में एक-एक प्राथमिक स्कूल थे ।<sup>3</sup> उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त (अधुनिक यूप) की सरकार की 1843 की रिपोर्ट के अनुसार जिनक ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय थे ।<sup>4</sup>

1. James Mill : *History of British India*, Vol. I, p. 562.
2. G. L. Prendergast's *Evidence of 1832*.
3. A. N. Ray : *Education in Modern India*, p. 5.
4. S. N. Mukherji : *History of Education in India*, p. 43.

2. कम्पनी का शासन-काल (1757-1858)—1757 से 1858 तक के लगभग 100 वर्ष के शासन-काल में दक्षिण ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने हितों की पूर्ति और अपने नवविजित प्रदेशों के निवासियों की सद्भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मद्रास, बनारस सहित कलिंग, पूना सहित कलिंग आदि की स्थापना तो की, पर प्राथमिक शिक्षा के प्रति कोई दृष्टि प्रकट नहीं की। इस शिक्षा के सम्बन्ध में केवल दो अंग्रेज प्रशासकों के नाम उल्लेखनीय हैं। पहला नाम है—भारत के गवर्नर-जनरल, लार्ड डलहौजी (Dalhousie) का, जिसने 1854 में बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। दूसरा नाम है—पश्चिमोत्तर प्रान्त के गवर्नर, जेम्स टॉमसन (James Thomason) का, जिसे भारत में प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। उसी के प्रयास के फलस्वरूप इस प्रान्त में 1851 में “हस्तावली स्कूलों की प्रणाली” (Circle School System) प्रारम्भ हुई, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई।

किन्तु, डलहौजी और टॉमसन के प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी कार्य—भारत जैसे विनाश जनसंख्या वाले देश के लिए गागर में दो बूंदों के समान थे। जहाँ तक कम्पनी की शिक्षा-नीति का प्रश्न था, उसने पन-तोतुपता के बर्णभूत होकर और अपने नव-स्थापित राज्य की चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से, प्रचलित देशी विद्यालयों को, जो अति प्राचीन काल से भारतीय शिक्षा और संस्कृति के केन्द्र थे, धनाभाव की दुसाध्य समस्या में उलझकर समय से पहले ही काल के गाल में पड़वा दिया। अंग्रेजों ने यह किस प्रकार किया, इसका वर्णन—बैलेरी जिले के अंग्रेज कलेक्टर, कैंपबेल (Campbell) से सुनिए<sup>1</sup>—“इस जिले में 533 शिक्षा-गस्थाएँ हैं, पर मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि अब इनमें से किसी को भी सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। सरकारी आय का वह अधिकांश भाग, जो पहले शिक्षा-गस्थाओं को अनुदान के रूप में दिया जाता था, अब अज्ञानता फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है।”

1813 के “वाचान-पत्र” (Charter) ने कम्पनी पर भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व रखा और उसको उनकी शिक्षा के लिए कम-से-कम एक लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय करने का आदेश दिया। यद्यपि यह धनराशि अत्यन्त अल्प थी, फिर भी कम्पनी ने अगले दस वर्षों तक भारतीयों की शिक्षा के लिए इसका उपयुक्त प्रयोग नहीं किया। व्यापारियों की कम्पनी का प्रमुख लक्ष्य—धन का अर्जन करना था, न कि शिक्षा-प्रसार के निष्प्रयोजन कार्य पर उसे व्यय करना। अतः ‘उमने कम धन व्यय करके शिक्षा-प्रसार के कार्य को सम्पन्न करने के लिए “निस्वन्दन-सिद्धान्त”

1. Report of Mr A. D. Campbell, the Collector of Bellary, submitted to the President of Board of Revenue, Fort St. George, in August, 1823.

1. भारतीय विद्या और उसकी समस्याएँ

Illustration Theory) का अनुसरण किया। 1854 के "वुड के आदेश-पत्र" (Wood's Despatch) में कम्पनी की इस नीति पर शोध व्यक्त किया गया और ने महात्मता-अनुसारी-पद्धति का प्रयत्न करने पर प्रोत्साहित किया गया। पर यह मुझ पर लागू नहीं रहा, कम्पनी के भारत-स्थित कर्मचारियों ने इस मुद्दा की समस्या को ठीक कर दिया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपने निष्कर्ष को डा० एन० एन० मुखर्जी के अग्रणी चर्चा में व्यक्त कर सकते हैं :— "कम्पनी के शासन-काल में प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की गई और कम-से-कम प्रारम्भिक काल में निश्चित रूप से उपाय की गई।"

3. पार्लियामेंट का शासन-काल (1858-1905)—नवम्बर, 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कम्पनी के शासन का अन्त करके, रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया। इस नवीन शासन-व्यवस्था में लॉर्ड स्टैनले (Stanley) ने "भारत-मंत्री" (Secretary of State for India) का पद ग्रहण किया। उसने 1859 में भारतीय विद्या के सम्बन्ध में एक आदेश-पत्र जारी किया, जिसे "स्टैनले का आदेश-पत्र" (Stanley's Despatch) कहा जाता है। इस "आदेश-पत्र" में उसने भारत-मन्त्रालय को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करने का आदेश दिया और उसके व्यय की पूर्ति के लिए अनिवार्य स्वामीय कर लगाने का परामर्श दिया।

स्टैनले के "आदेश-पत्र" ने प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक प्रदान किया और उसने विद्या के क्षेत्र में प्रवेश दिया। हिन्दु, मुसलमान और कुछ और वर्गों के बाद, 1882 के "भारतीय विद्या-आयोग" (Indian Education Commission) ने उसका कार्य अन्तर्गत कर दिया। इसका कार्य यह था कि "आयोग" को विद्यार्थियों का भोजन करके, सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वामीय मन्त्रालय को सौंप दिया, उसने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। यद्यपि ही समस्या में उसकी हुई सहायता मन्त्रालय ने प्राथमिक शिक्षा के प्रकार के लिए धन-प्राप्ति को प्राप्त करना चाहे था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में निविदा जा गई और देश का जीवन उसी शिक्षा प्राप्त करने में बाधित रह गया।

समय में, हम यह नहीं कह सकते कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को प्रति उत्साह से प्रवृत्त किया। 14-15, 1882 में उसे स्वामीय मन्त्रालय का भोजन सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण उपाय-पत्र को अर्पण किया, जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा में प्रतिशत







को अबाध गति से प्रवाहित होने में योग दिया और उसका विकास दिन, रूना, रात चौगुना होता चला गया।

किन्तु, विकास निरन्तर गतिशील रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसमें स्थिरता आना प्रकृति का नियम है। प्राथमिक शिक्षा भी इस नियम का अपवाद न बन सकी। उसका विकास 1931 में अवरुद्ध हो गया और वह 1937 तक स्थिरता की दशा में पड़ी करवटें बदलती रही। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, 1931 से 1937 तक की अवधि, विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद (Economic Depression) की अवधि थी, जिसका भारत पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। अतः भारत को अनिवार्य शिक्षा की व्यव-पूर्ण योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। दूसरा, "हर्टाग समिति" (1929) का प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक सुझाव यह था कि उसे वास्तव में हितप्रद बनाने के लिए, उसकी संख्यात्मक वृद्धि पर अंकुश लगा दिया जाय और प्राथमिक विद्यालयों को ठोस बना कर (Consolidation) उसकी गुणात्मक उन्नति की जाय। सरकार ने जनता के घोर विरोध के बावजूद "समिति" के इस सुझाव को स्वीकार करके निम्न श्रेणी के प्राथमिक विद्यालयों को तोड़ दिया और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया।

वर्षों से स्थिरता की दशा में पड़ी हुई प्राथमिक शिक्षा को 1935 के "भारत-सरकार-अधिनियम" से गतिशीलता का वरदान प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के अनुसार "प्रान्तीय स्वशासन" की स्थापना हुई और 6 प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सत्तासूट होकर प्राथमिक शिक्षा के विकास को सम्भव बनाया। उन्होंने अपने प्रान्तों की स्थानीय संस्थाओं को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देकर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की और बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान कीं। इस प्रकार, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राप्त होने पर प्राथमिक शिक्षा ने अपने विकास के पथ एक बार फिर अवरोधमुक्त अभियान आरम्भ किया।

### स्वतंत्र भारत में अनिवार्य शिक्षा

#### Compulsory Education in Free India

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा ने अपने विकास के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत ने भी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। इसीलिए "संविधान-सभा" (Constituent Assembly) ने, जिसे देश का संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, अग्रार्पित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति-निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया :— "राज्य इस संविधान के फार्मान्वित किए जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिये, जब तक वे

धीरे-धीरे बच्चों की आयु पूर्ण नहीं कर सेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा।”

“The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.”—Article 45 of the *Constitution Adopted by Free India on January 26, 1950.*

भारत-सरकार के निर्णय के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा—बेमिक प्रकार की होगी और सरकार हम शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए 1950 में ही प्रयत्नशील है। वह राज्य-सरकारों को सम्पूर्ण व्यय का 34 प्रतिशत वार्षिक महापता-अनुदान के रूप में देती है। शेष व्यय के 2 भाग से अधिक की पूर्ति राज्य-सरकारों द्वारा, 2 की स्थानीय सत्थाओं द्वारा और बाक़ी की अन्य स्रोतों से की जाती है।<sup>1</sup> पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विपुल धन-राशियाँ व्यय की गई हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप अब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की ओर प्रगति हुई है, उसे अपेक्षित तात्त्विक में दर्शाया गया है<sup>2</sup> :—

### अनिवार्य शिक्षा की प्रगति

विवरण	1950-51	1960-61	1970-71 अस्थापी
6-11 वय-वर्ग की कुल जनसंख्या का %	42.6	62.4	80.3
11-14 " " " "	12.7	22.6	34.1

### समस्याएँ व उनके समाधान Problems & Their Solutions

1950 के भारतीय संविधान के एक नीति-निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 10 वर्ष के अन्दर हो जानी चाहिए थी। किन्तु, यह लक्ष्य न तो अभी तक प्राप्त किया गया है और न निश्चित भविष्य में इसके प्राप्ति किए जाने की आशा ही है। इन दोनों विषयों में “चौबीस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा” में योजना-निर्माताओं ने अपनी धारणा का

1. S. N. Mukerji *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 69.

2. भारत, 1973, p. 76.

को अवाध गति से प्रवाहित होने में योग दिया और उसका विकास दिन दूना, रात चौगुना होता चला गया।

किन्तु, विकास निरन्तर गतिशील रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसमें स्थिरता आना प्रकृति का नियम है। प्राथमिक शिक्षा भी इस नियम का अपवाद न बन सकी। उसका विकास 1931 में अवरुद्ध हो गया और वह 1937 तक स्थिरता की दशा में पड़ी करवटें बदलती रही। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, 1931 से 1937 तक की अवधि, विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद (Economic Depression) की अवधि थी, जिसका भारत पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। अतः भारत को अनिवार्य शिक्षा की व्यय-पूर्ण योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। दूसरा, "हर्टाग समिति" (1929) का प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक सुझाव यह था कि उसे वास्तव में हितप्रद बनाने के लिए, उसकी संख्यात्मक वृद्धि पर अंकुश लगा दिया जाय और प्राथमिक विद्यालयों को ठोस बना कर (Consolidation) उसकी गुणात्मक उन्नति की जाय। सरकार ने जनता के घोर विरोध के बावजूद "समिति" के इस सुझाव को स्वीकार करके निम्न श्रेणी के प्राथमिक विद्यालयों को तोड़ दिया और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया।

वर्षों से स्थिरता की दशा में पड़ी हुई प्राथमिक शिक्षा को 1935 के "भारत-सरकार-अधिनियम" से गतिशीलता का वरदान प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के अनुसार "प्रान्तीय स्वशासन" की स्थापना हुई और 6 प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सत्तारुद्ध होकर प्राथमिक शिक्षा के विकास को सम्भव बनाया। उन्होंने अपने प्रान्तों की स्थानीय संस्थाओं को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देकर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की और बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान कीं। इस प्रकार, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राप्त होने पर प्राथमिक शिक्षा ने अपने विकास के पथ एक बार फिर अवरोधमुक्त अभियान आरम्भ किया।

### स्वतंत्र भारत में अनिवार्य शिक्षा

#### Compulsory Education in Free India

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा ने अपने विकास के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत ने भी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। इपीजि। "संविधान-सभा" (Constituent Assembly) ने, जिसे देश का संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, अप्रांक्ति शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति-निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया :— "राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किए जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिये, जब तक वे

बीबह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, नि शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा।"

"The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."—Article 45 of the *Constitution Adopted by Free India on January 26, 1950.*

भारत-सरकार के निर्णय के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा—बेमिक्त प्रकार की होगी और सरकार इस शिक्षा को नि.शुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए 1950 में ही प्रयत्नशील है। वह राज्य-सरकारों को सम्पूर्ण व्यय का 34 प्रतिशत वार्षिक महायत्ना-अनुदान के रूप में देती है। शेष व्यय के  $\frac{2}{3}$  भाग में अधिक की पूर्ति राज्य-सरकारों द्वारा,  $\frac{1}{3}$  की स्थानीय सरकारों द्वारा और बाकी की अन्य स्रोतों से की जाती है।<sup>1</sup> पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विपुल धन-राशियाँ व्यय की गई हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप अब तक नि.शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो प्रगति हुई है, उसे अद्योक्षरित तानिवा में दर्शाया गया है<sup>2</sup> :—

### अनिवार्य शिक्षा की प्रगति

विवरण	1950-51	1960-61	1970-71 अस्थायी
6-11 वर्ष-वर्ग की कुल जनसंख्या का %	42.6	62.4	80.3
11-14 " " " "	12.7	22.6	34.1

### समस्याएँ व उनके समाधान Problems & Their Solutions

1950 के भारतीय गणितान के एक नीति-निर्देशक विधान के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि.शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 10 वर्ष के अन्दर हो जानी चाहिए थी। किन्तु, यह लक्ष्य न तो अभी तक प्राप्त किया गया है और न निश्चित भविष्य में इसके प्राप्त किए जाने की आशा ही है। इन दोनों बिन्दुओं में "पौड़ी पंचवर्षीय योजना की स्मरणिका" में योजना-निर्माताओं ने अरती धारणा का

1. S. N. Mukerji *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 69
2. भारत, 1973, p. 76.

अग्रकित जल्दों में स्पष्टीकरण किया है :—“विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, वह प्रशंसनीय है। पर हम अब भी अपने संविधान के उस निर्देश को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिसके अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायगी। यह लक्ष्य 1981 से पहले प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसी आशा है।”

“In spite of the appreciable rise in the number of children going to school, we will still be far from fulfilling the Constitutional directive of free and compulsory education for all children up to the age of 14. The goal is not expected to be achieved before 1981.”—*Fourth Five-Year Plan, A Draft Outline*, p. 313.

संवैधानिक नीति-निर्देशक सिद्धान्त द्वारा निर्धारित लक्ष्य अब तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ है और निकट भविष्य में प्राप्त क्यों नहीं होगा? इसका कारण है—प्राथमिक शिक्षा के प्रसार-पथ में उपस्थित होने वाली समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ। हम इन समस्याओं एवं कठिनाइयों और इनके समाधान एवं निवारण की विधियों पर निम्नांकित पंक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं :

1. समस्या—शिक्षा की दोषपूर्ण नीति : Faulty Policy of Education—1950 में क्रियान्वित किए जाने वाले भारतीय संविधान की 45वीं धारा के माध्यम से यह घोषणा की गई थी कि सरकार 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रयास करेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता लेने के लिए “अखिल-भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद्” (All India Council for Elementary Education, 1957) का निर्माण किया गया, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-सरकारों को वार्षिक सहायता-अनुदान दिया गया और पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा पर 593.74 करोड़ रुपए व्यय किए गए।<sup>1</sup> किन्तु, इन सब प्रयासों के बावजूद 20 वर्ष के पश्चात् भी 6-11 वय-वर्ग के 80.3 प्रतिशत बच्चों को और 11-14 वय-वर्ग के 34.1 प्रतिशत बच्चों को ही शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जा सकी हैं।<sup>2</sup> 20 वर्ष के उपरान्त भी निर्धारित लक्ष्य तक न पहुँचने का आधारभूत कारण है—केन्द्रीय सरकार की दोषपूर्ण नीति।

सरकार की नीति दोषपूर्ण इसलिए है, क्योंकि वह वास्तविकता पर आधारित न होकर आदर्शवादिता पर अवलम्बित है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त भारत-सरकार ने वैमिक शिक्षा-प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के रूप में स्वीकार किया। उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए वैमिक शिक्षा को आदर्श

1. भारत, 1973, p. 75.

2. भारत, 1973, p. 76.

माता । अतः उमने "पहली पंचवर्षीय योजना" में ही प्राथमिक विद्यालयों को वैश्विक विद्यालयों में परिवर्तित करने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया । किन्तु, "दूसरी योजना" की अवधि में ही उमरो दस साल का अनुभव हो गया कि भारत जैसे विशाल देश में वैश्विक शिक्षा-प्रणाली को प्रवर्धित करने में बहुत अधिक समय लगेगा । अतः सरकार ने "तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा" (p. 98) में यह घोषित किया :— "पूरी तरह से विकसित बुनियादी विद्यालयों को चलाने की दिशा में प्रगति होने में बहुत समय लगेगा ।"

बहुत समय क्यों लगेगा ? इसके कारण स्पष्ट हैं । प्राथमिक विद्यालयों को वैश्विक विद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए साक्षर-मजदूर, प्रशिक्षित अध्यापकों और विज्ञान यन्त्रादि की आवश्यकता है । इन तीनों चीजों को भारत जैसे निर्धन देश के लिए अन्य समय में जुटाना असम्भव है, अपारहीन आशा है । यह जानते हुए भी सरकार अपने आदर्श के पीछे दौड़ रही है, जो मूल-मारीचिका के समान आगे बढ़ता जाता जा रहा है । दस साल का ज्ञान होने पर भी सरकार प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिए जाने वाले अधिकतर धन को, उसे वैश्विक शिक्षा का रूप प्रदान करने में व्यय कर रही है । इस प्रकार, सरकार अपने आदर्श के बलीभूत होकर, भारतीय परिवर्तन में सिमित सधम की प्राप्ति के लिए सविनय वन्दन न उठा कर, अपने उत्तरदायित्व की स्पष्ट अवहेलना कर रही है ।

समाधान—शिक्षा की निश्चित नीति Definite Policy of Education— दस समस्या का समाधान करने के लिए यह परम आवश्यक है कि सरकार अपनी आदर्श-वादी नीति को अविविष्ट रहकर, निश्चित नीति का अनुसरण करे । उसे दस साल का अनुभव हो चुका है कि प्राथमिक विद्यालयों को विकसित बुनियादी विद्यालयों का रूप प्रदान करने में बहुत अधिक समय लगेगा । अतः यह समझ में नहीं आता है कि यह दस कार्यक्रम को क्यों जारी रखता जा रही है और इसकी जारी रखकर देश के सब बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का निश्चित अधिकार में किस प्रकार सुलभ बना सकती है ? अनुभव बताता है कि पहले एक कार्य का पूर्ण कर लीजिए, फिर दूसरे को आरम्भ कीजिए ।

अतः सरकार को अपनी वर्तमान दोषपूर्ण नीति का परिणाम स्वीकारे, निश्चित नीति का निर्माण करने में संतुलित भी सहयोग नहीं करना चाहिए । उमरी सर्वोत्तम नीति यही हो सकती है कि वह पहले 6-14 वर्ष-वर्ग के सब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे । जब वह अपने दस वर्ष की प्राप्ति कर ले, तब प्राथमिक शिक्षा को वैश्विक शिक्षा का रूप प्रदान करने या प्राथमिक विद्यालयों को वैश्विक विद्यालयों में रूपान्तरित करने का कार्य आरम्भ करे । यदि सरकार ने दस निश्चित नीति का अनुसरण नहीं किया, तो वह "पहली पंचवर्षीय योजना" में 743 करोड़ रुपए खर्च करके भी निश्चित सधम को प्राप्ति करने में अनिवार्य विफल होगी ।

2. शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन : Faulty Administration of Education—भारत में शिक्षा—राज्य का विषय है और अधिकांश राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व—नगरपालिकाओं, जिला-परिषदों आदि स्थानीय संस्थाओं पर है। केन्द्रीय सरकार—आर्थिक सहायक के रूप में प्राथमिक शिक्षा का केवल आंशिक उत्तरदायित्व वहन करती है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में 4 मुख्य दोष प्रकट हो गए हैं; यथा :—

पहला, नव स्थानीय संस्थाएँ अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन करती हैं। परिणामतः देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में विविध गृह्यरूपता परिनिक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ स्थानीय संस्थाओं ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है और कुछ इस दिशा में एक-दो कदम ही उठा पाई हैं। इस प्रसंग में “कोठारी कमिशन” ने लिखा है :— “निर्धन क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं के ऊपर बहुधा ‘अपूर्ण’ कार्य का सबसे अधिक भार है।”

“It is the poorer areas that often have the heaviest load of the unfinished task to carry.”—Kothari Commission Report, p. 165.

दूसरा, भारत की लगभग सभी स्थानीय संस्थाएँ अपनी अयोग्यता, अकर्मण्यता एवं अकिञ्चनता के लिये कुख्यात हैं। या तो वे ऋण-ग्रस्त हैं या दरिद्रता के दावानल में प्रज्ज्वलित होकर क्षीणकाय बन चुकी हैं। ऐसी संस्थाओं से प्राथमिक शिक्षा के सुप्रशासन की बात सोचना व्यर्थ है। ये संस्थाएँ इस शिक्षा के व्यव की पूर्ति के लिए स्थानीय कर लगाकर इसकी उत्तम व्यवस्था कर सकती हैं और विस्तार भी। किन्तु, उन संस्थाओं के पदवीनुप सदस्य जागामी निर्वाचन में पदविहीन होने की आशंका से इन कार्य में अग्रणी बनने के बजाय दो कदम पीछे ही रहते हैं। इन परिस्थितियों में स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा के उत्तम प्रशासन के लिये धन जुटाया जाना सर्वथा असम्भव है।

तीसरा, स्थानीय संस्थाओं के सदस्य अपनी लोकप्रियता में अभिवृद्धि करने के लिए अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तो कर देते हैं, पर धनानाथ के कारण विद्यालय-निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। उनका परिणाम यह हुआ है कि जिस अनुपात में विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, उस अनुपात में निरीक्षकों की संख्या नहीं बढ़ी है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों का उपयुक्त निरीक्षण न होना और परिणामस्वरूप उनके प्रशासन में शिथिलता एवं अनियमितता का प्रवेश हो जाना स्वाभाविक है।

चौथा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिनियमों का निर्माण परतन्त्र भारत में हुआ था। उस समय की और नव भारत की परिस्थितियों में आकाश-पाताल का अन्तर है। किन्तु, अधिनियमों में किसी प्रकार का संशोधन न किए जाने के कारण







स्थिति के अनुसार वर्गा, शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं में इन भागों पर अपने भव्यकरतम रूप में प्रकट होती हैं। कम जनसंख्या वाले इन प्रदेशों के प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। अतः अभिभावक इन गकटपूर्ण भागों में अपने बच्चों को जीवन के लिए अर्धहीन एवं अनुपयोगी ज्ञान का अर्जन करने के लिए दूसरे ग्राम-विद्यालयों को भेजकर अपने और अपने बच्चों के प्राणों की विपत्ति में फैलाना विवेकपूर्ण कार्य नहीं समझते हैं।

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—प्राकृतिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने और उनकी उपस्थिति में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए नीचे सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, आवासमन के सुरक्षित भागों का निर्माण करके और यानायात के सुविधाजनक माधनों को उपलब्ध बना कर, उपरि-अंकित कठिनाइयों को पराभूत किया जा सकता है। भारत जैसे भू-रचना वाले देश में यह कार्य अमुगम अवश्य है, पर असम्भव नहीं है। दूसरा प्रमाण यह है कि पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में सड़को का निर्माण करके अनेक दूरस्थ ग्रामों को मूल-दूतरे में सम्बद्ध कर दिया गया है। ऐसी आशा है कि “पाँचवीं पंचवर्षीय योजना” की समाप्ति तक 1,500 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले गव ग्रामों का सड़कों के द्वारा मूल-दूतरे से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जायगा।<sup>1</sup> अतः हम कह सकते हैं कि अनेक ग्रामों के बालकों को विद्यालयों की जाने की सुविधा प्राप्त हो जायगी।

दूसरा, क्योंकि वास्तव—प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ 6 वर्ष की आयु में कर देता है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक विद्यालय उनके ग्राम के निकट हो। सरकार इस दिशा में सत्रिय कदम उठाने का निश्चय कर चुकी है। ‘पाँचवीं पंचवर्षीय योजना’ में यह प्रस्ताव अंकित किया गया है कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जायगी कि किसी भी वास्तव के निवास स्थान में प्राथमिक विद्यालय 1.5 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होगा।<sup>2</sup>

तीसरा, जब तक प्राथमिक विद्यालयों की उपर्युक्त योजना पूर्ण न हो जाय, तब तक जिन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उनके बच्चों की शिक्षा का भार सरकार द्वारा किसी स्थानीय व्यक्ति को सौंप दिया जाय।

5. समस्या—राजनीतिक कठिनाइयाँ : Political Difficulties—शिक्षा—प्रजातन्त्र की आधारशिला है। शिक्षा ही प्रजातन्त्र के निशानियों की उत्तम नागरिक बना सकती है। उत्तम नागरिक बनकर ही वे अपने कर्तव्यों का मकाना में पालन और अपने अधिकारों का विवेक से उपयोग करके, अपने देश की प्रगति के प्रगल्भ पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।

1. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol II, p. 177.

2. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol I, p. 88.

भारत भी प्रजातन्त्र देश है। अतः उसके निवासियों को भी उत्तम नागरिक बनाने के लिए कम-से-कम प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य है। इस तथ्य से गली-भाँति अवगत होने के बावजूद भी भारत-सरकार अभी तक उनकी शिक्षा पर अपने पूर्ण ध्यान को केन्द्रित नहीं कर पाई है। इसका कारण यह है कि सत्ता-हस्तान्तरण के समय से लेकर आज तक वह किसी-न-किसी जटिल समस्या में उलझी रही है; यथा :—देश के विभाजन से उत्पन्न होने वाली आर्थिक असंतुलन की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, रजवाड़ों की समस्या, काश्मीर की समस्या, विभिन्न भाषा-भाषी राज्यों की समस्या, मुद्रा-अवमूल्यन से उत्पन्न होने वाली समस्या, वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्या और भारत-चीन एवं भारत-पाकिस्तान युद्धों से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ।

एक के उपरान्त दूसरी और कभी-कभी दो या दो से अधिक एक साथ उपस्थित होने वाली इन समस्याओं ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति से आज तक सरकार के धन एवं ध्यान पर अपना एकमात्र अधिकार रखा है। यही कारण है कि सरकार—अनिवार्य शिक्षा के प्रसार को अपना पुनीत कर्त्तव्य मान कर भी इसको सम्पन्न करने के लिए समय नहीं निकाल पाई है।

**समाधान—सरकार का पूर्ण ध्यान : Full Attention of Government—** हमने उपर्युक्त पंक्तियों में जिन राजनीतिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है, वे सत्य हैं, सर्वविदित हैं। राजनीतिक कठिनाइयाँ प्रत्येक देश के समक्ष रहती हैं और भारत के सम्मुख भी रहेंगी। इतना ही नहीं, यह भी सम्भव है कि भावी राजनीतिक कठिनाइयाँ और भी अधिक पेचीदा हों। यह भी सम्भव है कि उनसे देश की एक या अनेक आर्थिक, सामाजिक या व्यावसायिक समस्याएँ संयुक्त हों। पर इसका अभिप्राय यह तो नहीं है कि सरकार उनका निराकरण करने में ही व्यस्त रहे और देश के किसी अन्य कार्य के प्रति ध्यान न दे। यदि इन कठिनाइयों एवं समस्याओं का निराकरण करना सरकार का कर्त्तव्य है, तो अपने देश के नागरिकों को सुशिक्षित बनाकर, उनकी ओर उनके समाज की उन्नति करना भी उसका कर्त्तव्य है। अतः सरकार द्वारा जन-शिक्षा की उपेक्षा किए जाने का कारण समझ में आना कुछ कठिन प्रतीत होता है।

यदि सरकार उक्त राजनीतिक कठिनाइयों की उपस्थिति में बड़े-बड़े बांध बना सकती है, बँकों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है और पंचायती राज की स्थापना कर सकती है, तो शिक्षा-प्रसार के कार्य के प्रति उदासीन क्यों रही है? कारण, जैसा कि संयोजन ने निरा है, यही ठीक जान पड़ता है :—“भारत की राजनीतिक स्थिति अनिवार्य शिक्षा-योजना का अविलम्ब कार्यान्वयन चाहती है, पर देश के राजनीतिज्ञ इसके लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं हैं।”

“While the political situation demands the immediate introduction of the scheme of compulsory education, the politicians are

not keen enough to take it up.”—K. G. Salydain : *Compulsory Education in India*, p. 111.

सरकार का संचालन करने वाले राजनीतिज्ञ अपने इस अन्याय को सुझ में तभी बदल सकते हैं, जब वे शिक्षा के प्रति आज और अभी में अपना पूर्ण ध्यान दें।

6. समस्या—धन का अभाव : Dearth of Money—प्राथमिक विद्यालयों के समस्त धन के अभाव की समस्या प्रति क्षण अपने विकरात रूप में मुँह फाड़े खड़ी रहती है। इसके दो व्यापारभूत कारण हैं। पहला यह है कि स्थानीय समस्याओं में से अधिकांश, जिन पर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व है, स्वयं धनाभाव के गहरे गर्त में पड़ी हुई हैं। दूसरा यह है कि भारत-सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण नहीं किया है। यह इस जनतंत्रीय सिद्धान्त को, कि जन-शिक्षा का उत्तरदायित्व देश की सरकार पर होना है, जोविन रखने के लिए थोड़ी-सी जीवन-रक्षक, धन-ओपधि समय-समय पर देती रहती है।

उक्त कथन की पुष्टि करने के लिए तथ्यों का बाहुल्य है। उदाहरणार्थ—अंग्रेजों की विदेशी सरकार, जो इस देश की मादरता की विरोधी थी, प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय का 30 प्रतिशत भार वहन करती थी। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस धनराशि को 30 प्रतिशत से 34 प्रतिशत करके अपनी उदार-हृदयता की सिद्ध किया है।<sup>1</sup> इतना ही नहीं, भारत-सरकार अन्य देशों की सरकारों की तुलना में शिक्षा पर सबसे कम धन व्यय करता है। जबकि इस अपनी राष्ट्रीय आय का 7%, जापान 6%, अमेरिका 4.7% और इंग्लैंड 4.5% शिक्षा पर व्यय करते हैं, भारत लगभग 2.3% करता है। इस बात पर दुःख प्रकट करते हुए, डा० एस० एन० मुकर्जी ने लिखा है :—“इस समय भारत अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 2.3 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है। यह प्रतिशत अत्यन्त अल्प है।”

“India spends about 2.3 per cent of her national income on education today. This is too meagre a percentage.”—Dr. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 98.

धनाभाव की ऐसी सखीय स्थिति में सम्पूर्ण भारत में अनिवार्य शिक्षा का प्रसार न होना, एक अनिवार्य निष्कर्ष है।

समाधान—कुछ सुझाव Some Suggestions—हादिक इच्छा एवं प्रयास से थोड़ी-थोड़ी सुधिरले आगान हो जाती है। उनकी तुलना में धनाभाव की सुधिरल नहीं ज्यादा आगान है। अतः इसे हल करने के 6 आगान तरीके हैं; जैसे :—

1 *Education in the Eighteenth Year of Freedom*, p. 15.

पहला, भारत-सरकार को अपनी सब योजनाओं में से थोड़ी-थोड़ी बचत करके, प्राथमिक शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करनी चाहिए।

दूसरा, इस समय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सरकार के व्यय का अनुपात 1 : 5 है।<sup>1</sup> सरकार को जनशिक्षा की गम्भीरता को समझकर, इस अनुपात को 5 : 1 कर देना चाहिए।

तीसरा, सरकार जिस धन का उपयोग प्राथमिक विद्यालयों को वैसिक विद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए कर रही है, उसका प्रयोग पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए करना चाहिए।

चौथा, दिनकर देसाई का सुझाव है कि चीन, रूस, मिस्र, जापान, जर्मनी एवं आस्ट्रेलिया के समान भारत में भी प्राथमिक शिक्षा के निम्न स्तर की अवधि—5 वर्ष के बजाय 4 वर्ष की कर दी जानी चाहिए और इस प्रकार बचने वाले धन से नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।<sup>2</sup>

पाँचवाँ, इस समय भारत की लगभग 55 करोड़ जनसंख्या में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे 42 प्रतिशत हैं।<sup>3</sup> बच्चों की इस अति विशाल संख्या के लिए सरकार अपनी सम्पूर्ण आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके भी अल्प समय में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कदापि नहीं कर सकती है। अतः यह आवश्यक है कि जनता इस कार्य में सरकार का हाथ बटाए। जनता ने भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान जिस तत्परता और जिस आत्म-त्याग का परिचय दिया है, उसका एक अंश भी यदि उसमें अनिवार्य शिक्षा के प्रति हो, तो भारत के किसी भी बच्चे का जीवन शिक्षा के अभाव के कारण उतना हीन, अनाकर्षक एवं अरुचिकर नहीं रह जायगा, जितना कि आज है।

छठवाँ, भारत-सरकार को विदेशी शासकों की प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने की नीति का कुछ समय के लिए परित्याग कर देना चाहिए और इससे बचने वाले धन को सामान्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में उसे मोरारजे के अग्रार्कित वाक्य को अपने निर्देशक-सूत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए :—“शिक्षा की गुणात्मक उन्नति महत्त्वपूर्ण अवश्य है, पर उस पर बल तभी दिया जाना चाहिए, जब निरक्षरता का अन्त हो जाय।”

“The quality of education is a matter of importance that comes only after illiteracy has been abolished.”—Gokhale's *Speeches*, p. 65.

## 7. समस्या—प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव : Dearth of Trained

1. Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Vol. III, p. 1666.

2. Dinker Desai : *Primary Education in India*, pp. 30-32.

3. *India*, 1974, p. 9.

Teachers—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का वांछित गुणवत्ता उपलब्ध न होने के कारण एक जटिल समस्या उपस्थित हो गई है। यह समस्या—छात्र-संख्या में निरन्तर होने वाली वृद्धि के कारण और भी अधिक जटिल हो गई है।

“कोठारी कमिशन” ने 1985-86 तक प्राथमिक स्तर पर छात्र-संख्या को सम्भावित वृद्धि की तालिका दी है और यह सुझाव दिया है कि इस स्तर पर शिक्षक एवं छात्रों का अनुपात 1 : 50 होना चाहिए।<sup>1</sup> इन दोनों बातों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में प्रतिबर्ष 24 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों में से 3 प्रतिशत या तो अपवाह ग्रहण कर लेते हैं या अध्यापन-कार्य छोड़ देने हैं। इस प्रकार, देश की भविष्य में प्रति वर्ष 3.46 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी।<sup>2</sup>

1965 के एक सर्वेक्षण के अनुसार सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए 28 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है।<sup>3</sup> किन्तु, सरकार के अथक् प्रयास के बावजूद भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में केवल 20.2 लाख प्रशिक्षित अध्यापक ही उपलब्ध हुए।<sup>4</sup> इस प्रकार, 1974 में सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए लगभग 8 लाख शिक्षकों का अभाव है। यदि हम इनमें लगभग 3 लाख प्रति वर्ष के हिमाव से अतिरिक्त शिक्षकों को और जोड़ दें, तो यह अभाव बढ़कर 35 लाख हो जाता है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की वांछित संख्या उपलब्ध होना असम्भव है, और इसलिए सम्पूर्ण देश में अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम भी पूर्ण होना असम्भव है।

प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के अभाव का सर्वप्रथम कारण यह है कि उनका वेतन इतना अल्प है कि नवयुवक—अध्यापक-कार्य के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, और यदि किन्हीं परिस्थितियों-वश हो भी जाते हैं, तो अधिक आर्थिक लाभ का पद प्राप्त होने पर अध्यापन-कार्य से संन्यत के लिए मुँह मोड़ लेते हैं।

नगरों की अपेक्षा ग्रामों के विद्यालयों में शिक्षकों का अधिक अभाव है। इसका कारण यह है कि नगरों में अतिरिक्त धनोपार्जन एवं मनोरंजन के जो साधन सुलभ होते हैं, उनके ग्रामों में कभी भूल कर भी दंगन नहीं होते हैं। अतः नगर में अतिरिक्त धन का अर्जन करने वाला, सायंकाल के समय राष्ट्रीय राजपथ पर

1. Kothari Commission Report, p. 161.

2. S. N. Mukerji. *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 100

3. *The Eighteenth Year of Freedom*, p. 97.

4. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 198

स्वच्छंदता से विवरण करने वाला या किसी सिनेमाघर में चित्रों एवं संगीत से अपने नेत्रों एवं कानों को तृप्त करने वाला नवयुवक शिक्षक—ग्राम में जाकर घूल फाँकने और आनन्दविहीन जीवन व्यतीत करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं होता है। यही कारण है कि नगरों की अपेक्षा ग्रामों में शिक्षकों का तिगुना अभाव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का अनुपात—2:6 है।<sup>1</sup>

अध्यापकों की तुलना में अध्यापिकाओं का अधिक अभाव है एवं ग्रामों में और भी अधिक है। नगरों में इस अभाव का मुख्य कारण—अल्प वेतन है और ग्रामों में निवास-स्थान की अनुविधा।

समाधान—अध्यापकों की पूर्ति : Supply of Teachers—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव अवश्य है, पर यह अभाव कृत्रिम है, क्योंकि यह उनके प्रति समाज की उदासीनता का परिणाम है। आज का समाज यह विस्मृत कर चुका है कि ज्ञान की जिस ज्योति की सुरक्षा करने का भार उन्हें सौंपा गया है, उसे वे जलाए रखने का प्रयत्न करते हैं, ताकि वे उस ज्योति को मन्द किए बिना अपने उत्तराधिकारियों के हाथों में सौंप सकें। यदि हमारा समाज इस सनातन सत्य को गाँठ में बाँध ले, तो अग्रांकित उपायों को अपना कर शिक्षकों की पूर्ति अत्यन्त सरलता से की जा सकती है।

पहला, शिक्षकों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि करके, अध्यापन-कार्य को आकर्षक बनाया जाय। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है और “कोठारी कमिशन” की निष्कारिण की मान्यता प्रदान करके प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का न्यूनतम वेतन 150 रुपए मासिक कर दिया है।<sup>2</sup> किन्तु, वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ी तेजी से जो असाधारण वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए यह वेतन अत्यन्त अल्प है। अतः आधुनिक समय में जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें तत्काल वृद्धि की जानी अनिवार्य है। शिक्षकों का वर्तमान वेतन जितना अल्प है, इसका शब्द-चित्र सँघटन के अग्रांकित वाक्य में देना—“अपने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को अक्सर हम उतना भी नहीं देते हैं, जितना कि पैसे वाले लोग अपने घर के नौकरों को देते हैं।”

दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में उन्हीं क्षेत्रों में निवास करने वाले पुरुषों एवं स्त्रियों की नियुक्ति की जाय और उनको शहरी क्षेत्रों के अध्यापकों से अधिक वेतन दिया जाय। अध्यापिकाओं को निवास की विशेष सुविधाएँ दी जायें। यदि आवश्यक हो, तो उनको भत्ता भी दिया जाय और कम शैक्षिक योग्यता होने पर भी नियुक्त कर दिया जाय।

1. *Second All-India Educational Survey*, p. 135.
2. *Kothari Commission Report*, p. 51.
3. कि० जी० मैथिली : शिक्षा की पुनर्रचना, p. 118.





स्वच्छंदता से विवरण करने वाला या किसी सिनेमाघर में चित्रों एवं संगीत से अपने नेत्रों एवं कानों को तृप्त करने वाला नवयुवक शिक्षक—ग्राम में जाकर घूल फाँकने और आनन्दविहीन जीवन व्यतीत करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं होता है। यही कारण है कि नगरों की अपेक्षा ग्रामों में शिक्षकों का तिगुना अभाव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का अनुपात—2 : 6 है।<sup>1</sup>

अध्यापकों की तुलना में अध्यापिकाओं का अधिक अभाव है एवं ग्रामों में और भी अधिक है। नगरों में इस अभाव का मुख्य कारण—अल्प वेतन है और ग्रामों में निवास-स्थान की अनुविधा।

**समाधान—अध्यापकों की पूर्ति : Supply of Teachers—**अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव अवश्य है, पर यह अभाव कृत्रिम है, क्योंकि यह उनके प्रति समाज की उदासीनता का परिणाम है। राज का समाज यह विस्मृत कर चुका है कि ज्ञान की जिस ज्योति की सुरक्षा करने का भार उन्हें सौंपा गया है, उसे वे जलाए रखने का प्रयत्न करते हैं, ताकि वे उस ज्योति को मन्द किए बिना अपने उत्तराधिकारियों के हाथों में सौंप सकें। यदि हमारा समाज इस सनातन सत्य को गाँठ में बाँध ले, तो अग्रांकित उपायों को अपना कर शिक्षकों की पूर्ति अत्यन्त सरलता से की जा सकती है।

पहला, शिक्षकों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि करके, अध्यापन-कार्य को आकर्षक बनाया जाय। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है और “कोठारी कमीशन” की निष्कारिण को मान्यता प्रदान करके प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का न्यूनतम वेतन 150 रुपए मासिक कर दिया है।<sup>2</sup> किन्तु, वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ी तेजी से जो असाधारण वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए यह वेतन अत्यन्त अल्प है। अतः आधुनिक समय में जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें तत्काल वृद्धि की जानी अनिवार्य है। शिक्षकों का वर्तमान वेतन कितना अल्प है, इसका शब्द-चित्र संयोजन के अग्रांकित वाक्य में देना—“अपने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को अक्सर हम उतना भी नहीं देते हैं, जितना कि पैसे वाले लोग अपने घर के नौकरों को देते हैं।”

दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में उन्हीं क्षेत्रों में निवास करने वाले पुराने एवं स्त्रियों की नियुक्ति की जाय और उनको शहरी क्षेत्रों के अध्यापकों से अधिक वेतन दिया जाय। अध्यापिकाओं को निवास की विशेष सुविधाएँ दी जायें। यदि आवश्यक हो, तो उनको नत्ता भी दिया जाय और कम शैक्षिक योग्यता होने पर भी नियुक्त कर दिया जाय।

1. *Second All-India Educational Survey*, p. 135.
2. *Kothari Commission Report*, p. 51.
3. कै० जी० मैथिल : शिक्षा की पुनर्रचना, p. 118.



उत्तर विलेखे हुए ग्रामों में निवास करने वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना—ये दोनों ही कार्य दुष्कर प्रतीत होते हैं। किन्तु, प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए सरकार ने जितनी धनराशि निर्धारित की है, उसको निम्नांकित योजना के अनुसार व्यय करके विद्यालय-स्थापना की दिशा में हितकर कार्य किया जा सकता है।

प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ऐसे केन्द्रीय ग्रामों में की जाय, जहाँ से अन्य ग्राम कम-से-कम दूरी पर हों। इस प्रकार के ग्रामों में स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों में अन्य ग्रामों के बच्चे सुगमता से पहुँच कर ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। भारत-सरकार ने इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। उसने निर्णय किया है कि पान्चवीं पंचवर्षीय योजना में विद्यालयों का निर्माण इस विधि से किया जायगा कि किसी भी बालक के ग्राम से प्राथमिक विद्यालय 1-5 किलोमीटर और मिडिल स्कूल 5 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होगा। सरकार को आशा है कि इस योजना के पूर्ण होने पर 6-11 वय-वर्ग के 97 प्रतिशत और 11-14 वय-वर्ग के 47 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल जायगी।<sup>1</sup>

9. समस्या—विद्यालयों के भवन : Buildings of Schools—विद्यालयों की स्थापना से बहुत-कुछ सम्बद्ध विद्यालय-भवनों की समस्या है। सम्पूर्ण देश में सरकार और स्थानीय संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के लिए विशेष रूप से निर्मित किए जाने वाले भवन केवल इतने हैं, जिनमें 50 प्रतिशत छात्र विद्या का अर्जन कर सकते हैं।<sup>2</sup> शेष विद्यालय विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों में चल रहे हैं। कुछ राज्यों में इनका नंचालन मन्दिरों, गाँवों की चौपालों, किराए के मकानों और धनी पुरुषों के निवास-स्थानों के थोड़े-से भागों में किया जा रहा है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जिनमें डेरों, भोंपड़ियों, गुने स्थानों या वृक्षों के नीचे शिक्षण-कार्य किया जा रहा है।<sup>3</sup>

उपरिनिर्दिष्ट सभी स्थान—विद्यालयों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। इसके कारण स्पष्ट हैं। अनेक विद्यालयों में शीत, वर्षा एवं उष्णता से किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। लगभग सभी विद्यालयों में वायु, प्रकाश एवं स्थान का अभाव है। कुछ विद्यालय दूषित अवस्था कोलाहलपूर्ण वातावरण में स्थित हैं। खेल का मैदान तो सम्भवतः किसी भी विद्यालय में नहीं है। इस प्रकार के विद्यालयों में लगभग 6 घंटे प्रतिदिन व्यतीत करने वाले बच्चे अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं और बहुधा ऐसे रोगों के चंगुल में फँस जाते हैं, जो आजीवन उनके कष्ट का कारण

1. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. I, p. 88.

2. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 105.

4. *Education in India*, 1958-59, Vol. I, p. 7.



तोसरा, जनता का सहयोग प्राप्त करके भी विद्यालय-भवनों के अभाव की बहुत-कुछ पूर्ति की जा सकती है। यदि सरकार—ग्राम-निवासियों को शिक्षण की सब सामग्री प्रदान कर दे, तो पहले शिक्षण-कार्य खुले स्थानों या वृक्षों के नीचे आरम्भ किया जा सकता है। उसके पश्चात् सरकार—भूमि एवं भवन-निर्माण की सामग्री की व्यवस्था करके, ग्राम-निवासियों को विद्यालय-भवन का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सरकार को यह परामर्श था :—“हमें ग्राम-निवासियों से अपील करनी चाहिए कि यदि हम उनके लिए भवन-निर्माण-सामग्री की व्यवस्था कर दें, तो वे अपने निवास करने के गृहों के समान विद्यालय-भवनों का निर्माण करें।”

“We should appeal to villagers that if we supply them with the raw material, they should build school houses of the same pattern as the houses in which they live.”—Late Maulana Abul Kalam Azad : *Schools for All*, p. 15.

10. समस्या—अपव्यय व अवरोधन : Wastage & Stagnation—  
प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की भीषण समस्या है। “कोठारी कमीशन” के अनुसार :—निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय क्रमशः 56% एवं 62% है और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात क्रमशः 24% एवं 34% है।<sup>1</sup> इसी प्रकार, जैसा कि “कोठारी कमीशन” के प्रति-वेदन में अंकित है<sup>2</sup> :—अवरोधन, बालकों की कक्षा 1 में 40.3%, कक्षा 4 में 21.7%, और कक्षा 8 में 13.2% है। बालिकाओं की इन तीन कक्षाओं में अवरोधन क्रमशः 47.1%, 25.6% और 16.4% है।

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—अपव्यय एवं अवरोधन का निवारण करने के लिए अग्रांकित उपायों का प्रयोग किया जा सकता है :—(1) पाठ्यक्रम में सुधार, (2) परीक्षा-प्रणाली में सुधार, (3) शिक्षा-व्यवस्था में सुधार, (4) विद्यालय के अन्दर और बाहर के वातावरण में सुधार, (5) अभिभावकों की शिक्षा, (6) उत्तम विद्यालयों की व्यवस्था, (7) शिक्षण-विधियों की रोचकता, (8) सामाजिक समस्याओं का समाधान, (9) छात्रों के स्वास्थ्य की उन्नति, और (10) शिक्षा एवं जीवन में उचित सम्बन्ध की स्थापना।

टिप्पणी—अधिक अध्ययन के लिए “अपव्यय व अवरोधन” अध्याय देखिए।

11. समस्या—भाषाओं का बाहुल्य : Multiplicity of Languages—  
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में भाषाओं का बाहुल्य असाधारण अवरोध उत्पन्न कर रहा है। “भारत”, 1973 (p. 17) के अनुसार :—हमारे देश में

1. Kothari Commission Report, p. 157.

2. Kothari Commission Report, p. 156.

826 भारतीय एवं गैर-भारतीय भाषाएँ और 1,652 बोलियाँ (मातृभाषाएँ) बोली जाती हैं। देश के प्रभागों तथा शिक्षाविदों के समस्त समझा यह है कि इतनी विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों का प्रयोग करने वाले बालकों एवं बालिकाओं को निम्न भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाय ?

भारतीय संविधान में जिन 15 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, वे इस देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती हैं। अतः उनको शिक्षा का माध्यम बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। किन्तु, केवल 811 भाषाओं को इस पद पर आसीन करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य कठिनाई यह है कि भारत में ऐसी अनेक जातियाँ हैं, जिनका न तो कोई साहित्य है और न कोई बोली। इनमें उत्तेजनयोग्य है :—अनुसूचित एवं आदिम जातियाँ (Scheduled Castes & Tribes), जिनकी संख्या लगभग 6.44 करोड़ और 3.01 करोड़ है<sup>1</sup>, और निर्वासित आदिम जातियाँ (Denotified Tribes), जिनकी संख्या 40 लाख है।<sup>2</sup> ये सभी जातियाँ पिछड़ी हुई हैं और इनमें अभी तक शिक्षा का बहुत कम प्रसार हुआ है।

समाधान—विशेष विद्यालय . Special Schools—भारत के जिन भूभागों में आदिम, अनुसूचित एवं पिछड़ी हुई जातियाँ निवास करती हैं, उनमें अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करने का सर्वोत्तम उपाय है—विशेष विद्यालयों की स्थापना। भारत सरकार इन विद्यालयों की स्थापना का कार्य उत्साहपूर्वक कर रही है, 6,000 से अधिक विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कर चुकी है, और इनमें अध्ययन करने वाले छात्रों को पुस्तकों, वेगन-नामपत्री आदि की सुविधाएँ भी प्रदान कर रही है।<sup>3</sup>

उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों के योग्य विद्यार्थियों को और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्येक आवेदन-कर्ता को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। सन् 1973 तक इन दोनों जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने में 80 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये जा चुके हैं।<sup>4</sup>

12. समस्या—प्रेरणा का अभाव : Lack of Incentive—अनिवार्य शिक्षा के विस्तार में बाधा उत्पन्न करने वाली अन्तिम समस्या है—प्रेरणा का अभाव। यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रामाण्य जनता निर्धन है और प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक

1. *India*, 1971-72, p. 129.

2. *Fourth Five-Year Plan, A Draft Outline* p. 383

3. *India*, 1971-72, p. 135.

4. *भारत*, 1973, p. 133.

विद्यालय नहीं है। निर्धन अभिभावक अपने बालकों को अपने ग्रामों के विद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ ही समय के लिए भेजते हैं, या बिल्कुल नहीं भेजते हैं। जहाँ तक उनको अन्य ग्रामों के विद्यालयों में भेजने का प्रश्न है, इसकी वे अभिभावक कभी कल्पना भी नहीं करते हैं।

इसका कारण यह है कि बालकों को विद्यालय जाने में और अभिभावकों को उनको भेजने में दो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बालक प्रातः-काल भोजन करके अपने गृहों से चलते हैं और सायंकाल को वापिस आने पर ही भोजन के दर्शन करते हैं। इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निर्धन अभिभावकों को अपने बालकों की पुस्तकों, लेखन-सामग्री एवं शिक्षा-सम्बन्धी अन्य व्यय का भार वहन करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में न तो बालक—विद्यालय जाने के लिए उत्सुक रहते हैं और न अभिभावक उनको भेजने के लिए।

समाधान—सहायक सेवाएँ : Ancillary Services—उल्लिखित समस्या का समाधान करने के लिए विद्यालयों में सहायक सेवाओं की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है। इन सेवाओं में निःशुल्क मध्याह्न भोजन, पाठ्य-पुस्तकों, लेखन-सामग्री, चिकित्सा आदि को स्थान दिया जाना चाहिए। ये सेवाएँ या सुविधाएँ ऐसी प्रबल प्रेरक शक्तियों का कार्य करेंगी कि स्वयं बालक—विद्यालय जाने का आग्रह करेंगे और अभिभावक उन्हें भेजने के लिए तत्पर रहेंगे।

सहायक सेवाओं के महत्त्व से मनी-भांति परिचित होने के कारण सरकार ने पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में इनके लिए पृथक् धनराशियाँ निर्धारित की थीं और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 112 करोड़ रुपए मध्याह्न भोजन पर एवं लगभग 160 करोड़ रुपए अन्य सहायक सेवाओं पर व्यय करने का निश्चय किया है।<sup>1</sup>

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. What, in your opinion, are the major problems of compulsory primary education in India? What suggestions can you offer to tackle them?

आपके विचारानुसार भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएँ क्या हैं? उनके समाधान के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं?

2. What are the main difficulties in the way of progress of free and compulsory education in India? What suggestions has the Kothari Commission given to remove them?

1. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 207.

भारत में निशुद्ध तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाईयों क्या हैं ? कोटारी आयोग ने उनको सुलझाने के लिए क्या प्रस्ताव दिए हैं ?

3. "Our primary schools today are no more than mere sheep-yards." Comment critically giving reasons. Also give your suggestions in the light of the recommendations made from time to time by the various Education Commissions to improve the conditions of the Primary Schools in our country.

"हमारे प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय केवल भेड़-बकरियों के बाटे जैसे बनकर रह गए हैं।" इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कारणों सहित कीजिए। देश में प्राथमिक शिक्षा की इस दुर्दशा के सुधार हेतु, विभिन्न शिक्षा-आयोगों द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों के मद्देन में अपने सुझाव दीजिए।

4. The target of free and compulsory education for all children up to the age of fourteen years as laid down in the Constitution of India has not been achieved as yet. What are the general causes which impede the progress in this direction ? What would you suggest to achieve the target mentioned ?

भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रत्येक बालक एवं बालिका को चौदह वर्ष की आयु तक निशुद्ध तथा अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इस दिशा में उन्नति को प्रवर्द्ध करने वाले सामान्य कारण क्या हैं ? उल्लिखित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके क्या सुझाव हैं ?

5. Write short notes on —(a) Gokhale's Bill, (b) Early efforts for compulsory education in India, and (c) Importance of Ancillary Services in Primary Schools

प्रदत्त विषय पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए — (अ) गोखले का विधेयक, (ब) भारत में अनिवार्य शिक्षा के प्राथमिक प्रयास और (स) प्राथमिक विद्यालयों में सहायक सेवाओं का महत्व।



# 24

## माध्यमिक शिक्षा

### SECONDARY EDUCATION

"If you want to feel the generations rushing to waste like rapids—yes like rapids—you should put your heart and mind into a private school."

—H. G. Wells.

#### विषय-प्रवेश

संयोजन के दृष्टियों में<sup>1</sup> :—“माने संसार के मौखिक क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के काम करने के प्रति गहरा असंतोष रहा है और वे काफी समय से यह अनुभव करने लगे हैं कि उनकी आसुर पुनर्रचना सम्पूर्ण आवश्यक है। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत-से बहुमूल्य परिवर्तन हुए हैं और स्वयं हमारे देश में बुनियादी शिक्षण-पद्धति ने उसकी समस्याओं के प्रति एक दिल्कुल ही नया रवैया अपनाया है, पर माध्यमिक शिक्षा अभी कुछ समय पहले तक कुल मिलाकर गतिहीन तथा अक्षरिहित रही है।”

हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा गतिहीन तथा अक्षरिहित क्यों नहीं है और इसमें सुनिश्चितता तथा परिचलनशीलता का क्या, क्यों एवं कैसे समावेश हुआ ?—इन सवालों की जानकारी प्रदान करने के लिए हम अधोलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के इतिहास पर विवेकपूर्ण दृष्टिकान कर रहे हैं; यथा :—

1. जे० जी० संयोजन : शिक्षा की पुनर्रचना, पृ० 165-166.

## माध्यमिक शिक्षा—स्वतन्त्रता से पूर्व Secondary Education Before Independence

हम स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा के इतिहास में उन सीमा-चिह्नों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा का गूत्रपात करके, उसके प्रसार में योग दिया एवं समय-समय पर उसके स्वरूप, संगठन आदि में परिवर्तन करने का प्रयास किया।

1. माध्यमिक शिक्षा का गूत्रपात—माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक युग की देन स्वीकार किया जाता है। वैदिक-युगीन एवं मध्ययुगीन शिक्षा-व्यवस्था में शिक्षा के केवल दो ही स्तर थे—प्राथमिक एवं उच्च। भारत में माध्यमिक शिक्षा का गूत्रपात करने का श्रेय—यूरोपीय मिशनरियों को प्राप्त है। उन्होंने 18वीं शताब्दी के अन्त में इस देश के कुछ भागों में माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की। उनके उदात्त उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त करके, 19वीं शताब्दी के आरम्भ में कतिपय राष्ट्र-प्रेमी भारतीयों ने उनके चरण-चिह्नों का अनुगमन करके, माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया। डा० एस० एन० मुकुर्जी के अनुसार<sup>1</sup> —“माध्यमिक स्कूलों की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य—यानी भारतीयों को अपने अग्रज शासकों की भाषा को सीखने की भाँग की पूर्ति करना था।”

2. माध्यमिक शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था—माध्यमिक शिक्षा को अपनी प्रारम्भिक अवस्था में भारत के अग्रज शासकों ने समय-समय पर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उसने प्रगति के पथ पर अपनी यात्रा आरम्भ की। उसे यह प्रोत्साहन निम्नांकित 4 रूपों में प्राप्त हुआ —

- (i) 1830 में कम्पनी के सचालकों ने अपने एक पत्र द्वारा फोर्ट सेंट जार्ज (मद्रास) के गवर्नर को यह आदेश दिया कि प्रशासन-कार्य में भारतीयों की सहायता प्राप्त करने के लिए उनको अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाय।<sup>2</sup>
- (ii) 1835 में लार्ड विलियम बैंटिन्क ने मंत्रालय के “विवरण-पत्र” को स्वीकार करके, यह निश्चय किया कि शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला सम्पूर्ण धन, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से चलाई जाने वाली कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यय किया जायगा।<sup>3</sup>

- 
1. S. N. Mukerji. *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 111.
  2. Letter from the Court of Directors to the Governor in Council of Fort St. George, September 29, 1830.
  3. Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Vol. III, pp. 1938-39.

(iii) 1837 में अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बना दिया गया।

(iv) 1844 में लार्ड हाटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त भारतीयों के लिए कम्पनी की नौकरियों के द्वार खोल दिए।

कम्पनी की इन नीतियों एवं निश्चयों के फलस्वरूप भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए सन् 1852 तक सम्पूर्ण भारत में 32 मान्यता-प्राप्त स्कूलों का निर्माण हो गया।

3. 1854 का ब्रुट का आदेश-पत्र—इस “आदेश-पत्र” में माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित निम्नांकित 3 मुख्य बातें थीं :—

- (i) “आदेश-पत्र” में यह घोषणा की गई कि भारत के निवासियों को यूरोप के लेखकों की पुस्तकों और वहाँ के निवासियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले ज्ञान से परिचित कराया जाय। इस घोषणा ने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में प्रणसनीय योग दिया।
- (ii) “आदेश-पत्र” ने विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने के लिए “सहायता-अनुदान-प्रणाली” को प्रचलित करने का सुझाव दिया। इस सुझाव ने नवीन माध्यमिक स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया।
- (iii) “आदेश-पत्र” ने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आज्ञा दी। ये विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित कर दिए गए और उनको मेट्रीकुलेशन की परीक्षा लेने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिकार ने माध्यमिक शिक्षा पर विश्वविद्यालयों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। वे अपने हित को ध्यान में रखकर माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम, शिक्षा के माध्यम आदि के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक शिक्षा में दो दोष प्रकट हो गए। वह स्वतः पूर्ण इकाई नहीं रह गई और उसका एकमात्र उद्देश्य—छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना हो गया।

4 1882 का हंटर कमिशन—इस कमिशन ने माध्यमिक शिक्षा को अत्यधिक साहित्यिक होने के दोष से मुक्त करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों (Diversified Courses) का सुझाव दिया। उसने यह विचार व्यक्त किया कि हाई स्कूल की शिक्षा को दो भागों में विभक्त कर दिया जाय :—‘अ’ कोर्स एवं ‘ब’ कोर्स (‘A’ Course & ‘B’ Course)। ‘अ’ कोर्स का उद्देश्य—छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना हो। ‘ब’ कोर्स का उद्देश्य—छात्रों को व्यावसायिक एवं असाहित्यिक कार्यों के लिए तैयार करना हो। कमिशन के सुझाव एवं विचार के प्रति न तो सरकार ने ध्यान दिया और न जनता ने। फलतः माध्यमिक शिक्षा का अपने पूर्व रूप में प्रसार होता रहा और उस पर विश्वविद्यालयों का प्रभुत्व बर्थावत बना रहा।



कि निम्न माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी के अध्ययन पर बल न दिया जाय और हाई स्कूल तक की सब कक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय ।

9. 1944 की साजेंट रिपोर्ट—इस रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए 3 अत्यन्त उपयोगी सुझाव दिए गए :—(i) हाई स्कूलों में केवल असाधारण योग्यता के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाय; (ii) प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य कर दिया जाय; और (iii) साहित्यिक एवं प्राविधिक (Academic & Technical)—दोनों प्रकार के हाई स्कूलों की स्थापना की जाय । यदि इन सुझावों को क्रियान्वित कर दिया गया होता, तो आज माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप ही भिन्न होता ।

उपयुक्त विवरण इस बात का साक्षी है कि स्वतन्त्रता से पूर्व माध्यमिक शिक्षा को स्थानांतरित करने और उसे वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी बनाने के विचार से समय-समय पर आयोगों, समितियों आदि के द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए । किन्तु, विदेशी सरकार की उदासीनता के कारण न तो वह समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनी और न उसके स्वरूप में ही कोई विशेष परिवर्तन हुआ । सन् 1943 में इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए, हैम्पटन ने लिखा :—“थोड़े-से महत्वपूर्ण अपवादों के अलावा आज का भारतीय हाई-स्कूल वंसा ही है, जैसा कि वह 1904 में था, पर उससे थोड़ा-सा अवश्य भिन्न है, जैसा कि वह बहुत समय पहले 1884 में था ।”

“The Indian high school with a few notable exceptions is much the same today as it was in 1904, but little changed from what it was as far back as 1884.”—H. V. Hampton : *The Education System*, “Secondary Education”, 1943, p. 31.

### माध्यमिक शिक्षा—स्वतंत्रता के पश्चात् Secondary Education After Independence

स्वतंत्र भारत में नियुक्त की जाने वाली निम्नांकित समिति एवं आयोगों ने माध्यमिक शिक्षा को गतिशील बनाने और उसको देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की चेष्टा की है :—

(1) 1948 की ताराचन्द समिति (Tarachand Committee)—इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा को जीवनीययोगी बनाने के लिए यह सुझाव दिया कि बहु-उद्देशीय माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की जाय ।

(2) 1948-49 का राष्ट्राध्यक्षन कमीशन—इस कमीशन ने भारतीय शिक्षा-प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा की गवने निर्वल कड़ी बताया और उनमें सुधार किए जाने पर बल दिया । स्वयं “कमीशन” के शब्दों में :—“हमारी शिक्षा-व्यवस्था में





माध्यमिक और उच्च। जब तक शिक्षा का बिभाजन इन तीन स्तरों में नहीं किया जायगा, तब तक माध्यमिक शिक्षा की सीमाएँ अनिश्चित रहेंगी और उसमें किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना असम्भव होगा।

4. समस्या—धन का अभाव : Dearth of Money—माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के मार्ग में धनाभाव ने प्रायः एक अजेय अवरोध उपस्थित कर दिया है। भारत के अधिकांश माध्यमिक स्कूल धनाभाव के कारण अपने छात्रों का शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास करने में पूर्णतया असफल होते हैं। धनाभाव का मुख्य कारण यह है कि ये स्कूल बहुत-कुछ छात्रों से प्राप्त होने वाले शुल्क से चलते हैं। 25 प्रतिशत में अधिक व्यक्तित्व माध्यमिक स्कुलों को सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।<sup>1</sup> सरकार की आर्थिक सहायता के अभाव में किसी भी स्कूल का कुशलतापूर्वक कार्य करना असम्भव है। यह सहायता इसलिए और अधिक आवश्यक है, क्योंकि स्कूलों को राज्य द्वारा छात्रों के लिए अधिक-से-अधिक पाठ्य-विषयों की शिक्षा और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था करने के लिए बाध्य किया जाता है। जब तक इन कार्यों के लिए स्कूलों को सहायता-अनुदान के रूप में सरकार से पर्याप्त धन नहीं मिलेगा, तब तक उनमें कार्य-क्षमता का अभाव अनिवार्य रूप में बना रहेगा।

समाधान—निश्चित आर्थिक नीति Definite Financial Policy—माध्यमिक स्कूलों की धनाभाव की समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों द्वारा निश्चित आर्थिक नीति का अनुमरण किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में “अन्तर्राष्ट्रीय टीम”<sup>2</sup> और ‘माध्यमिक शिक्षा-प्रायोग’<sup>3</sup> के निम्नलिखित सुझाव सामग्रद गिज्ञ हो मवते हैं —

1. केन्द्रीय सरकार को कुछ सीमा तक माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए और इस शिक्षा के पुनर्गठन के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
2. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य-सरकारों को पारस्परिक सहयोग से अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण करना चाहिए।
3. विद्यालयों को अपनी गुणात्मक उन्नति करने के लिए सरकार से समय-समय पर अतिरिक्त सहायता-अनुदान मिलना चाहिए।

5. समस्या—निर्देशन का अभाव : Absence of Guidance—भारत के अनेक माध्यमिक स्कूलों में निर्देशन का अभाव है। इन स्कूलों में निर्देशन न केवल

1. S. N. Mukerji . *op. cit.*, p. 159.

2. Report of the International Team, pp. 105-121.

3. Secondary Education Commission Report, p. 227.



छात्रों की दृष्टि से, चरन् शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की दृष्टि से भी आवश्यक है। छात्रों की दृष्टि से इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अपरिपक्व मस्तिष्क वाले होने के कारण वे अपनी क्षमताओं के अनुकूल पाठ्यविषयों का चयन करने में असमर्थ होते हैं। दृष्टिपूर्ण चयन का परिणाम होता है—परीक्षा में उनकी असफलता और असफलता—अपव्यय का कारण बनती है। जहाँ तक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का प्रश्न है, निर्देशन उनको अपने छात्रों की अभिरूचियों एवं योग्यताओं का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे सम्पन्न होकर वे उनकी शैक्षिक प्रगति में अधिक योग दे सकते हैं।

**समाधान—निर्देशन की व्यवस्था : Provision for Guidance—**“माध्यमिक शिक्षा-आयोग” की सिफारिश के अनुसार, भारत के 13 राज्यों में निर्देशन-सेवाओं (Guidance Services) की व्यवस्था कर दी गई है, जिनसे लगभग 3,000 माध्यमिक स्कूलों के छात्र, शिक्षक एवं प्रधानाचार्य लाभान्वित हो रहे हैं।<sup>1</sup> “India”, 1974 (p. 50) के अनुसार, इन समय भारत में हाई और हायर सेकण्डरी स्कूलों की संख्या 35,773 से अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि अब तक छात्रों को निर्देशन प्रदान करने की दिशा में जो कार्य किया गया है, वह केवल नाममात्र के लिए है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत के प्रत्येक हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल के छात्रों के लिए निर्देशन-सेवाओं को सुलभ बनाया जाय। “कोठारी-कमीशन” ने इस बात पर बल देते हुए लिखा है :—“अन्तिम लक्ष्य—सब माध्यमिक स्कूलों में पर्याप्त निर्देशन-सेवाओं को आरम्भ करना होना चाहिए।”

“The ultimate objective should be to introduce adequate guidance services in all secondary schools.”—*Kothari Commission Report*, p. 239.

6. समस्या—व्यावसायीकरण का अभाव : Absence of Vocationalization—“कोठारी-कमीशन” ने अपना प्रतिवेदन अग्रांकित वाक्यों से आरम्भ किया है :—“इन समय भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन-रक्षों में हो रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित आज के विश्व में शिक्षा ही व्यक्तियों की सम्पन्नता, समृद्धि एवं सुरक्षा के स्तर को निश्चित करती है।”

“The destiny of India is now being shaped in her classrooms. In a world based on science and technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare, and security of the people.”—*Kothari Commission Report*, p. 1.

हमारे देश की सम्पन्नता, समृद्धि एवं सुरक्षा का दायित्व निस्सन्देह रूप से ज्ञान की पीढ़ी पर है और वह इस दायित्व को तभी पूर्ण कर सकती है, जब शिक्षा—



यह नहीं दिया जायगा, तो युग की बदलती हुई मान्यताओं के बीच हमारा देश, जो विश्व के प्रगतिशील देशों की तुलना में अब भी सीढ़ियों पर पीछे है और पीछे रह जायगा। मान्यता का हम दृढ़तापूर्वक देश में उद्यार करते और उसे प्रगति की ओर पीछे न रहने देने के लिए, "कोटारी-कमीशन" का परामर्श है :—“हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता पर विशेष रूप से ध्यान देने हैं।”

“We must emphasize particularly the need to vocationalize higher secondary education.”—Kothari Commission Report, p. 34.

“कोटारी-कमीशन” ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर धन क्यों दिया है? इसका मुख्य कारण यह है कि माध्यमिक स्तरों में विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्रदान करने के उपरान्त, छात्र या तो स्वयं किसी व्यवसाय को स्वतन्त्र रूप में कर सकते हैं, या किसी व्यावसायिक समूह में प्रवेश करके अपनी जीविका का पर्याप्तता में धारण कर सकते हैं। हमें न केवल उनका, बल्कि मान्यता की औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगहों का और जनसंख्या देश का भी हित होगा। स्वतन्त्र भारत औद्योगीकरण की दिशा में अग्रसर होने के लिए कटिबद्ध है। देश में कितने ही उद्योगों एवं भवनियों की स्थापना हो चुकी है और विस्तृत होती जा रही है। इन सक्षम उद्योग—भारत के उत्पादन में वृद्धि करना है, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विदेशियों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। किन्तु, उत्पादन में वृद्धि करने की एक आवश्यक बात है—कुशल कार्यकर्ताओं की प्राप्ति, जिनकी शिक्षा का व्यावसायीकरण करके पैदा किया जाना है। इसी बात को ध्यान में रख कर, “कोटारी कमीशन” ने व्यावसायीकरण द्वारा शिक्षा एवं उत्पादन में सम्बन्ध स्थापित करने का सुझाव दिया है। “कमीशन” के मन्तव्यों में :—“माध्यमिक विद्यालय-स्तर पर विशेष रूप से शिक्षा का व्यावसायीकरण करके, शिक्षा एवं उत्पादन में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।”

“The link between education and productivity can be forged through vocationalization of education, especially at the secondary school level.”—Kothari Commission Report, p. 6.

समाधान—व्यावसायीकरण की व्यवस्था : Provision for Vocationalization—उपरोक्त नीतियों में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के विषय में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों की जीवन-समस्याओं और देश की औद्योगिक-व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाना परम आवश्यक है। इस तथ्य की और जनता एवं सरकार का समर्थन हासिल करने हेतु, “कोटारी कमीशन” ने लिखा है :—“माध्यमिक शिक्षा की यह पैमाने पर व्यावसायिक बनाया जाय और 1986 तक व्यावसायिक

पाठ्यक्रमों की अध्ययन करने वाली छात्र-संख्या को निम्न माध्यमिक स्तर पर सम्पूर्ण छात्र-संख्या का 20 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सम्पूर्ण छात्र-संख्या का 50 प्रतिशत कर दिया जाय।”

“Secondary education should be vocationalized in a large measure and enrolments in vocational courses raised to 20 per cent of total enrolment at the lower secondary stage and 50 per cent of total enrolment at the higher secondary stage by 1968.”—*Kothari Commission Report*, p. 634.

उक्त सध्यों की प्राप्ति के लिए, “कमीशन” ने अनेक सुझाव दिए हैं; यथा :—

1. निम्न माध्यमिक स्तर • Lower Secondary Stage—जो छात्र, कक्षा 7 या 8 के पश्चात् अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं, उनको व्यावसायिक शिक्षा की निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जायें :—

1. औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं (Industrial Training Institutes) में प्रवेश करने की आयु को कम करके 14 वर्ष कर दिया जाय।
2. टेकनिकल स्कूलों में चलाए जाने “अन्तिम पाठ्यक्रमों” (Terminal Courses) में अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाय।
3. छात्रों के लिए कृषि-शिक्षा एवं अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

2. उच्चतर माध्यमिक स्तर • Higher Secondary Stage—इस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जायें :—

1. पॉलीटेक्नीको में पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाय।
2. उद्योगों में अल्पकालीन, पूर्णकालीन एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में विस्तार किया जाय।
4. पत्राचार-पाठ्यक्रमों (Correspondence Courses) द्वारा विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने का कार्य शीघ्रतिशीघ्र आरम्भ किया जाय।

हमें इस बात की आशा है कि “कोठारी कमीशन” के सुझावों को क्रियारमक रूप प्रदान करके, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जा सकता है, जिससे उन अनेक समस्याओं का शमन हो सकता है, जो इस समय विकराल रूप धारण किए हुए हैं। किन्तु, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान करने के लिए घन की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति केवल सरकार द्वारा ही की जा सकती है। अतः यह आवश्यक है कि व्यावसायिक विषयों की शिक्षा का आयोजन करने के लिए, केन्द्रीय

सरकार द्वारा राज्य-सरकारों को वार्षिक सहायता दी जाय। उस सम्बन्ध में "कोठारी कमीशन" ने संयुक्त राज्य अमरीका में व्यावसायीकरण के लिए संघीय अनुदानों की चर्चा की है। उन अनुदानों ने ही उस देश में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को सम्भव बनाया। अतः भारत-सरकार को संयुक्त-राज्य-अमरीका के उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करने का परामर्श देते हुए, "कोठारी कमीशन" ने लिखा है :—"संयुक्त राज्य अमरीका में माध्यमिक विद्यालयों के व्यावसायीकरण के लिए संघीय अनुदानों ने ही माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित किया। यह अनुभव भारत के लिए महत्वपूर्ण पाठ है।"

"It was the federal grants for vocationalization in secondary schools that stimulated the vocationalization of secondary education in the U. S. A. and this experience has a valuable lesson for India."—*Kothari Commission Report*, p. 174.

7. समस्या—सामुदायिक जीवन का अभाव : Absence of Community Life—कुछ बोर्डों-में माध्यमिक स्कूलों के अतिरिक्त जेप सभी में सामुदायिक जीवन का पूर्ण अभाव है। उनमें पर्यटन, खेल-कूद, गाने-बोल, व्यायाम और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विनोदात्मक कार्यों का कमी भूल कर भी आयोजन नहीं किया जाता है। परिणामतः न तो छात्रों में गारम्परिक सम्पर्क स्थापित हो पाता है और न उनमें आत्मीयता एवं घनिष्ठता की ही अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार, हाई स्कूल—शैक्षणिक उत्पादन-केन्द्रों के समान है, जिनका एकमात्र उद्देश्य—विज्ञान पैमाने पर मेट्री-कुलेशन-परीक्षा-प्राप्त छात्रों का उत्पादन करना है। वे छात्रों की जन्मजात क्षमताओं एवं व्यक्तित्व के विकास में केवलमात्र योग नहीं देने हैं। इसमें क्षुब्ध होकर, सर पी० सी० रे ने लिखा है :—"क्या हम अपने बालकों को मनुष्यों का रूप प्रदान कर रहे हैं? क्या हम उनको परीक्षा के लिए बोर्डों-से सम्बन्ध प्रश्नों के उत्तरों को बताने के अलावा और कुछ बता रहे हैं? क्या हम वास्तव में उनमें चिन्तन-शक्ति का और आत्म-सहायता एवं आत्म-निर्भरता के गुणों का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं?"

"Are we making men of our youths? Are we after all giving them any more than the answers to a few hundred probable questions? Are we really striving to develop in them the power of thinking, self-help and self-reliance?—Sir P. C. Ray. Quoted by S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 161.

सर पी० सी० रे की चिन्ता बहुत अवश्य है, पर, उसमें सत्य कूट-कूट कर भरा हुआ है। माध्यमिक स्कूलों का कार्य केवल छात्रों को सम्बन्ध प्रश्नों के उत्तर बताना ही नहीं है। उनका कार्य यह भी है कि वे छात्रों की सुगठित जीवन व्यतीत



भारत-सरकार के शिक्षा-सचिव, के० जी० सैयदैन के उपरिर्बंकित विचारों में पूर्ण सत्य का आभास पाकर, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, डा० ज़ाकिर हुसेन ने माध्यमिक स्कूलों के विषय में सरकार की यह नीति घोषित की :—“हमारी समस्त शिक्षा-संस्थाएँ—क्रियाशील सामुदायिक केन्द्र होंगी।”

“All over institutions will be communities at work.”—Dr. Zakir Husain's Radio Broadcast, published in *The Future of Education : A Symposium*.

8. समस्या—दोषपूर्ण पाठ्यक्रम : *Defective Curriculum*—लगभग एक शताब्दी पूर्व निमित्त किया जाने वाला पाठ्यक्रम अब भी सम्पूर्ण देश के लगभग सभी माध्यमिक स्कूलों में प्रचलित है। समयानुकूल न होने के कारण उसकी उपयोगिता नष्ट हो गई है और उसमें अनेक गम्भीर दोष प्रकट हो गए हैं। “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” के अनुसार, उनका उल्लेख अग्रांकित क्रम में किया जा सकता है<sup>1</sup> :—

1. पाठ्यक्रम—पुस्तकीय एवं सैद्धान्तिक है।
2. पाठ्यक्रम—नीरस, बोझिल एवं परम्परागत है।
3. पाठ्यक्रम—संकुचित एवं एकमार्गीय (Unilateral) है।
4. पाठ्यक्रम—किजोरों की विभिन्न रुचियों एवं आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता है।
5. पाठ्यक्रम पर परीक्षा का पूर्ण प्रभुत्व है।
6. पाठ्यक्रम में प्राविधिक एवं व्यावसायिक विषयों का अभाव है।
7. पाठ्यक्रम का छात्रों के वातावरण और वास्तविक एवं सामाजिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पाठ्यक्रम के उपर्युक्त दोषों के कारण छात्रों का जो अहित होता है, उस पर प्रकाश डालते हुए, “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” ने लिखा है :—“जब छात्र, स्कूल छोड़ते हैं, तब वे समाज से अस्वाम्यत्व का अनुभव करते हैं और वे उसमें अपने स्थान को विश्वास एवं गुरुत्वता से ग्रहण नहीं कर पाते हैं।”

“When students pass out of school, they feel ill adjusted and cannot take their place confidently and competently in the community.”—*Secondary Education Commission Report*, p. 18.

समाधान—विविध व व्यावसायिक पाठ्यक्रम : *Diversified & Vocational Courses*—पाठ्यक्रम के दोषों का निवारण इस बात को ध्यान में रखकर किया जा सकता है कि नव वास्तवों के लिए समान पाठ्यक्रम नहीं हो सकता है। उसमें विभिन्न वर्गों के छात्रों की अनिवृत्तियों, अभिरुचियों एवं भावी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य-विषयों का समायोजन किया जाना आवश्यक है। साथ ही, यह भी आवश्यक है

1. *Secondary Education Commission Report*, p. 61.





"For nearly half a century, the examination has been recognized as one of the worst features of Indian Education."

—*Radhakrishnan Commission Report*, p. 328.

परीक्षा को एक निकृष्टतम तत्त्व समझे जाने का कारण है, उसमें दोषों की प्रचुरता। इन दोषों में सर्वप्रमुख दोष यह है कि सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर मेट्री-कुलेशन परीक्षा का अग्रगण्य आधिपत्य है। प्रत्येक हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल की कार्य-क्षमता, प्रत्येक अध्यापक की शिक्षण-दक्षता और प्रत्येक छात्र की बौद्धिक योग्यता की केवल एक ही कसौटी है—परीक्षा। जहाँ तक छात्रों का सम्बन्ध है, यह कसौटी उनके लिए अभिजाप बन गई है, क्योंकि इसने उनमें अपराध की प्रवृत्ति को इतना मजबूत बना दिया है कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करने में रज्जुमात्र भी संकोच नहीं करते हैं।

"माध्यमिक शिक्षा-आयोग" ने परीक्षा के उपर्युक्त दोष की ओर शिक्षाविदों का ध्यान आकृष्ट किया है। उसका मत है कि बाह्य एवं आन्तरिक, दोनों परीक्षाओं का एकान्वी उद्देश्य—छात्रों की मानसिक एवं साहित्यिक उपलब्धियों की जाँच करना है। वे छात्रों के विकास के अन्य पक्षों की जाँच नहीं करती हैं, और यदि करती हैं, तो अप्रत्यक्ष एवं अविवक्षणीय रूप में। "आयोग" ने इसे परीक्षा का अत्यन्त प्राचीन एवं संकुचित कार्य बताया है। उसका कहना है कि 20वीं शताब्दी में परीक्षा के अर्थ और विस्तार में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। उसका कार्य केवल छात्रों के मानसिक एवं साहित्यिक विकास की ही जाँच करना नहीं है, बल्कि उनके चतुर्मुखी विकास की भी जाँच करना है।

"माध्यमिक शिक्षा-आयोग" ने बलपूर्वक घोषित किया है कि वर्तमान परीक्षा-प्रणाली द्वारा छात्रों के मानसिक एवं साहित्यिक उपलब्धियों की माप में विश्वसनीयता का अभाव है। इसका कारण यह है कि प्रचलित निबन्धात्मक प्रकार के प्रश्नों के मूल्यांकन में परीक्षक के मनोभाव का मूर्खन्य स्थान है। अतः उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंकों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इन तर्कों के आधार पर, "माध्यमिक शिक्षा-आयोग" ने अपने निष्कर्ष को अग्रगण्य वाक्य में निरावद्ध किया है :—"उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस समय तो जाने वाली परीक्षाओं की विधि हमको विद्यार्थियों की मानसिक उपलब्धियों का भी ठीक-ठीक मूल्यांकन करने में सहायता नहीं देती है।"

"It may be fairly inferred that as at present conducted, examinations do not help us to evaluate correctly even the intellectual attainments of the pupils."—*Secondary Education Commission Report*, p. 118.

समाधान—परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन : Change in Examination System—“माध्यमिक शिक्षा-आयोग” द्वारा दक्षित किए जाने वाले परीक्षा-प्रणाली

के दोषों से चिन्तित होकर, भारत-सरकार ने उनका निवारण करने का निर्णय किया। इस उद्देश्य से, उसने 1958 में "केन्द्रीय परीक्षा-यूनिट" (Central Examination Unit) की नियुक्ति की। इस "यूनिट" के प्रशिक्षित मूल्यांकन अधिकारियों ने मूल्यांकन की नवीन धारणा के अनुसार परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मूल्यांकन की नवीन धारणा के अनुसार, मूल्यांकन की विधियाँ ऐसी होनी चाहिए, जिनसे छात्रों के बहुभंगी विकास के सम्बन्ध में पूर्णतया सत्य प्रमाण उपलब्ध हो। यह तभी सम्भव है, जब ये विधियाँ—विश्वसनीय वस्तुपरक एवं व्यावहारिक (Reliable, Objective & Practicable) हो। मूल्यांकन की इस नवीन धारणा की व्याख्या करते हुए, "कोठारी कमीशन" ने लिखा है:—"मूल्यांकन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है एवं शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। यह छात्र की अध्ययन की आदतों एवं अध्यापक की शिक्षण-विधियों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार, मूल्यांकन न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में, अपितु उसमें सुधार करने में भी सहायता देता है।"

"Evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education, and is intimately related to educational objectives. It exercises a great influence on the pupil's study habits and the teacher's methods of instruction, and thus helps not only to measure educational achievement, but also to improve it."

—Kothari Commission Report, p 243

"मुद्रालियर कमीशन" ने अपने परिपत्रव अनुम्व एव "कोठारी कमीशन" ने मूल्यांकन की नवीन धारणा के आधार पर समकालीन माध्यमिक परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं —

1. माध्यमिक शिक्षा के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् केवल एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाय।
2. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जायें और वे पाठ्यक्रम के अधिक-से-अधिक क्षेत्र पर आधारित किए जायें।
3. आन्तरिक जाँचों (Internal Assessments) को स्थापक बना कर, उनके द्वारा छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाय।
4. बाह्य एव आन्तरिक परीक्षाओं में छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन — अंकों में न किया जाकर, प्रतीकों (Symbols) में किया जाय।
5. बाह्य परीक्षाओं द्वारा छात्रों की उपलब्धियों का अन्तिम मूल्यांकन करने समय, आन्तरिक जाँचों और नियतकालिक जाँचों (Periodical Tests) को उचित महत्त्व दिया जाय।

10. समस्या—शिक्षण का निम्न स्तर : Low Standard of Teaching—वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की एक विकट समस्या—शिक्षण का निम्न स्तर है। पिछले कुछ वर्षों से माध्यमिक शिक्षा की संरचना (Pattern) को नवीन स्वरूप प्रदान करने के लिए, उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके उद्देश्यों, पाठ्यविषयों एवं कार्यक्रमों में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। परिणामतः आज के माध्यमिक स्कूल 10 या 15 वर्ष पहले के माध्यमिक स्कूल नहीं हैं। उनको अनेक नवीन कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। उनकी सफलता मुख्यतः दो बातों पर निर्भर है—उपयुक्त शिक्षण-विधियाँ एवं उत्साही शिक्षक।

जहाँ तक शिक्षण-विधियों का प्रश्न है, वे सर्वथा अनुपयुक्त हैं। इसका कारण यह है कि प्रचलित शिक्षण-विधियाँ केवल कुछ सीमा तक छात्रों का मानसिक विकास करती हैं। वे निर्जीव, नीरस एवं अमनोवैज्ञानिक होने के कारण न तो छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर प्रतिक्रिया करती हैं और न उनके समस्त गुणों का विकास करने में सहायता देती हैं। जहाँ तक उत्साही शिक्षकों का प्रश्न है, उनकी उपलब्धि की सुदूर भविष्य में भी आशा नहीं है। इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए “माध्यमिक-शिक्षा-आयोग” ने लिखा है :—“हमें इस बात से अत्यधिक दुःख हुआ कि शिक्षकों की सामाजिक स्थिति, वेतन और कार्य की दशाएँ अत्यन्त असंतोषजनक हैं। वास्तव में, हमारा सामान्य विचार यह है कि समग्र रूप में उनकी स्थिति पहले से बहुत अधिक सराव है।”

We were painfully impressed by the fact that the social status, the salaries, and the general service conditions of teachers are far from satisfactory. In fact, our general impression is that on the whole their position today is even worse than it was in the past.”  
—Secondary Education Commission Report, p. 126.

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—वर्तमान माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण-स्तर को समुन्नत बनाने के लिए दो सुझाव दिए जा सकते हैं—शिक्षण की विधियों एवं शिक्षक की स्थिति में सुधार। शिक्षण-विधियों के सुधार के सम्बन्ध में “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” ने जो सुझाव दिए हैं, वे प्रशंसनीय हैं और उनकी प्रमुख विनियमाएँ निम्नांकित हैं :—

1. शिक्षण-विधियों में “क्रिया-पद्धति” (Activity Method) एवं “योजना-पद्धति” (Project Method) का प्रमुख स्थान होना चाहिए।
2. शिक्षण-विधियों को छात्रों को व्यक्तिगत प्रयासों से ज्ञान का अर्जन करने और उसे प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए।
3. शिक्षण-विधियों को छात्रों में कार्य की प्रेम, कुशलता, ईमानदारी और पूर्ण रूप से करने की चकित्ताजी इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए।



Education Policy) में यह स्पष्ट कर दिया है कि माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। ये भाषाएँ इस प्रकार हैं<sup>1</sup> :—

1. हिन्दी-भाषी राज्यों में—हिन्दी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, जिसमें दक्षिण की कोई भाषा होनी चाहिए।

2. अहिन्दी-भाषी राज्यों में—हिन्दी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी।

“मुद्रानियंत्रण” और “कोठारी” आयोगों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर छात्रों की भाषाओं के अतिरिक्त लगभग 7 और विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है। इस प्रकार, 3 भाषाओं सहित कुल विषयों की संख्या लगभग 10 हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र साधारणतः 11-17 वय-वर्ग के होते हैं। इस वय-वर्ग के बच्चों के लिए 10 विषयों का पाठ्यक्रम निस्संदेह रूप से अत्यधिक बोझिल है। अतः उनमें अन्य विषयों के साथ-साथ भाषाओं की संख्या में भी कमी की जानी आवश्यक है।

समाधान—दो भाषाओं का अध्ययन : Study of Two Languages—माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की आयु एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उचित तो यही जान पड़ता है कि उनके लिए दो भाषाओं का अध्ययन बहुत काफी है। तीन भाषाओं के अध्ययन के दो दुष्परिणाम हो सकते हैं। या तो वे इनका अपूर्ण अध्ययन करें, या इनका पूर्ण अध्ययन करने के लिए अन्य विषयों का अपूर्ण अध्ययन करें। ये दोनों ही बातें स्पष्ट रूप से उनके हित के प्रतिकूल हैं। दो भाषाओं का अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए :—

1. हिन्दी-भाषी राज्यों में—हिन्दी और एक आधुनिक भारतीय भाषा।

2. अहिन्दी-भाषी राज्यों में—मातृभाषा और हिन्दी।

हम सरकार के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि 3 भाषाओं में से एक अंग्रेजी होनी चाहिए। हाँ, यदि छात्र चाहें, तो वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन कर सकते हैं। यह हम स्वीकार करते हैं कि अंग्रेजी—विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है, पर हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। सम्भवतः इसकी पृष्ठ-भूमि में यह धारणा है कि अंग्रेजी का अध्ययन न करने से भारत, औद्योगिक या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पीछे रह जायगा। पर यह धारणा निराधार है। रूस, जर्मनी और जापान के उदाहरण सामने हैं, जहाँ अंग्रेजी का गौण स्थान है। फिर भी, किसी दृष्टि से किसी भी देश से पीछे नहीं हैं।

समुक्त विवेक

अंग्रेजी

रूस कह नहीं

त्य और

कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए केवल दो भाषाओं









India ? What changes will you like to introduce in this system, keeping in view our present demands ?

भारत की वर्तमान माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली में तात्कालिक एवं उच्च परिवर्तनों की आवश्यकता क्यों है ? इस प्रणाली को हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे ?

3. Secondary Education in India is said to be excessive in quantity and defective in quality. Discuss the reforms that you would like to introduce in Secondary Education.

भारत की माध्यमिक शिक्षा को संख्या में अत्यधिक, और गुण में दोषपूर्ण कहा जाता है। उन सुधारों को बताइए, जिनको आप माध्यमिक शिक्षा में करना चाहेंगे ?

4. Comment critically on the need of vocationalization of secondary education in India. What difficulties may arise in doing so and how can they be removed ?

भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता पर गंभीरतापूर्वक आलोचना लिखिए। ऐसा करने में क्या कठिनाइयाँ उठ सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है ?

## 25

### उच्च (विश्वविद्यालय) शिक्षा HIGHER (UNIVERSITY) EDUCATION

"There is a general feeling in India that the situation in higher education is unsatisfactory and even alarming"—Kothari Commission Report

#### विषय-प्रवेश

भारत में उच्च शिक्षा की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक काल में "आश्रम" एवं "गुरुकुल", उच्च शिक्षा के केन्द्र थे, जहाँ छात्रों को निश्चित समय तक अध्ययन करना पड़ता था। बौद्ध-काल में अनेक "मठों" एवं "विहारों" में उच्च शिक्षा की अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था थी। इस काल में नालन्दा, तक्षशिला और विजय-शिला के समान अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के अनेक विश्वविद्यालय थे, जहाँ सुदूर देशों के छात्र—अध्ययन करने के लिए आते थे। मध्य-युग में मुगलमनों ने दिल्ली, आगरा, अजमेर, ससनऊ आदि अनेक स्थानों पर उच्च अध्ययन के लिए "मदरसों" का निर्माण किया।

आधुनिक भारत में दिखाई देने वाली उच्च शिक्षा की व्यवस्था—अंग्रेजों की देन है और उसका हमारे देश की प्राचीन परम्परा से कोई सम्बन्ध नहीं है। ब्रिटिश-काल में उच्च शिक्षा की इस नवीन व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ और हमारे देश में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?—हम इसका वर्णन निम्नांकित पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहे हैं।

## उच्च शिक्षा का विकास

### Development of Higher Education

आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा के विकास का अध्ययन 4 स्पष्ट चरणों में किया जा सकता है; यथा<sup>1</sup> :—

1. कॉलेजों का युग : Era of Colleges.
2. प्रथम विश्वविद्यालयों का युग : Era of First Universities.
3. नवीन विश्वविद्यालयों का युग : Era of New Universities.
4. स्वतन्त्रता का युग : Era of Independence.

1. कॉलेजों का युग : Era of Colleges, 1757-1857—सन् 1751 में प्लासी के युद्ध के पश्चात् जब इस देश पर अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ, तब यहाँ की उच्च शिक्षा अत्यन्त अस्त-व्यस्त दशा में थी। अंग्रेजों ने भारत के हिन्दू एवं मुसलमान शासकों के समान यहाँ के निवासियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना अपना कर्त्तव्य समझा। इस दिशा में सबसे पहला कदम वारेन हेस्टिंग्स ने उठाया, जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए “कलकत्ता मदरसा” का निर्माण किया।

“कलकत्ता मदरसा” के निर्माण के उपरान्त 1857 तक उच्च शिक्षा के अनेक कॉलेजों की सृष्टि की गई, जिनमें उल्लेखनीय हैं :—बनारस संस्कृत कॉलेज; हिन्दू कॉलेज, कलकत्ता; क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास; पंचयण्या कॉलेज, मद्रास, और आगरा कॉलेज। इस काल में व्यावसायिक कॉलेजों का भी शिलान्यास किया गया, जिनमें अधिक महत्वपूर्ण थे :—कलकत्ता मेडिकल कॉलेज; बम्बई मेडिकल कॉलेज; और मद्रासी इंजीनियरिंग कॉलेज। सन् 1857 में सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में 27 कॉलेज थे, जिनमें से 23 सामान्य शिक्षा के, 3 चिकित्सा-शास्त्र के और<sup>1</sup> इंजीनियरिंग का कॉलेज था।<sup>2</sup>

2. प्रथम विश्वविद्यालयों का युग : Era of First Universities, 1857-1916—सन् 1854 के “वुड के आदेश-पत्र” (Wood's Despatch) के मुताबिक के अनुसार 1857 में लन्दन-विश्वविद्यालय के आदेश पर मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया गया। उस समय लन्दन-विश्वविद्यालय केवल परीक्षा देने का कार्य करना था। अतः इन तीनों विश्वविद्यालयों का कार्य भी इसी क्षेत्र तक सीमित रहा। इन्हीं विश्वविद्यालयों के हंग पर 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

ये दोनों विश्वविद्यालय विद्या के नवनों में स्थित थे और शिक्षण-कार्य से

1. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 173.
2. Nurullah & Naik : *History of Education in India*, p. 278.



की गई :—मैसूर विश्वविद्यालय, 1916; बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय, 1916; और पटना विश्वविद्यालय, 1917 ।

विश्वविद्यालय-जिज्ञा का जगता सीमा-चिह्न—1917 का “कलकत्ता विश्व-विद्यालय आयोग” (Calcutta University Commission) है। इन “आयोग” ने उक्त “प्रस्ताव” की नीति का समर्थन करते हुए, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की निष्कारिण की। इस निष्कारिण के परिणामस्वरूप 1947 तक अग्रांकित विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई :—उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1918; ढाका विश्व-विद्यालय, 1920; अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1921, लगनऊ विश्वविद्यालय, 1921; दिल्ली विश्वविद्यालय, 1922; नागपुर विश्वविद्यालय, 1923; आंध्र विश्वविद्यालय, 1926; आगरा विश्वविद्यालय, 1927; अदामलई विश्वविद्यालय, 1929; ट्रावनकोर विश्वविद्यालय, 1937; उत्कल विश्वविद्यालय, 1943, सागर विश्वविद्यालय, 1946; और राजपूताना विश्वविद्यालय, 1947 ।

4. स्वतन्त्रता का युग : Era of Independence, 1947-1974—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालयों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। इस समय भारत में 90 विश्वविद्यालय हैं; यथा<sup>1</sup> :—

(1) आगरा, (2) अलीगढ़, (3) इनाहाबाद, (4) आंध्र प्रदेश, कृपि, हैदराबाद, (5) आंध्र, बालदेयर, (6) अदामलई, तमिलनाडु, (7) आसाम, कृपि, जोरहाट, (8) अवधेश प्रतापसिंह, रोवा, (9) बनारस, (10) बंगलौर, (11) बरहाम-पुर, बंजम, (12) भागलपुर, बिहार, (13) भोपाल, (14) बिहार, मुजफ्फरपुर, (15) बम्बई, (16) बंबयान, पश्चिमी बंगाल, (17) कलकत्ता, (18) कालीकट, केरल, (19) कोचीन, (20) दिल्ली, (21) डिब्रूगढ़, (22) गोहाटी, (23) गोविन्द बल्लभ, कृपि, फजलनगर, (24) गोरखपुर, (25) गुजरात, आमुवेद, (26) गुजरात, अहमदाबाद, (27) गुजरात, कृपि, अहमदाबाद, (28) गुरु नानक, अमृतसर, (29) हरियाणा, कृपि, हिमाचल प्रदेश, जिमला, (30) हिमाचल प्रदेश, जिमला, (31) उन्धिरा कला संगीत, मेरगाट, (म० प्र०), (32) दम्बोर, (33) जबलपुर, (34) जायवपुर, कलकत्ता, (35) डम्बू, (36) जवाहरलाल नेहरू, कृपि, जबलपुर, (37) जवाहरलाल नेहरू, नई दिल्ली, (38) जोधाजी, ग्वालियर, (39) जौनपुर, (40) कल्याणी, पश्चिमी बंगाल, (41) रामेश्वरसिंह, दरभंगा, (42) कानपुर, (43) कर्नाटक, बागदाट, (44) काशी, श्रीनगर, (45) केरल, त्रिवेन्द्रम, (46) केरल, कृपि, त्रिचूर, (47) कोनकन, कृपि, रंगोली, (48) कुरुक्षेत्र, (49) लगनऊ, (50) मद्रास, (51) मदुराई, (52) मधुप, बुल नगा, (53) महाराज सायाशीराव, चट्टोडा, (54) महात्मा फुले, कृपि, रातुगे, (55) मराठावाड, औरंगाबाद, (56) मराठावाड, कृपि, परनाली,



के अन्तर्गत आस-पास के अनेक कॉलेज होते हैं और प्रत्येक कॉलेज—विश्वविद्यालय-स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। भारत में इस प्रकार के कुल 4 विश्वविद्यालय हैं; यथा :—दिल्ली विश्वविद्यालय, इन्दौर विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और बंगलौर विश्वविद्यालय।

भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा की प्रगति को निम्नांकित तालिका में स्पष्ट किया गया है :—

### विश्वविद्यालय-शिक्षा की प्रगति<sup>1</sup>

विवरण	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1970-71 अस्थायी
1. विश्वविद्यालय-स्तर पर कला, विज्ञान व वाणिज्य के कुल छात्र (स्नातकों में)	3.6	6.3	8.9	14.9	25.1
2. कला, विज्ञान (अनुसंधान संस्थाओं सहित) व वाणिज्य कॉलेजों की संख्या	542	772	1,222	1,788	2,792
3. विश्वविद्यालयों की संख्या	27	32	45	64	86

### समस्याएँ व उनके समाधान

#### Problems & Their Solutions

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से उसका संस्थात्मक विकास अत्यन्त द्बलित गति से हुआ है। साथ ही, दूसरी विशेष बात यह है कि उसका विकास आदि में अन्त तक अनियोजित रहा है। परिणामतः शिक्षा का स्तर गिर गया है, छात्रों में जानाजर्न की अभिवाता नष्ट हो गई है, शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, और सर्वोपरि उच्च शिक्षा—देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई है। अतः जैसा कि 'कोठारी कमिशन' ने लिखा है :—“भारत में सामान्य भावना यह है कि उच्च शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक एवं भयप्रद भी है।”

“There is a general feeling in India that the situation in higher education is unsatisfactory and even alarming.”—*Kothari Commission Report*, p. 278.

1. *India*, 1974, p. 50.

उच्च शिक्षा के प्रति हम सामान्य भावना के कारण हैं, उनमें परितुष्टि होने वाली यदुंरणी समस्याएँ। हम कुछ प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों की निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हैं।

(1) समस्या—उद्देश्यहीनता : *Aimlessness*—हमारी उच्च शिक्षा की उद्देश्यहीनता एक सर्वविदित तथ्य है। जमाना बदल गया है, देश की परिस्थितियाँ बदल गई हैं, पर मेद का विषय है कि उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य—भारत के अग्रज शासकों ने अपनी स्वायं-मिद्वि के लिए निर्धारित किया था, वह स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वर्षों बाद भी अपने पुरातन रूप में उच्च शिक्षा पर अपना अग्रज साम्राज्य स्थापित किए हुए है। परतन्त्र भारत में इस उद्देश्य के वास्तविक स्वरूप का वर्णन गणरा मिरडल के अग्रोक्त शब्दों में पटिए—“विश्वविद्यालयों की उपाधियों, सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्टों की। शिक्षा—विद्याधियों को नौकरी के लिए, न कि जीवन के लिए तैयार करने के सीमित उद्देश्य से प्रदान की जाती थी।”

“University degrees were the passports to government service. Education was imparted with the limited object of preparing pupils to join the service and not for life.”—Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Vol. III, p. 1641

जिस प्रकार उच्च शिक्षा—परतन्त्र भारत में व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार नहीं करती थी, उसी प्रकार स्वतन्त्र भारत में भी नहीं करती है। इसकी पुष्टि में हमाम् कबीर के अग्रलिखित शब्दों का अवलोकन कीजिए<sup>1</sup>—“बहुत बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, वह व्यक्ति को श्यावहारिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती है।”

उपयुक्त दोनों उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्षों में उच्च शिक्षा का केवल एक ही उद्देश्य है—विश्वविद्यालय की उपाधि में अलटन होकर, कोई सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी प्राप्त करना। किन्तु, छात्रों द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपाधियों में श्रेणियों का अन्तर होता है, उनके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषयों में अन्तर होता है, और सर्वोपरि बड़े आदमियों तक उनकी पढ़ाई में अन्तर होता है। इन सब बातों का परिणाम होता है—छोटे-से छात्रों का सरकारी या गैर-सरकारी पदों पर नियुक्त हो जाना और अधिकांश का बेरोजगारी के विशाल समूह में सम्मिलित होना।

इस उद्देश्यहीन शिक्षा का सबसे दूषित प्रभाव यामों से नगरों में अध्ययन करने के लिए आने वाले छात्रों पर पड़ता है। इस प्रभाव के सबसे बड़े चित्र के दर्शन हमाम् कबीर के अग्रोक्त शब्दों में कीजिए<sup>2</sup>—“विश्वविद्यालय, गाँवों से योग्य और

1. हमाम् कबीर : स्वतन्त्र भारत में शिक्षा, p. 135.
2. हमाम् कबीर : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 135



4 | भारतीय जिद्दा और उसकी समस्याएँ

नहार मुयकों को शहरों में गाँव लाते हैं, परन्तु इस प्रकार गाँवों को जो हानि होती है, उससे शहरों को लाभ हो जाता हो, यह बात नहीं है। गाँव के छोटे-से माज में नेता बनने के बजाय—जो कि वे बड़ी आसानी से बन सकते थे—वे शहर की अज्ञात जनसंख्या के हताश और फट्टु भावना से भरे सदस्य-मात्र बन जाते हैं।"

हम कह सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों की उद्देश्यहीन जिद्दा का कारण यह रही है। विश्वविद्यालयों का

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों की उद्देश्यहीन जिज्ञासा, हमारे देश एवं नवयुवकों के जीवन पर कुठाराघात कर रही है। विश्वविद्यालयों की मोहमय जिज्ञासा ही राष्ट्र के वैभव और उनके निवासियों की बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता की निर्धारक शक्ति है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर डॉ० आर० के० सिंह ने लिखा है:—“देश का वैभव, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होता है। दूषित विश्वविद्यालय सम्पूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देता है।”

“The prosperity of the country is linked up with the university. A vicious university is like a contaminated fountain which is bound to imperil the health of those who drink from it.”—Dr. R. K. Singh : *Our Universities*, p. 9.

समाधान—शिक्षा के वांछनीय उद्देश्य : Desirable Aims of Education—  
विश्वविद्यालयों की उद्देश्यहीन शिक्षा ने देश और उसके नागरिकों को इतना विकृत  
कर दिया है कि इस शिक्षा के वांछनीय एवं उपयुक्त उद्देश्य शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित  
किए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो राष्ट्र की सम्पन्नता और उसके  
निवासियों के कल्याण की लम्बी-लम्बी रातें करना गल्प-संग्रह की विषय-सामग्री हो  
जायगी। राष्ट्राकुलान् कमोशन ने ठीक ही लिखा है :—“विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन  
पद्धति से आवद्ध नहीं रह सकते हैं। समाज की बढ़ती हुई जटिलता और उसकी  
बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन कर  
आवश्यक हो गया है।”

"The universities cannot persist in the old pattern. With the increasing complexity of society and its shifting pattern, universities have to change their objectives."—Radhakrishnan Commission Report, pp. 5-6.

Report, pp. 5-6.

जाने हम विन्यास के आधार पर "साधाकृष्णन् कमीशन" ने विश्वविद्यालय के अनेक उद्देश्य निर्धारित किए हैं। "कोठारी कमीशन" ने भी विश्वविद्यालय को भारगवामियों के जीवन, आशाओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल के विचार में हम विद्या के उद्देश्यों की तरफ की है। यदि हम इन दोनों कमीशन के उद्देश्यों का विवेचन करें, तो हमें उनकी व्यवस्थिति में तो अन्तर मिलेगा, में नहीं। परन्तु "कोठारी कमीशन" के उद्देश्यों के "साधाकृष्णन् कमीशन" के अन्तर्गत आते हैं।

उद्देश्यों का समावेश हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि "कोठारी कमिशन" द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उच्च शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य सर्वथा वाछनीय हैं<sup>1</sup> :-

1. नवीन ज्ञान की खोज और विकास करना।
2. राष्ट्रीय चेतना का विकास करने का सतत प्रयास करना।
3. सत्य की खोज के लिए उत्साह एवं निभयता से कार्य करना।
4. शिक्षा का प्रसार करके, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अन्तर को कम करना।
5. शिक्षा का प्रसार करके, समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना।
6. जीवन के समस्त क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए उचित प्रकार के व्यक्ति प्रदान करना।
7. प्रतिभाशाली नवयुवकों की खोज करके, उनकी प्रतिभाओं एवं क्षमताओं का पूर्ण विकास करना।
8. प्राचीन ज्ञान एवं प्राचीन विश्वासों की नवीन खोजों एवं नवीन आवश्यकताओं के प्रकाश में व्याख्या करना।
9. समाज को कला, कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी एवं अन्य अनेक व्यवसायों के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित स्त्री और पुरुष प्रदान करना।
10. छात्रों एवं शिक्षकों में और उनके माध्यम से समाज में "अच्छे जीवन" (Good Life) के लिए आवश्यक मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों का विकास करना।

स्वाधीन भारत में उच्च शिक्षा के उपर्युक्त उद्देश्यों के औचित्य के सम्बन्ध में मत-विभिन्नता नहीं हो सकती है। भारतीय विश्वविद्यालयों को मानवता एवं सहिष्णुता की शिक्षा देनी चाहिए। उनको नवीन विचारों, सत्य एवं विवेक की खोज करनी चाहिए। उनको भारतवासियों को उच्चतर उद्देश्यों की ओर अग्रसर करना चाहिए। उनको राष्ट्र को सशक्त, सम्पन्न और प्रगतिशील बनाना चाहिए। इन कार्यों को करके विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा अपने को सफल एवं सार्थक बहने की अधिकारिणी हो सकती है और सभी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की यह आशा पूर्ण हो सकती है।—“यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का समुचित रूप में पालन करें, तो राष्ट्र एवं जनता का कल्याण हो सकता है।”

“If the universities discharge their duties adequately, then it is well with the nation and the people.”—Jawaharlal Nehru's Convocation Address to the University of Allahabad, 1947.

2. समस्या—छात्र-अनुशासनहीनता : Student Indiscipline—उच्च शिक्षा

1. Kothari Commission Report, pp. 274-275.

की सम्भवतः मरने विचारान समस्या—छात्र-अनुशासनहीनता की है। यह कहना पूर्वतया नुक्तिवत् होगा कि इस समस्या की जननी—आधुनिक उच्च शिक्षा है, जिसकी छनछाया में यह दिन-प्रति-दिन भीमकाय रूप धारण करती चली जा रही है और नित्य नूतन आकृति में प्रकट हो रही है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति प्रोफ़ेसर एन० के० सिद्धान्त ने एक अध्ययन के आधार पर 7 प्रकार के अनुशासनहीन कार्यों का उल्लेख किया है<sup>1</sup> :—(1) उच्छृंखल व्यवहार, (2) सामान्य दुर्व्यवहार, (3) यौन-सम्बन्धी दुर्व्यवहार, (4) परीक्षा में दुर्व्यवहार, (5) स्वाधिकारों का दुरुपयोग, (6) धन-सम्बन्धी अनियमितता और (7) चोरी एवं सेंधमारी।

यह अनुशासनहीनता के कार्यों की अन्तिम सूची नहीं है, अपितु वानगो-माय है। इन कार्यों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि किसी भी सूची को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अकारण हड़तानें, अनावश्यक प्रदर्शन, पुलिस से भगड़ा, बल का अनुचित प्रयोग, छोटी-छोटी बातों के लिए अनशन, कक्षाओं से बहिर्गमन, परीक्षाओं का बहिष्कार, शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक स्थानों में मारपीट, कनिजों के भयनों एवं रजिस्ट्रारों के कार्यालयों का अग्निहोम, परीक्षा में अनुचित मापनों का गुनेजाम प्रयोग, छात्र-संघों के पदाधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग, युक्तियों का अपहरण और उनके साथ बलात्कार—ये सब प्रतिदिन देखे और सुने जाने वाले छात्र-अनुशासनहीनता के कुछ नमूने हैं।

यह कहना अतिजयोक्ति न होगी कि उच्च-शिक्षा की संस्थाओं में अनुशासनहीनता की समस्या उत्तरोत्तर अधिक-ही-अधिक जटिल होती जा रही है। इसीलिए, "भारतीय विश्वविद्यालय प्रशासन" ने यह मत प्रकट किया है :—"उच्च शिक्षा के केन्द्रों में अनुशासन बनाये रखने की समस्या प्रतिदिन अधिक गम्भीर होती जा रही है।"

"The problem of maintaining discipline in the seats of higher education is assuming greater importance every day."—*Indian University Administration*, p. 98.

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—छात्र-अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए उसके कारणों से अवगत होना आवश्यक है। "कोठारी समीक्षण" ने कुछ कारणों का उल्लेख किया है, जो नक्षिप्त होते हुए भी विमृष्ट हैं; यथा :—

1. N. K. Sidhanta : *The Problem of Discipline in Indian Universities*, p. 2.
2. Kothari Commission Report, pp. 296-297.

1. छात्रों का अनिश्चित भविष्य ।
2. छात्रों एवं शिक्षकों में पारस्परिक सम्पर्क का अभाव ।
3. अनेक शिक्षकों में विद्वता का अभाव एवं छात्रों की समस्याओं में उलझाव ।
4. अनेक पाठ्यविषयों का यात्रिक एवं असतोषजनक स्वरूप ।
5. शिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की विनाश संरक्षा ।
6. शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षण एवं सीखने की अपर्याप्त सुविधाएँ ।
7. शिक्षा-संस्थाओं के अध्यक्षों में दृढ़ता, कल्पना एवं कुशलता का अभाव ।
8. शिक्षा-संस्थाओं के कार्य में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप ।
9. कुछ कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पारस्परिक राजनीति ।
10. देश के सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का अभाव ।
11. बचपन में अनुशासन का निम्न स्तर ।
12. बचपन में नागरिक चेतना एवं मर्यादितता का अभाव ।

इसके अतिरिक्त, अनुशासनहीनता के कुछ कारण और भी हैं; यथा .—  
 (1) दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली, (2) अपूर्ण एवं कीमती पुस्तकें, (3) परिवार का दूषित वातावरण, (4) शिक्षा-संस्थाओं का दूषित वातावरण, (5) नैतिक शिक्षा का अभाव, (6) शिक्षकों में नेतृत्व की भावना का अभाव, (7) शिक्षा-संस्थाओं में सामुदायिक कार्यों का अभाव, और (8) निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का अभाव ।

अनुशासनहीनता के कारणों का निवारण करने और छात्रों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों, शिक्षाविदों आदि के द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं । हम उनकी चर्चा निम्नांकित पंक्तियों में कर रहे हैं ।

(i) उपकुलपतियों का सुझाव—सन् 1969 में भारतीय विश्वविद्यालयों के “उपकुलपतियों के सम्मेलन” (Vice-Chancellors' Conference) में यह सुझाव दिया गया कि छात्रों को समय-समय पर राष्ट्रीय विरासत के कार्यक्रमों, धर्म-निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण, संविधान एवं नागरिकता का परिचय दिया जाना चाहिए । यह परिचय उनमें देश के प्रति निष्ठा उत्पन्न करेगा, जिसके फलस्वरूप उनकी अनुशासनप्रियता में वृद्धि होगी ।

“It is desirable that student is exposed to and acquainted with national development programmes, secularism, national integration, the Constitution, and citizenship.”—Vice-Chancellors' Conference, 1969.

(ii) भारतीय विश्वविद्यालय-प्रशासन का सुझाव—“भारतीय विश्वविद्यालय-प्रशासन” (Indian University Administration) के अनुसार, अनुशासनहीनता

की समस्या का समाधान करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि तमिल छात्रों की प्रियाओं को स्वयं प्रियाओं में मिला दिया जाए। यह नतीजा सम्भव है, जब उनके लिए अविरक्त नैतिक सुविधाओं का आयोजन किया जाए; यथा :—मेन-हूट, छात्रावासों में सामुदायिक जीवन, भोजनानुष्ठानों का छात्रों द्वारा प्रबंध, वाद-विवाद एवं गोष्ठियाँ। परन्तु, जहाँ यह है कि उन सब बातों में शिक्षक अवगती हों।

"The best way of solving the problem of indiscipline is to divert the activities of young students into healthy channels including sports, games, co-operative living in hostels, self-management of messes, debates and symposia. However, the lead in all these matters should be given by the teachers themselves."—*Indian University Administration*, p. 98.

(iii) राष्ट्रावृत्तन् कर्मोन्नत का मुद्दा—“राष्ट्रावृत्तन् कर्मोन्नत” के विनायक-मुद्दार, अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए नैतिक शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। यह शिक्षा निश्चय रूप में उनके चरित्र का निर्माण कर सकती है। क्योंकि यह शिक्षा—श्रेष्ठ साहित्य एवं श्रेष्ठ पुस्तकों में निहित रहती है, हमारे छात्रों को उनका अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। हम सबमें से “कर्मोन्नत” ने लिखा है :—“श्रेष्ठ साहित्य, श्रेष्ठतम भावना को जाग्रत करता है और उच्चतम आदर्श एवं आकांक्षा को बढ़ावा देता है। अतः श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन, जो हममें आत्मा का संचार करता है, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अनिवार्य है।”

"Great literature sets fire to the highest emotion, and promotes the highest ideal and aspiration. A study of great books that fill us with hope is essential in University course."—*Radhakrishnan Commission Report*, p. 301.

(iv) फीटारी कर्मोन्नत के मुद्दा—“फीटारी कर्मोन्नत” ने छात्र-अनुशासन-हीनता की समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही सुलभ हल सुझाव दिए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :—

1. शिक्षा एवं प्रशासन में सम्बन्धित सब कमियों को दूर किया जाना चाहिए।
2. शिक्षा के सब स्तरों एवं सब समस्याओं में सुधार किया जाना चाहिए।
3. छात्र-समूह एवं छात्रों की सम्बन्ध समितियों में शिक्षक अवगती होनी चाहिए।

4. उच्च शिक्षा की सब समस्याओं द्वारा छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श दिए जाने का कार्य किया जाना चाहिए।
- 5 छात्रों में स्व-अनुशासन (Self-Discipline) एवं सरासरी अनुशासन (Positive Discipline) की भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए।
- 6 छात्रों एवं शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम एवं सम्मान पर आधारित एकरूपता का मापी होने की भावना का विकास किया जाना चाहिए। अतः छात्रों, सम्पूर्ण विश्वविद्यालय-जीवन को एक माना जाना चाहिए। अतः छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशासन के मध्य विभेदीकरण के सब प्रयासों का अन्त किया जाना चाहिए।
- 8 प्रत्येक विश्वविद्यालय की सभा एवं साहित्यिक परिषद् (Court & Academic Council) में छात्रों के प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि वे अपने दायित्वों को समझ सकें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी माँगों को प्रस्तुत कर सकें।
- 9 प्रत्येक कॉलेज एवं प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में छात्रों एवं शिक्षकों की संयुक्त समितियाँ (Joint Committees) होनी चाहिए। इन समितियों की बैठकों में छात्रों की सभी समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए और उनका समाधान खोजने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
10. विश्वविद्यालय के उपकुलपति एवं कॉलेज के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति (Central Committee) का निर्माण किया जाना चाहिए। इस समिति में छात्रों एवं शिक्षकों—दोनों के प्रतिनिधि उचित अनुपात में होने चाहिए। यह समिति न केवल छात्रों की जटिलतम समस्याओं का समाधान करने में सफल होगी, बल्कि छात्रों एवं शिक्षकों में निकट सम्पर्क भी स्थापित करेगी।
- 11 अनुशासनहीनता के चाहे जो भी कारण हों, छात्रों की इस प्रवृत्ति का दमन करना और उनको मध्य व्यक्त बनाना शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य है। "आयोग" के शब्दों में — "शिक्षा चाहे और कुछ करे या न करे, उसे कम-से-कम युवकों एवं युवतियों में मध्य व्यवहार के मानदण्डों को सीखने और प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।"

"Whatever else education may or may not aim at doing, it should at least strive to enable young men and women to learn and practise civilized norms of behaviour"—  
Education Commission Report, p 297

उपयुक्त मुद्दों का नतकता से अध्ययन करने के पश्चात् हम कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए 8 उपाय विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं; यथा :— (1) उच्च शिक्षा के समस्त दोषों का निवारण, (2) नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, (3) निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था, (4) छात्र-प्रियाओं एवं छात्र-कल्याण सेवाओं की व्यवस्था, (5) अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं का आयोजन, (6) छात्रों एवं शिक्षकों में निकट सम्पर्क, (7) छात्रों में स्व-अनुशासन की भावना का विकास और (8) विश्वविद्यालयों की सभाओं एवं साहित्यिक परिषदों में छात्रों का प्रतिनिधित्व।

ये उपाय, अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने में श्लाघनीय योग दे सकते हैं। किन्तु, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि छात्र, शिक्षक, समाज, सरकार, अभिभावक एवं राजनीतिक दल—सभी संयुक्त रूप से इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए हादिक प्रयास करें। इसका कारण यह है कि अनुशासनहीनता का दायित्व किसी एक पर न होकर सब पर है, एकपक्षीय न होकर बहुपक्षीय है। हम अपने इस विचार की पुष्टि में “शिक्षा-आयोग” के अग्रांकित शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं :—“यह स्मरण रखना आवश्यक है कि अनुशासनहीनता का उत्तरदायित्व एकपक्षीय नहीं है—यह केवल छात्रों या अभिभावकों या शिक्षकों या राज्य-सरकारों या राजनैतिक दलों का उत्तरदायित्व नहीं है—वरन् बहुपक्षीय है। इन सब का इस उत्तरदायित्व में भाग है।”

“It is necessary to remember that the responsibility for the situation is not unilateral—it is not merely that of the students or parents or teachers or State Governments or the political parties—but multilateral. All of them share it.”—*Education Commission Report* p. 297.

3. निर्देशन व परामर्श का अभाव : Absence of Guidance & Counselling—उच्च शिक्षा की संस्थाओं में निर्देशन एवं परामर्श-सेवाओं का प्रायः पूर्ण अभाव है। अतः छात्र अपनी स्वयं की दृष्टि से, अपने अभिभावकों के दबाव से, या किसी अनुभवहीन व्यक्ति के परामर्श से पाठ्य-विषयों का चयन करते हैं। इस प्रकार का चयन अनेक छात्रों के समक्ष संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देता है। पाठ्य-विषयों का चोड़ा-भा अध्ययन ही उनकी स्फूर्ति संकेत देने लगता है कि वे उनकी रुचियों के अनुरूप नहीं हैं, या उन पर अधिकार प्राप्त करने की उनमें शक्त नहीं है, या वे उनके भावी जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं।

इन बातों का पहला दुष्परिणाम होता है—परीक्षा में असफलता और दूसरा दुष्परिणाम होता है—जीवन में असफलता। इस प्रकार, निर्देशन एवं परामर्श-सेवाओं के अभाव के कारण अनेक छात्रों को अपने भावी जीवन में पग-पग पर निराशा एवं निष्फलता के भंसेटों का शिकार बनना पड़ता है।

**समाधान—निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था : Provision of Guidance & Counselling**—छात्रों की भाषी सफलता एवं सम्पन्नता के लिए यह परम आवश्यक है कि निर्देशन एवं परामर्श-सेवाओं को उच्च शिक्षा का अविभाज्य अंग बनाया जाए। ये सेवाएँ प्रत्येक कॉलेज और प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को उपलब्ध होनी चाहिए। ये सेवाएँ ही उसकी रुचियों एवं आवश्यकताओं, उसकी क्षमताओं एवं शैक्षिक योग्यताओं का अध्ययन करके, उसे उपयुक्त एवं उपयोगी पाठ्य-विषयों का चयन करने में सहायता दे सकती हैं। इतना ही नहीं, ये सेवाएँ उसकी आर्थिक, वैयक्तिक एवं पारिवारिक उलझनों को सुलझाने में भी उसकी सहायता कर सकती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा की सब संस्थाओं में निर्देशन एवं परामर्श-सेवाओं की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सेवाएँ—छात्रों को संस्थाओं में प्रवेश करने के समय से लेकर उनको छोड़ने के समय तक और उसके पश्चात् भी सुलभ होनी चाहिए।

“कोठारी कमिशन” ने इस बात पर दुःख प्रकट किया है कि हमारी उच्च शिक्षा की संस्थाओं में निर्देशन एवं परामर्श-सेवाओं का एक भी चित्त दृष्टिगोचर नहीं होता है। उमते सिफारिशों की है कि सभी संस्थाओं में इन सेवाओं की यथानीति स्थापना की जानी चाहिए। उसका गुमान है कि प्रत्येक 1,000 छात्रों वाली संस्था में एक परामर्शदाता (Counsellor) होना चाहिए और यदि संस्थाओं में छात्र-संख्या कम है, तो दो या अधिक संस्थाओं के लिए एक परामर्शदाता हो सकता है। निर्देशन एवं परामर्श-कार्यक्रम की अनिवार्य बताते हुए, “कोठारी कमिशन” ने लिखा है :—  
“निर्देशन एवं परामर्श का कार्यक्रम, जो छात्रों को पाठ्यक्रमों का चयन करने और उनकी संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देता है, उच्च शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए।”

“A guidance and counselling programme, which would assist the students in the choice of courses and help in dealing with emotional and psychological problems, should be an integral part of higher education.”—Kothari Commission Report pp 294-95

“कोठारी कमिशन” के सुझाव की उपयोगिता को स्वीकार करके, दिल्ली और बनारस जैसे कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रों के लिए निर्देशन एवं परामर्श का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस कार्यक्रम का सुन्वतान किया जाना आवश्यक है।

4. समस्या—दोषपूर्ण पाठ्यक्रम Defective Curriculum—स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा का इतना अधिक प्रचार हुआ है कि यह शिक्षा की समस्त उपलब्ध सीमाओं को पार कर गया है। शिक्षा-प्रसार के नाम में कुछ स्थानों में बहुत समृद्ध-सेवकों ने और अन्य स्थानों में पलायन के लिए लातियाँ लगीं ने बोड़ी-सी भूमि



पर कुछ कमरे गड़े करके, उनको कॉलेजों की संज्ञा दे दी है। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना और पुराने विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकारों में न्यूनता होने के कारण इन नामनाश के कॉलेजों की मान्यता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। इन सब कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में प्रायः वही विषय हैं, जिनके शिक्षण के लिए न तो विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है और न विशेष साह-संस्था की; यथा :—इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इत्यादि।

शिक्षा-विस्तार के लिए इन कॉलेजों की स्थापना की मराहना अवश्य की जा सकती है, पर इनमें प्रचलित पाठ्यक्रमों की नहीं। इसका कारण यह है कि ये पाठ्यक्रम अनेक क्षेत्रों में परिपूर्ण हैं; यथा :—कठोरता, विविधता एवं व्यावसायिक विषयों का अभाव, पाठ्यविषयों की छात्रों एवं समाज के लिए अनुपयोगिता और अध्ययन के विषयों की सीमित संख्या। अतः छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार, विषयों का चयन करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। फलस्वरूप, उनकी क्षमताएँ कुटित हो जाती है और उनका मानसिक विकास अवरोध हो जाता है।

यदि हम समग्र रूप में उच्च शिक्षा की समस्याओं के पाठ्यक्रमों पर दृष्टिपात करें, तो हमें उनका रूप बहुत-कुछ वही मिलता है, जो उक्त कॉलेजों के पाठ्यक्रमों का है। अतएव केवल इतना है कि कुछ शिक्षा-संस्थाओं में अध्ययन के विषय अधिक हैं। साक्षात्कार यह है कि यद्यपि आज के भारत की आवश्यकताएँ, पराधीन भारत की आवश्यकताओं से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि पाठ्यक्रमों में कोई विशेष अन्तर परि-रक्षित नहीं होता है। उनमें अब भी वही पिमे-पिटे विषय हैं, जो आज से लगभग 50 वर्ष पहले थे।

अतः हम कह सकते हैं कि हमारी उच्च शिक्षा की समस्याओं के पाठ्यक्रम दोषपूर्ण हैं और आधुनिक भारत के लिए निरर्थक हैं। इस नथ्य की ओर संकेत करते हुए, "राधाकृष्णन् कमीशन" ने लिखा है :—“जो पाठ्यक्रम वैदिक काल में उपयोगी था, उसे 20वीं शताब्दी में बिना परिवर्तन किए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।”

“A curriculum which had validity in the Vedic period cannot continue unaltered in the 20th century.”—*Radhakrishnan Commission Report*, p. 44.

समाधान— पाठ्यक्रम में सुधार : *Reform in Curriculum*—“राधाकृष्णन् कमीशन” के विचार से सफल होने के कारण “कोठारी कमीशन” ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं सुधार करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए हैं :—

1. *Kothari Commission Report*, p. 652.

1. उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को विद्यालय-पाठ्यक्रम से कटोरतापूर्वक सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए।
2. स्नातक-पूर्व स्तर पर पाठ्यक्रम उमते अधिक लचीला होना चाहिए, जितना कि इस समय है।
3. उक्त स्तर पर छात्रों को पाठ्य-विषयों का चयन करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए।
4. उक्त स्तर पर सामान्य, विशिष्ट एवं आनमें पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों को परिवर्तित करके अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए, "कोठारी कमिशन" का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि शिक्षा का देश एवं व्यक्तियों की आवश्यकताओं से सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। इस तथ्य की प्राप्ति के लिए, "कमिशन" ने पाठ्यक्रम में कार्य-अनुभव, व्यावसायिक विषयों और कृषि, विज्ञान एवं प्राविधिक शिक्षा को स्थान दिए जाने का सुझाव प्रस्तुत किया है।

भारत-सरकार ने "कमिशन" के सुझाव को स्वीकार करके, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए "पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" में ब्रह्मविहित कार्यक्रमों को स्थान देने का निश्चय किया है<sup>1</sup> —

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रचलित करके, स्नातकों की रोजगार-सम्बन्धी योग्यता में वृद्धि करना।
2. उच्च शिक्षा के प्रत्येक पाठ्यक्रम का व्यावहारिक समस्याओं एवं सामाजिक उपयोगिता से सम्बन्ध स्थापित करना।
3. पाठ्यक्रम को लचीला बनाकर, छात्रों का अधिक पाठ्य-विषयों में से अपने रुचियों के अनुकूल विषयों का चयन करने की स्वतन्त्रता प्रदान करना।

5. समस्या—दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली Defective System of Examination—कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रचलित परीक्षा-प्रणाली मुख्यतः निबन्धात्मक प्रकार की है। निश्चयात्मक प्रश्न सम्पूर्ण पाठ्य विषय पर आधारित न होकर, उन्हें केवल एक अंग पर आधारित होते हैं। अतः वर्तमान परीक्षा-पद्धति में ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता का पूर्ण अभाव है। इसके अतिरिक्त, पद्धति में बाह्य परीक्षाओं का शीर्षस्थ स्थान है और कक्षा-कार्य एवं छात्र-परीक्षाओं को तनिक भी महत्व नहीं दिया जाता है।

हमारी उच्च शिक्षा में दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली की समस्या लगभग एक सताष्टी के विद्यमान है। यह समस्या इतनी गंभीरपूर्ण है कि कोई भी छात्र सान्भर चैन की सोच नहीं सो पाता है, क्योंकि वह जानता है कि वर्ष के अन्त में होने वाली अन्तिम व्यापक परीक्षा उसके लिए विष की पोटली बन सकती है। दिल दहलाने वाली इन नवायद परीक्षा ने अनेक छात्रों और गणितियों के ध्यान को अपनी ओर खिंचा है। सन् 1902 में "भारतीय विश्वविद्यालय-आयोग" ने इसके विषय में यह मत व्यक्त किया :—“भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा का महानतम दोष यह है कि शिक्षण, परीक्षा के अधीन है, न कि परीक्षा, शिक्षण के।”

“The greatest evil from which university education in India suffers is that teaching is subordinated to examination, and not examination to teaching.”—*Report of the Indian University Commission.*

सन् 1949 में “विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग” ने यह विचार प्रकट किया :—“यदि हमसे विश्वविद्यालय-शिक्षा में केवल एक बात के बारे में सुझाव देने के लिए कहा जाय, तो यह सुझाव—परीक्षाओं के सम्बन्ध में होगा।”

“If we are to suggest one single reform in university education, it should be that of examination.”—*Report of the University Education Commission*, p. 328.

समाधान—परीक्षा-प्रणाली में सुधार : *Reform in Examination System*—उच्च शिक्षा में प्रद्योत की जाने वाली परीक्षा-प्रणाली को दोषमुक्त करने के लिए समय-समय पर जो सुझाव दिए गए हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन दृष्टव्य है; यथा :—

1. *समाकूल्यन् कमिशन* के सुझाव—इन “कमीशन” के मुख्य सुझाव निम्न-दिग्गि हैं :—

1. शिक्षा-संस्कारण को मूल्यांकन की वैज्ञानिक विधियों का कार्य धारम्भ करना चाहिए।
2. अन्तिम परीक्षा में छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करते समय उनके द्वारा दिए जाने वाले कक्षा-कार्य पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित सम्पूर्ण अंशों में से एक-निश्चय अंश कक्षा-कार्य के लिए होने चाहिए।
4. स्नातक-पूर्व स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्वतः

पूर्ण इकाइयों (Self-Contained Units) के रूप में नी जानी चाहिए।

5. स्नातकोत्तर-स्तर पर सत्र-परीक्षाओं को अन्तिम परीक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए।
6. प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षकों का एक स्थायी बोर्ड होना चाहिए, जिसे विश्वविद्यालय और उगमे सम्बद्ध कलेजों के शिक्षकों को वस्तु-निष्ठ परीक्षाओं की योजनाएँ बनाने में सहायता देनी चाहिए।

2. कोठारी कमिशन के सुझाव—परीक्षा-मुद्धार के सम्बन्ध में “कोठारी कमिशन” के सुझाव इस प्रकार हैं :—

1. सब शिक्षण-विश्वविद्यालयों में बाह्य परीक्षाओं का स्थान शिक्षकों के आन्तरिक एवं क्रमिक मूल्यांकन (Internal & Continuous Evaluation) को दिया जाना चाहिए।
2. सब सम्बद्धोत्तरण विश्वविद्यालयों में बाह्य परीक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आन्तरिक आँचो (Internal Assessments) की पद्धति प्रारम्भ की जानी चाहिए।
3. विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को मूल्यांकन की नवीन एवं उन्नत विधियों से परिचित कराया जाना चाहिए।

उल्लिखित आयोगों के सुझावों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। दोनों ने बाह्य परीक्षाओं के महत्त्व को कम करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, दोनों ने आन्तरिक परीक्षाओं एवं मूल्यांकन की नवीन विधियों के प्रयोग पर बल दिया है।

3. विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के सुझाव—“शिक्षा-संशोधन” ने “राष्ट्र-कृष्णन् कमिशन” के सुझाव को स्वीकार करके, “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” (University Grants Commission) से मूल्यांकन की नवीन विधियों एवं परीक्षा-प्रणाली में मुद्धार करने के उपायों के सम्बन्ध में अपना परामर्श देने को कहा। “आयोग” ने इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए अपने कुछ सदस्यों की एक “समिति” नियुक्त की। इस “समिति” ने सन् 1962 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें परीक्षा में मुद्धार करने के लिए निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए गए :—

1. विश्वविद्यालयों की बाह्य परीक्षाओं में कमी की जाए।

1. Kothari Commission Report, pp 648-49

2. Report of the U G C's Committee on Examination Reforms, 1962

2. छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, उनके शिक्षकों द्वारा प्रगति-परीक्षाओं (Continuous Assessments) का कार्य आरम्भ किया जाय।
3. शिक्षण-कार्य में व्याख्यानों के अतिरिक्त विनार-संश्लेषणों (Seminars), ट्यूटोरियल-कार्य (Tutorial Work) आदि का भी प्रयोग किया जाय।
4. ट्यूटोरियल रक्षाओं में छात्रों द्वारा किए जाने वाले कार्य का नियमित रूप में मूल्यांकन किया जाय, मूल्यांकन को निरन्तर रूप में रखा जाय और अन्तिम परीक्षा में उसको महत्त्व दिया जाय।

भारत-सरकार इन सुझावों को मान्यता प्रदान कर चुकी है और इनकी पूर्णभूमि में कार्य आरम्भ हो चुका है। "पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अनुसार :— "परीक्षा-सुधार का कार्यक्रम, जो विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" द्वारा आरम्भ किया जा चुका है, पाँचवीं योजना में और तेजी से किया जायगा।"

"The programme of examination reform, already started by the University Grants Commission, will be speeded up during the Fifth Plan."—*Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 199.

6. समस्या—अपव्यय : Wastage—हमारे देश में उच्च शिक्षा के स्तर पर "अपव्यय" की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। इसकी गम्भीरता का अनुमान "साधकव्ययन् कमीशन" के अर्पणित शब्दों में सहज ही लगाया जा सकता है :— "साधकजनिक धन का प्रति वर्ष अति महान् अपव्यय हो रहा है। किन्तु, इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि साधकजनिक धन की इस महान् हानि के प्रति उत्तनी ही उदासीनता है, जितनी कि छात्रों एवं उनके अभिभावकों के समय, शक्ति तथा धन के नाश, और उनकी आशाओं एवं अभिलाषाओं पर भयंकर हिमपात के प्रति।"

"A deplorable wastage of public funds goes on year after year but what is worse, there is an unconcerned complacency about this serious loss of public funds on the one hand, and waste of time, energy and funds of students and their parents, besides terrible frustration of their hopes and aspirations on the other."—*Radhakrishnan Commission Report*, p. 86.

दा० एम० एन० मुकर्जी ने उच्च शिक्षा में अपव्यय के कुछ आँकड़े इस प्रकार दिए हैं :—हिन्दी बोर्ड के प्रथम वर्ष में जिनमें छात्र प्रवेश लेते हैं, उनमें से 50 प्रतिशत में अधिस्तरीय बी० ए०, बी० कॉम० और बी० एम०-बी० की परीक्षाओं में

अनुत्तीर्ण होने हैं। स्नातकोत्तर-स्तर पर 20 से 30 प्रतिशत तक छात्र, परीक्षाओं में अग्रफल होते हैं। इस प्रसंग में डा० देशमुख के अप्रति वाक्य को उद्धृत करना असंगत प्रतीत नहीं होता है :—“भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा में अपभ्य की मात्रा संसार में सबसे अधिक है।”

“The degree of wastage in India of university education is the highest in the world.”—Dr. C. D. Deshmukh, Chairman of the U. G. C. in 1960.

उच्च शिक्षा में होने वाले इस महान् अपभ्य के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :—  
(1) शिक्षण का निम्न स्तर, (2) छात्रों की आर्थिक कठिनाइयाँ, (3) छात्रावासों की सुविधा का अभाव, (4) योग्य शिक्षकों का अभाव, (5) उपयुक्त शिक्षण-सुविधाओं का अभाव, और (6) अयोग्य छात्रों का उच्च शिक्षा की सम्पदाओं में प्रवेश।

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—उच्च शिक्षा की परिधि में से अपभ्य की अत्यधिक समस्या को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है :—

1. परीक्षा-प्रणाली को परिवर्तित एवं दोषमुक्त किया जाय।
2. बाह्य परीक्षाओं की तुलना में आन्तरिक परीक्षाओं को अधिक महत्त्व दिया जाय।
3. परीक्षाओं में अग्रफल होने वाले छात्रों के लिए पुनः परीक्षा एवं पुनः मूल्यांकन की व्यवस्था की जाय।
4. पाठ्यक्रमों में छात्रों की अभिरूचियों एवं अभिवृत्तियों के अनुसार अधिक विषयों को स्थान दिया जाय और उनको व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाय।
5. “मार्जेंट-रिपोर्ट” के अनुसार, हाई स्कूल की परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों में 15 में से केवल 1 को उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जाय।
6. “केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय-बोर्ड” (CABE) के अनुसार, केवल उन्हीं छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा दी जाय, जिनके लिए यह शिक्षा भविष्य में आवश्यक है।<sup>1</sup>
7. “बोटारी कमिशन” के अनुसार, “चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली (System of Selective Admissions) का प्रयोग करते, केवल योग्यतम विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा की सम्पदाओं में प्रवेश दिया जाय।

7. समस्या—शिक्षा में विशिष्टीकरण Specialization in Education—विश्वविद्यालय-स्तर पर शिक्षा में विशिष्टीकरण साम्प्रदायिक हो जाता है। दूसरे शब्दों

में, छात्रों को विभिन्न विषयों का विवेक अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। इन प्रकार का अध्ययन उनको कुछ विवेक विषयों में दक्षता प्रदान करता है। किन्तु, साथ ही इस अध्ययन से उनका दृष्टिकोण अंतर्मुखित एवं अव्यावहारिक हो जाता है। अतः विशिष्टीकरण के विरुद्ध लाभ शिकायत यह है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले छात्रों में जिज्ञासा, संतुलन एवं व्यावहारिकता का अभाव होता है, जो प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के चरित्र के प्रमुख लक्षण होने चाहिए।

छात्रों के चरित्र में उपर्युक्त दोषों का समावेश क्यों हो जाता है, इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए, के०जी० सायदान ने लिखा है :—“विशिष्टीकरण में एक प्रकार की संकीर्णता एवं अकाल्पनिकता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि विज्ञान के छात्रों को कला एवं कविता और सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता है और आर्ट्स के छात्रों को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि विज्ञान एवं वैज्ञानिक विधियों से उस विषय को, जिसमें वे निवास कर रहे हैं, किस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है।”

“There is a certain narrow, unimaginative type of specialisation which results in the science students being complacently ignorant of art and poetry, and social and political problems, and art students having no appreciation of how science and the scientific technique have transformed the world in which they are living.”—  
K. G. Saiyidain : *Education, Culture and Social Order*, p. 163.

**समाधान—सामान्य शिक्षा की व्यवस्था : Provision of General Education**—विशिष्टीकरण से उत्पन्न होने वाले दोषों का निराकरण करने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों द्वारा अर्जित किए जाने वाले विभिन्न अनुभवों एवं ज्ञान के विभिन्न अंगों में सामंजस्य एवं अन्तर्सम्बन्ध हो। जब तक यह नहीं होगा, जब तक उनके दृष्टिकोणों एवं मानसिक क्षक्तियों का संतुलित विकास सम्भव नहीं होगा। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में “सामान्य शिक्षा” को स्थान दिया जाय।

“सामान्य शिक्षा” के अंगरंग विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, भारतीय संस्कृति आदि सभी विषयों का सामान्य ज्ञान आ जाता है। अतः यह शिक्षा सभी छात्रों को सामान्यित करेगी। यह शिक्षा कला एवं साहित्य के छात्रों को विज्ञान के विषयों का, और विज्ञान के छात्रों को कला एवं साहित्य के विषयों का ज्ञान प्रदान करेगी। फलस्वरूप, इनके अपने अध्ययन-काल में उन सब बातों का ज्ञान प्राप्त हो जायगा, जो प्रत्येक शिक्षित पुरुष एवं स्त्री के लिए आवश्यक है।

इससे अविरक्त, “सामान्य शिक्षा”—विशिष्टीकरण से उत्पन्न होने वाली

संकीर्णता को दूर करके, छात्रों की समस्त मानसिक शक्तियों का संतुलित विकास करेगी। यह शिक्षा उनमें जीवन के प्रति उन मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों का विकास करेगी, जो उनको वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन व्यतीत करने में अपूर्व सहायता देगे। अतः वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और सुयोग्य नागरिकों के रूप में अपने देश की सेवा करेंगे।

उपरिअंशित तथ्यों से सुपरिचित होने के कारण "राधाकृष्णन् कमीशन" ने यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में "सामान्य शिक्षा" को सम्मिलित किया जाय।<sup>1</sup> इस सुझाव को स्वीकार करके भारत के 15 विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रों को "सामान्य शिक्षा" प्रदान करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। ये विश्वविद्यालय हैं—अलीगढ़, आंध्र, बनारस, बरोदा, जादवपुर, कर्नाटक, केरल, मैसूर, पूना, राजस्थान, सागर, एम० एन० डी० टी०, श्री वेंकटेश्वर, उत्कल एवं विश्वभारती।<sup>2</sup>

8 समस्या—शिक्षा का माध्यम : Medium of Instruction—उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न ने एक अग्न्यन्त जटिल समस्या उपस्थित कर दी है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, अंग्रेजी अति दीर्घ काल से माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित है। दूसरा, भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्र-भाषा घोषित किया गया है और 14 अन्य भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में, देश के प्रशासनिक के समस्त समय-समय पर यह समस्या उपस्थित हुई है कि उच्च शिक्षा का माध्यम—अंग्रेजी, हिन्दी या कोई अन्य भाषा होनी चाहिए?

इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत-सरकार ने 1956 में 'भाषा-आयोग' (Language Commission) की नियुक्ति की। "आयोग" ने यह निर्णय लिया कि सभी उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी द्वारा अंग्रेजी का स्थान ग्रहण किया जाना अम सम्भव है। अतः कम-से-कम 1965 तक अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखा जाय।

1966 में "कोटारी कमीशन" ने "राधाकृष्णन् कमीशन" की सिफारिशों को दोहराते हुए, इस बात पर बल दिया कि विश्वविद्यालय-स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं (Regional Languages) को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। साथ ही, उसने यह सुझाव भी दिया कि इन भाषाओं को 10 वर्षों की अवधि में शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण कर लिया जाय।<sup>3</sup> किन्तु, श्री चन्द्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने इस सुझाव को यह कह कर तिरस्कृत किया—“यदि हम चाहते हैं कि भारत पृथक् द्वीपों

1. Radhakrishnan Commission Report, p. 138.

2. Report on General Education, p. 4

3. Kothari Commission Report, p. 649.

4. C. Rajagopalachari : The Pitfalls of Fourteen Regional Languages, The Hindustan Times, August 28, 1967.



में विभाजित न हो, तो अंग्रेजी के स्थान पर 14 क्षेत्रीय भाषाओं को स्थापित करना राष्ट्र के लिए बहुत सराव सौदा होगा।”

श्री राजगोपालाचारी के विरोध के बावजूद भी भारत-सरकार के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री, डा० प्रिणु सेन ने यह घोषणा की कि उच्च शिक्षा की सब संस्थाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को 5 वर्ष की अवधि में शिक्षा का माध्यम बना दिया जाय।<sup>1</sup> किन्तु, अंग्रेजी के उपासकों द्वारा उन घोषणा का इतना जबरदस्त विरोध किया गया कि अपनी अभाधारण हृदयता के बावजूद भी डा० सेन उनका सामना न कर सके और उनको अपना त्याग-पत्र देना पड़ा।

शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर अब भी विवाद चल रहा है। इस प्रश्न को नकार शिक्षाविदों के दो दल बन गए हैं। एक दल अंग्रेजी का समर्थक है और दूसरा—क्षेत्रीय भाषाओं का।

**समाधान—शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषाएँ : Regional Languages as Medium of Instruction**—शिक्षा के माध्यम की समस्या का समाधान करने का केवल एक उपाय है। वह यह कि क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित किया जाय। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति अपनी ही मातृभाषा में दूसरों के विचारों को भली-भाँति समझ सकता है और अपने विचारों को प्रकट कर सकता है।

अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों की मातृभाषा अर्थात् क्षेत्रीय भाषा को न केवल उच्च शिक्षा के स्तर पर, बल्कि सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। हमारे राष्ट्रीय नेताओं—टैगोर, नेहरू और गांधीजी का अपने देशवासियों को यही परामर्श था। सम्भवतः इस परामर्श की उपयोगिता में ही प्रभावित होकर “राधाकृष्णन् कमीशन”, “कोठारी कमीशन”, “भावात्मक एकता-समिति” (Emotional Integration Committee), उपकुलपतियों के सम्मेलन (1967) और भारत-सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को ही माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इस समय 35 विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम—क्षेत्रीय भाषाएँ हैं और 17 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर-स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है।<sup>2</sup>

इस स्थान पर अंग्रेजी के सम्बन्ध में दो नजर लिए देना सम्भवतः अप्रामाणिक न होगा। यदि हम क्षेत्रीय भाषाओं के मोह में पड़कर, अंग्रेजी में सर्वेष्ट के लिए अपना नाता तोड़ देंगे, तो यह हमारी बड़ी भयंकर भूल होगी। उच्च शिक्षा की

1. *Times of India*, July 20, 1967.

2. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow* p. 515.

समस्याओं में छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम-माध्य अपेक्षों का अध्ययन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका अध्ययन करने में उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और फलस्वरूप शिक्षा के स्तर का उन्नयन होगा। हम अपेक्षों को दागना का प्रतीक मान कर न तो समझे धृष्टा करनी चाहिए और न उसे अपने देश की सीमाओं से बाहर निकालने का उद्योग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमें डॉ० राधाकृष्णन् के ये शब्द मदैव स्मरण रखने चाहिए :—“हमने भले ही अपेक्षों को अपने देश से निकाल दिया है, पर उनकी भाषा को नहीं निकाला है, और अपेक्षों पर केवल अपेक्षों का ही एकमात्र अधिकार नहीं है।”

We might have banished Englishmen, but not their language, and English is not the monopoly of Englishmen.”—Dr. S. Radhakrishnan, *Times of India*, September 6, 1967.

9. समस्या—छात्र-संख्या में वृद्धि—Increase in Number of Students—गन वर्षों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में अति तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1950-51 में विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 36 लाख, 1960-61 में 89 लाख और 1970-71 में लगभग 25.1 लाख थी।<sup>1</sup> भारत ऐसे सीमित माध्यमों वाले देश के लिए छात्रों की इस निरन्तर वृद्धि की संख्या के लिए शिक्षा की सुविधाएँ मुलभ बनाना अगम्य है।

“कोठारी कमिशन” का विचार है कि यदि छात्र-संख्या में इसी गति से वृद्धि होती रही, तो 1985-86 में देश को जितने शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उससे उनकी संख्या दूनी होगी।<sup>2</sup> छात्र-संख्या की यह वृद्धि—देश के समस्त शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी की दुःसाध्य समस्या उपस्थित कर देगी।

इस प्रकार, छात्र-संख्या की वृद्धि से दो गम्भीर समस्याएँ सम्बद्ध हैं—छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के लिए शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था और शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगारों की व्यवस्था। “कोठारी कमिशन” ने इन दोनों समस्याओं का समाधान असम्भव बताने हुए लिखा है :—“हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था न तो इस पैमाने पर उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए घन जुटा सकती है और न उसमें लाखों स्नातकों के लिए उपयुक्त रोजगारों की व्यवस्था करने की क्षमता है।”

“An economy like ours can neither have the funds to expand higher education on this scale, nor the capacity to find suitable employment for the millions of graduates.”—Kothari Commission Report, p 305

1. *India*, 1974, p. 50.

2. *Kothari Commission Report*, p. 305.

में विभाजित न हो, तो अंग्रेजी के स्थान पर 14 क्षेत्रीय भाषाओं को स्थापित करना राष्ट्र के लिए बहुत सराव सौदा होगा।”

श्री राजगोपालाचार्य के विरोध के बावजूद भी भारत-सरकार के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री, डा० त्रिगुण नेन ने यह घोषणा की कि उच्च शिक्षा की नव संस्थाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को 5 वर्ष की अवधि में शिक्षा का माध्यम बना दिया जाय।<sup>1</sup> किन्तु, अंग्रेजी के उपासकों द्वारा इस घोषणा का इतना ज्वरदस्त विरोध किया गया कि अपनी असाधारण हृदता के बावजूद भी डा० नेन उनका सामना न कर सके और उनको अपना त्याग-पत्र देना पड़ा।

शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर अब भी विवाद चल रहा है। इस प्रश्न को लेकर शिक्षाविदों के दो दल बन गए हैं। एक दल अंग्रेजी का समर्थक है और दूसरा—क्षेत्रीय भाषाओं का।

समाधान—शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषाएँ : Regional Languages as Medium of Instruction—शिक्षा के माध्यम की समस्या का समाधान करने का केवल एक उपाय है। वह यह कि क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित किया जाय। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति अपनी ही मातृभाषा में दूसरों के विचारों को भली-भाँति समझ सकता है और अपने विचारों को प्रकट कर सकता है।

अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों की मातृभाषा अर्थात् क्षेत्रीय भाषा को न केवल उच्च शिक्षा के स्तर पर, वरन् सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। हमारे राष्ट्रीय नेताओं—टैगोर, नेहरू और गाँधीजी का अपने देशवासियों को यही परामर्श था। सम्भवतः उस परामर्श की उपयोगिता में ही प्रभावित होकर “राधाकृष्णन् कमीशन”, “कोठारी कमीशन”, “भावार्थक एकता-समिति” (Emotional Integration Committee), उपकुलपतियों के सम्मेलन (1967) और भारत-सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को ही माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इस समय 35 विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम—क्षेत्रीय भाषाएँ हैं और 17 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर-स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है।”<sup>2</sup>

इस स्थान पर अंग्रेजी के सम्बन्ध में दो शब्द लिए देना सम्भवतः अप्रानयित न होगा। यदि हम क्षेत्रीय भाषाओं के मोह में फँसकर, अंग्रेजी में सदैव के लिए अपना नाता तोड़ देंगे, तो यह हमारी बड़ी भयंकर भूल होगी। उच्च शिक्षा की

1. *Times of India*, July 20, 1967.

2. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 518.

में विभाजित न हो, तो अंग्रेजी के स्थान पर 14 क्षेत्रीय भाषाओं को स्थापित करना राष्ट्र के लिए बहुत खराब सोचा होगा।”

श्री राजगोपालाचार्य के विरोध के बावजूद भी भारत-सरकार के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री, डा० विष्णु मेन ने यह घोषणा की कि उच्च शिक्षा की सब संस्थाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को 5 वर्षों की अवधि में शिक्षा का माध्यम बना दिया जाय।<sup>1</sup> किन्तु, अंग्रेजी के उपासकों द्वारा इस घोषणा का इतना ज्वरदस्त विरोध किया गया कि अपनी असाधारण दृढ़ता के बावजूद भी डा० मेन उसका सामना न कर सके और उनको अपना त्याग-पत्र देना पड़ा।

शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर अब भी विवाद चल रहा है। इस प्रश्न को लेकर शिक्षाविदों के दो दल बन गए हैं। एक दल अंग्रेजी का समर्थक है और दूसरा—क्षेत्रीय भाषाओं का।

**समाधान—शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषाएँ : Regional Languages as Medium of Instruction**—शिक्षा के माध्यम की समस्या का समाधान करने का केवल एक उपाय है। वह यह कि क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित किया जाय। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति अपनी ही मातृभाषा में दूसरों के विचारों को भली-भाँति समझ सकता है और अपने विचारों को प्रकट कर सकता है।

अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों की मातृभाषा अर्थात् क्षेत्रीय भाषा को न केवल उच्च शिक्षा के स्तर पर, बल्कि सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। हमारे राष्ट्रीय नेताओं—टैगोर, नेहरू और गांधीजी का अपने देशवासियों को यही परामर्श था। सम्भवतः इस परामर्श की उपयोगिता से ही प्रभावित होकर “सामाजिक-कमीशन”, “कोठारी कमीशन”, “भावात्मक एकता-समिति” (Emotional Integration Committee), उपकुलपतियों के सम्मेलन (1967) और भारत-सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को ही माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इस समय 35 विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम—क्षेत्रीय भाषाएँ हैं और 17 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर-स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है।<sup>2</sup>

इस स्थान पर अंग्रेजी के सम्बन्ध में दो बातें जितना सम्भवतः अप्रामाणिक न होना। यदि हम क्षेत्रीय भाषाओं के मोह में फँसकर, अंग्रेजी से संदेह के लिए अपना नाका तोड़ देंगे, तो यह हमारी बड़ी भयंकर भूल होगी। उच्च शिक्षा की

1. *Times of India*, July 20, 1967.

2. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 518.

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—छात्रों की बढ़ती हुई संख्या से उत्पन्न होने वाली उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए, “कोठार कमिशन” ने 3 सुझाव दिए हैं, यथा :—

1. चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली का प्रयोग ।
2. स्नातक-पूर्व स्तर पर कला एवं वाणिज्य की कक्षाओं में छात्र-संख्या की वृद्धि पर अंकुश ।
3. स्नातक-पूर्व स्तर पर कृषि, शिक्षण और इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था ।

जहाँ तक दूसरे और तीसरे सुझाव का प्रश्न है, शिक्षा-मर्मज्ञों में किंगी प्रकाश का मतभेद नहीं है । परन्तु, पहले सुझाव के सम्बन्ध में उनमें मतभेद नहीं है । कुछ शिक्षा-विशेषज्ञों ने “चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली” का जोरदार विरोध करते हुए कहा है कि प्रजातन्त्र की गुरुवृत्ता की दृष्टि से नवयुवकों की उच्च शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाना सर्वथा अनुचित है । उनके विपरीत, इस “प्रणाली” के समर्थकों ने इसके पक्ष में 2 अकादमिक तर्क दिए हैं । पहला, उच्च शिक्षा में होने वाले विशाल अपव्यय को रोकने और इस शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, “चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली” का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । दूसरा, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में उर्ध्व छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, जिनमें उसे प्राप्त करने की योग्यता है और जिनके लिए यह जीवन में उपयोगी सिद्ध हो ।

“चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली” को “केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड” और “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० देशमुख का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है । डा० देशमुख ने इस “प्रणाली” का देश के लिए शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता एवं उपलब्ध-आर्थिक साधनों के आधार पर समर्थन करते हुए कहा है :—  
“यदि उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध सीमित साधनों की अपव्यय से रक्षा की जानी है, तो विश्वविद्यालयों में छात्रों को चयन के आधार पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए ।”

“Admission to universities should be on a Selective Basis in view of the limited resources available for higher education are not to be frittered away.”—Dr. C. D. Deshmukh, Chairman, U. G. C. 1960.

10. समस्या—शिक्षा का निम्न स्तर : Low Standard of Education—हमें चतुष्पाद यह सुनिश्चित देना है कि आज की शिक्षा ने पहली शिक्षा कहीं ज्यादा अच्छी की । पहले बी० ए० पास व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी विद्वान और बोलता था, पर आज के एम० ए० पास व्यक्ति को न तो अंग्रेजी आती है और न हिन्दी । हमने यह सिद्ध होता है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का स्तर पहले से बहुत अधिक गिर गया



समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—छात्रों की बढ़ती हुई संख्या से उत्पन्न होने वाली उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए, "कोठारी कमिशन" ने 3 सुझाव दिए हैं, यथा :—

1. चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली का प्रयोग ।
2. स्नातक-पूर्व स्तर पर कला एवं वाणिज्य की कक्षाओं में छात्र-संख्या की वृद्धि पर अंकुश ।
3. स्नातक-पूर्व स्तर पर कृषि, शिक्षण और इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था ।

जहाँ तक दूसरे और तीसरे सुझाव का प्रश्न है, शिक्षा-मन्त्रियों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । परन्तु, पहले सुझाव के सम्बन्ध में उनमें मतव्यता नहीं है । कुछ शिक्षा-विशेषज्ञों ने "चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली" का जोरदार विरोध करते हुए कहा है कि प्रजातन्त्र की सुदृढ़ता की दृष्टि से नवयुवकों की उच्च शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाना सर्वथा अनुचित है । उनके विपरीत, इस "प्रणाली" के समर्थकों ने इसके पक्ष में 2 अकाट्य तर्क दिए हैं । पहला, उच्च शिक्षा में होने वाले विनाश अपव्यय को रोकने और इस शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए "चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली" का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । दूसरा, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, जिनमें उसे प्राप्त करने की योग्यता है और जिनके लिए वह जीवन में उपयोगी सिद्ध हो ।

"चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली" को "केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड" और "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० देशमुख का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है । डा० देशमुख ने इस "प्रणाली" का देश के लिए शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता एवं उपलब्ध-आर्थिक साधनों के आधार पर समर्थन करते हुए कहा है :—  
"यदि उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध सीमित साधनों की अपव्यय से रक्षा की जानी है, तो विश्वविद्यालयों में छात्रों को चयन के आधार पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए ।"

"Admission to universities should be on a Selective Basis if the limited resources available for higher education are not to be frittered away."—Dr. C. D. Deshmukh, Chairman, U. G. C., 1960.

10. समस्या—शिक्षा का निम्न स्तर : Low Standard of Education—हमें बहुधा यह गुनाह देना है कि आज की शिक्षा में पहली शिक्षा कहीं ज्यादा अच्छी थी । पहले बी० ए० पास व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना और लिखना था, पर आज के एम० ए० पास व्यक्ति को न तो अंग्रेजी आती है और न हिन्दी । हमने सिद्ध होता है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का स्तर पहले से बहुत अधिक गिर गया

है। इस पर चिन्ता प्रकट करते हुए, आयरन ने लिखा है :—“हमारे ज्ञान या शिक्षण का स्तर यों तो कभी भी ऊँचा नहीं था, पर अब तो वह तीव्र गति से नीचे की ओर जा रहा है।”

“Our standards whether in scholarship or teaching never very high or exacting, are now fast racing to the bottom.”—K. R. V. Iyengar : *A New Deal for Our Universities*, p. 29.

यस्तुतः जब किसी वस्तु का स्तर एक बार गिरना आरम्भ हो जाता है, तब वह फिर अपने पुराने स्तर पर नहीं पहुँच पाती है। यही बात उच्च शिक्षा के विषय में बही जा सकती है। इसका स्तर वर्षों में निरन्तर गिरता चला जा रहा है, और इसलिए इसका अपनी पूर्वं स्थिति की पुनः प्राप्ति करना असम्भव प्रतीत होता है। इसका कारण बताते हुए, डा० मुकर्जी ने लिखा है :—“शिक्षा का स्तर एक बार गिर जाने पर फिर ऊँचा नहीं उठता है, क्योंकि उस पर प्रेशम का नियम लागू हो जाता है।”

“Academic standards once lowered are not retrievable, and Gresham's law is applicable to them” - S N. Mukerji : *Administration of Education in India*, p. 231

समाधान—कुछ सुझाव Some Suggestions—यद्यपि डा० मुकर्जी के अनुसार, उच्च शिक्षा को अपने पूर्वं स्तर पर नहीं पहुँचाया जा सकता है, पर यदि इस कार्य की धैर्य, लगन और परिश्रम से किया जाय, तो इसमें गतिता सम्भव प्राप्त हो सकती है। इसी विश्वास में चल प्राप्त करने, शिक्षा-स्तर के गिरावट के प्रमुख कारणों और उनके निवारण के उपायों की पर्चा की जा रही है, यथा :—

1. कारण—प्रवेश-नौति में असमानता—शिक्षा-स्तर के गिरावट का पहला कारण—विश्वविद्यालयों की प्रवेश-नौति में असमानता है। उदाहरणार्थ—आम्र और अग्रामलाई विश्वविद्यालयों में “प्री-यूनीवर्सिटी क्लास” में प्रवेश की न्यूनतम आयु 14½ वर्ष है। दिल्ली, बरोडा और गुजरात में यह आयु 15 वर्ष है। मद्रास, कर्नाटक, कुरुक्षेत्र और आदमपुर विश्वविद्यालयों में “निवर्षीय द्वितीय पाठ्यक्रम” में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15½ वर्ष है।

प्रवेश-नौति में समानता न होने के कारण अग्रिमवर्ष अवस्था वाले छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव—शिक्षा के स्तर पर पड़ता है और वह गिर जाता है।

उपचार—प्रवेश-नौति में समानता—शिक्षा-स्तर का उन्नयन करने के लिए सब विश्वविद्यालयों में प्रवेश-नौति का समान होना आवश्यक है। उनमें केवल परिश्रम अवस्था वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। “वेस्टी”



recommends the pattern of 5 + 3 + 4, meaning five years of primary education, followed by 3 years of junior or lower secondary and 4 years of higher secondary stage."—The All-India Secondary Teachers' Federation, Seminar on Secondary Education, 1962.

1963-64 में होने वाले राज्यों के "शिक्षा-मंत्रियों के सम्मेलन" ने 11 वर्षीय विद्यालय-शिक्षा के विचार को अस्वीकार किया। 1966 में "कोटारो-कमीशन" ने 12 वर्ष की विद्यालय-शिक्षा का अनुमोदन किया (7 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा और 5 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा)।

12 वर्षीय विद्यालय-शिक्षा की योजना पर इतना अधिक बल दिए जाने के बावजूद भी अनेक राज्यों में इस योजना की प्रत्यक्ष अवहेलना की जा रही है। कथन: मानसिक परिपक्वता में पूर्ण हो छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है। इन छात्रों में उच्च अध्ययन की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। परिणामतः शिक्षा का स्तर गिर जाता है।

उपचार—12 वर्षीय विद्यालय-शिक्षा-योजना का कार्यान्वयन—मह राज्यों में 12 वर्षीय विद्यालय-शिक्षा की योजना का अनिवार्य रूप में कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। भाष्य-मर्यादा द्वारा यह नियम बना दिया जाना चाहिए कि 12 वर्ष की विद्यालय-शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाय। इन छात्रों की मानसिक क्षमताओं का पर्याप्त विस्तार हो जाता है। अतः उनको विभिन्न विषयों का उच्च अध्ययन करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। पर्याप्त, शिक्षा-स्तर के गिरावट की आशंका समाप्त हो जायगी।

5. कारण—शिक्षण का निम्न स्तर—शिक्षा-स्तर के गिरावट का सर्वप्रधान कारण—शिक्षण का निम्न स्तर है। इसका उत्तरदायित्व मुख्यतः अध्यापकों पर है, जो कक्षा-शिक्षण में व्याख्यान-विधि के अतिरिक्त भूल कर भी किसी अन्य विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। यह आश्चर्य में इस विधि का प्रयोग करने क्यों हैं? इसका एक-मात्र कारण है—इस विधि की सरलता। यह देखा गया है कि प्रत्येक अध्यापक अपने व्याख्यान के चोटों में प्रारम्भिक वर्षों में परिश्रम करके, अपने व्याख्यानों को बेकार पर गया है। लक्ष्यरहित, वह उनमें किसी प्रकार का परिश्रम या नवीनीकरण लिए बिना अवकाश ग्रहण करने के सममय उनको कक्षा में दोहराता रहता है। शिक्षण की मिलनी सरल विधि है। इसको प्रयोग करके, शिक्षक अपनी जक्ति, समय एवं परिश्रम की मजत करता है और छात्रों में अपने दिन गुजारता है।

व्याख्यान-विधि किसी समय उपयोगी थी, पर अब इसकी उपयोगिता नष्ट हो चुकी है। इसका कारण सेवुअल जॉर्जसन के शब्दों में सुनिष्ठ :—“व्याख्यान किसी समय लाभप्रद थे, पर अब जबकि सब शक्ति पढ़ सकने हैं और पुस्तकें इतनी विस्तृत संख्या में हैं, व्याख्यान अनावश्यक हो गये हैं।”

"Lectures were once useful, but now when all can read, and books are so numerous, lectures are unnecessary."—Samuel Johnson. Quoted in Boswell's *Life of Johnson*.

छात्रों की दृष्टि में व्याख्यान-विधि की जितनी कड़ी निन्दा की जाय, उतनी ही कम है। वे या तो निष्क्रिय श्रोताओं के समान बसा में बैठे रहते हैं, या धुनचाव बाहर सिमक कर मनोरंजन की खोज करते हैं। दोनों प्रकार के छात्रों को व्याख्यान के व्याख्यानों में रचमाय भी लाभ नहीं होता है। अतः उनके ज्ञान की वृद्धि की आशा करना व्यर्थ है, पर उनके मौखिक स्तर के गिरावट की आशा करना व्यर्थ नहीं है।

उपचार—शिक्षण में सुधार—“शिक्षा-आयोग” ने शिक्षण में सुधार किए जाने पर बल देते हुए लिखा है—“उच्च शिक्षा में किए जाने वाले सबसे अधिक आवश्यक सुधारों में से एक यह है कि शिक्षण में सुधार किया जाय।”

“One of the most important reforms needed in higher education is to improve teaching.”—*Education Commission Report*, p. 286.

“शिक्षा-आयोग” ने शिक्षण में सुधार करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया है, यथा :—औपचारिक बसा-नाय के समय में बसो, बचने वाले समय का ट्यूटोरियल कार्य एवं विचार-गोष्ठियों में प्रयोग, छात्रों द्वारा स्वतन्त्र अध्ययन, छात्रों की रटने की प्रवृत्ति का दमन, छात्रों की मौखिक चिन्तन एवं समस्या-समाधान के लिए प्रोत्साहन, प्रयोगशाला-कार्य पर बल, उत्तम पुस्तकालयों की व्यवस्था, छात्रों द्वारा पुस्तकालयों का अधिक प्रयोग, इत्यादि।

केरल विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डा० के० सी० राजा का एक प्रसक्तनीय सुभाष यह है कि बच्चों और विश्वविद्यालयों में प्रथम बार नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए सेवा-पूर्व प्रशिक्षण (Pre Service Training) की व्यवस्था की जाय। इस प्रशिक्षण में उनको अपने विभागों के गवर्नर, शिक्षण की उपयोगी विधियों और अपने छात्रों को ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने के विविध उपायों से अवगत कराया जाय। इस प्रशिक्षण की आवश्यकता बताते हुए, डा० राजा ने कहा—“यह धारणा अनुचित प्रतीत होती है कि एम० ए० की परीक्षा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले शक्ति में अपने विषय की शिक्षा देने की पर्याप्त योग्यता होती है। उसे सेवा-पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता है।”

“The assumption that a man with a first or second class M. A. in his own subject is adequately equipped for teaching that subject seems hardly justified. He needs pre service training”—*Dr. K. C. Raja* “The Changing University”, *A Symposium, Educational Quarterly*, December, 1962, p. 219.

recommends the pattern of 5-+-3-+-4, 'meaning five years of primary education, followed by 3 years of junior or lower secondary and 4 years of higher secondary stage.'—The All-India Secondary Teachers' Federation, Seminar on Secondary Education, 1962.

1963-64 में होने वाले राज्यों के "शिक्षा-मंत्रियों के सम्मेलन" ने 11 वर्षीय विद्यालय-शिक्षा के विचार को अस्वीकार किया। 1966 में "कोठारी-कमीशन" ने 12 वर्ष की विद्यालय-शिक्षा का अनुमोदन किया (7 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा और 5 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा)।

12 वर्षीय विद्यालय-शिक्षा की योजना पर इतना अधिक बल दिए जाने के बावजूद भी अनेक राज्यों में इस योजना की प्रत्यक्ष अवहेलना की जा रही है। फलतः मानसिक परिपक्वता से पूर्व ही छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है। इन छात्रों में उच्च अध्ययन की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। परिणामतः शिक्षा का स्तर गिर जाता है।

उपचार—12 वर्षीय विद्यालय-शिक्षा-योजना का कार्यान्वयन—सब राज्यों में 12 वर्षीय विद्यालय-शिक्षा की योजना का अनिवार्य रूप से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। भारत-सरकार द्वारा यह नियम बना दिया जाना चाहिए कि 12 वर्ष की विद्यालय-शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाय। इन छात्रों की मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विस्तार हो जाता है। अतः उनको विभिन्न विषयों का उच्च अध्ययन करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। फलस्वरूप, शिक्षा-स्तर के गिरावट की आशंका समाप्त हो जायगी।

5. कारण—शिक्षण का निम्न स्तर—शिक्षा-स्तर के गिरावट का सर्वप्रधान कारण—शिक्षण का निम्न स्तर है। इसका उत्तरदायित्व मुख्यतः अध्यापकों पर है, जो कक्षा-शिक्षण में व्याख्यान-विधि के अतिरिक्त भूल कर भी किसी अन्य विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। पर आश्चर्य के इस विधि का प्रयोग करते क्यों हैं? इसका एक-मात्र कारण है—इस विधि की सरलता। यह देखा गया है कि प्रत्येक अध्यापक अपने सेवा-काल के बोझ से प्रारम्भिक वर्षों में परिश्रम करके, अपने व्याख्यानों को तैयार कर लेता है। तदुपरान्त, वह उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या नवीनीकरण किए बिना अवकाश ग्रहण करने के समय तक उनको कक्षा में दोहराता रहता है। शिक्षण की कितनी सरल विधि है। इसको प्रयोग करके, शिक्षक अपनी शक्ति, समय एवं परिश्रम की बचत करता है और आराम से अपने दिन गुजारता है।

व्याख्यान-विधि किसी समय उपयोगी थी, पर अब इसकी उपयोगिता नष्ट हो चुकी है। इसका कारण मुख्यतः जॉन्सन के शब्दों में मुनिग :—“व्याख्यान किसी समय लाभदायक था, पर अब जबकि सब व्यक्ति पढ़ सकते हैं और पुस्तकें इतनी विशाल संख्या में हैं, व्याख्यान अनावश्यक हो गये हैं।”

"Lectures were once useful, but now when all can read, and books are so numerous, lectures are unnecessary."—Samuel Johnson. Quoted in Boswell's *Life of Johnson*.

छात्रों की दृष्टि में व्याख्यान-विधि की जितनी बड़ी निन्दा की जाय, उतनी ही कम है। वे या तो निष्क्रिय श्रोताओं के समान बड़ा मे बँठे रहते हैं, या पुनराव बाहर चिमक कर मनोरंजन की सोच करते हैं। दोनों प्रकार के छात्रों को व्याख्यान के व्याख्याता में रचनात्मक भी लाभ नहीं होता है। अतः उनके ज्ञान की वृद्धि की आशा करना व्यर्थ है, पर उनके मौखिक स्तर के गिरावट की आशा करना व्यर्थ नहीं है।

उपचार—शिक्षण में सुधार—“शिक्षा-आयोग” ने शिक्षण में सुधार किए जाने पर बल देने हुए लिखा है —“उच्च शिक्षा में किए जाने वाले सबसे अधिक आवश्यक सुधारों में से एक यह है कि शिक्षण में सुधार किया जाय।”

“One of the most important reforms needed in higher education is to improve teaching.”—*Education Commission Report*, p. 286.

“शिक्षा-आयोग” ने शिक्षण में सुधार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया है, यथा —औपचारिक बड़ा-कार्य के समय में बसो, बचने वाले समय का द्यूटोरियम कार्य एवं विचार-मोष्टियों में प्रयोग, छात्रों द्वारा स्वतन्त्र अध्ययन, छात्रों की गृह की प्रवृत्ति का ध्यान, छात्रों को मौखिक चिन्तन एवं समस्या-समाधान के लिए प्रोत्साहन, प्रयोगशाला-कार्य पर बल, उनमें पुनर्वासियों की व्यवस्था, छात्रों द्वारा पुनर्वासियों का अधिक प्रयोग, इत्यादि।

केरल विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डा० के० सी० राजा का एक प्रणमनीय सुभाष यह है कि बच्चों और विश्वविद्यालयों में प्रथम बार नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए सेवा-पूर्व प्रशिक्षण (Pre Service Training) की व्यवस्था की जाय। इस प्रशिक्षण में उनको अपने विभागों के मंचान्त, शिक्षण उपयोगी विधियों और अपने छात्रों को ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने के वि उपायों में अवगत कराया जाय। इस प्रशिक्षण की आवश्यकता बनाने हुए, डा० ने कहा :—“यह धारणा अनुचित प्रतीत होती है कि एम० ए० की परीक्षा में या द्वितीय घंटी में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति में अपने विषय की शिक्षा देने पर्याप्त योग्यता होती है। उसे सेवा-पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता है।”

“The assumption that a man with a first or second M. A. in his own subject is adequately equipped for teaching subject seems hardly justified. He needs pre service training.”—*Dr. K C Raja “The Changing University”, A Symposium, Annual Quarterly, December, 1962. p. 219*

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. Write a brief commentary on the development of University Education in India since 1947. Do you think the development satisfactory ? If not, suggest ways to improve our university education.

भारतवर्ष में सन् 1947 ई० से अब तक विश्वविद्यालय-शिक्षा के विकास पर एक संक्षिप्त आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। क्या इस विकास को आप संतोषजनक समझते हैं ? यदि नहीं, तो हमारी विश्व-विद्यालय-शिक्षा को समुन्नत करने के लिए सुझाव दीजिए।

2. What are the main defects of University Education in India ? What reforms have been suggested by the Kothari Commission of 1964 to improve University Education ?

भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा के प्रमुख दोष क्या हैं ? 1964 के कोटारी आयोग ने विश्वविद्यालय-शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए किन सुधारों का सुझाव दिया है ?

3. "There has been the 'Open-door' policy of admissions to Colleges and Universities for higher education in our country which has led to an overproduction of graduates". Discuss this statement enlightening upon the various problems that have cropped up due to the policy. Also discuss the suggestions or recommendations of the Kothari Commission to meet this growing heavy rush for admissions to Higher Education.

"हमारे देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु घुले द्वार की नीति रही है जिसने स्नातकों की भारी भीड़ को जन्म दिया है।" इस कथन की विवेचना इस नीति के कारण उत्पन्न हुई विविध समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कीजिए। यह भी बताइए कि उच्च शिक्षा में प्रवेश चाहने हेतु इस निरन्तर बढ़ती हुई भीड़ की समस्या के विषय में कोटारी आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं ?

# 26

## शिक्षक-शिक्षा (प्रशिक्षण)

### TEACHER EDUCATION (TRAINING)

"Investment in teacher-education can yield very rich dividends, because the financial resources required are small when measured against the resulting improvements in the education of millions"—*Kothari Commission Report.*

#### विषय-प्रवेश

भारत में ही नहीं, अविशुद्ध सभ्यता में शिक्षण को एक उन्नत व्यवसाय माना गया है। मानव-इतिहास की स्पष्टतम विधुतियों ने इस व्यवसाय को अपनाया है। समस्त युगों के समस्त धार्मिक नेताओं और सम्राज-मुपारकों ने इस व्यवसाय को अंगीकार करके, इसके गौरव में अभिवृद्धि की है। बुद्ध, ईसा, गांधी, मुहम्मद, कन्फ्यूशियस—ये सभी सच्चे अर्थ में मानव-जाति के शिक्षक थे। उन्होंने अपने समय के सामान्य व्यक्तियों द्वारा जीवन में स्वीकार किए जाने वाले मानदण्डों का माहुर और ईमानदारी से विश्लेषण किया और उनको उच्चतर जीवन के आदर्शों एवं कल्पना से परिवर्तित कराया। उनकी महानता इस बात में है कि वे अपनी इन कल्पना को साकार बनाने में तन-मन में जुटे रहे और उन्होंने इन कार्य में विषीन होकर, स्वयं अपने व्यक्तित्व की महाराज्यों में लोकोत्तर शक्तियाँ खोज लीं।

हमारे इस युग के शिक्षक भी इन महात्माओं के चल-विह्वलों का अनुगमन करें, अपने देश एवं राष्ट्र के लिए अधिक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें हैं। इसीलिए, आज के शिक्षक को बालकृष्ण जोशी का यह परामर्श है :—'शिक्षक को अपने को केवल धर्मगुरु नहीं समझना चाहिए, जिसका कार्य 10 बजे आरम्भ

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. Write a brief commentary on the development of University Education in India since 1947. Do you think the development satisfactory ? If not, suggest ways to improve our university education.

भारतवर्ष में सन् 1947 ई० से अब तक विश्वविद्यालय-शिक्षा के विकास पर एक संक्षिप्त आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। क्या इस विकास को आप संतोषजनक समझते हैं ? यदि नहीं, तो हमारी विश्व-विद्यालय-शिक्षा को समुन्नत करने के लिए सुझाव दीजिए।

2. What are the main defects of University Education in India ? What reforms have been suggested by the Kothari Commission of 1964 to improve University Education ?

भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा के प्रमुख दोष क्या हैं ? 1964 के कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय-शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए किन सुधारों का सुझाव दिया है ?

3. "There has been the 'Open-door' policy of admissions to Colleges and Universities for higher education in our country which has led to an overproduction of graduates". Discuss this statement enlightening upon the various problems that have cropped up due to the policy. Also discuss the suggestions or recommendations of the Kothari Commission to meet this growing heavy rush for admissions to Higher Education.

"हमारे देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु खुले द्वार की नीति रही है जिसने स्नातकों की नारी भीड़ को जन्म मिला है।" इस कथन की विवेचना इस नीति के कारण उत्पन्न हुई विविध समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कीजिए। यह भी बताइए कि उच्च शिक्षा में प्रवेश चाहने हेतु इस निरन्तर बढ़ती हुई भीड़ की समस्या के विषय में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं ?

## 26

### शिक्षक-शिक्षा (प्रशिक्षण) TEACHER EDUCATION (TRAINING)

"Investment in teacher-education can yield very rich dividends, because the financial resources required are small when measured against the resulting improvements in the education of millions"—Kothari Commission Report.

#### विषय-प्रवेश

भारत में ही नहीं, अगिनु मण्ण ममार म शिक्षण को तर उदात्त व्यवसाय माना गया है। मानव-विकास की श्रेष्ठतम विधुनियो ने इस व्यवसाय को अपनाया है। समस्त युगों के समस्त धार्मिक नेताओं और समाज गुणारकों ने इस व्यवसाय को अंगीकार करते, इसके गौरव में अभिप्राय को है। बुद्ध, ईसा, गीषी, मुकरान, मुहम्मद, बनारसजीयम—ये सभी मन्वे अर्ध में मानव-जाति के शिक्षण में। उन्होंने अपने समय के सामान्य व्यक्तियों द्वारा जीवन में स्वीकार किए जाने वाले मानदण्डों का साहस और ईमानदारी में विवेचन किया और उनका उच्चतर जीवन के आदर्श एवं कल्पना में परिचित कराया। उनकी महानता इस बात में है कि वे अपनी इस होशर, स्वयं अपने व्यक्तित्व की महानता में लोकोत्तर शक्तियों को निरानी करके, अपने देश एवं राष्ट्र के लिए अधिक उन्नत मविव्य का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए, आज के शिक्षक की घालकृष्ण जोशी का यह परामर्श है :—'शिक्षक को अपने को केवल धमजोबी नहीं समझना चाहिए, जिसका कार्य 10 बने आरम्भ



होता है और 4 बजे समाप्त होता है, जब वह अपने पैरों की धूल साइकर, जीविका प्रदान करने वाली विद्यालय स्त्री फुँवड़ी से बाहर जा सकता है।”

“A teacher must not regard himself as a mere wage-earner, whose job begins at 10 a. m. and ends at 4 p. m., when he can shake the dust off his feet and walk out of the bread-giving factory.”

—S. Balakrishna Joshi : *Education in Practice*, p. 100.

शिक्षण के उदात्त व्यवसाय के विषय में इन थोड़े-से शब्दों के बाद हम शिक्षक-शिक्षा के उद्भव एवं विकास का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं।

### शिक्षक-शिक्षा का उद्भव व विकास

#### Origin & Development of Teacher-Education

स्वतन्त्र भारत में जिसे “शिक्षक-शिक्षा” की संज्ञा दी गई है, उसे उससे पूर्व “शिक्षक-प्रशिक्षण” कहा जाता था। शिक्षक-प्रशिक्षण का उद्भव प्राचीन भारत में माना जाता है। उस समय से आज तक इसका विकास 4 अस्पष्ट चरणों में हुआ है; यथा<sup>1</sup> :—

1. छात्राध्यापक-पद्धति : Pupil-Teacher System.
2. शिष्यता-पद्धति : System of Apprenticeship.
3. शिक्षक-प्रशिक्षण : Teacher-Training.
4. शिक्षक-शिक्षा : Teacher-Education.

हम निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत शिक्षक-शिक्षा और शिक्षक-प्रशिक्षण के उद्भव एवं विकास पर विहंगम दृष्टिपात कर रहे हैं।

#### प्राचीन काल में शिक्षक-प्रशिक्षण

हमें “महाभारत” के समान प्राचीन ग्रंथों में शिक्षक के गुणों एवं मूल्य शिक्षण-विधियों का वर्णन तो मिलता है, पर शिक्षक-प्रशिक्षण का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। किन्तु, इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि प्राचीन भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। वस्तुतः उस गुरुकुल अनीत में भी शिक्षक-प्रशिक्षण की पद्धति प्रचलित थी। हम अपने इस कथन की पुष्टि निम्नांकित वर्णन से कर रहे हैं।

प्राचीन भारत में शिक्षा केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों तक ही सीमित थी। अतः सामान्य रूप से शिक्षकों के पास कम छात्रों का होना स्वाभाविक था। ऐसी स्थिति में वे अपने छात्रों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान देते थे और उनकी सम्पूर्ण शिक्षा उनके शिक्षकों के व्यक्तिगत निरीक्षण में होती थी। परन्तु, कुछ शिक्षकों की न्यायि

1. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, pp. 362 & 365.

एवं कुशलता के कारण उनके पास मानार्जन के लिए देने अधिक छात्र होते थे कि उनके लिए प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से निर्देशन करना असम्भव था। अतः वे शिक्षण-कार्य में छात्रों की सहायता एवं सहयोग प्राप्त करते थे। वे छात्र—शिक्षण-कार्य किस प्रकार करते थे, इस विषय में डा० थीयरनाथ मुनीशपाषाण ने लिखा है<sup>1</sup> :—“आचार्य या गुरु सबसे ऊपर के वर्गों के छात्रों को पढ़ाने थे। वे विद्यार्थी अपने से निम्न वर्ग के छात्रों को सिखाने थे, और वे अपने से नीचे वर्गों को।”

आचार्य—शिक्षण-कार्य के लिए दिन विद्यार्थियों का चयन करते थे, वे अपनी कक्षाओं में सबसे अधिक अवकाश योग्यता होते थे। वे अधिपति छात्र—‘पित्त-आचार्य’ (Pitta-Acharya) कहलाते थे। वे अपने गुरु के आदेशों के अनुसार निम्न कक्षाओं के छात्रों को शिक्षा देने थे और उनकी प्रगति एवं व्यवहार के सम्बन्ध में समय-समय पर गुरुजी को सूचना देने थे। यदि गुरु जी किसी कार्यवाहक विद्यालय नहीं आते थे, तो भी अधिपति छात्रों की शिक्षा का कार्य विधिवत् चलता रहता था।

उच्च कक्षाओं के अधिपति छात्रों या नायकों (Monitors) द्वारा निम्न कक्षाओं के छात्रों को शिक्षा देने की यह प्रणाली—“कक्षा-नायकीय पद्धति” (Monitorial System) कहलाती थी। इस पद्धति में शिक्षा-विद्यार्थी नामक विषय का कोई स्थान नहीं था। किन्तु, दिन नायकों की शिक्षण कार्य सीता जाता था, उनकी कुछ समय के पश्चात् शिक्षण-विधियों एवं विद्यार्थी-सहायता या पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था। अतः उन्हें स्वतन्त्र रूप से अध्ययन-कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता था।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षण-प्रशिक्षण में औद्योगिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं था। इसके विपरीत, उसमें व्यावहारिक शिक्षण (Practical Teaching) की प्रधानता थी और ‘करके सीखना’ (Learning by Doing) विधि को अपनाया जाता था। प्राचीन भारत में हमी की शिक्षण-प्रशिक्षण का अग्रवर्ग आरम्भ माना जाता है।

### मुस्लिम काल में शिक्षण प्रशिक्षण

भारत में मुस्लिम काल की औद्योगिक व्यवस्था का पुनः माना जाता था। इस काल में अरबों के अनिश्चित और किसी भी सुसंगतता नामक ने शिक्षा में विशेष रुचि की अभिव्यक्ति नहीं की। तदनुसार सभी मुस्लिम नामों के दो प्रमुख उद्देश्य थे—इस्लाम धर्म का प्रचार करना और हिन्दुओं को सुसंगतता बनाना। अतः मुस्लिम काल में शिक्षण-प्रशिक्षण नाम की कोई योजना नहीं थी।

1. डा० थीयरनाथ मुनीशपाषाण भारतीय शिक्षा का इतिहास (आधुनिक काल),

2 | भारतीय जिज्ञा और उमकी नमस्याएँ

वस्तुतः भारत में वैदिक काल से लेकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक शिक्षक-प्रशिक्षण की यदि कोई विधि थी, तो वह "कक्षा-नायकीय पद्धति" थी, जिसे छात्राध्यापक पद्धति" (Pupil-Teacher System) भी कहा जाता है।

### शिक्षक-प्रशिक्षक के प्रारम्भिक प्रयास

भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में डेन मिशनरियों ने पय-प्रदर्शक का कार्य किया। उन्होंने सन् 1716 में ट्रान्स्वूवर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम नार्मन स्कूल स्थापित किया, जहाँ के प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जाता था। तदुपरान्त, उन्होंने सन् 1793 में मीरामपुर में एक और नार्मन स्कूल की सृष्टि की। उनके उत्कृष्ट उदाहरण से प्रभावित होकर, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की "जिज्ञा परिषदों" (Educational Societies) ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण-संस्थाओं का निर्माण किया। इन प्रशिक्षण-संस्थाओं और डेन मिशनरियों के नार्मन स्कूलों में प्राचीन काल से चली आने वाली और कम खर्चीली "छात्राध्यापक-पद्धति" (Pupil-Teacher System) का प्रयोग किया जाता था।

जिस समय भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण का उपयुक्त कार्यक्रम चल रहा था, उस समय सन् 1787 में डा० एण्ड्रयू बेल (Dr. Andrew Bell) मद्रास नगर में अंग्रेजों द्वारा संचालित "मद्रास सैनिक अनाथालय" नामक बालकों के विद्यालय का सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हुआ। उसने अपने विद्यालय में "कक्षा-नायकीय" अर्थात् "छात्राध्यापक-पद्धति" का प्रयोग किया। इंग्लैंड लौटने पर उसने वहाँ इस पद्धति का प्रचार किया। इससे प्रभावित होने के कारण वहाँ के जिज्ञा-मण्डलों ने इसका नमर्दन किया। फलस्वरूप, सन् 1801 से 1845 तक इंग्लैंड के प्राथमिक स्कूलों में इस पद्धति का प्रचलन रहा।

इस पद्धति के अनेक नामकरण हुए हैं; यथा—मद्रास-पद्धति, मनीटर-पद्धति, लैकास्ट्रियन पद्धति, ग्लामो-पद्धति, पेस्टॉनाजी-पद्धति, इत्यादि। यह पद्धति कम खर्चीली होने के साथ-साथ अल्प समय में शिक्षकों के अभाव की पूर्ति के लिए अमोघ प्रयोग थी। यह पद्धति—भारत में निरन्तर से प्रचलित "कक्षा-नायकीय पद्धति" ही का परिमार्जित एवं रूपान्तरित स्वरूप थी। अतः हम कह सकते हैं कि भारत विश्व के अनेक देशों की शिक्षक-प्रशिक्षण की प्रथम विधि प्रदान की।

### ब्रिटिश-काल में शिक्षक-प्रशिक्षण, 1801-1882

ब्रिटिश-काल में सन् 1801 से 1882 तक गूर-सरकारी संगठनों ने शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए श्लाघनीय कार्य किया। परन्तु, उनका यह कार्य—प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण तक ही सीमित था।

सन् 1815 में बम्बई की "देशी जिज्ञा-परिषद्" (Native Education Society) ने 24 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया और उनकी प्राथमिक विद्यालयों

शिक्षण-संगर को ऊँचा उठाने के लिए प्रांत के विभिन्न भागों में प्रबन्धकों (Organisers) के रूप में भेजा ।

सन् 1819 में बंगाल में "कलकत्ता-शिक्षासंस्था-परिषद्" (Calcutta School Society) का निर्माण हुआ । इस "परिषद्" ने "छात्राध्यापक-गठन" के अनुसार शिक्षक-प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ किया । सन् 1825 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के संचालकों ने इस "परिषद्" के कार्य को बत प्रदान करने के लिए 500) रु० मासिक महापत्रा-अनुदान देने की घोषणा की ।

सन् 1826 में मद्रास के गवर्नर, सर थॉमस मुनरो (Sir Thomas Munro) के प्रस्ताव के अनुसार, मद्रास नगर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए "केन्द्रीय स्कूल" (Central School) की मृष्टि की गई ।

उक्त अवधि में गैर-सरकारी गण्डनों के कार्य में अनुप्राणित होकर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण की दिशा में कुछ कदम उठाए । उदाहरणार्थ—बम्बई में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए "नार्मल क्लासेस" (Normal Classes) प्रारम्भ की गई । 1849 में कलकत्ता में एक नार्मल स्कूल स्थापित किया गया और अगले 10 वर्षों में बंगाल के विभिन्न भागों में नार्मल स्कूलों का निरन्तर स्थापित किया गया । उत्तरी-पश्चिमी प्रांत में आगरा, मेरठ और बनारस में क्रमशः 1852, 1856 और 1857 में नार्मल स्कूलों की मृष्टि की गई ।

1854 के "वुड के आदेश-पत्र" (Wood's Despatch) ने इस बात पर बल दिया कि प्रादेशिक प्रांत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग स्कूलों और कक्षाओं का स्वीकृत हो निताम्नित किया जाय । "आदेश-पत्र" में कम्पनी के संचालकों ने यह इच्छा व्यक्त की कि छात्रों को प्रशिक्षण-काल में छात्रवृत्तियों एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर, शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाय ।<sup>1</sup>

किन्तु, कम्पनी के भारत-स्थित प्रबंध कार्यचारियों ने संचालकों के आदेश के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया और यत्र-तत्र केवल कुछ प्रशिक्षण-सम्पात्रों की स्थापना कर दी । उनकी इस अवहेलना पर रोद प्रकट करने हुए, सर्वप्रथम भारत-मन्त्रि (Secretary of State for India) लार्ड स्टैनले (Lord Stanley) ने 1859 के अपने "आदेश-पत्र" में लिखा<sup>2</sup> — "कम्पनी के संचालकों ने जिस सीमा तक प्रशिक्षण-विद्यालयों की स्थापना का विचार प्रकट किया था, उस सीमा तक यह कार्य नहीं किया गया है ।"

लार्ड स्टैनले के अपने "आदेश-पत्र" में शिक्षक-प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने और प्रशिक्षण-सम्पात्रों को महापत्रा-अनुदान दिए जाने का आदेश दिया । भारत के अनेक प्रशासकों में सत्ता-हस्तांतरण के पश्चात् भारतीय प्रशासन

1. Wood's Despatch, Para 67.

2. Stanley's Despatch, Para 41

के सर्वोच्च अधिकारी, लार्ड स्टैन्ले के आदेश की अवज्ञा करने का साहस नहीं था। अतः उन्होंने शिक्षक-प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने में अदम्य उत्साह का परिचय दिया। फलस्वरूप, 1881-82 तक सम्पूर्ण देश में 106 नामेल स्कूलों की स्थापना हो गई। इन स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या 3,886 थी और इनका वार्षिक व्यय लगभग 4 लाख रुपए था।<sup>1</sup>

1801 से 1882 तक स्थापित की जाने वाली प्रशिक्षण-संस्थाओं का लक्ष्य केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। इस अवधि में शिक्षकों का वेतन अति न्यून था। अतः प्रशिक्षण-संस्थाओं में केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही प्रवेश लेते थे। उनके पाठ्यक्रम विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न थे। इन पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य—छात्राध्यापकों को केवल उन विषयों का ज्ञान प्रदान करना था, जिनकी उनको शिक्षकों के रूप में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने की आवश्यकता थी।

इन प्रशिक्षण-संस्थाओं में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रारम्भ में 'कक्षा-नायकीय पद्धति' अथवा "छात्राध्यापक-पद्धति (Pupil Teacher System) का प्रयोग किया। किन्तु, कुछ समय के पश्चात् "शिष्यता-पद्धति" (System of Apprenticeship) का अनुसरण किया जाने लगा। इस पद्धति में छात्र को एक निश्चित अवधि के लिए किसी अनुभवी शिक्षक का शिष्य बना दिया जाता था। बम्बई प्रान्त में यह अवधि 3 वर्ष की थी और इस अवधि में प्रत्येक छात्र को 3) २० से 5) २० तक मासिक छात्रवृत्ति मिलती थी। इस अवधि में शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात् छात्रों को कुछ समय तक "जिला ट्रेनिंग कॉलेज" (District Training College) में प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके पश्चात् ही उनकी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित माना जाता था और उनको प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त हो जाता था।

उक्त अवधि की एक अन्य विशेषता—महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए नामेल स्कूलों की स्थापना थी। इनकी स्थापना का श्रेय—टंगलैड की विधुषी, मिस् मैरी कारपेन्टर (Miss Mary Carpenter) को जाता, जिसने इस अवधि में अनेक बार भारत पधार कर, महिला-नामेल स्कूलों के निर्माण के लिए व्यक्तिगत रूप में अथक प्रयास किए। 1881-82 में इन स्कूलों की संख्या 15 थी।<sup>2</sup>

जहाँ तक माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का सम्बन्ध था, उस ओर अति अल्प ध्यान दिया गया। 1882 तक सम्पूर्ण देश में केवल दो प्रशिक्षण संस्थाओं का जिनान्यास हुआ—1856 में मद्रास में 'मधर्नमेन्ट नामेल स्कूल' का

1. Hunter Commission Report, 134.

2. S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 366.

धौर 1877 में "ताहौर ट्रेनिंग स्कूल" का। इन संस्थाओं में स्नातकों और उप-स्नातकों—दोनों को एक ही रक्षा में प्रवेश दिया जाता था। इनमें प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण निम्न कोटि का था, क्योंकि छात्राध्यापकों को शिक्षण के अन्वयागत एवं मिद्धान्तों में ध्यवगत नहीं कराया जाता था। कुछ समय के उपरान्त मद्रास के नार्मल स्कूल में शिक्षण के अभ्यास का प्रबन्ध कर दिया गया था।<sup>1</sup>

### ब्रिटिश-काल में शिक्षक-प्रशिक्षण, 1882-1947

ब्रिटिश-काल में 1882 तक शिक्षकों को किसी प्रकार का वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता था और उनको शिक्षण का कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता था। शिक्षक-प्रशिक्षण की वास्तविक आवश्यकता का अनुभव—"हटर कमीशन" की सिफारिशों के फलस्वरूप किया गया। उसके उपरान्त 1904 धौर 1913 के सरकारी प्रस्तावों, मैहलर कमीशन, हर्टिंग-समिति आदि ने शिक्षक प्रशिक्षण के विषय में नवीन एवं उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए, जिनके फलस्वरूप शिक्षक-प्रशिक्षण का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। हम इन कमीशनों की रिपोर्टों, प्रस्तावों आदि में शिक्षक-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रष्ट किए जाने वाले विचारों का विवेचन उल्लिखित कर रहे हैं; यथा :—

1. हटर कमीशन, 1882 — "हटर कमीशन" अथवा "भारतीय शिक्षा-आयोग" ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए<sup>2</sup> :—

1. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नार्मल स्कूलों की स्थापना हम प्रकार की जाय कि वे सम्पूर्ण देश के प्राथमिक विद्यालयों की माँग को पूर्ति कर सकें।
2. प्रत्येक विद्यालय-निरीक्षक के क्षेत्र में कम-से-कम एक नार्मल स्कूल का निर्माण किया जाय।
3. नार्मल स्कूलों को तत्काल बनाने के लिए, विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उनमें रुचि ली जाय और उनके कुशल संचालन का प्रयत्न किया जाय।
4. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग स्कूलों और ट्रेनिंग कॉलेजों की स्थापना इस प्रकार की जाय कि वे सम्पूर्ण देश में फैल जायें।
5. स्नातकों एवं उपस्नातकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाय।

"हटर कमीशन" के सुझावों के फलस्वरूप नार्मल स्कूलों, ट्रेनिंग स्कूलों और ट्रेनिंग कॉलेजों की आगामीय वृद्धि हुई। साथ ही, सभी स्तरों के शिक्षकों के प्रशिक्षण

1. Stanley's Despatch, Para 23

2. Hunter Commission Report, Paras 2 & 3.

का स्पष्ट चित्र उभर कर सामने आ गया। उनकी सैद्धान्तिक शिक्षा के लिए विभिन्न एवं निश्चित पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया और शिक्षण-अभ्यास का वह कार्यक्रम आरम्भ किया गया, जो आज की प्रशिक्षण-संस्थाओं में दृष्टिगोचर होता है।

“हण्टर कमीशन” के सुझावों के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के अन्त तक 133 नॉर्मल स्कूलों, 50 ट्रेनिंग स्कूलों और 6 ट्रेनिंग कॉलेजों (मद्रास, लाहौर, कुरुतांग, जबलपुर, इलाहाबाद और राजमुन्दरी) की स्थापना की गई।<sup>1</sup>

2. शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, 1904—इस “प्रस्ताव” ने शिक्षक-प्रशिक्षण के समस्त पक्षों की समुचित व्यवस्था पर बल दिया और निम्नांकित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया :—

1. भारतीय शिक्षा-सेवा (Indian Educational Service) में योग्य, अनुभवी एवं उच्च प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाय।
2. माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनिंग कॉलेजों की साज-सज्जा को कला-महाविद्यालयों (Arts Colleges) की साज-सज्जा से कम महत्त्व न दिया जाय।
3. स्नातकों एवं उपस्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि क्रमशः 1 वर्ष और 2 वर्ष निश्चित की जाय।
4. प्रशिक्षण के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों में निकट सम्बन्ध स्थापित किया जाय।
5. प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम “अभ्यासात्मक स्कूल” (Practising School) सम्बद्ध किया जाय।
6. ट्रेनिंग कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में सम्बन्ध स्थापित किया जाय, ताकि प्रशिक्षित शिक्षक सीखी हुई विधियों का व्यावहारिक प्रयोग कर सकें।

उपरिर्वाणित सिद्धान्तों ने शिक्षक-प्रशिक्षण-आन्दोलन में नवीन शक्ति का संचार कर दिया और उनकी मूर्त रूप दिए जाने पर चार महत्त्वपूर्ण परिणाम दृष्टिगोचर हुए :—(1) प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या में वृद्धि, (2) स्नातकों एवं उपस्नातकों के लिए पृथक् पाठ्यक्रमों का आयोजन, (3) स्नातकों एवं उपस्नातकों के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः 1 वर्ष और 2 वर्ष का कार्यक्रम, और (4) प्रत्येक प्रशिक्षण-संस्था से अभ्यासात्मक स्कूल की संलग्नता।

3. लार्ड कर्जन की शिक्षा-नीति—विद्या-प्रेमी लार्ड कर्जन ने शिक्षा के प्रसार के लिए प्राचीन सरदारों की गहायता-अनुदान देने की प्रथा आरम्भ की।

1. S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 368.

2. Government Resolution on Educational Policy, 1904, Para 39

इस प्रथा के फलस्वरूप 5 वर्षों की अवधि में 5 ट्रेनिंग कॉलेजों का गिनाना हुआ; यथा :—(1) एम० टी० कॉलेज, बम्बई, 1906; (2) डेविड हैयर ट्रेनिंग कॉलेज, बलरुता, 1908, (3) पटना ट्रेनिंग कॉलेज, 1908; (4) दाका ट्रेनिंग कॉलेज, 1910, और (5) स्पेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, जबलपुर, 1911।

4 शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, 1913—इस “प्रस्ताव” ने अप्राप्त भूमि निर्धारित करके, शिक्षक-प्रशिक्षण के विषय में अविशेष योग दिया :— ‘शिक्षा की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षक को उस समय तक शिक्षण-कार्य करने की अनुमति प्रदान न की जाय, जब तक कि उसके पास तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र न हो।’

“Under modern system of education, no teacher should be allowed to teach without a certificate that he has qualified to do so.”—*Government Resolution on Educational Policy*, 1913, p. 51.

5 संस्कार कमिशन, 1919—“गैडर कमिशन” अथवा “बलरुता-विश्व-विद्यालय-आयोग” ने शिक्षक-प्रशिक्षण के विषय में अपोतिवित्त सुझाव देकर, उसकी विभाग-प्रक्रिया को नीचेता प्रदान की —

1. प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय।
2. प्रशिक्षण-सम्बन्धी शोध-कार्य की व्यवस्था की जाय।
3. प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा-विभाग की स्थापना की जाय।
4. इन्टर और बी० ए० के पाठ्यक्रमों में शिक्षा विषय को सम्मिलित किया जाय।
5. प्रयोगात्मक कार्य के लिए प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज में “प्रदर्शन स्कूल” (Demonstration School) सम्बद्ध किया जाय।

6. हर्टग-समिति, 1929—इस “समिति” ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए, यथा :—

1. शिक्षकों की सामान्य शिक्षा के स्तर का उन्नयन किया जाय।
2. शिक्षक-प्रशिक्षण की अवधि में वृद्धि की जाय।
3. प्रशिक्षण-संस्थाओं में योग्य एवं कुशल शिक्षकों की नियुक्ति की जाय और उनकी सहाय में पर्याप्त वृद्धि की जाय।
4. विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा-सम्मेलनों एवं अभिनवन पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरम्भ किए जायें।
5. योग्य व्यक्तियों को शिक्षण-कार्य के प्रति आकर्षित करने के लिए, शिक्षकों की कार्य करने की दशाओं में सुधार किया जाय।

उपरिलिखित आयोगों, प्रस्तावों और समिति के सुझावों के परिणामस्वरूप शिक्षक-प्रशिक्षण की दशा एवं सुविधाओं में प्रथम उन्नति होती लगी गई। मनु



1947 में अर्थात् स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 3 प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थाएँ थीं; यथा :—

1. नार्मल स्कूल : Normal Schools—इनमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इनमें प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की थी और मिटिल पास व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता था। सन् 1941 में पुरुष एवं महिला नार्मल स्कूलों की संख्या क्रमशः 346 एवं 236 थी और उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः 22,435 एवं 8,896 थी।<sup>1</sup>

2. माध्यमिक प्रशिक्षण-विद्यालय : Secondary Training Schools—इनमें मिटिल स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इनमें प्रशिक्षण की अवधि 1 या 2 वर्ष की थी और हाईस्कूल एवं इन्टर पास व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता था। सन् 1947 में ट्रेनिंग स्कूलों एवं उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 649 एवं 38,773 थी।<sup>2</sup>

3. प्रशिक्षण महाविद्यालय : Training Colleges—इनमें हाई स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इनमें प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की थी और स्नातकों एवं परस्नातकों को प्रवेश दिया जाता था। सन् 1947 में ट्रेनिंग कॉलेजों एवं उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 51 एवं 3,262 थी।<sup>3</sup>

### स्वतन्त्र भारत में शिक्षक-शिक्षा

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से भारतीय शिक्षा अपने विस्तार के मार्ग पर अति द्रुत गति से अग्रसर हो रही है। फलस्वरूप, शिक्षा के अनेक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की माँग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सम्भवतः इसीलिए हमारे देश की शिक्षा की पुनर्रचना में शिक्षक-प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसकी कार्यवाही और गुणात्मक उन्नति के उपायों को शक्ति करने के लिए शिक्षा आयोगों की नियुक्ति की गई है, उने मफल एवं मायंक बनाने के लिए विविध कार्यक्रमों का समारम्भ किया गया है, और उसकी धारणा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया है। हम इन सब बातों का विवेचन यथास्थान उपस्थित कर रहे हैं।

### शिक्षक-शिक्षा की नवीन धारणा

#### New Concept of Teacher-Education

स्वतन्त्रता से पूर्व शिक्षक-प्रशिक्षण की अद्वितीय संस्थात्मक और गुणात्मक

1. डा० गणेशचन्द्र सिंघल : भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, p. 240.
2. NCERT : *Indian Year-Book of Education*, 1964.
3. NCERT : *The Second National Survey of Secondary Teacher Education in India*, p. 14.

उपनि हुई। किन्तु, उसे प्रशिक्षण के क्षेत्र में आविर्भूत होने वाले नवीन विचारों के अनुकूल बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, उसका स्वरूप गुरु-चित हो गया। अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश के शिक्षाशास्त्रियों एवं राज-नीतिज्ञों ने “शिक्षक-प्रशिक्षण” को नवीन रूप प्रदान करके, उसको अधिक व्यापक बनाया और उसको “शिक्षक-शिक्षा” (Teacher-Education) का नामा जामा पहनाया।

“शिक्षक-शिक्षा” की इस नवीन धारणा के निर्माण में निम्नलिखित कारणों ने विशेष योग दिया<sup>1</sup> —

1. अमरीका के प्रसिद्ध शिक्षा-महारथी, हिल्डेब्रिक् के अनुसार :—“सर्वस में काम करने वाले नरों और पशुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, पर शिक्षकों को शिक्षा दी जाती है।”

“One trains circus performers and animals, but one educates teachers”—W. H. Kilpatrick.

2. स्वतन्त्रता से पूर्व प्रशिक्षण द्वारा शिक्षक में खिल धारणाओं और व्यवहार के प्रतिमानों का निर्माण किया जाता था, उनकी उपयोगिता—स्वतन्त्र भारत के लिए नष्ट हो गई थी।
3. शिक्षक-प्रशिक्षण की धारणा में परिवर्तन करके ही उसे भारत की जनतन्त्रीय मान्यताओं के अनुकूल बनाया जा सकता था।
4. स्वतन्त्र भारत में शिक्षक-शिक्षा के दार्शनिक एवं व्यावहारिक सिद्धान्तों का निर्माण, भारतीय शिक्षाशास्त्रियों द्वारा न, वि विदेशियों द्वारा किया जा रहा था। अतः इसकी धारणा में परिवर्तन किया जाना आवश्यक था।
5. स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण में सुधार किया जाना अनिवार्य था। अतः शिक्षक को प्रशिक्षण देने के बजाय उसे शिक्षा देने की आवश्यकता थी।
6. बेमिह शिक्षा की नवीन विचारधारा के अनुसार, शिक्षक को छात्रों एवं समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अतः शिक्षक को प्रशिक्षण के बजाय शिक्षा दी जानी आवश्यक है।
7. शिक्षक-प्रशिक्षण की विचारधारा में सम्पूर्ण जगत् में अति तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। इस विचारधारा के अनुसार, शिक्षक-प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षक-शिक्षा अधिक व्यापक है।
8. शिक्षक-शिक्षा—जीवन के सब क्षेत्रों को प्रभावित करती है एवं मानवों

के दैनिक जीवन से सम्बन्धित है। अतः केवल कक्षा-शिक्षण का प्रशिक्षण—शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर सकता है।

9. "राधाकृष्णन् कमोशन" ने शिक्षक-प्रशिक्षण की धारणा में यह कह कर परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया :—"सच्ची शिक्षा केवल कुछ पाठों को पढ़ना और स्मरण करना ही नहीं है, बरन् जीवन-यापन एवं उद्देश्यपूर्ण कार्यों में भाग लेना भी है।"

"A real education is not so much a matter of lessons to be learnt and memorized as of a life to be lived and purposeful activities to be shared."—*Radhakrishnan Commission Report*, p. 215.

## शिक्षा-आयोग व शिक्षक-शिक्षा

### Education Commissions & Teacher-Education

स्वतन्त्र भारत में शिक्षक-शिक्षा के विस्तार एवं सुधार के विषय में अग्रान्वित आयोगों के विचार एवं सुझाव सराहनीय हैं :—

1. राधाकृष्णन् आयोग—इस "आयोग" ने शिक्षक-शिक्षा के विषय में निम्नांकित विचार प्रकट किए हैं :—

1. प्रशिक्षण-संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाना चाहिए।
2. शिक्षा-मिद्धान्त (Theory of Education) के पाठ्यक्रम लचीले और स्थानीय वातावरण के अनुकूल होने चाहिए।
3. पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा कक्षा-शिक्षण के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
4. शिक्षण के अभ्यास के लिए केवल उपयुक्त विद्यालयों का ही चयन किया जाना चाहिए।
5. छात्राध्यापकों के कार्य का सुव्यापन करने में उनकी शिक्षण की सफलता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
6. प्रशिक्षण-संस्थाओं के अधिकांश अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ा चुकने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
7. प्रशिक्षण-संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा मौलिक कार्य—अग्नि-भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए।
8. एम० एड० डिग्री प्राप्त करने के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिन्हें कुछ वर्षों का शिक्षण का अनुभव हो।

2. मुद्रासिद्धि आयोग—इस “आयोग” ने शिक्षक-शिक्षा के सम्बन्ध में अधोनिहित सुझाव दिए हैं :—

1. प्रशिक्षण-मंर्यादे केवल दो प्रकार की होनी चाहिए :—(i) माध्यमिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों के लिए । इनकी प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होनी चाहिए । (ii) स्नातकों के लिए । इनकी प्रशिक्षण की अवधि अभी 1 वर्ष की होनी चाहिए, पर कुछ समय के उपरान्त 2 वर्ष की कर दी जानी चाहिए ।
2. छात्राध्यापकों को एक या एक से अधिक अनिवार्य पाठ्य-क्रियाओं (Extra-Curricular Activities) में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।
3. छात्राध्यापकों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको प्रशिक्षण-काल में राज्य द्वारा उपयुक्त निव्यवृत्तियाँ (Stipends) दी जानी चाहिए ।
4. ट्रेनिंग कनिष्ठों में अभिनवन पाठ्यक्रमों (Refresher Courses), विशेष विषयों में गतिवृत्त-समय पाठ्यक्रमों (Short Intensive Courses), कार्यशाळाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training in Workshops) और व्यावसायिक सम्मेलनों (Professional Conferences) की नियमित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए ।
5. शिक्षासचिवों में कार्य करने वाले अग्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण-काल के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए ।
6. अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति करने के लिये अल्पकालीन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ।

3. कोठारी आयोग—इस “आयोग” ने शिक्षक-शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, यथा<sup>1</sup> —

1. पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए ।
2. सब प्रशिक्षण-मंर्यादों में “प्रसार-सेवा-विभाग” (Extension Service Department) का निर्माण किया जाना चाहिए ।
3. सब राज्यों में “समग्र कनिष्ठों” (Comprehensive Colleges) की स्थापना की जानी चाहिए और उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।
4. प्रशिक्षण मंर्यादों में छात्राध्यापकों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं

1. Mukhtar Commission Report, p. 194

2. Kothari Commission Report, pp. 622-623

दिया जाना चाहिए और उनको ऋण एवं छात्रवृत्तियों के रूप में वार्षिक सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय स्तरों पर "शीष्मकालीन संस्थाओं" (Summer Institutes) की योजना आरम्भ की जानी चाहिए।
6. शिक्षक-शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को उन आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दोहराया जाना चाहिए, जिनके लिए अध्यापकों को तैयार किया जा रहा है।
7. प्रत्येक राज्य में "शिक्षक-शिक्षा की राज्य-परिषद्" (State Board of Teacher Education) का निर्माण किया जाना चाहिए, जिस पर सब क्षेत्रों एवं सब स्तरों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

### शिक्षक-शिक्षा का विस्तार

#### Expansion of Teacher-Education

"पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अनुसार<sup>1</sup> :—"तीसरी पंचवर्षीय योजना" के अन्त तक लगभग 23.8 प्रशिक्षित शिक्षक थे (20.2 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 3.6 लाख माध्यमिक स्कूलों में)। "पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अन्त में यह संख्या बढ़कर लगभग 30.4 लाख हो जायगी। पूर्वी भाग के अतिरिक्त देश के सब भागों में प्रशिक्षण-मुविद्याओं का इतना पर्याप्त विस्तार हो गया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है।

स्वतन्त्र भारत में शिक्षक-शिक्षा का विस्तार निम्नांकित तालिका में स्पष्ट किया गया है :—

#### शिक्षक-शिक्षा का विस्तार<sup>2</sup>

विवरण	1950-51	1960-61	1970-71 अंदाजी
ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या	782	1,138	832
ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या	53	478	833
प्रशिक्षित शिक्षक %			
प्राथमरी स्कूल	58.8	64.1	82.9
मिडिल स्कूल	53.3	66.5	84.9
हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल	53.8	64.1	81.2

1. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 198.

2. *India*, 1974, p. 50.

## प्रशिक्षण-संस्थाओं के प्रकार Types of Training Institutions

डा० एस० एन० मुकुर्जी के अनुसार<sup>1</sup> :—मोटे तौर पर हम समय हमारे देश में निम्नलिखित 8 प्रकार की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं :—

1. पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाएँ : Pre-Primary Training Institutions.
2. सामान्य या प्राथमिक प्रशिक्षण-विद्यालय : Normal or Primary Training Schools
3. उन्वितानकों के लिए माध्यमिक प्रशिक्षण—विद्यालय : Secondary Training Schools for Undergraduates.
4. स्नातकों के लिए प्रशिक्षण-महाविद्यालय : Training Colleges for Graduates
5. शिक्षा के प्रादेशिक कॉलेज : Regional Colleges of Education.
6. शिक्षा के राज्य-महाविद्यालय : State Institutes of Education.
7. पत्राचार-पाठ्यक्रम-केन्द्र : Correspondence Course Centres.
8. विशेषज्ञ-प्रशिक्षण-केन्द्र : Training Centres for Specialists.

1. पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण-संस्थाएँ—इनमें पूर्व-प्राथमिक स्तरों के लिए शिक्षकों की प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है, पर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में 2 वर्ष की है। इनमें हाई स्कूल और अपर प्राइमरी पाठ्यक्रमों को प्रवेश दिया जाता है। 1965-66 में इनकी संख्या 59 थी।<sup>2</sup>

पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण-संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, यथा — नर्सरी, माटेमरी, टिचरगाइंट, पूर्व-बैथिक, डीपी एड्युकेशन आदि। हमारे देश में यह प्रशिक्षण अभी अपनी शुरुआत में है। इसीलिए, हम प्रशिक्षण की संस्थाओं की संख्या अत्यंत अल्प है। ये संस्थाएँ 2 प्रकार की हैं —राष्ट्रीय और स्वयं-चालित (Private)। अधिकांश संस्थाएँ स्वयं-चालित हैं और उनको राज्यों में महापदा-अनुदान प्राप्त होता है।

2. सामान्य या प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय —इनमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें यह शिक्षा प्रचलित नहीं है। अन्धप्रदेश और बिहार के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण-संस्थाएँ हैं। 7 संस्थाएँ—राज्य-सरकारों, स्थानीय बोर्डों, व्यक्तिगत प्रबन्धकों आदि के द्वारा संचालित की जाती हैं। 1965-66 में इन संस्थाओं की कुल संख्या 1,604 थी। इनमें से 177 पुरुषों के लिए

1. S. N. Mukerji : op cit p 372

2. IATE : Teacher Training Institutions in India p 9

और 427 मतिज्ञाओं के लिए थीं। इनमें से 923 संस्थाएँ सरकारी थीं और शेष गैर-सरकारी थीं।<sup>1</sup>

इन समय भारत में 2 प्रकार के प्राथमिक विद्यालय हैं :—बुनियादी और गैर-बुनियादी। इसलिए इन विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए दो प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थाएँ भी हैं :—

(1) नामल स्कूल—इनमें हाई स्कूल पास छात्रों को गैर-बुनियादी स्कूलों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के पश्चात् उनको “सीनियर टीचर्स मट्रिफिकेट” प्रदान किया जाता है।

(2) वेसिक ट्रेनिंग स्कूल—इनमें अपर प्राइमरी छात्रों को बुनियादी स्कूलों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के पश्चात् उनको “वेसिक टीचर्स मट्रिफिकेट” प्रदान किया जाता है।

दोनों प्रकार की संस्थाओं में प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की है। 1964-65 में सम्पूर्ण देश में 448 बुनियादी और 153 गैर-बुनियादी प्रशिक्षण-संस्थाएँ थीं।<sup>2</sup> बुनियादी और गैर-बुनियादी का अन्तर समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को वेसिक रूप प्रदान करने का निश्चय कर लिया है।

3. उपस्नातकों के लिए माध्यमिक प्रशिक्षण-विद्यालय—इनमें मिडिल स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें प्रशिक्षण की अवधि कुछ राज्यों में 1 वर्ष की और कुछ में 2 वर्ष की है। इनमें उपस्नातकों अर्थात् हाई स्कूल एवं इन्टर पास व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। 1964-65 में सम्पूर्ण देश में इन प्रशिक्षण-विद्यालयों की संख्या 630 थी।<sup>3</sup>

माध्यमिक प्रशिक्षण-विद्यालयों में अध्ययन करने वाले मफल छात्रों को विश्व-विद्यालयों या राज्य के शिक्षा-विभागों द्वारा मट्रिफिकेट या डिप्लोमा दिए जाते हैं, जिनके विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ—बड़ोदा, बम्बई, गुजरात, मराठवाड़ा और पूना विश्वविद्यालय 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद “T. D.” (Teachers' Diploma) देते हैं। नागूर, नागपुर और जबलपुर विश्वविद्यालय 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद “Dip. T.” (Diploma in Teaching) देते हैं। उड़ीसा राज्य का शिक्षा-विभाग 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद “C. T.” (Certificate of Teaching) देता है। महाराष्ट्र राज्य का शिक्षा-विभाग 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद “S. T. C.” (Secondary Teachers' Certificate) देता है।

4. स्नातकों के लिए प्रशिक्षण-महाविद्यालय—इनमें हाई स्कूलों और हायर मास्टर स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें प्रशिक्षण की

1. S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 375.

2. *Education in India*, 1964-65, Vol. I, p. 287.

3. *Education in India*, 1964-65, Vol. I, p. 287.

अथवा 1 वर्ष की है और स्नातकों एवं परस्नातकों को प्रवेश दिया जाता है। इनमें महाशिक्षा प्रचलित है, विन्तु पुराने एवं महिदाओं के लिए वृषक प्रशिक्षण-महाशाला भी हैं। इनमें अध्ययन करने वाले छात्राध्यापकों को बी० टी० या बी० एड० की उपाधि, डि० एड० का डिप्लोमा या एल० टी० का प्रमाणपत्र दिया जाता है। इनका संचालन—राज्यों के शिक्षा-विभागों या विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। कुछ प्रशिक्षण-महाविद्यालय स्वतंत्र इकाइयाँ हैं और कुछ प्रशिक्षण-कक्षाएँ—जाने-बोले एवं विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षा-विभाग हैं। 1965-66 में सम्पूर्ण भारत में इन महाविद्यालयों और विभागों की संख्या 286 थी।<sup>1</sup>

भारत में प्रशिक्षण-महाविद्यालय दो प्रकार के हैं :—(1) परम्परागत या गैर-बुनियादी (Traditional or Non-Basic) और (2) बुनियादी (Basic)। 1965-66 में 25% बुनियादी महाविद्यालय थे और 75% गैर-बुनियादी।<sup>2</sup>

5. शिक्षा के प्रादेशिक कवित्व —“मुशनिघर कमीशन” का एक सुझाव यह था कि कृषि, वाणिज्य, गृह-विज्ञान, ललित कलाओं आदि की शिक्षा के लिए बहु-उद्देशीय विद्यालयों (Multipurpose Schools) की स्थापना की जाय। परम्परागत प्रशिक्षण-कवित्वों द्वारा इन विषयों की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता था। यह अनुभव करते भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय ने बहु-उद्देशीय विद्यालयों के शिक्षकों को व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विषयों (Practical & Scientific Subjects) में प्रशिक्षण देने के लिए जुलाई, 1963 में 4 प्रादेशिक शिक्षा-महाविद्यालयों (Regional Colleges of Education) की स्थापना की। इन रोजनल कवित्वों की स्थिति एवं प्रादेशिक सीमाएँ इस प्रकार हैं :—

(i) रोजनल कवित्व ऑफ़ ऐज़रुहेसन, भोपाल —यह कवित्व पश्चिमी प्रदेश, अर्घाच गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य-प्रदेश के लिए है।

(ii) रोजनल कवित्व ऑफ़ ऐज़रुहेसन, मैसूर —यह कवित्व दक्षिणी प्रदेश, अर्घाच मद्रास, केरल, मैसूर और आंध्र-प्रदेश के लिए है।

(iii) रोजनल कवित्व ऑफ़ ऐज़रुहेसन भुवनेश्वर —यह कवित्व पूर्वी प्रदेश, अर्घाच मेका, आसाम, बिहार, उड़ीसा, मनीपुर और पश्चिमी बंगाल के लिए है।

(iv) रोजनल कवित्व ऑफ़ ऐज़रुहेसन, जयपुर —यह कवित्व उत्तरी प्रदेश, अर्घाच दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, उत्तर-प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लिए है।

1. IATE Teacher Training Institutions in India, p. 9

2. NCERT Second National Survey of Secondary Teacher Education, p. 113



रीजनल कॉलेजों के मुख्य उद्देश्य अधोलिखित हैं :—

1. बहु-उद्देशीय स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ।
2. शिक्षण की प्रचलित विधियों में सुधार करना, नवीन विधियों को योजना और उनको क्रियान्वित करना ।
3. प्रसार-सेवाओं (Extension Services) के लिए प्रादेशिक केन्द्रों के रूप में कार्य करना ।
4. एक “आदर्श प्रदर्शन बहु-उद्देशीय विद्यालय” (Model Demonstration Multipurpose School) का संगठन एवं विकास करना ।
5. कृषि, शिल्प (Crafts), विज्ञान, वाणिज्य, गृह-विज्ञान और ललित कलाओं की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ।
6. बहु-उद्देशीय स्कूलों में कार्य करने वाले व्यावहारिक विषयों (Practical Subjects) के शिक्षकों के लिए “सेवा-कालीन शिक्षा” (In-Service Education) की व्यवस्था करना ।
7. अपने क्षेत्रों में स्थित बहु-उद्देशीय स्कूलों में सम्बन्धित शिक्षकों, प्रशासकों एवं सुपरवाइजर्स के लिए “सेवा-कालीन शिक्षा” एवं “क्षेत्रीय कार्य” (Field Work) की व्यवस्था करना ।

रीजनल कॉलेजों के कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम (Courses) निम्नलिखित हैं :—

1. सेवाकालीन शिक्षा का अल्पकालीन कोर्स ।
2. बी० एड० का शीघ्रकालीन एवं पन्नाचार-कोर्स ।
3. विज्ञान के शिक्षकों के लिए 4 वर्ष का कोर्स ।
4. प्रौद्योगिकी (Technology) के शिक्षकों के लिए 4 वर्ष का कोर्स ।
5. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षा में 4 वर्ष का एकीकृत (Integrated) कोर्स ।<sup>1</sup>
6. शिल्प-अध्यापकों (Craft Teachers) के लिए अधोलिखित 3 प्रकार के विशेष कोर्स :— (i) 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स, (ii) 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स, और (iii) 2 वर्ष का डिग्री कोर्स ।
7. अधोलिखित में से प्रत्येक में 1 वर्ष का कोर्स :—(i) कृषि, (ii) विज्ञान, (iii) वाणिज्य, (iv) प्रौद्योगिकी, (v) ललित कलाएँ (केवल भोपाल और भुवनेश्वर के कॉलेजों में), और (vi) गृह-विज्ञान (केवल मैसूर और अजमेर के कॉलेजों में) ।

1. “शिक्षा में चार-वर्षीय डिग्री कोर्स” (Four-Year Degree Course in Education) सर्वप्रथम पंजाब राज्य के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1960 में आरम्भ किया गया था ।

6. शिक्षा के राज्य-संस्थान—“तीसरी पंचवर्षीय योजना” में भारत के प्रायः प्रत्येक राज्य और दिल्ली में “शिक्षा के राज्य-संस्थान” की स्थापना की गई। इन संस्थाओं के ध्येय का पूर्ण भार—भारतीय शिक्षा-संवर्धन द्वारा वहन किया जाता है। इन संस्थाओं के 5 मुख्य कार्य हैं :—(i) शिक्षा का विस्तार करना, (ii) पुस्तकों का प्रकाशन करना, (iii) शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, (iv) शिक्षा-सम्बन्धी शोध-कार्य करना, और (v) क्षेत्रीय कार्य करना।<sup>1</sup>

“प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के अध्ययन दल” ने सुझाव दिया है कि शिक्षा की राज्य-संस्थाओं को निम्नलिखित कार्यों का भार भी सौंपा जाना चाहिए<sup>2</sup> :—

1. प्राथमिक शिक्षा में सम्बन्धित निरीक्षकों और शिक्षकों को शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में सम्बन्धित शिक्षा की समस्याओं को शोध करना, शिक्षण-विधियों के विषय में अनुसंधान करना और पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में शोधकार्य करना।
3. बुनियादी और गैर-बुनियादी प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन करना।

7. पत्राचार-पाठ्यक्रम-केन्द्र—हमारे देश में शिक्षक-प्रशिक्षण में सम्बन्धित एक अत्यन्त दुष्कर समस्या—विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों की है। इस समय हमारे देश में प्राथमिक, मिडिल और हाई/हायर सेकण्डरी स्तरों में अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत क्रमशः 17.1, 15.1 और 18.8 है।<sup>3</sup>

इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, यथा—आंध्र में बी० एड० का 5 माह का और मद्रास में 4 माह का शक्ति पाठ्यक्रम, जोधपुर-विश्वविद्यालय में 2 दीर्घकालीन अरकाणों का पाठ्यक्रम और उत्तर-प्रदेश में 3 माह का सेवाकालीन प्रशिक्षण।

उपरोक्त विधियों में से किसी ने भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं किया है। इस तथ्य में अवगत होने के कारण भारत-सरकार ने “पत्राचार-विद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों” की योजना का निर्माण किया और 1962 में दिल्ली में “पत्राचार-पाठ्यक्रम-निदेशालय” (Directorate of Correspondence Courses) की सृष्टि की।

1. S. N. Mukerji : *op cit*, p. 377.

2. *Report of the Study Group on the Training of Elementary Teachers in India*, p. 37

3. *India*, 1974, p. 50.

उन "निदेशालय" के परामर्शों को स्वीकार करते, सन् 1966 में माध्यमिक स्तरों में सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 5 स्थानों पर "पद्याचार-पाठ्यक्रम-केन्द्रों" की स्थापना की गई :—दिल्ली का "सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन" और मैसूर, भोपाल, अजमेर तथा भुवनेश्वर के शिक्षा के रोजनन कॉलेज। इन स्थानों पर वारम्भ किए जाने वाले पद्याचार-पाठ्यक्रमों की मुख्य विशेषताएँ दृष्टव्य हैं<sup>1</sup> :—

1. पद्याचार-कोर्स की अवधि साधारण प्रशिक्षण की अवधि से अधिक है। साधारण प्रशिक्षण की अवधि लगभग 10 माह की है। किन्तु, पद्याचार-कोर्स की अवधि रोजनन कॉलेजों में 14 माह की और सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन में 16 माह की है।
2. पद्याचार-कोर्स का लाभ, विद्यालयों में कार्य करने वाले वही शिक्षक उठा सकते हैं, जो स्नातक एवं परस्नातक हों और जिनको शिक्षण का अनुभव हो। रोजनन कॉलेजों के कोर्स के लिए अनुभव की अवधि 5 वर्ष की है और सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन के कोर्स के लिए 3 वर्ष की है।
3. पद्याचार-कोर्स समाप्त करने वाले शिक्षकों को बी० एड० की उपाधि प्रदान की जाती है।
4. पद्याचार-कोर्सों और ट्रेनिंग कॉलेजों के कोर्सों में कोई अन्तर नहीं है।
5. प्रशिक्षण-काल में शिक्षकों को कुछ समय "पद्याचार-पाठ्यक्रम-केन्द्रों" में व्यतीत करना पड़ता है। समय की यह अवधि—रोजनन कॉलेजों में दो शीष्मकालीन अवकाशों में 6-6 सप्ताह और केन्द्रीय शिक्षा-संस्थान (Central Institute of Education) में एक शीष्मकालीन अवकाश में 8 सप्ताह की है।
6. उक्त अवधि में शिक्षकों को प्रशिक्षण ने सम्बन्धित विभिन्न कार्य करते पड़ते हैं; यथा :—नित्य-कार्य, शारीरिक शिक्षा, द्यूटोरियल कार्य, द्यूटोरियल परीक्षाओं का प्रयोग, व्यव-सामग्री का प्रयोग, पाठ्यक्रम-सहायकी-विद्याओं में भाग, आदि।

प्राथमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए पद्याचार-पाठ्यक्रमों की योजना तैयार हो चुकी है। इसे लगभग सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। राजस्थान के "राज्य-शिक्षा-संस्थान" ने इस योजना के अनुसार कार्य करना भी आरम्भ कर दिया है।

8. विशेषतः-प्रशिक्षण-केन्द्र—इन केन्द्रों का उद्देश्य—व्यक्तियों को विशेष विषयों में प्रशिक्षण देना है। इस समय भारत में अप्रशिक्षित विषयों के प्रशिक्षण केन्द्र

1. S. N. Mukerji : *op. cit.*, pp. 385-386.

हैं :—(1) शारीरिक शिक्षा, (2) सज्जित कलाओं की शिक्षा, (3) गृह-विज्ञान की शिक्षा, (4) किलों की शिक्षा, (5) भाषा-अध्यापकों की शिक्षा, और (6) विज्ञान की शिक्षा। हम इनमें से कुछ मुख्य विषयों के प्रशिक्षण-केन्द्रों का विवरण उपस्थित कर रहे हैं; यथा :—

(i) शारीरिक शिक्षा : *Physical Education*—यह शिक्षा—स्नातक और स्नातकोत्तर, दोनों स्तरों पर दी जाती है। दोनों स्तरों पर इस शिक्षा की अवधि 1 वर्ष की है। इस समय भारत में शारीरिक शिक्षा के 55 प्रशिक्षण-केन्द्र हैं, जिनमें से मुख्य हैं :—(1) गवर्नमेंट कनिज ऑफ़ फ़िजिकल ऐजुकेशन, पटियाणा और (2) महर्षीदास कनिज ऑफ़ फ़िजिकल ऐजुकेशन, स्थानियर।

(ii) सज्जित कलाओं की शिक्षा : *Aesthetic Education*—इन कलाओं का प्रशिक्षण देने वाली मुख्य संस्थाएँ हैं :—(1) कला-शोध, अहमदाबाद (मद्रास)—नृत्य; (2) टीचर्स कनिज ऑफ़ म्यूजिक, मद्रास—संगीत, (3) बरोडा विश्वविद्यालय—संगीत व चित्रकला; (4) सर जे० जे० स्कूल ऑफ़ आर्ट्स, बम्बई—ड्राइंग; (5) गवर्नमेंट स्कूल ऑफ़ आर्ट्स, मंगलूरु—कला, (6) विश्वभास्ती, शान्ति-निकेतन—नृत्य, संगीत व चित्रकला, और (7) इस्टीड्यूट ऑफ़ आर्ट्स ऐजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली—कला व किल्प।

(iii) गृह-विज्ञान : *Home Science*—गृह-विज्ञान के प्रशिक्षण की आवश्यकता—महिलाओं के लिए है। इसके मुख्य प्रशिक्षण-केन्द्र हैं :—(1) बरोडा विश्वविद्यालय; (2) मेहरो इन्विस कनिज, दिल्ली (3) शिक्षा के चारों क्षेत्रों में कनिज; (4) होमोस्टिक गाइंग ट्रेनिंग कनिज, हैदराबाद, (5) एम० एन० टी० टी० बीमेन यूनी-वर्सिटी, बम्बई; और (6) गवर्नमेंट कनिज ऑफ़ होम गाइड पर बीमेन, इलाहाबाद।

(iv) भाषा-अध्यापकों की शिक्षा : *Education of Language Teachers*—भाषा अध्यापकों को विभिन्न भाषाओं में प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों में केन्द्रों की स्थापना की गई है। अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए विभिन्न राज्यों में 11 संस्थाएँ हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैदराबाद का “मेम्टन इस्टीड्यूट ऑफ़ ट्रेनिंग” है। हिन्दी की शिक्षा के लिए हिन्दी और अहिन्दी—दोनों क्षेत्रों में 26 संस्थान हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जागरा का “केन्द्रीय हिन्दी संस्थान” है। इसी प्रकार, देश के विभिन्न स्थानों में उर्दू, अरबी, तामिल, ब्रज, मराठी, मलयालम आदि भाषाओं में प्रशिक्षण देने के केन्द्र हैं।

### सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा In-Service Teacher-Education

सेवाकालीन शिक्षा का अर्थ—शिक्षक-शिक्षा के दो पक्ष हैं। पहला, व्यक्ति को प्रशिक्षण-काल में प्रशिक्षण देकर, शिक्षक के रूप में तैयार किया

शिक्षक की सेवा-काल में शिक्षा-सम्बन्धी नवीन तथ्यों, विधियों, सिद्धान्तों आदि से परिचित कराके, उसकी व्यावसायिक दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि की जाती है। शिक्षा के इसी पक्ष को "सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा" की संज्ञा दी गई है।

सेवाकालीन शिक्षा का महत्त्व व आवश्यकता—शिक्षा—आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अतः सच्चा शिक्षक वही व्यक्ति हो सकता है, जो स्वयं अपने सम्पूर्ण जीवन में विद्यार्थी बना रहता है। जो व्यक्ति अपने 9 या 10 माह के प्रशिक्षण के पश्चात् फिर कभी कुछ सीखने का प्रयत्न नहीं करता है, वह सच्चा शिक्षक कहलाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि वह अपने सम्पूर्ण शिक्षण-काल में अपने ज्ञान में वृद्धि और उसका परिमार्जन करता रहे। यह तभी सम्भव है, जब उसे सेवाकालीन शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हों। इस शिक्षा के महत्त्व एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में आपके अवलोकनायें कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं; यथा :—

1. रवीन्द्रनाथ टैगोर :—"शिक्षक तब तक सच्ची शिक्षा कदापि नहीं दे सकता है, जब तक कि वह स्वयं न सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक कदापि नहीं जला सकता है, जब तक कि वह स्वयं न जल रहा हो।"

"A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame."—Rabindranath Tagore : *Siksa*, p. 264.

2. राधाकृष्णन् कमीशन<sup>1</sup> :—"यह विनियमन बात है कि हमारे विद्यालय-शिक्षक 24 या 25 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही उन विषयों के सम्बन्ध में सब-कुछ सीख लेते हैं, जो उनको पढ़ाने होते हैं और उसके पश्चात् उनकी सब भावी शिक्षा—अनुभव पर छोड़ दी जाती है।"

3. मुशलिमर कमीशन<sup>2</sup> :—"शिक्षक-प्रशिक्षण का कार्यक्रम चाहे जितना भी उत्तम क्यों न हो, पर यह स्वयं उत्तम शिक्षक का निर्माण नहीं कर सकता है। यह प्रशिक्षण—न्यूनतम अनुभव वाले शिक्षक को पर्याप्त आत्म-विश्वास में अपने शिक्षण-कार्य की आरम्भ करने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षक अपने कार्य में अधिक कुशलता केवल व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप ही प्राप्त कर सकता है। सेवा-काल की हम दिशा में प्रशिक्षण-नैसर्गिकों को शिक्षक की सहायता करनी चाहिए।"

4. कोठारी कमीशन :—"ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में होने वाली तीव्र प्रगति और शिक्षा के सिद्धान्तों एवं प्रयोगों में होने वाले निरन्तर विकास के कारण शिक्षण-व्यवस्था में सेवाकालीन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है।"

1. Radhakrishnan Commission Report, p. 152.

2. Muslimar Commission Report, p. 137.

"The need of in-service education is most urgent in the teaching profession, because of the rapid advance in all fields of knowledge and continuing evolution of pedagogical theory and practice."—*Kothari Commission Report*, p 84.

सेवाकालीन शिक्षा की विधियाँ—“मुदालिफर कमीशन” (p. 137) ने सेवाकालीन शिक्षा के लिए अप्रावित विधियों का सुझाव दिया है :—

1. विचार-गोष्ठियाँ : Seminars.
2. अभिनवन-पाठ्यक्रम : Refresher Courses
3. व्यावसायिक सम्मेलन : Professional Conferences.
4. कार्यशालाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण : Practical Training in Workshops.
5. विशेष विषयों में सक्षिप्त-गहन पाठ्यक्रम : Short Intensive Courses in Special Subjects

सेवाकालीन शिक्षा की अवधि—शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षा कब और कितने समय तक प्राप्त होनी चाहिए, इस विषय में “कोठारी कमीशन” का मत है<sup>1</sup> :—“प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवा-काल में प्रति 5 वर्ष के पर्याप्त कम-से-कम 2 या 3 माह को सेवाकालीन शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।”

भारत-सरकार द्वारा “सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा” की आवश्यकता एवं उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। अतः “पाँचवीं योजना” में प्रकाशित किया गया है :—“वर्तमान शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण का व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायगा।”

“A comprehensive programme of in-service training of existing teachers will be implemented”—*Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p 198.

### समस्याएँ व उनके समाधान Problems & Their Solutions

डा० मुकजी का कथन है —“विद्यते कुछ वर्षों में शिक्षक-शिक्षा का तीव्र विकास हुआ है, पर उसकी वर्तमान स्थिति किसी भी प्रकार संतोषजनक नहीं है। इस विकास के साथ-साथ उसमें अनेक समस्याएँ उपस्थित हो गई हैं।”

“The present position in relation to teacher-education is by no means satisfactory, in spite of its rapid progress during recent years. Numerous problems have arisen with this development.”—*S. N. Mukherji : Education in India, Today & Tomorrow*, p. 401.

1. *Kothari Commission Report*, p 624.

नीचे की पंक्तियों में हम शिक्षक-शिक्षा की मुख्य समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर विचार कर रहे हैं, यथा :—

1. समस्या—विभाजित उत्तरदायित्व : Divided Responsibility—शिक्षक शिक्षा के 2 मुख्य पक्ष हैं—संख्यात्मक और गुणात्मक। संख्यात्मक पक्ष अर्थात् विस्तार का उत्तरदायित्व—राज्य-सरकारों पर और गुणात्मक उन्नति का उत्तरदायित्व—केन्द्रीय सरकार पर है।

केन्द्रीय स्तर पर शिक्षक-शिक्षा का उत्तरदायित्व 4 निकायों के मध्य विभाजित है :—शिक्षा-मंत्रालय, योजना-आयोग (Planning Commission), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-परिषद् (National Council of Educational Research & Training), और विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग।

“शिक्षा-मंत्रालय”—शिक्षक-शिक्षा की योजनाओं का निर्माण करता है। “योजना-आयोग” उनमें से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है और उनको कार्यान्वित करने के लिए धन देता है। “राष्ट्रीय परिषद्” स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित करती है। “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” यह निश्चित करता है कि उनका सम्बन्ध विश्वविद्यालय-शिक्षा से है या नहीं।

ये चारों निकाय अपने-अपने सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करते हैं। अतः उनके उद्देश्यों में समानता नहीं है। परिणामतः हमारे देश में शिक्षक-शिक्षा—अनियोजित, असंगठित एवं अव्यवस्थित दशा में है।

समाधान—विभाजित उत्तरदायित्व की समाप्ति : End of Divided Responsibility—उल्लिखित समस्या का समाधान करने का एकमात्र उपाय है—केन्द्रीय स्तर पर विभाजित उत्तरदायित्व की समाप्ति। यह तभी सम्भव है, जब शिक्षक-शिक्षा का नियोजन, संगठन एवं सर्वेक्षण करने और उसे आर्थिक नहायता देने के लिए अखिल-भारतीय स्तर पर शिक्षक-शिक्षा की समिति का निर्माण किया जाय। जिन प्रकार देश में चिकित्सा-शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व—“भारतीय चिकित्सा-समिति” (Indian Medical Council) पर और प्राविधिक शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व—“अखिल-भारतीय प्राविधिक शिक्षा-समिति” (All India Council of Technical Education) पर है, उसी प्रकार शिक्षक-शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व एक अखिल-भारतीय समिति पर होना चाहिए।

इस प्रकार की समिति की स्थापना का सुझाव—“शिक्षक-शिक्षकों के भारतीय मंच” (Indian Association of Teacher Educators), अनेक “अध्ययन-दलों” (Study Groups), समितियों एवं आयोगों द्वारा दोहराया जा चुका था। इसकी स्थापना के विषय में “कोठारी कमिशन” का सुझाव था<sup>1</sup> :—“विश्वविद्यालय-अनुदान

आयोग—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से शिक्षक-शिक्षा के लिए एक स्थायी समिति का निर्माण करे, जिसे शिक्षक-शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने का कार्य सौंपा जाय।”

“कोठारी कमिशन” के सुझाव को स्वीकार करके, भारत-सरकार ने “विश्व-विद्यालय-अनुदान-आयोग” की अधीनता में “शिक्षक-शिक्षा की स्थायी समिति” (Standing Committee on Teacher Education) का निर्माण किया है। किन्तु, इस “समिति” का कार्यक्षेत्र सीमित है, क्योंकि इसका नियमन केवल उन प्रशिक्षण-संस्थाओं पर है, जो विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। शेष प्रशिक्षण-संस्थाएँ इसके अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं। इस घुटि को दूर करने के लिए राज्य-स्तर पर भी शिक्षक-शिक्षा की समितियाँ या परिषदें होनी चाहिए। उक्त “समिति” और इन परिषदों के कार्यों में समन्वय होना चाहिए तभी शिक्षक-शिक्षा की गुणात्मक उन्नति होगी और उसका नियोजित विस्तार होगा।

इस दिशा में भारत के सभी राज्य प्रयत्नशील हैं। मद्रास, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में “शिक्षक-शिक्षा की राज्य-परिषद्” (State Board of Teacher Education) और आंध्र प्रदेश में “शिक्षक-शिक्षा की राज्य-समिति” (State Council of Teacher Education) की स्थापना की जा चुकी है। शेष राज्यों के विषय में भारत-सरकार ने “पाँचवी योजना” में अपना यह निर्णय लिपिबद्ध किया है :—“शेष राज्यों में शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षक-शिक्षा की राज्य-परिषदों की स्थापना की जायगी।”

“State Boards of Teacher Education will be set up in the remaining States for co-ordinating teacher education programmes.”  
—Draft Fifth Five-Year Plan, Vol II, p. 198

2. समस्या—प्रवेश के मानदण्डों में विविधता Diversity in Admission Criteria—शिक्षक-शिक्षा की बहुरंगी समस्याओं में से एक समस्या—प्रशिक्षण-संस्थाओं के मानदण्डों में विविधता है। इन मानदण्डों में इतनी विलक्षण विविधता है कि कभी-कभी उनके कारण परेशानी का अनायास हादसा भी होता है। इसका कारण यह है कि अनेक प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रवेशार्थियों का चुनाव के 2 मुख्य आधार हैं—घन और मिफारिश। ऐसी स्थिति में निम्न योग्यताओं के व्यक्तियों का चयन तो हो जाता है, जबकि उच्च मानात्मक योग्यताओं वाले शिक्षण में अमिरचिर करने वाले व्यक्ति—प्रवेश पाने में विफल रह जाते हैं।

प्रशिक्षण-संस्थाओं में निम्न क्रांति के व्योमगता के प्रवेश के दो मुख्य परिणाम उभर कर सामने आ गए हैं—छात्र-अनुसंधानशीलता में वृद्धि और शिक्षक-शिक्षा के स्तरों में अधिक गिरावट। अब प्रशिक्षण के लिए योग्यताओं का चुनाव—शिक्षाविदों के लिए चिन्ता का विषय बन गया है।



सैमर्सेन ने लिखा है<sup>1</sup> :—“अब तक लोगों में अध्यापक बनने की इच्छा की धीरे-धीरे प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या, माँग से अधिक नहीं थी, तब तक परिस्थिति उतनी उग्र और नुक़्क़मय नहीं थी, जितनी कि आज है। अब एक ओर तो वर्तमान प्रशिक्षण-कमिजों में भरती होने का प्रयत्न करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और दूसरी ओर नभी योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए काफी नौकरियाँ नहीं हैं। इसलिए, उचित लोगों को चुनने की समस्या स्वयं इन लोगों के हित में और अध्यापनवृत्ति के हित में भी बहुत महत्त्वपूर्ण बन गई है।”

**समाधान—प्रवेश के मानदण्डों का निर्धारण : Determination of Admission Criteria**—भारतीय शिक्षा की पुनर्रचना में शिक्षक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारक है, पर शिक्षण का कार्य नभी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। अतः प्रशिक्षण-संस्थाओं के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों द्वारा स्वनिर्मित मानदण्डों के प्रयोग का समय बीत चुका है। अब इन मानदण्डों का प्रयोग न केवल भारतीय शिक्षा के पुनर्संगठन, परन्तु देश के भावी नागरिकों और स्वयं देश के लिए महान् संकट का कारण है। अतः यह अति आवश्यक है कि प्रवेश के मानदण्ड निर्धारित किए जायें और उनको बिना किसी अपवाद के प्रत्येक प्रशिक्षण-संस्था द्वारा प्रयोग किया जाय। इन मानदण्डों को निर्धारित करने के लिए, डा० सैमर्सेन के 2 महत्त्वपूर्ण सुझाव उल्लेखनीय हैं; यथा<sup>2</sup> :—

1. प्रत्येक राज्य की प्रशिक्षण-संस्थाएँ और शिक्षा-विभाग संयुक्त रूप में प्रत्येक 5 वर्ष के परचात् यह सर्वेक्षण करें कि उनके राज्य के लिए कितने प्रशिक्षित शिक्षकों की माँग है। इसी माँग के आधार पर विभिन्न स्तरों की प्रशिक्षण-संस्थाओं में छात्रों को प्रवेश दिया जाय।
2. इन समय प्रशिक्षण-संस्थाओं में छात्रों को प्रवेश देने के लिए जिन अल्पवस्थित विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके स्थान पर ऐसे मानदण्ड निर्धारित किये जायें, जिनमें छात्रों के नैतिक एवं मानसिक गुणों की पर्याप्त जानकारी प्राप्ता हो जाय।

डा० सैमर्सेन के दूसरे सुझाव के अनुसार दिल्ली के “मेन्ट्रन इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन” ने छात्रों के चयन के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना में 4 माध्यमकार (प्राचार्य, उपप्राचार्य, अध्यापक-मंडल एवं स्वास्थ्य-अधिकारी द्वारा), 5 परीक्षाएँ (Tesis) (रचि-परीक्षा, मुक्ति परीक्षा, अभिवृत्ति-परीक्षा, सामान्य ज्ञान-परीक्षा एवं नैवेदनशीलता-परीक्षा) और एक सामूहिक विचार-विमर्श को स्थान दिया गया है।<sup>3</sup>

1. डा० जी० सैमर्सेन : शिक्षा की पुनर्रचना, p. 272.
2. डा० जी० सैमर्सेन : पूर्णक पुस्तक, pp. 272-273.
3. E. A. Pires : *Better Teacher Education*, p. 81.

प्रशिक्षण-संस्थाओं द्वारा इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें एक प्रवेशार्थी के चयन-सम्बन्धी तथ्यों को एकत्र करने में 4 घंटे का समय लगता है। अतः यह आवश्यक है कि इसमें केवल अप्रकृति 4 बातों को स्थान देकर, इसे संक्षिप्त बनाया जाय।—रुचि-परीक्षा, बुद्धि-परीक्षा, भाषा में लिखित परीक्षा और अध्यापक-महसल से साक्षात्कार।

3. समस्या—स्वतंत्रताविहीन वातावरण : *Unfree Environment*—शिक्षक-शिक्षा पर एक गम्भीर आरोप यह लगाया जाता है कि छात्राध्यापक अपना सम्पूर्ण परीक्षण-काल स्वतंत्रताविहीन वातावरण में व्यतीत करते हैं। उनको “नई शिक्षा” (*New Education*) में निहित नेतृत्व, स्वतन्त्रता, पहलकदमी, सामुदायिक जीवन एवं सामाजिक प्रेरणा आदि विचारों की शिक्षा तो दी जाती है, पर उनको इन विचारों का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है।

इसके विपरीत, उनसे यह आशा की जाती है कि वे इन विचारों के सार-तत्त्व को प्रत्यक्ष पूर्वाभाम की किसी प्रक्रिया द्वारा अपनी पाठ्य-पुस्तकों से ग्रहण कर लें और फिर उनको अपने विशालयों में संप्राण वास्तविकता का रूप प्रदान करें। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे बिना सोचे-समझे, बिना तर्क-वितर्क किए अपने गुरुजनों के धेनुनियाम विचारों को भी आत्मसात् कर लें। माग्य द्वारा ठुकराए हुए व्यक्ति—शिक्षण-व्यवसाय में प्रवेश करके, इन सब बातों के विरुद्ध अपनी आत्मा की चोत्कार को सुनकर भी अनसुनी कर देने हैं और अपनी प्रशिक्षण-संस्थाओं के दम घोटने वाले वातावरण में अपनी आत्माओं का हनन करके, ग्यो-त्यो करके अपने प्रशिक्षण-काल के दिन गुजारते हैं।

कटु सत्य यह है कि जो प्रशिक्षण-संस्थाएँ स्वयं “करके सीखने” के सिद्धान्त की शिक्षा देती हैं, वही अपने इस सर्वप्रिय सिद्धान्त का कार्य रूप में कभी पालन नहीं करती हैं। इस विरोधाभास पर शोभ प्रकट करते हुए, डॉ० संपर्जन ने लिखा है<sup>1</sup> :—“स्वतन्त्रता या आत्म-क्रिया या सहयोगी कार्य जैसी किसी भी महत्त्वपूर्ण एवं सारगर्भित धारणा के पूरे महत्त्व को उस समय तक नहीं समझा जा सकता है, जब तक कि इन धारणाओं में निर्विघ्न परिस्थितियों में कार्य करने का वास्तविक अनुभव प्राप्त न किया जाय।”

समाधान—स्वतंत्र वातावरण : *Free Environment*—शिक्षक-शिक्षा को उपयुक्त आरोप से मुक्त करने के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रशिक्षण-संस्थाओं को कठोर नियमों के बंधनों से और छात्राध्यापकों के जीवन तथा उनकी गतिविधियों को दमनकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाय। इसके अतिरिक्त, यह भी परम

आवश्यक है कि प्रशिक्षण-संस्थाओं को ऐसे सक्रिय तथा स्वतंत्र समुदायों (Communities) के रूप में संगठित किया जाय, जिनमें छात्राध्यापक उन्हीं प्रेरणाओं तथा परिस्थितियों के अधीन कार्य करें, जिनको स्वतंत्र भारत अपने नवीन तथा प्रगतिशील विद्यालयों में स्थापन देने की चेष्टा कर रहा है। यदि इस दिशा में तत्काल सक्रिय पग नहीं उठाया गया, तो प्रशिक्षण-संस्थाओं के दम घोटने वाले तथा स्वतंत्रता-विहीन वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्राध्यापक इस दूषित वातावरण की प्रक्रिया को खोल अपनी शिक्षा की सलत धारणाओं को अपने-अपने विद्यालयों में अन्त समय तक चलाते रहेंगे।

पिछले कुछ वर्षों से प्रशिक्षण-संस्थाओं के वातावरण में प्रत्यक्ष परिवर्तन परिचित हो रहा है। इस बात पर हर्ष प्रकट करते हुए और इसका कारण बताते हुए डा० सैपदेन ने लिखा है<sup>1</sup> :—“युनिटादी प्रशिक्षण-कालेजों को सहकारी उत्पादन-शील कार्य पर आधारित ‘सामुदायिक केन्द्रों’ के रूप में संगठित किया जा रहा है और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के कॉलेजों में भी उपेक्षित अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है। परन्तु, सचमुच प्रभावशाली बनने के लिये इस आन्दोलन को अभी काफी प्रगति करनी होगी।”

4. समस्या—मानवीय पक्ष की उपेक्षा : Neglect of Human Aspect—प्रशिक्षण-काल में शिक्षण के प्राविधिक पक्ष (Technical Aspect) पर इतना अधिक धन दिया जाता है कि मानवीय पक्ष की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। सैद्धान्तिक विषयों, अध्यापन-विधियों, शिक्षण-अभ्यास एवं व्यावहारिक कार्यक्रमों को इतना अधिक महत्त्व दिया जाता है कि छात्राध्यापकों को शिक्षा के लक्ष्यों, मूल्यों एवं प्रयोजनों पर आलोचनात्मक ढंग से विचार करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। अतः वे भूल जाते हैं कि वे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनका मुख्य उद्देश्य—अपने विद्यार्थियों का सर्वतोमुखी विकास करके, उत्तम समाज के निर्माण में अपनी भूमिका बढ़ा करनी है।

इस प्रकार, प्रशिक्षण-संस्थाओं में मानवीय पक्ष की पूर्ण अवहेलना की जाती है। ये बहल भूल जाते हैं कि जिन छात्राध्यापकों को वे शिक्षकों के रूप में तैयार कर रही हैं, वे मानव हैं, मशीन नहीं। प्रशिक्षण-संस्थाओं की इस हताशकारी प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए, डा० सैपदेन ने लिखा है :—“अदूरदर्शिता के कारण छोटी-छोटी व्योरे की बातों एवं प्राविधिक आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित रहने के कारण समाज के साथ विद्यालय का सम्बन्ध एवं उनकी जीती-जागती समस्याएँ और मसले छिपि-छिपि नज़र न पड़ते हैं।”

“The relation of the school to society and its living problems and issues have been obscured by concentrating short-sightedly on

minor details and technical requirements"—K. G. Saiyidain : *op. cit.*, p. 318.

समाधान—प्रशिक्षण-संस्थाओं के मानदण्डों में परिवर्तन : *Change in the Values of Training Institutions*—हमारी प्रशिक्षण-संस्थाओं में मानवीय पक्ष की उपेक्षा करने की अपराध-वैतन्यता तो है, पर फिर भी वे अपने अपराध की निर्भीकता से अस्वीकार करती हैं। वे इस निराधार तर्क का प्रचार करती हैं कि उनको छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए इतना घोरा समय मिलता है कि उनके लिए मानवीय पक्ष पर यदा-कदा भी ध्यान केन्द्रित करना सम्भव नहीं है।

तर्क की दृष्टि में तो यह तर्क मान्य है, पर सचमुच यह है केवल बहाना। यदि हम इस बहाने के आधार पर प्रशिक्षण-संस्थाओं में दशाब्दियों से विद्यमान इस परिस्थिति में सुधार करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो यह इस बात का सजीव प्रमाण होगा कि हम गलत मानदण्डों में आस्था रखते हैं और उनमें सुधार किए जाने के पक्ष में नहीं हैं।

अत उल्लिखित समस्या के समाधान का स्पष्ट उपाय यह है कि प्रशिक्षण-संस्थाएँ अपने मानदण्डों में परिवर्तन करें और मानवीय पक्ष पर अपना प्रचुर ध्यान केन्द्रित करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण-संस्थाओं को समाज-केन्द्रित बनाना होगा और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उनके पाठ्यक्रमों में संशोधन करना होगा। हम अपने इस कथन का समर्थन डा० सैयदैन के अप्रति उद्धरण से कर रहे हैं<sup>1</sup> :—“प्रशिक्षण-संस्थाएँ अपने मानदण्डों को बदलें और गुफा में रहने वाले मनुष्य को उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचें, जो अपने चारों ओर के नयनाभिराम दृश्य को केवल इसलिए नहीं देख सकता था, क्योंकि उसकी दृष्टि उसके घड़ीगृह की घाटबीवारों तक सीमित थी। शैक्षणिक कार्यों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया जाता है और इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।”

5. समस्या—शिक्षान्त पर अनावश्यक बल *Unnecessary Emphasis on Theory*—शिक्षक-शिक्षा-सम्बन्धी कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण-संस्थाओं की यह कह कर आलोचना की जाती है कि उनमें शिक्षान्तों की शिक्षा आवश्यकता में अधिक दी जाती है। छात्राध्यापकों के लिए शिक्षान्त के रूप में त्रिन विषयों का अध्ययन अनिवार्य है, उनमें से अनेक ऐसे हैं, जो उनके वास्तविक शिक्षण-कार्य के लिए पूर्णतया निरर्थक एवं निष्प्रयोजन हैं। उदाहरणस्वरूप, इस प्रकार के कुछ विषय हैं :—सांख्यिकी, त्रिधा-अनुसंधान, शिक्षा में विभिन्न 'वाद', अनेक रायों के कारण और उपचार, प्रत्येक शिक्षा-आयोग और नॉमिनि के विचार, इत्यादि। छात्राध्यापक मत्ती-

removed, its effectiveness will continue to be very questionable indeed."—K. G. Saiyidain : *op., cit.* p. 323.

**समाधान—सिद्धान्त व व्यवहार में अपृथक्ता : No Divorce between Theory & Practice**—उपर्युक्त दोष का मूलभूत कारण यह है कि ऐसी प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या प्रायः नगण्य है, जिनसे उचित प्रकार के “प्रदर्शन-स्कूल” (Demonstration Schools) सम्बद्ध हैं। अतः छात्राध्यापकों को इस बात का अवसर नहीं मिल पाता है कि वे उन सिद्धान्तों एवं प्रणालियों को जिनको उन्होंने बड़े परिश्रम से सीखा है, व्यवहार में परख सकें। फलस्वरूप, जैसा कि डा० सैयदेन ने लिखा है<sup>1</sup> :—“उनके अध्यापन में जीवन तथा वास्तविकता का वह घुट नहीं होता है, जो केवल सफल व्यावहारिक अनुभव ने ही आ सकता है।”

इन दोषों के निराकरण का उपाय बताते हुए, डा० सैयदेन ने लिखा है :—“व्यवहार एवं सिद्धान्त—दोनों ही की कल्पना विकासवान् शकाइयों के रूप में की जानी चाहिए। सिद्धान्त—व्यवहार का पथ आलोकित करे और व्यवहार—सिद्धान्तों में नित्य नए सुधार करे।”

“Practice and theory must both be visualized as growing entities : theory illuminating practice; practice constantly modifying theory.”—K. G. Saiyidain : *op. cit.*, p. 314.

किन्तु, यह नभी सम्भव है, जब प्रत्येक प्रशिक्षण-संस्था से सम्बद्ध और नभी आवश्यक माधमों में परिपूर्ण एक प्रदर्शन-विशालय हो, जो प्रायोगिक पद्धति (Experimental Method) के अनुसार चलाना जाता हो और जिसमें छात्राध्यापकों को बताने जाने वाले सिद्धान्तों एवं प्रणालियों के बारे में छानबीन की जाती हो। डा० सैयदेन के शब्दों में :—“यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र इन प्रणालियों को व्यवहार में परख कर वैयक्तिक रूप में उनका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेंगे और यदि अध्यापन के अन्तर्गत के दौरान में वे स्कूल को इन सिद्धान्तों के अनुसार चलाने में सहायता दे चुके होंगे, तो इस बात की सम्भावना अधिक होगी कि उनमें अपने काम के प्रति नए-नए प्रयोग करने का रुचि पैदा हो और धीरे-धीरे चलकर अपने जीवन में मौलानिक ज्ञान और व्यवहार के बीच कलप्रद क्रिया-प्रतिक्रिया स्थापित कर सकें।”

**7. समस्या—शिक्षक-शिक्षा की पृथक्ता : Isolation of Teacher Education**—“कोठारी-रामोशन” के अनुसार, शिक्षक-शिक्षा की पृथक्ता के 3 रूप हैं, यथा :—

1. के० जी० सैयदेन : पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० 266.
2. के० जी० सैयदेन : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 267.
3. *Kethari Commission Report*, p. 68.

1. विश्वविद्यालयों से साहित्यिक जीवन से पृथक्ता—प्रशिक्षण-संस्थाओं का विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि ये सभी संस्थाएँ पूर्णतया पृथक् इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। इसके कारण स्वयं विदित हैं। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का संचालन, राज्यों के शिक्षा-विभागों द्वारा किया जाता है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली अधिकांश संस्थाएँ, विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध अवश्य होती हैं, किन्तु उनका विश्वविद्यालयों के शैक्षिक जीवन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता है।

2. विद्यालयों से पृथक्ता—प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का विद्यालयों और विद्यालय-शिक्षा की प्रचलित विधियों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता है।

3. एक-दूसरे से पृथक्ता—विविध श्रेणियों की प्रशिक्षण-संस्थाओं की एक-दूसरे से पूर्ण पृथक्ता है, क्योंकि उनके छात्रों एवं शिक्षकों में किसी प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं होता है। वे अपने को एक-दूसरे से श्रेष्ठतर या निम्नतर समझते हैं। अतः वे विलकुल पृथक् इकाइयों में विभाजित हैं।

इस प्रकार, सब प्रशिक्षण-संस्थाओं का अपना-अपना पृथक् अस्तित्व है। उनका विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों और एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। शिक्षक-शिक्षा का यह ऐसा गम्भीर दोष है, जिसका उन्मूलन किया जाना आवश्यक है। इस मदभं में "शिक्षा-आयोग" ने लिखा है:—“हम प्रशिक्षण-संस्थाओं की पृथक्ता की समाप्ति के प्रस्ताव को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। हमारी राय में यह एक ऐसा सुधार है, जो शिक्षक-शिक्षा में जीवन का संवार कर सकता है।”

“We attach great importance to the proposal to break the isolation of training institutions. In our opinion, this is the one reform that can vitalize teacher education.”—*Education Commission Report*, p 68

समाधान—पृथक्ता का अन्त Removal of Isolation—‘कोठारी कमिशन’ ने शिक्षक-शिक्षा की पृथक्ता के तीनों रूपों का अन्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं; यथा —

1. विश्वविद्यालयों से पृथक्ता का अन्त

(i) चुने हुए विश्वविद्यालयों में शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों का शिक्षा किया जाय।

1. *Kothari Commission Report* pp 68-71

- (ii) विश्वविद्यालयों के बी० ए० और एम० ए० के पाठ्यक्रमों में "शिक्षा" को वैकल्पिक विषय के रूप में स्थान दिया जाय।
- (iii) "शिक्षा" विषय का चयन करने वाले छात्रों को विद्यालयों में शिक्षण-अभ्यास की सुविधा दी जाय।

## 2. विद्यालयों से पृथक्ता का अन्त

- (i) प्रशिक्षण-संस्थाओं में "पुरातन छात्र-समितियों" का संगठन किया जाय।
- (ii) प्रशिक्षण-संस्थाओं में "प्रसार-सेवा-विभाग" की अनिवार्य रूप से स्थापना की जाय।
- (iii) प्रशिक्षण-संस्थाओं एवं उनसे सम्बद्ध 'शिक्षण-अभ्यास' के स्कूलों के अध्यापकों में समय-समय पर विनिमय किया जाय।

## 3. एक-दूसरे से पृथक्ता का अन्त

- (i) सब प्रशिक्षण-संस्थाओं को ट्रेनिंग कॉलेजों की संज्ञा दी जाय और उनको विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाय।
- (ii) शिक्षक-शिक्षा के सब स्तरों के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए, "समन कॉलेजों" (Comprehensive Colleges) की स्थापना की जाय।

टिप्पणी—“कोठारी कमीशन” का सुझाव है कि विभिन्न स्तरों के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए पृथक् संस्थाएँ नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत, सबको एक ही प्रशिक्षण-संस्था में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। “कमीशन” ने इस संस्था को “समन कॉलेज” की संज्ञा दी है। समन कॉलेजों में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों को एक ही स्थान पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अनिश्चित, इनमें छात्रों को एम० एड० की उपाधि के लिए भी शिक्षा दी जाती है। “समन कॉलेज”—जिलानी, उदयपुर, सरदार नहर आदि स्थानों में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

समन कॉलेजों की स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थाओं में विद्यमान पृथक्ता का अन्त हो जाएगा। अतः भारत-सरकार ने इनके निर्माण के प्रति विशेष स्थान देने का निर्णय किया है। “पाँचवीं पंचवर्षीय योजना” के अनुसार :—“शिक्षा के कुछ कॉलेजों का समन कॉलेजों के रूप में विकास किया जायगा, जिनमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के सब प्रकार के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायगा।”

“A few colleges of education will be developed as comprehensive colleges, where training will be provided for all types of teachers in elementary and secondary schools.”—*Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 198.

8. समस्या—शिक्षक-शिक्षा का निम्न स्तर : Low Standard of Teacher Education—शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रम का सार-तत्त्व उमका गुण या श्रेष्ठता (Quality) है। यदि उमके श्रेष्ठता का अभाव है, तो वह न केवल आर्थिक अपव्यय का, बरन् विद्यालय-शिक्षा के सब स्तरों के पतन का कारण बन जाती है। यदि हम अपने देश की शिक्षक-शिक्षा की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यद्यपि उमका हाल के वर्षों में पर्येष्ट विस्तार हुआ है, पर उसके स्तर का अनिवार्य रूप में पतन हुआ है। इसके कारण पर प्रकाश डालने हुए “शिक्षा-आयोग” ने लिखा है :—“शिक्षक-शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रम अधिकांश रूप में परम्परागत, कठोर और स्कूलों की वास्तविक दशाओं एवं शैक्षिक पुनर्गठन के वर्तमान या प्रस्तावित कार्यक्रमों से असम्बद्ध हैं।”

“Existing programmes of teacher education are largely traditional, rigid and divorced from the realities of schools and existing or proposed programmes of educational reconstruction.”

—Education Commission Report, p 72.

समाधान—शिक्षक-शिक्षा का पुनर्गठन : Reorganisation of Teacher Education—शिक्षक-शिक्षा को आर्थिक अपव्यय एवं शैक्षिक स्तरों के पतन के दोषारोपण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसकी श्रेष्ठता में उन्नति की जानी आवश्यक है। यह सभी सम्भव है, जब उमका आमूल परिवर्तन करके, उमका पुनर्संज्ञकन किया जाय। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, “कोठारी कमिशन” ने पुनर्संज्ञकन के निम्नांकित सिद्धान्तों का उल्लेख किया है।—

1. विश्वविद्यालयों में सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाय।
2. स्नातको, परस्नातको, प्रधानाचार्यों एवं प्रशिक्षण-सम्पादकों के अध्यापकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाय।
3. प्रशिक्षण-संस्थाओं में व्यावसायिक अध्ययन को सजीव बनाया जाय और उमको भारतीय दशाओं पर आधारित किया जाय।
4. प्रशिक्षण-सम्पादकों के पाठ्यक्रमों की विषय-सामग्री को छात्राध्यापकों की वैयक्तिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाय।
5. प्रशिक्षण-संस्थाओं में अध्यापन-अभ्यास को महत्व दिया जाय और छात्राध्यापकों के प्रत्येक पाठ का उचित प्रकार से निरीक्षण किया जाय।



6. प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण एवं मूल्यांकन की प्राचीन एवं परम्परागत विधियों के स्थान पर नवीनतम एवं प्रगतिशील विधियों का प्रयोग किया जाय।

अपरिष्कृत सिद्धान्तों में “कोठारी कमीशन” ने पाठ्यक्रमों के पुनः निर्धारण पर सबसे अधिक धन दिया है। “पाँचवीं पंचवर्षीय योजना” में इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय किया गया है :—“भावी शिक्षकों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक तैयारी में अभिवृद्धि करने के लिए, प्रशिक्षण-विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का पुनः निर्धारण किया जायगा।”

“The curricula of the training schools and colleges will be reoriented so as to ensure the deepening of the prospective teachers academic and professional preparation.”—*Draft Fifth Five-Year Plan, Vol. II, p. 198.*

9. समस्या—प्रशिक्षण-संस्थाओं के कार्यक्रमों में विभिन्नता : Diversity in Programmes of Training Institutions—भारत की प्रशिक्षण-संस्थाओं के कार्यक्रमों और उनके संचालन की विधियों में आश्चर्यजनक विभिन्नता है। उदाहरणार्थ—(1) शिक्षा-विभागों द्वारा संचालित बुनियादी और गैर-बुनियादी “प्राइमरी ट्रेनिंग स्कूलों” में गटिक्रिकेट का कार्यक्रम; (2) विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा-विभागों द्वारा संचालित “मैकमटरी ट्रेनिंग स्कूलों” में डिप्लोमा या गटिक्रिकेट का कार्यक्रम; (3) विश्वविद्यालयों और शिक्षा-विभागों द्वारा संचालित “ट्रेनिंग कॉलेजों” में बी० टी० एन० टी०, बी० एड० या डिप० एड० का कार्यक्रम; और शिक्षा के रोजनम कॉलेजों में 6-7 प्रकार के अधिक के कार्यक्रम।

इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों के कार्यकाल में भी विभिन्नता है। य विभिन्नता। वर्षों से केवल 4 वर्ष तक की है। डिप्लोमा, गटिक्रिकेट और उपाधि के कार्यक्रमों का काल 1 या 2 वर्ष का है। रोजनम कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों का काल 1 वर्ष से 4 वर्ष तक का है।

प्रशिक्षण-संस्थाओं में पाई जाने वाली इन विभिन्नताओं की ओर देज न सरकार और शिक्षा-विभागों का ध्यान बाह्य रूप से हुए, “शिक्षा-आयोग” ने कहा है :—“प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए अध्यापकों की तैयार करने वाले संस्थानों के पाठ्यक्रमों, कार्य की दशाओं एवं प्रशिक्षित किए गए अध्यापकों में विविधता विभिन्नता परिलक्षित होती है।”

“Institutions that prepare teachers for the primary and secondary schools show a bewildering variety of courses, conditions of work, and quality of teachers turned out.”—*Education Commission Report, p. 57.*

समाधान—कार्यक्रमों में समरूपता : Uniformity in Programmes—  
प्रशिक्षण-संस्थाओं के कार्यक्रमों, कार्यकालों आदि में इस विलक्षण विभिन्नता का कारण यह है कि इनमें समरूपता स्थापित करने के लिये राज्य या केन्द्रीय स्तर पर कोई निकाय या संस्था नहीं है। इस तथ्य से अवगत होने के कारण “कोठारी-कमीशन” का यह सुझाव है कि राज्य-स्तर पर प्रशिक्षण-संस्थाओं के कार्यक्रम में एक-रूपता स्थापित करने का उत्तरदायित्व—“शिक्षक-शिक्षा की राज्य-परिषदों” (State Boards of Teacher Education) पर रखा जाय और केन्द्रीय स्तर पर यह कार्य—“विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” को सौंपा जाय और वह इस कार्य की “शिक्षक-शिक्षा की स्थायी समिति” (Standing Committee on Teacher Education) के माध्यम से सम्पन्न करे।<sup>1</sup>

10. समस्या—प्रशिक्षण-संस्थाओं की निम्न कोटि : Low Quality of Training Institutions—स्वातन्त्र्योत्तर काल में शिक्षक-शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि के साथ-साथ प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या में भी यथेष्ट वृद्धि हुई है। जबकि 1950-51 में सब स्तरों की प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या 835 थी, 1970-71 में यह संख्या बढ़कर 1665, अर्थात् लगभग दूनी हो गई।<sup>2</sup> किन्तु, गुणात्मक दृष्टि से इन संस्थाओं के अनवरत ह्रास से साक्षात्कार होता है। परिस्थितियों की विडम्बना कुछ ऐसी रही है कि विभिन्न आयोगों, समितियों एवं अध्ययन-गोष्ठियों की चेतावनी के बावजूद भी उनकी दशा में सुधार करने के लिए बहुत समय तक एक भी पग नहीं उठाया गया। परिणामतः उनमें अधिकतर संस्थाएँ किम्वदुता स्थिति में पड़ चुकी हैं, इसकी कल्पना ‘शिक्षा-आयोग’ के इस शब्द-चित्र से कीजिए :—“कुछ प्रशिक्षण-संस्थाओं के अलावा शेष सब साधारण या निम्न कोटि की हैं।”

“The quality of training institutions remains, with a few exceptions, either mediocre or poor.”—*Education Commission Report*, p. 67.

ये प्रशिक्षण-संस्थाएँ किन दृष्टियों से निम्न कोटि की हैं, इसका स्पष्टीकरण, डा० एच० एन० मुकर्जी ने स्वतन्त्रता से पूर्व और बाद की प्रशिक्षण-संस्थाओं का विश्लेषण करके किया है; यथा<sup>3</sup> :—पहली प्रशिक्षण-संस्थाओं में सच्चे-बोड़े सेन के मैदानों, भव्य भवनो, पूर्णतया सुसज्जित पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं के दर्शन होते थे। उनमें योग्य, अनुभवी और पर्याप्त अध्यापक होते थे। इनके विपरीत, आज की प्रशिक्षण-संस्थाओं में सुसज्जित पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, शिक्षण-मामूरी और साज-सज्जा का पूर्ण अभाव है।

1. Kothari Commission Report, p. 87.

2. India, 1974, p. 50.

3. S. N. Mukerji · Education in India, Today & Tomorrow, p. 421.

साल वर्षों में 244 प्रशिक्षण-संस्थाओं के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि उनमें से 68 विभाग के भवनों में स्थित हैं, केवल 37 में अपनी स्वयं की प्रयोगशालायें हैं और केवल 144 में शिक्षण-उपकरण के लिए विज्ञानलय संग्रहण हैं। इन विभिन्न प्रशिक्षण-संस्थाओं का बजट लगभग करने हुए, टा० एन० एन० मुद्राओं में दिया है :—

“निम्नलिखित रूप से आज की कुछ प्रशिक्षण-संस्थाएँ—महलों और किलों में चल रही हैं, पर कुछ घुड़मार्गों में भी कार्य कर रही हैं। किन्तु, किराए के भवन या महल या घुड़मार्ग का निर्माण निश्चित रूप से शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं किया गया है।”

**समाधान—प्रशिक्षण-संस्थाओं का सुधार : Improvement of Training Institutions—** शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं के सुधार-सम्बन्धी उपायों का वर्णन करने से पूर्व हम जान की आवश्यक है कि ये निम्न कौटि की क्यों हैं ? इसका सर्वविधित कारण यह है कि हमारी सरकार ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से लेकर 25 वर्ष के लम्बे काल में उनके साथ सीधे-सी संघर्ष का सा व्यवहार किया और उसमें तद्विषय भी सचि व्यक्त न करके, हमारी अनुचित व्यवहारना की। हमका जीना-मानना प्रमाण यह है कि शिक्षक-शिक्षा की पृथक् एवं स्वतन्त्र इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई। यही कारण था कि शिक्षा-संस्थान, विश्वविद्यालय-अनुदान-कार्यक्रम एवं राज्य-सरकारों ने प्रशिक्षण-संस्थाओं की एक पैदा की गढ़ायना-अनुदान के रूप में नहीं दिया। शिक्षक-शिक्षा के सीमावर्त से सन् 1969 में उनके इष्टिकोन में परिष्करण आया और हमलिय “चौथी पंचवर्षीय योजना” (1969-74) में प्रथम बार शिक्षक-शिक्षा पर व्यय किए जाने के लिए एक समर्पित निर्धारित की गई।<sup>1</sup> फलस्वरूप, शिक्षक-शिक्षा में सुशासन उपरति के लिए दिखाई देने लगे।

इस प्रकार प्राथमिक समस्या का समाधान हो जाने के बाद, प्रशिक्षण-संस्थाओं में सुधार करने के लिए “कोटारी समीक्षण” द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देश उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिये :—

1. ट्रेनिंग कवियों में हमी अध्यापकों की नियुक्त किया जाय, जिनके पास शिक्षा की उपाधि के अतिरिक्त दो विषयों में स्नातकोत्तर-उपाधियाँ हों।
2. ट्रेनिंग कवियों में हमी अध्यापकों की नियुक्त किया जाय, जिनके पास बी० ए० की उपाधि के अतिरिक्त निर्मा विषय में स्नातकोत्तर-उपाधि हों।
3. प्रशिक्षण-संस्थाओं के वाक्यक्रमों, शिक्षण-उपकरण और अध्यापन एवं सहायक की विधियों में सुधार किया जाय।

1. S. N. Mukherji : *op. cit.*, p. 422.

2. *Ibid.*, p. 422.

3. *Kothari Commission Report*, pp. 623-624.

4. प्रशिक्षण-संस्थाओं में वर्कशॉपों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार किया जाय।
5. प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था से एक प्रयोगात्मक या प्रदर्शन-विद्यालय का सम्बद्ध होना अनिवार्य कर दिया जाय।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. What 'shortcomings' do you find in your Teacher-Training Programme? Give your suggestions in the light of the recommendations of Mudaliar Commission and those of the Kothari Commission given thereafter to improve the Teacher-Training Programmes in the country.

आप अपने शिक्षक-प्रशिक्षण के कार्यक्रम में क्या-क्या कमियाँ पाते हैं? शिक्षक-प्रशिक्षण के कार्य में सुधार लाने हेतु मुदालियर आयोग के सुझावों तथा उसके पश्चात् कोटारी आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में अपने सुझाव दीजिए।

2. Describe some chief problems of Teacher-Education and suggest measures to solve them.

भारत में अध्यापक-शिक्षा की कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए और उनके समाधान के लिए सुझाव दीजिए।

3. What reforms have been suggested by the Education Commission to break down the isolation of Primary and Secondary teachers' training institutions from the academic life of the universities and the everyday problems of schools?

प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापकों की प्रशिक्षण-संस्थाओं का विश्व-विद्यालयों के विद्वत्परिपद् के जीवन तथा विद्यार्थियों की दैनिक समस्याओं से पर्याप्त दूरी हटाने के लिए शिक्षा-आयोग ने क्या सुधार प्रस्तुत किये हैं?

4. Write short notes on the following :—(i) Teacher Education by Correspondence Courses, (ii) In-Service Teacher-Education, (iii) Regional Colleges of Education, and (iv) State Institutes of Education.

अप्रतिष्ठित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—(1) पत्र-व्यवहार पाठ्य-क्रम द्वारा अध्यापक शिक्षा, (2) सेवाशालीन अध्यापक शिक्षा, (3) शिक्षा के प्रादेशिक केंद्र, और (4) शिक्षा के राज्य-संस्थान।

# 27

## प्रौढ़ व समाज शिक्षा

### ADULT & SOCIAL EDUCATION

"Adult education is education for everybody at all times and in all conditions."—Bryson.

#### विषय-प्रवेश

आधुनिक ज्ञान में प्रचलित शिक्षा के समस्त क्षेत्रों के समान प्रौढ़-शिक्षा की धारणा भी यूरोपीय है। जब यूरोप-निवासियों के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का भारत में प्रवेश हुआ, तब लोगों में निवास करने वाले प्रौढ़ों में भी अपनी भौतिक सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिए, ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी इस इच्छा की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम मिट्टाग्रिज—जन् 1882 के "इन्टर कमीनन" ने की। उनसे मिट्टाग्रिज की मि निरक्षर प्रौढ़ों के लिए जहाँ-जहाँ सम्भव हो, वहाँ-वहाँ रात्रि-विद्यालयों (Night Schools) की स्थापना की गयी।

जबकि "जर्मनी" की मिट्टाग्रिज का कोई दायराधिक फल न मिलता, तथापि द्वितीय ज्ञान (1921-1937) एवं प्राम्तीय स्वजायन (1937-1947) में भारतीय शिक्षा-संस्थानों ने प्रौढ़-शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किए। स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक, माध्यमिक, राजकीय, औद्योगिक एवं साम्प्रदायिक दृष्टियों ने प्रौढ़-शिक्षा के महत्व की स्वीकार किया गया है। इसलिए, 1949 में "प्रौढ़-शिक्षा" (Adult Education) को "समाज-शिक्षा" (Social Education) का नाम देकर, उसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

#### भारत में प्रौढ़-शिक्षा का विकास

##### Development of Adult Education in India

इस सन्दर्भ की दृष्टि में भारत में प्रौढ़-शिक्षा के विकास का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों एवं कालों के अन्तर्गत कर रहे हैं :—

1. प्रौढ़-शिक्षा के लिए प्रारम्भिक प्रयास—भारत में प्रौढ़-शिक्षा के लिए प्रारम्भिक प्रयास का श्रेय—ईसाई मिशनरियों को प्राप्त है। उनका यह प्रयास सर्व-प्रथम 19वीं शताब्दी के मध्य में मद्रास-प्रान्त में आरम्भ हुआ। डा० मुन्नीषाप्पाय के अनुसार<sup>1</sup> :—ईसाई मिशनरियों ने मद्रास-प्रान्त में हरिजनो के लिए कनिष्ठ रात्रि-विद्यालयों की स्थापना की। कुछ समय के बाद किसान भी उनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगे। मद्रास के बाद मिशनरियों ने बंगाल, बम्बई, मध्य-प्रदेश और संयुक्त प्रान्त में रात्रि-विद्यालयों की स्थापना की। इस प्रकार, उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में यत्र-तत्र प्रौढ़-शिक्षा के लिए पर्याप्त कार्य किया।

2. प्रौढ़-शिक्षा के लिए "हण्टर कमीशन" का सुझाव—सन् 1882 के "हण्टर कमीशन" ने अपने प्रतिवेदन में प्रौढ़-शिक्षा को स्थान दिया और बम्बई-प्रान्त में 357 रात्रि-विद्यालयों का उल्लेख किया। इन विद्यालयों में वयस्कों को साधारण लिखना-पढ़ना और अकर्मणित सिखाया जाता था। इनकी लोकप्रियता में दिन-प्रति-दिन वृद्धि हो रही थी। अतः "कमीशन" ने सरकार का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट किया और सुझाव दिया कि उपयुक्त स्थानों पर रात्रि-विद्यालयों के संचालन का कार्य आरम्भ किया जाय। किन्तु, भारतीयों की शिक्षा के प्रति उदासीन अंग्रेजी सरकार ने इस सुझाव की पूर्ण उपेक्षा की।

3. प्रौढ़-शिक्षा के लिए भारतीयों के प्रयास—"हण्टर कमीशन" के सुझाव से प्रेरणा प्राप्त करके, भारतीयों ने व्यक्तिगत रूप में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। सन् 1910 में बड़ोदा राज्य में माध्यमिक पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य आरम्भ हुआ। सन् 1912 में मैसूर राज्य के दीवान श्री विश्वेश्वरैया ने इस राज्य में अनेक रात्रि-विद्यालय खोले। कुछ उत्साही भारतीयों ने बंगाल, मद्रास और बम्बई में रात्रि-विद्यालयों का आयोजन किया। परन्तु, धनमात्र और सरकार से अधिक सहायता न मिलने के कारण 1917 तक उनकी संख्या निरन्तर शून्य होती चली गई।

4. प्रौढ़-शिक्षा के क्रमवद्ध इतिहास का आरम्भ—भारत में प्रौढ़-शिक्षा का क्रमवद्ध इतिहास सन् 1919 से आरम्भ हुआ। इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान में भारत के अनेक निरक्षर सैनिक अन्य देशों के निवासियों के सम्पर्क में आए। वे वहाँ से नए विचार और ज्ञान की पिपासा लेकर स्वदेश लौटे। दूसरा, 1919 के "भारत-सरकार-अधिनियम" (Government of India Act) के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की बागडोर भारतीय शिक्षा-मन्त्रियों के हाथ में आ गई। उन्होंने प्रौढ़-शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया। तीसरा, उक्त "अधिनियम" के परिणामस्वरूप भारतीयों की अनिवार्य जनशिक्षा को वयस्क-मताधिकार प्राप्त हो

1. डा० धीरनारायण मुन्नीषाप्पाय - भारतीय शिक्षा का इतिहास (आधुनिक काल), p. 209.

गया। अतः प्रौढ़-शिक्षा की ओर उनका ध्यान जाना स्वाभाविक था, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके ही निरक्षर प्रौढ़ अपने मताधिकार का उचित प्रयोग कर सकते थे।

5. 1921 से 1937 तक प्रौढ़-शिक्षा—सन् 1919 के "अधिनियम" ने भारत में द्वैध प्रणाली की स्थापना की। उस "अधिनियम" के अनुसार, शिक्षा हस्ता-न्तरित विषय था। अतः उसे जनप्रिय भारतीय मन्त्रियों को सौंप दिया गया। अपने देशवासियों के लिए चरित्र-शिक्षा के महत्त्व से नली-भाँति अवगत होने के कारण, भारतीय मन्त्रियों ने अपने पदों की सम्हालते ही प्रौढ़-शिक्षा के व्यापक कार्यक्रमों का मूलपात किया।

ये कार्यक्रम विभिन्न प्रान्तों में समान एवं असमान रूपों में प्रकट हुए। 1921 में पंजाब में "प्रौढ़-निरक्षरता-निवारण-आन्दोलन" आरम्भ हुआ और राजि-विद्यालयों का निरालाप्यस्त किया गया। उन्नीस वर्ष संयुक्त प्रान्त की सरकार ने राजि-विद्यालयों की स्थापना के लिए 6 नगरपालिकाओं को अनुदान दिया। 1922 में बम्बई में 27 प्रौढ़-विद्यालयों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार के विद्यालयों की बंगाल और मध्य-प्रान्त में नृष्टि की गई। 1924 में बाघणगोर की सरकार ने राजि-विद्यालयों को विधिवत् स्वीकार करने के लिए कानूनों का निर्माण किया।

इस प्रकार, देश के लगभग सभी प्रान्तों में भारतीय शिक्षा-मन्त्रियों ने प्रौढ़-शिक्षा का प्रचार करने में अद्वय उत्साह का प्रमाण दिया। फलस्वरूप, 1922 में प्रौढ़-विद्यालयों की जो संख्या 630 थी, वह 1927 में बढ़कर 3,784 हो गई। किन्तु, 1927 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने प्रौढ़-शिक्षा के समस्त धनाभाव की समस्या उपस्थित कर दी। परिणामतः उसी प्रचार में शिथिलता आ गई और प्रौढ़-शालाओं की संख्या कम होकर 1937 में 2,027 रह गई। पर फिर भी, यह कहना असंभव न होगा कि इस अवधि में प्रौढ़-शिक्षा के लिए जो चेष्टाएँ की गईं, उन्होंने हमको मुहूर्त आधार प्रदान किया। 1937 के उपरान्त, जब परिस्थितियों ने करवट बदली, तब इसी आधार पर प्रौढ़-शिक्षा के प्रचार का कार्य पुनः आरम्भ किया गया।

6. 1937 से 1942 तक प्रौढ़-शिक्षा—सन् 1935 के "भारत-सरकार-अधिनियम" (Government of India Act) के अनुसार, देश में प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना हुई। यह "अधिनियम" सन् 1937 में क्रियान्वित किया गया और प्रान्त के समस्त विषय—जनप्रिय भारतीय मन्त्रियों के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आ गए। परिस्थितियों के इस परिवर्तन ने प्रौढ़-शिक्षा में नव-जीवन का संचार दिया और हमने समस्त पराक्रम पर अपना अभियान आरम्भ किया। यह देखकर, केन्द्रीय सरकार का ध्यान प्रथम बार प्रौढ़-शिक्षा की ओर गया। अतः हमने 1939 में बिहार के शिक्षा-मंत्री, डा० मैथिल महामुद की अध्यक्षता में "प्रौढ़-शिक्षा-समिति" (Adult Education Society) का निर्माण किया और हमने प्रौढ़ों की साक्षर बनाने के विषय में व्यावहारिक सुझाव देने की शुरुआत की।

उक्त "समिति" और भारतीय शिक्षा-मन्त्रियों ने प्रौढ़-शिक्षा के विस्तार में अमिनन्दनीय योग दिया। विभिन्न प्रान्तों में उनके कार्यों का विवरण हृष्टम्भ है :—

1. आसाम—इस प्रान्त में प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का उत्तरदायित्व—शिक्षा-विभाग पर रखा गया। इस विभाग ने अपने कर्मचारियों की सहायता से प्रौढ़-साक्षरता एवं साक्षरता के उपरान्त "अनवरत शिक्षा" (Continuation Education) को शिक्षा में प्रशसनीय कार्य किए।

2. बंगाल—इस प्रान्त में प्रौढ़-शिक्षा को "ग्राम-पुनर्निर्माण-योजना" (Rural Reconstruction Scheme) का अंग बनाया गया। इस "योजना" के अन्तर्गत सरकार ने ग्राम-सभाओं को प्रौढ़-शालाओं की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुदान दिया।

3. बिहार—इस प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री, डा० सैयद महमूद ने 1938 में "अपना परिवार साक्षर बनाओ" (Make your home literate) नामक साक्षरता-आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन की अवधि में हजारों ग्रामों में वाचनालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना की गई।

4. बम्बई—इस प्रान्त की सरकार ने 1937 में "प्रान्तीय प्रौढ़-शिक्षा-परिषद्" (Provincial Board of Adult Education) का संगठन किया। इस "परिषद्" के सत्वावधान में बम्बई नगर में वयस्क-साक्षरता की योजना त्रिदिविनी की गई। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने व्यक्तिगत मम्पाओं द्वारा संचालित प्रौढ़-शालाओं को उदार आर्थिक सहायता दी। यह योजना इतनी अधिक सफल हुई कि सरकार ने "बम्बई नगर प्रौढ़-शिक्षा-समिति" का निर्माण करके, नगर की प्रौढ़-शिक्षा का भार उगे सौंप दिया।

5. पंजाब—इस प्रान्त में सरकार ने निरक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी हजारों पुस्तकें प्रकाशित करवा के, उनको जिना कोई मूल्य लिए वितरित करवाया।

6. मद्रास—मद्रास के मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचार्य ने प्रौढ़ों के लिए सामिल भाषा में एक पुस्तक लिखी।

7. मध्य-प्रान्त—इस प्रान्त में सरकार ने प्रौढ़-शालाओं की स्थापना के लिए (2,000) रुपए की धनराशि स्वीकृति की।

8. उत्तर प्रदेश—इस प्रान्त की सरकार ने 1930 में "प्रौढ़ शिक्षा-विभाग" की स्थापना की और अगले 8 वर्षों में पुरुषों के लिए 100, एवं स्त्रियों के लिए 62 प्रौढ़-शालाओं की और 1,319 पुस्तकालयों की स्थापना की।<sup>1</sup>

सारांश में, 1937-42 की अवधि में भारतीय शिक्षा-मन्त्रियों ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में "प्रौढ़-शिक्षा" का नवीन अध्याय आरम्भ किया। उन्होंने अपने प्रान्तों के आर्थ-व्यय (Budget) में प्रौढ़-शिक्षा को स्थान दिया। उन्होंने प्रौढ़-शालाओं,



राष्ट्र-विद्यालयों, ग्रामीण पुस्तकालयों और चन्दे-फिरले पुस्तकालयों की व्यवस्था करके निरस्मरणीय कार्य किया। इसीलिए, जैसा कि डा० मुनोपाध्याय ने लिखा है<sup>1</sup> :—“यथार्थ में, सन् 1937-42 की अवधि—प्रौढ़-शिक्षा का स्वर्ण-युग मानी जा सकती है।”

7. 1942 से 1947 तक प्रौढ़-शिक्षा—इन अवधि में द्वितीय विश्व-युद्ध, पर विधेय रूप से 1942 के राजनीतिक आन्दोलन और ब्रिटिश दमन-नीति का विषम प्रभाव प्रौढ़-शिक्षा पर भी पड़ा। इस नीति के परिणामस्वरूप, 1942 से 1947 तक सभी प्रान्तों में प्रौढ़-शिक्षा के कार्य में शिथिलता आ गई। इसका कारण बताते हुए, डा० मुनोपाध्याय ने लिखा है<sup>2</sup> :—“भिन्न-भिन्न राज्य-सरकारों ने अपने आय-व्यय की रकम को घटा कर सीमित क्षेत्र में तथा सीमित दंग पर साक्षरता-प्रसार के कार्य को जोधित रहने दिया।”

8. योजना से पूर्व प्रौढ़-शिक्षा (1947-1951)—इस अवधि में प्रौढ़-शिक्षा के सम्बन्ध में काफी छान-बीन करके, उसके भावी स्वरूप एवं कार्यक्रम को निश्चित किया गया। इसीलिए, इस अवधि को प्रौढ़-शिक्षा का “अन्वेषण-काल” (Period of Exploration) कहा जाता है।

इस अवधि में सर्वप्रथम 1948 में “केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय बोर्ड” ने अपनी एक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वतन्त्र भारत में प्रौढ़-शिक्षा का पुन-संगठन किया जाना आवश्यक है। भारत-सरकार ने इस प्रस्ताव से गहमत होकर, सन् 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में एक “ममिति” का निर्माण किया और उसमें प्रौढ़-शिक्षा के पुनर्संगठन के विषय में अपने मुद्दाय देने को कहा।

इस “ममिति” का सर्वप्रमुख मुद्दाय यह था कि प्रौढ़-शिक्षा को धारणा ज्ञापन संकुचित है। अतः उसके कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए, उसे “समाज-शिक्षा” की संज्ञा दी जाय, ताकि वह देश के नागरिकों को नवीन सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भाग लेने की क्षमता प्रदान कर सके।

सरकार ने “ममिति” के मुद्दाय का स्वागत किया। सन् 1949 में “केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय-बोर्ड” का 15वां अधिवेशन उद्घाटन में हुआ। उस अवसर पर भारत के तत्कालीन शिक्षा-मंत्री, मोराना आज़ाद ने उपस्थित सदस्यों को “प्रौढ़-शिक्षा” के स्थान पर “समाज-शिक्षा” शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया। उसी समय से केन्द्रीय एवं राज्य-स्तरीय पर समाज-शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए; जिनमें :—

केन्द्रीय स्तर पर—दिल्ली में “केन्द्रीय चलचित्र पुस्तकालय” (Central Film Library) और “केन्द्रीय श्रवण-दृश्य-संस्था” (Central Audio-Visual

1. डा० श्रीधरनाथ मुनोपाध्याय : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 210.

2. डा० श्रीधरनाथ मुनोपाध्याय : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 210.

Institute) की स्थापना की गई। ग्रामीण बयस्कों की शिक्षा को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए "जनता कॉलेजों" की गृष्टि की गई। डेन्मार्क के "लोक-विद्यालयों" (Folk Schools) की पद्धति पर मैसूर में ग्रामीण विद्यापीठों का निर्माण किया गया। 1951 में "यूनेस्को" के सहयोग से "दिल्ली मायेंब्रैटिक पुस्तकालय" (Delhi Public Library) में ग्रामीण बयस्कों के लिए चलते-फिरते पुस्तकालयों की योजना आरम्भ की गई।

राज्य-स्तर पर—मैसूर राज्य की "बयस्क शिक्षा-मर्मिनि" (Adult Education Council) ने वाचनालय-सेवा का गूत्रपात किया। आंध्र प्रदेश और दिल्ली के जामिया मिलिया ने प्रौढ-शिक्षा-महित्व के उत्पादन में रत्नायनीय कार्य किया। मद्रास में "फिरका-विकास-योजना" (Firka Development Scheme) के अन्तर्गत शिक्षकों एवं युवक-नेताओं पर प्रौढ-शिक्षा के कार्य का उत्तरदायित्व रखा गया। उत्तर प्रदेश में श्री इमी उदाहरण का अनुमरण किया गया। बिहार में प्रौढ-शिक्षा को औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत स्थान दिया गया और विद्यालयों के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रौढ-शिक्षा का कार्य सौंपा गया। पश्चिमी बंगाल में स्टेरियोतो, लोकनाटकों एवं भजन-मङ्गलियों द्वारा यह कार्य आरम्भ किया गया।

इस प्रकार, 1947 से 1951 तक केन्द्रीय एवं राज्य-स्तरो पर प्रौढ-शिक्षा-प्रसार की विविध गतिविधियाँ परिलक्षित हुईं। मुकजी व ओड के अनुसार<sup>1</sup> :—“ये गतिविधियाँ इस बात की सूचक हैं कि प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में उम्रतिशील हृष्टिकोण अपनाया जा रहा था।”

### पंचवर्षीय योजनाओं में समाज-शिक्षा Social Education Under Five-Year Plans

स्वतन्त्र भारत में समाज-शिक्षा के क्षेत्र का केवल साक्षरता प्रसार तक ही सीमित नहीं रखा गया है। उसके अन्तर्गत बयस्कों के लिए स्वास्थ्य-शिक्षा, अपने समय का सदुपयोग एवं नागरिकता की शिक्षा का भी सम्मिलित किया गया है। “पहली पञ्चवर्षीय योजना” के अनुसार<sup>2</sup> :—“व्यापक रूप में समाज-शिक्षा के अन्तर सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक रूप से किए गए सभी कार्य आ जाते हैं।”

पञ्चवर्षीय योजनाओं में ये कार्य किस प्रकार सम्पादित किए जा रहे हैं, इसका सशित वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है।

पहली योजना में समाज-शिक्षा (1951-56)—इस “योजना” के अन्तर्गत मत् 1952 में “सामुदायिक विकास-कार्यक्रम” (Community Development Programme) आरम्भ किया गया। इस “कार्यक्रम” के अनुसार, ग्रंथेय विरास-

1. डा० मुकजी व डा० ओड भारतीय शिक्षा, पृ० 140।

2. पहली पञ्चवर्षीय योजना, पृ० 307।

संघ में दो समाज-शिक्षा-अधिकारी (एक पुरुष और एक महिला) नियुक्त किए गए। इन दोनों अधिकारियों के मुख्य कार्य थे :—साक्षरता-आन्दोलन चलाना, ग्रामों में वाचनालय स्थापित करना, शिक्षा-सम्बन्धी प्रदर्शनियों का आयोजन करना और सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यों की व्यवस्था करना।

इस "योजना" के दौरान में 5 "समाज-शिक्षा-संगठनकर्त्ता-प्रशिक्षण-केन्द्र" (Social Education Organizers' Training Centres) एवं 116 "आदर्श सामुदायिक केन्द्र" (Model Community Centres) स्थापित किए गए। साथ ही, 454 प्राथमिक विद्यालयों को "विद्यालय एवं सामुदायिक केन्द्रों" (School-cum-Community Centres) का रूप प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में 55,000 "युवक गोष्ठियाँ" (Youth Clubs), "ग्रामीण रेडियो फोरम" (Rural Radio Forums) और जिला एवं ग्राम-स्तरीय पर वाचनालयों एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई।

"पहली पंचवर्षीय योजना" में समाज-शिक्षा के लिए 7.5 करोड़ रुपए का प्रावधान था।<sup>1</sup>

दूसरी योजना में समाज-शिक्षा (1956-61)—इस "योजना" के मुख्य कार्यक्रम अग्रनिर्दिष्ट थे :—समाज-शिक्षा की प्रणालियों में सुधार, विभिन्न स्तरों पर समाज-शिक्षा की कक्षाओं का विस्तार, राज्य-सरकारों द्वारा साक्षरता एवं समाज-शिक्षा के केन्द्रों का उद्घाटन, समाज-शिक्षा के कार्यकर्त्ताओं एवं संगठनकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, प्रौढ़-साहित्य का प्रकाशन, दृश्य-श्रव्य-शिक्षा की व्यवस्था और जनता-कॉलेजों की स्थापना। ये कार्यक्रम—समाज-शिक्षा के प्रति सरकार की बढ़ती हुई रुचि एवं जागरूकता के स्रोतक थे।

इस "योजना" के दौरान में यूनेस्को एवं अमरीका के सहयोग से 1956 में दिल्ली में "राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र" (National Centre for Fundamental Education) की स्थापना की गई। इस "केन्द्र" के मुख्य उद्देश्य हैं :—उच्च क्रम-पारियों को समाज-शिक्षा का प्रशिक्षण देना एवं समाज-शिक्षा की मुख्य समस्याओं पर अनुसंधान करना। 1958 में पुस्तकालयाध्यक्षों के अभाव की पूर्ति करने के लिए दिल्ली-विश्वविद्यालय में "पुस्तकालय-विज्ञान का केन्द्रीय संस्थान" (Central Institute of Library Science) खोला गया। नवसाक्षरों के लिए उपयोगी पुस्तकों का उत्पादन करने के लिए दिल्ली में "राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट" (National Book Trust) का संगठन किया गया।

इसी बीच इसी दौरान में "औद्योगिक कार्यकर्त्ताओं का समाज-शिक्षा-संस्थान" (Social Education Institute for Industrial Workers) संगठित किया गया। साथ ही, 8 "समाज-शिक्षा-संगठनकर्त्ता-प्रशिक्षण-केन्द्र" खोले गए। महिलाओं की

समस्याओं का समाधान करने के लिए "केन्द्रीय समाज-कल्याण-परिषद्" (Central Social Welfare Board) की स्थापना की गई। स्त्रियों को शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए "संक्षिप्त कार्यक्रमों" (Condensed Courses) का श्रीगणेश किया गया। स्त्रियों के लिए "महिला-श्रवण-गोष्ठियों" (Listening Clubs for Women) का आयोजन किया गया। 1960 में दिल्ली के निवासियों को कृषि-सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करने के लिए "टेलीविजन-सेवाओं" (T. V. Services) का सुरूवात किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, "ग्रामीण रेडियो फोरमों", "औद्योगिक श्रम-फोरमों" (Industrial Labour Forums) और "युवक गोष्ठियों" की सहायता में वृद्धि करने का सराहनीय कार्य किया गया। समुदाय एवं विश्वविद्यालय को एक-दूसरे के निश्चित करने के लिए "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग" ने 1960 में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए "प्रसार-व्याख्यान" (Extension Lectures) की योजना आरम्भ की।

"दूसरी पंचवर्षीय योजना" में समाज-शिक्षा के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।<sup>1</sup>

तीसरी योजना में समाज-शिक्षा (1961-66) — इस "योजना" के कार्य-क्रमों में "चीन-भारत-युद्ध" के कारण कुछ शिथिलता आ गई। फिर भी, सरकार ने समाज-शिक्षा और व्यस्क-भाषाश्रिता की प्रगति के लिए कुछ उल्लेखनीय कदम उठाए।

इस "योजना" की अवधि में सन् 1962 में दिल्ली-विश्वविद्यालय ने "पत्राचार-पाठ्यक्रमों" (Correspondence Courses) द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कार्य आरम्भ किया। पूना, मैसूर और राजस्थान-विश्वविद्यालयों में "प्रौढ़-शिक्षा-विभाग" की स्थापना की गई। मैसूर में "जनता-कॉलेजों" के माध्यम से 6 विद्यापीठों का सृजन किया गया। महाराष्ट्र में ग्राम-निवासियों को साक्षर बनाने के लिए "ग्राम-शिक्षण-मोहिम" (Gram Shikshan Mohim) का गठन किया गया।

मुक्तों व ओड़ के अनुसार<sup>2</sup> :— "इसी काल में "श्रमिक-शिक्षा-योजना" (Workers' Education Scheme) के अन्तर्गत 18 "क्षेत्रीय केन्द्र" (Regional Centres) आरम्भ किए गए, जिनमें 217 शिक्षा-अधिकारियों और 6,340 "श्रमिक शिक्षकों" (Worker Teachers) को प्रशिक्षण दिया गया। साथ में, इसी काल में "साक्षरता" (Literacy) के स्थान पर "क्रियात्मक भाषाश्रिता" (Functional Literacy) शब्द का प्रचलन हुआ।"

1. *Third Five-Year Plan*, p. 577.

2. डा० मुक्तों व डा० ओड़ : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 143.

“तीसरी पंचवर्षीय योजना” में समाज-शिक्षा के लिए 12 करोड़ रुपए की घनराशि निर्धारित की गई थी।<sup>1</sup>

चौथी योजना में समाज-शिक्षा (1969-1974)—विद्यार्थी तीन योजनाओं की तुलना में इस “योजना” में सरकार ने समाज-शिक्षा के प्रसार में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की। इस “योजना” में अप्रतिष्ठित शिक्षाओं में नवीन प्रयत्न किए गए।

ग्रामों और कस्बानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रौढ़-शिक्षा का व्यापक आन्दोलन किया गया। ग्रामों का विकास करने के लिए, प्रौढ़-शिक्षा को जनता के जीवन और कार्यों में सम्मिलित किया गया। साक्षरता को प्रभावशाली बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना की गई। समाज-शिक्षा के कार्य-कर्ताओं और पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। दिल्ली के “पुस्तकालय-विज्ञान के केन्द्रीय-संस्थान” का विकास और दिल्ली नगर में पुस्तकालय-सेवा का विस्तार किया गया। जनता-कमिटी, प्रौढ़-शिक्षाओं एवं अनवरत शिक्षा का आयोजन किया गया।

उपनिर्भरित के अभाव, यूनेस्को की सहायता से नवसाक्षरों के लिए विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का भारी संग्रह प्रकाशन किया गया। यूनेस्को और शिक्षा-संस्थान के पारस्परिक सहयोग में औद्योगिक कार्यकर्ताओं की शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिए “अमिक विद्यार्थी” (Polyvalent Centres) का जन्म-लब्ध किया गया। “ज्ञान-सरोवर” नामक प्रौढ़-विश्वकोष एवं 10 मंठों में “द्वितीय विश्वभास्वी” का प्रकाशन किया गया। राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-परिषद् (National Adult Education Board) की स्मृति की गई।

“तीसरी पंचवर्षीय योजना” में समाज-शिक्षा के लिए 64 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी।<sup>2</sup>

राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-परिषद्—इस “परिषद्” को “तीसरी पंचवर्षीय योजना” का सबसे मुख्यत्वात् उपहार माना जाता है। अब हम इसकी स्थापना के कारण और इसके कार्यों की सार-संग में आसक्त कर रहे हैं।

मुक्तजी व ओढ़ के विद्वान्मुक्तः—“भारत में साक्षरता की वृद्धि एवं प्रतिफल प्रति वर्ष के हिसाब से हो रही है।” इस वृद्धि को देखकर भारतीय राज-सीमाओं द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि देश के समस्त निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने में लगभग 70 वर्ष लगेंगे। इस दीर्घकालीन अवधि में कमी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़-शिक्षा परिषद् की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव किया

1. Third Five-Year Plan, p. 577.

2. चौथी पंचवर्षीय योजना (पारम्परिक नदरेमा), p. 231.

3. डा० मुक्तजी व डा० ओढ़ : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 144.

गया। अतः “कोटारी कमीशन” के सुझाव के अनुसार, 5 दिसम्बर, 1969 को “राष्ट्रीय श्रीढ़-शिक्षा-परिषद्” का गठन किया गया। इस “परिषद्” को निम्नलिखित कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है<sup>1</sup> :—

1. श्रीढ़-शिक्षा के प्रसार के लिए उपयुक्त साहित्य का उत्पादन करना।
2. श्रीढ़-शिक्षा के सम्बन्ध में अन्वेषण, अनुसंधान एवं भूगोलीय प्रोत्साहन देना।
3. श्रीढ़-शिक्षा के प्रसार में योग देने वाले कार्यों के विषय में परामर्श देना और उनको सफल बनाना।
4. विभिन्न मन्त्रालयों, सरकारों और व्यक्तिगत संस्थाओं के श्रीढ़-शिक्षा-विषयक कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करना।
5. केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों एवं केन्द्र-प्रणामित प्रदेशों की सरकारों को श्रीढ़-शिक्षा से सम्बन्धित सब विषयों पर परामर्श देना।
6. श्रीढ़-शिक्षा के लिए सुनिश्चित नीति का निर्धारण करना, उचित सम्बन्धित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करना, और समय-समय पर उसकी प्रगति का पुनरावलोकन करना।

पाँचवीं योजना में समाज-शिक्षा (1974-1979)—इस “योजना” में समाज शिक्षा के अपाक्षित कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं<sup>2</sup> :—श्रीढ़-शिक्षा, देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आधारशिला है। अतः श्रीढ़-शिक्षा का अधिक-से-अधिक प्रसार करने का प्रयास किया जायगा। इस कार्य को सफल बनाने के लिए, श्रीढ़-शिक्षा को कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, परिवार-नियोजन आदि में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है। यह भी निश्चय किया गया है कि श्रीढ़-शिक्षा का धपरकों के कार्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाय, ताकि उनमें स्वयं ही शिक्षा ग्रहण करने की इति उत्पन्न हो जाय।

एक प्रस्ताव यह है कि श्रीढ़-शिक्षा का विकास के सब कार्यक्रमों में सम्बन्ध स्थापित किया जाय और श्रीढ़-शिक्षा के अभिहरणों (Agencies) को इसके लिए उत्तरदायी बनाया जाय। इस दिशा में “मघन कृषि-विकास-कार्यक्रम” (Intensive Agricultural Development Programme) की सहायता में 100 बिर्तों में कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इस कार्य का “पाँचवीं योजना” में अधिक विस्तार किया जायगा।

“पाँचवीं योजना” में समाज-शिक्षा के अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रम अधो-निहित हैं<sup>3</sup> :—

1. डा० मुन्शी व डा० ओढ़ : पूर्वोक्त पुस्तक, pp. 144-145.
2. Draft Fifth Five-Year Plan, Vol. II, p. 200.
3. Draft Fifth Five-Year Plan, Vol II, pp. 200-201.

1. विन्हाय प्रौढ़ों के लिए विभिन्न भाषायी भाषाओं में "राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट" द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन ।
2. "जिला-पुस्तकालयों" (District Libraries) की सृष्टि और जिले के सम्मान प्रौढ़-पुस्तकालयों ने उसके सम्बन्ध की स्थापना ।
3. प्रौढ़-शिक्षा एवं विद्यार्थक साक्षरता के कार्यक्रमों का प्राची एवं विद्यार्थक-पुस्तकों के पुस्तकालयों की सहायता से विस्तार ।
4. नहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित "युवक-सोशियल" और "नेहरू-युवक-केंद्रों" का अनौपचारिक शिक्षा के केंद्रों के रूप में परिवर्तन ।
5. मैसूर की विद्यापीठों, बम्बई की "श्रमिक विद्यापीठों", "केंद्रीय समाज कल्याण-परिसर" द्वारा व्यवस्था विषयों के लिए संशोधन पाठ्यक्रमों और महाभारत के "ग्राम-निर्माण-सोशियल" द्वारा समाज-शिक्षा के सम्बन्ध में किए जाने वाले कार्यों का विस्तार ।

"सोचनी योजना" में समाज-शिक्षा पर 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का निर्णय किया गया है ।<sup>1</sup>

### प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ व परिभाषा

#### Meaning & Definition of Adult Education

प्रौढ़-शिक्षा का सामान्य अर्थ है—निम्नतर प्रौढ़-पुस्तकों एवं स्त्रियों की साक्षरता-विमर्श, पढ़ना और अंकगणित विद्याना । विभिन्न लेखकों ने विभिन्न परिभाषाओं द्वारा प्रौढ़-शिक्षा के अर्थ का स्पष्टीकरण किया है; यथा :—

1. हाइमन :—"प्रौढ़-शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सब अवसरों पर और सब परिस्थितियों में शिक्षा है ।"

"Adult Education is education for everybody at all times and in all conditions."—Lyman Bryson : *Adult Education*, p. 6.

2. मॉरगन, होल्मस व बंडी :—"प्रौढ़-शिक्षा किसी नई बात को सीखने के लिए प्रौढ़ व्यक्ति का ज्ञान-वृद्ध कर दिया जाने वाला प्रयास है ।"

"Adult Education may be thought of as the conscious effort of a mature person to learn something new."—Morgan, Holmes & Bundy : *Methods in Adult Education*, p. 12.

3. रॉस, होल्मस्टर व हाउसे :—"प्रौढ़-शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन के तीन पक्षों में से किसी एक से या अधिक से हो सकता है—उसका व्यावसायिक जीवन, उसका व्यक्तिगत जीवन या नागरिक के रूप में उसका जीवन ।"

"Adult education may be concerned with any or more of the three aspects of an individual's life—his work life, his personal

life, or his life as a citizens."—Reenes, Fensler & Houle : *Adult Education*, p. 171.

उल्लिखित परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मापदण्डन प्रौढ-शिक्षा में प्रौढ़ों को दी जाने वाली सम्पूर्ण औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित है। भारत में प्रौढ-शिक्षा के इसी अर्थ को स्वीकार किया गया है। अब हम भारतीय दृष्टिकोण से प्रौढ-शिक्षा की परिभाषा को डा० मुखर्जी के जयान्वित शब्दों में संक्षेपित कर सकते हैं :—“भारत में प्रौढ-शिक्षा के दो पहलू हैं : (1) प्रौढ-साक्षरता, अर्थात् उन प्रौढ़ों की शिक्षा—जिनको विद्यालयों में कभी किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, और (2) साक्षर-प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा।”

“In India, adult education has two aspects : (i) Adult literacy, i. e. education of those adults who never had any schooling, and (ii) Continuation education of the adult literate.”—S. N. Mukerji : *Education in India, Today and Tomorrow*, p. 434.

प्रौढ कौन है ? : Who is an Adult ?

सामान्यतया 40 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति को प्रौढ़ों में स्थान दिया जाता है। किन्तु, प्रौढ-शिक्षा की दृष्टि में यह आयु विभिन्न देशों में विभिन्न है। इंग्लैंड में सब व्यक्तियों के लिए 15 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा और 18 वर्ष की आयु तक अल्पकालीन शिक्षा का आयोजन है। अब वहाँ 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति—प्रौढ़ों की श्रेणी में आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 20 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति को प्रौढ़ों में गणना की जाती है।

भारत के कुछ राज्यों में अभी तक केवल 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है।<sup>1</sup> अब हमारे देश में वय के अनुसार प्रौढ़ों को मोटे तौर पर अग्रलिखित ढंग में रखा गया है—(1) 12 वर्ष से 18 वर्ष तक प्रौढ़, (2) 19 वर्ष से 35 वर्ष तक के प्रौढ़ और (3) 35 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़।

### प्रौढ़-शिक्षा की नवीन धारणा New Concept of Adult Education

जनतन्त्र की सफलता के 3 मुख्य आधार हैं—उमके नागरिकों की साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण और उनमें नागरिकता की गमात भावना का विकास। इस दृष्टि में स्वतन्त्र भारत के लिए प्रौढ़-शिक्षा को केवल प्रौढ-साक्षरता तक सीमित रखना, देश की जनतन्त्रीय व्यवस्था के लिए अहितकर माना गया। साथ ही यह

1. S. N. Mukerji *op cit*, p. 434.



स्वीकार किया गया कि देश की प्रगति के लिए निरक्षर नागरिकों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त, उनका नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है। अतः सरकार ने 1948 में श्री मोहनलाल नक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त की जाने वाली समिति के परामर्श को स्वीकार करके, प्रौढ़-शिक्षा को समाज-शिक्षा की संज्ञा देने का निर्णय किया।

“केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड” का 15वाँ अधिवेशन जनवरी, 1949 में अलाहाबाद में हुआ। उस अवसर पर भारत के तत्कालीन शिक्षा-मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने भाषण के माध्यम से प्रौढ़-शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए कहा<sup>1</sup> :—“प्रौढ़-शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें उस शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक नागरिक को जनसंघीय सामाजिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए तैयार करे।” उसी समय से भारत में प्रौढ़-शिक्षा की धारणा में परिवर्तन हो गया और उसे “समाज-शिक्षा” कहा जाने लगा।

### प्रौढ़-शिक्षा व समाज-शिक्षा में अन्तर

#### Difference between Adult & Social Education

प्रौढ़-शिक्षा एवं समाज-शिक्षा के अन्तर को वंशीधर श्रीवास्तव के अग्रलिखित शब्दों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है<sup>2</sup> :—“प्रौढ़-शिक्षा की संकल्पना में आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। साक्षरता के अपने छोटे दायरे से निकलकर वह सामाजिक शिक्षा का व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है। पहले उसका आयोजन केवल औपचारिक ढंग और व्यक्ति को साक्षर बनाकर तथा उसके लिए थोड़ा-बहुत पढ़ने-लिखने का प्रयत्न कर वह अपने कर्तव्य की दृष्टिशील समझ लेती थी। अब उसका लक्ष्य प्रौढ़ों को इस प्रकार की शिक्षा देना हो गया है जिससे वे व्यक्ति के रूप में और समाज के एक अंग के रूप में अपनी अभावग्रस्त दशा से ऊपर उठकर पहले से अधिक सम्पन्न और समस्त जीवन व्यतीत कर सकें।”

### समाज-शिक्षा का अर्थ व परिभाषा

#### Meaning & Definition of Social Education

समाज-शिक्षा नामक में प्रौढ़-शिक्षा का व्यापक एवं विकसित रूप है। इसमें शिक्षा के सामाजिक पक्ष पर धन दिया जाता है और व्यक्ति को अपने हित-साधन के

1. Maulana Abul Kalam Azad's Address at the 15th Meeting of the Central Advisory Board of Education held in Allahabad in January, 1949.
2. नवसत्तारोपयोगी साहित्य-निर्माण-मोष्टी की आख्या, शिक्षा-विभाग, उत्तर प्रदेश, 1958, pp. 54-55.

साधन-साध समाज के हित-साधन में न्यायमक भाग लेने की शिक्षा दी जाती है। समाज-शिक्षा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों व परिभाषाओं को उद्धृत कर रहे हैं; यथा :—

1. भीताना आवाद :—“समाज शिक्षा से हमारा अभिप्राय—पूर्ण मानव की शिक्षा है।”

“By social education, we mean an education for the complete man.” —Maulana Abul Kalam Azad's Inaugural address to UNESCO Seminar on Rural Adult Education, held in December, 1949 in Mysore

2. हुमायूँ कबीर :—“समाज-शिक्षा को एक प्रकार के अध्ययन के पाठ्य-क्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य—व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का निर्माण करना एवं सामाजिक सुदृढ़ता का विकास करना है।”

“Social Education may be defined as a course of study directed towards the production of consciousness of citizenship among the people and the promotion of social solidarity among them.” —Humayun Kabir *Education in New India*, p 82

3. “एजुकेशन इन इंडिया — समाज-शिक्षा के तीन पक्ष हैं —(1) अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों में साक्षरता का प्रसार, (2) साहित्यिक शिक्षा प्राप्त न करने वाले जन-समूहों में शिक्षित मस्तिष्क का निर्माण, और (3) व्यक्तियों में व्यक्तियों के रूप में एवं शक्तिशाली राष्ट्र के सदस्यों के रूप में नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश।”

“Social education has three aspects (1) the speed of literacy among grown-up illiterates (2) the production of an educated mind in the masses in the absence of literary education, and (3) the cultivation of a lively sense of rights and duties of citizenship, both individuals and as members of a powerful nation” —*Education in India*, 1947-48 Vol I, p 113

उद्धृत परिभाषाओं के आधार पर हम समाज-शिक्षा की धारणा में निहित अर्थों का विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं :—

1. समाज-शिक्षा—प्रौढ़ शिक्षा है।
2. समाज-शिक्षा—नागरिकता की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा है।
3. समाज-शिक्षा—समाज की प्रगति में योग देने की शिक्षा है।
4. समाज-शिक्षा—व्यक्ति के वैयक्तिक, आर्थिक, वैयक्तिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अधिक उत्पन्न बनाने की शिक्षा है।

5. समाज-शिक्षा—व्यक्ति को अधिक उत्तम कार्य, आराम, अवकाश का सदुपयोग और मनोरंजन की विधियाँ बताने की शिक्षा है।

### समाज-शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम Five-Point Programme of Social Education

भारत-सरकार ने समाज-शिक्षा की नवीन धारणा के अंतर्गत न केवल साक्षरता को, अपितु वयस्कों की व्यक्तियों और समाज के सदस्यों के रूप में सर्वतोमुखी उन्नति को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सरकार ने समाज-शिक्षा के अधोलिखित पंचमुखी कार्यक्रम का गृहण किया है<sup>1</sup> :—

1. निरक्षर वयस्कों में साक्षरता का प्रसार।
2. वयस्कों के लिए स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-विज्ञान के नियमों की शिक्षा की व्यवस्था।
3. वयस्कों की आर्थिक उन्नति के लिए उद्योग-धन्धों की शिक्षा की व्यवस्था।
4. वयस्कों के लिए व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल मनोरंजन के स्वस्थ साधनों की व्यवस्था।
5. वयस्कों में कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति पर्याप्त जागरूकता के साथ-साथ नागरिकता की भावना का विकास।

भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला समाज-शिक्षा का यह पंचमुखी कार्यक्रम अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत है। इसका चरम लक्ष्य—वयस्कों को साक्षर बनाने के साथ-साथ उनकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक उन्नति भी करना है, ताकि उनके जीवन का बहुमुखी विकास हो और वे विकसित मानवों की श्रेणी में अपना स्थान ग्रहण करें।

### समाज-शिक्षा की संस्थाएँ Institutions of Social Education

समाज-शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम उसके उद्देश्यों का स्पष्ट संकेत देता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है, जब समाज-शिक्षा की ऐसी संस्थाओं की सृष्टि हो जाय, जो वयस्कों की चेष्टाओं एवं अभिलाषाओं को स्वस्थ दिशाओं में मोड़कर, उनकी उद्दिष्ट मानव-प्राप्ति का ऐसा रूप प्रदान करें, जिसमें उनकी और समाज की हितसृष्टि हो। इन विचारों को अपना पथ-प्रदर्शक मानकर, समाज-शिक्षा के कार्यक्रमों ने निम्नलिखित प्रकार की संस्थाओं का आयोजन किया है :—

1. साक्षरता-कक्षाएँ : Literary Classes—इन कक्षाओं का संचालन

मुख्यतः "सामुदायिक योजनाओं" (Community Projects) द्वारा दिया जाता है।  
निरक्षरता के उन्मूलन में इनका योगदान प्रशंसनीय है।

2 सामुदायिक केंद्र : Community Centres—इन केंद्रों में मनोरंजन, सूचना-प्राप्ति और विचार-विमर्श-गोष्ठियों की व्यवस्था है। कुछ केंद्रों में बचस्को को विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की शिक्षा प्रहण करने की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

3. युवक गोष्ठियाँ Youth Clubs - ये गोष्ठियाँ साधारणतः युवकों के लिए खेल-कूद की व्यवस्था करती हैं। इनका मंडिक महत्त्व इस बात में है कि ये युवकों को सामूहिक जीवन की नवीन विधियों में प्रशिक्षण देती हैं।

4 महिला-समितियाँ Mahila Samities—इन समितियों में ग्रामीण स्त्रियों के लिए अवलम्बित कार्यों का आयोजन किया जाता है :—स्त्री-साक्षरता; गीत और भजन, खेल और मनोरंजन, धार्मिक और सामाजिक समारोह; बाल-कल्याण और पारिवारिक कार्यों पर व्याख्यान, मित्ताई, कढ़ाई और अन्य शिल्पों की शिक्षा; सज्जित आहार, सामान्य रोगों और उनके उपचारों की शिक्षा, इत्यादि।

### प्रौढ-शिक्षा का षष्ठमुखी कार्यक्रम

Six-Point Programme of Adult Education

"कोठारी कमिशन" द्वारा प्रौढ-शिक्षा का षष्ठ-मुखी कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसका वर्णन अध्याय 20 में किया जा चुका है। देखिए—पृष्ठ 257।

### समाज-शिक्षा के उद्देश्य

Aims of Social Education

भारत-सरकार ने समाज-शिक्षा के उद्देश्यों का 2 गण्ट वर्गों में विभाजित किया है :—

1. व्यक्तिगत उद्देश्य Individual Aims
2. समाजगत उद्देश्य Social Aims

हम इन उद्देश्यों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं, यथा :—

#### 1. व्यक्तिगत उद्देश्य : Individual Aims

समाज-शिक्षा का मुख्य प्रयोजन—व्यक्ता का व्यक्तियों के रूप में सर्वाङ्गीण बनाना है। अतः व्यक्तिगत दृष्टि से समाज-शिक्षा के निम्नलिखित 6 उद्देश्य रखे गए हैं :—

1. बचस्को का आत्म-विकास Self-Development—बचस्कों का आत्म-विकास करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं का परिचय देना व अनुकूल स्थिति

विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति, जीवन के निदानों का प्रतिपादन या किसी कला के अनुसरण के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

2. बच्चों का शारीरिक विकास : Physical Development—बच्चों का शारीरिक विकास करने के लिए स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों, वातावरण, अस्वस्थता से बचने के उपायों, बच्चों के क्षेत्रों में फैलने वाले मुख्य रोगों को रोकने एवं पोषक भोजन की समस्या का समाधान करने के लिए, उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

3. बच्चों का मानसिक विकास : Mental Development—जो बच्चा अपनी आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएँ हैं, उनका मानसिक विकास करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था करना ।

4. बच्चों का सांस्कृतिक विकास : Cultural Development—बच्चों का सांस्कृतिक विकास करने और उनको अपने देश के प्राचीन एवं वर्तमान सांस्कृतिक कार्यों से परिचित कराने के लिए, गीतों, लोकगीतों, नृत्यों, लोकनृत्यों, चर्चासत्रों, व्याख्यानो आदि की व्यवस्था करना ।

5. बच्चों की सामाजिक कुशलता का विकास : Development of Social Skill—बच्चों की सामाजिक कुशलता का विकास करने के लिए, उन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ रहने, जीवन में उन्नति करने, पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने और आधुनिक जटिल संसार में अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था करना ।

6. बच्चों की व्यावसायिक कुशलता का विकास (Development of Professional Skill)—बच्चों की व्यावसायिक कुशलता का विकास करने के लिए, नगरों में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की और ग्रामों में कृषि एवं कुटीर उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था करना ।

## 2. समाजगत उद्देश्य : Social Aims

यदि समाज-शिक्षा का मुख्य प्रयोजन—बच्चों का व्यक्तियों के रूप में सर्वांगीण विकास करना है, तबपि इसका प्रयोजन—बच्चों को समाज का लाभप्रद सदस्य बनाना भी है, ताकि उनका और उनके माध्यम से समाज का उत्थान हो । अतः समाजगत दृष्टि से समाज-शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :—

1. सामाजिक एकता का विकास : Promotion of Social Unity—आधुनिक भारतीय समाज—समुदायों एवं व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक द्वेषों एवं संघर्षों का महासागर बन गया है । परिणामतः भारतीय समाज—पूण्यता के कगार की ओर बढ़ी नहीं है बल्कि दूर हो रहा है । इसे यह पूण्यता अनेक स्तरों में दृष्टिगोचर होती है; यथा :—विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषा-भाषी समूहों, कुलों और कुलों, धर्मों



“समाज-शिक्षा का उद्देश्य—उन विधियों का निर्माण करना है, जिनमें सहकारी समुदायों एवं संस्थाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता एवं सम्मान से वंचित न हो।”<sup>1</sup>

4. सामाजिक आदर्श का समावेश : Inculcation of Social Ideal—प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हित का, अपने समूह, अपने समाज और अपने देश के हित के लिए मर्त्य्य वनिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सामाजिक आदर्श को समस्त युगों में सब देशों एवं समाजों द्वारा सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। इस आदर्श को एक प्रख्यात अंग्रेज लेखक के अश्रांक्ति वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है :—“यदि इंग्लैंड जीवित है, तो अन्त किसका है और यदि इंग्लैंड का अन्त होता है, तो जीवित कौन है ?” (“Who dies if England lives; who lives if England dies”)

वस्तुतः उक्त सामाजिक आदर्श का अनुसरण करके ही विश्व की महान् विभूतियों ने मानव-जाति की प्रगति में योग दिया है। अस्तु,

“समाज-शिक्षा का उद्देश्य—भारत के जन-जन में इस भावना का समावेश करना है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज एवं मानव-जाति की प्रगति में योग प्रदान करना अपना सर्वोच्च आदर्श समझे।”<sup>2</sup>

### समाज (प्रौढ़) शिक्षा का स्थान व महत्त्व

#### Place & Importance of Social (Adult) Education

भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में प्रौढ़ अथवा समाज-शिक्षा के स्थान एवं महत्त्व का विवेचन करते हुए, डा० के० जी० सेपदेन ने लिखा है :—“हम राष्ट्रीय जीवन के एक ऐसे नये युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो जायद और घाली कई जवाबदारीयों के लिये हमारे देश की भावी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्धारित कर देगा। हमारे राष्ट्रीय जीवन को विपाक करने वाले आपस के संगीन झगड़ों की परंपरा पट्टाई भी विनाश की बदली की तरह छंट जायेगी और हम फिर न्याय और स्वतंत्रता और समझदारी के प्रकाशमय वातावरण में पहुँच जायेंगे। यदि आप मुझे एक स्वतः स्पष्ट सत्य की दोहराने की अनुमति दें, तो मैं कहूँगा कि अकेले राज-नीतिक स्वतंत्रता सिंगी भी समाज या राष्ट्र के लिये, ‘अच्छे जीवन’ का आश्वासन नहीं कर सकती है। हम सभी-भाँति जानते हैं कि कई राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी हमारे जेबों में जकड़े हुए हैं, जो उन्हें ‘अच्छे जीवन’ की ओर नहीं बढ़ने देती हैं क्योंकि इन प्रकार का जीवन सख्त परिश्रम तथा समाजोपयोगी कार्य द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में, जब तक जनता ‘निरन्तर नवोत्थान’

1. *Teachers' Handbook of Social Education*, p. 23.

2. *Ibid.*

3. के० जी० सेपदेन : शिक्षा की पुनर्रचना, pp. 182-183.

के रूप में अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का मूल्य चुकाने को तैयार न हो, तब तक यह इस स्वतन्त्रता को भी सुरक्षित नहीं रख सकती है, और इस 'मनकंठा' के लिये उचित नागरिक तथा सामाजिक-शिक्षा की आवश्यकता होती है। यदि हमारा लक्ष्य ऊँचा है और हम अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के गहारे सामाजिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक लोकतन्त्र के लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, तो स्पष्टतः हमें जनमाधारण के लिये कहीं अधिक उच्च-स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होगी। नती तो हमेशा इस बात का सतर्क रहना कि चतुर लेकिन बेईमान दल या व्यक्ति अपने निरुष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तथाकथित 'स्वतन्त्रता' का धनुचित लाभ उठावें। इसी बात को मैं तत्काल और बड़े पैमाने पर 'प्रौढ़-शिक्षा' का आन्दोलन शुरू करने के राजनीतिक औचित्य का आधार कहूँगा।"

इन सारगर्भित शब्दों में समाजवादी शिक्षा-शास्त्रियों के अधिराज डा० संवर्दन ने हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन में समाज-शिक्षा के स्थान एवं महत्त्व का मन्देश दिया है। इसी संदेश को कुछ भिन्न शब्दावली में "कोठारी समीक्षण" ने इस प्रकार पुनरावृत्ति की है<sup>1</sup> :—“कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के भार को केवल पुलिस एवं सेना को नहीं सौंप सकता है। वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ी गीमा तक नागरिकों की शिक्षा, विभिन्न कार्यक्रमों के उनके ज्ञान, उनके चरित्र, उनकी अनुशासन की भावना एवं सुरक्षा-सम्बन्धी कार्यों में उनके कुशलतापूर्वक भाग लेने की क्षमता पर आधारित रहती है।” अतः हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन में समाज-शिक्षा का विशिष्ट स्थान और महत्त्व होना चाहिए।

### समाज (प्रौढ़) शिक्षा की आवश्यकता

#### Need of Social (Adult) Education

डा० मणि के शब्दों में :—“समाज-शिक्षा बहुमुखी प्रयास है, क्योंकि भारत ऐसे जनतंत्रीय धर्म-निरपेक्ष राज्य में इसका प्रमुख उद्देश्य—व्यक्ति में न केवल नागरिकता के अधिकारों की, परन्तु उत्तरदायित्वों की भी सजीव चेतना का विकास करना है।”

“Social education is a many-sided endeavour, since its aim is primarily to develop in an individual a live sense not only of the privileges but also of the responsibilities of citizenship in a democratic secular state like India.”—Dr R. S. Mani *Educational Ideas & Ideals of Eminent Indians*, p. 128

समाज-शिक्षा के इस उद्देश्य में उगड़ी आवश्यकता समाविष्ट है। इस आवश्यकता के अनेक रूप हैं, जिनका दिग्दर्शन निम्नांकित पक्षों में कराया जा रहा है।

1. Kothari Commission Report, p. 422



1. अशिक्षित वयस्कों की आवश्यकता : Need of Illiterate Adults—  
 "कोठारी कमिशन" के अनुसार, हमारे देश के 70 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं।<sup>1</sup>  
 इसके दो आधारभूत कारण हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षा को अभी तक देश के सब  
 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य नहीं बनाया जा सका है। 6-14 वर्ष के 40  
 प्रतिशत से अधिक बच्चे अब भी ऐसे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा के लाभ से वंचित रह  
 जाते हैं।<sup>2</sup> दूसरा, अनेक बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी संकटग्रस्त  
 है कि वे अपने अनिवाकों द्वारा अल्प आयु ही में किसी-न-किसी कार्य में लगा दिए  
 जाते हैं।

दोनों प्रकार के बच्चे बड़े होकर निरक्षर वयस्कों की श्रेणी में अपना स्थान  
 ग्रहण करते हैं। शिक्षा प्राप्त न कर सकने के कारण उनका मानसिक विकास अवरोध  
 हो जाता है। अतः समाज में उनका स्थान—शिक्षित व्यक्तियों से निम्नतर होता है,  
 जो विविध विधियों का प्रयोग करके, उनका शोषण करते हैं। यह भारतीय संविधान  
 की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि यह देश के सब नागरिकों को समानता एवं  
 स्वतन्त्रता के समान अधिकार प्रदान करता है। अशिक्षित वयस्क इन अधिकारों का  
 उपभोग करने से वंचित रह जाते हैं। इन अशिक्षित वयस्कों के लिए समाज-शिक्षा  
 की आवश्यकता है, ताकि वे शिक्षित होकर समानता एवं स्वतन्त्रता के अधिकारों का  
 उपभोग कर सकें।

2. अर्द्ध-शिक्षित वयस्कों की आवश्यकता : Need of Half Illiterates—  
 भारत में अनेक बच्चों को आर्थिक, पारिवारिक या किसी अन्य कारण से प्राथमिक  
 शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पहले ही अपना अध्ययन स्थगित करने के लिए विवश  
 होना पड़ता है। ये अर्द्ध-शिक्षित बच्चे—वयस्कों के रूप में भी अर्द्ध-शिक्षित  
 रहते हैं।

प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को ही साक्षर माना  
 जाता है। अतः अर्द्ध-शिक्षित व्यक्तियों की शिक्षा को पूर्ण करने और उनको समस्त-  
 दार नागरिक बनाने के लिए समाज-शिक्षा की आवश्यकता है।

3. वयस्क-नागरिकों की आवश्यकता : Need of Adult Citizens—जो  
 देश जायिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है, उसे अपने  
 वयस्क नागरिकों को विकास कार्यक्रमों में कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से भाग लेने की  
 शिक्षा देनी चाहिए। यह बात भारत के लिए विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि यहाँ के  
 विज्ञान जनसमूहों को विद्यालयों में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है और  
 जिनको शिक्षा प्राप्त भी हुई है, वह विकास-कार्यक्रमों के लिए व्यर्थ है। जो कृषक,  
 भूमि की जोतता है, उसे भूमि की बनावट का ज्ञान होना चाहिए। जो श्रमिक,

1. Kothari Commission Report., p. 422.

2. India, 1974, p. 50.

मशीन को चलाता है, उसे मशीन के अंगों का ज्ञान होना चाहिए। दृष्टियों, श्रमिकों आदि को अपने कार्यों का ज्ञान नहीं है। इन सभी वयस्क-नागरिकों को उनके कार्यों से सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करने के लिए समाज-शिक्षा की आवश्यकता है।

भारत में वयस्क-नागरिकों के लिए समाज-शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, 'कोठारी कमिशन' ने लिखा है<sup>1</sup> :—“भारत—जननन्ध्रिय गणनन्ध्र है। अतः उसका कर्तव्य प्रत्येक वयस्क-नागरिक को ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है, जो वह प्राप्त करना चाहता है और जो उसे अपनी व्यक्तिगत उन्नति, व्यावसायिक प्रगति और सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में गरिमा प्राप्त करने के लिए प्राप्त करनी चाहिए।”

**4. पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता : Need of Complete Education—** हमारी शिक्षा-मस्याओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा अपूर्ण होने के कारण दोषपूर्ण है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्तियों के वास्तविक जीवन, आवेगों एवं आवश्यकताओं से असम्बद्ध है। अतः जब व्यक्ति जीवन में प्रवेश करते हैं, तब वे अपनी शिक्षा को अपूर्ण पाते हैं। इस अपूर्ण शिक्षा के दोषों को दूर करने और उसे पूर्ण बनाने के लिए समाज-शिक्षा की आवश्यकता है।

इस आवश्यकता पर बल देने हुए, “कोठारी कमिशन” ने लिखा है<sup>2</sup> :—“विद्यालय-शिक्षा के बाद शिक्षा का अन्त नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आज के वयस्क को तीव्र गति में परिवर्तित होने वाले समाज की ओर समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं की जानकारी होना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों ने सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए भी जीवन में शिक्षा की आवश्यकता है।”

**5. आर्थिक आवश्यकता Economic Need—** भारत के असह्य निवासियों और उनके पूर्वजों के लिए आर्थिक सम्पन्नता सपनानी बात है और रही है। वे यहाँ से नहीं, अपितु शताब्दियों में आर्थिक विवशताओं के गिरावर हैं। उनको इन विवशताओं से मुक्त करने के लिए नगरों में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की और ग्रामों में कृषि एवं कुटीर उद्योग-पधों की शिक्षा की ध्येयता की गई है। समाज-शिक्षा के संगठनकर्त्ताओं द्वारा इस व्यवस्था के लिए जाने के कारण ही, उनकी आवश्यकता की स्वीकार किया जाता है।

**6. सामाजिक आवश्यकता Social Need—** समाज की प्रगति का मूल-धार, उसके सदस्यों का पारस्परिक सहयोग है। सहयोग ही समाज की बल देता है, उसकी रक्षा करता है और उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। आज के भारतीय समाज में सहयोग की अनुपस्थिति में गीधा गाथाकार होता है। उसके स्थान पर

1. *Kothari Commission Report*, p. 422

2. *Ibid*

देगने को मिलाते हैं—पारस्परिक द्वेष, संघर्ष एवं वैमनस्य, जिन्होंने देग के नियामियों के जीवन को विष्टुंघलित कर दिया है।

समाज-शिक्षा—देग के नागरिकों को पारस्परिक सहयोग ने समुदायों एवं संस्थाओं का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसीलिए, समाज-शिक्षा की आवश्यकता का एक स्वर ने अनुमोदन किया जाता है।

डाक्टर राव ने समाज-शिक्षा की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के विषय में अपने विचारों को इस प्रकार लेखबद्ध किया है<sup>1</sup> :—“प्रौढ़-शिक्षा एवं प्रौढ़-साक्षरता के अभाव में आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को उस सीमा एवं गति को प्राप्त करना असम्भव है, जिसको हमें आवश्यकता है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रौढ़-शिक्षा और प्रौढ़-साक्षरता के कार्यक्रमों को सर्वोच्च स्थान ग्रहण करना चाहिए।”

7. राजनीतिक आवश्यकता : Political Need—समाज-शिक्षा—देग की राजनीतिक आवश्यकता को पूर्ण करने में किस भीमा तक सहायक सिद्ध हो सकती है। इस सम्बन्ध में 1958 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा-मंत्री, माननीय कमलापति त्रिपाठी के अग्रनिमित्त शब्द उल्लेखनीय हैं<sup>2</sup> :—

“आज का समय हमारे देग के लिए पुनर्नियोजन एवं पुनर्निर्माण का, उत्थान एवं विकास का समय है। हमने अपने देग में धर्म-निरपेक्ष कल्याणकारी लोकतन्त्र की स्थापना की है। हमें उसे सुदृढ़ एवं गतिजाती बनाना है, किन्तु यह तब तक सम्भव नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी आधारशिक्षा सुदृढ़ एवं गतिजाती न हो। और यह आधारशिक्षा है—इस देग की वह समस्त जनता, जिसके ऊपर आज राज्य सरकारों का सुयोग्य निर्वाचन निर्भर है तथा समूचे राष्ट्र के मंगलमय स्वरूप का निर्धारण अवलम्बित है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है—उस दिशा की ओर अग्रसर करने वाली जन-जन की उपयुक्त शिक्षा एवं उपयुक्त साहित्य।”

अतः जिन प्रकार हम अपने बालकों एवं बालिकाओं, युवकों एवं युवतियों के लिए उपयुक्त शिक्षा एवं उपयुक्त साहित्य की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था हमें अपने देग के वयस्कों के लिए भी करनी चाहिए। इस व्यवस्था का नारा—समाज-शिक्षा ने अपने ऊपर दिया है। इसीलिए, समाज-शिक्षा की आवश्यकता का नारा बुलन्द किया जाता है।

8. देग की आवश्यकता : Need of the Country—अशिक्षित व्यक्ति—देग के लिए अभिजात है। देग भले ही उनके द्वारा की जाने वाली हानि से अनभिज्ञ

1. Dr. V. K. R. V. Rao : *Education & Human Resource Development*, p. 80.
2. माननीय शिक्षा-मंत्री कमलापति त्रिपाठी : नव-साक्षरतायोगी साहित्य निर्माण-मोन्ठी की भाषा ने “शशकपन” ने।

हो, पर उगे उनकी शिक्षा का बहुत भारी भूख भुजाना पड़ता है। इसका कारण बताते हुए, "कोठारी कमीशन" ने लिखा है<sup>1</sup> :—"विशाल घटना के रूप में निरक्षरता—आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को अवरोध कर देती है और आर्थिक उत्पादकता, जनसंख्या-नियंत्रण, राष्ट्रीय एकीकरण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और सफाई की उन्नति पर दूषित प्रभाव डालती है।"

"कमीशन" का यह कथन हमारे देश पर अक्षरशः लागू होता है। यहाँ के 70 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं। मानसिक शक्तियों में विहीन होने के कारण, उनकी स्वयं निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अतः उनके देश की उत्पादकता में वृद्धि करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि भारत की उत्पादकता का स्तर निम्न है और उसकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। समाज-शिक्षा इन व्यक्तियों को भाँसकर बनाकर, इनकी देश की प्रगति में योग देने की सामर्थ्य प्रदान करती है। यही कारण है कि समाज शिक्षा के पक्ष में शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं।

सारंग में, हम यह सक्ते हैं कि समाज-शिक्षा की न केवल हमारे देश के लिए, बल्कि हमारे देशवासियों के लिए भी आवश्यकता है। इस शिक्षा को प्राप्त करके उनकी बौद्धिक शक्तियों का विकास होगा। फलस्वरूप, उनका आर्थिक एवं पारिवारिक उत्थान होगा। साथ ही, वे भारत की सामाजिक एवं व्यावसायिक उन्नति में अमूलपूर्व योग देंगे। परिणामतः राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होगी और आवश्यक समाज-सेवाओं का विस्तार होगा। इस प्रकार, एक दिन, भारत का कल्याणकारी राज्य का स्वप्न साकार होगा। अतः हम हमारे ख़बरे के गन्धों में आपसपूर्वक यह कहते हैं :—"समाज-शिक्षा ही वह आधार है, जिस पर स्वतन्त्र भारत, कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर सकता है, जो वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सामाजिक सुरक्षा की सँग की स्वीकार करेगा।"

"Social education is the foundation on which alone free India can build up a Welfare State which will recognize the claims of both individual freedom and social security"—Hamayun Kabir : *Education in New India*, p. 96.

### समस्याएँ व उनके समाधान Problems & Their Solutions

भारत के प्रशासकों, राजनीतिज्ञों, शिक्षा-शास्त्रियों एवं समाज-सेवकों का यह विश्वास है कि जब तक समाज-शिक्षा का समुचित आयोजन नहीं, भारतवासियों की निरक्षरता का विनाश नहीं किया जाएगा, तब तक न तो देश के औद्योगिक विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाएँ ही सफल होंगी और न आर्थिक एवं सामाजिक

1. Kothari Commission Report, p. 423.

पुनर्निर्माण का कार्य ही सम्भव होगा। इसी विश्वास से प्रेरित होकर समाज-शिक्षा एवं साक्षरता-प्रसार के लिए "चतुर्थी पंचवर्षीय योजना (1951-56) के समय में ही विभिन्न कार्यक्रमों का सूचनाय किया गया है। परन्तु, 20 वर्षों में अधिक अवधि के पश्चात् भी इन कार्यक्रमों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसका व्यापारभूत कारण है—समाज-शिक्षा के कार्य में बाधाएँ उत्पन्न करने वाली सहानामी समस्याएँ (Concomitant Problems)। हम इन प्रकार की अनिष्ट मुख्य समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों की क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं; यथा :—

1. समस्या—निरक्षरता : Illiteracy—भारत में निरक्षरता की समस्या—जटिल भी है और गम्भीर भी है। यह जटिल इसलिए है, क्योंकि हमारे ग्रामों में निवास करने वाले 80 प्रतिशत व्यक्तियों में से अधिकांश निरक्षर होते हुए भी अनिश्चित नहीं हैं। इसकी पुष्टि में एन० ए० दूथी के अप्रॉक़िमेट जर्चों की पढ़िए :—  
 "यद्यपि भारतीय ग्रामवासी निरक्षर हैं, पर इसलिये वह अनिश्चित नहीं हैं। वह एक जगह में निश्चित हैं। उनकी स्मृति विशाल है, जिसमें उसने अपने देश के प्राचीन समय के विनाश ज्ञान का संचय कर रखा है।"

"Although the Indian villager is illiterate, he is not, therefore, uneducated. He is educated in a sense. He has a tremendous memory in which he carries a vast amount of folklore."—N. A. Toothi : *The Vaishnavas of Gujarat*, p. 130.

यह समस्या, गम्भीर इसलिए है, क्योंकि विश्व के निरक्षर व्यक्तियों में से आधे से अधिक हमारे देश में हैं। उन लक्ष्य के समर्थन में पी० एन० चटर्जी के इन वाक्यों का अध्ययन पढ़िए :—  
 "विश्व के निरक्षर व्यक्तियों की सम्पूर्ण संख्या के आधे से अधिक भारत में निवास करते हैं। उनको ज्ञान के स्वरूप प्रकाश में आलोक्ति करने का कार्य भी अति विनाश है।"

"More than half of the total number of adult illiterates in the world live in India. The work of bringing some light to them is one of tremendous magnitude."—P. N. Chatterjee.

निरक्षरता की समस्या की जटिलता एवं गम्भीरता के इन चिन्तों की आगे के मानस-पटल पर बुझती या सफ़ेद छाप छोड़कर, अब हम इसका थोड़ा-सा विस्तृत विवेचन कर देना आवश्यक समझते हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 54.80 करोड़ है।<sup>1</sup> इस जनसंख्या में केवल 29.45 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। इन व्यक्तियों में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात क्रमशः 39.45 और 18.76 है।<sup>2</sup>

1. *India*, 1974, p. 6.

2. *India*, 1974, p. 6.

अन्तर्राष्ट्रीय ध्यानि के यूरोपीय असेम्बलियों, मन्त्रालय मिरहल ने इन बातों को प्रामाणिकता पर दो कारणों से अनास्था प्रकट की है। पहला, साक्षर बनाए जाने वाले व्यक्तियों की माधरता की कोई परीक्षा नहीं की जाती है। दूसरा, जन-गणना के अवसर पर जो व्यक्ति अपने को साक्षर बनाने हैं, उनको बिना किसी प्रमाण के साक्षर मान लिया जाता है। इन दोनों कारणों के आधार पर, मिरहल ने सम्पूर्ण विश्व को यह समाचार दिया है :—“भारत में प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है और यदि विशेष प्रगति हुई भी है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकला है।”

“No very significant progress was made in India in adult education; even if significant progress had been made, it could have had no result.”—Gunnar Myrdal. *Asian Drama*, Vol. III, p. 1671.

शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता अधिक है।<sup>1</sup> इसके अतिरिक्त, निरक्षरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। “कोठारी समीक्षण” का कथन है<sup>2</sup> :—“भारत 1951 की अपेक्षा 1961 में अधिक निरक्षर था, क्योंकि इस अर्धशताब्दी में लगभग 36 लाख निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई।” इस कथन के आधार पर हम बलपूर्वक कह सकते हैं कि इस समय तक यह संख्या और भी बढ़ गई होगी, क्योंकि 1961 से 1971 तक जनगणना में लगभग 11 करोड़ की वृद्धि हो चुकी थी।<sup>3</sup>

आश्चर्य इस बात का है कि यह वृद्धि प्राथमिक शिक्षा के अभावपूर्ण विस्तार और माधरता-प्रसार के अनेक कार्यक्रमों एवं आन्दोलनों के बावजूद हुई है। इस वृद्धि का उत्तरदायित्व—भारत-सरकार पर रखते हुए, मिरहल ने लिखा है :—“भारत में ब्रिटिश शासन के अन्त में प्रौढ़-शिक्षा के प्रति अत्यधिक उत्साह था, किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् उसका कोई विशेष समर्थन नहीं किया गया है।”

“In India there had been marked enthusiasm for adult education toward the end of the British rule, but after independence there was no significant support”—Myrdal : *op. cit.*, p. 1686.

समाधान—निरक्षरता का उन्मूलन Liquidation of Illiteracy—निरक्षरता की समस्या की सम्भारना और उसके उन्मूलन के प्रति सरकार की उत्साहीता के कारण, हमारे निरक्षर देशवासियों की सुनीबों में ये होंकर गुहर रहे हैं। इन सुनीबों और इनके कारणों के सम्प्रमाण बिना की पोलीजी नहीं हमें डॉ॰ मन्दरे

1. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृ. 482.

2. Kothari Commission Report, p. 423

3. India, 1974, p. 5

इस शब्द-चित्र में मिलती हैं<sup>1</sup> :—“हमारे निरक्षर देशवासी न तो छपी हुई पुस्तक का एक भी पृष्ठ पढ़ सकते हैं, न वे मतदान की पर्ची पर समझदारी के साथ नेपान लगा सकते हैं, और न ही रोजमर्रा के छोटे-छोटे हिसाब लगा सकते हैं। अगर मंगार का एक ऐसा मानचित्र बनाया जाय जिसमें साक्षरता की स्थिति देगाई जाय और पृथ्वी के निरक्षर इलाकों को काला रंगा जाय, तो भारत उस मानचित्र में तन्त्रकारपूर्ण महाद्वीप जैसा दिखाई देगा और यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है ! इस परिस्थिति पर हम लज्जित भी हैं और हमें क्रोध भी आता है— लज्जित इसलिए कि एक ऐसा देश, जो संसार को सबसे पुरानी सांस्कृतिक परम्पराओं का मालिक होने का गर्व करता है; आज इस दुर्दशा को पहुँच गया है; और क्रोध इसलिए कि हम इस कलंक को इतने समय से सहन करते आये हैं। यह सिर्फ इसलिए कि निरक्षरता को समूल नष्ट करने के लिए अब तक राष्ट्रव्यापी पैमाने पर काम कर कोई सुसंगठित आन्दोलन नहीं चलाया गया है।”

सम्भवतः डा० सैयदेन के विचारों से परिचित एवं प्रभावित होने के कारण, ‘कोठारी कमीशन’ ने हड़तापूर्वक कहा है<sup>2</sup> :—“इस असह्य स्थिति का अन्त करने के लिए, हम राष्ट्रव्यापी पैमाने पर सामंजस्यपूर्ण एवं अविराम गति से चलने वाले निरक्षरता-उन्मूलन-आन्दोलन की सिफारिश करते हैं।”

यह आन्दोलन किन उपायों का प्रयोग करके, निरक्षरता का उन्मूलन कर सकता है, इन विषय में “कोठारी कमीशन” ने अनेक ठोस और व्यावहारिक सुझाव दिए हैं; यथा<sup>3</sup> :—

1. 6-11 वय-वर्ग के सब बच्चों लिए 5 वर्ष की सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. 11-14 वय-वर्ग के उन बच्चों के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जिन्होंने बीन में विद्यालय जाना बन्द कर दिया हो, या जिन्होंने विद्यालय जाने की मुविद्या से लाभ न उठाया हो।
3. 15-30 वय-वर्ग के पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए अल्पकालीन एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
4. सब विद्यालयों को सामुदायिक जीवन के केन्द्रों का रूप प्रदान किया जाय, उन पर अपने-अपने क्षेत्र की निरक्षरता के उन्मूलन का दायित्व लगा जाय और उनके शिक्षकों द्वारा निरक्षरता-उन्मूलन के आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया जाय।

1. के० जी० सैयदेन : शिक्षा की पुनर्रचना, p. 185.  
 2. Kothari Commission Report, p. 424.  
 3. Kothari Commission Report, pp. 665-666.

5. सब स्तरों की शिक्षा-संस्थाओं के छात्रों द्वारा वषरों को पढ़ाया जाना, "अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा-कार्यक्रम" (Compulsory National Service Programme) का अभिन्न अंग बना दिया जाय।
6. फार्मों, मिलों, उद्योगों एवं व्यवसायों आदि के मानिकों को एक अधिनियम बनाकर अपने कर्मचारियों को 3 वर्ष में माशर बनाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय।
7. ग्रामों में नियाम करने वाली स्त्रियों को माशर बनाने के लिए, "ग्राम-सेविकाओं" (Village Sisters) की नियुक्ति की जाय।
8. नगरों में निवाम करने वाली स्त्रियों में माशरता की उन्नति करने के लिए, "केन्द्रीय समाज-कल्याण-परिषद्" (Central Social Welfare Board) द्वारा "सघन पाठ्यक्रमों" (Condensed Courses) का संचालन किया जाय।
9. माशरता को कायम रखने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की जाय, पठन-मामपी का निर्माण किया जाय एवं "अनुसरण कार्यक्रम" (Follow-up Programme) क्रियान्वित किया जाय।

आकाश का शिक्षक : Teacher in the Sky—"कोठारी कमीशन" द्वारा प्रस्तावित निरक्षरता-उन्मूलन के उपायों के वर्णन के उपरान्त एक नवीनतम उपाय का विवरण आपके आन्तरिक अभ्यासिक न होगा। निरक्षरता-उन्मूलन के इस उपाय का प्रयोग—समुक्त राज्य अमरीका द्वारा किया जा रहा है। उसने 30 मई, 1974 को एक शैक्षिक उपग्रह वायुमंडल में भेजा है, जिसे "आकाश का शिक्षक" कहा गया है। भारत-सरकार को एक वर्ष के लिए इस शिक्षक की सेवाएँ प्राप्त हुई हैं।

इस अवधि में यह अद्भुत शिक्षक—शिक्षा-प्रसार का कार्य करेगा। वह बिहार, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के निवासियों के लिए आकाश से शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम 2,400 टेलीविजनों की महापना में उक्त राज्यों के प्रत्येक ग्राम के निवासियों तक पहुँचाये जायेंगे। इन कार्यक्रमों के आ-गंत कृषि, स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन एवं शिक्षा के अन्य अंगों को ग्यान दिया गया है। जुलाई 1975 से जून 1976 तक आकाश का यह शिक्षा समयम 1,500 घण्टों की अवधि में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करेगा।<sup>1</sup>

2. समस्या—पाठ्यक्रम . Curriculum—समाज-शिक्षा की दूसरी महत्वाती समस्या—पाठ्यक्रम की है। अभी तक वषरों के लिए किसी उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जा सका है, जिसके कवस्वम्न समाज-शिक्षा के कार्य की सीमाएँ

1. *The Hindustan Times* Dated 31st of May, 1974.



अभी तक संकुचित हैं और उसकी गति में तीव्रता नहीं आ पाई है। बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण न किए जा सकने के 4 मुख्य कारण हैं; यथा :—

- (i) बच्चों की अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, आवश्यकताएँ एवं जीवन-सम्बन्धी धारणाएँ बालकों से भिन्न होती हैं। अतः जिस पाठ्यक्रम का प्रयोग बालकों के लिए किया जाता है उसका प्रयोग बच्चों के लिए नहीं किया जा सकता है।
- (ii) कुछ बच्चे विस्कुल निरक्षर होते हैं, जिनके लिए सर्वप्रथम अक्षर-ज्ञान की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है। कुछ बच्चे अर्द्ध-शिक्षित होते हैं, जिनके लिए कुछ विशिष्ट विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है। कुछ बच्चे नवसाक्षर होते हैं, जिनको कुछ निपटना-पढ़ना आता है। डा० सीताराम जायसवाल के विचार से<sup>1</sup> :—  
“उन बच्चों में नागरिकता की भावना का विकास करने के लिए सम्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है।” अतः तीनों प्रकार के बच्चों के लिए एक ही पाठ्यक्रम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- (iii) भारत के समस्त बच्चों को आयु के अनुसार, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :—(i) 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे, (ii) 19 वर्ष से 35 वर्ष तक के बच्चे, और (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे। इन वर्गों में बालक और बालिकाएँ, युवक और युवतियाँ, पुरुष और स्त्रियाँ मानी हैं। विभिन्न वर्गों और विभिन्न अवस्थाओं के होने के कारण, उनकी रुचियों, गतियों, प्रवृत्तियों, मानसिक योग्यताओं आदि में अन्तर होना स्वाभाविक है। अतः इन सबके लिए एक ही पाठ्यक्रम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- (iv) समाज-शिक्षा का उद्देश्य—बच्चों को केवल साक्षर बना कर, उनका मानसिक विकास करना ही नहीं है, बल्कि उनको किसी उपयोगी हस्त-शिल्प का प्रशिक्षण देना भी है, ताकि वे अपने समय का सदुपयोग करते, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। शैक्षिक माँगों के अनुसार, इन हस्तशिल्पों की विभिन्नता में साहस्य है। अतः विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों के लिए विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था करना, यदि असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है।

उपर्युक्त वदित्वाद्यों के कारण बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम के संकल्पना-कार्य में एक बड़का समस्या का रूप धारण कर लिया है।

1. डा० सीताराम जायसवाल : प्रौढ़ शिक्षा-प्रकार, p. 50

**समाधान—उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण : Construction of Suitable Curriculum—**बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण अप्रतिष्ठित 4 आधारों पर किया जा सकता है :—

- (i) निरक्षर, अर्द्ध-माक्षर एवं नवमाक्षर बच्चों की आवश्यकताओं का अध्ययन ।
- (ii) विभिन्न लिंगों एवं वय-वर्गों के बच्चों की रुचियों, रुझानों, प्रवृत्तियों एवं मानसिक योग्यताओं का अध्ययन ।
- (iii) बच्चों का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास करने के लिए, उपयुक्त विषयों का चयन ।
- (iv) बच्चों की आर्थिक उन्नति करने के लिए, उनके परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तशिल्पों का चयन ।

उपयुक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए, हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए एक नहीं, बल्कि अनेक पाठ्यक्रमों का निर्माण करना पड़ेगा । किन्तु, इन पाठ्यक्रमों के विषय समान होंगे । अन्तर केवल यह होगा कि इन विषयों की सामग्री का स्तर—निम्न, उच्च या विस्तृत होगा । दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम—प्रारम्भिक, मध्य एवं उच्च स्तरों के लिए भिन्न होंगे । इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्धारित हो सकते हैं :—

1. प्रारम्भिक स्तर—सामान्य ज्ञान, पढ़ना, लिखना और प्रारम्भिक अकण्ठित ।

2. मध्य स्तर—मातृभाषा, गणित, नागरिक ज्ञान, भारत का भूगोल एवं इतिहास, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक या अधिक शिल्प, कृषि (केवल बालकों और पुरुषों के लिए) और मजदूरी एवं विद्युत (केवल बालिकाओं और स्त्रियों के लिए) ।

3. उच्च स्तर—साहित्य, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, विश्व का भूगोल एवं इतिहास, परिवार-नियोजन, प्रजातन्त्र एवं राष्ट्रीयता के सिद्धान्त, गृहकारी गतिविधियाँ एवं संस्थाओं का समन्वय और संचालन, द्रव्यादि ।

बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्बन्धित एक उपयोगी सुझाव—राजस्थान राज्य-शिक्षा-संस्थान के भूतपूर्व निदेशक, श्री बालगोविन्द तिवारी ने अपने 'प्रयोजनशील प्रौढ़-शिक्षा' शीर्षक लेख में दिया है, जो इस प्रकार है :—

"बहुत-सा ज्ञान ऐसा होता है, जो जिना पड़ा-लिखा ज्ञान या मजदूर जानता है । परन्तु, बहुत-सा ऐसा है, जिसकी वह प्राप्ति करना चाहता है, परन्तु बिना साक्षरता के उसका लाभ उठाने नहीं मिल सकता है । उदाहरण के लिए, घर-घर में बालक जन्म लेते हैं और बीमार भी होते हैं । यदि ऐसी छोटी-छोटी पुष्पिकाएँ तैयार कर ली जायें जिनमें कि परेले नुस्खे दिए हों, तो यह प्रत्येक प्रौढ़ को साक्षरता

की ओर ने जाने में बहुत सहायक होंगे। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न उपयोगी विषयों पर छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ साधारण भाषा में लिख कर उपलब्ध की जायें। जहाँ पढ़े-लिखे लोगों को ये पुस्तिकाएँ साक्षरता की ओर अग्रसर करेंगी, वहाँ साक्षरता-प्राप्त लोगों की साक्षरता की रक्षा करते में तथा उसके दृढ़ीकरण में भी ये अमूल्य सहायता करेंगी।”

श्री तिवारी ने लगभग 30 विषयों की सूची दी है, जिन पर पुस्तिकाएँ तैयार करवाई जा सकती हैं। इन विषयों में मुख्य हैं :—(1) वस्त्रों के रंग, (2) वस्त्रों की कहानियाँ, (3) पशुपालन, (4) दाना-चारा, (5) पशु-चिकित्सा, (6) गन्ध वेली, (7) बीज, (8) गाद, (9) जुलाई, (10) बुझाई, (11) पौधों की गन्धाल, (12) मिनाई, (13) ऋतु-फल, (14) शाक-भाजी, (15) नीम, बड़, बनूज, इत्यादि।

3. समस्या—शिक्षण-विधि : Method of Teaching—व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शिक्षण-विधि का निर्धारण इतनी जटिल समस्या है कि अभी तक इसका समाधान नहीं किया जा सका है। यह समस्या जटिल इसलिए है, क्योंकि वयस्क आर्थिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं, जिस पर वे किसी प्रकार का प्रतिक्रम नहीं चाहते हैं। उनमें अहम् की भावना होती है, जिस पर वे किसी प्रकार का प्रहार करने नहीं कर सकते हैं। उनकी अपनी कुछ आदतें होती हैं, अपने कुछ मित्राण होते हैं, जिनके प्रतिकूल वे कार्य नहीं करना चाहते हैं। उनका अपना जीवन-दर्शन होता है, संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण होता है, जिनमें वे सरलता में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

उपरिर्क्षित सभी तथ्यों ने वयस्कों के लिए उपयुक्त शिक्षण-विधि के निर्धारण को एक दुर्माध्य समस्या बना दिया है। यदि शिक्षण-विधि का कोई भी तत्त्व, उनकी आदतों, मित्राणों, स्वतन्त्रता, जीवन-दर्शन, अहम् की भावना आदि में टकरावा है, तो उस शिक्षण-विधि की असफलता अवश्यम्भायी है। यही कारण है कि अभी तक वयस्कों के लिए कोई निश्चित विधि निर्धारित नहीं की जा सकी है। वस्त्रों के मन्त्रिण के समान वयस्कों के मन्त्रिण तैरी पटिया नहीं हैं, जिन पर शिक्षक स्वेच्छा से कुछ भी या चाहे जैसे लिख दे। हमोविण, किसी भी वयस्क को शिक्षा देने समय शिक्षक अपने को दुर्धर्म निषिद्ध में पाता है। डा० राय का यह कथन अक्षरशः सत्य है :—“वयस्क निरक्षर होते ही हैं, पर उसका मस्तिष्क विकसित होता है और उसकी रुचियों का निर्माण हो जाता है। अतः जब हम उसे शिक्षा प्रदान करते हैं, तब हम कोरी पटिया पर नहीं लिखते हैं।”

“An adult may be illiterate, but his mind is grown-up and his interests are already cultivated. We are not writing on a blank state, when we are dealing with an adult.”—Dr. V. K. R. V. Rao : *op. cit.*, p. 62.

समाधान—उपयुक्त शिक्षण-विधि : Suitable Method of Teaching  
हमारे देश के शिक्षा-समस्य पर्याप्त समय से बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण-विधि  
गोत्र करने में यथेष्ट रूप में मग्न है। उन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान का  
अध्ययन करके, बतियय शिक्षण-विधियों की खोज भी की है। हम इनमें में कुछ प्र  
विधियों का एक संक्षेप की विधि का शिक्षण परिचय दे रहे हैं; यथा :—

1. वर्ण-परिचय-विधि—इस विधि में बच्चों को पहले वर्णों का, उनके बाद  
शब्दों का और अन्त में वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है। हमारे प्राथमिक स्कूलों  
में यही विधि प्रचलित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की "मोशन ग्राफिक्स सीम" में  
इस विधि के आधार पर बच्चों के लिए "दीर्घाः प्रादमर" तैयार की है।

2. वाक्य-विधि—इस विधि में बच्चों को पहले वाक्यों का, उनके बाद  
शब्दों का और अन्त में अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है।

3. शब्द-वाक्य-विधि—यह शब्दों और वाक्यों की मिश्रित विधि है। इस  
विधि में बच्चों को पहले दो शब्दों का एक-मात्र ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद,  
उन शब्दों को विभिन्न क्रम में रखकर, उनको वाक्यों में परिवर्तित कराया जाता है।  
उदाहरणार्थ—हम "आ" और "मा" दो शब्दों से मग्न हैं। हम इन शब्दों का विभिन्न  
क्रमों में रखकर, अनेक प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, जैसे—मा मा। मा आ। आ  
मा आ। आ मा मा। मा मा आ। मा मा मा आ।

4. कहानी-विधि—इस विधि की खोज बर्न का थ्रेय—थ्री सगम मान  
अप्रवाण को प्राप्त है। इस विधि में प्रत्येक अक्षर, श्रवणपट पर निर्या जाता है और  
फिर उसके विषय में कोई कहानी सुनाई जाती है। इस प्रकार, कहानी द्वारा उन  
अक्षरों को बच्चों के मानस-पटल पर प्रविष्ट कर दिया जाता है।

5. सरल शब्द-विधि—यह विधि—थ्री पथिक न निर्याती है। हमने शीतो  
का प्रधान स्थान है। बच्चों द्वारा पहले इन शीतो का गाया जाता है और फिर  
उनको गाए जाने वाले शब्दों का चाटों की म्हायना ग ज्ञान प्रदान किया जाता है।  
उदाहरणार्थ—"बनम से निर्गमे, बनम मे पड़ेग। बनम मे बड़ेग, बनम ग ब्रिपेग।"

6. रायसम की विधि—थ्री ब्रिटिश राय रायसम न एक नया विधि की खोज  
की है। यह विधि 6 भागों और 2 परीक्षाओं में विभाजित है। थ्री रायसम न इस  
विधि का प्रयोग—हिमाचल प्रदेश के ग्राम-निवासियों और शिक्षकों के  
लिए किया है। इस विधि द्वारा उन्होंने बच्चों का 6 माह की अवधि में अक्षर-ज्ञान  
आरम्भ करके, गणित, भूगोल, इतिहास, मजदूर, स्वस्थ, देश-पता, पचासी रात्र  
दि में भरो भानि परिवर्तित कर दिया है। उनका दाव है कि जब कि प्रचलित  
विधि में एक बच्चा को शिक्षा देने में 1,500 रुपए व्यय होते हैं, उनकी विधि में  
व्यय केवल 6 या 7 रुपए हैं।

7. लॉचक की विधि—डा० फ्रैंक लॉचक (Dr. Frank Laubach) अमरीका का विख्यात मिशनरी और शिक्षा-विशारद था। उसने फ़िलिपाइन द्वीप-समूह के लानाव (Lanao) नामक प्रान्त में निवास करने वाली मोर जाति (Moros) के व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया, उसकी विश्व के सभी उच्च कोटि के शिक्षा-विशेषज्ञों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। उसकी पद्धति इस प्रकार थी। उसने आरम्भ में मोर जाति के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को चुनकर, उनको शिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया। वह प्रति दिन उन शब्दों की संख्या में वृद्धि करता रहता था। वह चारों की सहायता से वयस्कों को एक दिन में 17 अक्षरों का ज्ञान करा देता था। जिन वयस्कों को वह साक्षर बना देता था, उनको वह दूसरे वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए भेज देता था। इस प्रकार, उसने 5 वर्ष में लानाव प्रान्त के 70,000 व्यक्तियों को साक्षर बना दिया।<sup>1</sup>

उपर्युक्त सभी विधियाँ अच्छी हैं और वयस्कों को शिक्षा देने के लिए सभी का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु, हमारे विचार से इन विधियों में सर्वोत्तम डा० लॉचक की विधि है। हमें इसको इसलिए स्वागत नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि यह एक विदेशी की विधि है। डा० लॉचक ने 1935, 1937 और 1938 में भारत का भ्रमण कर हिन्दी, बंगाली, तामिल, तेलगू, मराठी और गुजराती भाषाओं के लिए अपनी विधि की उपादेयता निरूपित की। उसकी पद्धति का प्रयोग करके, पंजाब में मोघा के मिशनरियों को साक्षरता-प्रसार के कार्य में अद्भुत सफलता मिली। स्वयं लॉचक ने लानाव प्रान्त में वयस्कों को साक्षर बनाने का असाधारण कार्य किया। उसकी शिक्षण-विधि की सफलता के इतने सजीव प्रमाण हैं। अतः हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि भारत-सरकार—वयस्कों की शिक्षा के लिए इस विधि को प्रचलित कर दे, तो अल्प समय में ही भारत के प्रत्येक वयस्क को साक्षर बनाया जा सकता है।

4. समस्या—धन का अभाव : Dearth of Money—सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 54.80 करोड़ है।<sup>2</sup> उनमें से 37.67 करोड़ व्यक्ति निरक्षर हैं।<sup>3</sup> इस समय सरकार एक व्यक्ति को साक्षर बनाने में 1,500 रुपये व्यय कर रही है।<sup>4</sup> अब यदि हमारा लक्ष्य जाय, तो 37.67 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए अरबों रुपयों की आवश्यकता है।

भारत-सरकार ने "चौथी पंचवर्षीय योजना" (1969-1974) में समाज-

1. T. N. Siqueira : *Modern Indian Education*, p. 162.

2. *India*, 1974, p. 6

3. *India*, 1974, p. 51.

4. "दिनमान" साप्ताहिक, 11 July, 71, p. 44.

शिक्षा पर 64 करोड़ रुपए व्यय किए ।<sup>1</sup> "पाँचवीं योजना" में यह धनगति पट्टा 35 करोड़ रुपए कर दी गई है ।<sup>2</sup> स्पष्ट है कि ये धनगतिपट्टा भारत के मा-  
निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए अत्यन्त है । किन्तु, अधिक धन व्यय  
नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1971-72 में भारत की राष्ट्रीय आय 19,000  
करोड़ रुपए थी ।<sup>3</sup> अब सरकार का औचित्यपूर्ण तर्क है कि वह धनाभाव के कारण  
समाज-शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने के लिए पूर्णतया अशक्य है ऐसी स्थिति  
में भारत के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने की समस्या का समाधान करना  
असम्भव है ।

समाधान—धन का अभाव, एक बहाना . Dearth of Money, A Pre-  
tence—सरकार का यह तर्क प्रत्येक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है कि वह धनाभाव के कारण  
साक्षरता-प्रसार के लिए अधिक धन व्यय करने में असमर्थ है । किन्तु शिक्षा विभाग,  
डा० संयुक्त ने धनाभाव को बहाना-मात्र बताया है । वे इस बात को स्वीकार करते  
के लिए उद्यत नहीं हैं कि भारत—धनाभाव या निर्धनता के कारण निरक्षरता की  
समस्या का समाधान करने में असमर्थ है । अपने इस विचार को सुनिश्चित तथ्यों  
द्वारा पुष्ट करने हुए, डा० संयुक्त ने लिखा है :—

"क्या यह तर्क दिया जा सकता है कि हमारा निर्धन' देग इस पैमाने की  
शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने का शर्त नहीं कर सकता है ? वास्तव में केवल  
एक ही प्रकार की दरिद्रता होती है, जिसका कोई इलाक़ नहीं होता है, और वह  
होती है—'उत्पाद की दरिद्रता' । यदि हम सम्मोचनापूर्वक प्रयत्न करें तो अन्य सभी  
प्रकार की दरिद्रताएँ दूर की जा सकती हैं । यह एक बहुत घिरी मिटी बात है, जिस  
भी मैं उसे दोहराना चाहूँगा कि इसी निर्धन देग ने एक तम पुष्ट व जिम जिम छेदन  
में उगता कोई हाथ नहीं था, बग़ावत स्पष्ट शर्तें कर देगा व । इन परिस्थितियों को  
देखते हुए इस बात का क्या कारण हो सकता है कि शिक्षा व श्रम में भी, जो शक्ति  
और मानवीय गुणों का मूल आधार है, इनका ही बड़ा प्रयोग न किया जा सके ?  
मेरा विश्वास है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बड़ी-बड़ी समस्याओं का सुनिश्चित समाधान  
हिटलर से नहीं देगना चाहिए । हमारे बजट में इन बग़ावत को सुझाव है और  
इनके 'बड़े' पैमाने पर धरने श्री शिक्षा पर ही इनका शर्त आ जायगा— हमारे  
समय-काल अशक्य होने के कारण इस सुझाव का स्वीकार नहीं किया जा सकता  
है ।' मेरी राय में समस्या पर विचार करने का मही नहीं है यह नहीं है कि हम "व  
शिक्षा-व्यवस्था का, या एक अच्छी स्वास्थ्य नीति बनाने का शर्त दक्ष नहीं

चौथी पंचवर्षीय योजना (शास्त्रिक रूपरेखा) पृ. 231  
Draft Fifth Five-Year Plan Vol II पृ. 21  
India, 1974, पृ. 132.  
ड० जी० संयुक्त शिक्षा की सुनिश्चिता पृ. 190

कर सकते; बल्कि हमें इस तरह सोचना चाहिए कि इन 'बीजों' के बिना क्या हमारा काम चल सकता है ?' यदि इस बात को स्वीकार किया जाता है कि कोई भी देश बहुत बड़ी हद तक अस्वस्थ और ज़ाहिल तथा सांस्कृतिक दृष्टि से दरिद्र नहीं रह सकता है, तो इसके लिए धन जुटाना—सरकार, वित्त-विभाग और राष्ट्रीय अर्थतन्त्र की योजना बनाने वालों की जिम्मेदारी है ।"

**5. समस्या—शिक्षकों का अभाव : Dearth of Teachers**—वयस्क-विद्यालयों के लिए शिक्षकों के अभाव ने समाज-शिक्षा के विस्तार में एक दुर्लभ समस्या उत्पन्न कर दी है । इस अभाव के दो स्वरूप हैं । पहला स्वरूप यह है कि वयस्कों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है । सामान्य रूप से, उनको शिक्षा देने का कार्य—प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सौंपा जाता है । ये अध्यापक—वयस्कों के मनोविज्ञान से पूर्णतया अपरिचित होते हैं । अतः उनमें वयस्कों के लिए उपयुक्त शिक्षण-सामग्री एवं शिक्षण-विधियों का चयन करने की क्षमता नहीं होती है । यही कारण है कि ये प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्रों का दक्षतापूर्वक संचालन करने में असफल होते हैं ।

दूसरा स्वरूप यह है कि प्रौढ़-शालाओं के लिए शिक्षकों की वांछित संख्या उपलब्ध नहीं है । इसके दो मुख्य कारण हैं । पहला, वयस्क-विद्यालयों के शिक्षकों को इतना अल्प वेतन मिलता है कि वे अपनी जीवन-सम्बन्धी आवश्यकताओं को जुटाने में भी असमर्थता का अनुभव करते हैं । दूसरा, अधिकांश प्रौढ़-विद्यालय—ग्रामों में स्थित हैं । ग्रामों में शिक्षकों को दैनिक प्रयोग की वस्तुओं, निवास-स्थानों, मनोरंजन की सुविधाओं आदि का स्थायी अभाव रहता है । अतः ग्रामों के कष्टपूर्ण जीवन की कल्पना करके ही वे व्यग्र हो जाते हैं ।

प्रौढ़-शालाओं के लिए अध्यापिकाओं का और भी अधिक अभाव है । शिक्षित होने के कारण, वे अपने परिवारों से पृथक् दूर के गाँवों के गैरारु और भैंसे-कुत्ते यातावरण में अल्प धनराशि का अर्जन करने के लिए जाना अपनी मान-हानि समझती हैं । साथ ही, उनको उन ग्रामीण स्त्रियों से स्वाभाविक घृणा होती है, जिनकी शिक्षा का भार उनको दिया जाता है, क्योंकि वे उनको बंध और परम्परा—दोनों दृष्टियों से अजिष्ट एवं असम्यक् समझती हैं ।

**समाधान — शिक्षकों की पूर्ति : Supply of Teachers**—प्रौढ़-विद्यालयों के लिए आवश्यक योग्यताओं में युक्त शिक्षकों की वांछित संख्या की उपलब्धि के लिए दो उपायों को काम में लाया जा सकता है । पहला, वयस्कों को शिक्षा देने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण की सरकार द्वारा सीधे ही समुचित व्यवस्था की जाय । उनकी प्रशिक्षण-तालिम में प्रौढ़-मनोविज्ञान एवं प्रौढ़-शिक्षा की नवीनतम विधियों से अवगत कराया जाय । साथ ही, उनको दृष्टि, श्रवणोपकरण, अनुपालन, कठोर उद्योगों, स्वास्थ्य-विज्ञान, प्रारम्भिक निरक्षरता, कलाई और चुनौती में इतना प्रशिक्षित कर दिया जाय

कि ये ग्रामीण बच्चों को साधुप्रद ज्ञान प्रदान करके, उनके उत्थार में वास्तविक योग दे सकें। दूसरा, प्रौढ़-शालाओं के शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से पर्याप्त अधिक वेतन दिया जाय। जहाँ तक अध्यापिकाओं का प्रश्न है, उनके लिए विशेष वेतन-क्रम निर्धारित किए जायें। इसके अनतिरिक्त, उनको ग्रामी में आवास की विशेष सुविधाएँ प्रदान की जायें।

इन दोनों उपायों के विषय में किसी प्रकार की मन-विभिन्नता नहीं हो सकती है। किन्तु, प्रौढ़-विद्यालयों के लिए वाछित मर्यादा में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में पर्याप्त समय लगेगा। उस समय तक के लिए बचस्व शिक्षा के कार्य को स्थगित करना, बच्चों के लिए अमानवीय एवं देश की प्रगति के लिए अनर्वादी होगा। अतः इस अन्तःकालीन समय में "कोठारी कमिशन" द्वारा अर्चित किए जाने वाले इन सुझावों को व्यावहारिक रूप प्रदान करना, दोनों के लिए हितप्रद सिद्ध होगा<sup>1</sup> :—  
"देश के समस्त उपलब्ध शिक्षित पुरुषों एवं स्त्रियों के दल बना दिए जायें और व्यापक एवं सुनियोजित साक्षरता-अभियान में उनका उपयोग किया जाय। सब स्तरों की शिक्षा-संस्थाओं के छात्रों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना, 'अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा-कार्यक्रम' का अमित्र अंग बना दिया जाय।"

6. समस्या—उपयुक्त साहित्य का अभाव : Dearth of Suitable Literature—बच्चों के लिए उपयुक्त साहित्य का अभाव होने के कारण ममात्र शिक्षा का कार्य अत्यन्त मन्द गति से चल रहा है। उनके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य-ग्रन्थों का उपयोग किया जाता है। यह ग्रन्थें उनको साक्षर अवश्य बना सकती हैं, पर ममात्र-शिक्षा के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में रक्षमात्र भी सहायता नहीं दे सकती है। उनके लिए ऐसी पाठ्य-ग्रन्थों की आवश्यकता है, जो उनका बौद्धिक विकास करने के साथ-साथ उनमें नागरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का भी विकास करे। इसके अनतिरिक्त, यह भी आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले नवमाधरों के लिए उपयुक्त साहित्य हो। अन्यथा, कुछ समय के उपरान्त उनका पुनः निरक्षर हो जाना स्वाभाविक है।

बच्चों की साक्षरता एवं उनके साहित्य के विषय में डा० सैमरन के अग्रजित शब्द ध्यान देने के योग्य हैं<sup>2</sup> :—"यदि हमारी ममस्त जनता पढ़ना-लिखना और जोड़-बाँटो तथा गुणा-भाग के सवाल मही-मही सगाना मीग भी से, तो उनमें उमें क्या कायदा होगा? हमने अम्बारों में तथा मार्ब्रनिस मव पर लपकात्री करने वाली को उन्हें बेबडूफ बनाने का उतना ही ज्यादा ममाना और मिल जायगा। हमने न तो उनके मानदण्ड ऊँचे होने, न उमकी रुचियों में सुधार हागा और उनका

1. Kothari Commission Report, p. 427.

2. डे० जी० सैमरन : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 211.



जीवन ही समृद्ध बनेगा। उनकी सहानुभूति या समझ या सामाजिक चेतना में कोई गहराई नहीं पैदा होगी। इसलिए, हमें इस समस्या को बिल्कुल ही दूसरे तथा अधिक व्यापक दृष्टिकोण में देखना चाहिए। हमें जनता में चीजों की परस्पर की क्षमता, आलोचनात्मक शक्ति और सामाजिक भावना का विकास करने में योग देना चाहिए, ताकि वे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट तथा निकृष्ट के बीच, ज्ञान के क्षेत्र में सच और झूठ के बीच और आचरण के क्षेत्र में भले और बुरे के बीच अन्तर कर सकें।”

उक्त प्रकार के साहित्य के अभाव ने समाज-शिक्षा के कार्य में भारी बाधा उत्पन्न कर दी है। डा० सैयदने के शब्दों में :—“बयस्कों की सचियों के अनुकूल पाठ्य-सामग्री के अभाव के कारण समाज-शिक्षा के कार्य में भारी बाधा उत्पन्न हो गई है।”

“The work of social education is greatly handicapped by the paucity of suitable reading material graded to appeal to the adults”—K. G. Saiyidain : *Proceedings of the 19th Meeting of the Central Advisory Board of Education in India, Appendix C (d)*.

**समाधान—उपयुक्त साहित्य का उत्पादन : Production of Suitable Literature**—समाज-शिक्षा की मन्द गति में तीव्रता उत्पन्न करने के लिए, उपयुक्त बयस्क-साहित्य का उत्पादन किया जाना एक आवश्यक जगत है। यह साहित्य ऐसा होना चाहिए, जो बयस्कों को अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के प्रति जागरूक करे, उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के ज्ञान से सम्पन्न करे, उनकी व्यावसायिक क्षमता में अभिवृद्धि करे, एवं अन्ततोगत्वा उनको भारतीय गणतंत्र का आदर्श नागरिक बनाए।

बयस्कों की आयु, लिंग आदि में भेद होने के कारण, नवके लिए समान साहित्य का निर्माण किया जाना अविवेकपूर्ण कार्य होगा। अतः उत्तर प्रदेश की “नवसाक्षरोपयोगी साहित्य-निर्माण-मोष्टी की आज्ञा” का नुस्खा है कि साहित्य का निर्माण करते समय अव्यक्ति 5 बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—(i) आयु-भेद, (ii) लिंग-भेद, (iii) क्षेत्र-भेद, (iv) मांग एवं आवश्यकता, और (v) समाज-शिक्षा के उद्देश्य।

बयस्कों के लिए उपयुक्त साहित्य से सम्बन्धित अन्तिम बात यह है कि उसमें किन-किन वस्तुओं को स्थान दिया जाना चाहिए। इन वस्तुओं में ऐसे चारों, निशों, पुस्तकों और समाचार-पत्रों को स्थान प्राप्त होना चाहिए, जो बयस्कों की विभिन्न रुचियों एवं जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर सकें। उनके अनिश्चित, बयस्कों के लिए निम्नपूर्ण मासिक एवं मासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जाना चाहिए। इनमें कृषि, स्वास्थ्य, गैल-बूढ़, देन-विदेन के समाचारों एवं ग्रामों में सम्बन्धित प्रमुख समस्याओं को स्थान दिया जाना चाहिए।<sup>1</sup>

विद्येन कुछ वर्षों से भारत के सभी राज्य—वयस्को के लिए उपयुक्त साहित्य का उत्पादन करने में संलग्न हैं। इस दिशा में “साक्षरता-निकेतन”, लखनऊ; मेसूर राज्य की “प्रौढ़-शिक्षा-परिषद्” और ‘राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-परिषद्’ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सरकार ने निश्चय किया है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में वयस्को के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में कम मूल्य की पुस्तकों का भारी मत्पा में प्रकाशन किया जायगा।<sup>1</sup>

7. समस्या—शिक्षा के साधनों का अभाव : Dearth of Agencies of Education—“समाज-शिक्षा की अध्यापक-निर्देशन-पुस्तिका” में समाज-शिक्षा के साधनों की व्याख्या इस प्रकार की गई है :—“समाज-शिक्षा के साधनों में तात्पर्य है—वे समूह या संस्थाएँ, जो समाज शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क रखती हैं, उनकी ज्ञान प्रदान करती हैं, एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।”

“By agencies of social education is meant the bodies or institutions which ‘deliver the goods’ and which contact the ‘consumers’ of social education and satisfy their needs”

—*Teachers’ Hand-Book of Social Education*, p. 66.

समाज-शिक्षा के उपयुक्त साधनों का चयन करना सरल कार्य नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि इनका चयन—वयस्कों की आयु, निग, रुचियों, आवश्यकताओं आदिके अनुकूल नहीं किया जाता है, तो इनका प्रयोग पूर्णतया निष्फल हो जाता है। फलस्वरूप, वयस्को के ज्ञान-कोष में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में समाज-शिक्षा के कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख एक विचित्र समस्या आ खड़ी होती है।

समाधान—शिक्षा के उपयुक्त साधन Suitable Agencies of Education—प्रौढ़-मनोविज्ञान में दश व्यक्तियों ने अथक परिश्रम करके उक्त समस्या का समाधान किया है। उन्होंने ऐसे अनेक साधनों के सुझाव दिए हैं, जो वयस्को को ज्ञान से सम्पन्न करने में उपयोगी सिद्ध हो सकें हैं। इस प्रकार के कुछ सुझाव सन् 1958 में उत्तर प्रदेश की ‘नवसाक्षरोपयोगी साहित्य-निर्माण-गोष्ठी’ द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जो इस प्रकार हैं—(i) वाचन, (ii) दिनोद-वार्त्ता, (iii) कथा-कहानी, (iv) पत्र एवं दैनिकी, (v) वर्णन-प्रधान गद्य, (vi) नाटक, प्रहसन एवं सम्वाद, और (vii) काव्य, गीतगीत एवं पहेलियाँ।

वयस्कों के मानसिक, धारितिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए इन सुझावों की उपादेयता को स्वीकार किया गया है। किन्तु, साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि इन सुझावों को मूर्त रूप देकर भी, वयस्कों का सर्वांगीण विकास किया जाना अगम्भव है। अतः प्रौढ़-मनोविज्ञान-विशेषज्ञों ने गहन

अध्ययन के पश्चात् शिक्षा के अग्रगामी नावनों को पर्याप्त प्रभावोत्साहक बताया है :—(1) चार्टर, पोस्टर, प्रदर्शनी, मंत्रहालय, वाचनालय एवं पुस्तकालय । (2) कथा-कहानी, पत्र-पत्रिकाएँ, साहित्यिक एवं वादविवाद गोष्ठियाँ । (3) श्रव्य-दृश्य साधन :—रेडियो, सिनेमा, ग्रामोफोन, टेलीविजन एवं फिल्मस्ट्रिप । (4) ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :—मेले, नाटक, नृत्य, संगीत, धार्मिक एवं सामाजिक नगारोह ।

8. समस्या—अनवरत शिक्षा का अभाव : Absence of Continuation Education—हमारे देश में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए पर्याप्त उत्साह से कार्य किया गया है । सभी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के भाल से इस कलंक-कालिमा को मिटाने की नवत चेष्टाएँ की गई हैं । केन्द्रीय एवं राज्य-स्तरों पर साक्षरता-प्रसार के लिए आन्दोलनों का संगठन किया गया है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है । भारत-सरकार के अनुसार<sup>1</sup> :—“वयस्कों में निरक्षरता समाप्त करने के लिए शिक्षा-मंत्रालय एक योजना चला रहा है । उसका मुख्य उद्देश्य—उन्हें ऐसी शिक्षा देना है, जिससे वे अपना जीवन अधिक उत्तम बना सकें और उनमें परम्परागत के स्थान पर प्रगतिशील समाज बनाने की इच्छा उत्पन्न हो ।”

किन्तु, सरकार में जितना उत्साह—निरक्षरता-उन्मूलन के लिए है, उसका दर्शाव भी साक्षरता को कायम रखने के लिए नहीं है । वयस्कों को साक्षर बनाने के उपरान्त साक्षरता-आन्दोलनों की इतिश्री हो जाती है । ऐसा होना स्वाभाविक प्रतीत होता है, क्योंकि वयस्कों को साक्षर बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाती है । किन्तु, सरकार द्वारा हम सामान्य अनुभव को विस्मृत कर दिया जाता है कि साक्षरता-आन्दोलनों के समाप्त होने ही वयस्क—निरक्षरता की ओर बढ़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और कुछ ही समय के पश्चात् अपनी पूर्वकालीन स्थिति में पहुँच जाते हैं । हम सामान्य अनुभव के आधार पर “कोठारी कमोशन” ने वयस्वकों को पतित किया है :—“यदि सीखने की प्रक्रिया को किसी रूप में जीवित नहीं रखा जायगा, तो साक्षरता-आन्दोलन का उद्देश्य नष्ट हो जायगा ।”

“The very purpose of the literacy campaign will be defeated, if it does not continue in some form to keep the process of learning alive.”—Kothari Commission Report, pp. 430-431.

समाधान—अनवरत शिक्षा की व्यवस्था : Provision for Continuation Education—शिक्षा की प्रक्रिया का कभी अन्त नहीं होता है । प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, अवकाश के सुव्यवहार और तिनकी ही अन्य

घातों के बारे में कुछ-न-कुछ सीखना रहता है। यदि वह सीखना बन्द कर देता है, तो उसके व्यावसायिक एवं अन्य कार्यों में सम्बन्धित उसकी कुशलता का हानि होने लगता है। फलस्वरूप, वह स्वरित गति में परिवर्तित होने वाले ससार से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है और असंतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगता है। अतः औपचारिक शिक्षा या साक्षरता की प्राप्ति के पश्चात् भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए निरन्तर शिक्षा की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, "कोठारी कमिशन" ने लिखा है :— "तीव्र परिवर्तन और बढ़ते हुए ज्ञान की दशाओं में पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को निरन्तर सीखते रहना चाहिए।"

● "In conditions of rapid change and advancing knowledge, man must continue to learn in order to live a full life."—*Kothari Commission Report*, p 431

अनुभव सभी का शिक्षक है। सरकार ने भी अनुभव में यह शिक्षा प्राप्त करके कि साक्षरता-प्रसार के लिए प्रयोग की जाने वाली जन-शक्ति एवं धनराशि का अपव्यय हो रहा है, अनवरत शिक्षा के प्रति ध्यान देना आरम्भ कर दिया है। शिक्षा-मन्त्रालय ने विभिन्न व्यवसायों में लगन व्यक्तियों के लिए कुछ विशिष्ट विषयों में पत्राचार-पाठ्यक्रमों का संचालन आरम्भ कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी इन पाठ्यक्रमों का मूलपाठ कर दिया है।

पत्राचार-पाठ्यक्रमों को अनवरत शिक्षा का एक चरण माना जाता है। अन्य चरणों की ओर "कोठारी कमिशन" के संकेत इस प्रकार हैं<sup>1</sup> :—

1. सब प्रकार की शिक्षा-मस्याओं को अपने शिक्षण-समय से पढ़ते या याद में उन व्यक्तियों को ऐसे पाठ्यविषयों की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनकी शिक्षा वे प्राप्त करना चाहते हैं।
2. उक्त शिक्षा-मस्याओं को उक्त समय में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिनमें वयस्कों को अपनी समस्याओं का समाधान करने और अधिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिले।
3. साक्षर वयस्कों को स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों के समान डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने का अवसर देने के लिए अल्पशालीन शिक्षा की प्रणाली प्रचलित की जानी चाहिए।
4. अनवरत शिक्षा प्रदान करने के लिए "केन्द्रीय वयस्क-महिता समाज-कल्याण-परिषद्" और मैमूर राज्य की विद्यार्थी के समान विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए।

1. *Kothari Commission Report*, p. 666.

8. नियोजन का अभाव : Absence of Planning—भारत-सरकार अनेक वर्षों से साक्षरता-प्रसार के कार्य में यथेष्ट रूप से सक्रिय है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, उसने अनेक कार्यक्रम प्रियान्वित किए हैं। फिर भी, उसे सफलता के दर्शन नहीं हुए हैं। इस प्रसंग में "कोठारी कमिशन" ने लिखा है<sup>1</sup> :—"साक्षरता-प्रसार के कार्यक्रम अत्यधिक शक्ति एवं उत्साह से आरम्भ किए गए, पर शनैः-शनैः उनमें शिथिलता आती चली गई और कुछ वर्षों के पश्चात् वे पूर्णतया समाप्त हो गए।"

उक्त कार्यक्रमों की शिथिलता एवं नगण्यता का कारण यह था कि उनमें नियोजन का पूर्ण अभाव था। इसकी पुष्टि में "कोठारी कमिशन" ने 4 तथ्यों का उल्लेख किया है; यथा<sup>2</sup> :—

1. साक्षरता-प्रसार के कार्यक्रमों के क्षेत्र इतने अधिक सीमित थे कि वे भविष्य में अधिक कार्य के लिए उत्साह उत्पन्न न कर सके।
2. उक्त कार्यक्रमों को व्यक्तियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का गतकंता से अध्ययन किए बिना, बड़ी जल्दबाजी में आरम्भ किया गया।
3. उक्त कार्यक्रमों को व्यक्त-साक्षरता में जनता की रुचि जाग्रत किए बिना और अनवरत शिक्षा की व्यवस्था किए बिना आरम्भ किया गया।
4. उक्त कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए जिन विभागों, निकायों, संस्थाओं आदि का साधनों के रूप में प्रयोग किया गया उनके कार्यों में किसी प्रकार का समन्वय एवं सामंजस्य नहीं था। अतः उन्होंने पारस्परिक सहयोग से कार्य न करके अलग-अलग कार्य किया।

"कोठारी कमिशन" का मत है कि नियोजन की अनुपस्थिति में सरकार द्वारा प्रियान्वित किए जाने वाले निरक्षरता-उन्मूलन के आन्दोलनों का असफल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

समाधान --नियोजन की आवश्यकता : Need of Planning—साक्षरता-प्रसार के प्रदान में सफलता प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित एवं सुसंगठित नियोजन पक्षी कर्त है। नियोजन किस प्रकार दिया जाना चाहिए, अर्थात् साक्षरता-प्रसार की योजना किस प्रकार निमित्त एवं प्रियान्वित की जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में "कोठारी कमिशन" ने कुछ अत्यन्त विवेकपूर्ण सुझाव दिए हैं; यथा<sup>3</sup> :—

1. योजना का निर्माण भली-भाँति सोच-विचार कर किया जाना चाहिए और उसके अंतर्गत सभी कार्यक्रमों को संगठित रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

1. Kothari Commission Report, pp. 423-424.

2. Kothari Commission Report, p. 424.

3. Kothari Commission Report, p. 425.



की जाड़माइशी परियोजनाएँ चलाना है, जो समूचे देश में समाज-शिक्षा का काम करती हों।"

**समाधान—दो सुझाव : Two Suggestions**—उत्तरदायित्व-समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? इस विषय में दो सुझाव उल्लेखनीय हैं—एक, डा० सैम्युएल का और दूसरा, "कोठारी कमीशन" का।

डा० सैम्युएल ने संयुक्त उत्तरदायित्व का सुझाव देते हुए लिखा :—“यह एक ऐसी जिम्मेदारी है, जिसे न शिक्षा-विभाग अकेले पूरा कर सकता है, और न पूरी भागन-जवाबदारी हो। इसके लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी—सभी संस्थाओं और सहभागिता तथा सामाजिक वेत्ताना रखने वाले इन सभी व्यक्तियों के बीच जो भावना का कल्याण चाहते हैं, प्रतिष्ठित तथा दायित्व सहयोग आवश्यक है। अभी हमारे सामने इतना बहुत-सा और इतना विविध प्रकार का काम करने का पड़ा है कि जो भी इस सेवा-रथ में शामिल होना चाहे, उसके लिए उसमें स्थान है—विद्यार्थी, अध्यापक, घर बैठकर पढ़ने वाले लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, वैद्यक, श्रमिक, दस्ताकार, छात्र, महिला—सभी के लिए।”

“कोठारी कमीशन” ने समाज-शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय पर रखा और यह सुझाव दिया कि शिक्षा-मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-परिषद् का निर्माण किया जाय और उसे “समाज-शिक्षा” में सम्मन्वित सब कार्य सौंप दिया जाय। “कोठारी कमीशन” के शब्दों में :—“एक राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-परिषद् का निर्माण किया जाना चाहिए और उसमें समाज-शिक्षा में सम्मन्वित सब संस्थाओं एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि होने चाहिए।”

डा० सैम्युएल के सुझाव की तुलना में “कोठारी कमीशन” का सुझाव अधिक विवेकपूर्ण एवं व्यावहारिक था। अतः सरकार ने कमीशन के सुझाव को स्वीकार करने, मन् 1969 में “राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-परिषद्” (National Board of Adult Education) की स्थापना की। (उन्हा दसरे इसी अध्याय में “बीबी पंचवर्षीय योजना” के प्रसंग में किया जा चुका है।) इस प्रकार, उत्तरदायित्व की समस्या का समाधान इस तरह किया गया है। प्रौढ़-शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व—केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय पर है। यह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह “राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-परिषद्” के द्वारा करता है। “परिषद्” में केन्द्रीय प्रशासन में सम्मन्वित जम्मेदार सभी संस्थाओं तथा विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार, प्रौढ़-शिक्षा का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण प्रशासन पर है। इस प्रशासन-व्यवस्था की अधिक स्पष्टता की

1. डे० जी० सैम्युएल : शिक्षा की पुनर्रचना, p. 214.

2. Kothari Commission Report, p. 667.

“शिक्षा-आयोग” के अर्थांकित शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है :—“यह सत्य है कि प्रौढ-शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षा-मन्त्रालय का कार्य है, पर ऐसी विधियों को अपनाना आवश्यक है, जिनसे प्रशासन के सभी अंग इस कार्य में व्यावहारिक योग्य हों।”

“It is true that adult education is mainly the function of the Ministry of Education, but it is necessary to adopt procedures which will ensure practical involvement of the entire administrative machinery.”—*Education Commission Report*, p. 439.

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. What are the aims and ideals of Social Education in India ? What efforts are being made to achieve them ?

भारत में सामाजिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य तथा आदर्श क्या हैं ? उनकी प्राप्ति हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

2. Throw light on the need of Social Education in modern India and mention the reasons of its unsatisfactory progress in the country.

वर्तमान भारत में समाज-शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए और देश में इसकी असंतोषजनक प्रगति के कारण बताइए।

3. What is meant by “Adult Education” and “Social Education” ? What efforts have been made by the Government in this direction ? Give your suggestions to make these efforts more effective and successful

“प्रौढ-शिक्षा” और “सामाजिक शिक्षा” में क्या तात्पर्य है ? इन दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं ? इन प्रयत्नों को अधिक प्रभावकारी और मजबूत बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

4. Discuss the importance of social education in a democracy How is the expenditure on social education justified in India when the country is facing the problem of free and compulsory education ?

जनतन्त्र में समाज-शिक्षा के महत्त्व का विवेचन कीजिए। जबकि देश के सम्पूर्ण निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की समस्या मंडी है, तब भारत में समाज शिक्षा पर दिया गया व्यय किस प्रकार न्यायोचित है ?



की आवश्यकता परियोजनाएँ बनाना है, जो समूचे देश में समाज-विद्या के विकास के लिए उपयोगी हों।”

समाधान—दो सुझाव : Two Suggestions — उत्तरदायित्व-सम्बन्धी समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? इस विषय में दो सुझाव उल्लेखनीय हैं—एक, डा० सैयदैन का और दूसरा, “कोठारी कमीशन” का।

डा० सैयदैन ने संयुक्त उत्तरदायित्व का सुझाव देते हुए लिखा<sup>1</sup> :—“यह एक ऐसी जिम्मेदारी है, जिसे न शिक्षा-विभाग अकेले पूरा कर सकता है, और न पूरी ज़ातमान-व्यवस्था ही। इसके लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी—सभी संस्थाओं और नृभावना तथा सामाजिक चेतना रखने वाले उन सभी व्यक्तियों के बीच, जो भारत का कल्याण चाहते हैं, घनिष्ठतम तथा हार्दिक सहयोग आवश्यक है। अभी हमारे सामने इतना बहुत-सा और इतना विविध प्रकार का काम करने को पड़ा है कि जो भी इस सेवा-कार्य में शामिल होना चाहे, उसके लिए उसमें स्थान है—विद्यार्थी, अध्यापक, घर बैठकर रहने वाले लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक, धर्मिक, दस्तकार, टायटर, बकील—सभी के लिए।”

“कोठारी कमीशन” ने समाज-विद्या का पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय पर रखा और यह सुझाव दिया कि शिक्षा-मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय प्रौढ़-विद्या-परिषद् का निर्माण किया जाय और उसे “समाज-विद्या” से सम्बन्धित सब कार्य सौंप दिया जाय। “कोठारी कमीशन” के जर्नल में<sup>2</sup> :—“एक राष्ट्रीय प्रौढ़-विद्या परिषद् का निर्माण किया जाना चाहिए और इसमें समाज-विद्या से सम्बन्धित सब मंत्रालयों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि होने चाहिए।”

डा० सैयदैन के सुझाव की मुक्तता में “कोठारी कमीशन” का सुझाव अधिक विवेकपूर्ण एवं व्यावहारिक था। अतः सरकार ने कमीशन के सुझाव को स्वीकार करके, सन् 1969 में “राष्ट्रीय प्रौढ़-विद्या-परिषद्” (National Board of Adult Education) की स्थापना की। (उसका वर्णन इसी अध्याय में “चौदो पंचवर्षीय योजना” के प्रसंग में किया जा चुका है।) इस प्रकार, उत्तरदायित्व की समस्या का समाधान इस तरह किया गया है। प्रौढ़-विद्या का मुख्य उत्तरदायित्व—केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय पर है। यह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह “राष्ट्रीय प्रौढ़-विद्या-परिषद्” के द्वारा करता है। “परिषद्” में केन्द्रीय प्रशासन से सम्बन्धित लगभग सभी मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार, प्रौढ़-विद्या का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण प्रशासन पर है। इस प्रशासन-व्यवस्था की अधिक स्पष्टता की

1. फो० जी० सैयदैन : विद्या की पुनर्वचना, p. 214.

2. Kothari Commission Report, p. 667.

“शिक्षा-आयोग” के अप्रारित गजनों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है :—“यह सत्य है कि ग्रीड-शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षा-मंत्रालय का कार्य है, पर ऐसी श्रितियों को अपनाना आवश्यक है, जिनसे प्रशासन के सभी अंग इस कार्य में व्यावहारिक योग हैं।”

“It is true that adult education is mainly the function of the Ministry of Education, but it is necessary to adopt procedures which will ensure practical involvement of the entire administrative machinery.”—*Education Commission Report*, p. 439.

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. What are the aims and ideals of Social Education in India ? What efforts are being made to achieve them ?

भारत में सामाजिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य तथा आदर्श क्या हैं ? उनकी प्राप्ति हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

2. Throw light on the need of Social Education in modern India and mention the reasons of its unsatisfactory progress in the country.

वर्तमान भारत में समाज-शिक्षा की आवश्यकता पर प्रमाण ढालिए और देश में इसकी असतोषजनक प्रगति के कारण बताइए।

3. What is meant by “Adult Education” and “Social Education” ? What efforts have been made by the Government in this direction ? Give your suggestions to make these efforts more effective and successful

“ग्रीड-शिक्षा” और “सामाजिक शिक्षा” में क्या तात्पर्य है ? इन दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं ? इन प्रयत्नों को अधिक प्रभावकारी और गहन बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

4. Discuss the importance of social education in a democracy. How is the expenditure on social education justified in India when the country is facing the problem of free and compulsory education ?

जनतन्त्र में समाज-शिक्षा के महत्व का विवेचन कीजिए। जबकि देश के सम्पूर्ण नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की समस्या गंभीर है, तब भारत में समाज-शिक्षा पर दिया गया व्यय किस प्रकार न्यायोचित है ?

का अनेक भागों में विभाजन कर दिया है। इन भागों ने सम्बन्धित कार्यों को प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यक्ति कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। अतः इस शिक्षा की उचित व्यवस्था की माँग की जा रही है।

उक्त दोनों कारणों के फलस्वरूप प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की माँग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः इस शिक्षा की व्यवस्था न केवल पृथक् शिक्षा-संस्थाओं में की जा रही है, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भी प्राविधिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान प्रदान किया जा रहा है। रायट्ट सूचि के शब्दों में :—“स्कूलों और कॉलेजों में अधिक ही अधिक नवीन विषयों को समाविष्ट किया जा रहा है और प्राचीन मानवशास्त्रों तथा नवीन वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक विषयों में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है।”

“More and more new subjects are forced into schools and colleges; and reconciliation is being found between the older humanities and the new scientific and vocational interests.”—Robert Ulich : *op cit*, p. 315

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के इस सामान्य परिणाम के पश्चात् अब हम इसके विस्तृत अध्ययन पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

### प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य

#### Meaning & Aims of Technical & Vocational Education

अर्थ—प्राविधिक शिक्षा—व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ है। व्यावसायिक शिक्षा—व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय में सम्बन्धित प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, ताकि वह उस व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। अतः इस व्यावसायिक शिक्षा के अर्थ को “सामाजिक विज्ञानों के विश्वकोष” के अनुसार, इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :—“ध्यातक रूप में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत उस मध्य प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिये प्रशिक्षण प्राप्त होता है।”

उद्देश्य—“यूनेस्को” (UNESCO) के द्वााराये अधिवेशन में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के सामंजस्यित उद्देश्य निर्धारित किए गए :—

1. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के समस्त कार्यक्रमों में सामान्य, वैज्ञानिक एवं विविध विषयों में समुचित संतुलन होना चाहिए।
2. इस शिक्षा के समस्त कार्यक्रमों में नवीन विज्ञानों के विकास की प्रवृत्ति के अनुसर होने चाहिए।

3. इस शिक्षा के कुछ कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, जो शारीरिक या मानसिक दृष्टि से दोषपूर्ण व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हों, ताकि वे समाज एवं उनके व्यवसायों में समायोजित हो जायें।
4. इस शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शारीरिक कार्य के महत्त्व की भावना होनी चाहिए और उत्पादन की विधियों में इस महत्त्व की स्वीकार किया जाना चाहिए।
5. इस शिक्षा का लक्ष्य केवल आधारभूत कौशल का विराम करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आधारभूत वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना भी होना चाहिए।
6. इस शिक्षा का मगटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपनी शिक्षा को उम्र समय तक जारी रख सके, जब तक उसकी बुद्धिमत्ताओं का पूर्णतम सम्भव विराम न हो जाय।

### प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता व महत्त्व Need & Importance of Technical & Vocational Education

हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि आधुनिक शिक्षा में परिलक्षित होने वाला एक मुख्य परिवर्तन यह है कि प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ही अधिक बल दिया जा रहा है। इसका आधारभूत कारण यह है कि इस शिक्षा के महत्त्व एवं आवश्यकता को सब देशों में एक स्वर में स्वीकार किया जा रहा है। यही हमारा प्रयोजन इस तथ्य का स्पष्टीकरण करना है।

भारतीय शिक्षा-विचारक प्रो० हमामुं बखोर ने अपने एक लेख में हमारे के कुछ प्रमुख देशों के उदाहरण देकर प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व एवं आवश्यकता को प्रमाणित किया है। हम उक्त लेख में लिखित उनके विचारों को गार रूप में अक्षरबद्ध कर रहे हैं, यथा—प्रो० बखोर का मत है कि किसी देश अपना राष्ट्र की समुन्नति एवं सुदृढ़ता का आधार—विज्ञान एवं प्राविधिक विषयों की शिक्षा है। यदि किसी देश में इस शिक्षा की मजदूती एवं समुचित व्यवस्था है और यदि यह शिक्षा—प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, तो उक्त देश की प्रगति भी अवश्यभावी है। संयुक्त राज्य अमेरीका, सोवियत रूस, जर्मनी और जापान इसके मजबूत उदाहरण हैं। आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरीका एक निरक्षर हुआ और अविश्वसनीय देश था। परन्तु, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का उत्कृष्ट आयोजन एवं उत्तमोत्तर उत्पान करने के कारण आज वह हमारे का सबसे धनी देश है और अनेक देश उसके ऋण-भार में दबे हुए हैं। सन् 1918 में उस रूस में जारशाही का अन्त

1. "Need of Scientific & Technical Education"—Article by Hamayun Kabir, in *The Leader* : Republic Day Supplement, 1956

निकाल कर, गणसन्ध को प्रतिष्ठित किया गया, तब उसका स्थान संसार के निर्धन एवं अग्रगतिशील देशों में था। किन्तु, प्राविधिक एवं व्यावसायिक मिथा का सुन्दर नियोजन करने के कारण आज उसका स्थान, संसार के मजबूत एवं सुदृढ़ देशों में है। मैदानीय विश्व-युद्ध ने जर्मनी और जापान को जबरन बनाकर अपनी अर्थ-व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। पर उन्होंने प्राविधिक एवं व्यावसायिक मिथा के विकास के लिए जी-जान से मेहनत करके, अपनी पूर्व स्थिति को बहुत-कुछ पुनः प्राप्त कर लिया है। ये उदाहरण हम बात के समर्थन प्रमाण हैं कि किसी भी देश की उन्नति में प्राविधिक एवं व्यावसायिक मिथा का कितना असर महत्त्व है। वस्तुतः देश की उन्नति के लिए यह मिथा एक अनिवार्य आवश्यकता है।

**प्राविधिक एवं व्यावसायिक मिथा के अनिवार्य राष्ट्र की सम्पत्ति के दो आधार और हैं—भौतिक सम्पत्ति एवं जनशक्ति।** किन्तु, इन दोनों आधारों को महत्त्वपूर्ण आधारों में स्थान दिया गया है। भौतिक सम्पत्ति के अन्तर्गत कच्चा माल और मनुज पदार्थ सम्मिलित है। यदि देश में भौतिक सम्पत्ति एवं जनशक्ति का अभाव नहीं है, तो देश सम्पन्न हो सकता है। पर यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि भौतिक सम्पत्ति का प्रयोग करने वाली जनशक्ति—प्राविधिक एवं व्यावसायिक मिथा के ज्ञान से युक्त हो। यदि जनशक्ति इस ज्ञान से रिक्त है, तो भौतिक सम्पत्ति की प्रचुरता के बावजूद भी देश अर्थकमल एवं अग्रगतिशील देश में रहना है।

(भारत के विषय में यह बात अक्षरशः सत्य है। यहाँ भौतिक सम्पत्ति का बाहुल्य है। यहाँ की परती—कपास, पटसन, कच्चा जेसम आदि के उत्पादन के लिए जगत्-प्रसिद्ध है। हम धरती के गर्भ में तेल, लौहा, कोयला आदि मनुज पदार्थों के असार भण्डार छिपे पाते हैं। परन्तु, प्राविधिक एवं व्यावसायिक मिथा के अभाव के कारण भारतीयों को कच्चे माल और मनुज पदार्थों का न तो उपयुक्त उपयोग कर पाते हैं और न कर रहे हैं।)

भारत के विपरीत, जापान एक ऐसा देश है, जिसमें भौतिक सम्पत्ति की दृष्टि में सम्पन्न नहीं माना जाता है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने-ही माल और मनुज पदार्थों का प्रयोग देशों में आयात करना पड़ता है। परन्तु, यहाँ प्राविधिक एवं व्यावसायिक मिथा की उत्तरी उत्तम व्यवस्था है कि वह जन-जन को उपलब्ध है। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों ने भौतिक सम्पत्ति के अभाव में भी अपने देश को संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों के समान स्तर पर आगे बढ़ा दिया है।

हम प्रचार, हम हम मानते हैं कि देश की समृद्धि के लिए सबसे अधिक आवश्यकता हम बात की है कि अपनी जनशक्ति—धैर्यावित, प्राविधिक एवं व्यावसायिक ज्ञान से युक्त हो। यही हम देश की उन्नति भौतिक सम्पत्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने,

अपने देश को उन्नतिशील देशों की श्रेणी में सुनिश्चित स्थान प्रदान कर सकती है। इस ज्ञान के महत्व एवं आवश्यकता से सुपरिचित होने के कारण हमारी सरकार ने 1958 के अपने "विज्ञान-नीति-प्रस्ताव" में भारत के औद्योगिक विकास के लिए अग्रणी नीति निर्धारित की है :—"राष्ट्र की सम्पदा एवं सम्पत्ति—औद्योगीकरण के द्वारा उसके मानव एवं भौतिक साधनों के समुचित उपयोग पर आधारित है। औद्योगीकरण के लिए मानव-साधनों का उपयोग—विज्ञान की शिक्षा और प्राविधिक कुशलताओं में प्रशिक्षण की माँग करता है। भारत की जनशक्ति के विज्ञान-साधन—प्रशिक्षित एवं शिक्षित होकर ही आधुनिक सत्तार में उपयोगी हो सकते हैं।"

"The wealth and prosperity of a nation depends on the effective utilization of its human and material resources through industrialization. The use of human material for industrialization demands its education in science and training in technical skills. India's enormous resources of manpower can only become an asset in the modern world, when trained and educated"—*Science Policy Resolution, Government of India, 4th March, 1958.*

### प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा का इतिहास History of Technical & Vocational Education

आधुनिक भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का ज़िग रूप में विकास हो रहा है, वह पार्श्वचार्य देशों से ग्रहण किए जाने के कारण पूर्णतया नवीन है। किन्तु, प्राचीन भारत में इस शिक्षा का जो पुरातन रूप था, वह इसके आज के रूप से सर्वथा भिन्न था और कहीं अधिक विस्मृत एवं विमृश्य करने वाला है। उस रूप की कल्पना मात्र से ही हमारी चेतना गुनगुना कर कहने लगती है कि प्राचीन काल में हमारा देश इस शिक्षा के क्षेत्र में अपने चरम उत्कर्ष पर था। उस स्थिति से इस शिक्षा का अपकर्ष क्यों हुआ? किन प्रतिकूल परिस्थितियों से जुझनी हुई वह अतीत के गर्त में अदृश्य हो गई? किन कारणोंवश यह नवीन रूप धारण करके पुनः प्रकट हुई है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है? इन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाली आपकी उत्कण्ठा का शमन करने के लिए हम भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के इतिहास पर विह्वल दृष्टिपात कर रहे हैं।

### वैदिक काल में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा

वैदिक काल में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का सुनिश्चित विस्तार करके ही आर्य लोगों ने मग्न जीवन की गम्भीर बाधुओं को अन्तर्ने लिए उपलब्ध किया। इस शिक्षा में प्राप्ति होने वाले ज्ञान के प्रमाण हमें इस काल के ग्रन्थों में दृष्ट-नय बिखरे हुए मिलते हैं। उदाहरणार्थ—ऋग्वेद में बाँधों और नहरों का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में सूत्री और ज्ञानी बह्वी, रणमात्री, बन्दीदाहारी,

गृहस्थों, रथों, नीलाओं, पाषाण की प्रतिमाओं, गी पनवार वाले जलयानों, सहस्रों हारों वाले और सहस्रों स्तम्भों पर आधारित प्रासादों आदि के विवरण मिलते हैं।<sup>1</sup> "गीतम धर्म सूत्र" में 27 प्रकार के शिल्पियों का वर्णन है, जिनमें उल्लेखनीय हैं :—स्वर्णकार, चातुकार, रत्नकार, कुम्भकार, चित्रकार और वास्तुकार।<sup>2</sup>

इन शिल्पियों की प्रशिक्षण देने के लिए आजकल की भी शिक्षा-संस्थाएँ नहीं थीं। इसका कारण यह था कि वैदिक युग में श्रम का विभाजन या और नव जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य एवं व्यवसाय निर्धारित थे। इन व्यक्तियों में ने कुछ अपने जिल्लों और व्यवसायों का उच्च कोटि का ज्ञान रखते थे। यही व्यक्ति अपने पुत्रों एवं जिष्णों को शिल्पों एवं व्यवसायों की शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार, प्राविधिक एवं व्यावसायिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्ता-न्तरित होता रहता था। इन शिक्षा का यह अटूट क्रम राजपूत काल तक विधिवत् चलता रहा। इस अवधि में भारत ने इस शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारिक उन्नति की।

### बौद्ध-काल में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा

वैदिक काल में धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की प्रधानता थी। इसके विपरीत, बौद्ध-काल में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षा और प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा की भी माँग थी। अतः इस युग में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के स्वरूप तथा व्यवस्था में परिवर्तन होना स्वाभाविक था।

"मिलिन्द पाण्डु" में बौद्ध-काल में प्रचलित 19 शिल्पों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 10 की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। भिक्षुओं के लिए मठों में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्ध-धर्म के अनुयायियों और जनसाधारण के लिए अनेक ज्ञानप्रद व्यवसायों की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध था। बौद्ध-काल में चित्रकला, मूर्तिकला एवं भवन-निर्माण-कला की असाधारण प्रगति हुई।

### मुस्लिम काल में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा

भारत के लगभग सभी मुस्लिम शासक शोहीन थे और उनके पास धन का अभाव नहीं था। जब देश के समस्त व्यवसायों को उनका संरक्षण प्राप्त हुआ। यही कारण था कि मुस्लिम काल में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की बहुमूर्ती उन्नति हुई। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय—बम्बों का बनाना था। इन बम्बों में सादर, मरमर और जरीदार, मुकी, जर्जी एवं रेजमी बरत सम्मिलित थे।

1. श्री एन० सुमिता : भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, pp. 54-55.
2. Dr. Veda Mitra : Education In Ancient India, p. 25.

ये चम्पन इतने बढ़िया किस्म के थे कि मैं जहाज़, मत्ताया, मध्य पूर्व आदि देशों को निर्यात किए जाते थे।<sup>1</sup>

भारत के मुस्लिम शासकों की अपने राज्य की सुरक्षा एवं गृहयुद्धों के लिए समय-समय पर युद्ध करने पड़ते थे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि बाघद, भालों, बछियों, घड़ों आदि युद्ध-सामग्री से सम्बन्धित व्यवसायों की असाधारण प्रगति हुई। साथ ही, भारतीय पोतखला-निर्माण ने इतना अधिक प्रगति प्राप्त किया कि उस समय के पुर्तगालियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ पोतों का निर्माण भारत में करवाया।<sup>2</sup>

अधिकांश मुस्लिम शासक और विशेष रूप से मुगल सम्राट—ऐकबर् एवं विलागिता का जीवन व्यनोत करते थे। अतः इस जीवन में सम्बन्धित स्थापत्य-कला, चित्रकला, मन्दिर कलाओं और प्रायः सभी हस्तकलाओं की आवश्यकताओं को अत्यधिक उत्प्रेरित किया। इनमें से अनेक कलाओं की शिक्षा बारखानों में दी जाती थी। मुहम्मद तुगलक और फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में इन बारखानों का उत्कर्ष मिलता है। अकबर के समय में सब बारखाने एक सरकारी विभाग की अधीनता में थे। इन बारखानों में लहकों की विनिश्चित कलाओं एवं दस्तकारियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी शिल्पकार का नियुक्त बना दिया जाता था।<sup>3</sup>

### ब्रिटिश काल में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा

भारत में ब्रिटिश काल का आरम्भ सन् 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के समय में माना जाता है। उस समय से लेकर सन् 1947 तक उन्होंने भारत पर असह्य शासन किया। व्यापार के उद्देश्य में हम देश में आने के कारण उनका ध्यान अपने आर्थिक हित पर केन्द्रित होता स्वाभाविक था। अतः उन्होंने एक जगह योजना के अनुसार भारतीय उद्योगों का विनाश किया और ब्रिटिश उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अपने मूल्य पर विपणन करने, भारत के समस्त आर्थिक स्रोतों को शुष्क कर दिया। उन्होंने यह किस प्रकार किया, हम विषय में कुछ पंक्तियाँ लिख देना समीचीन प्रतीत होता है।

भारतीय उद्योग-धर्मों का विनाश—जिस समय भारत के शासन का शून्य अंग्रेजों के हाथ में आया, उस समय यहाँ प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की विज्ञान-पुनर् एवं गुरु-शास्त्र की परम्परागत पद्धति प्रचलित थी। इस पद्धति ने भारत के उद्योग-धर्मों की प्रगति उत्कर्ष पर पहुँचा दिया था और भारतीय वस्तुएँ—यूरोप की मंडियों में भी पट्टीबारी थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के दल-तोड़र व्यापारियों ने उस पद्धति का गला घोट कर, उसके अस्तित्व का एक बिल भी देश में नहीं रहने

1. बी० एन० सूनिवा : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 379

2. बी० एन० सूनिवा : पूर्वोक्त पुस्तक, p. 380.

3. S. M. Jaffer : *Education in Muslim India*, pp. 12-13.



दिया। उनकी इस नीति के परिणामस्वरूप ब्रिटिश कान के पूर्व और अन्त में इस देश के उद्योगों एवं उनमें संलग्न व्यक्तियों की क्या दशा थी, इसकी कल्पना अयोग्य-निमित्त दो उद्धरणों से सहज ही की जा सकती है।

1. 17वीं शताब्दी में लगभग सम्पूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले फ्रांसीसी यात्री, बर्नियर (Bernier) ने इस देश की अमीरी का वर्णन करते हुए लिखा है :—“भारत एक ऐसा अयाह गड्ढा है जिसमें विश्व का अधिकांश सोना-चांदी चारों ओर से अनेक मार्गों से आ-आकर जमा होता है, और जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी मार्ग नहीं मिलता है।”
2. 20वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत की गरीबी का चित्र प्रस्तुत करते हुए, विलियम डिग्बी (William Digby) ने लिखा है :—“बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटिश भारत में लगभग दस करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं, जिनको किसी समय भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। ऐसे अघ-पतन का दूसरा उदाहरण इस समय किसी भी अन्य एवं उन्नतिशील देश में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है।”

सुन्दर लाल के अनुसार इस असाधारण अघःपतन का मूलभूत कारण था :—“अंग्रेजों का अपनी निर्धारित नीति के अनुसार भारत की ग्राम-पंचायतों, विधा-प्रणाली, हजारों-लाखों पाठशालाओं और हजारों गाल में उन्नत उद्योग-धंधों का नाश कर डालना।”

इन उद्योग-धंधों में सर्वप्रथम नष्ट किया गया—भारत के सबसे अधिक उन्नति-शील वस्त्र-उद्योग लो। उनके पश्चात् चारों ओर—काँच, कागज, धातु, जलपोत आदि उद्योगों की। इस प्रकार, अंग्रेजों ने भारत की भारतीय वस्तुओं से रक्त करके अंग्रेजी वस्तुओं में भर दिया।”

भारतीय उद्योगों के विनाश का एक भयावह परिणाम यह हुआ कि लाखों शिल्पी बेरोजगार हो गए और उनमें से हजारों क्षुधा की असाह्य वेदना में तड़प-तड़प कर निःश्वस हो गए। उस समय के एक गौभक्त दृश्य का चित्र हमें भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल, लार्ड विलियम बेंटिंक के इन शब्दों में देखने को मिलता है :—“पाणिज्य के इतिहास में ऐसे दुर्भाग्य का अन्य उदाहरण मिलना कठिन है। कुत्तारों की हड्डियों ने भारत के मैदानों को सफेद कर दिया है।”

“The misery hardly finds a parallel in the history of Commerce. The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of

1. सुन्दर लाल : भारत में अंग्रेजी राज्य, प्रथम संस्करण, पृ. 23.

2. Jawaharlal Nehru : *The Discovery of India*, p. 351.

India."—Lord William Bentincks' Report to the Court of Directors, 1834

इस प्रकार, चिरकाल से चली आने वाली प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की परम्परागत पद्धति मईव के लिए बाव के गाल में समा गई। एक नये अरसे के बाद उमका स्थान ग्रहण किया—प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की पाश्चात्य पद्धति ने। परिणामतः इस शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। हम सुविधा की दृष्टि से उसके आरम्भ एवं विकास का वर्णन निम्नलिखित बातों में कर रहे हैं; यथा :—

(1) 1800 से 1857 तक—इस अवधि में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उमने कुछ इनी-गिनी समस्याएँ अवश्य स्थापित कीं, जिनका मुख्य उद्देश्य—शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इन समस्याओं में उल्लेखनीय हैं :—(1) रडकी का टॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज (1847); (2) पूना का इंजीनियरिंग स्कूल (1854); और (3) कलकत्ता का इंजीनियरिंग कॉलेज (1856)।

(2) 1857 से 1902 तक—भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास आरम्भ करने का श्रेय 1854 के "गुड के आदेश-पत्र" को प्राप्त है। इस "आदेश-पत्र" में बलपूर्वक कहा गया :—'जनसाधारण को व्यावहारिक एवं लाभप्रद शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए।' किन्तु, कम्पनी के भारत-नियत कर्मचारियों ने इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूर्व के समान केवल शासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा-संस्थाओं की सृष्टि की। सन् 1866 में पूना के इंजीनियरिंग स्कूल को विस्तृत करके कॉलेज का रूप दिया गया। सन् 1887 में महारानी विक्टोरिया की होरक जयन्ती के अवसर पर लन्दन में "विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट" की स्थापना की गई।

इस प्रकार, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को तो कुछ व्यवस्था कर दी, पर उसने औद्योगिक शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की। इस शिक्षा के प्रति उमका ध्यान सर्वप्रथम 1877-78 के "दुर्निश-प्रयोग" (Famine Commission) द्वारा आरपिन किया गया, पर उमने इस शिक्षा में किसी प्रकार की रधि प्रकट नहीं की। इस शिक्षा में मिशनरियों ने अवश्य कुछ कार्य किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर औद्योगिक स्कूलों (Industrial Schools) का निमाग्याग किया। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य—भारतीय ईगार्ड वालों को जीविकोपार्जन के लिए बड़ और मुहार के कार्यों में प्रशिक्षित करना था।

1882 के इटर कमीशन ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को समझकर सबसे पहले ईगार्ड स्कूल के पाठ्यक्रम में इस शिक्षा को स्थान दिया। कमीशन ने सुभाष दिया कि इन पाठ्यक्रम को दो बनों में विभाजित कर दिया जाए—

“अ” पाठ्यक्रम और “ब” पाठ्यक्रम। पहला पाठ्यक्रम साहित्यिक हो और उन छात्रों के लिए हो, जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना चाहते हैं। दूसरा पाठ्यक्रम व्यावहारिक एवं व्यावसायिक हो, और उन छात्रों के लिए हो, जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने के बजाय किसी व्यावसायिक कार्य को अपनी जीविका का उपार्जन करने में साधन बनाना चाहते हैं। इस मुझाव को सरकार की तत्काल स्वीकृति तो प्राप्त नहीं हुई, पर कुछ समय के पश्चात् हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित कर दिया गया।

वस्तुतः सरकार आरम्भ से ही भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार की विनोदी थी। उसका विचार था कि इस शिक्षा का प्रसार होने से भारत की औद्योगिक उन्नति आरम्भ हो जायगी, जिससे इंग्लैंड के उद्योगों को भारी प्रतिद्वन्द्विता मिलेगी। इसके विपरीत, भारत के राष्ट्रीय नेताओं का अखण्ड विश्वास था कि देश की दरिद्रता को दूर करने के लिए इस शिक्षा का अधिक-से-अधिक प्रसार किया जाना आवश्यक था। इस विश्वास से प्रेरित होकर, उन्होंने 1887 में होने वाले कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में सरकार से इस शिक्षा की जोरदार शब्दों में मांग की और अपनी मांग को वार्षिक अधिवेशनों में दोहराते रहे। किन्तु, निज स्वार्थ में लब्ध भारत की अंग्रेजी सरकार अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, इस मांग को निरस्त करती रही<sup>1</sup>।

सन् 1902 में सम्पूर्ण अंग्रेजी भारत में 80 प्राविधिक एवं औद्योगिक स्कूल थे, जिनकी छात्र-संख्या 4,804 थी।<sup>2</sup>

(3) 1902 से 1937 तक—इस अवधि में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की पर्याप्त प्रगति हुई। इसके अनेक कारण थे; यथा :—

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रत्येक अधिवेशन में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की मांग की। अतः सरकार को इस शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य होना पड़ा।
2. भारत के अनेक उदार महानुभावों ने इस शिक्षा के लिए दान दिए और इसका आयोजन करने के लिए अनेक भारतीय नावैजलिक संस्थाओं का संगठन हुआ।
3. भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस शिक्षा के विविध विषयों में डिग्री और डिप्लोमा के कार्यक्रम आरम्भ किए।
4. सन् 1917 के सैल्वर कमीशन ने इस शिक्षा के विकास के लिए दो मुख्य मुझाव दिए :—(1) इण्टरमीडिएट स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा

1. Madan Mohan Malviya's Views, Quoted in the Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18, p. 250.

2. S. N. Mukerji : Education in India, Today & Tomorrow, p. 279.

की व्यवस्था की जाय; और (2) विश्वविद्यालयों में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम आरम्भ किए जायें।

5. सन् 1929 की हर्टाग समिति ने अनुरोध किया कि हार्ड मूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाय।
6. सन् 1936 की युट एवं एवट समिति ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के विषय में तीन मुख्य सुझाव दिए :—(1) देश के उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार इस शिक्षा का विस्तार दिया जाय; (2) कुटीर उद्योग-अगुओं में सत्यन व्यक्तियों को प्राविधिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाय; और (3) जूनियर एवं सीनियर बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की जाय।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1887 में अपने प्रत्येक अधिवेशन में सरकार से प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की माँग कर रही थी। सरकार इस माँग की उपेक्षा न कर मनी। अतः उसने भारतीय छात्रों को इंग्लैंड में उच्च प्राविधिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए प्रति वर्ष दस छात्रवृत्तियाँ देने की योजना आरम्भ की। इस योजना के अनुसार 1905 में 1917 तक 113 भारतीय युवकों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं।<sup>1</sup> किन्तु, इस योजना में कोई नाम नहीं हुआ, क्योंकि भारत वापिस आने पर 113 युवकों में से एक को भी किसी उद्योग में प्रवेश नहीं मिला।<sup>2</sup> इसके अनिश्चित, ये छात्रवृत्तियाँ अधिक व्ययपूर्ण होने के साथ-साथ इनकी कम थी कि प्राविधिक शिक्षा के अभिलाषी सब छात्रों को प्राप्त नहीं हो पाती थी।

अतः कांग्रेस ने पुनः आन्दोलन आरम्भ किया और यह माँग की कि सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली योजना में संशोधन की आवश्यकता है। सरकार ने इस माँग को स्वीकार करके, सन् 1917 में "मॉर्गिसन समिति" (Morrison Committee) की नियुक्ति की और उसे इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने का आदेश दिया। समिति के सदस्यों ने परस्पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् अग्रहित सुझाव दिए :—(1) यूरोप में उच्च प्राविधिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या 30 में अधिक नहीं होनी चाहिए, (2) इन छात्रवृत्तियों की अवधि कम-से कम दो वर्ष और अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष की होनी चाहिए, और (3) छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से अग्रहित विषयों के लिए दी जानी चाहिए—वस्त्र-उद्योग, गन्नित्र-विद्या, वर्तन-निर्माण, चमड़ा पकाना, दियामलाई, कपड़े, कागज, चीनी एवं वैनिश व्यवसाय।<sup>3</sup>

1. S. N. Mukerji : *History of Education in India*, p. 287

2. श्रीधरनाथ मुनोसास्त्राय . भारतीय शिक्षा का इतिहास, पृष्ठ 250.

3. Bhagwan Dayal : *The Development of Modern Indian Education*, p. 432.

सरकार ने "मॉर्गिस्तन समिति" के सुझावों के अनुसार छात्रवृत्तियों की योजना में संशोधन कर दिया। परन्तु, इसमें कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज उद्योग-पतियों ने अपने उद्योगों के गुप्त विधियों को भारतीयों को नहीं बताया। इसके अतिरिक्त, भारतीय छात्रों को विदेश में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी बीच में सन् 1921 में प्रान्तों में उच्च शिक्षण की स्थापना हो गई। इसमें प्रोत्साहित होकर भारतीय जनता ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए आन्दोलन आरम्भ किया और कहा कि इस शिक्षा की आवश्यकता भारत में की जाती चाहिए।

सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिटन (Lord Lytton) की अध्यक्षता में एक विभिन्न समिति की नियुक्ति की, जो "इंग्लैंड में भारतीय छात्रों की समिति" (Committee on Indian Students in England, 1921-22) के नाम से प्रसिद्ध है। इस समिति ने भारतीय छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि भारतीय छात्रों को भारत में ही उच्च प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाय और इस शिक्षा के विभिन्न अंगों का सीधे-से-सीधे अधिकतम विकास किया जाय।<sup>1</sup>

भारत में, सरकार और जनता—दोनों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप इस कार्य में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की विकास-प्रक्रिया में तीव्रता आ गई। उसका प्रमाण यह है कि भारतीय छात्रों को इस शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अग्रनिर्मित शिक्षा-संस्थाओं का निर्माण किया गया :—(1) इण्डियन स्कूल ऑफ़ साइंस, बनारस; (2) गवर्नमेंट स्कूल ऑफ़ टेक्नालॉजी, मद्रास; (3) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस, बंगलौर; (4) इंग्लैंड टेक्नालॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर; (5) स्कूल ऑफ़ केमिकल टेक्नालॉजी, बम्बई; और (6) कनिंग ऑफ़ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी, लाहौर। सन् 1937 में सम्पूर्ण भारत में 535 प्रौद्योगिक, प्राविधिक एवं शैक्षणिक शिक्षा-संस्थाएँ थीं।

(4) 1937 से 1947 तक—इस अवधि में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की तीन घटनाओं में तेज़ी प्राप्त हुई, जिनके फलस्वरूप इसके प्रसार में तीव्रता आ गई। पहली, निर्मित व्यक्तियों में बेरोजगारी की समस्या की बढ़ के कारण सामन्यावस्थाओं का ध्यान इस शिक्षा की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। दूसरी, भारतीयों में इस शिक्षा के प्रति अब तक जो संकोच विचार थे, उनमें परिवर्तन हो गया। अतः भारतीयों में इस शिक्षा को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। तैमूर, द्वितीय विश्व-युद्ध ने इस देश की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में अल्पि-उपद्रव कर दी। युद्ध के लिए मानवी और प्राविधिक शिक्षा प्राप्त

1. *Report of the Commission on Indian Students in England*, Para 24.

व्यक्तियों की माँग में महत्ता असाधारण वृद्धि हो गई। इस माँग की पूर्ति करने के लिए प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं का नव-निर्माण किया गया और सरकार द्वारा प्रत्येक फ़ैक्टरी को प्राविधिक प्रशिक्षण-केन्द्र के रूप में प्रयोग किया गया।<sup>1</sup>

द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान में ब्रिटिश सरकार को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी अनिवार्य थी। अतः उसने एक दश-धारी प्राविधिक शिक्षा-योजना का प्रस्ताव किया, जिसके प्रमुख अंग इस प्रकार थे<sup>2</sup> — (1) मई 1940 में औद्योगिक अनुसंधान-कार्य में सहायता देने के लिए “वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान-परिषद्” (Board of Scientific & Industrial Research) की स्थापना; (2) मई 1941 में “दिल्ली पॉलिटेक्नीक” (Delhi Polytechnic) की स्थापना; (3) मई 1945 में उपर्युक्त प्राविधिक शिक्षा के आयोजन के विषय में परामर्श देने के लिए मजिनीकरण सरकार की अध्यक्षता में “सरकार समिति” (Sarkar Committee) की नियुक्ति; (4) मई 1945 में “अभिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा-परिषद्” (All-India Council for Technical Education) की स्थापना, और (5) मई 1947 में सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों के वैज्ञानिक एवं प्राविधिक कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने के लिए “वैज्ञानिक मानवीय शक्ति-समिति” (Scientific Manpower Committee) की स्थापना।

1947 में सम्पूर्ण देश में 8 जूनियरिंग एवं प्राविधिक शिक्षा देने वाले 28 इंजीनियरिंग और 41 पॉलिटेक्नीक गठान थे।<sup>3</sup>

### स्वतन्त्र भारत में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय में ही हमारे राष्ट्रीय नेता — भारत का औद्योगिक विभाग बनाने के लिए बटिखड़ा है। यह सभी सम्भव है, जब देश के प्रत्येक उद्योग को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिष्ठित व्यक्ति उपलब्ध हो। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का नियोजन अनिवार्य है। इस विषय में स्वतन्त्र भारत में नियुक्त दिग्गज जाने वाले शिक्षा आयोगों ने अथवा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ‘योजना-आयोग’ ने अपने विचारों में इन सुझावों का समूह बनाया है।

भारत के प्रशासकों ने इन सुझावों एवं विचारों और अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर पञ्चवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में सम्बन्धित

1. श्रीपरनाथ मुनोताध्याय : पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० 252

2. S. N. Makerji . *India Today & Tomorrow* pp 280-281.

3. श्रीपरनाथ मुनोताध्याय . पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० 266

अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए हैं। इनके परिणामस्वरूप इस शिक्षा की आवश्यकजनक प्रगति हुई है। हम इस प्रगति के आँकड़े प्रस्तुत करने से पूर्व शिक्षा-आयोगों के सुझावों और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस शिक्षा से सम्बन्धित उपलब्धियों का विवरण लेखबद्ध कर रहे हैं।

### शिक्षा-आयोगों के प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा-विषयक सुझाव

1. विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग (1948-49) ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करके अनेक सुझाव दिए, जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

1. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया जाना चाहिए।
2. वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 3 या 4 प्रकार की विभिन्न व्यावसायिक क्रमों में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
3. वर्तमान इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलॉजी की संस्थाओं को देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाना चाहिए और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जानी चाहिए।
4. देश की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का शिलान्यास किया जाना चाहिए।
5. उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नॉलॉजिकल संस्थाओं की शीघ्र-से-शीघ्र गृष्टि की जानी चाहिए।

2. माध्यमिक शिक्षा-आयोग (1952-53) ने माध्यमिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य—छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उत्पत्ति करना बताया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एवं प्राविधिक शिक्षा के विषय में “आयोग” ने जो सुझाव दिए, उनमें निम्नांकित महत्त्वपूर्ण हैं :—

1. माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए।
2. ग्रामीण स्कूलों में कृषि-शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। अतः इन स्कूलों में उद्यान-विज्ञान, पशु-पालन एवं कुटीर उद्योग-वंधों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए।
4. बड़े नगरों में टेक्नॉलॉजिकल इंस्टीट्यूटों का निर्माण किया जाना चाहिए।

5. उद्योगों पर "शिक्षा-कर" लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त होने वाले धन को प्राविधिक शिक्षा का विस्तार करने में व्यय किया जाना चाहिए।

3. शिक्षा-आयोग (1964-66) ने देश के औद्योगीकरण को सफल बनाने के लिए प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था की आवश्यकता बताया और इस सम्बन्ध में अधोलिखित मुख्य सुझाव प्रस्तुत किए :—

1. विद्यालय-स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम अपने-आप में सम्पूर्ण होने चाहिए, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा की समस्याओं में निराशा महसूस करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं में सर्वोच्च के आधार पर प्रशिक्षण की सुविधाओं का अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाना चाहिए।
3. विद्यालय-शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को व्यावसायिक एवं प्राविधिक-प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पत्राचार-पाठ्यक्रमों, अल्पकालीन पाठ्यक्रमों एवं मशिन्स-मघन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. टेक्निकल स्कूलों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं में व्यावहारिक कार्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए एवं उनमें उत्पादन-शुद्धि बनाया जाना चाहिए।
5. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को अधिक-से-अधिक व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। और इस स्तर पर वाणिज्यिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक कार्यों के विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पंचवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा

"पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अनुसार — "देश ने अपने लिए दो मौलिक-निर्देशक लक्ष्य निर्धारित किए हैं— निर्यता का उन्मूलन एवं आर्थिक आत्म-निर्भरता की प्राप्ति। हमारी योजनाएँ इन्हीं लक्ष्यों से अपनी मूल प्रेरणा ग्रहण करती हैं।"

"Removal of poverty and attainment of economic self-reliance are the two strategic goals that the country has set for itself. Our Plans derive their basic inspiration from these objectives."—*Draft Fifth Five-Year Plan, Vol. I, p. 1.*

इसी प्रेरणा के परिणामस्वरूप पंचवर्षीय योजनाओं में अन्य कार्यों के साथ-साथ प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं की पर्याप्तता को प्राथमिकता दी गई है। हम अपने इस कथन की सत्यता की सिद्ध करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का मशिलन करने उद्दिष्ट कर रहे हैं; यथा :—



पहली योजना, 1951-56—किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रशिक्षित जनशक्ति का निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण भाग होता है। अतः स्वतन्त्र भारत की सम्भावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं में सराहनीय विस्तार किया गया और इस कार्य पर 23 करोड़ रुपए व्यय किए गए।<sup>1</sup>

सन् 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ था, तब देश में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या क्रमशः 38 और 58 थी। इन संस्थाओं की वार्षिक प्रवेश-क्षमता क्रमशः 2,940 और 3,670 थी।<sup>2</sup> सन् 1956 में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़कर क्रमशः 71 और 109 हो गई। इन संस्थाओं की वार्षिक प्रवेश-क्षमता क्रमशः 6,612 और 10,118 थी।<sup>3</sup>

पहली योजना में बंगलौर के “इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइन्स” का विस्तार किया गया। इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 14 कॉलेजों की स्थापना का निश्चय किया गया, कुछ विशिष्ट विषयों में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई और इस शिक्षा को ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए “परामर्शदाता केन्द्रों” का संगठन किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कलाकारों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं में विस्तार किया गया और उनके लिए ग्रामों में भी प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किए गए। प्रिंटिंग (छपाई) टेक्नॉलॉजी, ऊत और रेशम की टेक्नॉलॉजी, भवन-निर्माण-विज्ञान और नगर-आयोजन में प्रशिक्षण देने के कार्य आरम्भ किए गए।<sup>4</sup>

पहली पंचवर्षीय योजना की अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ अग्रलिखित थीं :— जूनियर बहु-उद्योगीय स्कूलों की स्थापना; क्राफ्ट स्कूलों का जूनियर टेक्निकल हाई स्कूलों में रूपान्तर; सामान्य माध्यमिक स्कूलों का टेक्निकल हाई स्कूलों के रूप में विकास; वाणिज्यिक, प्राविधिक और प्रौद्योगिक स्कूलों का कॉलेजों में परिवर्तन; प्राविधिक, प्रौद्योगिक, औद्योगिक और व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना; तथा विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 633 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

दूसरी योजना, 1956-61—पहली योजना में होने वाली प्रगति के बावजूद देश में नवीन उद्योगों की स्थापना के कारण प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या में माँग थी। इस माँग की अधिक-से-अधिक पूर्ति करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर 48 करोड़ रुपए व्यय करने का निश्चय किया गया।<sup>5</sup>

1. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृ० 279.

2. S. N. Mukerji : *Administration of Education in India*, p. 234.

3. *India*, 1966, p. 72.

4. पहली पंचवर्षीय योजना, पृ० 308.

5. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृ० 279.

दूसरी योजना के दौरान में द्वितीय और द्वितीयमा प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या को गगनग दूना कर दिया गया । मन् 1961 में इनकी संख्या त्रमश. 111 और 209 थी । इन संस्थाओं की वारिक प्रवेन-शमना त्रमश 15,497 और 26,525 थी ।<sup>1</sup>

दूसरी योजना में प्राविधिक एव प्रौद्योगिक शिक्षा का विराम करने पर वन दिया गया; दिल्ली के “पॉलिटेक्नीक स्कूल” में प्रौद्योगिकी एव इंजीनियरिंग की शिक्षा-मुविषाओं में पर्याप्त विस्तार किया गया; लडनपुर के “इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी” को स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पूर्ण रूप में विकसित किया गया; बंगलूर के “इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंग” का धातु-विज्ञान, शक्ति-इंजीनियरिंग, विद्युत-इंजीनियरिंग, वायु एव त्रय इंजीनियरिंग, एव आन्तरिक त्रयन्त इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए विकास किया गया, और घनवाद के “इंडियन स्कूल ऑफ माइंग एव ऐप्पाइड त्रियोलॉजी” का विस्तार करके, माइनिंग इंजीनियरिंग एवं उमसे मन्वगिता क्षेत्रों में प्रशिक्षण की अनिरिक्त मुविषाएँ प्रदान की गईं ।<sup>2</sup>

उपयुक्त के अनिरिक्त, फोरमनों की प्रशिक्षण करने की योजना की उद्योगों के सहयोग में पूर्ण किया गया । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के सभी स्तरों में अधिक प्रवीणता उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा के लिए रि.फेजर एवं अन्य पाठ्यत्रओं को गुणगठित किया गया ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अन्य महत्वपूर्ण उन्नतियियाँ अपनिमित थीं — बानपुर एव वरबंद में हायर टेक्नॉलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना, छत्ताई-मन्वन्धी प्रौद्योगिक प्रवीणता के लिए एव केन्द्रीय मन्दा का निर्माण, पड़नी योजना में स्थापित किए जाने वाले प्राविधिक एव व्यावसायिक शिक्षा के केन्द्री में स्नातकोत्तर और प्रौद्योगिक एवं इंजीनियरिंग के अनुमणन की व्यवस्था, और विदेशों में उन्नत अध्ययन के लिए 633 के स्थान पर 800 छात्रवृत्तियों की ध्यम्या ।

तीसरी योजना, 1961-66 — दूसरी योजना में प्राविधिक एव व्यावसायिक शिक्षा की उत्तेगनीय प्रगति हुई । उद्योगों की भावी मांग को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया कि तीसरी योजना के दौरान में 45,000 स्नातकों एवं 80,000 द्वितीयमापाशियों की आवश्यकता पड़ेगी । इन आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राविधिक एव व्यावसायिक शिक्षा के वार्यत्र्यों का विराम करने के लिए 142 करोड रुप का पनरानि निर्धारित की गई ।<sup>3</sup>

1. *India*, 1966, p 72

2. संक्षिप्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ 159

3. *Third Five-Year Plan*, p 107

तीसरी योजना में डिग्री प्रदान करने की 3 और डिप्लोमा प्रदान करने की 10 संस्थाओं का निर्माण किया गया। सन् 1966 में इनकी संख्या क्रमशः 137 और 284 थी।<sup>1</sup>

तीसरी योजना की अवधि में खानों, धातु-शोधन एवं अन्य टेकनॉलॉजियों के विशेषज्ञ तैयार करने के अतिरिक्त, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं केमिकल इंजीनियर तैयार करने पर अधिक बल दिया गया। डिग्री एवं डिप्लोमा के स्तर तक अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकारी अनुसंधानशालाओं; प्रतिरक्षा, रेलवे, सिचाई और बिजली, परिवहन और संचार आदि मंत्रालयों और सार्वजनिक निर्माण-विभाग के तकनीकी संगठनों; और सरकारी तथा निजी औद्योगिक संस्थाओं का भी उपयोग किया गया।<sup>2</sup>

तीसरी योजना के अन्य कार्यक्रम अग्रलिखित थे :—घनवाद के “इंडियन स्कूल ऑफ़ माइंस एण्ड ऐप्लाइड जियोलॉजी; दिल्ली के “पॉलिटैकनीक स्कूल”; खड़गपुर के “इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेकनॉलॉजी; और बम्बई, मद्रास एवं कानपुर में दूसरी योजना की अवधि में खोले जाने वाले इंस्टीट्यूटों का विकास; मुद्रण के चारों स्कूलों एवं” इंस्टीट्यूशन ऑफ़ टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग” का विस्तार; व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए निर्वाह-वृत्तियाँ एवं अनुसंधान-प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ देने की योजनाएँ; शिक्षकों को प्रशिक्षित करने एवं प्रशिक्षणार्थियों के छात्रावास खोलने की योजना; और 21 संस्थाओं में इंजीनियरिंग एवं टेकनॉलॉजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का आरम्भ।

चौथी योजना, 1969-1974—पिछली तीन योजनाओं की अवधि में जिस अनुपात में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार हुआ, उस अनुपात में इस शिक्षा के लिए भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हुईं। “चौथी पंचवर्षीय योजना” (प्रारम्भिक रूपरेखा) (pp 226-227) के अनुसार:—“1964 के एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हो गया था कि इंजीनियरी कॉलेजों और पॉलिटैकनीक संस्थानों में 35 प्रतिशत अध्यापक कम थे, 53 प्रतिशत उपकरण कम थे, 51 प्रतिशत शिक्षा देने के लिए भवन कम थे और 55 प्रतिशत छात्रावासों का अभाव था। अब यह प्रस्ताव है कि प्रथम प्राथमिकता के रूप में इन अभावों को दूर किया जाय।” इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर 253 करोड़ रुपए व्यय किए गए।<sup>3</sup>

चौथी योजना में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए सुविधाओं में वृद्धि की गई। जो अध्यापक, शिक्षण-कार्य में संलग्न थे, उनको अपनी शैक्षिक योग्यताओं

1. *India*, 1971-72, p. 75.

2. तीसरी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० 103-104.

3. *Fourth Five-Year Plan : A Draft Outline*, p. 325.

में वृद्धि करने में सहायता दी गई। उद्योगों एवं शिक्षा-संस्थाओं के कर्मचारियों की अटना-बदली की प्रोत्साहित करने के उपाय किए गए। उद्योगों में कार्य करने वाले इंजीनियरों को एक निश्चित अवधि तक शिक्षण-कार्य करने के लिए और अध्यापकों को उस अवधि में उद्योगों में कार्य करें औद्योगिक तरानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।<sup>1</sup>

उच्च स्तरीय प्रबन्ध कर्मचारी तैयार करने के लिए तीसरी योजना में बनरना एवं अहमदाबाद में दो "प्रबन्ध सम्मेलन" स्थापित किए गए थे। इन सम्मेलनों का दो वर्ष का पूर्णकालीन पाठ्यक्रम था और ये "मास्टर ऑफ विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन" की उपाधि प्रदान करते थे। तीसरी योजना के अन्त तक इन सम्मेलनों में तैयार होकर निकलने वाले छात्रों की संख्या 300 थी। प्रबन्ध कर्मचारियों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए इन सम्मेलनों की प्रवेश-शुल्कता को बढ़ाकर 600 कर दिया गया। इसके अलावा, दिल्ली, मद्रास एवं बम्बई जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में अगकालीन प्रबन्ध शिक्षा की व्यवस्था की गई।

चौथी योजना के अन्य कार्यक्रम अग्रलिखित थे :—शिक्षा-संस्थाओं की वार्षिक प्रवेश-शुल्कता में वृद्धि; डिप्लोमा-स्तर की शिक्षा-संस्थाओं का विस्तार; नवीन एवं वर्तमान संस्थाओं और देश के विकासशील औद्योगिक क्षेत्रों में निकट सम्बन्ध की स्थापना; छात्रों को बड़े कारखानों में व्यावहारिक कार्य की सुविधाएँ, और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के लिए अल्पकालीन एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन।

पाँचवीं योजना 1974-79 — चौथी योजना में डिग्री स्तर पर 25,000 और डिप्लोमा-स्तर पर 50,000 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य था। परन्तु, इंजीनियरों की बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या ने इस लक्ष्य की प्राप्ति को असम्भव बना दिया। पिछले कुछ वर्षों में इस समस्या का आंशिक समाधान हो जाने के कारण डिग्री और डिप्लोमा—दोनों स्तरों पर छात्रों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। अतः पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार न करके उसे सुदृढ़ किया जायगा। "पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अनुसार :—“पाँचवीं योजना में प्राविधिक शिक्षा-व्यवस्था के हड़ोकरण एवं गुणान्तरक पद्धति पर विशेष धन दिया जायगा।”

“The main stress in the Fifth Plan will continue to be on

the consolidation and improvement of the quality of the technical education system."—*Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 203.

उल्लिखित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए "पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए 164 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।<sup>1</sup>

पाँचवीं योजना में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के हढ़ीकरण एवं गुणात्मक उन्नति के लिए निम्नांकित कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया है :—

1. प्रत्येक संस्था की भौतिक सुविधाओं में विस्तार करके, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करना।
2. प्रत्येक संस्था के वर्कशॉप और प्रयोगशाला को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करना।
3. पाठ्यक्रमों का आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन करना और व्यावहारिक कार्य को प्रमुखता देना।
4. जनशक्ति के संदर्भ में सब प्रकार की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन करना।
5. विनिष्ट उद्योगों की शिक्षा देने के लिए नवीन संस्थाओं का निर्माण करना।
6. विश्वविद्यालयों में "प्रबन्ध-शिक्षा" (Management Education) के विभागों की सृष्टि करना।
7. शिक्षकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।
8. प्राविधिक सेवाएँ आरम्भ करके जनता, संस्था और उद्योगों में समन्वय स्थापित करना।
9. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक विकास से समन्वय स्थापित करना।
10. व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के लिए अनवरत शिक्षा की व्यवस्था करना।
11. रोजनल इन्जीनियरिंग कॉलेजों में स्वानीय उद्योगों के सहयोग से उद्योग पाठ्यक्रमों एवं अभ्यास-प्रयोगशालाओं का आयोजन करना।

1. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 207.

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति  
तालिका 1—व्यावसायिक व टेक्निकल स्कूल शिक्षा<sup>1</sup>

वर्ष	स्कूल-संख्या	छात्र-संख्या	शिक्षक-संख्या	व्यय (करोड़ रुपए)
1961-62	3,751	4,08,443	28,857	12.80
1962-63	3,846	4,24,264	29,847	13.04
1963-64	4,137	4,57,350	33,494	16.24
1964-65	3,147	2,69,096	17,380	7.29
1965-66	2,775	2,47,021	17,785	7.66
1966-67	2,754	2,45,148	18,344	8.27

तालिका 2—उच्च टेक्निकल शिक्षा (इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी)<sup>2</sup>

वर्ष	संख्या		प्रवेश पा सकने वाले छात्र		उत्तीर्ण छात्र	
	डिग्री	डिप्लोमा	डिग्री	डिप्लोमा	डिग्री	डिप्लोमा
1951	53	89	4,788	6,716	2,693	2,626
1956	71	109	6,612	10,118	4,337	4,103
1961	111	209	15,497	26,525	7,026	10,349
1966	137	284	25,006	48,579	13,051	22,260
1969	136	277	21,340	43,412	15,686	21,751
1970	136	277	21,300	43,400	15,700	21,750
1974 <sup>3</sup>	138	307	27,000	50,000	—	—

प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति  
Present Position of Technical & Vocational Education

हम प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का वर्णन  
अप्रारम्भिक चर्चा के अन्तर्गत कर रहे हैं —

1. India, 1971-72, p. 67
2. India, 1966, p. 72 & India, 1971-72, p. 75.
3. Draft Fifth Five-Year Plan, Vol. II, p. 203.

प्राविधिक व व्यावसायिक स्कूल-शिक्षा—इस समय भारत के अधिकांश राज्यों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, पशु-पालन एवं हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जाती है। जो बालक 8वीं या 9वीं कक्षा के बाद पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए “औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाएँ” (Industrial Training Institutes) प्राविधिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाती हैं। जूनियर टेक्निकल स्कूल—छात्रों को इंजीनियरिंग से सम्बन्धित व्यवसायों के लिए तैयार करते हैं। देश में कुछ पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण-केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं।<sup>1</sup>

उच्च प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा—खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली और कानपुर स्थित राष्ट्रीय महत्त्व की उच्च प्रौद्योगिकी संस्थाएँ पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं में पूर्व-स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, परीक्षा के आधार पर होता है, जो देश के कई केन्द्रों में होती है। इन संस्थाओं में प्रति वर्ष 1,250 विद्यार्थी पूर्व-स्नातक कक्षाओं में और 1,200-1,500 विद्यार्थी स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर प्रवेश लेते हैं। इनके अतिरिक्त, 14 प्रादेशिक इंजीनियरिंग कॉलेज और कई अन्य इंजीनियरिंग और औद्योगिक संस्थाएँ और कई पॉलिटैक्नीकों की भी स्थापना की गई है। खान और धातुकर्म-विज्ञान आदि विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए डिग्री और डिप्लोमा स्तर के कई केन्द्रों की स्थापना की गई है। पुरानी संस्थाओं का विस्तार और विकास किया गया है। इंजीनियरिंग शिक्षा को व्यावहारिक प्रशिक्षण से सम्बद्ध करने के लिए उद्योगों के सहयोग से 60 इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटैक्नीकों में दोमुठे पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। इंजीनियरिंग के डिग्री स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रमों की अवधि 5½ वर्ष और डिप्लोमा स्तर की अवधि 3½ वर्ष की है।<sup>2</sup>

प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा के स्तर—इस समय भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के 4 स्तर या कोर्स हैं; यथा :—

1. स्नातकोत्तर कोर्स व अनुसंधान—स्नातकोत्तर कोर्सों की अवधि एक या दो वर्षों की है। अनुसंधान-कार्य की अवधि दो या तीन वर्षों की है और स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही किया जा सकता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान-कार्य के कुछ मुख्य विषय हैं :—धातु विज्ञान, उत्पादन टेक्नॉलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नॉलॉजी और इंजीनियरिंग की अनेक शाखाएँ।

2. स्नातक-कोर्स—स्नातक-कोर्सों की अवधि 3 से 5 वर्षों की है। इस कोर्स के

1. India, 1975, p. 52.

2. India, 1974, p. 53.





श्रम से घृणा करते हैं और हस्तकार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने से निम्नतर समझते हैं। वे गले ही कौशलों एवं हस्तकलाओं में प्रवीण होने के कारण असाधारण शिल्पी हों, पर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं।

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में हस्तकार्य का मुख्य स्थान है। अतः हम इस कार्य को करके, अपने और अपने परिवार के सम्मान का संहार नहीं करना चाहते हैं। हमारे इस दृष्टिकोण को 'कोठारी कमीशन' ने अग्रलिखित शब्दों में अंकित किया है :—“दुर्भाग्य से, अब भी व्यापक रूप में यह अनुभव किया जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा, निम्न कोटि की शिक्षा है।”

“It is unfortunately still widely felt that vocational education is an inferior form of education.”—*Kothari Commission Report*, p. 369.

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में निहित हस्तकार्य के प्रति हमारे इस अनुचित दृष्टिकोण ने इस शिक्षा के विस्तार में अल्लङ्घनीय अवरोध उपस्थित कर दिया है।

**समाधान—दृष्टिकोण में परिवर्तन: Change in Attitude—**इस समस्या का समाधान करने के लिए हस्तकार्य के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जब सरकार और कर्मठ समाज-सेवक देशव्यापी आन्दोलन आरम्भ करें और अग्रान्वित तीन नारों के सिंहनाद से नवयुवकों में जागृति उत्पन्न कर दें :—(1) शारीरिक श्रम अपमानजनक न होकर, वरिष्ठतम गुण है। (2) प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, देश की उन्नति का मूलाधार है। (3) भारतीय नवयुवकों पर ही अपने देश की उन्नति और नवनिर्माण का भार है।

उक्त आन्दोलन, भारतीय नवयुवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में सहायता अवश्य करेगा, पर केवल आन्दोलन ही पर्याप्त नहीं है। इससे कहीं अधिक आवश्यक यह है कि सरकार, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को सभी प्रकार के सम्भव आकर्षण एवं सुविधाएँ प्रदान करें; यथा :—अध्ययन-काल में उदार छात्रवृत्तियाँ; अध्ययन की समाप्ति के पश्चात् उत्तम वेतन पर तत्काल नौकरियाँ; और मानसिक एवं शारीरिक श्रम करने वालों को समान सम्मान एवं पुरस्कार।

हमने हस्तकार्य के प्रति अनुचित दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए, जो सुझाव दिए हैं, उनको सार रूप में “कोठारी कमीशन” के इन शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है<sup>1</sup> :—“कुशल कारीगरों और शिल्पकारों की स्थिति और महत्त्व को ऊँचा उठाने के लिए सरकार और उद्योगों—दोनों के द्वारा सम्मिलित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उनको उत्तम पारिश्रमिक

नौतियों का निर्माण, व्यावसायिक विदेशों का आगोजन एवं जनमत के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए।"

2 समस्या—सामान्य व प्राविधिक शिक्षा में स्पष्ट अन्तर : *Sharp Distinction between General & Technical Education*—हमारी प्राविधिक शिक्षा-सम्पादों में सामान्य और प्राविधिक शिक्षा में स्पष्ट अन्तर रिया जाता है। वे मर्यादा केवल प्राविधिक शिक्षा को महत्व देती हैं और मानवीय पहलु की पूर्ण उपेक्षा करती हैं। जहाँ इनमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा—एसागी है। वह बुद्धिमान शिल्पकार या इंजीनियर का निर्माण तो करती है, पर श्रेष्ठ मानव का नहीं। वह उसे उत्पादन के आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का रक्षक भी ज्ञान प्रदान नहीं करती है।

इस एकांगी शिक्षा का परिणाम यह होता है कि जब छात्र अपना अध्ययन समाप्त करके, वास्तविक जगत् में पदार्पण करते हैं, तब उनकी व्यावहारिक एवं कार्य-सम्पन्नी समार का कोई ज्ञान नहीं होता है। वे इस तथ्य से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं कि वे जिन उत्पादन-कार्य में संलग्न हैं, उसके आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य क्या हैं? माय ही, वे अपने सहयोगियों, अधीनस्थ कर्मचारियों एवं उच्च पदाधिकारियों से सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम होता है—प्राविधिक जगत् में उनकी विकलता, जिसका उत्पादन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

समाधान—सामान्य व प्राविधिक शिक्षा का उचित मिश्रण : *Appropriate Combination of General & Vocational Education*—इस समस्या का समाधान करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्राविधिक एवं सामान्य शिक्षा में विभाजन की स्पष्ट रेखा न खींची जाय। दम्बुत में एक-दूसरे में मिश्र न होकर, शिक्षा-प्रक्रिया के दो रूप हैं। "बुट-एबट रिपोर्ट" के अनुसार —"सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रूप से एक-दूसरे से भिन्न न होकर निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के पहले और बाद के रूप हैं।"

"General and Vocational education are not essentially different branches, but the earlier and later phases of a continuous process."—*Wood-Abbott Report*, p. 40.

अब प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-सम्पादों में सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक या प्राविधिक शिक्षा में विभाजन की स्पष्ट रेखा नहीं खींची जाना सवया अनुचित है। इंजीनियर—व्यावसायिक कार्यकर्ता है। इसलिए, उसमें व्यावसायिक कुशलता होना आवश्यक है। परन्तु, इंजीनियर होने से पूर्व वह मानव है। व्यावसायिक कार्यकर्ता होने के कारण उसे एकान्त में नहीं, बल्कि समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी व्यावसायिक कुशलता का सर्वोत्तम प्रयोग नहीं कर सकता है, जब उसे मानव-सम्बन्धों का और उस समाज के

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का पूर्ण ज्ञान हो, जिसका कि वह सदस्य है। अतः उसे इस ज्ञान से सम्पन्न किया जाना आवश्यक है।

यह तभी सम्भव है, जब प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं में सामान्य शिक्षा को निश्चित स्थान प्रदान किया जाय। इस शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों को मानव-शास्त्रों एवं सामाजिक विज्ञानों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। यह ज्ञान उनकी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करेगा। परिणामतः वे उत्पादन-कार्य में अधिक योग दे सकेंगे। इसीलिए, “कोठारी कमीशन” का यह सुझाव है :—“सामान्य एवं प्राविधिक शिक्षा में स्पष्ट अन्तर नहीं किया जाना चाहिए। सब प्रकार की प्राविधिक शिक्षा में सामान्य शिक्षा का समुचित अंश होना चाहिए।”

“Too sharp a distinction must not be drawn between general and vocational education. All technical education should contain an appropriate element of general education.”—*Kothari Commission Report*, p. 370.

**3. समस्या—दोषपूर्ण पाठ्यक्रम : Defective Curriculum**—हमारी प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में दो मुख्य दोष हैं—संकीर्णता एवं समरूपता। उनमें व्यापकता और विविधता, बहुचयनता और बहु-उद्देश्यता का पूर्ण अभाव है। उनका निर्माण—छात्रों की विभिन्न रुचियों एवं उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। अतः वे छात्रों और उद्योगों—दोनों के लिए अहितकर, अनुपयुक्त एवं अनुपयोगी हैं। इसकी पुष्टि में तीन प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

पहला, पाठ्यक्रम में निर्धारित समस्त विषयों का अध्ययन सब छात्रों के लिए अनिवार्य होता है। अतः उनको अपनी रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसका परिणाम होता है—परीक्षा में असफलता, जो अपव्यय एवं अवरोधन को जन्म देती है।

दूसरा, समान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के कारण समान शैक्षिक योग्यताओं वाले इतने व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं कि उनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं। इसका परिणाम होता है—बेरोजगारी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं में इस बेरोजगारी के कारण ही छात्रों की संख्या कम हो गई थी।

तीसरा, समय की गति के साथ देश की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। परिणामतः देश के उद्योगों की माँगें बदल रही हैं। समरूप पाठ्यक्रम इन बदलती हुई माँगों की पूर्ति करने में विफल होते हैं।

**समाधान—विविध व संशोधित पाठ्यक्रम : Diversified & Revised Curriculum**—पाठ्यक्रम के उपरिलिखित दोषों का उन्मूलन करने के लिए दो सुझाव

दिए जा सकते हैं। पहला सुझाव यह है कि पाठ्यक्रम में अधिक-से-अधिक विभिन्न विषयों को समाविष्ट करके, उसे विविधता का गुण प्रदान किया जाय। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से छात्रों को अपनी रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर सुलभ हो जायगा। अतः उनकी क्षमकता का प्रश्न उपस्थित नहीं होगा और न इससे उत्पन्न होने वाले अपक्षय एवं अवरोधन का। दूसरा सुझाव यह है कि देश के विभिन्न उद्योगों की माँगों का सतर्कता से अध्ययन करने के पश्चात् पाठ्यक्रम में समय-समय पर संशोधन किया जाय। इस प्रकार माँगोपित किया जाने वाला पाठ्यक्रम—देश और छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। देश के उद्योगों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति गहरना से उपलब्ध हो जायेंगे और छात्रों को बेरोज़गारी का मुँह नहीं देखना पड़ेगा।

हम अपने सुझावों के समर्थन में “कोठारी समीक्षण” के अग्रलिखित दो वाक्य उद्धृत कर रहे हैं:—“कोठार समीक्षा को सावधानी से दूर रखकर, पाठ्यक्रम में निरन्तर संशोधन किया जाना चाहिए। बदलती हुई माँगों की पूर्ति करने के लिए, डिप्लोमा और डिप्लोमा-सोनों स्तरों के पाठ्यक्रमों की विविधता प्रदान की जानी चाहिए।”

“Syllabus should be continually revised, avoiding any rigid conformity. Courses at both degree and diploma levels should be diversified to meet the changing needs”—Kothari Commission Report, pp 659-660

4. समस्या—शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम Unsuitable Medium of Instruction—2 मितम्बर, 1956 के राज्य-शिक्षा-मन्त्रियों के सम्मेलन में माँगन देते हुए, श्री नेहरू ने कहा था —‘यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो रहेगा।’

उस समय में आज तक प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है और हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने इसमें परिवर्तन करने का कभी कोई विचार प्रकट नहीं किया है। सम्भवतः उनकी पारणा है कि श्री नेहरू ने जो मन व्यक्त किया था, वह केवल उसी समय के लिए नहीं, अपितु मई के लिए था। किन्तु, उस समय में आज तक हमारी माध्यमिक शिक्षा में ज्ञानिकारी परिवर्तन हो चुके हैं। अंग्रेजी अपने परागमन से अपदस्थ हो चुकी है। भारतीय मायाएँ शिक्षा के माध्यम के पर पर आगीन हो चुकी हैं। डिप्लोमा और डिप्लोमा स्तर की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-महाराजों में प्रवेश करने वाले अधिकांश छात्र उच्चतर माध्यमिक या इंटरमीडिएट परीक्षा पास होते हैं।

जब ये छात्र इन महाराजों में प्रवेश करते हैं, तब वे करने की विचित्र नई दुनियाँ में पाते हैं। उन्होंने यहाँ से अपनी मातृभाषा में गुना और समझा, पढ़ा और

निम्ना है। पर अब उनको अंग्रेजी में सुनने और समझने, पढ़ने और लिखने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके सभी दुष्परिणाम स्वयंविदित हैं। न तो वे कक्षा में शिक्षकों के व्याख्यानों की समझ पाते हैं और न पुस्तकों में लिखी हुई बातों को। अतः वे अपना अधिकांश समय, माध्यम की भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में व्यय करते हैं। इस कार्य में कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों को तो सफलता हासिल हो जाती है, पर शेष को नहीं। वे शेष छात्र या तो अपना अध्ययन स्थगित कर देते हैं या परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में मर्देव के लिए मुँह मोड़ लेते हैं। अब तनिक कल्पना कीजिए इन छात्रों की दयनीय दशा की, इनके अथक परिश्रम के निरर्थकता की और इनके अभिभावकों की ग़ाढ़ी कमाई के नष्ट धन की। इन सभी बातों के लिए शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम ही उत्तरदायी है।

**समाधान—क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग : Use of Regional Languages—**

शिक्षा के माध्यम की समस्या का समाधान तभी हो सकता है, जब अंग्रेजी को मर्देव के लिए अलविदा देकर, उसका स्थान क्षेत्रीय भाषाओं की प्रदान किया जाय। इस कार्य में समय अवश्य लगेगा, क्योंकि इन भाषाओं में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में सम्बन्धित पुस्तकें तैयार करनी पड़ेंगी। यह कार्य कठिन अवश्य है, पर असम्भव नहीं है। रूस, जर्मनी, जापान आदि देशों के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। इन देशों में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है, वरन् उनकी स्वयं अपनी भाषाएँ हैं। यदि ये देश अपनी भाषाओं के माध्यम से अत्यन्त उच्च कोटि की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है ?

यदि भारत की सरकार किसी कारणवश इस नीति का तुरन्त अनुसरण करने में अपने को असमर्थ पाती है, तो उसे “कोठारी कमिशन” के इस सुझाव का स्वागत करना चाहिए<sup>1</sup> :—“पॉलिटेक्नीकों (टिप्पनीमा स्तर की शिक्षा-संस्थाओं) में शिक्षा का माध्यम—क्षेत्रीय भाषाएँ होनी चाहिए; अंग्रेजी कुछ समय तक इंजीनियरिंग की शिक्षा (टिप्पनीमा स्तर की शिक्षा) का माध्यम रह सकती है। किन्तु, क्षेत्रीय भाषाओं में प्राविधिक विषयों की पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने के लिए उत्साहपूर्ण कार्य की आवश्यकता है।”

**5. समस्या—व्यावहारिक प्रशिक्षण की उपेक्षा : Neglect of Practical Training—** हमारे देश की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं के चिरह्रा एक आम नितावन यह है कि उनमें जितना बल सैद्धान्तिक शिक्षा पर दिया जाता है, उसका दर्ज़ान भी व्यावहारिक प्रशिक्षण पर नहीं दिया जाता है। इन शिक्षागत की मांगों के वर्धन के लिए शिक्षा-संस्थाएँ दो तर्क प्रस्तुत करती हैं। पहला, उनके बजटों और प्रयोगशालाओं में उपकरणों का अभाव है और जो उपकरण हैं भी, वे

इतने पुराने हो चुके हैं कि आधुनिक उद्योगों की दृष्टि में उनकी उपयोगिता नष्ट हो चुकी है। दूसरा, उनके छात्रों में स्थित पेशेवरों और औद्योगिक क्षेत्र उनके छात्रों को अपने वहाँ व्यावहारिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं।

तक अक्राद्य है, यथार्थता पर आधारित है। किन्तु, वर्तमान व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण छात्रों का अकथनीय अहित होता है। वे व्यावहारिक कार्य में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी उनको अपने मापी व्यावसायिक जीवन में प्रति पन आवश्यकता पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अपने व्यवसायों में सम्बद्ध व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने सहयोगियों और विशेष रूप से अपने अल्प शिक्षित अधीनस्थ कर्मचारियों से कृपा की याचना करनी पड़ती है। इस विधि द्वारा ज्ञान-याप्ति में शिथिल भी होता है और उनकी मान-हानि भी होती है।

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-मस्याओं के छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान में परिपूर्ण करने के लिए, “कोठारी कमिशन” ने तीन सुझावों की सुझाव दी है, यथा<sup>1</sup> —

1. किसी कोर्स के छात्रों को बीसवें वर्ष में ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाय।
2. डिप्लोमा कोर्स के छात्रों को मैट्रिकुलेशन ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान अधिक दिया जाय।
3. छात्रों की स्थानीय उद्योगों में वास्तविक अनुभव प्राप्त करने की सम्पत्ति सुविधाएँ प्रदान की जायें। इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, उद्योगों को कुछ धन दिया जाय।

जहाँ तक वर्कशॉपों और प्रयोगशालाओं का प्रश्न है, उनको नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया जाय। इस सम्बन्ध में “पाँचवीं पञ्चवर्षीय योजना” द्वारा व्यक्त किया जाने वाला सरकार का यह निर्णय अभिनन्दनीय है<sup>2</sup> — “वर्कशॉपों और प्रयोगशालाओं को आधुनिक रूप प्रदान किया जायगा और अबतक हुई औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पुरानी समस्याओं की अनुपयोगी मात्राओं की उपयोगी साजसज्जा से बदला जायगा।”

6 समस्या—अव्यय Wastage—प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में अव्यय की समस्या वर्तमान समस्या है। “कोठारी कमिशन” ने अनुमानित<sup>3</sup> —

1. Kothari Commission Report, pp. 659-660
2. Draft Fifth Five-Year Plan, Vol. II, p. 204
3. Kothari Commission Report, pp. 373 & 381

स्तर पर अपव्यय लगभग 40% और डिग्री स्तर पर 20% है, पर कुछ विजिण्ट विषयों में 44% तक है।

उपयुक्त दोनों स्तरों पर अपव्यय के प्रधान कारण दृष्टव्य हैं :—

1. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा इतनी महँगी है कि साधारण वार्षिक स्थिति के छात्रों को अपने अभिभावकों से पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा-सम्बन्धी विविध प्रकार की सामग्री के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है।
2. इस शिक्षा की संस्थाओं में योग्य अध्यापकों का अभाव है। अतः इनमें शिक्षण का स्तर निम्न है।
3. इस शिक्षा की संस्थाओं में अध्यापकों का वेतन इतना अल्प है कि वे धन-लाभ से प्रलोभित होकर औद्योगिक या व्यावसायिक केन्द्रों में चले जाते हैं। उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति या तो होती नहीं है या बहुत समय के बाद होती है। ऐसी दशा में छात्रों की शिक्षा का क्रम टूट जाता है।
4. इस शिक्षा की संस्थाओं में अनेक ऐसी हैं, जिनकी वर्कशॉपों और प्रयोग-शालाओं में पर्याप्त उपकरण नहीं हैं, और जो हैं भी वे प्राचीन हंग के हैं। अतः छात्र उचित और आवश्यक प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं।
5. इस शिक्षा की संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी है। अतः जिन छात्रों को इस भाषा पर अधिकार नहीं होता है, वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं।
6. इस शिक्षा की संस्थाओं के पाठ्यक्रम संकीर्ण हैं। अतः छात्रों को अपनी रुचियों के अनुकूल विषयों का चयन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है।
7. इस शिक्षा की संस्थाओं में अनेक ऐसी हैं, जिनसे या तो छात्रावास सम्बद्ध नहीं है और यदि है भी, तो उनमें नव छात्रों के निवास के लिए स्थान नहीं होता है। अतः जो छात्र अपने सम्बन्धियों के पास या किराए के कमरों में रहते हैं, वे अध्ययन के प्रति अपना पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते हैं।

**समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—**प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विद्यमान अपव्यय को समाप्त करने के लिए, इन कारणों को दूर किया जाना आवश्यक है, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। इनको समाप्त करने के लिए "फोठारी कमीशन" द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले अग्रिम उपाय भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं :—“अच्छे छात्रों का चुनाव, प्रवेश की निम्नतम शैक्षिक योग्यताओं से छात्रों को मुक्त करने की प्रचलित प्रथा की समाप्ति और अंग्रेजी पर अपर्याप्त अधिकार रखने वाले छात्रों के लिए इन भाषा के शिक्षण की व्यवस्था।”

"Further steps can be taken through the better selection of students, arresting the present practice of relaxing minimum academic requirements for admission, and the provision of remedial courses in English for students with an inadequate command over this language"—*Kothari Commission Report*, p. 381.

7. समस्या—शिक्षकों का अभाव : *Paucity of Teachers*—प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की एक दुर्गाध्य समस्या—शिक्षकों का अभाव और इस अभाव की अविराम अभिवृद्धि है। हम अपने हम कपन की पुष्टि नीचे की तालिका में दिए गए तथ्यों से कर रहे हैं :—

शिक्षकों का अभाव

वर्ष	द्वितीय स्तर पर	टिप्पणीमा स्तर पर
1959	24.5%	---
1961	33%	25.3% <sup>1</sup>
1963	38.9%	25% <sup>2</sup>
		31.2% <sup>3</sup>

उक्त दोनों स्तरों पर शिक्षकों के अभाव के दो व्यापारमूल कारण हैं —  
 प्रयोगों द्वारा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की मांग और प्रावि-  
 क समस्याओं में इन व्यक्तियों की कार्य करने की अनिच्छा। प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त  
 व्यक्तियों की सभी उद्योगों में मांग रहती है। उनको इन उद्योगों में उत्तम  
 धन, आवास और कितनी ही अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। इसके विपरीत,  
 समस्याओं में उनको मिलता है—अल्प वेतन और जीवन एवं कार्य करने की  
 अपूर्ण दशाएँ। वे जानते हैं कि उद्योगों और व्यवसायों में कार्य करने की  
 इससे विपरीत, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-समस्याओं में वे मंदिर पन  
 में घुस रहे हैं और शिक्षक होने के कारण समाज द्वारा निर्णयित व्यक्तियों  
 अपने जीवन के दिन काटेंगे।



अतः उनके मस्तिष्क में शिक्षकों के रूप में कार्य करने के विचार का प्रादुर्भाव नहीं होना है। ये शिक्षण-व्यवसाय को तभी ग्रहण करने हैं, जब भाग्य उनकी टुकड़ा देता और मय उद्योगों के द्वारा उनके लिए बन्द हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षकों का अभाव होना स्वाभाविक है। "कोठारी कमीशन" ने ठीक ही लिखा है :—“इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों का वर्तमान विनाश अभाव परेशानी में डालने वाला है।”

“The existing shortage of teachers in engineering colleges is disturbingly large.”—*Kothari Commission Report*, p. 380.

समाधान—शिक्षकों की पूर्ति : Supply of Teachers—प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षकों के अभाव की पूर्ति करने की सबसे आवश्यक शर्त यह है कि उनके व्यवसाय को आकर्षक बनाया जाय। “कोठारी कमीशन” के अनुसार :—“आधारभूत कार्य—शिक्षण-व्यवसाय को आकर्षक बनाना है।”

“The key step is to make the profession attractive.”—*Kothari Commission Report*, p. 379.

शिक्षण-व्यवसाय को आकर्षक बनाने के लिए “कोठारी कमीशन” ने चार व्यावहारिक सुझाव दिए हैं<sup>1</sup> :—(1) शिक्षकों के वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि; (2) उनकी कार्य करने की दशाओं में सुधार; (3) उनके लिए अनुसंधान की सुविधाएँ; और (4) उनकी स्थानीय उद्योगों में परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति।

भारत-सरकार ने शिक्षकों के अभाव की समस्या का समाधान करने की यथेष्ट चेष्टा की है और पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न प्रकार के उपायों का प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ—दूसरी और तीसरी योजनाओं में इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिप्यवृत्तियाँ देकर शिक्षक तैयार किए गए और स्नातकों को विदेश में अध्ययन करने के लिए हम शर्त पर छात्रवृत्तियाँ दी गईं कि वे वहाँ से लौटकर शिक्षण-कार्य करेंगे।<sup>2</sup> चौथी योजना में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधानों की सुविधाओं में विस्तार किया गया और शिक्षण-कार्य में नवीन अध्यापकों को अपनी शैक्षिक योग्यताओं में वृद्धि करने में सहायता दी गई।<sup>3</sup> पाँचवी योजना में शिक्षकों के लिए निवास-स्नानों और उनके सम्बन्धित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने का आयोजन है।<sup>4</sup>

8. समस्या—अध्ययन के उपरान्त शिक्षा का अभाव : Absence of Education after Study—शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। परन्तु, जो छात्र

1. *Kothari Commission Report*, p. 379.

2. तीसरी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक स्वरूप), पृष्ठ 105.

3. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक स्वरूप), पृष्ठ 227.

4. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 203.

प्राविधिक या व्यावसायिक मंथ्याओं में अपना अध्ययन करने के उपरान्त किसी उद्योग या व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने अध्ययन-काल में जिन ज्ञान का जर्जन करते हैं, वह समय की गति के साथ-साथ मीमित होना जाता है। अन्त में, एक व्यक्ति ऐसी आती है, जब उनकी स्मृति में ज्ञान का केवल कुछ ही अंग रह जाता है। इसका उनकी दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रवृत्ति थारम्भ हो जाती है।

विज्ञान की इस शताब्दी में निरन्तर नये अनुसंधान एवं आविष्कार हो रहे हैं। प्राविधिक कार्यकर्त्ता को इसका जिनका अधिक ज्ञान होता है, उनकी ही अधिक कुशलता से वह अपने कार्य को करता है। यदि ऐसा नहीं है, तो उसकी कुशलता के स्तर में गिरावट अनिवार्य है। हमारे देश के लगभग सभी प्राविधिक या व्यावसायिक कार्यकर्त्ताओं के विषय में यह बात मध्य है। परन्तु, इसके लिए उन पर दोषारोपण किया जाना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि उनके लिए अध्ययन के उपरान्त शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

**समाधान—अनवरत शिक्षा की व्यवस्था . Provision of Continuation Education—**उपरिअंकित समस्या का समाधान तभी हो सकता है, जब प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-प्राप्त सब व्यक्तियों के लिए अनवरत शिक्षा की व्यवस्था की जाय। इस शिक्षा के अनेक रूप होने चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार उगमे लाभान्वित हो सकें। इस तथ्य को ध्यान में रक्खकर, “कोटारो कमीशन” ने तीन ठोस सुझाव दिए हैं, यथा—

1. उद्योगी एवं व्यवसायी में गलत प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-प्राप्त कर्मचारियों के लिए सब प्रकार की शिक्षा-मंथ्याओं में सामंजस्य के समय अल्पकालीन शिक्षा (Part Time Education) की व्यवस्था की जाय और उनको यह शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवकाश दिया जाय।
2. उक्त कर्मचारियों को प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पत्राचार-पाठ्यक्रमों (Correspondence Courses) का आयोजन किया जाय।
3. उक्त कर्मचारियों की व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training) देने के लिए प्राविधिक मंथ्याओं के वर्कशॉप्स और प्रयोगशालाओं का छुट्टियों के दिनों में प्रयोग किया जाय।

**भारत-भारत—अल्पकालीन शिक्षा का कार्यक्रम आरम्भ कर चुकी है।** हमने अतिरिक्त, अनवरत शिक्षा के लिए “पाँचवीं संवत्सरीय योजना” में अग्रणी

कार्यक्रमों का सूत्रपात किया जायगा<sup>1</sup> :—(1) अल्पकालीन एवं अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education) के कार्यक्रमों का विस्तार; (2) विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों (Special Training Programmes) का संचालन; और (3) अल्प अवधि के एवं अभिनवन पाठ्यक्रमों (Short-Term & Refresher Courses) का आयोजन। इन सभी कार्यक्रमों का प्रयोजन औद्योगिक एवं व्यावसायिक केन्द्रों के प्राविधिक कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि करना है। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए “पाँचवीं पंचवर्षीय योजना” में कहा गया है :—“उद्योगों को अपने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उनको अपने कर्मचारियों की श्रेष्ठतर प्राविधिक कुशलता प्राप्त करने में सहायता देनी चाहिए।”

“The industry would need to recognise their responsibility to help its employees acquire higher technical competence.”—*Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 203.

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Write a critical note on the progress of Technical and Vocational Education in India during the Five-Year Plans.  
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
2. Discuss the present position of Technical and Vocational Education in India and summarize briefly the recommendations of the Kothari Commission, 1966 for vocationalising education in the country.  
भारतवर्ष में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए, तथा देश में शिक्षा के व्यावसायीकरण विषयक कोठारी समिशन, 1966 द्वारा की गयी सिफारिशों का संक्षिप्त सारांश लिखिए।
3. “The development of Technical and Vocational Education has been one of the major achievements in the Post-independent period of India.” Comment.  
What have been the recommendations of the Mudaliar Commission and of the Kothari Commission thereafter for vocationalizing education in the country?  
“भारत में स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् की अवधि में प्रौद्योगिक तथा

1. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 203.

व्यावसायिक शिक्षा का विकास यही उपलब्धियों में से एक रहा है।” इस कथन की विवेचना कीजिए।

देश में शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए मुदालिखर आयोग तथा उसके उपरान्त कोटारी आयोग की क्या सिफारिशें रही हैं ?

4. What are the main handicaps responsible for the slow pace of progress in the sphere of technical education in India ? Suggest ways for its rapid expansion in the right direction.

भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मन्द प्रगति के लिए उत्तरदायी प्रमुख खराबों क्या हैं ? उचित दिशा में इसके शीघ्र विस्तार के लिए सुझाव दीजिए।

5. The large-scale industrialization which India is undergoing has necessitated reconstruction of its technical and engineering education. Discuss briefly the efforts of the States and the Central Government since 1947 to meet this situation.

जिम बड़े पैमाने पर भारत का औद्योगीकरण हो रहा है, उसके कारण उसकी तकनीकी और इंजीनियरी-शिक्षा का पुनर्निर्माण आवश्यक हो गया है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा सन् 1947 से अब तक किए गए प्रयासों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

## 29

### स्त्री-शिक्षा

#### WOMEN'S EDUCATION

"The question of the education of children cannot be solved unless efforts are made simultaneously to solve the women's education."—M. K. Gandhi.

#### विषय-प्रवेश

"देवि, मां, सहचरि, प्राण"—भारतीय परम्परा में नारी के इतने रूप बताये हैं, कविवर पन्त ने। पर क्या पुरुष ने नारी के इन रूपों का सम्मान करके, उसकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की है? इसका उत्तर सुनिए स्वामी विवेकानन्द से :—  
"स्त्रियों को संदेव असहायता और दूसरों पर दासवत् निर्भरता की शिक्षा दी गई है।"

"Women have all the time been trained in helplessness and servile dependence on others."—Swami Vivekananda : *Complete Works*, Part VII, p. 41.

यह शिक्षा देकर ही पुरुष—युगों से नारी पर शासन करता आ रहा है। उसने सहस्रों वर्षों से नारी को सरस्वती की बंदना से विमुख रखा है और उसे ज्ञान के आलोक से बाहर धसीट कर अज्ञानता से आवृत रखने में ही अपने कर्त्तव्यों की इतिथी गमभी है। तभी से नारी, विवशता की जजीर में जकड़ी हुई, अपनी शिक्षा की बात जोड़ रही थी। आज इस जजीर की कड़ियां चटख-चटख कर टूट रही हैं। नारी, घर की चहारदीवारी के अन्दर घट-घुट कर जिन्दगी के दिन काटने वाली, बेपट्टी-निगरी घूँघट की गुड़िया नहीं है। आज वह शिक्षित महिला के रूप में बाह्य जगत् में प्रवेश कर रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेप में पुरुष से होड़ ले रही है।

यह सब क्यों और कैसे हुआ ? स्त्री-शिक्षा की तत्पौर शुरु में क्यों थी ? वह क्यों बिगड़ी और बिगड़ने के बाद क्यों और क्यों बन रही है ? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, स्त्री-शिक्षा के इतिहास पर गहरा ध्यान आवश्यक है । आइए हम इसकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं ।

### प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा

वैदिक काल में घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, आर्यवी, गङ्गुलता आदि के गमान अनेक विदुषी महिनाएँ थी । यह हम बात का प्रमाण है कि उनकी पुरखों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था । किन्तु, उनके लिए पृथक् शिक्षागृहों की व्यवस्था नहीं थी । हाँ, गृह-शिक्षा का प्रचलन अवश्य था । गङ्गुलता ने कव्य के आश्रय में और आर्यवी ने वात्सकी के आश्रय में शिक्षा प्राप्त की थी । वस्तुतः उस युग में परिवार ही स्त्रियों की शिक्षा का केन्द्र था, जहाँ उनकी अपने पिता, पति या कुल-गुरु से शिक्षा प्राप्त होती थी । इन तथ्यों के आधार पर एल० मुक्तार्थ ने यह मत प्रकट किया है — “यह सम्भव है कि इस युग में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी । किन्तु, इस विषय में हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है ।”

“It is just possible that no organised system of education as such did exist for women at this period. Anyway we have no definite proof to assert one way or the other”—A. Mukherjee *Problems of Administration of Education in India*, p. 259

वैदिक काल के अन्तिम चरण में लगभग 200 ई० पू० में बार्हस्पत्य की विवाह की आयु को कम करके, उनकी शिक्षा-प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया गया । परन्तु, महारमा बुद्ध ने स्त्रियों को मगध में प्रवेश करने की आज्ञा देकर, उनकी शिक्षा को नव जोचन प्रदान किया । ए० एल० अल्तेकर के अनुसार :— “स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा ने स्त्री-शिक्षा को परोक्ष प्रोत्साहन प्रदान किया ।”

“The permission given to women to enter the order gave a fairly good impetus to the cause of female education”—A. S. Altekar *Education in Ancient India* p. 233

किन्तु, यह आज्ञा केवल बुद्धीय और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों की दी गई थी । अतः केवल उन्हीं की शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, न कि बहुसंख्य सामान्य स्त्रियों की शिक्षा की ।

### मुस्लिम भारत में स्त्री-शिक्षा

मुस्लिम युग में सिद्धुखों और मुननमतों—दोनों में परदा-प्रथा एवं वात-विराट का प्रचलन था । अतः छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त, जेब तक स्त्रियों का विज्ञान गमूना शिक्षा-प्राप्ति के लाभ में बंजित रहा । हमने स्पष्ट है कि मुस्लिम काल में

स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई। जहाँ तक अल्प आयु की बालिकाओं का प्रश्न आ, वे भी केवल कुछ ही वर्षों की प्राथमिक शिक्षा से लाभान्वित होती थीं। इस अंदर्भ में मजूमदार, रायचौधरी व दत्त ने लिखा है<sup>1</sup> :—“प्रायः प्रत्येक मसजिद से अलग मकतब होता था, जिसमें आस-पास के बालक और बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते थे। शाही घराने और धनी अमीरों की लड़कियाँ अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त करती थीं और हम यह मान सकते हैं कि हिन्दुओं में मध्य वर्ग के व्यक्तियों की लड़कियाँ स्कूलों में लड़कों के साथ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती थीं और उनमें से कुछ को धार्मिक साहित्य का ज्ञान था।”

शाही घरानों की अनेक विदुषी नारियों के नाम आज भी इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं; यथा :—रजिया सुल्ताना, चांद सुल्ताना, गुलबदन बेगम, जेबुन्निसा बेगम आदि। हिन्दू विदुषियों में रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, इन्दौर की शासिका अहिल्याबाई और शिवाजी की माता जीजाबाई के नाम स्त्री-शिक्षा के जगत् में आज भी स्मरणीय हैं।

### ब्रिटिश भारत में स्त्री-शिक्षा

ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में—ईस्ट इंडिया कम्पनी ने स्त्री-शिक्षा को अनावश्यक समझकर, उसकी ओर रचनात्मक भी ध्यान नहीं दिया। सम्भवतः इसका कारण यह था कि उसे अपने प्रशासकीय एवं व्यावसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, स्त्री-शिक्षा के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी था। सन् 1838 में विलियम एडम ने स्त्री-शिक्षा का वर्णन करते हुए लिखा :—“शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थाएँ केवल पुरुषों के लाभार्थ हैं और समस्त महिला-जगत् को विधिपूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया है।”

“All the established native institutions exist for the benefit of the male sex only, and the whole of the female sex is systematically consigned to ignorance.”—William Adam. A. N. Basu : *Adam's Report*, p. 452.

कम्पनी के शासन-काल में बालिका-विद्यालयों की स्थापना—मिशनरियों और सरकारी एवं गैर-सरकारी मनुष्यों के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप हुई। सन् 1851 में मिशनरियों द्वारा 371 बालिका-विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या 11,193 थी।<sup>2</sup> व्यक्तिगत प्रयासों के

1. Majumdar, Raychaudhuri & Datta : *An Advanced History of India*, p. 579.
2. M. A. Sherring : *The History of Protestant Missions*, pp. 442-47.

फलस्वरूप स्थापित किए जाने वाले बालिका-विद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध बनरस का बैथून स्कूल था। इसका गिताग्याप्त सन् 1849 में सरकार के कानून-मस्य, जे० ई० डी० बैथून (J. E. D. Bethune) के द्वारा किया गया था।

1854 से 1882 तक—सन् 1854 के “बुड के आदेश-पत्र” में सर्वप्रथम स्त्री-शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया और कहा गया कि इस शिक्षा का प्रसार करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जायें। परिणामतः नव-निमित्त शिक्षा-विभागों ने अनेक स्थानों पर बालिकाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की। इस प्रकार कम्पनी द्वारा उपेक्षित स्त्री-शिक्षा की प्रगति आरम्भ हुई। सन् 1882 में 2,697 बालिका-विद्यालय थे और उनमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या 1,27,066 थी।

1882 से 1902 तक—सन् 1882 के “हंटर कमीशन” ने तत्कालीन स्त्री-शिक्षा की दयनीय दशा से द्रवित होकर, जोरदार शब्दों में यह सिफारिश की :—  
“स्त्री-शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है।”

“Female education is still in an extremely backward condition and needs to be fostered in every legitimate way.”—*Hunter Commission Report*.

“कमीशन” के विचारों ने न केवल सरकार को बल्कि जनता को भी स्त्री-शिक्षा का प्रसार करने की प्रेरणा प्रदान की। ए० ए० मुकर्जी के अनुसार<sup>1</sup> :—  
जनता एवं सरकार के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा की अति द्रुत गति से प्रगति हुई और 1902 में सब प्रकार के बालिका-विद्यालयों की संख्या 6,107 हो गई।

1902 से 1921 तक—19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आरम्भ होने वाले पुनरुत्थान के कारण स्त्री-शिक्षा की प्रभूत प्रगति हुई। किन्तु, इस प्रगति में महिलाओं की अपेक्षा सरकार और पुरुषों ने अधिक योग दिया। विद्या-प्रेमी साईं कर्जन ने स्त्री-शिक्षा की पतित अवस्था से दुःख होकर, उसका उत्थान करने का सक्ल किया। अतः उसने 1904 का “शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव” पारित करवा के स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक धन व्यय किया, आदर्श बालिका-विद्यालयों की स्थापना की और अध्यापिका-प्रशिक्षण का प्रावधान किया। 1913 के “शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव” की सिफारिशों के फलस्वरूप स्त्री-शिक्षा की प्रत्येक स्तर पर प्रगति हुई।

1. S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 242.



ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी जैसी अने सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं ने स्त्री-शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया। 1904 श्रीमती एनी बेसेन्ट ने बनारस में “सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल” का निर्माण किया। 1916 में कर्वे और भंडारकर के प्रयासों के परिणामस्वरूप पूना में महिला विश्व विद्यालय (एस० एन० डी० टी०) का शिलान्यास हुआ। 1916 में दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हाइज मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई।

उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप स्त्री-शिक्षा का प्रलापनीय विस्तार हुआ सन् 1921 में बालिकाओं की कुल शिक्षा-संख्याएँ 26,144 थीं और उनमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या 14 लाख से अधिक थी।

1921 से 1947 तक—इस अवधि में अग्रंशित कारणों के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई :—(1) महात्मा गांधी के “राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण स्त्रियों में उत्पन्न होने वाली जागृति; (2) सन् 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद्” (National Council of Women) की स्थापना; (3) 192 में आयोजित किए जाने वाले “अखिल-भारतीय स्त्री-शिक्षा-सम्मेलन” (All-India Women's Education Conference) द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता की माँग; (4) द्वंद्व शासन की अवधि में भारतीय शिक्षा पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण; (5) प्रान्तीय स्वशासन की अवधि में स्त्री-शिक्षा का प्रोत्साहन; (6) द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में विभिन्न प्रशासकीय एवं व्यावसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं की माँग; और (7) “शारदा अधिनियम” द्वारा बाल-विवाह का निषेध।

उल्लिखित कारणों ने स्त्री-शिक्षा के विकास में अपूर्व योग दिया। 194 में स्त्री-शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं की संख्या 28,196 थी और उनमें अध्ययन कर वाली बालिकाओं की 42,97,785।<sup>1</sup>

### स्वतंत्र भारत में स्त्री-शिक्षा

स्वतंत्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन रहा है। जिन बन्धनों में वह बँधी हुई थी, वे जनैः-जनैः ढीले होते जा रहे हैं। जिस स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया गया था, वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है। उस सम्बन्ध में पुरुषों का दृष्टिकोण बदल रहा है, उनकी मान्यताएँ भी बदल रही हैं। “भारतीय संविधान” ने भी नारी को समरक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है : “राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म-स्थान व इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।”

“The State shall not discriminate against any citizen o

grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or an-  
them"—Article 15 of the Constitution of Free India.

उपरोक्त सभी तथ्यों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में नारी-जाति ने कदम बढ़ाया है। उसने अपने वास्तविक महत्त्व को जानना और पहचानना शुरू कर दिया है और वह अपनी गिरी हुई दशा के प्रति सचेत हुई है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत—नारी-जागरण का युग बन गया है और स्त्री-शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विलक्षण प्रगति परिलक्षित हो रही है। हम इस प्रगति से सम्बन्धित तथ्यों एवं परिणामों का विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत यथास्थान वर्णन कर रहे हैं; यथा :—

### राष्ट्रीय महिला-शिक्षा-समिति, 1958 'National Committee on Women's Education, 1958

भारत-सरकार ने सन् 1958 में स्त्री-शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय महिला-शिक्षा-समिति" की नियुक्ति की। इस समिति को 'देशमुख समिति' (Deshmukh Committee) भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य—स्त्री-शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। "समिति" ने जनवरी, 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें निम्नांकित सुझाव दिए :—

1. केन्द्रीय सरकार को स्त्री-शिक्षा से कुछ समय के लिए एक विनिश्चित समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसका प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
2. केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री-शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।
3. केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों के लिए स्त्री-शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए और उनको इस नीति का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए।
4. सामाजिक क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार का प्रसार-मन्त्रालय इस कार्य का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
5. पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान विषमता को परामर्श समाप्त करके, दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित की जानी चाहिए।
6. केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय को स्त्री-शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने

के लिए "राष्ट्रीय महिला शिक्षा-परिपद्" नामक एक पृथक् इकाई की दृष्टि करनी चाहिए।

7. राज्यों में स्त्री-शिक्षा का प्रसार करने के लिए "बालिका एवं स्त्री-शिक्षा की राज्य-परिषदों" (State Councils of Education for Girls & Women) का निर्माण किया जाना चाहिए।
8. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

### राष्ट्रीय महिला-शिक्षा-परिपद्, 1959

National Council of Women's Education, 1959

"देशमुख समिति" की सिफारिश को स्वीकार करके, केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने 1959 में "राष्ट्रीय महिला-शिक्षा-परिपद्" का निर्माण किया। 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया। इस समय इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 27 सदस्य हैं। उनके मुख्य कार्य अधोलिखित हैं<sup>1</sup> :—

1. विद्यालय-स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।
2. उक्त क्षेत्रों में बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रमों एवं प्राथमिकताओं के विषय में सुझाव देना।
3. उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए उपायों का सुझाव देना।
4. बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए उचित उपायों का सुझाव देना।
5. उक्त शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रमों की प्रगति पर दृष्टि रखना।
6. उक्त शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विचार-मोष्ठियों का आयोजन किए जाने की सिफारिश करना।

### हंसा मेहता समिति, 1962

Hansa Mehta Committee, 1962

"राष्ट्रीय महिला-शिक्षा-परिपद्" का एक मुख्य कार्य—विद्यालय-स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना है। इन समस्याओं में सर्वप्रमुख यह है :— क्या विद्यालय-स्तर पर बालकों एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रमों

1. S. N. Mukerji : *op. cit.*, pp. 250-251.

में अन्तर होना चाहिए ? “परिषद्” ने इस समस्या पर विचार करने के लिए धीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसे “हंसा मेहता समिति” कहा जाता है। इस समिति के सदस्यों ने पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् दो सुझाव प्रस्तुत किए; यथा :—

पहला सुझाव यह था कि विद्यालय-स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अन्तर नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में करने तर्क प्रस्तुत करते हुए, “समिति” ने कहा :—हम भारत में जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे समाज में शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्तिगत क्षमताओं, रुझानों एवं रुचियों से होना चाहिए, जिनका लिंग में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। “अतः ऐसे समाज में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में अन्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

“There would, therefore, be no need in such a society to differentiate curricula on the basis of sex.”—*Hansa Mehra Committee Report*.

दूसरा सुझाव यह था कि भारत में अभी जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अतः इस अन्तःजातीय अवधि में हमें पुरुषों एवं स्त्रियों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यों के भेदों के आधार पर बालकों एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। किन्तु, पाठ्यक्रमों की विभिन्नता को नए समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। “अतः ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जो पुरुषों एवं स्त्रियों के वर्तमान अन्तर को स्थायी या अधिक उग्र बना दे।”

“Care should be taken to see that no step is taken which will tend to perpetuate or intensify the existing difference.”—*Hansa Mehra Committee Report*.

### कोठारी कमिशन व स्त्री-शिक्षा

“कोठारी कमिशन” ने स्त्री-शिक्षा के समस्त पक्षों के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हम आपको इन सुझावों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, यथा :—

1. प्राथमिक शिक्षा—“कोठारी कमिशन” ने बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अधोनिहित सुझाव दिए हैं। —

1. भारत संविधान द्वारा प्रतिपादित सभ्य की प्राप्ति के लिए बालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयाग किए जायें।
2. बालिकाओं की बालकों के प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए जगमग का निर्माण किया जाय।

3. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयत्न किया जाय ।
4. बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें, लेखन-सामग्री एवं वस्त्र देकर, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।
5. 11-13 वय-वर्ग की बालिकाओं के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

2. माध्यमिक शिक्षा—“कोठारी कमीशन” ने बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नांकित विचार प्रकट किए हैं<sup>1</sup> :—

1. बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों की स्थापना की जाय । जहाँ यह सम्भव नहीं है, वहाँ के विद्यालयों में कुछ अध्यापिकाओं की अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जाय ।
2. बालिकाओं को छात्रावास एवं यातायात के साधनों की सुविधाएँ प्रदान की जायें ।
3. बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों और अल्पकालीन एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजनाएँ आरम्भ की जायें ।

3. उच्च शिक्षा—“कोठारी कमीशन” ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा के बारे में अग्रान्वित सुझाव अक्षरबद्ध किए हैं<sup>2</sup> :—

1. छात्रवृत्तियों एवं मितव्ययी छात्रावासों की व्यवस्था करके, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।
2. बालिकाओं के लिए पूर्व-स्नातक स्तर पर पृथक् कॉलेजों का निर्माण किया जाय ।
3. बालिकाओं को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र आदि पाठ्य-विषयों में से चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाय ।
4. शिक्षा, गृह-विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य-विषयों को विकसित करके, उनको बालिकाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाय ।
5. बालिकाओं को व्यावसायिक प्रबन्ध एवं प्रणामन (Business Management & Administration) की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाय ।
6. एक या दो विश्वविद्यालयों में स्त्री-शिक्षा की समस्याओं का समाधान ढोने के लिए अनुसंधान-केंद्रों की स्थापना की जाय ।

1. *Kothari Commission Report*, pp. 175-176.

2. *Kothari Commission Report*, p. 651.

4. सामान्य सुभाव—“कोठारी समीक्षण” ने स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सुभाव भी दिए हैं; यथा<sup>1</sup> :—

1. स्त्री-शिक्षा के मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए टोंग और निश्चित कदम उठाए जायें।
2. स्त्रियों एवं पुरुषों की शिक्षा के बीच में जो सार्द उत्तर हो गई है, उसे यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जायें।
3. स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा की देखभाल करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य-स्तरी पर उपयुक्त प्रशासनिक संस्थानों का गृहण किया जाय।
4. स्त्रियों के लिए अशकालीन रोजगारों की व्यवस्था की जाय, ताकि वे पारिवारिक बाधों में निवृत्त होने के पश्चात् अपनी शिक्षा से अधिक लाभ उठा सकें।
5. अविवर्हित स्त्रियों के लिए पूर्णकालीन रोजगारों की व्यवस्था की जाय।

### पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री-शिक्षा

पहली योजना—इस योजना में स्त्रियों की पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने की सब सुविधाएँ प्रदान की गईं। क्योंकि भारत की अधिकांश स्त्रियों को किशोरावस्था में ही अपनी शिक्षा स्थगित करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें प्राइवेट रूप में उच्च परीक्षाएँ पास करने के अवसर दिए गए। यह व्यवस्था भी की गई कि माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय-शिक्षा इस प्रकार की हो कि वह स्त्रियों को किसी गृहयोग या हस्तशिल्प की शिक्षा दे सके।<sup>2</sup>

दूसरी योजना—इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार एवं अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए आरम्भ की जाने वाली योजनाओं में उल्लेख प्रगति हुई। केन्द्रीय सरकार ने अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वृत्ति देकर, बालिकाओं की उपस्थिति के लिए छात्रवर्षियाँ देकर एवं अध्यापिकाओं के लिए बिना किराए के क्वार्टरों का निर्माण करके विशेष रूप में सामील श्रेष्ठों में, सहायता दी। स्त्री-शिक्षा में सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार का परामर्श देने के लिए “राष्ट्रीय महिला-शिक्षा परिषद” का निर्माण किया गया।

तीसरी योजना—केन्द्रीय सरकार ने परामर्श के अनुसार प्रत्येक राज्य के शिक्षा-विभाग में एक उप-निदेशक अथवा मुख्य निदेशक नियुक्त किया गया, जिसे बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा में सम्बन्धित कार्यक्रमों का निर्माण करने और उनको कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया। बालिकाओं और प्रौढ महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया। इस बात का प्रयत्न कि

1. Kothari Commission Report, pp 138-139

2. पहली पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ 308

गया कि बालिकाओं की हॉकी, क्रिकेट, फुटबाल, बालीबॉल आदि आधुनिक खेलों में रुचि उत्पन्न हो। शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा के बीच की दूरी को कम करने की चेष्टा की गई।<sup>1</sup>

**चौथी योजना**—पहली तीन योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा-सुविधाओं में विस्तार करने के प्रयत्न किए गए। फिर भी, बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में पर्याप्त दूरी थी। विद्यालय-स्तर पर इस दूरी को और अधिक कम करने के लिए चौथी योजना में अग्रलिखित उपाय किए गए :—अध्यापिकाओं के लिए व्टाटर्स की व्यवस्था; ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं के लिए विशेष भत्ता; विद्यालय-माताओं (School Mothers) की नियुक्ति; बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण; और अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति करने के लिए वयस्क महिलाओं के लानार्थ संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का संचालन।<sup>2</sup>

**पाँचवीं योजना**—यद्यपि बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार किया जा चुका है, फिर भी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उनकी और बालकों की शिक्षा में पर्याप्त दूरी है। इस दूरी का मुख्य कारण है—अध्यापिकाओं का अभाव। पाँचवीं योजना में इस अभाव की पूर्ति के लिए बालिकाओं को इस शत पर छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी कि वे शिक्षा समाप्त करने के बाद शिक्षण-व्यवसाय को ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त, कम शिक्षित स्त्रियों एवं बालिकाओं के लिए संक्षिप्त एवं पत्राचार-पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की जायगी।<sup>3</sup>

### बालिका-शिक्षा का विस्तार<sup>4</sup>

नामांकन लाखों में

वर्ष	कक्षा I-V		कक्षा VI-VIII		कक्षा IX-XI, XII	
	नामांकन		नामांकन		नामांकन	
	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
1950-51	137.7	53.8	25.9	5.3	10.2	1.9
1955-56	175.3	76.4	34.2	8.7	16.5	3.3
1960-61	235.9	114.0	50.7	16.3	24.7	5.6
1965-66	321.8	182.9	76.8	28.5	40.8	12.0
1968-69	342.1	201.8	97.1	33.4	50.9	17.4
1973-74	393.5	244.0	104.9	45.4	61.6	23.4
संग्रहित						

1. *The Hindustan Times*, May 4, 1966.
2. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक स्वरूप), p. 224.
3. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 197.
4. *Draft Fifth Five-Year Plan*, Vol. II, p. 197.

## समस्याएँ व उनके समाधान Problems & Their Solutions

स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। के० मटराजन के अनुसार :—“यदि सौ वर्ष पूर्व मरने वाला व्यक्ति आज फिर जीवित हो जाय, तो उसे आश्चर्यचकित करने वाला सर्वप्रथम एवं सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन—स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।”

“If a person who died a hundred years ago came to life today, the first and the most important change that would strike him is the revolution in the position of women.”—K. Natrajan's Article in the *Indian Social Reformer*, September 25, 1937.

स्त्रियों की स्थिति में इस क्रांतिकारी परिवर्तन के बावजूद अत्याचारी एवं अप्रगतिशील विचारों वाला पुरुष-वर्ग, नारी की महत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वह नारी-शिक्षा का विरोध करके अट्टहास करता है, भले ही उसकी मन्तान निरक्षर रह जाय। वह अपनी ऋद्धिवादिता, धार्मिक संकीर्णता एवं नारी-जाति पर शासन करने की विराटान में विरामन में मिलने वाली घारणा का परिणाम करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही प्रजातन्त्र की मार्गों की पूर्ति न हो और भले ही भारत, स्त्रियों की अशिक्षा के कारण प्रगति की दौड़ में अन्य देशों में पीछे रह जाय।

हिन्दु सरकार और प्रगतिशील विचारों वाला पुरुष-वर्ग—नारी के साथ है। सरकार ने मविधान के माध्यम से स्त्रियों को समस्त अधिकारों का भजन कर दिया है। प्रगतिशील विचारों वाला पुरुष-वर्ग, राष्ट्रीय जीवन में स्त्री-शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करके, इसके तीव्र प्रचार का प्रयत्न समर्थक है। यही कारण है कि स्वतन्त्र भारत में समस्त क्रांतियों के मध्य जनान्दियों में जोषित नारी ने एक जबरदस्त अंग-टार्ई ली है। वह शिक्षा के समान अवसरों का उपभोग करके, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक—सभी क्षेत्रों में सक्रिय है और पुरुष को चकित कर रही है। फिर भी, वस्तुस्थिति यह गह्रादन पेन करती है कि स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा दबे पाँव, रेंगती हुई आगे बढ़ रही है। इसके क्या कारण हैं? ऐसी कौन-सी भागी अड़चनें और गम्भीर समस्याएँ हैं, जिनके कारण यह शिक्षा गहज और मुनम नहीं बन पाई है? इनमें से सभी का ध्यान आकृष्ट करने वाली समस्याएँ दृष्टव्य हैं; यथा :—

1. समस्या—**ऋद्धिवादिता एवं प्रसंगिकता . Conservatism & Religiosity**—आधुनिक युग, विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अनेक ऋद्धिवादी विचारों, धार्मिक अंधविश्वासों एवं प्राचीन परम्पराओं को सह गह करके गारहीन मिट कर दिया है। हिन्दु, भगवान्ता के रूप में पढ़े हुए करोड़ों भारतीय (हिन्दू और मुसलमान) अब भी



उन्में चिपटे हुए हैं।<sup>1</sup> वे अब भी प्राचीन विचारों एवं विश्वासों का पोषण एवं समर्थन करते हैं। फलस्वरूप, स्त्री-शिक्षा अपने सीमित एवं संकुचित दायरे में बाहर नहीं निकल पा रही है। हम अपने इस कथन की पुष्टि में निम्नांकित 4 ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं।

पहला, प्राचीन परम्पराओं का अनुसरण करने में गर्व का अनुभव करने वाले अनेक हिन्दू एवं मुसलमान—पदा-प्रदा में अब भी विश्वास करने हैं और उसका परित्याग करने में अपनी और अपने कुल की मानहानि समझते हैं। अतः वे अधिक आयु की बालिकाओं के विद्यालय जाने पर कठोर प्रतिबंध लगा देते हैं।

दूसरा, अंधविश्वासों के जिक्र में अकड़े हुए, अनेक हिन्दू एवं मुसलमान—बालिकाओं का अल्प आयु में विवाह करना अपना परम पुनीत कर्तव्य समझते हैं। अतः वे “भारतीय वयस्कता-अधिनियम” (Indian Majority Act) एवं “बाल-विवाह-निषेध-अधिनियम” (Child Marriage Restraint Act) का उल्लंघन करके भी अपने कर्तव्य का पालन करने में संकोच नहीं करते हैं। परिणामतः बालिकाओं का शिक्षा में वंचित रह जाना स्वाभाविक है।

तीसरा, रुढ़िवादी विचारों के सीमित दायरे में निबध्न करने वाले अनेक हिन्दू एवं मुसलमान—स्त्री का उचित स्थान, घर के अन्दर मानते हैं। अतः उनके मतानुसार, बालिकाओं को घरेलू हिमाय-किताब के लिए थोड़ा-सा अक्षर-ज्ञान ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, उनकी धारणा है कि बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् समानता एवं स्वतंत्रता का दावा करने लगती हैं। उनके विचार में यह स्त्री-धर्म की प्रतिकूलता एवं चरित्रहीनता का सूचक है। अतः वे बालिकाओं की शिक्षा के विरोधी हैं।

चौथा—धार्मिक कट्टरता की भावना ने मरुबोर अनेक हिन्दू एवं मुसलमान—रजोदर्शन में पूर्व कन्याओं का विवाह करना धार्मिक कृत्य मानते हैं। ऐसे हिन्दुओं या मूढों के इस नीति-चरित्र में अविचल विश्वास है :—“कन्या के दशवें वर्ष में पहुँचने पर जो पिता उसका विवाह नहीं करता है, वह प्रति मास उसका लाल रज पीता है।”<sup>2</sup>

उसी प्रकार, धार्मिक निद्वान्तों में अटिग आस्था रखने वाले मुसलमान—रजोदर्शन में पूर्व ही अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए व्याकुल रहते हैं,

1. भारत की 54 करोड़ जनसंख्या में से केवल 16 करोड़ व्यक्ति साक्षर हैं।  
—India, 1954, p. 51.
2. ‘प्राप्ते तु दशमे वर्षे यस्तु कन्या न यच्छति।  
नामि-नामि रजस्तस्या. पिता पिबति नोदितम् ॥

क्योंकि वे प्रतिमाग के रजोदशन को "गुनाह" मानते हैं।<sup>1</sup> दसवें वर्ष में या रजोदशन से पूर्व विवाह हो जाने पर बालिकाओं की शिक्षा का समुक्त अनिवार्य है।

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—रूढ़िवादियों एवं धर्मांधता जिन कारणों को जग्य देकर बालिका-शिक्षा के मार्ग में अवरोध उपस्थित कर रही है, उनका समाधान करने के लिए अनेक आचारहारिक सुझाव दिए जा सकते हैं; यथा :—

1. अशिक्षित पुरुषों एवं स्त्रियों में श्रौद्ध-शिक्षा का अधिकतम प्रसार।
  2. स्त्री-शिक्षा के राष्ट्रीय, सामाजिक एवं सामुहिक महत्त्व का व्यापक प्रचार।
  3. स्त्री-शिक्षा के प्रति भारतीयों के मनुष्यन दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए देशव्यापी आन्दोलन।
  4. भारतीयों के बाल-विवाह एवं विवाह की अनुचित धारणा में परिवर्तन करने के लिए चलचित्रों का प्रदर्शन।
  5. भारतीयों की रूढ़िवादियों एवं धार्मिक बट्टरता में आमूल परिवर्तन करने के लिए व्याख्यातों, प्रदर्शनियों एवं सामाजिक समारोहों का आयोजन।
  6. भारतीयों को स्त्री-शिक्षा के प्रति अपनी उदासीनता एवं विरक्तता का परित्याग करने में सहायता देने के लिए आचारजवाणी द्वारा विविध नार्यत्रयों का सूत्रपात।
  7. स्त्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार की दृढ़ता में मीन। स्मृतिपत्र वासी के शब्दों में — 'भारत में स्त्रियों के निश्चय, दृढ़ता, सद्यधिक एवं कार्य-कुशलता पर ही उनकी शिक्षा का भविष्य निर्भर है।'
- "Upon their determination, compactness, good sense and efficiency rests the future of education of women in India"—Muriel Wasi in *Women of India*, Edited by Tara Ali Beg
8. पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर जाग्रत करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन। महारमा गांधी के शब्दों में — "हिन्दी-ज-हिन्दी प्रकार पुरुष—पुर्णों से स्त्री पर शासन करता आ रहा है और इसलिये स्त्री में निम्न होने की भावना का विकास हो गया है।"

1. "Every month of menstruation is regarded as a period of *Gunah* by Muslims."

"Somehow or other man has dominated woman for ages past, and so woman has developed an inferiority complex."—Mahatma Gandhi's Article in the *Harijan*, dated February 25, 1940.

2. समस्या—अपव्यय व अवरोधन : Wastage & Stagnation—बालिका-शिक्षा की एक पर्याप्त गम्भीर समस्या—अपव्यय एवं अवरोधन की है। "कोठारी कमीशन" के अनुसार<sup>1</sup> :—सन् 1958-59 में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली 100 बालिकाओं में से केवल 37.5 प्रतिशत 1961-62 में चौथी कक्षा में पहुँचीं और पाँचवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 100 बालिकाओं में से केवल 66.2 प्रतिशत मानवीं कक्षा में पहुँचीं।<sup>2</sup>

बालकों की तुलना में बालिकाओं में अपव्यय एवं अवरोधन अधिक है। उसके कारणों का उल्लेख करता, "रूढ़िवादिता एवं वर्मान्विता" के अन्तर्गत वर्णित कारणों की पुनरावृत्ति करना होगा। किन्तु, विषय की क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए, ये कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं :—(1) पर्दा प्रथा एवं बाल-विवाह का प्रचलन; (2) प्राचीन विचारों एवं परम्पराओं में विश्वास, (3) धार्मिक सिद्धान्तों एवं अन्धविश्वासों में आस्था; और (4) बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण।

उक्त कारणों के फलस्वरूप बालिकाएँ अपने को विवशता में इतना डलभा दृष्टा पाती हैं कि हादिक अभिलाषा के बावजूद भी वे बालकों के समान दीर्घकाल तक ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाती हैं। यदि कुछ बालिकाओं को माध्यम सहारा दे देता है, तो वे कुछ वर्षों की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं। परन्तु, उनके उपरान्त उनकी शिक्षा पर उनके अनुदार अभिभावकों या तंगदिल पतियों के द्वारा स्थायी अंकुश लगा दिया जाता है।

उल्लिखित कारणों के अनिरिक्त, बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के कुछ कारण और भी हैं; यथा :—

1. बालिका-विद्यालयों का अभाव।
2. यानायात के माधवों का अभाव।
3. दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली का प्रचलन।
4. विद्यालयों में नीरस शिक्षण-विधियों का प्रयोग।
5. बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का अभाव।

समाधान—कुछ सुझाव : Some Suggestions—बालिकाओं की शिक्षा में

1. *Kothari Commission Report*, p. 158.
2. *Kothari Commission Report*, pp. 156 & 158.

विद्यमान अपभ्यष एवं अवरोधन का उन्मूलन करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं :—

- 1 परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन ।
2. बालिका-विद्यालयों की संख्या में वृद्धि ।
- 3 मृत्याङ्कन की नवीन विधियों का प्रयोग ।
- 4 निम्न कक्षाओं में खेल-विधि का प्रयोग ।
- 5 शिक्षण की प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग ।
- 6 बालिकाओं के लिए निर्देशन की व्यवस्था ।
- 7 बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण ।
- 8 बालिकाओं के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था ।
- 9 बालिकाओं के लिए यातायात के साधनों की सुविधा ।
- 10 बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सन्तुष्टिपूर्ण दृष्टिकोण में परिवर्तन ।

3 समस्या—*Defective Curriculum*—बालिका एवं स्त्री-शिक्षा की सर्वप्रधान समस्या—दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की है । पाठ्यक्रम दोषपूर्ण क्यों है ? इसका कारण डा० एस० एन० मुकर्जी का अग्रलिखित वाक्य में पढ़िए — “भारत के भारत में बालिकाओं की शिक्षा—बालकों की ही जाने वाली शिक्षा की प्रतिलिपि मात्र है । यथायत बालकों के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं को अन्य किसी बात की शिक्षा देने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है ।”

“Education of girls in India today is a mere replica of the education given to boys. Practically, there is no special provision for teaching the girls anything outside the boys' curriculum.”—Dr S. N. Mukerji : *Education in India, Today & Tomorrow*, p. 264

वस्तुतः शिक्षा के सब स्तरों पर बालकों एवं बालिकाओं के समान पाठ्यविषय हैं । हाँ, इतना अवश्य है कि बालिकाओं की मनीष, चित्रकला, दृष्टिविज्ञान जैसे कुछ बालिक विषयों का अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध है । हिन्दु, इस्लाम तो बालकों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा—भारतीयों की घोर निन्दा का लक्ष्य बन गई है । शिक्षा की निन्दा के अनेक कारण हैं, यथा—

- 1 यह शिक्षा—ज्ञान-प्रधान, पुस्तक-प्रधान एवं अभ्यासवृत्तिपूर्ण होने के कारण बालिकाओं में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में अनुकूलन करने की सामर्थ्य का विकास नहीं करती है ।
- 2 यह शिक्षा—बालिकाओं को गार्हस्थ्य जीवन के लिए तैयार नहीं करती है और उनका पारिवारिक उत्तरदायित्वों को बहन करने की —

3. यह शिक्षा—बालिकाओं को पाश्चात्य स्त्री-जाति का अध्यानुकरण करने का पाठ पढ़ाकर, उनका प्राचीन भारतीय आदर्श से सम्बन्ध-विच्छेद कर देती है।
4. यह शिक्षा—बालिकाओं को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से विमुख करके, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की उपासिका बना देती है।
5. यह शिक्षा—बालिकाओं के मस्तिष्क पर जो पाश्चात्य मुलम्मा चढ़ा देती है, उसके फलस्वरूप भारतीय परिवार का अति त्वरित गति से विघटन हो रहा है।
6. यह शिक्षा—बालिकाओं को सब प्रकार के कृत्रिम साधनों, रंग-विरंगे वस्त्रों एवं आभूषणों से सज-सँवर कर कामिनी या मोहिनी बनने में और पुरुषों को रिझाने में दक्ष बना देती है, जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज का नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है।
7. यह शिक्षा—महिलाओं में बेरोजगारी की समस्या को उतना ही विकराल रूप प्रदान करती जा रही है, जितना कि वह पुरुषों की बेरोजगारी की समस्या को प्रदान कर चुकी है। मनुष्यों के लिए बेरोजगारी हानिकारक है, पर स्त्रियों के लिए भयंकर है।<sup>1</sup>
8. "राधाकृष्णन् कमोशन" के अनुसार :—"स्त्री-शिक्षा की वर्तमान पद्धति, पुरुषों की आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण उनको दैनिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्रदान नहीं करती है।"
9. "विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग" के अनुसार :—"स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन लिए पूर्णतया निरर्थक है, जो उनको व्यतीत करना है। यह शिक्षा न केवल अपव्यय है, वरन् बहुधा उनकी निश्चित असमर्थता का कारण है।"

"Women's present education is entirely irrelevant to the life they have to lead. It is not only a waste, but often a definite disability."—*University Education Commission.*

समाधान—विभिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था : *Provision of Different Curriculum*—हमने प्रचलित पाठ्यक्रम से होने वाली जिन हानियों का वर्णन किया है, उनकी देखते हुए सामान्य निष्कर्ष यही निकलता है कि बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। किन्तु, इन निष्कर्षों के सम्बन्ध में शिक्षा-विशेषज्ञों एवं राजनीतिज्ञों के विचारों में विभिन्नता है। इस प्रकार के कुछ विचार आपके अवलोकनायें प्रस्तुत किए जा रहे हैं; यथा :—

1. "हंता मेहता समिति" ने बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम की सिफारिश करते हुए लिखा :—"जनतन्त्रिय एवं समाजवादी समाज में शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्तिगत क्षमताओं अभिवृत्तियों एवं रवियों से होता चाहिए, जिनका निगम कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः ऐसे समाज में शिक्षा के आधार पर पाठ्यक्रमों में अन्तर करने की आवश्यकता नहीं है।"

2. 'कोठारी कमिशन' ने "हमा मेहता समिति" की सिफारिशों में सहमत होते हुए लिखा :—"हम इन सिफारिशों से सहमत हैं। यही कारण है कि हमने कदा दस के अन्त तक सब छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया है।"

"We agree with these recommendations. This is why we have proposed a common curriculum for all the students till the end of class X"—*Kothari Commission Report*, p. 208.

3. भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कन्या महाविद्यालय, जलन्धर के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम की आवश्यकता का संकेत देते हुए कहा :—"प्रकृति और ईश्वर ने मानव-जाति को स्थिर बनाए रखने का भार स्त्री पर रखा है और मनुष्य का मूलन पुण्य नहीं, अपितु स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। इस गौरवपूर्ण तथा विनिष्ट दायित्व को स्त्रियाँ और समाज को समझ लेना चाहिए और चाहे जो भी शिक्षा-पद्धति हो, उसमें इसकी गरिमा या अनिवार्यता को ध्यान में रखना चाहिए।"

4. महात्मा गांधी ने बालकों एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए लिखा :—"जबकि आधार रूप में पुण्य एवं स्त्री—दोनों समान हैं, यह भी शिष्टकूल मत्व है कि शरीर की बनावट में दोनों में महान् भेद है। अतः दोनों के वसंध्य भी भिन्न होने चाहिए। इस तर्क के आधार पर महात्मा गांधी ने धोषित किया :—"पुद्ग्यों एवं स्त्रियों की शिक्षा में उसी प्रकार का अन्तर किया जाना आवश्यक है, जैसा कि स्वयं प्रकृति माता ने उनमें किया है।"

"There is need for similar distinction between the education of males and females as has been made between them by Mother Nature."—*M K Gandhi True Education*, p. 31

उप्युक्त विरोधी विचारों पर टीका-टिप्पणी करना, हमारे अधिकार क्षेत्र में बाहर की बात है। हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि हमें "हमा मेहता समिति"

1. राजेन्द्र प्रसाद (संश्लिष्ट) भारतीय शिक्षा, पृ० 60.

2. Mahatma Gandhi's Article in the *Harjan*, dated 25th of February, 1940.

और "कोठारी कमीशन" के विचारों में यथार्थता की एक भी झलक नहीं मिलती है, भले ही उनके सदस्य—भारत एवं विदेशों के अग्रगण्य शिक्षा-विशारद क्यों न हों। इसका कारण यह है कि सभी दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों एवं शरीरवैज्ञानिकों ने स्त्रियों एवं पुरुषों के कार्यों, रुचियों, रुझानों, क्षमताओं आदि में स्पष्ट अन्तर किया है। इस अन्तर के कारण बालकों एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम अनिवार्यतः भिन्न होने चाहिए।

अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए। हम भारत के वर्तमान आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक परिवर्तनों के संदर्भ में उनके विषय में कुछ सुझाव दे रहे हैं; यथा :—

1. प्राथमिक स्तर—अनेक बालिकाएँ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की, प्राथमिक स्तर के बाद अपना अध्ययन स्थगित कर देती हैं। अतः इस स्तर पर सामान्य शिक्षा के साथ-साथ अग्रकित विषयों को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए :—सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कोई स्थानीय हस्त-शिल्प। ये सभी कार्य उनके भावी जीवन में लाभप्रद सिद्ध होंगे और आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता भी देंगे।

2. माध्यमिक स्तर—अनेक बालिकाएँ, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों की, माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त करती हैं। अतः इस स्तर के पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ ऐसे विषय भी होने चाहिए, जो उनको सुमाता एवं सुगृहिणी के रूप में प्रशिक्षण देने के अलावा उनको किसी व्यवसाय के लिए भी तैयार करें। इस दृष्टि से उनके पाठ्यक्रम में संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प, गृह-विज्ञान, सिलाई-कटाई, भोजनशास्त्र, शिशु-संरक्षण एवं पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करके, वे आवश्यकता पड़ने पर किसी सामाजिक संस्था या औद्योगिक केन्द्र में कार्य करके धन का अर्जन कर सकती हैं।

3. उच्च स्तर—स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करके, महिलाएँ सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासकीय आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों से प्रतिद्वन्द्विता करके, अपने को उनके समवक्ष सिद्ध कर रही हैं। यही कारण है कि सभी क्षेत्रों में उनकी भाग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः जैसा कि "राधाकृष्णन् कमीशन" ने लिखा है :—“स्त्रियों की शिक्षा विशेषतया परिवारों की दृष्टि से उनको अच्छी माता, अध्यापिका, डाक्टर और नर्स बनाने के लिए व्यावहारिक होनी चाहिए।”

“The education of women should give them a practical bias, especially from the point of view of families, for making them good mothers, teachers, doctors, and nurses.”—*Radhakrishnan Commission*.

"गणपतृष्णन् कमीशन" के कथन को ध्यान में रखते हुए, हम कह सकते हैं कि बालिकाओं के लिए बालकों के समान सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही, उनके पारिवारिक जीवन को सुगम बनाने के लिए, उनके पाठ्यक्रम में अव्यक्त विषयों का समावेश किया जाना चाहिए :—मानव-जन्म, गृह-प्रबंध, गृह-परिचर्या और गृह-अर्थशास्त्र।

4. समस्या—दोषपूर्ण प्रशासन . Faulty Administration—दोषपूर्ण शिक्षा-प्रशासन के कारण स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार में भारी अड़चन का अनुभव किया जा रहा है। प्रशासन दोषपूर्ण इसलिए है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, बिहार, बंगाल, हैदराबाद जैसे कुछ राज्यों की टोंडर गेज मर राज्यों में स्त्री-शिक्षा के प्रशासन का भार—पुरुष अधिकारियों पर है। पुरुष होने के कारण न तो उनकी स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा में विशेष रूचि होती है और न उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी। अतः वे स्त्रियों एवं बालिकाओं के लिए उचित प्रकार की शिक्षा को व्यवस्था करके, उसका वांछनीय विस्तार करने में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

समाधान—प्रशासन में सुधार Reform in Administration—उपरोक्त समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षा-प्रशासन में सुधार किया जाना अनिवार्य है। इस मध्य को प्राप्ति नहीं हो सकती है, जब स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रशासन का भार—पुरुषों के वजह से स्त्रियों को भीत जाय। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा-विभाग में एक शिक्षा-उपसचिव की ओर उन्हें प्रशासन-कार्य में सहायता देने के लिए विद्वान्-निरीक्षकों एवं उप-निरीक्षकों की नियुक्ति हो जाय। स्त्रियाँ होने के कारण उनसे स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा में रूचि होगी। साथ ही, वे उनसे विशिष्ट आवश्यकताओं को भली-भाँति समझेंगी। अतः वे उनकी शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का निर्माण करेंगी और उनको सफलतापूर्वक क्रियान्वित करके, स्त्री एवं बालिका-शिक्षा के विस्तार में योग देंगी।

5. समस्या—सरकार की उपेक्षा Indifference of Government—सरकार द्वारा स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति, उमर लिए अस्मिता गढ़ रही है। हमारा इस कथन को धुनौनी नहीं होना चाहती है कि सरकार की अतिनी रूचि बालकों की शिक्षा में है, उमर बढ़े गुना कम बालिकाओं की शिक्षा में है। इसके वजह यह बहुत अधिक नम्रमय होगा कि सरकार—बालकों की शिक्षा को प्राथमिक और बालिकाओं की शिक्षा को निम्नस्थान करती है।

स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सरकार के इस रुबंद का निन्द करने के लिए प्रयाणों का अभाव नहीं है। यदि सरकार को अभी इस में अभी रुबंद की आवश्यकता पड़ेगी है तो वह इस कमी का ध्यान रखी की शिक्षा के वजह बालिकाओं



की शिक्षा में करती है। उदाहरणार्थ—भारत-चीन-युद्ध के समय जब देश में आर्थिक संकट की घोषणा की गई, तब सब राज्यों ने उस संकट का सामना करने के लिए बालिका-शिक्षा के व्यय में कटौती की और यह कटौती 15 लाख रुपये की थी।<sup>1</sup>

किन्ती हास्यास्पद नीति है। एक ओर तो सरकार—बालिका-शिक्षा के प्रसार को प्राथमिकताओं की सूची में स्थान देती है, और दूसरी ओर उस पर व्यय किए जाने वाले धन में कमी करती है। सरकार की इस हास्यास्पद नीति पर व्यंग्य करने हुए, डा० मुकर्जी ने लिखा है :—‘यह निश्चय रूप से कुनियोजित प्राथमिकताओं का दुःख उदाहरण है।’

‘This is surely a sad case of badly placed priorities.’—Dr. S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 250.

समाधान—सरकार की नीति में परिवर्तन : Change in Government's Policy—स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा का समुचित प्रसार तभी हो सकता है, जब सरकार उसकी उपेक्षा करने की अपनी नीति में परिवर्तन करे। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी और बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार में अदृश्य उत्साह एवं निस्स्वायं भावना में नहीं कुछ आवेगी, तब तक देश के समाज-सेवकों या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा हिमानय पवन ने कुमारी अन्तरीप तक फैली हुई स्त्री-शिक्षा का और शिक्षा के अभाव के कारण सदियों से बेमुर्खी में पड़ी हुई नारी-जाति का उद्धार किया जाना असम्भव होगा। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार अपनी स्त्री-शिक्षा-सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करे और उसका प्रसार, विकास एवं विस्तार करने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो।

यह परिवर्तन इसलिए और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने माध्यम में महिलाओं की पुरस्कारों के समान समस्त अधिकारों को प्रदान करने की उद्घोषणा की है। इस उद्घोषणा को साकार रूप प्रदान करना, सरकार का राजनीतिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करना, सरकार का नरम लक्ष्य होना चाहिए, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर अपनी स्त्री-शिक्षा-सम्बन्धी नीति का निर्माण करना चाहिए :—

1. बालकों एवं बालिकाओं की संख्या के अनुपात में बालिका (एवं स्त्री) शिक्षा के लिए धनराशि निर्धारित करना।
2. उक्त धनराशि को केवल बालिका-शिक्षा पर व्यय करना और उसमें कमी न करना।
3. उक्त धनराशि का बालिका-शिक्षा के समस्त स्तरों के लिए आवश्यकता-नुसार विभाजन करना।

6. समस्या—अध्यापिकाओं का अभाव : Dearth of Women Teachers—  
 "पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अनुसार :—"अध्यापिकाओं की अपर्याप्त पूर्ति की  
 समस्या, बालिकाओं के कम नामांकन का प्रधान कारण है।"

"The problem of the inadequate supply of women teachers  
 is a major reason for the low enrolment of girls."—Draft Fifth  
 Five-Year Plan, Vol II, p. 197.

अध्यापिकाओं की अपर्याप्त पूर्ति अर्थात् उनका अभाव प्रारम्भ में ही है और  
 गिरी के सब स्तरों पर है। हम अध्यापकों की तुलना में उनके अभाव को नीचे की  
 तालिका में प्रदर्शित कर रहे हैं —

तालिका—अध्यापिकाएँ 1950-1965

विवरण	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
निम्न प्राथमिक स्कूल	18%	20%	21%	21%
उच्चतर प्राथमिक स्कूल	18%	19%	32%	37%
माध्यमिक स्कूल	19%	23%	27%	28%
व्यावसायिक स्कूल	23%	22%	17%	17%
व्यावसायिक कॉलेज	7%	8%	12%	11%
उच्च गिरी-संस्थाएँ	10%	13%	16%	17%

अध्यापिकाओं के अभाव के अनेक कारण हैं। स्त्रियों में शिक्षा का कम प्रचार  
 के कारण शिक्षित स्त्रियों का अभाव है। जो स्त्रियाँ शिक्षित भी हैं, उनमें से  
 नेक दृष्टि होने हुए भी नौकरी नहीं कर पाती हैं। इसका कारण यह है कि उनके  
 ना-पिता, सास-ससुर या पति, उनसे नौकरी करवाना अपनी पारिवारिक या  
 राजीव प्रतिष्ठा के प्रतिद्वन्द्व समझते हैं।

अधिकतर स्त्रियाँ उसी नगर या ग्राम में नौकरी चाहती हैं, जिनमें वे निवास  
 हैं। इसका एक कारण यह है कि अन्य स्थानों में उनकी सुरक्षा, आश्रय आदि  
 विभागों प्राप्त होना कठिन होता है। दूसरा कारण यह है कि यदि वे अविराति  
 उनके अभिभावक उनको अन्य स्थानों में नौकरी करने की अनुमति नहीं

अध्यापिकाओं के रूप में कार्य करने वाली कुछ स्त्रियाँ, विवाह के पश्चात्  
 एक भभटो में उत्तम जाने के कारण नौकरी छोड़ देती हैं। कुछ स्त्रियाँ अपने

पतियों के साथ किसी ऐसे स्थान में पहुँच जाती हैं, जहाँ के विचित्र वातावरण वाले विद्यालयों में उनकी कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी हैं, जो उत्तम आर्थिक स्थिति का वर प्राप्त हो जाने पर अल्प वेतन वाले अध्यापिका के पद पर कार्य करना अपना अपमान समझती हैं।

प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का विशेष रूप से अभाव है। इसका कारण यह है कि स्त्री-प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल बड़े नगरों में है। अतः आर्थिक या किसी अन्य कठिनाई के कारण उन नगरों से दूर निवास करने वाली अनेक स्त्रियाँ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अध्यापिकाओं का अधिक अभाव है, क्योंकि ग्रामों में जीवन-यापन की सामान्य वस्तुओं की पूर्ति में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामों में चिकित्सा, मनोरंजन, सुरक्षित आवास आदि की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

**समाधान—अध्यापिकाओं की पूर्ति : Supply of Women Teachers—**  
अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, सरकार पर है और वह अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति सजग है। वह अध्यापिकाओं के अभाव को दूर करने के लिए अग्रानिकित उपायों का प्रयोग कर रही है :—

1. अध्यापिकाओं के लिए बिना किराए के क्वार्टरों का निर्माण।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ता।
3. वयस्क महिलाओं को अध्यापिकाओं के रूप में तैयार करने के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का संचालन।
4. बालिकाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ देने का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम "दूसरी योजना" में आरम्भ किया गया था और "पाँचवीं योजना" में भी जारी रहेगा। "पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अनुसार<sup>1</sup> :—“अध्यापिकाओं के अभाव का समाधान करने के लिए स्थानीय बालिकाओं को उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इस शर्त पर छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी कि वे शिक्षण-व्यवसाय को ग्रहण करें।”

अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नवीन उपाय प्रशंसनीय हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त, कुछ अन्य उपाय भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं; यथा :—

1. स्त्री-प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या में वृद्धि।
2. अध्यापिकाओं के वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि।
3. अध्यापिकाओं के लिए अल्पकालीन रोज़गारों की व्यवस्था।

4. स्थानीय शिक्षित महिलाओं की अध्यापन-कार्य करने के लिए प्रोत्साहन ।
5. अध्यापकों की शिक्षित पत्नियों की शिक्षण-अवसरों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन ।
6. शिक्षण-अवसरों में पदोन्नति करने की दृष्टि रखने वाली अधिक आयु की महिलाओं की आयु-सीमा से मुक्ति ।
7. वयस्क महिलाओं की अधिक शिक्षित बनाने एवं प्रशिक्षित करने के लिए सक्षिप्त एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों की सुविधाओं में विस्तार ।
8. कम शिक्षित एवं अशिक्षित स्त्रियों की नियुक्ति और उनको अपनी शैक्षिक योग्यताओं की मूढ़ि करने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता ।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Describe briefly the progress of women's education in India under the Five-Year Plans  
पञ्चवर्षीय योजनाओं की अवधि में भारत में स्त्री-शिक्षा की प्रगति का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
2. What recommendations have been made by the Education Commission (1966) regarding women's education ? How far can they help in improving the condition of women's education ?  
स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में "शिक्षा-आयोग" (1966) ने क्या सिफारिशें की हैं ? वे स्त्री-शिक्षा की दशा में सुधार करने में कहीं तक सहायता कर सकती हैं ?
3. What are the main problems of women's education in India ? Point out satisfactory solutions of these problems.  
भारत में महिलाओं की शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं ? इन समस्याओं के संतोषजनक समाधान बताइए ।
4. "Differentiation of curricula for boys and girls is unnecessary" Comment.  
"बच्चों एवं बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रमों में भिन्न अन्तर आवश्यक है ।" इस कथन का विवेचन कीजिए ।

पतियों के साथ किसी ऐसे स्थान में पहुँच जाती हैं, जहाँ के विचित्र वातावरण वाले विद्यालयों में उनकी कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी हैं, जो उत्तम आर्थिक स्थिति का घर प्राप्त हो जाने पर अल्प वेतन वाले अध्यापिका के पद पर कार्य करना अपना अपमान समझती हैं।

प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का विशेष रूप से अभाव है। इसका कारण यह है कि स्त्री-प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल बड़े नगरों में है। अतः आर्थिक या किसी अन्य कठिनाई के कारण उन नगरों से दूर निवास करने वाली अनेक स्त्रियाँ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अध्यापिकाओं का अधिक अभाव है, क्योंकि ग्रामों में जीवन-यापन की सामान्य वस्तुओं की पूर्ति में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामों में चिकित्सा, मनोरंजन, सुरक्षित आवास आदि की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

समाधान—अध्यापिकाओं की पूर्ति : Supply of Women Teachers—  
अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, सरकार पर है और वह अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति सजग है। वह अध्यापिकाओं के अभाव को दूर करने के लिए अग्रिम उपायों का प्रयोग कर रही है :—

1. अध्यापिकाओं के लिए बिना किराए के क्वार्टरों का निर्माण।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ता।
3. वयस्क महिलाओं को अध्यापिकाओं के रूप में तैयार करने के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का संचालन।
4. बालिकाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ देने का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम “दूसरी योजना” में आरम्भ किया गया था और “पाँचवीं योजना” में भी जारी रहेगा। “पाँचवीं पंचवर्षीय योजना” के अनुसार<sup>1</sup> :—“अध्यापिकाओं के अभाव का समाधान करने के लिए स्थानीय बालिकाओं को उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इस शर्त पर छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी कि वे शिक्षण-व्यवसाय को ग्रहण करें।”

अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नवीन उपाय प्रशंसनीय हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त, कुछ अन्य उपाय भी उपयोगी मिल सकते हैं; यथा :—

1. स्त्री-प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या में वृद्धि।
2. अध्यापिकाओं के वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि।
3. अध्यापिकाओं के लिए अल्पकालीन रोजगारों की व्यवस्था।

4. स्थानीय शिक्षित महिलाओं को अध्यापन-कार्य करने के लिए प्रोत्साहन ।
5. अध्यापकों की शिक्षित पत्नियों को शिक्षण-अवसरों में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन ।
6. शिक्षण-अवसरों में पदार्पण करने की दृष्टि रखने वाली अधिक आयु की महिलाओं को आयु-सीमा से मुक्ति ।
7. वयस्क महिलाओं को अधिक शिक्षित बनाने एवं प्रशिक्षित करने के लिए संक्षिप्त एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों की सुरक्षाओं में विस्तार ।
8. कम शिक्षित एवं अशिक्षित स्त्रियों को नियुक्ति और उनकी अपनी शैक्षिक योग्यताओं की वृद्धि करने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता ।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Describe briefly the progress of women's education in India under the Five-Year Plans  
पञ्चवर्षीय योजनाओं की अवधि में भारत में स्त्री-शिक्षा की प्रगति का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
2. What recommendations have been made by the Education Commission (1966) regarding women's education ? How far can they help in improving the condition of women's education ?  
स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में "शिक्षा-आयोग" (1966) ने क्या सिफारिशें की हैं ? वे स्त्री-शिक्षा की दशा में सुधार करने में कहीं तक सहायता कर सकती हैं ?
3. What are the main problems of women's education in India ? Point out satisfactory solutions of these problems.  
भारत में महिलाओं की शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं ? इन समस्याओं के संतोषजनक समाधान बताइए ।
4. "Differentiation of curricula for boys and girls is unnecessary." Comment.  
"बच्चों एवं युवकों के लिए पाठ्यक्रमों में अंतर अनावश्यक है ।" इस कथन का विवेचन कीजिए ।

# 30

## अपव्यय व अवरोधन WASTAGE & STAGNATION

"The extent of wastage and stagnation in our system of education is very large."—*Kothari Commission Report.*

### विषय-प्रवेश

जब कोई बालक (या बालिका) किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश करता है, तब हम उममे दो बातों की आशा करते हैं। पहली, वह अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात् ही संस्था को छोड़ेगा और इसलिए वह धन, शक्ति एवं समय के अपव्यय का कारण नहीं बनेगा। दूसरी, वह प्रति वर्ष, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और इसलिए उसकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। किन्तु, अनेक बालक हमारी आशा को पूर्ण नहीं करते हैं। उनमें से कुछ अपनी शिक्षा को पूर्ण करने से पहले ही संस्था को छोड़ देते हैं और कुछ परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। इन दोनों बातों का परिणाम होता है—अपव्यय एवं अवरोधन। ये शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मिलते हैं और अति विज्ञान मात्रा में। "कोठारी कमिशन" के अनुसार<sup>1</sup> :—"हमारी शिक्षा-व्यवस्था में अपव्यय एवं अवरोधन की मात्रा अत्यन्त विशाल है।"

अपव्यय एवं अवरोधन के इन संक्षिप्त परिचय के पश्चात्, हम उनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं।

### अपव्यय का अर्थ व परिभाषा

#### Meaning & Definition of Wastage

प्रत्येक स्तर पर शिक्षा की एक निश्चित अवधि है। उदाहरणार्थ—निम्न

1. *Kothari Commission Report*, p. 154.

प्राथमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष की ओर उच्चतर प्राथमिक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष की है। जो छात्र इन स्तरों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमें यह भावना होती है कि वे निश्चित अवधि में अपनी शिक्षा समाप्त कर लेंगे। किन्तु, अनेक छात्र निश्चित अवधि में पहुँचे ही किसी कारणवश अपना अध्ययन स्थगित कर देते हैं। ऐसे छात्रों की शिक्षा अधूरी रह जाती है और इसलिए उन पर घा, शक्ति और समय का अपव्यय होता है।

प्राथमिक शिक्षा में होने वाले "अपव्यय" का उल्लेख सर्वप्रथम "हर्टीग समिति" ने किया। उसने यह विचार प्रकट किया कि जो छात्र प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं करते हैं, वे साक्षर नहीं हो पाते हैं। अतः उन पर घन, शक्ति एवं समय का अपव्यय होता है। अपने इस विचार के आधार पर "हर्टीग समिति" ने "अपव्यय" का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा—“अपव्यय से हमारा अभिप्राय है—प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पहले बच्चों की विद्यालय की शिक्षा से हटा लेना।”

“By wastage we mean the premature withdrawal of children from school at any stage before the completion of the primary course”—*Hartog Committee Report*, p. 47

### अवरोधन का अर्थ व परिभाषा

#### Meaning & Definition of Stagnation

हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि छात्रों में यह भावना होती है कि वे प्रत्येक स्तर की शिक्षा को एक निश्चित अवधि में समाप्त कर लेंगे। किन्तु, अनेक छात्र किसी कारणवश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष व्यतीत करते हैं। ऐसे छात्रों की शिक्षा में “स्थिरता”, “निर्दिष्टता” या “अवरोधन” उत्पन्न हो जाता है।

प्राथमिक शिक्षा में होने वाले “अवरोधन” का भी उल्लेख सर्वप्रथम “हर्टीग समिति” ने ही किया और इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा—“अवरोधन से हमारा अभिप्राय है—किसी बच्चे का किसी निम्न कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका जाना।”

“By stagnation we mean the retention in a lower class of a child for a period of more than one year”—*Hartog Committee Report*, p. 47.

### अपव्यय व अवरोधन : स्वरूप व परिणाम

#### Wastage & Stagnation : Nature & Result

“अपव्यय” एवं “अवरोधन”—एक से दो पढ़ते हैं और दोनों के ही कारण छात्र-संख्या में निरन्तर ह्रास होता जाता है। इन दोनों में “अवरोधन”—एक



या ह्रास का अधिक शक्तिशाली कारण है। "हर्टाग समिति" के अनुसार :—“हमें अपनी स्त्रियों से ज्ञात हुआ है कि अपव्यय अधिक शक्तिशाली कारण है।”

“Our enquiries show that by far the more important factor is wastage”—*Hartog Committee Report*, p. 47.

“अपव्यय” एवं “अवरोधन” के भयावह परिणाम के चित्र को सन् 1972 में शिक्षा-मन्त्री प्रोफ़ेसर नुरुल हसन ने इन शब्दों में अंकित किया<sup>1</sup> :—पिछले वर्षों में 100 बच्चों में से 80 ने कक्षा 1 में प्रवेश लिया। 11 वर्ष के होने पर उनमें से 40 ने पढ़ना छोड़ दिया। शेष 40 में से केवल 25 ने 14 वर्ष की आयु तक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। 17 वर्ष की आयु में उनकी संख्या घट कर 10 और 21 वर्ष की आयु में 2 रह गई। इस प्रकार, 100 बच्चों में से केवल 2 ने 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण की।

### अपव्यय व अवरोधन : कारण व उपचार

#### Wastage & Stagnation : Causes & Remedies

“कोठारी कमीशन” के शब्दों में :—“सिर-दर्द और बुखार के समान अपव्यय एवं अवरोधन स्वयं रोग नहीं हैं। वे वास्तव में शिक्षा-व्यवस्था के अन्य रोगों के लक्षण हैं।”

“Wastage and stagnation, like headache and fever, are not diseases in themselves : they are really symptoms of other diseases in the educational system.”—*Kothari Commission Report*, p. 161.

“कोठारी कमीशन” के कथन का अभिप्राय यह है कि “अपव्यय” एवं “अवरोधन” स्वयं दोष नहीं हैं बल्कि शिक्षा-व्यवस्था के दोषों के परिणाम हैं। हम इस अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिक शिक्षा में “अपव्यय” एवं “अवरोधन” के कारणों और उनके निवारण के उपायों का वर्णन कर रहे हैं; यथा :—

1. कारण—दोषपूर्ण प्रशासन : Faulty Administration—प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का पहला कारण—दोषपूर्ण प्रशासन है। इस प्रशासन का नार—स्थानीय संस्थाओं पर है, जो धनानाथ में ग्रस्त हैं। अतः उनका निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीन होना स्वाभाविक है। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में नार मुख्य दोष प्रकट हो गए हैं, जो अपव्यय एवं अवरोधन के लिए उत्तरदायी हैं।

पहला, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के अनुपात में शिक्षा-निरीक्षकों की संख्या अत्यन्त अल्प है। अतः वे अपने अधीन सब विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त, उनको यातायात, परिवहन, रात्रि-विश्राम

आदि की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। अतः वे दूर के विद्यालयों का, विशेष रूप से ग्राम-विद्यालयों का, नियमित निरीक्षण अपने सेवा-काल में सम्भवतः करी नहीं करते हैं। नियमित निरीक्षण न करने के कारण, वे अध्ययन एवं अवरोधन के कारणों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। अतः वे उनके निवारण के उपायों के बारे में करी गंभीर भी नहीं हैं।

दूसरा, कम आयु एवं कम योग्यता के बालकों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश मिल जाता है। फलस्वरूप, कक्षा में छोटे और बड़े, कम और अधिक मानसिक योग्यता वाले छात्र होते हैं। इनसे कक्षा के बालकों में होने वाली गमकता नष्ट हो जाती है। इसका कम आयु और कम योग्यता वाले बालकों पर बड़ा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है। वे या तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, या अपनी निम्नता से सज्जिन होकर शिक्षा की ओर से अपना मुँह मोड़ लेते हैं।

तीसरा, बालकों को प्रत्येक कक्षा में वर्ष में सिन्ही गमय भी प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। इनसे तो अनेक बालक अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप, वे वार्षिक परीक्षा में अग्रकन हो जाते हैं।

चौथा, बालकों की नियमित उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः वे स्वेच्छा से विद्योपाजन के लिए विद्यालय में करी-कभी आते हैं। इन प्रकार के बालक या तो घुरी गमति में पड़ कर पढ़ना छोड़ देने हैं या परीक्षा की एक से अधिक वर्ष में आराम से पास करते हैं।

उपचार—प्रशासन में सुधार : Reform in Administration—प्रस्तावित शिक्षा-प्रशासन में होने वाले अध्ययन एवं अवरोधन का निराकरण करने के लिए, उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जब स्थानीय तत्त्वार्थ-निष्ठाहित आचार्यों पर प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन की एवं निम्नलिखित नीति का निर्धारण करें :—

1. प्राथमिक विद्यालयों की गम्या के अनुपात में शिक्षा-निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय।
2. शिक्षा-निरीक्षकों को यातायात, परिवहन, रात्रि-विश्राम आदि की सुविधाएँ प्रदान की जायें।
3. विद्यालय-प्रवेश की आयु, गमय, योग्यता एवं उपस्थिति-दिनों के विषय में निम्नलिखित नियमों का निर्माण किया जाय और उनका कठोरतापूर्वक पालन किया जाय।

2. कारण—दोषपूर्ण पाठ्यक्रम : Defective Curriculum—प्राथमिक शिक्षा में अध्ययन एवं अवरोधन का दूसरा कारण—दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है। इन पाठ्यक्रम के दोषपूर्ण होने के पाँच मुख्य कारण हैं, यथा —

पहला, इस पाठ्यक्रम में विषयों की संख्या बहुत अधिक है। अतः अल्प आयु के बालकों एवं बालिकाओं के लिए उन सब का भली-भाँति अध्ययन करना असम्भव है।

दूसरा, यह पाठ्यक्रम, बालकों एवं बालिकाओं की रुचियों एवं आवश्यकताओं में किसी प्रकार का अन्तर नहीं करता है।

तीसरा, यह पाठ्यक्रम कठोर एवं एकमार्गीय है, क्योंकि ग्रामों एवं नगरों के सब बालकों एवं बालिकाओं को एक ही पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है।

चौथा, यह पाठ्यक्रम अरोचक एवं व्यावहारिक है, क्योंकि यह बालकों को “करके सीखने” (Learning by doing) का कोई अवसर प्रदान नहीं करता है।

पाँचवाँ, जो विद्यालय, वैज्ञानिक प्रकार के नहीं हैं, उनमें हस्तशिल्प की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः यह उनकी क्रियाशीलता की अपेक्षा करता है।

उक्त सभी कारणों के फलस्वरूप अनेक बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं और अनेक विद्या-देवी की आराधना की इतिश्री कर देते हैं।

**उपचार—पाठ्यक्रम में सुधार : Reform in Curriculum—**प्रचलित पाठ्यक्रम से होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन का निवारण करने के लिए, उसमें निम्नलिखित आधारों पर सुधार किया जाना आवश्यक है :—

1. पाठ्यक्रम में स्थानीय वातावरण एवं आवश्यकताओं के अनुसार विषयों को स्थान दिया जाय।
2. पाठ्यक्रम के वर्तमान विषयों में कमी की जाय या बालकों एवं बालिकाओं को अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता दी जाय।
3. पाठ्यक्रम को रोचक एवं व्यावहारिक बनाने के लिए, उसमें हस्तशिल्प, कार्य-अनुभव एवं सृजनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाय।
4. ग्रामों एवं नगरों और बालकों एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाय।

**3. कारण—दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली : Defective Examination System—**प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का तीसरा कारण—दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली है। के० जी० सैपटन के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से लगभग 40% परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं।<sup>1</sup>

छात्रों की इस विनाश संख्या की असफलता के लिए उत्तरदायी है—प्रचलित परीक्षा-प्रणाली, जो केवल उनकी स्मरण करने या रटने की शक्ति की कसौटी है और जो उनके सम्पूर्ण वर्ष के कार्य के प्रति कोई ध्यान नहीं देती है। यह सम्भव है कि वार्षिक परीक्षा के अवसर पर कुछ छात्र रोगग्रस्त हों या सम्भावित प्रश्नों को न रट

पाए हों। ये छात्र, वास्तव में, निरपराध होते हैं। फिर भी उनकी वास्तविक परीक्षा में अवरोध होने का अकारण दण्ड निवृत्त है।

उपचार—परीक्षा-प्रणाली में सुधार : *Reform in Examination System*—  
प्रचलित परीक्षा-प्रणाली से होने वाले अव्यय एवं अवरोधन का विनाश करने के लिए, उनमें अप्रतिष्ठित आधारों पर सुधार किया जाना आवश्यक है :—

1. निम्न प्राथमिक स्तर पर निर्मित परीक्षाओं के बजाय मौखिक परीक्षाओं एवं निरीक्षण विधियों (*Observation Techniques*) का प्रयोग किया जाय।
2. उच्चतर प्राथमिक स्तर पर निर्मित परीक्षाओं के साथ-साथ मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाय।
3. दोनों स्तरों पर प्रत्येक छात्र के सम्पूर्ण बर्तन के बारे में विवरण—  
अभिलेख-पत्र में रखा जाय और कक्षा-उन्नति के समय उसे विशेष महत्त्व दिया जाय।

4. कारण—विद्यालयों की निम्न क्वालिटी : *Low Quality of Schools*—  
प्राथमिक शिक्षा में अव्यय एवं अवरोधन का प्रमुख कारण है—विद्यालयों की निम्न क्वालिटी। “राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्” ने अपने एक सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों का जो अप्रतिष्ठित चित्र अंकित किया है, उसमें कर्तक बिन्दुओं का बाहुल्य है :—अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के उद्देश्यों और योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। उनमें परम्परागत एवं प्रभावहीन शिक्षण-विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनका शिक्षण-स्तर निम्न है। उनमें पूरा पाठ्यक्रम कभी समाप्त नहीं किया जाता है। उनके भवनों में स्थान का अभाव है और वे स्वस्थ वातावरण में निर्मित नहीं हैं। उनमें साहायक केबलों के दर्शन नहीं होते हैं। उनमें पाठ्यक्रम-महत्त्वपूर्ण विषयों का कभी आयोजन नहीं किया जाता है। उनमें वे अनेक एक शिक्षक वाले विद्यालय हैं।

इतनी निम्न क्वालिटी के विद्यालयों में यह आना करना अपर्याप्त है कि वे छात्रों की शैक्षिक एवं मानसिक वृद्धि में योग देंगे। इसके विपरीत, उनसे यह आशा करना अपर्याप्त नहीं है कि वे अव्यय एवं अवरोधन की दृष्टि में अपर्याप्त गहिराई देंगे।

उपचार—विद्यालयों का सुधार : *Improvement of Schools*—निम्न क्वालिटी के विद्यालयों से होने वाले अव्यय एवं अवरोधन का उन्मूलन करने के लिए, उनका सुधार किया जाना आवश्यक है। इस कार्य का उत्तरदायित्व स्वयं सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए और अप्रतिष्ठित विद्यालयों में सन्निधि पन उठाने चाहिए :—

1. NCERT : *Wastage & Stagnation in Primary & Middle Schools in India.*

शिक्षा के उपकरणों में वृद्धि, योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षण-विधियों का प्रयोग, शिक्षण-स्तर का उन्नयन, सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की समाप्ति, स्वस्थ वातावरण में उपयुक्त विद्यालय-भवनों का निर्माण, सहायक सेवाओं एवं पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, और एक शिक्षक वाले विद्यालयों की समाप्ति ।

आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व सरकार का ध्यान प्राथमिक विद्यालयों की निम्न कोटि के प्रति आकृष्ट हुआ था और उसने लिखित रूप में यह स्वीकार किया था<sup>1</sup> :—“एक अध्यापक वाले प्राथमिक विद्यालयों ने अपव्यय में अत्यधिक योग दिया है । विद्यालयों के अपूर्ण शिक्षा-उपकरण, अनुपयुक्त भवन और नीरस एवं उत्साहहीन वातावरण दुर्भाग्य से छात्रों को अध्ययन करते रहने के लिए प्रभावपूर्ण प्रेरणा प्रदान नहीं कर पाते हैं ।”

रोद का विषय है कि प्राथमिक विद्यालयों की शोचनीय दशा और उससे उत्पन्न होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन से भली-भाँति अवगत होते हुए भी, सरकार ने उनमें सुधार करने के लिए अभी तक कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाया है । जब तक सरकार अपने इस उत्तरदायित्व को हृदयंगम नहीं करेगी और उसे पूर्ण करके विद्यालयों को उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी, तब तक उन पर अपव्यय एवं अवरोधन का अखंड साम्राज्य स्थापित रहेगा ।

5. कारण—सामाजिक कुरीतियाँ : Social Evils—प्राथमिक शिक्षा में होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन का पाँचवाँ कारण—सामाजिक कुरीतियाँ हैं । इनका सम्बन्ध मुख्यतः बालिकाओं से है । भारतीय समाज को अपयश से निमज्जित करने वाली कुछ विश्व-विदित कुरीतियाँ हैं—पर्दा-प्रथा का प्रचलन, बाल-विवाह का बोलबाला और सह-शिक्षा का विरोध । इन कुरीतियों के कारण अधिक आयु की बालिकाओं के विद्यालय-गमन पर स्थायी अंकुश लगा दिया जाता है । इसका परिणाम होता है—अपव्यय ।

उपचार—सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति : Abolition of Social Evils—सामाजिक कुरीतियों से होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन को अदृश्य करने के लिए, इन कुरीतियों की समाप्ति अनिवार्य कर्तव्य है । इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दो उपाय विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं :—बालिका-शिक्षा के महत्त्व एवं आवश्यकता का व्यापक प्रचार और सामाजिक कुरीतियों को विमूर्छित करने के लिए नरकार, शिक्षित वर्ग एवं स्वयं स्त्रियों द्वारा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन । (अधिक जानकारी के लिए “स्त्री-शिक्षा” का अध्याय देखिए ।)

6. कारण—अनिभावकों की निर्धनता : Poverty of Guardians—प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का छठवाँ कारण—अनिभावकों की

नियंत्रता है। "कोठारी समीक्षण" के अनुसार<sup>1</sup> :—“प्राथमिक शिक्षा में होने वाले 65% अपक्षय का कारण इस बात के विवागियों की निर्धनता है।”

प्राथमिक शिक्षा निशुनर होने के कारण निर्धन भारतीय 6 से 9 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं यात्रिकाओं को विद्यालयों में इसलिए भेज देते हैं, ताकि वे घर पर रह कर कष्ट का कारण न बनें। किन्तु, जब बालक 9 या 10 वर्ष के हो जाते हैं, तब वे अपने अभिभावकों के कार्य में हाथ बँटा करने हैं या बहरी काम करके पन का अर्थन कर सकते हैं। जहाँ तक यात्रिकाओं का प्रश्न है, वे परेलू बावों में अपनी माता को महापत्ता दे सकती हैं। अतः जैसा कि “कोठारी समीक्षण” ने लिखा है :—जब बालक एवं यात्रिकाएँ 9 या 10 वर्ष के हो जाते हैं, तब उनको विद्यालयों से हटा लिया जाता है और इस प्रकार वे अपक्षय का कारण बनते हैं।<sup>2</sup>

उपचार—निर्धनता की समाप्ति . Abolition of Poverty—निर्धनता में होने वाले अपक्षय एवं अवरोधन का तोष करने के लिए जनता की निर्धनता की समाप्ति आवश्यक है। सरकार अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग है। वह जनता की निर्धनता का अन्त करने के लिए देश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास कर रही है और साधन-सहायों एवं कृषि-सम्बन्धी विभिन्न यन्त्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्राण-प्रण से भेंपटा कर रही है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों में यन्त्रों के निम्नतर बढ़ते हुए मूल्यों ने जनता की आर्थिक परेशानियों से साह्य देने के बजाय उनको उनके कर्मे में बहुत बुरी तरह से र्कोसा दिया है।

अतः सबसे पहली आवश्यकता यह है कि सरकार—यन्त्रों के मूल्यों में कमी करे, पर साथ ही जनता की आर्थिक कठिनाइयों में मुक्त करने के लिए ओछादिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करे। जब तक सरकार इन दोनों बावों को सम्पादित न कर ले, तब तक वह अपक्षय एवं अवरोधन की मात्रा में कमी करने के लिए “कोठारी समीक्षण” के अर्थात्त मुझाव का व्यावहारिक रूप में जारी रखे<sup>3</sup> :—“अन्तःकालीन अवधि में आर्थिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाय, ताकि छात्र शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ पन का भी अर्थन कर सकें।”

7. कारण—अभिभावकों की अशिक्षा Illiteracy of Guardians प्राथमिक शिक्षा में अपक्षय एवं अवरोधन का माननी कारण—अभिभावकों की अशिक्षा है। “राष्ट्रीय संश्लेष अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद्” ने अपने सर्वेक्षण व आलोचन पर लिखा है<sup>4</sup> :—“कृषी, अदिशी, गिलियों और विछरी एवं अरु” व। व। “अज्ञान

1. Kothari Commission Report, p 159

2. Kothari Commission Report, p 159

3. Kothari Commission Report, p 159

4. NCERT : op. cit.

शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है। अतः शिक्षित परिवारों के बच्चों की अपेक्षा उनके बच्चों की शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन बहुत अधिक है।

अशिक्षित होने के कारण अनिभावक न तो शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक महत्त्व को समझते हैं और न समझने की चेष्टा करते हैं। यदि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की कभी भूल भी कर देते हैं, तो यह ज्ञान होते ही वे उनको विद्यालय से पृथक् करके अपनी भूल को सुधार अवश्य लेते हैं। अपने इस अविवेकपूर्ण कार्य के द्वारा वे अपव्यय एवं अवरोधन के प्रकटीकरण को आमंत्रित करते हैं।

**उपचार—अभिभावकों की शिक्षा : Education of Guardians—**अनिभावकों की अशिक्षा से होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन को नष्ट करने के लिए, उनको शिक्षित किया जाना आवश्यक है। शिक्षित होकर ही, वे व्यक्ति एवं समाज के लिए शिक्षा की उपयोगिता का अनुभव कर सकते हैं। अतः अशिक्षित अभिभावकों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रौढ़-शालाओं, रात्रि-विद्यालयों एवं अल्प-कालीन शिक्षालयों का शीघ्रातिशीघ्र शिलान्यास किया जाना चाहिए।

**8. कारण—छात्रों की शारीरिक निर्वलता : Students' Physical Weakness—**प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अन्तिम कारण—छात्रों की शारीरिक निर्वलता है। यह तथ्य सर्वविदित है कि उनकी शारीरिक निर्वलता में अनुदिन वृद्धि हो रही है। विशुद्ध खाद्य-पदार्थों की विलुप्ति, पोष्टिक बाह्यार की अनुपलब्धि एवं विविध रोगों की व्याप्ति के कारण हमारे देश के निवासियों एवं नौनिहालों की शारीरिक शक्ति निरन्तर क्षीण होती चली जा रही है। जेम्स हेमिंग का कथन है :—“भारत के निवासियों की स्थायी अस्वस्थता के कारण देश की शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, उनमें से एक चौथाई, एक वर्ष की आयु से पूर्व और प्रति 10 बच्चों में से 4 बच्चे, पाँच वर्ष की आयु से पूर्व काल के माल में पहुँच जाते हैं। जन्म लेने वाले बच्चों में से आधे कभी भी दस वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच पाते हैं।”

उक्त कथन के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों की निर्वलता एवं अस्वस्थता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार के बालकों से ज्ञान-प्राप्ति के लिए परिश्रम की आशा करना निराधार है। परिश्रम न कर सकने के कारण उनका एक वर्ष का पाठ्यक्रम एक से अधिक का हो जाता है। यदि कुछ दुराग्रही बालक अपने निर्वल शरीर से जूझकर परिश्रम करते हैं, तो वे किसी ऐसे असाध्य रोग द्वारा नुक़्तमोर दिए जाते हैं कि वे अपने मरघट की बाट जोहने लगते हैं।

**उपचार—छात्रों की स्वास्थ्य-उन्नति : Improvement of Students' Health—**छात्रों की शारीरिक निर्वलता से होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की

साहस्रिया करने के लिए उनके स्वास्थ्य में उन्नति की जानी आवश्यक है। सभी छात्र—बालक और नवयुवक—देश की भावी सम्पत्ति हैं। वे ही देश की भावी गुरदा एवं उन्नति के आधार-स्तम्भ हैं। यही कारण है कि सगार ने अनेक देशों में विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालकों एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क बिरिया, पोष्टिक स्वल्पाहार आदि की अत्युत्तम व्यवस्था की है।

भारत की सरकार और जनता इन देशों के उत्कृष्ट उदाहरण का अनुसरण करके अपने छात्रों एवं छात्राओं की स्वास्थ्य-उन्नति कर सकती है और इस प्रकार उनकी दुर्यन्तता एवं अस्वस्थता से होने वाले अपभ्रंश एवं अवरोधन की प्रतीति भी घटनाएँ दूना सकती है।

### कोठारी कमिशन के अपभ्रंश व अवरोधन विषयक विचार Kothari Commission's Views on Wastage & Stagnation

अपभ्रंश व अवरोधन के कारण—“कोठारी कमिशन” ने प्राथमिक शिक्षा में होने वाले अपभ्रंश एवं अवरोधन के अप्रतिष्ठित कारण बताए हैं<sup>1</sup>—

1. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम।
2. दीर्घपूर्ण परीक्षा-प्रणाली।
3. कक्षाओं में बालकों की अत्यधिक संख्या।
4. प्रत्येक कक्षा में विभिन्न आयु के बालकों की उपस्थिति।
5. बालकों की अनिश्चित उपस्थिति।
6. बालकों को वर्ष में विगो समय की प्रवेश देने की पद्धति।
7. बालकों एवं विद्यार्थियों के पाठ्य-शिक्षा-नामों का अभाव।
8. शिक्षकों की शिक्षण-कार्य के लिए अपूर्ण तैयारी।
9. शिक्षकों में शैल-विधि का प्रयोग करने की अयोग्यता।
10. शिक्षकों में बालकों की प्रारम्भिक क्षमता में पड़ना निम्नता का अयोग्यता।

अपभ्रंश व अवरोधन-उन्मूलन के उपाय—“कोठारी कमिशन” ने अपभ्रंश एवं अवरोधन का उन्मूलन करने के लिए अप्रतिष्ठित उपाय बताए हैं<sup>2</sup>—

1. शैल-विधि का प्रयोग।
2. मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग।
3. पूर्ण-विद्यार्थ्य-शिक्षा की व्यवस्था।
4. छात्रों एवं छात्राओं की निर्देशन देने की व्यवस्था।
5. छात्रों एवं छात्राओं के लिए अन्तर्गत शैल-विधि की व्यवस्था।

1. Kothari Commission Report p. 1.

2. Kothari Commission Report pp. 157-161.



6. छात्रों एवं छात्राओं के प्रति व्यक्तिगत ध्यान ।
7. अभिभावकों की आर्थिक स्थिति में सुधार ।
8. निरक्षर अभिभावकों में प्रीढ़-शिक्षा का प्रसार ।
9. शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध ।
10. भारत के सब राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की समरूपता ।
11. प्राथमिक शिक्षा के व्यय की पूर्ति के लिए "स्थानीय कर" का आरोपण ।
12. हाई स्कूल पास एवं दो वर्ष का प्रशिक्षण-प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति ।
13. कक्षा 1 के अन्त में होने वाली परीक्षा की समाप्ति ।
14. कक्षा 1 और 2, या कक्षा 1, 2 और 3, या कक्षा 1, 2, 3 और 4 का शिक्षण की एक इकाई के रूप में संगठन ।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. "Wastage and stagnation in primary education in India still remain its major problems." Comment and suggest measures to overcome them.

"भारत में प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन अब भी प्रधान समस्याएँ हैं ।" समीक्षा कीजिए और उनको दूर करने के उपायों का सुझाव दीजिए ।

2. Point out the main causes of wastage and stagnation at the Primary Stage. What suggestions have been made by Kothari Commission to remove these causes ?

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन के मुख्य कारण बताइए । कोठारी आयोग ने इन कारणों का निराकरण करने के लिए किन उपायों को प्रस्तावित किया है ?

## विविध विषय

### MISCELLANEOUS TOPICS

#### 1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद् National Council of Educational Research & Training

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत की जनतन्त्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शिक्षा के समस्त अंगों का असाधारण विकास हुआ। किन्तु, इन अंगों के विकास में समन्वय स्थापित करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। अतः भारतीय शिक्षा-मंत्रालय ने सन् 1961 में "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद्" (NCERT) की स्थापना की। इस "परिषद्" के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

1. उच्च कोटि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. शिक्षक-प्रशिक्षण की नवीन विधियों की खोज करना और उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करके, शिक्षक-प्रशिक्षण का उपग्रहण करना।
3. शिक्षा के सब अंगों से सम्बन्धित अनुसंधान का पोषण, प्रचार एवं संगठन करना।
4. शिक्षा के विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में अध्ययन, अनुसंधान एवं सर्वेक्षण करना।
5. शिक्षा-संस्थाओं को शिक्षण की नवीन विधियों एवं प्रयोगों से परिचित करना।

"परिषद्" ने उपरिअंकित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए "राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसंधान" (National Institute of Education) का निर्माण किया है, जिसके मुख्य विभाग ये हैं :—(1) क्षेत्रीय सेवाएँ; (2) प्रौढ़-शिक्षा, (3) विज्ञान-शिक्षा, (4) तुलनात्मक शिक्षा; (5) अध्य-दृष्ट-शिक्षा; (6) शैक्षिक प्रणाली, (7) पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, (8) शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार; और (9) शिक्षा के सामाजिक एवं दार्शनिक आधार।

## 2. ग्रामीण उच्चतर शिक्षा

### Rural Higher Education

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के प्रति सरकार का ध्यान सर्वप्रथम राधाकृष्णन् "कमीशन" ने आकृष्ट किया। "कमीशन" ने ग्रामीण कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश करते हुए कहा<sup>1</sup> :— "ग्रामीण भारत की सामान्य प्रगति के लिए कुशलता एवं प्रशिक्षण की निरन्तर विस्तृत होने वाली सीमा एवं श्रेष्ठता आवश्यक है। इनकी और शिक्षित नागरिकता की माँगों को पूर्ण करने के लिये ग्रामीण कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की प्रणाली आवश्यक है।"

भारत-सरकार ने "कमीशन" की सिफारिश को मान्यता प्रदान करके अक्टूबर, 1954 में "राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिषद्" (National Council for Rural Higher Education) की स्थापना की और उससे ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह माँगी। "परिषद्" ने ग्रामीण भारत एवं नवयुवकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, "ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-योजना" (Scheme of Rural Higher Education) का निर्माण किया। इस योजना में "परिषद्" ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए; यथा<sup>2</sup> :—

1. ग्रामीण नवयुवकों में समुदाय-सेवा एवं ग्रामीण जीवन के लिए रुचि उत्पन्न करना।
2. ग्रामीण नवयुवकों को केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों के ग्राम-विकास-कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करना।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, "परिषद्" ने यह सुझाव दिया कि ग्रामीण नवयुवकों के लिए माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाय और इस शिक्षा के लिए "ग्रामीण संस्थानों" (Rural Institutes) की स्थापना की जाय। इन संस्थानों के पाठ्यक्रमों के विषय में "परिषद्" ने अग्रार्कित विचार व्यक्त किए :— (1) शिक्षण-डिप्लोमा का 1 वर्ष का कोर्स; (2) शिक्षण-सर्टिफिकेट का 1 वर्ष का कोर्स; (3) ओवरसियरों का 2 वर्ष का सर्टिफिकेट-कोर्स; (4) कृषि-विज्ञान का 2 वर्ष का सर्टिफिकेट-कोर्स; (5) ग्रामीण सेवाओं का 3 वर्ष का डिप्लोमा-कोर्स; और (6) ग्रामीण स्वास्थ्य-नेविकताओं का 2 वर्ष का सर्टिफिकेट-कोर्स।

"परिषद्" द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली योजना 1956 में कार्यान्वित की गई और देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण संस्थाओं की स्थापना का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस समय देश में 15 ग्रामीण संस्थान अग्रार्कित स्थानों में कार्य कर रहे

1. Radhakrishnan Commission Report, p. 575.

2. India, 1974, p. 53.

हैं<sup>1</sup> :—1. श्री निकेतन, पश्चिमी बंगाल; 2. गांधीग्राम, तामिलनाडु; 3. जामिया-मिलिया, दिल्ली; 4. उदयपुर, राजस्थान; 5. विरोली, बिहार; 6. बिषपुरी, झारखण्ड; 7. सनोहर, गुजरात; 8. कायम्बटोर, तामिलनाडु; 9. गरमोनी, महाराष्ट्र; 10. अमरावती, महाराष्ट्र; 11. रात्रपुरा, पंजाब; 12. वर्षा, महाराष्ट्र; 13. हनुमानगढ़ी, मैसूर; 14. तवानूर, केरल; 15. इन्दौर, मध्य-प्रदेश।

### 3. उत्तर प्रदेश में अध्यापक-शिक्षा

#### Teacher-Education in Uttar Pradesh

स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय से उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के स्कूलों में अनिवार्य गति से वृद्धि हो रही है। इन स्कूलों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग रहती है। अतः उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षक-शिक्षा अथवा अध्यापक-प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया है। हमारे राज्य में इस प्रशिक्षण की व्यवस्था का स्वरूप निम्नांकित है :—

प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण—इन स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण—नामक स्कूलों एवं जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कॉलेजों में होता है। इनमें उपस्नातको को प्रवेश दिया जाता है। उनके प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को “सर्टिफिकेट” प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण सड़को और सड़कियों—दोनों के लिए है। कुछ स्थानों में सड़कियों के लिए सी० टी० के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है।

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं का अभाव है। इस अभाव को पूर्ण करने के लिए सरकार ने पाँचवीं वर्षीय योजना में राजकीय बालिका नामक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने का निश्चय किया है। विज्ञान के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की मांग को पूरा करने के लिए समन्वय के “गवर्नमेंट कन्स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कॉलेज” में सी० टी० का पाठ्यक्रम आरम्भ किया जायगा।<sup>2</sup>

हाई स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण—इन स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण—ट्रेनिंग कॉलेजों या सामान्य शिक्षा एवं विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध शिक्षा-विभागों में होता है। इनमें स्नातको और पर-स्नातको को प्रवेश दिया जाता है। उनके प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को एम० टी० का प्रमाणपत्र या बी० एड० की उपाधि प्रदान की जाती है। कुछ ट्रेनिंग कॉलेजों और शिक्षा-विभागों में एम० एड० की शिक्षा की भी व्यवस्था है। एम० टी०, बी० एड० और एम० एड० पुरुषों और महिलाओं—दोनों के लिए है। कुछ स्थानों में महिलाओं के लिए पृथक् प्रशिक्षण-कॉलेज भी है।

1. *Hindustan Year-Book*, 1974, p. 182.

2. *Fifth Five-Year Plan, Uttar Pradesh, Annual Plan*, 1974-75, p. 305.

**विशिष्ट प्रशिक्षण-संस्थाएँ—**उत्तर प्रदेश में कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण-संस्थाएँ भी हैं; यथा :—

**1. राज्य-शिक्षा-संस्थान : State Institute of Education—**इसकी स्थापना 1964 में इलाहाबाद में की गई थी। इस पर अग्रांकित पाँच कार्यों का भार है :—(1) प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण-कार्यक्रम में अनुसंधान करना; (2) प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रसार-सेवाओं का आयोजन करना; (3) प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों के लिए साहित्य तैयार करना; (4) निरीक्षक-वर्ग को सेवाकार्त्तन प्रशिक्षण देना; और (5) निरीक्षक-वर्ग एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नवीन पाठ्यक्रमों का निर्माण करना।

**4. शिक्षा-विज्ञान-केन्द्र : Pedagogical Institute—**इसकी स्थापना 1948 में इलाहाबाद में की गई थी। इसके मुख्य कार्य हैं :—(1) शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं की जाँच करना; (2) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना; और (3) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में नवीन प्रयोग करना।

**5. मनोवैज्ञानिक केन्द्र : Psychological Bureau—**इसकी स्थापना 1947 में इलाहाबाद में की गई थी। इसमें विभिन्न विधियों द्वारा छात्रों की बुद्धि एवं चरित्रों की परीक्षा लेकर, उनकी शिक्षा, पाठ्यक्रम एवं व्यवसायों का चयन करने में सहायता दी जाती है। सन् 1952 में इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की सृष्टि—मेरठ, बरेली, बनारस, लखनऊ और कानपुर में की गई। इस प्रकार के केन्द्रों की प्रत्येक जिले में स्थापना करने की योजना है।

**4. नर्सरी ट्रेनिंग कॉलेज : Nursery Training College—**इसकी स्थापना 1951 में इलाहाबाद में की गई थी। इसमें उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो नर्सरी या माटेनरी स्कूलों में शिक्षण का कार्य करने के अभिलाषी होते हैं।

**5. राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण-महाविद्यालय : Government Constructive Training College—**इसकी स्थापना 1948 में इलाहाबाद में की गई थी। अब कई वर्षों में इसको लखनऊ ले आया गया है। इसमें छात्रों को अनेक प्रकार की दृष्टिकोणों का प्रशिक्षण देकर, रचनात्मक वर्ग के विशिष्ट विषयों का शिक्षण देने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें रचनात्मक पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष की एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को एन० टी० का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

**6. शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज : Physical Training College—**यह कॉलेज, लखनऊ में है। इसमें पुरुष एवं स्त्री स्नातक एवं उपस्नातक प्रवेश लेकर, शारीरिक व्यायाम का प्रशिक्षण प्राप्त करने है।

पाँचवीं योजना में शिक्षा-विशेष—उत्तर प्रदेश की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-विशेष के अनेक नवीन कार्यक्रमों को स्थान दिया गया है, जिनमें से अत्यंत उत्प्रेरणीय हैं<sup>1</sup> :—

1. इलाहाबाद के “अंग्रेजी भाषा-शिक्षण-अस्थान” (English Language Teaching Institute) को गुरुत्व बनाना ।
2. जिन 19 जिलों में “राजकीय शान्ति नार्मल स्कूल” नहीं हैं, उनमें इन स्कूलों का निर्माण करना ।
3. फैजाबाद में “शारीरिक शिक्षा का जूनियर बेसिक प्रशिक्षण कालेज” (Junior Basic Training College of Physical Education) स्थापित करना ।
4. वर्तमान नार्मल स्कूलों में से 42 में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए “अभिनवन पाठ्यक्रम केन्द्रों” (Refresher Course Centres) की गृष्टि करना ।
5. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को “सेवाकालीन प्रशिक्षण” (In-Service Training) देने के लिए “क्षेत्रीय सेवाकालीन केन्द्रों” (Regional In-Service Training Centres) का निमाग्य करना ।
6. राज्य-शिक्षा-अस्थान में अत्यंत विभागों का आयोजन करना :—  
(1) पुस्तक-प्रकाशन विभाग, (2) निरीक्षण-वर्ग, बेसिक शिक्षा-अधि-कारियों, नार्मल स्कूलों के प्राधानाचार्यों आदि को पूर्व-सेवा (Pre-Service) एवं सेवाकालीन (In-Service) प्रशिक्षण देने का विभाग; और (3) शिक्षकों के अभिनवन पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के माध्यम का निर्माण, समया प्रकाशन एवं उसे अभिनवन पाठ्यक्रम-केन्द्रों में वितरित करने का विभाग ।

1. *Fifth Five-Year Plan, Uttar Pradesh, Annual Plan, 1974-75*, pp. 323-325.



